प्रतियोगिता दर्पण

जनवरी 2024 मूल्य ₹ 125.00

हिन्दी मासिक

शिक्षित युवा वर्ग के स्वर्णिम भविष्य के लिये

For e-magazine:
http://emagazine.pdgroup.in

अर्द्ध-वार्षिकांक

- आजादी के अमृत महोत्सव का समापन, मेरा युवा भारत का शुभारम्भ
- ग्वालियर व कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल
- 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं पर सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट
- जातिगत गणना के परिणामों के आधार पर बिहार में कुल आरक्षण अब 75 प्रतिशत
- अमरीका व आस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ताएं
- बुकर पुरस्कार, मिस यूनिवर्स व बैलन डि'ओर पुरस्कार (2023)
- अफगानिस्तान का भारत स्थित दूतावास स्थायी रूप से बंद
- आस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप (2023) का विजेता
- 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में सम्पन्न: महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान
- ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम
- इटली डेविस कप व कनाडा बिली जीन किंग कप (2023) का विजेता
- एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट (2024)
- 2024 में फॉर्मूला-1 रेसों का कार्यक्रम

INTERNATIONAL YEAR OF CAMELIDS 2024

हल प्रश्न-पत्र

- उ.प्र. पीसीएस (मुख्य), 23
- यू.जी.सी.-नेट/जेआरएफ, 23

मॉडल हल आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी

भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

STUDYP ALLAH

संस्थापक सम्पादक
स्व. श्री महेन्द्र जैन

सम्पादक
राहुल जैन

प्रधान सलाहकार
डॉ. रवि कान्त

रजिस्टर्ड ऑफिस
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002

सम्पादकीय ऑफिस
1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी,
आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा–282 005
फोन–2531101, 2530966
ई-मेल : सम्पादकीय : publisher@pdgroup.in
कस्टमर केयर : care@pdgroup.in

दिल्ली ऑफिस
4845, अंसारी रोड, दरियागंज,
नई दिल्ली–110 002
फोन–011-23251844, 43259035

हैदराबाद ऑफिस
16-11-23/37, मूसारामबाग, टीगन गुडा
आर.टी.ए. ऑफिस के सामने मेन रोड
(यूनियन बैंक के बगल में), हैदराबाद–500 036
(तेलंगाना) मो.–09391487283

पटना ऑफिस
पारस भवन (प्रथम तल), खजांची रोड,
पटना–800 004
मो.–09334137572

हल्द्वानी ऑफिस
8-310/1, ए.के. हाउस हीरानगर, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल–263 139
(उत्तराखण्ड) मो.–07060421008

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

के पाठकों से...

प्रिय पाठको !

आपकी सर्वाग्रगण्य एवं लोकप्रिय पत्रिका **'प्रतियोगिता दर्पण'** का **जनवरी 2024 अंक** आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष एवं सन्तोष की अनुभूति हो रही है. पत्रिका के प्रस्तुत अंक को आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है. प्रकाशन से सम्बन्धित सभी लोगों के सामूहिक प्रयास एवं सहयोग से यह अंक इतना अधिक परीक्षोपयोगी बन पाया है.

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से इस अंक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित एवं विश्लेषणात्मक लेख दिए गए हैं. इनमें से कुछ लेख इस प्रकार हैं–वित्तीय बाजार में प्रयुक्त अद्यतन शब्दावली, डीप फेक : उपयोग और चुनौतियाँ, पुनर्गठन से ही रहेगी सुरक्षा परिषद् प्रभावी, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्भावित लाभ, भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए सम्भावनाएं, कॉर्पोरेट जगत् में ऊँचे पदों पर महिलाएं कम क्यों हैं ?

पत्रिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चयनित हल प्रश्न-पत्र आवश्यक व्याख्या एवं संकेतों के साथ दिए गए हैं. इनमें से कुछ प्रश्न-पत्र इस प्रकार हैं–

हल प्रश्न-पत्र–उ.प्र. लोक सेवा आयोग (मुख्य) परीक्षा, 2023 का हल प्रश्न-पत्र–सामान्य अध्ययन-III.

ऐच्छिक विषय–अर्थशास्त्र–यू.जी.सी.–नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा, 2023.

हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि **"कठिन परिश्रम एवं उचित और सामयिक मार्गदर्शन सफलता प्राप्त करने का मूलमंत्र है."** **प्रतियोगिता दर्पण** आपका सही एवं सामयिक मार्गदर्शन करने में बेजोड़ है. आप प्रयास कीजिए, आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए प्रतियोगिता दर्पण आपके साथ है.

नियमित रूप से एवं समझदारी के साथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए. यह आपको अभीष्ट सफलता दिलाने एवं आपके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में पूर्णतः सक्षम है.

आपकी चतुर्दिक सफलता एवं स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं सहित

राहुल जैन
(सम्पादक)

All rights reserved. No part of this Magazine may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, Electronic, Mechanical, Photocopying, Recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither publisher nor any of its employees accept any responsibility for any error or omission. Articles that cannot be used are returned to the authors if accompanied by a self addressed and sufficiently stamped envelope. But no responsibility is taken for any loss or delay in returning the material. Pratiyogita Darpan assumes no responsibility for statements and opinions advanced by the authors nor for any claims made in the advertisements published in the Magazine.

STUDYPDF WALLAH

46 वर्ष | षष्ट्म अंक | जनवरी 2024

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

543 वाँ सफलतम अंक

इस अंक में...

7 सम्पादकीय

9 राष्ट्रीय घटनाक्रम

14 अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

18 आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

21 भारतीय अर्थव्यवस्था : एक दृष्टि में

28 नवीनतम सामान्य ज्ञान

34 खेलकूद

39 गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान : सेना व हरियाणा का क्रमश: दूसरा व तीसरा स्थान

40 आस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप (2023) का विजेता : लगातार 10 मैच जीतने के पश्चात् अंतिम फाइनल मैच में भारत पराजित

43 रोजगार समाचार

45 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

47 **कॅरियर लेख :** सिविल सेवा परीक्षा चुनौतीपूर्ण, दें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास !

अनुप्रेरक युवा प्रतिभाएं

51 **मुकेश कुमार यादव**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित (9वाँ स्थान)

53 **महेशानन्द**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

54 **रजनीश शंकर झा**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

56 **मोहम्मद फैसल चाँद**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

58 दिव्य दर्पण

फोकस

65 (1) तेजी से बढ़ते असुरक्षित उपभोक्ता ऋणों पर लगाम

68 (2) 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा

71 (3) जलवायु परिवर्तन के उपजे खतरे : कॉप-28 (CoP-28) से अपेक्षाएं

74 स्मरणीय तथ्य

विश्व परिदृश्य

76 भारत तथा जी-20 सम्मेलन

78 भारत व फ्रांस सम्बन्धों की समृद्ध विरासत

STUDYPDF WALLAH

विविधा

80 ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल

84 वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं

लेख

90 **आर्थिक एवं वाणिज्यिक लेख**—वित्तीय बाजार में प्रयुक्त अद्यतन शब्दावली

93 **आर्थिक लेख**—भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अद्यतन प्रवृत्तियाँ

97 **प्रौद्योगिकी लेख**—सिंथेटिक मानव भ्रूण : विज्ञान की नई उपलब्धि

99 **प्रौद्योगिकी लेख**—डीपफेक : उपयोग और चुनौतियाँ

101 **वैश्विक संस्था लेख**—पुनर्गठन से ही रहेगी सुरक्षा परिषद् प्रभावी

103 **प्रौद्योगिकी लेख**—शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्भावित लाभ

105 **सामयिक लेख**—जलवायु वित्त की आवश्यकता

108 **सागर-सम्पदा लेख**—भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए सम्भावनाएं

111 **उद्योग जगत् लेख**—कॉर्पोरेट जगत् में ऊँचे पदों पर महिलाएं कम क्यों हैं ?

113 सार संग्रह

116 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

हल प्रश्न-पत्र

120 उ.प्र. लोक सेवा आयोग (मुख्य) परीक्षा, 2023 का हल प्रश्न-पत्र : सामान्य अध्ययन-III

ऐच्छिक विषय

128 यू.जी.सी. नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा, 2023 का हल प्रश्न-पत्र : अर्थशास्त्र

मॉडल हल प्रश्न

140 आगामी उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न : सामान्य अध्ययन

155 उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता

विविध/सामान्य

156 वर्षांत समीक्षा-2022 रेल मंत्रालय

ज्ञानार्जन के नवीन क्षितिज

160 क्या आप जानते हैं ?

161 अपना ज्ञान बढ़ाइए

श्रेष्ठतर प्रतिभागी

163 **प्रथम पुरस्कृत निबन्ध**—भारत के लिए चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता के निहितार्थ

165 **निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक-532 का परिणाम**

166 **प्रथम पुरस्कृत समीक्षा** : पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित किए जाने से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल हो गया है

अर्द्ध-वार्षिकांक

169 राष्ट्रीय घटनाक्रम

179 अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

185 आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

195 नवीनतम सामान्य ज्ञान

204 खेलकूद

प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित किसी भी सामग्री अथवा चित्र के लिए सम्पादक की सहमति होना आवश्यक नहीं है. –सम्पादक

STUDYPDF WALLAH

सम्पादकीय

अपनी उपेक्षा करना बन्द कीजिए

"Eat like you love yourself
Move like you love yourself
Speak like you love yourself
Act like you love yourself."

धुलाई के लिए कोट देते समय उसके कान में किसी की आवाज आई–कोट की जेबें देख लो, किसी जेब में कुछ रखा न हो ''नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैंने इसे अभी-अभी सन्दूक में से निकाला है'' तर्क देकर उसने अपने मन को झटक दिया अगले दिन उसको ध्यान आया कि कोट को बक्से से बाहर निकालते समय उसके हाथ में अमुक कागज था वह कहीं गिर न जाए. इस कारण उसने उस कागज को कोट की सामने वाली जेब में रख दिया था. समस्त प्रयास करने के बाद भी कागज नहीं मिल सका.

यह आवाज किसकी थी ? यह आवाज स्वयं उसी की थी जिसे उसके कानों ने नहीं, उसके मन ने सुना था हम सब उसे सुनते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और दुःख पाते हैं.

महान् दार्शनिक सोफोक्लीज के मतानुसार ''कोई साक्षी इतना विकट और इतना शक्तिशाली नहीं है, जितना अपना अन्तःकरण, अपना अन्तर्मन'' यह वह शक्ति है, जो हमारे मन-मस्तिष्क का मार्गदर्शन करती है, परन्तु हम उसकी उपेक्षा करते रहते हैं. मन में, अपने भीतर काम करने वाली इस शक्ति को दर्शन की भाषा में अन्तःकरण और लोक की भाषा में अन्दर की आवाज कहते हैं. जब भी हम कोई गलत कदम उठाते हैं, अनुचित, लोक विरुद्ध एवं अपने हित के विरुद्ध काम करने को उद्यत होते हैं. यह हमें सावधान करती है, हमारे मन में एक प्रकार की झिझक पैदा करती है. हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं. जो इसके अनुसार आचरण करते हैं, वे भाग्य-शाली होते हैं, वे ही सफलता और शक्ति के अधिकारी बनते हैं.

महात्मा गांधी प्रायः कहा करते थे कि मैं अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता हूँ. उनकी सुनिश्चित मान्यता थी कि अन्तर की आवाज कभी गलत नहीं होती है. ''अन्तःकरण के मामले में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं होता है.'' जैसे वासनाएं देह की वाणी हैं, वैसे ही अन्तःकरण आत्मा की वाणी है. यदि वे एक-दूसरे का खण्डन करती हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है ? ऐसा करते हुए महात्माजी ने क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त नहीं किया ? इसे समस्त विश्व जानता है. एक सामान्य बालक मोहनदास ने विश्वबन्धु बापू का पद प्राप्त कर लिया. जब भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन पूर्ण प्रकर्ष पर था. उस समय चौरी-चौरा में हत्याकाण्ड का समाचार पाकर गांधीजी ने अन्दर की आवाज के नाम पर आन्दोलन एकदम वापस ले लिया था. उन्हीं महात्मा गांधी ने सन् 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो, भारतवासी जियो या मरो का नारा दिया था. कहने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य ने सिद्ध कर दिया कि उनके उक्त दोनों निर्णय उपयुक्त थे. कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भीतर से आने वाली आवाज सदा सही मार्गदर्शन करती है. उसने आपका मार्गदर्शन किया होगा, आपसे कहा होगा–आप अमुक अवसर पर अमुक विषय लें, अमुक प्रकार से परीक्षा की तैयारी करें, अमुक स्थान पर, मेले में, तमाशे में, यारवासी में न जाएं. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा होगा–आप अमुक प्रतियोगिता में भाग लें. आप स्वयं विचार कर लें कि आपने उसके अनुसार क्या किया है और क्या नहीं किया है ?

भले और बुरे, उचित और अनुचित, ग्राह्य और त्याज्य आदि का निर्णय करने वाली वृत्ति को हम विवेक कहते हैं. यह विवेक इसी अन्तर-ध्वनि की देन है. विचारणीय यह है कि क्या हम विवेक का सम्यक् उपयोग करते हैं? इसकी उपेक्षा ही वस्तुतः हमारी असफलताओं के मूल में स्थित रहती है जीवन की विडम्बना यह है कि हम अनेक बार असफलता का संत्रास भोगने के उपरान्त भी कुछ भी नहीं सीख पाते हैं. हम वस्तुतः नरक के कीड़े हैं और नरक में ही रहना जानते हैं और उसी का वरण करते रहते हैं.

भौतिक सुख-सम्बन्धी अनेक वासनाएं तथा आकांक्षाएं हमको प्रत्येक क्षण घेरे रहती हैं. हम उनकी व्यर्थता जानते हुए भी उनके पीछे दौड़ते रहते हैं. विवेक की महती शक्ति होते हुए भी हम यह भी तो नहीं करते हैं कि केवल इनी-गिनी वासनाओं की तृप्ति का विधान करें. हम सबको सन्तुष्ट करना चाहते हैं और ऐसा होना सम्भव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख-सुविधा के साधन सीमित हैं. अतएव सुख-सुविधाओं की तीव्र उत्कंठा के वशीभूत हम न अपना करणीय कर्त्तव्य निर्धारित कर पाते हैं और न सफलता के द्वार तक पहुँच पाते हैं. निराशा की प्रतिमूर्ति बने हुए संत्रास संकुल, व्यथित, उत्तेजित एवं उपेक्षित जीवन-यापन के लिए अभिशप्त बने रहते हैं. स्मरण रखिए कि इस दुर्भाग्यपूर्ण नियति के लिए हम सब स्वयं उत्तरदायी हैं. मैथिलीशरण गुप्त के कथन–अपना अन्तःकरण आप हैं आचारों के सुविचारों के अनुसार हम स्वयं विचार करें कि क्या हमने आरम्भ में अपनी सामर्थ्य को दृष्टिगत करके, किसी विशेष प्रतियोगिता में सफलता को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था? ऐसा न करके हम अपनी सीमित शक्ति को इधर-उधर बिखेरते रहे हैं और भाग्य, भगवान एवं समाज की व्यवस्था एवं परीक्षा-प्रणाली आदि को दोषी ठहराकर मन को समझाते रहे हैं. अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है हमारे सामने कुछ अवसर शेष हैं. हम अपने अन्तर की आवाज को सुनकर निर्णय करें और लक्ष्य-प्राप्ति के प्रति प्राणपन से प्रयासरत् हो जाएं. महाकवि एवं विचारक कालिदास के इस कथन से प्रेरणा ग्रहण करें कि ''संताहि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाण-मन्तःकरण प्रवृत्तम'' अर्थात् संदेह की दशा में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है.

स्वार्थबद्ध होने के कारण हम अपने अन्दर की आवाज की अवहेलना करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं. इस प्रक्रिया में वह कुंठित होती रहती है, फिर भी वह मरती नहीं है. अपनी मंद ध्वनि को हम तक पहुँचाने का प्रयत्न करती रहती है. हमने उसके प्रति कितनी ही निर्ममतापूर्ण व्यवहार किया हो, परन्तु वह हमारे मार्गदर्शन हेतु सदैव प्रस्तुत एवं उपलब्ध है. उसके रहते हुए हमें निराश एवं हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है. हम उसके प्रति आश्वस्त हों तथा एकाग्रचित्त होकर उसको सुनने का प्रयत्न करें. सुनना ही अलम् न मान लें, उसके अनुसार आचरण भी करें. आपको सही दिशा में जाने का संकेत प्राप्त होगा और आपके जीवन की ऋतु बदल जाएगी. अभी तक आप स्वयं की उपेक्षा करते रहे हैं. अपने प्रति विश्वास कीजिए. कस्तूरी मृग की भाँति कस्तूरी की गंध के स्रोत की खोज में चारों ओर भटकना बंद कीजिए. सुगंध का कोष आपके अन्तर में स्थित है. गुरुदेव कवीन्द्र रवीन्द्र का यह कथन ध्यातव्य है– एक बार अन्तःकरण की ओर आँख घुमाओ तो सही, सब कुछ समझ में आ जाएगा. ''अन्तःकरण दीपक की भाँति स्वयं को प्रत्यक्ष करता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष करता है.'' वास्तविकता यह है कि अन्तःकरण मानव में परमात्मा की उपस्थिति है–*Conscience is God's presence in man.*

विचार कीजिए–जो अपनी उपेक्षा करता है. उसकी उपेक्षा अन्य जन क्यों न करेंगे ?

●●●

STUDYPDF WALLAH

आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं

2023

2–30 दिसम्बर–बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, 2023
6–22 दिसम्बर–यू.जी.सी.–नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा (दिसम्बर 2023)
10 दिसम्बर–ऑल इण्डिया बार परीक्षा–XVIII
17 दिसम्बर–मध्य प्रदेश पी.एस.सी. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2023
17 दिसम्बर–मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2023
17 दिसम्बर–उत्तराखण्ड समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा, 2023
22 दिसम्बर–एस.एस.सी. सब-इंस्पेक्टर्स परीक्षा, 2023 (दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल), पेपर-II
26, 27 एवं 28 दिसम्बर–सी.एस.आई.आर.–यू.जी.सी. नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा (दिसम्बर 2023)
30 दिसम्बर–आई.बी.पी.एस. बैंक विशेषज्ञ अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा, 2024-25
30-31 दिसम्बर–आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जूनियर सहायक प्रबंधक और कार्यकारी भर्ती परीक्षा, 2023
दिसम्बर-जनवरी–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पी.ओ. मुख्य परीक्षा, 2023

2024

जनवरी–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एण्ड सेल्स) प्रारम्भिक परीक्षा, 2023
6-7 जनवरी–बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, 2023
20 जनवरी–जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, 2024 (कक्षा-6)
21 जनवरी–अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, 2024-25
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 16 दिसम्बर, 2023)
21 जनवरी–केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) जनवरी, 2024
21 जनवरी–राजस्थान एस.एस.सी. सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2023
28 जनवरी–आई.बी.पी.एस. बैंक विशेषज्ञ अधिकारी मुख्य परीक्षा, 2024-25
फरवरी–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एण्ड सेल्स) मुख्य परीक्षा, 2023
3 फरवरी–राजस्थान एस.एस.सी. संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, 2023
3 फरवरी–राजस्थान एस.एस.सी. संविदा नर्स (GNM) सीधी भर्ती परीक्षा, 2023
4 फरवरी–राजस्थान एस.एस.सी. कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, 2023
11 फरवरी–राजस्थान एस.एस.सी. कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2023
11 फरवरी–छत्तीसगढ़ पीएससी राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2023
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 30 दिसम्बर, 2023)
11 फरवरी–हरियाणा सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2023
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 21 फरवरी, 2024)
फरवरी-मार्च–एस.एस.सी. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एसएसएफ कॉंस्टेबिल (जीडी), व राइफलमैन (जीडी) असम राइफल्स परीक्षा, 2024
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 31 दिसम्बर, 2023)
3 मार्च–राजस्थान एस.एस.सी. संगणक (Sanganak) सीधी भर्ती परीक्षा, 2023
11–16 मार्च–म.प्र. पी.एस.सी. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, 2023
अप्रैल–जून–राजस्थान एस.एस.सी. पशु परिचर (Animal Attendent) सीधी भर्ती परीक्षा, 2023

निबन्ध प्रतियोगिता

विषय–"जाति व्यवस्था की ओर वापस लौटती भारतीय राजनीति"
अन्तिम तिथि–28 जनवरी, 2024.
शब्द संख्या–लगभग 2000 शब्द.

1. निबन्ध कागज के एक ओर ही टंकित अथवा स्वहस्तलिखित होना चाहिए.
2. निबन्ध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट आकार का छायाचित्र भेजें. प्रथम तीन निबन्धों पर क्रमशः ₹ 2000, ₹ 1500 व ₹ 1000 चेक के माध्यम से व प्रमाण-पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे. अन्य 5 अनुशंसित निबन्धों को आकर्षक प्रमाण-पत्र व उपकार प्रकाशन की ₹ 300 मूल्य तक की वांछित पुस्तक पुरस्कारस्वरूप दी जाएगी.
3. प्रत्येक प्रविष्टि पर अपना नाम English के Capital Letter में लिखें जिस नाम से आपका बैंक खाता हो, बैंक का नाम, खाता नम्बर व बैंक का IFSC कोड नं. भी अवश्य लिखें.

सदस्यता शुल्क

प्रतियोगिता दर्पण

	हिन्दी	अंग्रेजी
एक प्रति मूल्य	125.00	125.00
वार्षिक मूल्य :		
साधारण डाक से	1130·00	1125·00
रजिस्टर्ड डाक से	1350.00	1345·00
द्विवार्षिक मूल्य :		
साधारण डाक से	2105·00	2100·00
रजिस्टर्ड डाक से	2545·00	2540·00

सामान्य ज्ञान दर्पण / सक्सेस मिरर

		सामान्य ज्ञान दर्पण	सक्सेस मिरर
एक प्रति मूल्य	₹	45.00	25.00
वार्षिक मूल्य :			
साधारण डाक से	₹	405.00	225.00
रजिस्टर्ड डाक से	₹	620.00	440.00
द्विवार्षिक मूल्य :			
साधारण डाक से	₹	755.00	420.00
रजिस्टर्ड डाक से	₹	1185.00	850.00

- कृपया अपना सदस्यता-शुल्क मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही प्रेषित करें. चेक स्वीकार नहीं होंगे. आप हमारी Website : www.pdgroup.in द्वारा भी सदस्यता शुल्क अदा कर सकते हैं.
- अपने स्पष्ट पते के साथ यह भी सूचित करें कि आप किस माह से किस माह तक के लिए ग्राहक बन रहे हैं.
- पुराने ग्राहक कृपया अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें.
- मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट **'प्रतियोगिता दर्पण'** के नाम से आगरा में देय ही स्वीकार किए जाएंगे.

ऑर्डर फार्म

मैं प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी/अंग्रेजी मासिक)/ सामान्य ज्ञान दर्पण (हिन्दी मासिक)/ सक्सेस मिरर का वार्षिक/ द्विवार्षिक नियमित ग्राहक बनना चाहता हूँ/चाहती हूँ. कृपया मेरी प्रति मुझे निम्नांकित पते पर प्रेषित करने की कृपा करें.

नाम_____

पता_____

_____

_____

पिन ☐☐☐☐☐☐

मो. नं.....

मैं ₹.....मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित कर रहा हूँ/रही हूँ.

दिनांक _____ प्रेषक के हस्ताक्षर _____

प्रतियोगिता दर्पण
1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास **आगरा**–282 005
फोन : 2531101, 2530966
Website : www.pdgroup.in
E-mail : care@pdgroup.in

STUDYPDF WALLAH

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- सिल्क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल
- जातिगत गणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि
- भारत के दो और शहर ग्वालियर व कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए
- 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राज-मार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट
- तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा पुनः पारित
- निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय द्वारा रद्द
- मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी
- भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सम्पन्न

सिल्क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल

उत्तराखण्ड के उत्तराकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिल्क्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फँसे 41 मजदूरों को 28 नवम्बर, 2023 की शाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के अनुसार सभी मजदूरों को एक-एक करके 900 मिमी के उस पाइप के जरिए बाहर निकाला गया है, जिसे मलबे में ड्रिल करके डाला गया था. टनल से बाहर आए प्रत्येक मजदूर के लिए उत्तराखण्ड के सीएम धामी ने ₹ 1 लाख दिए जाने की घोषणा की है.

इस रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में अन्तिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट-होल माइनिंग का सहारा लिया गया. उल्लेखनीय है कि अमरीकी ऑगुर ड्रिल मशीन जैसे–दक्ष उपकरण के भी फेल (टूटने) हो जाने के बाद बचाव कर्मियों ने अन्तिम कुछ मीटर की खुदाई के लिए रैट-होल माइनिंग का सहारा लिया. यह अधिक चर्चा का विषय इसलिए भी रहा क्योंकि वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा इसे बैन कर दिया गया था.

रैट-होल माइनिंग क्या है ?

रैट-होल माइनिंग विशेषतया मेघालय में काफी समय से प्रचलित है. यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है. 'रैट-होल' शब्द जमीन में खोदे गए संकरे गड्ढों को दर्शाता है. यह गड्ढा आमतौर पर सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए होता है. एक बार गड्ढे खुदने के बाद माइनर कोयले की परतों तक पहुँचने के लिए रस्सियों या बाँस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं. फिर कोयले को गैंती, फावड़े और टोकरियों जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके मैन्युअली निकाला जाता है. रैट-होल माइनिंग मुख्य रूप से दो तरह की होती है. एक है साइड कटिंग प्रोसीजर तथा दूसरी कहलाती है बॉक्स कटिंग. साइड कटिंग में संकरी सुरंगें बनाई जाती हैं. पहाड़ों के ढलान पर इन्हें बनाया जाता है. फिर इस टनल में श्रमिक जाकर कोयले की परत को तलाशते हैं. बॉक्स कटिंग तरीके में 10 से 100 वर्गमीटर तक की एक ओपनिंग बनाई जाती है. उसके बीच से 100 से 400 फीट गहरा एक वर्टिकल गड्ढा खोदा जाता है.एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें हॉरिजॉन्टल रूप से खोदी जाती हैं. इसके जरिए श्रमिक कोयला निकालते हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2014 में इस तरीके पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. 2015 में भी उसने प्रतिबन्ध बरकरार रखा था. हालाँकि, यह आदेश मेघालय के सम्बन्ध में था. राज्य में कोयला खनन के लिए यह एक प्रचलित प्रक्रिया बनी हुई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसे कई मामले हैं जहाँ बरसात के मौसम के दौरान रैट-होल माइनिंग के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर गया. नतीजतन, श्रमिकों सहित कई लोगों की मौत हो गई.

सिल्क्यारा–बड़कोट सुरंग

सिल्क्यारा–बड़कोट सुरंग केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है. इस सुरंग के निर्माण का कार्य/टेंडर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है. 4531 मीटर लम्बी यह सुरंग सड़क की दूरी 26 किमी और यात्रा समय 45 मिनट तक कम कर देगी.

सुरंग ढहने का कारण

अभी तक सुरंग ढहने के किसी ठोस कारण का तो पता नहीं लगा है, लेकिन टनल के ढहने के प्राथमिक कारणों में सुरंग के मुहाने से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित ढहे हुए भाग में अज्ञात खंडित या कमजोर चट्टान का हिस्सा के टूटने या खिसकने के कारण हो सकता है. ऐसे कमजोर या अज्ञात खंडित चट्टानी क्षेत्र को कतरनी क्षेत्र (Shear Zone) कहा जाता है.

जातिगत गणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि

जातिगत गणना के परिणाम आने के पश्चात् बिहार में राज्य सरकार की सेवाओं में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश

STUDYPDF WALLAH

के मामलों में अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि की है. इसके लिए बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक (Bihar Reservation Amendment Bill) के मसौदे को राज्य मंत्रिमण्डल ने मंजूरी 7 नवम्बर को प्रदान की थी. विधान सभा में मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को विधान सभा ने सर्व सम्मति से 9 नवम्बर को पारित किया तथा अगले ही दिन 10 नवम्बर को विधान परिषद् में भी उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया. दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी विधेयक का समर्थन किया. विधान मण्डल में दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित विधेयक को राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेका ने अनुमोदन 17 नवम्बर को प्रदान कर दिया. जिसके बाद ही इस अधिनियम को गजट में अधिसूचित कर दिया गया है. अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में कुल प्रतिशत 60 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है. अभी तक राज्य में कुल 60 प्रतिशत आरक्षण में 50 प्रतिशत अनु. जातियों, (SC), जनजातियों (ST), अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) व अति पिछड़ा वर्गों (EBCs) के लिए था, जबकि 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए था. इस 10 प्रतिशत आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नए लागू किए गए अधिनियम में नहीं की गई है, जबकि अन्य वर्गों के लिए इसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है, जिससे कुल आरक्षण अब 75 प्रतिशत हो गया है.

बिहार में आरक्षण के संशोधित प्रावधान

श्रेणी/वर्ग	आरक्षण का पहले का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
अनुसूचित जाति (SC)	16	20
अनु. जनजाति (ST)	1	2
पिछड़े वर्ग (OBC)	12	18
अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC)	18	25
पिछड़ी जाति की महिलाएं (BC Women)	3	—
योग	**50**	**65**
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	10	10

संशोधित प्रावधानों के तहत् अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, जन जातियों (STs) के लिए यह 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBCs) के लिए 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पूर्ववत् 10 प्रतिशत सीटें ही आरक्षित रहेंगी.

उल्लेखनीय है कि बिहार की जातिगत गणना 2023 के परिणाम 2 अक्टूबर, 2023 को जारी हुए थे. इस गणना में राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 19·7 प्रतिशत तथा जनजाति की जनसंख्या 1·7 प्रतिशत पाई गई थी. इसी के आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान क्रमशः 20 प्रतिशत व 2 प्रतिशत किया गया है. पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 27·1 प्रतिशत जातिगत गणना में पाई गई है, किन्तु इनके लिए आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत जहाँ किया गया है, वहीं अति पिछड़े वर्गों (राज्य की कुल जनसंख्या में 36 प्रतिशत) के लिए आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है.

भारत के दो और शहर ग्वालियर व कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए

*भारत के दो शहर–ग्वालियर व कोझि-कोड (Kozhikode) विश्व के उन 55 शहरों में शामिल हैं, जिन्हें यूनेस्को **(UNESCO)** ने अपने **क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क** (UCCN) में शामिल करने की घोषणा 31 अक्टूबर, 2023 को विश्व शहर दिवस (World City Day) पर की. **यूनेस्को का सिटीज़ नेटवर्क 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है.** इसमें शिल्प एवं लोककला (Crafts and Folk Arts), डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी (Gastronomy), साहित्य, मीडिया कला एवं संगीत शामिल हैं. **भारत के नए शामिल किए गए नगरों में ग्वालियर को संगीत तथा कोझिकोड (Kozh-ikode) को साहित्य श्रेणी में नेटवर्क में शामिल किया गया है.** जिन 53 अन्य रचनात्मक शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क (UCCN) में 31 अक्टूबर, 2023 को शामिल किया गया है. उनमें बुखारा (शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में) कैसाब्लोका (मीडिया कला), चोंग किंग (डिजाइन), काठमांडू (फिल्म), रियो डि जेनेरियो (साहित्य) तथा उलान बटोर (शिल्प एवं लोक कला) आदि शामिल हैं. इन्हें मिला कर नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या 350 हो गई है.*

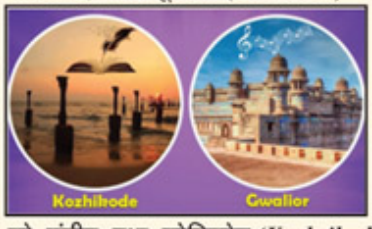

*ग्वालियर व कोझिकोड को शामिल किए जाने के पश्चात् यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या अब 8 हो गई है. **नेटवर्क में पहले से शामिल 6 अन्य भारतीय शहर जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई व श्रीनगर हैं. जयपुर को** 2015 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, वाराणसी को भी 2015 में संगीत श्रेणी में, चेन्नई को 2017 में संगीत श्रेणी में, हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी में, मुम्बई को भी 2019 में फिल्म श्रेणी में तथा श्रीनगर को 2021 में शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया था.*

2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट

वर्ष 2022 के दौरान देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं व उनके परिणामस्वरूप हुई मौतों के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2023 में जारी की, '**भारत में सड़क दुर्घटनाएं–2022** (Road Accident in India 2022)' शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि–

- वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11·9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2021 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 4,12,432 थी, जो बढ़कर 2022 में 4,61,312 रही है.
- सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या में 9·4 प्रतिशत की वृद्धि 2022 में हुई, रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 2021 में 1,53,972 थी, जो 2022 में 1,68,491 रही है.
- रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2019 के अन्त में देश में सड़कों की कुल लम्बाई 63·63 लाख किमी थी, जिसमें 1·32 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 1.80 लाख किमी राज्य राजमार्ग तथा 60·19 लाख किमी अन्य सड़कें (जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें व परियोजना सड़कें) थीं. इस प्रकार कुल सड़क मार्ग का 2·1 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग 2·8 प्रतिशत राज्य राजमार्ग व 95 प्रतिशत अन्य सड़कें थीं. रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2·1 प्रतिशत है, इसके बावजूद 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं की 32·95 प्रतिशत दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुईं, जबकि इन राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सड़क दुर्घटना की कुल मौतों का 36·23 प्रतिशत रही.
- देश में राज्य राजमार्ग (State Highways) कुल सड़क नेटवर्क का 2·8 प्रतिशत है.

STUDYPDF WALLAH

इसके बावजूद इन राजमार्गों पर 2022 में हुई दुर्घटनाएं कुल सड़क दुर्घटनाओं का 23·13 प्रतिशत रहीं, जबकि राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या ऐसी दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 24·34 प्रतिशत रही.

हाल ही के वर्षों में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या व उनके परिणामस्वरूप मौतें

वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं	मृतकों की संख्या
2018	4,70,403	1,57,593
2019	4,56,959	1,58,984
2020	3,72,181	1,38,383
2021	4,12,432	1,53,972
2022	4,61,312	1,68,491

- अन्य सड़कें, जो देश के कुल नेटवर्क का 95 प्रतिशत है, में 2022 में हुई दुर्घटनाएं पूरे वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं का 43·93 प्रतिशत थीं तथा इन दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 39·43 प्रतिशत थी.

वर्ष 2021 व 2022 में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या

क्रम	राज्य	2021	2022
1.	उत्तर प्रदेश	8,506 (15·2)	8,479 (13·9)
2.	तमिलनाडु	5,263 (9·4)	5,978 (9·8)
3.	महाराष्ट्र	4,080 (7·3)	4,923 (8·1)
4.	कर्नाटक	3,487 (6·2)	4,164 (6·8)
5.	राजस्थान	3,829 (6·8)	4,156 (6·8)
6.	मध्य प्रदेश	3,389 (6·1)	4,025 (6·6)
7.	बिहार	3,517 (6·3)	3,953 (6·5)
8.	आन्ध्र प्रदेश	3,602 (6·4)	3,793 (6·2)
9.	तेलंगाना	2,735 (4·9)	3,010 (4·9)
10.	गुजरात	2,077 (3·7)	2,109 (3·5)
पहले 10 राज्यों में योग		**40,485** 72·3	**44,590** 73·1
राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क दुर्घटनाएं		**56,007**	**61,038**

नोट–कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सम्बन्धित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क दुर्घटनाओं के प्रतिशत.

- 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों में 19·5 प्रतिशत मौतें पैदल चलने वालों की, 2·9 प्रतिशत मौतें साइकिल सवारों की तथा 44·5 प्रतिशत दो पहिया वाहन चालकों की हुई. इस प्रकार सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतों में 66·9 प्रतिशत मौतें इन श्रेणियों में हुईं.
- 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 66·5 प्रतिशत 18-45 वर्ष आयु वर्ग के थे. 18-60 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे शिकारों की संख्या कुल मौतों का 83·4 प्रतिशत थी.
- 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 86·2 प्रतिशत पुरुष व 13·8 प्रतिशत महिलाएं थीं.
- रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुईं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप हुई मौतों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही.

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा पुनः पारित

राज्य विधान सभा द्वारा पारित अनेक विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लम्बे समय तक दबाए रखने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील हाल ही में की थी. राजभवन द्वारा इस सन्दर्भ में विधेयकों को रोके रखने को गम्भीर चिन्ता का विषय शीर्ष अदालत ने 10 नवम्बर, 2023 को ही करार दिया था. सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी के पश्चात् तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने लम्बे समय से रोके हुए कम-से-कम 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नवम्बर 2023 में ही लौटाया था. **राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयकों को पुनः पारित करने के लिए तमिलनाडु विधान सभा का विशेष सत्र 18 नवम्बर, 2023 को आहूत किया गया. राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर पुनर्विचार कर पुनः पारित करने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा विशेष सत्र में पेश किया गया. मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के आधार पर ये सभी 10 विधेयक विधान सभा में पुनर्पारित किए गए. इनमें से 2 विधेयक 2020 में व 2 अन्य 2023 में विधान सभा द्वारा मूलतः पारित किए गए थे. शेष 6 विधेयक 2022 में विधान सभा द्वारा पारित किए गए थे.** मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए इन विधेयकों को रोक रखा था.

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सदन में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के तहत् पुनः पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह अपनी मंजूरी नहीं रोक सकते.

निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय द्वारा रद्द

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया कानून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवम्बर, 2023 को रद्द कर दिया है.

निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों को 75 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाला विधेयक हरियाणा विधान सभा ने 2 मार्च, 2021 को पारित किया था, जिसे उसी वर्ष 2 नवम्बर को श्रम विभाग ने अधिसूचित कर दिया था. राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इस Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इन विभिन्न चुनौतियों पर सुनवाई के दौरान 3 फरवरी, 2022 को हाई कोर्ट ने इसके लागू होने पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि हटा दिया, किन्तु साथ ही सभी पक्षों की सुनवाई कर 4 सप्ताह में निर्णय सुनाने को उच्च न्यायालय को कहा. विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात् उपर्युक्त कानून को रद्द करने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवम्बर, 2023 को सुनाया है. उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की घोषणा राज्य सरकार ने की है.

आरक्षण के लिए लाए गए कानून के विरुद्ध दायर याचिकाओं में उद्योग जगत् के संगठनों ने यह आवाज उठाई थी कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से उद्योगों का विस्थापन हो सकता है. साथ ही इससे वास्तविक कौशलयुक्त युवाओं के अधिकारों का हनन होगा. याचिकाओं में कहा गया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियाँ पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल पर आधारित होती हैं. इस कानून को उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया था, जो शिक्षा के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी की योग्यता रखते हैं. योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी देना रोजगार संरचना में अराजकता पैदा करेगा और इस कारण राज्य से इंडस्ट्री स्थानांतरित भी हो सकती हैं.

STUDYPDF WALLAH

मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन : मेरा युवा भारत का शुभारम्भ

*मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के दिन हुआ इसके साथ ही 12 मार्च, 2021 से शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी औपचारिक समापन हो गया तथा अमृत काल की शुरूआत हो गई. इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया. देश भर के सभी गाँवों से 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव स्मारक शिलान्यास का शुभारम्भ उन्होंने ग 2021 से शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी औपचारिक समापन हो गया तथा अमृत काल की शुरूआत हो गई. इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया गया. देश भर के सभी गाँवों से 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई पवित्र मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका व अमृत महोत्सव स्मारक शिलान्यास का शुभारम्भ उन्होंने किया. इसके साथ-साथ देश के युवाओं के लिए एक नए मंच **मेरा युवा भारत (My Bharat)** का शुभारम्भ प्रधानमंत्री ने किया. इसके साथ ही यह आशा उन्होंने व्यक्त की कि 'मेरा भारत' संगठन 21वीं सदी में देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा.*

*कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी और देश के युवाओं के लिए **'मेरा युवा भारत' (MY BHARAT)** प्लेटफॉर्म की शुरूआत की. आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ मंत्रालयों या विभागों को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रधानमंत्री ने प्रदान किए. शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, गुजरात तथा संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान (तीसरे स्थान के लिए) हैं, जबकि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय रहे.*

इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधन के दौरान महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित आजादी के अमृत महोत्सव की 12 मार्च, 2021 को शुरूआत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर, 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव का समापन किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का 2 वर्ष लम्बा उत्सव 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के साथ सम्पन्न हो रहा है.

*लगभग 1000 दिन तक चले आजादी के अमृत महोत्सव **(AKAM)** के दौरान भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विश्व में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के उदय, चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग, जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन, एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, नए संसद भवन का उद्घाटन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना. निर्यात, कृषि उपज में नए रिकॉर्ड वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का विस्तार. अमृत भारत स्टेशन अभियान की शुरूआत, देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन नमो भारत, 65,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण, मेड इन इंडिया 5जी की शुरूआत और विस्तार और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान की शुरूआत का उल्लेख अपने इस सम्बोधन में उन्होंने किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा, कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान, देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक की यात्रा पूरी की तथा गुलामी के कई प्रतीकों को भी हटा दिया. इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष बोस की प्रतिमा, नौसेना के नए प्रतीक चिह्न, अंडमान और निकोबार के द्वीपों के प्रेरक नाम, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा, साहिबजादे की स्मृति में वीर बाल दिवस और हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के निर्णय आदि का उल्लेख भी अपने इस सम्बोधन में उन्होंने किया.*

*अमृत महोत्सव के समापन के साथ माय भारत के शुभारम्भ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कि "**माय भारत** की युवा शक्ति का उद्घोष है." उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह देश के प्रत्येक युवा को एक मंच पर लाने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा, और बताया कि युवाओं के लिए जो अलग-अलग प्रोग्राम चलते हैं, वे सभी इसमें समाहित होंगे.*

*अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही विकसित भारत के **अमृत काल** की एक नई यात्रा प्रारम्भ की घोषणा प्रधानमंत्री ने की. इसके तहत्, 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया.*

भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सम्पन्न

भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India–IFFI) गोवा में 20-28 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न हुआ. 20 नवम्बर, 2023 को इसका भव्य उद्घाटन पणजी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व देश विदेश की फिल्म जगत् की हस्तियों की उपस्थिति में आकर्षक कार्यक्रम के साथ हुआ. महोत्सव का उद्घाटन केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया. अपार शक्ति खुराना व करिश्मा तन्ना की मेजबानी में संचालित उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, श्रेया घोषाल व पंकज त्रिपाठी व सुखविंदर सिंह आदि ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए. **भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान (Special Recognition for Contribution to Bharatiya Cinema) उद्घाटन समारोह में ही दिया गया.** यह लगातार 20वाँ वर्ष था जब भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ.

भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को पुरस्कृत करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर

- पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी महोत्सव में भाग लेने के लिए देश भर से चुने गए 75 महत्वाकांक्षी युवा फिल्म निर्माताओं को महोत्सव में आमंत्रित किया गया था. 35 वर्ष से कम उम्र के इन युवाओं को निर्देशन, गायन, पटकथा लेखन व सम्पादन आदि क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कौशल के आधार पर **'75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो'** प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था. इनके लिए '48 घण्टे में एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती'

STUDYPDF WALLAH

का शुभारम्भ सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किया. **इस बार भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी महोत्सव में आमन्त्रित किया गया था** तथा इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरिज़ (OTT) पुरस्कार भी महोत्सव में शुरू किया गया, जिसके लिए राज कुमार हिरानी को ज्यूरी का अध्यक्ष बनाया गया था.

- हॉलीवुड के फिल्म निर्देशक माइकल डगलस (Michael Douglas) को **सत्यजीत रे लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार** समापन समारोह में प्रदान किया गया.
- स्टुअर्ट गैट (Stuart Gatt) द्वारा निर्देशित ब्रिटिश ड्रामा फिल्म 'कैचिंग डस्ट' (Catching Dust) इस महोत्सव की **उद्घाटन फिल्म थी**, जबकि रॉबर्ट कोलोडनी (Robert Kolodny) द्वारा निर्देशित अमरीकी फिल्म **द फेदरवेट** (The Featherweight) महोत्सव की **समापन फिल्म** थी.
- 9 दिन चले इस महोत्सव में 198 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों सहित 105 देशों की 270 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया. महोत्सव के प्रतियोगिता खण्ड में 12 विदेशी व 3 भारतीय फिल्मों सहित 15 फीचर फिल्में शामिल थीं. (तीन भारतीय फिल्में कंतारा (कन्नड़), साना व मीरबीन थी) प्रतियोगिता खण्ड के अतिरिक्त वर्ल्ड पैनारोमा, इंडियन पैनारोमा, श्रद्धांजलि (tribute) व पूर्वव्यापी (Retrospectives) आदि खण्ड महोत्सव में शामिल थे.
- महोत्सव की अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी में भारतीय फिल्म निर्माता-निर्देशक शेखर कपूर (चेयर पर्सन) के अतिरिक्त स्पेन के सिनेमेटोग्राफर जोस लुइस एल्केन (Jose Luis Alcaine), फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जेरोम पेलॉर्ड (Jerome Paillard) व कैथरीन डुसार्ट (Catherine Dussart) व आस्ट्रेलियाई निर्माता हेलन लीक (Helen Leake) शामिल थे.
- महोत्सव के पुरस्कारों का विवरण 28 नवम्बर को समापन समारोह में हुआ इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर (Golden Peacock) ईरान के अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म **एंडलेस बॉर्डर्स** (Endless Borders) के लिए दिया गया. बुल्गारियन फिल्म **ब्लागाज लेसन्स** (Blagas's Lessons) के निर्देशन के लिए निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव (Stephen Komandarev) को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार रजत मयूर के साथ दिया गया. फिल्म 'एंडलैस बॉर्डर्स' में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ईरानी अभिनेता पूरिया रहीमी सैम (Pouria Rahimi Sam) को दिया गया. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर फ्रांसीसी फिल्म **पार्टी ऑफ फूल्स** से भूमिका के लिए **फ्रांसीसी अभिनेत्री मिलेनी थिएरी** (Melanie Thierry) को दिया गया. ज्यूरी का विशेष पुरस्कार (रजत मयूर) भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक रिषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कंतारा (Kantara) के लिए दिया गया.
- **शान्ति, अहिंसा व सहिष्णुता को निरूपित करने वाली उत्कृष्ट फिल्म के लिए पेरिस स्थित इंटरनेशनल काउन्सिल फॉर फिल्म टेलीविजन एण्ड ऑडियो विजुअल कम्यूनिकेशन (ICFT) व यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया ICFT-UNESCO Gandhi Medal** एंथनी चेन (Anthony Chen) द्वारा निर्देशित ब्रिटेन, फ्रांस व ग्रीस की संयुक्त फिल्म **ड्रिफ्ट** (Drift) के लिए प्रदान किया गया.
- **किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार** (Award for the Best Debut Film of a Director) सीरिया के निर्देशक रेगर आजाद काया (Reger Azad Kaya) को फिल्म **व्हैन द सीडलिंग्स ग्रो** के लिए दिया गया.
- इस महोत्सव में इस वर्ष पहली बार ही शुरू किया गया सर्वश्रेष्ठ वेब सीरिज (OTT) का पुरस्कार दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित पंचायत सीज़न 2 के लिए दिया गया.

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरूआत 1952 में हुई थी तथा ऐसा पहला महोत्सव मुम्बई में आयोजित किया गया था. इसके पश्चात् चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता व तिरुवनंतपुरम् आदि शहरों में आयोजन के पश्चात् 2004 में इसका आयोजन गोवा में हुआ. तब से गोवा में ही यह प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा है तथा इसे ही इस महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल बना दिया गया है.

भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

(20–28 नवम्बर, 2023, गोवा)

महोत्सव की उद्घाटन फिल्म–कैचिंग डस्ट (Catching Dust) **निर्देशक**–स्टुअर्ट गैट (Stuart Gatt)
महोत्सव की समापन फिल्म–द फेदरवेट (The Featherweight) **निर्देशक**–रॉबर्ट कोलोडनी
अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष–भारतीय फिल्म निर्माता-निर्देशक शेखर कपूर
फिल्म-पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी–स्वर्ण/रजत मयूर

महोत्सव के पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ फिल्म (स्वर्ण मयूर)–ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स–(Endless Borders)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (रजत मयूर)–बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव (फिल्म–ब्लागाज लेसन्स के लिए)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (रजत मयूर)–ईरानी अभिनेता पूरिया रहीमी सैम (Pouria Rahimi Sam), **एंडलैस बॉर्डर्स** में भूमिका के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (रजत मयूर)–फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलैनी थिएरी (Melanie Thierry) फिल्म **पार्टी ऑफ फूल्स** में भूमिका के लिए
ज्यूरी का विशेष पुरस्कार–भारतीय निर्माता निर्देशक रिषभ शेट्टी (कन्नड़ फिल्म **कंतारा** के लिए)
किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार (Best Debut Film of a Director)–सीरियाई निर्देशक रेगर आजाद काया (**व्हैन द सीडलिंग्स ग्रो** के लिए)
ICFT–UNESCO गांधी पदक–एंथनी चेन, फिल्म ड्रिफ्ट (Drift) के लिए
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरिज (OTT)–दीपक कुमार मिश्रा (पंचायत सीज़न 2 के लिए)
सिनेमा में जीवनपर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार–हॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक माइकल डगलस
भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान–माधुरी दीक्षित

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान

(PM–JANMAN)

*विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups–PVTGs), की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान** (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan–PM JANMAN) की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखण्ड में खूँटी में एक कार्यक्रम में की थी. (इसका उल्लेख 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी किया था).*

कुल ₹ 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 29 नवम्बर की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है. इसमें केन्द्र व राज्यों का अंश क्रमशः ₹ 15,336 करोड़ व ₹ 8,768 करोड़ होगा. 9 विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से पक्के मकानों, सम्पर्क मार्गों, नल जल आपूर्ति, छात्रावासों के निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल के प्रावधान, आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, सड़कों में सौर प्रकाश व्यवस्था व मोबाइल टावरों की स्थापना जैसे कार्य इस अभियान के तहत् सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा पूरे किए जाएंगे.

●●●

STUDYPDF WALLAH

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

- ब्रिटेन मंत्रिमण्डल में फेरबदल : भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन मंत्रिमण्डल से बाहर पूर्व प्रधानमंत्री डेविड केमरन अब विदेश मंत्री बने
- पाकिस्तान व ईरान से अफगान शरणार्थियों का निष्कासन : शरणार्थी दयनीय स्थिति में
- भारत-अमरीका के बीच मंत्रिस्तरीय 2 + 2 वार्ता नई दिल्ली में सम्पन्न
- अमरीका के पश्चात् आस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
- अफगानिस्तान ने भारत स्थित अपना दूतावास स्थायी रूप से बन्द किया : दूतावास सम्बन्धी सभी परिसम्पत्तियाँ भारत सरकार को सौंपी
- सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की पराजय के पश्चात् नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैण्ड के नए प्रधानमंत्री
- दक्षिण पंथी जेवियर मिलेई अर्जेन्टीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित
- भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा
- मालदीव से भारतीय सेनाएं हटाने का वहाँ की नई सरकार का भारत से अनुरोध
- बंधकों व कैदियों की रिहाई एवं आदान-प्रदान हेतु इजराइल-हमास के बीच अस्थायी युत्र विराम

ब्रिटेन मंत्रिमण्डल में फेरबदल : भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन मंत्रिमण्डल से बाहर पूर्व प्रधानमंत्री डेविड केमरन अब विदेश मंत्री बने

ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में व्यापक फेरबदल 13 नवम्बर, 2023 को किया है तथा पूर्व वर्षों में (2010-2016 के दौरान) प्रधानमंत्री तथा 2005-2016 के दौरान कंजरवेटिंग पार्टी के अध्यक्ष रहे डेविड केमरन (David Cameron) को अब नया विदेश सचिव (Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs) विदेश मंत्री उन्होंने बनाया है. ब्रेक्जिट मामले में एक जनमत संग्रह में पराजय के पश्चात् केमरन ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र 2016 में दिया था. हाल ही में फिलीस्तीन के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन को गलत तरीके से रोकने के आरोप अपने एक लेख में पुलिस पर लगाने के कारण विवादित हुई भारतीय मूल की सुएला **ब्रेवर मैन** (Suella Braverman), जो गृह मंत्री (गृह सचिव) के रूप में सितम्बर 2022 से कार्यरत् थीं, को उनके इस पद से हटाया विदेश मंत्री रहे जेम्स क्लेवरली (James Cleverly) को गृह मंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री ने सौंपा है. सुएला के इस लेख की विपक्ष ने ही नहीं, उनकी अपनी ही पार्टी के कई सांसदों ने आलोचना की थी.

डेविड केमरन : ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री

सुएला ब्रेवरमैन : बर्खास्त गृह मंत्री

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने विदेश मंत्री को ऐसे समय में बदला है, जब उनकी वार्ता 5 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर पहुँचे भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ 14 नवम्बर को होनी थी. विदेश मंत्री बदले जाने के कारण भारतीय विदेश मंत्री की वार्ता नए विदेश मंत्री डेविड केमरन के साथ 14 नवम्बर को हुई. विदेश मंत्री व गृह मंत्री के पदों पर परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ अच्छे परिवर्तन भी ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवम्बर को किए हैं.

नए नियुक्त किए गए विदेश मंत्री डेविड केमरन 5 वर्षों तक विपक्ष के नेता व 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, किन्तु विगत् 7 वर्षों से सक्रिय राजनीति से बाहर हैं. इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ कॉमन्स (ब्रिटिश संसद के निचले सदस्य) के सदस्य भी नहीं हैं. संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स (उच्च सदन) का सदस्य बनाया जाएगा.

गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन की कैबिनेट से बर्खास्तगी ने प्रधानमंत्री सुनक के समक्ष अनेक समस्याएं एवं चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं. सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी में दक्षिण पंथियों की पसंदीदा मानी जाने वाली सुएला ने अनेक नीतियों के तिरस्कार एवं उपेक्षा के आरोप प्रधानमंत्री सुनक पर लगाए हैं तथा पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी भी इससे शुरू हुई है.

पाकिस्तान व ईरान से अफगान शरणार्थियों का निष्कासन : शरणार्थी दयनीय स्थिति में

पाकिस्तान सरकार ने बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए आदेश सितम्बर 2023 में जारी किए थे तथा इसके लिए 31 अक्टूबर, 2023 की समय सीमा निर्धारित की थी. यह समय सीमा निकलने के पश्चात् अप्रवासियों के निष्कासन की प्रक्रिया वहाँ शुरू कर दी गई है, जिससे सर्वाधिक प्रभावित अफगान अप्रवासी हो रहे हैं. कूटनीतिज्ञों का मानना है कि देश छोड़ने का पाकिस्तान सरकार का आदेश वहाँ अवैध रूप से रह रहे अफगानों की वजह से ही जारी किया गया था. संयुक्त राष्ट्र सूत्रों के अनुसार लगभग 17 लाख अफगान पाकिस्तान में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं. इनमें से लगभग 6 लाख लोग 2021 में वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के पश्चात् वहाँ से भाग कर पाकिस्तान जा पहुँचे थे. इनके अतिरिक्त कई अफगान वर्षों से बिना पंजीकरण के पाकिस्तान में रह रहे हैं. पाकिस्तान के साथ-साथ ईरान ने भी अवैध रूप से रह रहे अफगानों के निष्कासन का काम शुरू किया हुआ है. इससे सबसे ज्यादा मुश्किल उन अफगानों के लिए है, जो तालिबानी शासन शुरू होने पर अफगानिस्तान से भाग कर पाकिस्तान या ईरान जा पहुँचे थे. इनके लिए वापस तालिबानों की ही शरण में जाना काफी कष्टदायक है.

STUDYPDF WALLAH

यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग 4 लाख अफगानी सीमा पार कर अफगानिस्तान लौट चुके थे, जबकि ईरान भी 21 हजार से अधिक अफगानों को निष्कासित कर चुका था. प्रतिदिन हजारों की संख्या में अफगानों के सीमा पर आने से दोनों देशों के बीच की सीमाएं भी अवरुद्ध हो गई हैं. पाकिस्तान की इस कड़ाई की तालिबानी प्रशासन के साथ-साथ शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (UN High Commission for Refugees) व मानवाधिकार उच्चायोग द्वारा भी कड़ी आलोचना की गई है.

भारत-अमरीका के बीच मंत्रिस्तरीय 2 + 2 वार्ता नई दिल्ली में सम्पन्न

भारत व अमरीका के बीच 2 + 2 मंत्रि-स्तरीय वार्ता 10 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. (2 +2 मंत्रिस्तरीय वार्ता दो देशों के बीच ऐसी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता होती है, जिसमें सामान्यतः दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री ही शामिल होते हैं. भारत द्वारा ऐसी पहली द्विपक्षीय वार्ता अमरीका के साथ ही सितम्बर 2018 में शुरू की गई थी तथा चार बार ऐसी द्विपक्षीय वार्ताएं दोनों देशों के बीच इससे पूर्व क्रमशः 2018, 2019, 2020 व 2022 में सम्पन्न हो चुकी हैं. 10 नवम्बर की वार्ता इस शृंखला में पाँचवीं 2 + 2 वार्ता थी, जिसमें भाग लेने के लिए अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी बिलंकन (Antony Blinken) 10 नवम्बर को ही प्रातः नई दिल्ली पहुँचे, जबकि रक्षा मंत्री लायड आस्टिन (Lloyd Austin) एक दिन पूर्व ही नई दिल्ली पहुँच गए थे. भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की.

नई दिल्ली में अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, विदेश मंत्री एंटनी बिलंकन के साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री एस. जयशंकर

2+2 वार्ता से पूर्व दोनों देशों के विदेश मंत्रियों व रक्षा मंत्रियों की अलग से द्विपक्षीय बैठक भी हुई. दोनों देशों के बीच रक्षा सम्बन्धों एवं इनके विस्तार पर विस्तृत चर्चा इस बैठक में हुई. भारत में सैन्य बख्तरबंद वाहनों के सह उत्पादन पर सहमति वार्ता में बनी. भारत में जीई एफ-414 जैट इंजन के निर्माण के लिए जीई, एयरोस्पेस एचएएल के बीच वाणिज्यिक स्तर पर चल रही बातचीत पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया.

भारत द्वारा मंत्रिस्तरीय 2 + 2 वार्ता अमरीका के अतिरिक्त जापान, आस्ट्रेलिया व रूस के साथ सम्पन्न की जाती है. सर्वप्रथम यह सिलसिला अमरीका के साथ सितम्बर 2018 में शुरू हुआ था तथा चार बार अमरीका के साथ 2 +2 वार्ताएं क्रमशः दिसम्बर 2019, अक्टूबर 2020 व अप्रैल 2022 में सम्पन्न हो चुकी थीं. पिछली चौथी 2 + 2 वार्ता के लिए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन गए थे तथा पाँचवीं वार्ता अब 10 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई है

जापान के साथ 2 बार 2 + 2 वार्ता भारत की सम्पन्न हो चुकी है. पहली ऐसी वार्ता नवम्बर 2019 में नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी, जिसके लिए जापान के तत्कालीन विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री नई दिल्ली आए थे. जापान के साथ ऐसी दूसरी 2 + 2 वार्ता सितम्बर 2022 में टोक्यो में सम्पन्न हुई थी.

रूस व आस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2 + 2 वार्ता एक-एक बार ही सम्पन्न हुई है. आस्ट्रेलिया के साथ यह सितम्बर 2021 में नई दिल्ली में तथा रूस के साथ यह दिसम्बर 2021 में नई दिल्ली में ही सम्पन्न की गई थी.

दोनों विदेश मंत्रियों एवं रक्षा मंत्रियों की सह अध्यक्षता में बाद में सम्पन्न बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गई. चीन के अतिक्रमण तथा पाकिस्तान समर्थित आतंक-वाद का मुद्दा भी वार्ता में जहाँ उठा, वहाँ पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन-रूस युद्ध तथा कनाडा-भारत कूटनीतिक विवाद आदि पर भी विस्तार से चर्चा हुई. हिन्द प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए 'क्वाड' (QUAD) को और अधिक गतिशील बनाने का निर्णय बैठक में किया गया. दक्षिण एशिया के हालातों के साथ-साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग संवर्द्धन के लिए भी सार्थक चर्चा वार्ता में हुई.

बैठक के पश्चात् जारी संयुक्त बयान में चीन व पाकिस्तान की ओर से पैदा होने वाली समस्याओं का परोक्ष जिक्र भी किया गया है तथा इन मामलों में भारत के हितों के पक्ष में बात अमरीका द्वारा कही गई है. अल कायदा व आईएस के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की माँग इसमें की गई है. विवाद के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के सन्दर्भ में संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत व अमरीका विधि सम्मत अन्त-र्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जिसमें यूएन चार्टर के पालन के साथ-साथ दूसरे देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय सम्पन्नता का आदर हो. **इजराइल पर हुए हमले के सन्दर्भ में साझा बयान में इजरायल का ही पक्ष दोनों देशों की ओर से लिया गया है तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन व निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है. द्विपक्षीय मामलों में रणनीतिक रिश्तों को गहरा करने, रक्षा सम्बन्धों को मजबूत बनाते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उत्पादन व अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति साझा बयान में व्यक्त की गई है.** हिन्द प्रशांत क्षेत्र में स्थिति, भारत-चीन, तनाव, भारत-कनाडा सम्बन्धों में तनाव, यूक्रेन-रूस युद्ध व पश्चिम एशिया संघर्ष आदि के परिप्रेक्ष्य में भारत व अमरीका के बीच यह 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता अत्यंत महत्वपूर्ण थी तथा अमरीकी मंत्रियों की स्वदेश वापसी से पूर्व चारों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की तथा वार्ता के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया.

अमरीका के पश्चात् आस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

अमरीका के साथ 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न करने के 10 दिन पश्चात् ही आस्ट्रेलिया के साथ भी 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता भारत ने 20 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में सम्पन्न की. इसके लिए आस्ट्रेलिया के रक्षामंत्री रिचर्ड मार्लेस (Richard Marles), जो वहाँ के उपप्रधानमंत्री भी हैं, एक दिन पूर्व ही भारत-आस्ट्रेलिया फाइनल मैच के अवलोकन के लिए भारत पहुँचे हुए थे, जबकि विदेश मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong) ने 19 नवम्बर, को ही नई दिल्ली में कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया था. दोनों मेहमान मंत्रियों तथा भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सह अध्यक्षता में दोनों पक्षों की वार्ता 20 नवम्बर को सम्पन्न हुई. उससे पूर्व दोनों विदेश मंत्रियों व रक्षा मंत्रियों की अलग-अलग बैठकें भी द्विपक्षीय सम्बन्धों के सिलसिले में हुईं. **भारत व आस्ट्रेलिया के बीच मंत्रि-स्तरीय 2 + 2 वार्ता का यह दूसरा संस्करण था. दोनों देशों के बीच ऐसी पहली 2 + 2 वार्ता 11 सितम्बर, 2021 को नई दिल्ली में ही सम्पन्न हुई थी.**

2 + 2 वार्ता के अवसर पर आस्ट्रेलिया को विदेश मंत्री पेनी वोंग व रक्षामंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस. जयशंकर

STUDYPDF WALLAH

20 नवम्बर, 2023 को 2 + 2 वार्ता में रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा अंतरिक्ष तथा लोगों से लोगों के बीच सम्बन्धों सहित भारत-आस्ट्रेलिया बहुआयामी सम्बन्धों को गहरा करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया गया. द्विपक्षीय मुद्दों के अतिरिक्त पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे भी चर्चा में शामिल थे. वार्ता के दौरान आपसी आर्थिक सहयोग में हो रही वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया. चालू वर्ष 2023 को दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों के लिए असाधारण वर्ष बताते हुए **भारतीय विदेश मंत्री ने वार्ता में कहा कि दिसम्बर 2022 में दोनों देशों के बीच लागू हुए आर्थिक सहयोग एवं यापार समझौते (Economic Cooperation and Trade Agreement–ECTA) के आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं.** उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक भारतीय समुदाय तथा एक लाख से अधिक भारतीय छात्र दोनों देशों के बीच एक जीवंत पुल बनाते हैं.

आस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा, "दोनों देश इतिहास के साथ-साथ लोकतांत्रिक परम्पराओं तथा कानून के शासन और अभिव्यक्ति की आजादी को साझा करते हैं. वर्तमान में दोनों के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से दोनों के लिए चीन सबसे बड़ी चिन्ता है, हम एक महासागर साझा करते हैं और दोनों देशों के लिए एक साथ काम करने का इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं रहा." इसी परिप्रेक्ष्य में व्यापक रणनीतिक भागीदारी (Comprehensive Strategic Partnership–CSP) को और अधिक गहन बनाने में रुचि दोनों पक्षों की वार्ता में रही. यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र सिद्धान्तों के अनुरूप शांति की स्थापना पर बल दोनों पक्षों ने दिया. म्यांमार में भी स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए हिंसा की तत्काल समाप्ति का आह्वान करते हुए आसियान द्वारा शुरू की गई शांति प्रक्रिया का समर्थन दोनों पक्षों ने किया. समुद्री सुरक्षा के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए इसे दोनों पक्षों के लिए अति महत्व-पूर्ण स्वीकार किया गया. इसी सन्दर्भ में भारत में 2024 में होने वाले क्वाड (QUAD) शिखर सम्मेलन से उच्च अपेक्षाएं वार्ता में व्यक्त की गई. इजरायल पर हुए आतंकी हमले की निन्दा वार्ता में की गई.

भारत व आस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत् सहयोग की स्थिति का जायजा लेने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 14वीं विदेश मंत्रिस्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता भी 2 + 2 वार्ता के अगले दिन 21 नवम्बर को सम्पन्न की.

अफगानिस्तान ने भारत स्थित अपना दूतावास स्थायी रूप से बन्द किया : दूतावास सम्बन्धी सभी परिसम्पत्तियाँ भारत सरकार को सौंपी

अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को 23 नवम्बर, 2023 से स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी है. इससे दोनों देशों के बीच 22 वर्ष पुराने राजनयिक सम्बन्धों पर विराम लग गया है. इससे पहले 30 सितम्बर, 2023 को अफगानिस्तानी दूतावास ने घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहा है. दूतावास ने तब भारत सरकार से समर्थन की कमी, अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में विफलता और कर्मियों और संसाधनों में कमी का हवाला दिया था. दूतावास को अब स्थायी रूप से बन्द करने की घोषणा करते हुए विगत वर्षों में भारत सरकार से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दूतावास ने कहा है कि हम पिछले 22 वर्षों में अफगानिस्तान को समर्थन और सहायता देने के लिए भारत के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. दूतावास की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह फैसला 23 नवम्बर से ही मान्य है.

दूतावास ने कहा कि उसे नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने पर खेद है. अफगानी दूतावास ने कहा है कि अब उनका कोई भी राजनयिक भारत में मौजूद नहीं है. अफगानी राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया है. दूतावास भवन, बैंक अकाउंट व वाहन आदि इनमें शामिल हैं. इनके साथ ही दूतावास ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः बहाल हो सकेंगे.

सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की पराजय के पश्चात् नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैण्ड के नए प्रधानमंत्री

न्यूजीलैण्ड में अक्टूबर 2023 में सम्पन्न संसदीय चुनावों के परिणामस्वरूप नेशनल पार्टी, न्यूजीलैण्ड फर्स्ट पार्टी (New Zealand First Party) तथा एसीटी न्यूजीलैण्ड पार्टी (ACT New Zealand Party) की गठबंधन सरकार नवम्बर 2023 में वहाँ बनी है तथा नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 27 नवम्बर, 2023 को ग्रहण की है.

एक माह से भी अधिक समय तक चली वार्ताओं के पश्चात् नेशनल पार्टी, न्यूजीलैण्ड

क्रिस्टोफर लक्सन

फर्स्ट तथा एसीटी न्यूजीलैण्ड के गठबंधन सरकार के लिए सहमति बनी है. समझौते के तहत् न्यूजीलैण्ड फर्स्ट के नेता विन्स्टन पीटर्स तथा एसीटी के डेविड सीमोर आधे-आधे कार्य-काल के लिए उपप्रधानमंत्री रहेंगे.

प्रधानमंत्री पद पर क्रिस हिपकिंस (Chris Hipkins), जिन्होंने जनवरी 2023 में ही जेसिंडा एडर्न (Jacinda Ardern) के त्यागपत्र के पश्चात् कार्यभार सँभाला था, का स्थान न्यूजीलैण्ड नेशनल पार्टी के 53 वर्षीय लक्सन ने लिया है. लम्बे समय तक सत्ता में रही, जेसिंडा अर्डर्न के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को पराजय का सामना ताजा चुनाव में करना पड़ा है. नए प्रधानमंत्री लक्सन ने मध्यम वर्ग के लिए करों में कटौती के साथ-साथ अपराधों पर नियंत्रण के वायदे मतदाताओं से किए हैं.

दक्षिण पंथी जेवियर मिलेई अर्जेन्टीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित

अर्जेन्टीना में राष्ट्रपति पद के लिए नवम्बर 2023 में सम्पन्न चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई (Javier

जेवियर मिलेई : अर्जेन्टीना के नव निर्वाचित राष्ट्रपति

Milei) ने विजय प्राप्त की है. इस पद के लिए 19 नवम्बर को सम्पन्न दूसरे दौर के मतदान में 55·7 प्रतिशत मत उन्होंने प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वन्द्वी सर्जियो मासा (Sergio Massa) को 44·3 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए. इस प्रकार भारी बहुमत से विजय दर्ज कर लिबर्टी एडवांसेज पार्टी के मिलेई निर्वाचित हुए हैं. अर्जेन्टीना के डोनाल्ड ट्रम्प के रूप में कहे जाने वाले **मिलेई 10 दिसम्बर, 2023 को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.** इस पद पर एलबर्टो फर्नांडिज़ जो 2019 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सँभाले हुए हैं, का स्थान 53 वर्षीय मिलेई लेंगे. निवर्तमान राष्ट्रपति एलबर्टो फर्नांडिज़ स्वयं दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के पात्र थे, किन्तु उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा.

STUDYPDF WALLAH

अर्जेन्टीना में राष्ट्रपति पद के लिए एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि पहले दौर के 22 अक्टूबर, 2023 को सम्पन्न मतदान में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार जेवियर मिलेई तथा सर्जियो मासा थे (जिसके चलते 19 नवम्बर के दूसरे दौर के मतदान में तीन अन्य प्रत्याशियों को हटाते हुए उन दोनों के बीच ही मतदान दूसरे दौर में कराया गया था). इसमें आश्चर्य की बात यह रही कि सुनिश्चित जीत वाले उम्मीदवार माने जा रहे मिलेई को पहले दौर में 30 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए, जबकि अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मासा ने 36 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे. दूसरे दौर के मतदान में पासा पलट गया तथा 55·7 प्रतिशत मत मिलेई को मिले, जबकि सर्जियो मासा का 44·3 प्रतिशत मत ही मिले. वस्तुतः सर्जियो मासा निर्वर्तमान सरकार में अर्थव्यवस्था मंत्री थे तथा उनके इस कार्यकाल में भारी मुद्रास्फीति की शिखर अर्थव्यवस्था रही थी.

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) ने अपने देश के उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा 3-10 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न की. 6 माह पश्चात् ही भारत की इनकी यह आधिकारिक यात्रा थी. इस यात्रा से पूर्व द्विपक्षीय सम्बन्धों के सिलसिले में 3-5 अप्रैल, 2023 को भारत की यात्रा उन्होंने की थी.

नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सीमा विवाद पर चीन द्वारा भूटान के साथ चल रही वार्ता पर नजर के परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश की भारत की ताजा यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी. **आठ दिन की भारत की अपनी इस यात्रा की शुरूआत असम से उन्होंने की.** जहाँ गुवाहाटी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की. हवाई अड्डे से ही सबसे पहले सीधे कामाख्या मंदिर वह गए. जहाँ पूजा अर्चना उन्होंने की. अगले दिन काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का दौरा उन्होंने अपने साथ आए दल सहित किया.

5 नवम्बर को नई दिल्ली पहुँचे भूटान नरेश की नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अगवानी विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वयं ही की. विदेश मंत्री द्वारा स्वयं ही उनकी अगवानी करना उनकी इस यात्रा को भारत द्वारा दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवम्बर को हुई. **द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वार्ता में की गई.** दोनों नेताओं के बीच अप्रैल 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया. भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-2023) की परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भूटान की ओर से दिया गया. भूटान में 1020 मेगावाट की पुनातशांगछू-II (Punatshangchhu-II) जल विद्युत् परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया. असम में कोकराझार तथा भूटान में गेलेफू (Gelephu) के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे के लिए काम शुरू करने को सहमति बनी. भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया. तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में डारंगा (Darranga) तथा भूटान में सामद्रुप जोंगखार में इमीग्रेशन चैक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी. भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिए भी सहमति वार्ता में बनी.

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात् मुम्बई होते हुए भूटान नरेश की स्वदेश वापसी हुई. मुम्बई में अग्रणी उद्यमियों के साथ मिलने का भूटान नरेश का कार्यक्रम था.

मालदीव से भारतीय सेनाएं हटाने का वहाँ की नई सरकार का भारत से अनुरोध

मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो 30 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए थे तथा जो शुरू से ही चीन के पक्षधर तथा भारत विरोधी विचार धारा के लिए जाने जाते हैं, ने 17 नवम्बर, 2023 को शपथ ग्रहण करके 24 घण्टे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को वहाँ से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया है. उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है.

राष्ट्रपति पद पर मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भागीदारी के लिए भारत की ओर से केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू माले (मालदीव की राजधानी) गए थे. भारत मालदीव सम्बन्धों के सिलसिले में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ उनकी विस्तृत वार्ता भी वहाँ हुई. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मालदीव के नागरिकों की मेडिकल सुविधाओं के लिए भारतीय हेलीकॉप्टरों व विमानों के योगदान को मेजबान राष्ट्रपति ने स्वीकार किया. भारत के सहयोग से मालदीव में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी बैठक में की गई तथा इनके लिए भारत के योगदान की सराहना भी राष्ट्रपति द्वारा की गई.

उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के कार्यकाल में मालदीव प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए सौ से अधिक समझौते भारत के साथ किए थे. मालदीव सरकार ने एक प्रवक्ता के अनुसार नया प्रशासन उनकी समीक्षा कर रहा है.

बंधकों व कैदियों की रिहाई एवं आदान-प्रदान हेतु इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम

इजराइल व हमास के बीच 7 अक्टूबर, 2023 से चल रहे भीषण युद्ध, जिसके परिणामस्वरूप 11 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है तथा गाजा शहर अधिकांशतः खण्डहर का रूप ले चुका है, को बंद करने के सभी प्रयास विफल रहने के पश्चात् अन्ततः मिस्र व कतर की मध्यस्थता से चार दिन के लिए युद्ध विराम 24 नवम्बर, 2023 से शुरू हुआ. एक-दूसरे के बंधकों की रिहाई एवं आदान-प्रदान के उद्देश्य से शुरू किए गए युद्ध विराम में रिहाई की गति बहुत धीमी रही. 48 दिन के युद्ध के पश्चात् पहले दिन 25 बंधकों की रिहाई 24 नवम्बर को हमास द्वारा की गई, जिनमें 12 थाइलैण्ड के नागरिक थे. इजराइल द्वारा 39 फलीस्तीनी कैदियों को पहले दिन रिहा किया गया. दोनों ओर से रिहा बंधकों को मिस्र पहले ले जाया गया. युद्ध विराम के चौथे दिन हमास की ओर से 51 इजरायली व 19 अन्य राष्ट्रीयता वाले बंधकों को रिहा किया जा चुका था, जबकि 150 फलीस्तीनी कैदी इजराइल की जेलों से रिहा हो चुके थे. और अधिक बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम को दो दिन और बढ़ाया गया. युद्ध विराम की समाप्ति पर हमले जारी रखने की चेतावनी इजराइल ने दी है.

●●●

STUDYPDF WALLAH

- **2023-24** की पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि **7·6** प्रतिशत : सीएसओ के अनंतिम आँकड़े
- पीएम किसान योजना की **15**वीं किश्त डीबीटी के जरिए पात्र किसानों के बैंक खाते में जारी
- रबी मौसम **2023-24** के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण
- भारत-बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखाउरा रेल लिंक सहित तीन परियोजनाओं का उद्घाटन
- केन्द्रीय वित्त मंत्री के अनुसार **2027** तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी
- एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट **(2024)** में : आय में वृद्धि के साथ-साथ असमानताओं में वृद्धि का चित्रण
- स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स ने **2023-24** में भारत में वृद्धि का पूर्वानुमान **6·0** प्रतिशत से बढ़ाकर **6·4** प्रतिशत किया
- भारत का **42**वाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में सम्पन्न
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् **81·35** करोड़ लाभार्थियों को **5** वर्ष तक निःशुल्क अनाज : मंत्रिमण्डल का निर्णय
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 7·6 प्रतिशत : सीएसओ के अनंतिम आँकड़े

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (8 जुलाई-सितम्बर 2023) के सकल घरेलू उत्पाद सम्बन्धी अनंतिम आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा 30 नवम्बर, 2023 को जारी किए गए. इन आँकड़ों के अनुसार **2023-24 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि 7·6 प्रतिशत प्राप्त की गई है,** जबकि पूर्व वर्ष समान अवधि में यह वृद्धि 6·2 प्रतिशत थी. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तिमाही (जुलाई-सितम्बर **2023**) के लिए **6·5** प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया था. इस प्रकार **2023-24** Q_2 में प्राप्त की गई वृद्धि आरबीआई के पूर्वानुमान से अधिक रही है. एनएसओ के आँकड़ों के अनुसार **2023-24** की पहली तिमाही Q_1 में जीडीपी वृद्धि **7·8** प्रतिशत थी. इससे 2023-24 की पहली छमाही H_1 में वृद्धि 7·7 प्रतिशत रही है.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा 30 नवम्बर, 2023 को जारी किए गए.

तुलना एक दृष्टि में–

GVA

- 2023-24 की दूसरी तिमाही Q_2 (जुलाई-सितम्बर 2023) में जीवीए में वृद्धि 7·4 प्रतिशत रही है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि (जुलाई-सितम्बर 2022) में 5·4 प्रतिशत थी.
- 2023-24 की पहली छमाही H_1 (अप्रैल-सितम्बर) में जीवीए में वृद्धि 7·6 प्रतिशत रही है, जो पूर्व वर्ष 2022-23 H_1 में 8·6 प्रतिशत थी.

GDP

- 2023-24 की दूसरी तिमाही (Q_2) में जीडीपी में वृद्धि 7·6 प्रतिशत रही है, जो 2022-23 (Q_2) में 6·2 प्रतिशत थी.
- 2023-24 की पहली छमाही (H_1) (अप्रैल-सितम्बर 2023) में जीडीपी में वृद्धि 7·7 प्रतिशत रही है, जो पूर्व वर्ष 2022-23 (H_1) (अप्रैल-सितम्बर 2022) में 9·5 प्रतिशत थी.

अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि (2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर)

(प्रतिशत में)

		2022-23			2023-24		
	उत्पादक क्षेत्र	Q_1 (अप्रैल-जून)	Q_2 (जुलाई-सितम्बर)	H_1 (अप्रैल-सितम्बर)	Q_1 (अप्रैल-जून)	Q_2 (जुलाई-सितम्बर)	H_1 (अप्रैल-सितम्बर)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी (Agriculture, Forestry and Fishing)	2·4	**2·5**	2·4	3·5	1·2	2·4
2.	खनन व उत्खनन (Mining and Quarrying)	0·5	–0·1	5·1	5·8	**10·0**	**7·6**
3.	विनिर्माणी (Manufacturing)	6·1	–3·8	0·9	4·7	**13·9**	**9·3**
4.	विद्युत्, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं (Electricity, Gas, Water Supply and Other Utility Services)	14·9	**6·0**	10·3	2·9	**10·1**	**6·4**
5.	निर्माण (Construction)	16·0	5·7	10·7	7·9	**13·3**	**10·5**
6.	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं (Trade, Hotels, Transport, Communications and Services related to Broadcasting)	25·7	15·6	20·1	9·2	**4·3**	**6·6**
7.	वित्तीय, रीयल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं (Financial Real Estate and Professional Services)	8·5	7·1	7·8	12·2	**6·0**	**9·0**
8.	सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं (Public Administration, Defence and Other Services)	21·3	5·6	12·6	**7·9**	**7·6**	**7·7**
	मूल कीमतों पर जीवीए (GVA at Basic Prices)	**11·9**	**5·4**	**8·6**	**7·8**	**7·4**	**7·6**
	सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	**13·1**	**6·2**	**9·5**	**7·8**	**7·6**	**7·7**

STUDYPDF WALLAH

इन आँकड़ों के अनुसार 2023-24 की दूसरी तिमाही Q_2 (जुलाई-सितम्बर 2023) में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at constant prices) ₹ 41·74 लाख करोड़ रहा है, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि (जुलाई-सितम्बर 2022) में ₹ 38·78 लाख करोड़ था. इस प्रकार दूसरी-तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 7·6 प्रतिशत रही है, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि (जुलाई-सितम्बर 2022) में 6·2 प्रतिशत थी. प्रचलित मूल्यों पर जुलाई-सितम्बर 2023 में जीडीपी में वृद्धि 9·1 प्रतिशत दर्ज की गई है.

सीएसओ के 30 नवम्बर, 2023 के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार 2023-24 की दूसरी-तिमाही (Q_2) में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि जहाँ 7·6 प्रतिशत रही है, सकल मूल्यवर्धन (GVA) में वृद्धि 7·4 प्रतिशत रही है. इससे पूर्व पहली-तिमाही (Q_1) में जीवीए में वृद्धि 7·8 प्रतिशत रही थी. इससे 2023-24 की पहली-छमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि जहाँ 7·7 प्रतिशत अनुमानित है, जीवीए में इस छमाही में वृद्धि 7·6 प्रतिशत रही है.

सीएसओ के ताजा आँकड़ों के अनुसार 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2023) के दौरान कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन के क्षेत्र में 1·2 प्रतिशत तथा विद्युत्, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में 10·1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. खनन-उत्खनन के विनिर्माणी (Manufacturing) क्षेत्र में भी जुलाई-सितम्बर 2023 में जीवीए में वृद्धि 10·0 प्रतिशत प्राप्त की गई है. 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीवीए में सर्वोच्च 13·9 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्माणी (Manufacturing) के उपक्षेत्र में दर्ज की गई है.

अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपक्षेत्रों में 2023-24 की पहली व दूसरी तिमाही के सकल मूल्य वर्धन (GVA) के आँकड़े तथा 2023-24 की पहली छमाही के यह आँकड़े तालिका में दर्शाए गए हैं. तुलना के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 की इन अवधियों के लिए आँकड़े भी तालिका में हैं.

2023-24 की तीसरी-तिमाही Q_3, (अक्टूबर-दिसम्बर 2023) के जीडीपी के आँकड़े सीएसओ द्वारा 29 फरवरी, 2024 को जारी किए जाएंगे.

पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त डीबीटी के जरिए पात्र किसानों के बैंक खाते में जारी

किसानों को पूरक आय प्रदान करने के उद्देश्य से दिसम्बर 2018 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर, 2023 को पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी. झारखण्ड में खूंटी स्थित बिरसा महाविद्यालय परिसर में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक बटन दबाकर **8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में कुल मिलाकर ₹ 18000 करोड़ की राशि इस किश्त के तहत् प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा कर दी.** वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह इस योजना की दूसरी किस्त थी. इस वित्तीय वर्ष में इससे पूर्व, इस योजना की पहली किश्त 27 जुलाई, 2023 के पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा की गई थी. इस वित्तीय वर्ष की तीसरी अंतिम किश्त अब फरवरी मार्च 2024 में सम्भावित है, जो पीएम किसान योजना की 16वीं किश्त होगी.

दिसम्बर 2018 में शुरू की गई, इस योजना के तहत् प्रति वर्ष ₹ 2000-2000 की तीन किश्तें (कुल मिलाकर ₹ 6000-6000 की राशि किसानों के खाते में जमा की जाती है. योजना की ₹ 2000 की पहली किश्त 2018-19 में 24 फरवरी, 2019 को पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए जमा करा दी गई थी. बाद में 3-3 किश्तें 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में जमा कराने से 2022-23 के अन्त तक कुल 13 किश्तें पात्र किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी थीं तथा 2023-24 में दो किश्तों के पश्चात् लगभग ₹ 2·80 लाख करोड़ की राशि का अंतरण लगभग साढ़े ग्यारह करोड़ किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है, कृषि भूमि जिनके नाम हैं. संस्थागत भूमि धारक इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत् अथवा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान भी इस योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि के रूप में पंजीकृत पेशेवरों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता. कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है, तो ऐसे भू-स्वामी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं.

संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक, पूर्व एवं वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए अपना ई-केवाईसी कराना आवश्यक है.

रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण

रबी मौसम 2023-24 (1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024) के दौरान सभी फॉस्फेक्टिक एवं पोटाश उर्वरक (P & K Fertilizers) किसानों को आसानी से सुविधा-जनक मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए इन उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल ने 25 अक्टूबर, 2023 को प्रदान की है. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डलीय समिति की इस बैठक में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) व सल्फर (S) जैसे–विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट व पोटाश (P & K) उर्वरकों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व आधारित (Nutrient Based Sub-sidy—NBS) सब्सिडी रबी सत्र 2023-24 के लिए स्वीकृत की गई है–

पोषक तत्व	पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (₹ प्रति किग्रा)
N	47·02
P	20·82
K	2·38
S	1·89

मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) का परिव्यय ₹ 22,303 करोड़ आकलित किया गया है. उपर्युक्त रसायनिक उर्वरकों में यूरिया (N) का मूल्य सरकार निर्धारित करती है, जबकि न्यूट्रिएंट्स आधारित फर्टिलाइजर्स अर्थात् डीएपी, एनपीके व एमओपी जैसे मिश्रित उर्वरकों का मूल्य कम्पनियाँ ही तय करती हैं, हालाँकि इन पर सरकार पूरी नजर रखती है, ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे.

भारत-बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखाउरा रेल लिंक सहित तीन परियोजनाओं का उद्घाटन

भारत व बांग्लादेश के आपसी सम्बन्धों में एक नया ऐतिहासिक दौर 1 नवम्बर,

परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना

STUDYPDF WALLAH

2023 को उस समय शुरू हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया. **अगरतला (त्रिपुरा) और अखाउरा (बांग्लादेश) के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है.** इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय की 10 घण्टे की बचत होगी. भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12·24 किमी इस डबल गेज रेल लिंक में 6·78 किमी लम्बा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5·46 किमी लम्बी रेल लाइन त्रिपुरा में है, **प. त्रिपुरा में निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटर-नेशनल इमीग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा.**

दो अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवम्बर को किया गया उसमें 65 किमी लम्बी खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्ला-देश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पॉवर प्लांट के यूनिट-2 शामिल हैं. 1320 मेगावाट की इस सुपर थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पॉवर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से ही की गई है. परियोजनाओं के उद्घाटन के पश्चात् बांग्लादेश के साथ भारत के सहयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ 'सबका साथ, सबका विकास' का रुख अपनाया है तथा विकास की दिशा में बांग्लादेश का सबसे बड़ा साझीदार भारत बन गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बांग्लादेश को भारत ने 10 अरब डॉलर की सहायता दी है तथा इन 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार तीन गुना बढ़ा है. उन्होंने कहा कि हमारे बांग्लादेश के साथ सम्बन्ध नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता ने दोनों देशों की मित्रता को और मजबूत किया है.

केन्द्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी

भारतीय अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में अमरीका, चीन, जापान व जर्मनी के पश्चात् विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी की दृष्टि से है, वर्ष 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, यह विश्वास वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों के हवाले से गत नवम्बर माह में व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 2027 तक जीडीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था जापान व जर्मनी को पीछे छोड़ देगी. उस समय भारत का सकल घरेलू उत्पाद 5000 डॉलर के बिन्दु को पार कर जाएगा. वर्ष 2047 तक देश के एक विकसित अर्थव्यवस्था हो जाने की आशा भी इसके साथ ही वित्त मंत्री ने व्यक्त की.

उल्लेखनीय है कि विश्व की अन्य अनेक वित्तीय एजेंसियों ने भी अगले 4–5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने के पूर्वानुमान व्यक्त किए हैं.

स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स ने 2023-24 में भारत में वृद्धि का पूर्वानुमान 6·0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6·4 प्रतिशत किया

बदलती हुई परिस्थितियों में एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विभिन्न अन्य रेटिंग एजेंसियों ने 2023-24 में भारत में वृद्धि दर के मामले में अपने संशोधित पूर्वानुमान सितम्बर-अक्टूबर 2023 में प्रस्तुत किए हैं, इसी सन्दर्भ में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी **स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स** (S&P) ने भी अपने पूर्वानुमान में परिवर्तन नवम्बर 2023 में किया है. अमरीका स्थित एसएण्डपी ने 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि, 6·0 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान पहले व्यक्त किया था, जिसे बढ़ाकर 6·4 प्रतिशत इसने अब नवम्बर 2023 में किया है. एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू माँग ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति व कमजोर निर्यात से उत्पन्न बाधाएं दूर की हैं, जिसके चलते आर्थिक विकास के अनुमान को 6·0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6·4 प्रतिशत इसने किया है.

एक ओर 2023-24 के लिए भारत के लिए जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6·0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6·4 प्रतिशत जहाँ एसएण्डपी ने किया है, वहीं 2024-25 के लिए वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6·9 प्रतिशत से घटाकर 6·4 प्रतिशत इसने कर दिया है. एजेंसी का मानना है कि उच्च आधार प्रभाव तथा धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-

शेष पृष्ठ 162 पर

एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट (2024) : भारत में आय में वृद्धि के साथ-साथ असमानताओं में वृद्धि का चित्रण

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की वर्ष 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवम्बर 2023 में जारी हुई. Making Our Future : New Directions for Human Development in Asia and the Pacific शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया है. यूएनडीपी की यह रिपोर्ट देश में दीर्घकालिक प्रगति के साथ-साथ असमानता एवं व्यापक व्यवधानों का चित्रण करती है. इसमें बताया गया है. कि भारत उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है.

रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेज उछाल दर्ज किया गया है जब यह 442 डॉलर से बढ़कर 2389 डॉलर हो गई है. इस वृद्धि ने बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता के जाल से बाहर निकाला है तथा जनसंख्या के बड़े भाग के रहन-सहन के स्तर में सुधार किया है. इसके साथ ही देश में निर्धनता अनुपात (2·15 डॉलर प्रति दिन की आय की दृष्टि से) 2004 से 2019 के बीच 40 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत ही रह गया है. रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ आय एवं सम्पत्ति की असमानता में वृद्धि एक चुनौती बनी हुई है.

*रिपोर्ट में बताए गए एक अन्य आँकड़े के अनुसार 2015-16 व 2019–21 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता (Multidimentional Poverty) 25 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है. **यह दर्शाता है कि सन्दर्भित अवधि में न केवल आय के स्तर में, बल्कि मानव विकास के अन्य पहलुओं में भी बड़े पैमाने पर सुधार जनसंख्या के बड़े भाग में हुए हैं.***

*निर्धनता के देश के कुछ ही राज्यों में केन्द्रित होने की बात भी **'मेकिंग अवर फ्यूचर : न्यू डायरेक्शन्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक'** शीर्षक वाली नई रिपोर्ट में कही गई है. इसमें बताया गया है कि इन सफलताओं के बावजूद निर्धनता उन राज्यों में केन्द्रित है जहाँ देश की 45 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, किन्तु 62 प्रतिशत निर्धन इन्हीं राज्यों में हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन समूहों में दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है उनमें महिलाएं, अनौपचारिक श्रमिक और अन्तर्राज्यीय प्रवासी शामिल हैं.*

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास में दो-तिहाई का योगदान देगा, लेकिन आय और धन की असमानताएं बन रही हैं, विशेषतः दक्षिण एशिया में, जहाँ सबसे धनी 10 प्रतिशत लोग कुल आय के आधे पर नियंत्रण रखते हैं. इस प्रकार एशिया-प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट (2024) दीर्घकालिक प्रगति के साथ-साथ असमानता और व्यापक व्यवधान की स्थिति का चित्रण करती है, एक अशांत विकास परिदृश्य की भविष्यवाणी करती है और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिशाओं का आह्वान करती है.

STUDYPDF WALLAH

भारतीय अर्थव्यवस्था : एक दृष्टि में

INDIAN ECONOMY : AT A GLANCE

[30 नवम्बर, 2023 तक यथा संशोधित]

क्षेत्रफल

देश का कुल क्षेत्रफल	3287263 वर्ग किमी
विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत	2·42 प्रतिशत (सातवाँ स्थान)
समुद्र तट की कुल लम्बाई	7517 किमी
अनन्य आर्थिक क्षेत्र	2·02 मिलियन वर्ग किमी
कॉन्टीनेन्टल शेल्फ क्षेत्र	0·53 मिलियन वर्ग किमी
कुल वन एवं वृक्षादित क्षेत्रफल (2021)	809537 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24·62%)
कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल (2021)	713789 वर्ग किमी (21·71%)
कृषि के अन्तर्गत भूमि (2019-20)	179·993 मिलियन हेक्टेयर
जोती गई भूमि (2019-20)	153·672 मिलियन हेक्टेयर
निवल बोया गया क्षेत्रफल (2019-20)	139·902 मिलियन हेक्टेयर
फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल (2019-20)	211·359 मिलियन हेक्टेयर
खाद्यान्नी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (2021-22)	130·5 मिलियन हेक्टेयर
सिंचित क्षेत्र (निवल) (2019-20)	75·456 (मि. हे.) (54·5%)
सकल सिंचित क्षेत्र (2019-20)	112·229 (मि. हे.) (53·1%)
वर्षाधीन क्षेत्रफल (2019-20)	45·5%
फसल सघनता (2019-20)	151·5%
फसलों में खाद्यान्न फसलों की हिस्सेदारी	
1950-51	76·7%
2021-22	61·74%
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य	गोवा
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य	राजस्थान
सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य	उत्तर प्रदेश (8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है– उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार)
प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता (2022-23)	0·131 हेक्टेयर
भूजोत का औसत आकार (2015-16)	1·08 हेक्टेयर

आर्थिक संकेतक

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (जुलाई 2023 के लिए अनंतिम) (आधार : 2011-12 = 100)	142·0
खनन क्षेत्र के लिए सूचकांक	111·9
विनिर्माण क्षेत्र के लिए सूचकांक	141·2
विद्युत क्षेत्र के लिए सूचकांक	204·0
(सभी सूचकांक जुलाई 2023 के लिए तथा अनंतिम हैं)	
GVA में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2022-23 I PE)	28·2%
नवरत्न कम्पनियों की संख्या (सितम्बर 2023 की स्थिति)	14
महारत्न कम्पनियों की संख्या (सितम्बर 2023 की स्थिति)	13
लघु (मिनी रत्न) रत्न कम्पनियों की संख्या संवर्ग-I	60
लघु (मिनी रत्न) रत्न कम्पनियों की संख्या संवर्ग-II	11
सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम सरकारी इक्विटी	51%
MSME क्षेत्र का योगदान	
जीडीपी (2021-22) में	29·2%
कुल निर्यातों (2021-22) में	43·6%
MSME क्षेत्र में रोजगार	123·6 मिलियन
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या	02
अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखे गए उद्योगों की संख्या	04

भारत की राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित प्रमुख आँकड़े एक दृष्टि में

मद	2021-22 (28 फरवरी, 2023 के पहले संशोधित अनुमान)	2022-23 (31 मई, 2023 के अनंतिम अनुमान)
सकल घरेलू उत्पाद (GDP)		
2011-12 के स्थिर मूल्यों पर	₹ 149·26 लाख करोड़ (9·1%)	₹ 160·06 लाख करोड़ (7·2%)
चालू मूल्यों पर	₹ 234·71 लाख करोड़ (18·4%)	₹ 272·41 लाख करोड़ (16·1%)
राष्ट्रीय आय		
2011-12 के स्थिर मूल्यों पर	₹ 126·71 लाख करोड़ (8·6%)	₹ 136·04 लाख करोड़ (7·4%)
चालू मूल्यों पर	₹ 203·27 लाख करोड़ (18·0%)	₹ 238·24 लाख करोड़ (17·2%)
प्रति व्यक्ति आय		
2011-12 के स्थिर मूल्यों पर	₹ 92,583 (7·6%)	₹ 98,374 (6·3%)
चालू मूल्यों पर	₹ 1,48,524 (16·9%)	₹ 1,72,276 (16·0%)

नोट : कोष्ठक में दिए आँकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं.

एनएसओ के अनंतिम आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि जहाँ 7·2 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) अनुमानित की गई है. वहीं इस वित्तीय वर्ष में ***मूल कीमतों पर जीवीए*** *(Gross Value Added at Basic Prices—GVA at Basic Prices) में वृद्धि 7·0 प्रतिशत अनुमानित की गई है.*

अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि

(2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर)

(प्रतिशत)

		(अप्रैल-जून)	
		2022-23	2023-24
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी (Agriculture, Forestry and Fishing)	2·4	3·5
2.	खनन व उत्खनन (Mining and Quarrying)	9·5	5·8
3.	विनिर्माणी (Manufacturing)	6·1	4·7
4.	विद्युत्, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएँ (Electricity, Gas, Water Supply and Other Utility Services)	14·9	2·9
5.	निर्माण (Construction)	16·0	7·9
6.	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं (Trade, Hotels, Transport, Communication and Services Related to Broadcasting)	25·7	9·2
7.	वित्तीय, रीयल एस्टेट, एवं व्यावसायिक सेवाएं (Financial, Real Estate and Professional Services)	8·5	12·2
8.	सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं (Public Administration, Defence and Other Services)	21·3	7·9
	मूल कीमतों पर जीवीए (GVA at Basic Prices)	**11·9**	**7·8**

STUDYPDF WALLAH

कृषि उत्पादन का सूचकांक (2022-23) (आधार : 2007-08 = 100)	163·7
GVA में कृषि क्षेत्र का अंश प्रचलित मूल्यों पर (2022-23 I PE)	18·4%
भारत की मुख्य खाद्य फसल	चावल
गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान	द्वितीय
सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य (2022-23)	उत्तर प्रदेश
सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य (2022-23)	पश्चिम बंगाल
सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य (2022-23)	मध्य प्रदेश
सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला राज्य (2022-23)	कर्नाटक
सर्वाधिक तिलहन (सभी तिलहन) उत्पादन करने वाला राज्य (2022-23)	राजस्थान

मुख्य उत्पादन

खाद्यान्न उत्पादन (2020-21)	308·65 मिलियन टन
खाद्यान्न उत्पादन (2021-22)	315·62 मिलियन टन
खाद्यान्न उत्पादन (2022-23)	329·69 मिलियन टन
बागवानी फसलों का उत्पादन (2021-22)	347·18 मिलियन टन
बागवानी फसलों का उत्पादन (2022-23) (IIAE)	351·92 मिलियन टन
कूड आयरन (2021)	118·1 मिलियन टन
कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान (2021)	दूसरा
स्पॉंज आयरन के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान (2021)	पहला
इस्पात उपभोग में विश्व में भारत का स्थान (2019)	दूसरा
कोयला (2021-22)	777·3 मिलियन टन
लिग्नाइट (2022-23)	47·4 मिलियन टन
सीमेन्ट (2020-21)	329 मिलियन टन
चीनी (2021-22)	394·0 लाख टन
वस्त्र उत्पादन	60·453 बिलियन वर्ग मीटर
रासायनिक उर्वरक (2021-22) (अप्रैल-फरवरी) Estimated	
(i) यूरिया	22·87 मिलियन टन
(ii) डी.ए.पी.	3·86 मिलियन टन
(iii) मिश्रित (डी.ए.पी. से इतर)	7·88 मिलियन टन
(iv) एस.एस.पी.	4·9 मिलियन टन
कच्चा तेल (2021-22)	29·69 मिलियन टन
प्राकृतिक गैस (2021-22)	34·45 मिलियन घन मीटर
तेल परिशोधन क्षमता (1 अप्रैल, 2018)	251·9 मिलियन टन (4·62 मिलियन बैरल प्रतिदिन)
2021-22	241·773 मिलियन टन
कुल तेल परिशोधन (2021-22)	241·773 मिलियन टन

- **महारत्न कम्पनियाँ (अक्टूबर 2023)** : 13 (BHEL, CIL, GAIL, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, PGCIL, SAIL, BPCL, PFC, REC, OIL)
  सार्वजनिक क्षेत्रक की ऐसी कम्पनियों को महारत्न कम्पनी का दर्जा दिया जाता है जिसके अभिलक्षण निम्नलिखित हों–
  - यह नवरत्न दर्जा प्राप्त कम्पनी हो.
  - यह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो.
  - विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार ₹ 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो.
  - विगत 3 वर्षों में इसका औसत रेट वर्थ ₹ 15,000 करोड़ या इससे अधिक हो.
  - विगत 3 वर्षों में इसका कर पश्च औसत लाभ ₹ 500 करोड़ अधिक रहा हो.
  - वैश्विक पहुँच हो.
- **नवरत्न कम्पनियाँ (नवम्बर 2023 तक संशोधित)** : 16 नवरत्न कम्पनियाँ (NALCO, MTNL, BEL, SCI, HAL, RINL, NMDC, NLL, NBCCL, EIL, CONCOR, RVNL, ONGC VIDESH LTD. RASHTRIYA CHEMICAL & FERTILISER, IRCON, RITEAS Ltd.)
  सार्वजनिक क्षेत्रक की ऐसी कम्पनी को नवरत्न कम्पनी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अभिलक्षण मौजूद हों–
  - इसे मिनी रत्न कम्पनी-I एवं सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की अनुसूची A का दर्जा प्राप्त हो.
  - विगत 5 वर्षों में कम-से-कम 3 वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन में 'उत्कृष्ट' अथवा 'अति उत्तम' रेटिंग मिली हो.
  - निम्नलिखित 6 प्राचलों के आधार पर विकसित कम्पोजिट स्कोर 60 या अधिक प्राप्त किया हो.
  (i) नेटवर्थ से निवल लाभ अनुपात.
  (ii) उत्पादन/सेवा की कुल लागत से मानव शक्ति लागत अनुपात.
  (iii) नियोजित पूँजी से घिसाई व्यय, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ अनुपात.
  (iv) टर्न ओवार से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ.
  (v) प्रति शेयर आय.
  (vi) अन्तर-क्षेत्रक उपलब्ध.
- **मिनी रत्न कम्पनियाँ (सितम्बर 2023)**—I : 60
  सार्वजनिक क्षेत्रक की ऐसी कम्पनियाँ जिन्होंने विगत 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो तथा नेटवर्थ धनात्मक रही हो.
- **मिनी रत्न कम्पनियाँ (मार्च 2023)**—II : 11
- **भारत के प्रमुख उद्योग** (Core Industries)–कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, तेल परिशोधन उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, विद्युत्. (कुल 8)
- **आर्थिक अधोरचना क्षेत्रक**–परिवहन (रेलवे, सड़कें एवं राजमार्ग, हवाई अड्डे, बन्दरगाह) दूर संचार, सिंचाई (बाँध नहरें), विद्युत् (उत्पादन, पारेषण, वितरण) कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा.
- **सामाजिक अधोरचना क्षेत्रक**–शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वहनीय आवास.

परिवहन

रेलवे मार्ग की लम्बाई (मार्च 2022 की स्थिति)	68043 किमी
रेलवे विद्युतीकृत मार्ग की लम्बाई (31 मार्च, 2022)	50394 किमी (कुल का 74·06%)
एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी बड़ी रेल प्रणाली	भारतीय रेल
फ्रेट लोडिंग (2021-22)	1418 मि. टन
फ्रेट लोडिंग (2020-21)	1233·2 मिलियन
फ्रेट लोडिंग (2019-20)	1212 मि. टन
रेल यात्रियों की संख्या (2021-22)	3519 मिलियन
रेलवे परिचालन अनुपात	
2023-24 (ब.अ.)	98·45%
2022-23 (स.अ.)	98·22%
2021-22	107·39%
2020-21	96·96%
सड़कों की कुल लम्बाई (31 मार्च, 2020)	63·73 लाख किमी
राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषित लम्बाई (30 नवम्बर, 2022)	1,44,634 किमी
राज्य राजमार्ग की लम्बाई (31 मार्च, 2020)	1,86,908 किमी
अन्य सड़कों की लम्बाई	59,02,539 किमी
राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई (सड़कों की कुल लम्बाई के प्रतिशत रूप में)	2·19%
कुल सड़क यातायात का राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा ढोया गया यातायात	40%
सड़क परिवहन द्वारा ढोया जाने वाला माल यातायात	65%
सड़क परिवहन द्वारा ढोया जाने वाला यात्री यातायात	80%
बड़े बन्दरगाहों की कुल संख्या	13
विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी	चाइना मोबाइल
भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता (मिलियन)	761·29

STUDYPDF WALLAH

केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम : एक दृष्टि में

योजना/कार्यक्रम	प्रारम्भ तिथि/ कार्यान्वयन अवधि	उद्देश्य/फोकस
जिज्ञासा	6 जुलाई, 2017	विद्यार्थी-वैज्ञानिक सम्पर्क कार्यक्रम
स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत	22 अगस्त, 2017	केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य प्रोन्नयन
सौभाग्य' योजना	25 सितम्बर, 2017	प्रधानमंत्री-सहज बिजली हर घर योजना व (SAUBHAGY) का शुभारम्भ
गरीबी भारत छोड़ो अभियान	11 अक्टूबर, 2017	गरीबी भारत छोड़ो अभियान
सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना	13 अक्टूबर, 2017	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा योजना का लाभ पहुँचाना
जीरो हंगर कार्यक्रम	16 अक्टूबर, 2017	गोरखपुर (उ.प्र.), थाणे (महाराष्ट्र) तथा कोरापुट (ओडिशा) में सन् 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना
भारतमाला परियोजना	24 अक्टूबर, 2017	स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूरब पश्चिम : उत्तर दक्षिण गलियारा से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास
'एक धरोहर गोद लो' योजना	25 अक्टूबर, 2017	कार्पोरेट क्षेत्र की कम्पनियों को देश की किसी एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करने की योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार (RAFTAR)	1 नवम्बर, 2017	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अब 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक रेम्यूनरेटिव एप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सेक्टर रीजुवेनेशन (रफ्तार) के रूप में चलेगी
दीनदयाल स्पर्श योजना (SPARSH)	3 नवम्बर, 2017	छात्र-छात्राओं में डाक टिकटों के संग्रह की रुचि बढ़ाए जाने से सम्बन्धित छात्रवृत्ति योजना
भारतनेट (चरण-II) योजना	13 नवम्बर, 2017	2019 तक देश की सभी पंचायतों तक उच्चगति ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन की सुविधा
कुसुम-किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान		2022 तक देश में 3 करोड़ पम्पिंग सैटों को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाए जाने की योजना
ऑपरेशन ग्रीन	बजट 2018-19	टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों से उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत् इसे सभी फलों एवं सभी सब्जियों के लिए विस्तारित किया गया.
गोबरधन योजना	बजट 2018-19	कम्पोस्ट खाद, गोबर गैस, बनाए जाने की योजना
नभ (NABH) निर्माण	बजट 2018-19	New Generation Airports for Bharat—NABH निर्माण योजनान्तर्गत नए आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण
आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	25 सितम्बर, 2018	10 करोड़ परिवारों को ₹ 5 लाख तक की तृतीयक स्वास्थ्य/चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना
राइज़ योजना	बजट 2018-19	Revitalising Infrastructure and System in Education—RISE के तहत् शिक्षा प्रणाली की अधोरचना
प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम	बजट 2018-19	आई.आई.टी./एन.आई.टी. से उत्तीर्ण बी.टेक. छात्रों को फेलोशिप सह-पी-एच.डी. कार्यक्रम
वन धन योजना	14 अप्रैल, 2018	अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वनोत्पादों के मूल्य वृद्धिकरण की योजना
सेवा भोज योजना	1 जून, 2018	चैरिटी संस्थाओं–मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि द्वारा कराए जाने वाले नि:शुल्क भोजन की सामग्री के क्रय पर CGST तथा IGST की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति
समग्र शिक्षा अभियान	1 अप्रैल, 2018	पहले से संचालित सर्वशिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिलाते हुए समग्र शिक्षा अभियान
पीएम-आशा (PM-AASHA)	12 सितम्बर, 2018	कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
पीएम-किसान (PM-KISAN)	1 दिसम्बर, 2018	2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों के खाते में ₹ 2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष हस्तान्तरण
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना	1 फरवरी, 2019	₹ 15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रकों को ₹ 100 के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ₹ 3,000 मासिक की पेंशन जीवनपर्यन्त
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	30 मई, 2019 संघीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित (12 सितम्बर, 2019 को रांची से शुभारम्भ)	सीमान्त एवं लघु कृषकों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर ₹ 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना	30 मई, 2019 संघीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित (12 सितम्बर, 2019 को रांची से शुभारम्भ)	खुदरा कारोबारियों, दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर ₹ 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना

STUDYPDF WALLAH

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III	10 जुलाई, 2019 को संघीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित	₹ 80,250 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र की 125000 किमी सड़कों का सुदृढ़ीकरण
अटल भूजल योजना	25 दिसम्बर, 2019	गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 8350 ग्राम पंचायतों (78 जिलों) में भूमिगत जल संवर्द्धन की योजना
सागर मित्र योजना	1 फरवरी, 2020	मत्स्य उत्पादन 2022-23 तक 200 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3477 सागर मित्र तथा 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की योजना
ग्राम भण्डारागार योजना	1 फरवरी, 2020	ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भण्डारागारों का निर्माण एवं परिचालन
धान्यलक्ष्मी योजना	1 फरवरी, 2020	महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (धनलक्ष्मी) को नाबार्ड भण्डारागारों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता देगा
किसान रेल योजना	1 फरवरी, 2020	शीघ्र नाशवान वस्तुओं के परिवहन विशेष प्रशीतन कोचों से युक्त रेलगाड़ी पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने की योजना
कृषि उड़ान (UDAN) योजना	1 फरवरी, 2020	शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों को हवाई जहाजों से परिवहन करने की योजना
विवाद से विश्वास योजना	1 फरवरी, 2020	करदाताओं पर बकाया आयकर बिना दण्ड एवं ब्याज के वसूल करने की योजना
राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन	1 फरवरी, 2020	2020-21 से 2023-24 की अवधि में ₹ 1,480 करोड़ से टेक्नीकल टेक्स-टाइल्स मिशन
निर्यात ऋण विकास (NIRVIK) योजना	16 सितम्बर, 2020	निर्यातकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना
टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना	1 फरवरी, 2020	सन् 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की योजना
क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन्स पर राष्ट्रीय मिशन	1 फरवरी, 2020	₹ 8,000 करोड़ के परिव्यय से क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास हेतु राष्ट्रीय मिशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना	26 मार्च, 2020	कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने की ₹ 1·70 लाख करोड़ लागत की योजना
आत्मनिर्भर भारत अभियान	12 मई, 2020	कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लागू की गई परिस्थितियों से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जान फूँकने की योजना की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा
गरीब कल्याण रोजगार अभियान	20 जून, 2020	कोविड-9 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को 116 जिलों (6 राज्यों–उ. प्र., म. प्र., बिहार, झारखण्ड, राजस्थान तथा ओडिशा) में रोजगार प्रदान करने की योजना
पीएम एसवी निधि (PM-SVNidhi)	1 जून, 2020	स्ट्रीट वेण्डरों, रेहड़ी, पटरी वालों को कार्यशील पूँजी मुहैया कराने की योजना
सहकार मित्र योजना	12 जून, 2020	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल के अन्तर्गत युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना
प्रज्ञाता (PRAGYATA)	14 जुलाई, 2020	डिजिटल एजूकेशन की दिशा-निर्देश योजना (Plan Review Arrange Guide Yak (Talk) Assign Track Appreciate)
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	9 दिसम्बर, 2020	औपचारिक क्षेत्रक रोजगार सृजन हेतु कम्पनियों/इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप ईपीएफ में अंशदान हेतु सब्सिडी
पी-एम जय सेहत	25 दिसम्बर, 2020	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र के सभी लोगों के लिए
मिशन अभ्यास (ABHYAAS)	1 जुलाई, 2020	देश में स्नातकोत्तर/पी-एचडी स्तर के सम्भाव्य विद्यार्थियों का कौशल विकास का एक कार्यक्रम जिसे विज्ञान एवं इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान (AV) के तहत् चलाया जा रहा है.
कपिला (कलाम प्रोग्राम फॉर इण्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी लिटरेसी एण्ड अवेयरनेस)	16 अक्टूबर, 2020	बौद्धिक सम्पदा साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने की पहल
आयुष्मान सीएपीएफ योजना	23 जनवरी, 2021	7 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना की तर्ज पर ₹ 5 लाख सीमान्तर्गत चिकित्सा उपचार की सुविधा

STUDYPDF WALLAH

2021-22 में घोषित नवीन योजनाएं

जेण्डर संवाद	16 अप्रैल, 2021	दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) तथा इंस्टीट्यूट फॉर ह्वाट वर्क्स टु एडवांस वूमेन एण्ड गर्ल्स इन दी इकनॉमी (IWWAGE) तथा LEAD की एक संयुक्त पहल, जो देश में लैंगिग हस्तक्षेपों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.
सीएसआईआर पुष्पोत्पादन मिशन	4 मार्च, 2021	केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद् के 21 राज्यों/के.शा.क्षे. में कार्यरत् संस्थाओं द्वारा पुष्प खेती को बढ़ावा देने की एक योजना.
ई-रूपी (e-RUPI)	2 अगस्त, 2021	प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने की नकदी रहित तथा सम्पर्क रहित भुगतान प्रणाली की शुरुआत.
समृद्धि (SAMRIDHI)	25 अगस्त, 2021	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की "स्टार्ट अप एक्सीलरेटर्स ऑफ Meity फॉर प्रोडक्ट इन्नोवेशन डेवलेपमेन्ट एण्ड ग्रोथ योजना, जो सॉफ्टवेयर डेवलेपमेन्ट पर केन्द्रित है."
सुजलम (SUJALAM) अभियान	25 अगस्त, 2021	जलशक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया. 100 दिनों का अभियान, जो गाँवों में 10 लाख सोख्ता गढ्ढे बनाकर ठोस एवं अर्द्धठोस कचरा निस्तारण पर केन्द्रित है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3·0	24 अप्रैल, 2021	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के अन्तर्गत मई से मार्च 2022 तक राशन कार्ड धारकों को 5 किग्रा प्रति यूनिट की दर से गेहूँ/चावल का निःशुल्क वितरण (24 नवम्बर, 2021 को मार्च 2022 तक विस्तार)
सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान	8 जून, 2021	नीति आयोग तथा पीरामल फाउण्डेशन द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में सहायता देने का कार्यक्रम.
खाद्य तेल–पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन	18 अगस्त, 2021	खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में पाम की खेती को बढ़ावा देने की ₹ 11,040 करोड़ की एक योजना.
आयुष्मान भारत डिजिटिल मिशन	27 सितम्बर, 2021	आधार की तर्ज पर सभी नागरिकों को हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना.
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (पुनः प्रारम्भ) (MPLADS)	10 नवम्बर, 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि तक एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि (2021-22 से 2025-26 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फिर से प्रारम्भ की गई. इस योजना को कोविड-19 महामारी में 6 अप्रैल, 2020 को बन्द कर दिया गया था.)
डिजीसक्षम (Digisaksham)	30 सितम्बर, 2021	युवाओं में कौशल वृद्धि करके उनकी रोजगारनीयता को बढ़ाने का एक डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम.
प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2·0	1 अक्टूबर, 2021	सभी शहरों को कचरा मुक्त एवं जल सुरक्षित बनाए जाने का कार्यक्रम.
अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन 2·0	1 अक्टूबर, 2021	देश के 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100 प्रतिशत सीवेज निस्तारण.
पीएम मित्रा (PM-MITRA)	6 अक्टूबर, 2021	देश में 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने की (मेगा इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एण्ड एपेरल) योजना.
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोरचना मिशन	25 अक्टूबर, 2021	देश में स्वास्थ्य क्षेत्रक में अधोरचना का सृजन और विकास.
नवभारत साक्षरता कार्यक्रम	16 फरवरी, 2022	2022–27 की अवधि के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर केन्द्रित एक ऑनलाइन कार्यक्रम.
SMILE–सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इण्डिवीजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एण्ड एण्टरप्राइज योजना	12 फरवरी, 2022	ट्रांसजेण्डर समुदाय एवं भिखारियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजना.
SEED–स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेन्ट ऑफ डीएटीज़	16 फरवरी, 2022	डी-नोटीफाइड नोमेडिक एवं सेमी-नोमेडिक समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना.
सुजलम 2·0 अभियान	22 मार्च, 2022	जनसहभागिता से गन्दे पानी के प्रबन्धन पर केन्द्रित.
एक स्टेशन एक उत्पाद योजना	1 फरवरी, 2022 (9 दिसम्बर, 2022 को लॉन्च)	भारतीय रेल के स्टेशनों पर उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय उत्पादों के बिक्री पटल स्थापित कर स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ाने की योजना.
पर्वतमाला : राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम	1 फरवरी, 2022	दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पीपीपी मोड के अन्तर्गत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम द्वारा कनेक्टिविटी में सुधार लाना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना.
किसान ड्रोन योजना	1 फरवरी, 2022 (8 फरवरी, 2022 को लॉन्च)	कृषि फसलों का आकलन करने, भू-दस्तावेजों का डिजिटाइज़ेशन करने, कीट नाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा.
वन क्लास-वन टीवी चैनल कार्यक्रम	1 फरवरी, 2022	शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों की व्यवस्था.
राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	1 फरवरी, 2022	गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच को स्थापित करना.
प्राइम मिनिस्टर डेवलेपमेन्ट इनीशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (PM-DeviNE)	1 फरवरी, 2022	उत्तर-पूर्व परिषद् के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं का वित्त पोषण.
महत्वाकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम	1 फरवरी, 2022	देश के चयनित 112 महत्वाकांक्षी जनपदों के अभी भी अति पिछड़े विकास-खण्डों के त्वरित विकास का कार्यक्रम.
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम	1 फरवरी, 2022 (15 फरवरी, 2023 को अनुमोदित)	देश की उत्तरीय सीमा के सीमावर्ती गाँवों, जहाँ की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, में कनेक्टिविटी सुधार तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक पहल.

STUDYPDF WALLAH

केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषित योजनाएं/कार्यक्रम

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना निर्माण	1 फरवरी, 2023	एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतरप्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा.
कृषि वर्धक निधि (AAF)	1 फरवरी, 2023	ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप की स्थापना हेतु सहायतार्थ.
श्री अन्न हेतु वैश्विक केन्द्र	1 फरवरी, 2023	श्री अन्न–ज्वार, बाजरा, रागी कुट्टु, रामदाना, कगनी, कुटकी, कोदों, चीना और सामा के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा देना.
सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन	1 फरवरी, 2023	सिकिल सेल एनीमिया से प्रभावित 0–40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जाँच, उपचार और काउंसिलिंग.
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	1 फरवरी, 2023	अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय. पंचायत स्तर तथा वार्ड स्तर पर भी ऐसे ही पुस्तकालयों की स्थापना.
प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन	1 फरवरी, 2023	विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTG) का विकास.
भारत साझा पुरा लेख निधान (Bharat SHRI)	1 फरवरी, 2023	साझा पुरालेखों के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना.
कृत्रिम बुद्धिमता (AI) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र	1 फरवरी, 2023	कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमता से भारत के लिए कार्य कराएं.
हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम	1 फरवरी, 2023	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत् हरित ऋण कार्यक्रम.
प्रधानमंत्री प्रणाम (PM-PRANAM)	1 फरवरी, 2023	पृथ्वीमाता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु कार्यक्रम
मिश्टी (MISHTI)	1 फरवरी, 2023	तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैनग्रूव पहल.
अमृत धरोहर	1 फरवरी, 2023	आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि.
आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत-पत्र	1 फरवरी, 2023	मार्च 2025 तक 2 वर्षीय एककालिक लघु बचत योजना 7·5 प्रतिशत गारण्टीशुदा ब्याज के साथ.
पीएम विश्वकर्मा योजना	17 सितम्बर, 2023	बढ़ई, सुनार, लेहार, सहित 18 विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए आर्थिक उन्नयन हेतु रियायती ब्याज पर ₹ 3 लाख तक का ऋण.

विदेशी व्यापार

भारत के विदेशी व्यापार के आँकडे एक दृष्टि में (अप्रैल-सितम्बर 2023) वस्तुगत व्यापार (वस्तुओं का व्यापार) (Merchandise Trade)

(अरब डॉलर)

	अप्रैल-सितम्बर	
	2022-23	**2023-24**
निर्यात (Exports)	231·73	211·40 (– 8·77)
आयात (Imports)	– 372·56	326·98 (– 12·23)
व्यापार शेष (Trade Balance)	**– 140·83**	**– 115·58**

सेवाओं का व्यापार (Trade in Service)

(अरब डॉलर)

	अप्रैल-सितम्बर	
	2022-23	**2023-24**
निर्यात (प्राप्तियाँ)	156·07	164·89 (5·65)
आयात (भुगतान)	90·58	89·22 (– 1·5)
व्यापार शेष	**65·49**	**+ 75·67**

वस्तुओं व सेवाओं का व्यापार (Trade in Goods and Services)

(अरब डॉलर)

	अप्रैल-सितम्बर	
	2022-23	**2023-24**
निर्यात (प्राप्तियाँ)	387·80	376·29 (– 2·97)
आयात (भुगतान)	463·14	416·20 (– 10·14)
व्यापार शेष	**– 75·34**	**– 39·91**

भारत का विदेशी विनिमय भण्डार कोष (27 अक्टूबर, 2023)

(अरब अमरीकी डॉलर में)

(i) विदेशी करेंसी	517·5
(ii) स्वर्ण कोष	45·90
(iii) एसडीआर	17·91
(iv) आईएमएफ के पास अन्य रिजर्व	4·77
(v) **कुल योग**	**586·5**

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी का अन्तर्प्रवाह

2022-23	70·970 अरब डॉलर
2021-22	58·773 अरब डॉलर
2020-21	59·636 अरब डॉलर
2019-20	49·977 अरब डॉलर
2018-19	44·366 अरब डॉलर
2017-18	44·857 अरब डॉलर
2016-17	43·478 अरब डॉलर

कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह

2016-17	60·220 अरब डॉलर
2017-18	61·963 अरब डॉलर
2018-19	62·001 अरब डॉलर
2019-20	74·390 अरब डॉलर
2020-21	81·72 अरब डॉलर
2021-22	84·835 अरब डॉलर
2022-23	46·034 अरब डॉलर

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल

निवेश	2015-16	(–) 4·016 अरब डॉलर
	2016-17	7·735 अरब डॉलर
	2017-18	22·165 अरब डॉलर

STUDYPDF WALLAH

2018-19	(–) 2225 अरब डॉलर
2019-20	0·552 अरब डॉलर
2020-21	38·097 अरब डॉलर
2021-22	(–) 14·541 अरब डॉलर
2022-23	(–) 5·407 अरब डॉलर

विदेशी ऋण सम्बन्धी आँकड़े एक दृष्टि में

(जून 2023 के अन्त की स्थिति)

कुल विदेशी ऋण	629·1 अरब डॉलर
दीर्घकालिक ऋण	505·5 अरब डॉलर
कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग	80·4 प्रतिशत
अल्पकालिक ऋण	123·6 अरब डॉलर
कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग	19·6 प्रतिशत
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण	18·6 प्रतिशत
कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का भाग	7·8 प्रतिशत
मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना	
डॉलर मूल्य में	54·4 प्रतिशत
रुपए मूल्य में	30·4 प्रतिशत
एसडीआर में	5·9 प्रतिशत
येन में	5·7 प्रतिशत
यूरो में	3·0 प्रतिशत

सर्वाधिक FDI अन्तर्प्रवाह क्षेत्र (घटते क्रम में) सेवाएं (18%), कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (15·0%), दूरसंचार (6·0%) तथा ट्रेडिंग (6·0%), ऑटोमोबाइल (5·0%)

सर्वाधिक FDI की हिस्सेदारी (1) मॉरिशस (26%), (घटते क्रम में) (2) सिंगापुर (23%) (3) यू.एस.ए. (9%), (4) नीदरलैण्ड्स (7·0%), (5) जापान (6·0%), (6) यू.के. (5·0%)

सर्वाधिक FDI वाले राज्य (घटते क्रम में) महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गुजरात

मौद्रिक एवं साख नीति के उपकरण (6 अक्टूबर, 2023 को)

नकद आरक्षण अनुपात	4·50%
बैंक दर	6·75%
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) की दर	6·75%
रिवर्स रेपो दर	3·35%
रेपो दर	6·50%
सांविधिक तरलता अनुपात	18·00%
स्थायी जमा सुविधा दर	6·25%

बैंकिंग एवं बीमा (31 अक्टूबर, 2023)

* **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	
(i) भारतीय स्टेट बैंक	1
(ii) अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक	11
(BOB, PNB, Canara Bank, UBI, India Bank, IOB, UCO Bank, BOM, P&S Bank, CBI)	
* **अनुसूचित निजी बैंक**	21
* **अन्य बैंक**	
(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43
(ii) पेमेण्ट बैंक	6
(iii) स्माल फायनेन्स बैंक	12
(iv) लोकल एरिया बैंक	2
* **सहकारी बैंक** (मार्च 2022)	
(i) शहरी सहकारी बैंक (अनुसूचित)	52
(ii) शहरी सहकारी बैंक (गैर-अनुसूचित)	1462
(iii) राज्य सहकारी बैंक	34
(iv) जिला सहकारी बैंक	351
(v) प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ	102,559
(vi) राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	13
(vii) प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	603
* **विदेशों में कार्यरत् भारतीय बैंक**	
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	9
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक	5
* **भारत में कार्यरत् विदेशी बैंक**	44
भारतीय मुद्रा बाजार में शीर्ष स्थान	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
नाबार्ड की स्थापना	12 जुलाई, 1982
SEBI की स्थापना	अप्रैल 1988
PPF पर वार्षिक ब्याज (2023-24) (Q_3)	7·1%
EPF पर वार्षिक ब्याज (वर्ष 2022-23 से)	8·15%
PPF खातों में सालाना निवेश की अधिकतम सीमा (2014-15 से)	₹ 1·50 लाख

केन्द्रीय बजट 2023-24

बजट का प्रस्तुतीकरण	1 फरवरी, 2023
राजस्व घाटा	₹ 8,69,855 करोड़ (GDP का 2·9%)
राजकोषीय घाटा	₹ 17,86,816 करोड़ (GDP का 5·9%)
प्राथमिक घाटा	₹ 7,06,845 करोड़ (GDP का 2·3%)
ब्याज एवं ऋण सेवा भुगतान (सबसे बड़ी व्यय मद)	₹ 10,79,971 करोड़

वित्त आयोग

वित्त आयोग का गठन	राष्ट्रपति द्वारा (अनु. 280 के तहत्)
अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या	15
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष	एन. के. सिंह
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि	2020-21 एवं 2021–26
पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्र के विभाज्यनीय करों में से राज्यों को वितरित अंश की सिफारिश	41%
पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2021-26 की अवधि के लिए अनुशंसित राज्यों को कुल हस्तांतरण (केन्द्रीय करों में हिस्सा + अनुदान सहायता)	₹ 52,41,422 करोड़

●●●

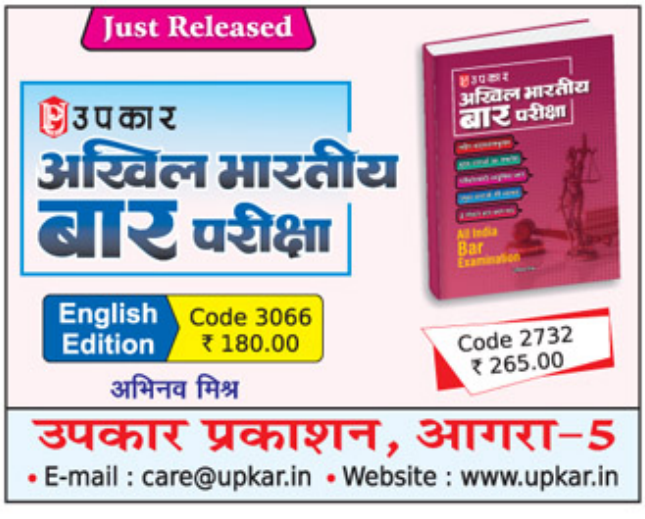

STUDYPDF WALLAH

नवीनतम सामान्य ज्ञान

शब्द संक्षेप (Abbreviation)

डब्ल्यूसीडीएम–वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट

WCDM—World Congress on Disaster Management

व्याख्या–आपदा प्रबन्धन पर शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं व अन्य विशेषज्ञों का यह वार्षिक सम्मेलन है. ऐसा छठा सम्मेलन उत्तराखण्ड में देहरादून में 28 नवम्बर-1 दिसम्बर, 2023 को सम्पन्न हुआ.

नियुक्तियाँ (Appointments)

आलोक शर्मा अब विशेष सुरक्षा दल (SPG) के नए प्रमुख

भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के श्री आलोक शर्मा विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group—SPG) के नए निदेशक नवम्बर 2023 में नियुक्त किए गए हैं. इस पद पर अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन 6 सितम्बर, 2023 को हो गया था, का स्थान उन्होंने लिया है. इस नियुक्ति से पूर्व एसपीजी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में वह कार्यरत् थे.

आलोक शर्मा

- स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना मूलतः प्रधानमंत्री (आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार के सदस्यों) की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संसद के एक अधिनियम 1988 के तहत् में की गई थी.
- पूर्व निदेशक अरुण कुमार सिन्हा 2016–23 तक 7 वर्ष तक इस ग्रुप के निदेशक रहे थे.

सर्वोच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की संस्तुति पर तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में नवम्बर 2023 में की है. इनमें न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह व न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल हैं. इस नियुक्ति से पूर्व न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे.

तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड ने 9 नवम्बर को इनके पद की शपथ दिलाई.

- **इन नियुक्तियों के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो गई है तथा न्यायाधीश का कोई पद अब वहाँ रिक्त नहीं है (नवम्बर 2023 की स्थिति) शीर्ष आदालत में अब पहली रिक्ति 25 दिसम्बर, 2023 को होगी जब न्यायमूर्ति संजय किशन कौल 25 दिसम्बर, 2023 को सेवानिवृत्त होंगे.**

प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को एक बार पुनः गुजरात स्थित पवित्र सोमनाथ मंदिर से सम्बन्धित श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 31 अक्टूबर, 2023 से चुने गए हैं. इस बार उनका यह चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ है.

पुरस्कार/सम्मान (Awards/Honours)

निकारागुआ की शेयन्निस पेलेसिऑस को मिस यूनीवर्स (2023) का खिताब

वर्ष 2023 की (72वीं) मिस यूनीवर्स प्रतियोगिता एल सेल्वाडोर (El Salvador)

मंच पर खितावी ताज पहने मिस यूनीवर्स (2023) शेयन्निस पेलेसिऑस

हीरा लाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त

नवम्बर 2020 से केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत् रहे श्री हीरा लाल सामरिया अब देश के मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner—CIC) नवम्बर 2023 में नियुक्त किए गए है. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 नवम्बर, 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई.

श्री सामरिया 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है तथा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति पाने वाले वह पहले दलित हैं.

हीरा लाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाती राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

- *मुख्य सूचना आयुक्त पद पर श्री यशवर्धन सिन्हा जो 3 अक्टूबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे, का स्थान श्री सामरिया ने लिया है. वह देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं. उनके पूर्ववर्ती श्री यशवर्धन लगभग 3 वर्ष तक इस पद पर रहे थे. 63 वर्षीय सामरिया 13 सितम्बर, 2025 तक इस पद पर रहेंगे. (सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किन्तु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है.)*
- *मुख्य सूचना आयुक्त पद पर श्री सामरिया की नियुक्ति के साथ ही 2 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी नवम्बर 2023 में की गई है. उन्हें बाद में मुख्य सूचना आयुक्त श्री सामरिया ने सीआईसी कार्यालय में ही शपथ दिलाई.*
- *केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) का गठन आरटीआई एक्ट के तहत् 2005 में हुआ था. आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल रहते हैं. नवम्बर 2023 में दो नए आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात् सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 3 (मुख्य सूचना आयुक्त सहित) हो गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर आठ सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अभी की जा सकती है.*
- *नए मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयोग हेतु सूचना आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है. लोक सभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी (कांग्रेस) के नेता व प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं.*

STUDYPDF WALLAH

में नवम्बर 2023 में सम्पन्न हुई. निकारागुआ (Nicaragua) की 23 वर्षीय शेयन्निस पेलेसिऑस (Sheynnis Palacios) ने इसका खिताब जीता. राजधानी सैन सेल्वाडोर में 18 नवम्बर को सम्पन्न फाइनल दौर में 83 अन्य देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए उन्होंने यह खिताब जीता. मिस यूनीवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की वह पहली ही महिला हैं. थाइलैण्ड की एंटोनियो पोर्सिल्ड को प्रथम उपविजेता व आस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन को द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में घोषित किया गया. वर्ष 2022 की मिस यूनीवर्स आर' बोनी गैब्रियल ने नई मिस यूनीवर्स (2023) शेन्निस पलासियोस को इस खिताब का ताज प्रतियोगिता मंच पर ही पहनाया.

इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने किया था, जो पहली 20 सुंदरियों में स्थान बनाने में सफल रहीं तथा इसके आगे नहीं बढ़ सकी. **भारत की केवल 3 सुंदरियों ने ही अब तक मिस यूनीवर्स का खिताब जीता है. इनमें सुष्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) तथा हरनाज संधू (2021) शामिल हैं.**

शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार

शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार (Indira Gandhi Award for Peace, Disarmament and Development—2022) देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि (Covid 19 Warriors) के प्रतिनिधि के रूप में चिकित्सकों के संघ **इंडियन मेडिकल एसोसिएशन**

वर्ष 2022 का पुरस्कार आईएमए व टीएनएआई के प्रतिनिधियों को प्रदान करते हुए

(IMA) व नर्सों के संघ ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है. दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस (19 नवम्बर) पर नई दिल्ली में एक समारोह में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आईएमए अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार अग्रवाल व ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) के अध्यक्ष डॉ. रॉय के जॉर्ज को यह पुरस्कार प्रदान किया. इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी समारोह में उपस्थित थीं. इस पुरस्कार के तहत् ₹ 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है.

इससे पूर्व, पिछले वर्ष, वर्ष 2021 का यह पुरस्कार शिक्षा के लिए समर्पित एनजीओ **प्रथम** को दिया गया था.

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के पश्चात् भारत सरकार के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार की शुरूआत 1986 से की गई थी. **यह अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है, जिसने समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण अथवा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो.**

वर्ष	पुरस्कृत व्यक्ति/संस्था
1986	पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन
1987	मिखाइल गोर्बाच्योव (तत्कालीन सोवियत संघ के नेता)
1988	ग्रो हार्लेम ब्रंड्टलैण्ड (नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री)
1989	यूनीसेफ
1990	सैम नुजोमा (नामीबिया के पहले राष्ट्रपति)
1991	राजीव गांधी (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, मरणोपरान्त)
1992	साबुरो ओकिता (जापानी अर्थशास्त्री)
1993	वाक्लाव हावेल (चैक गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति)
1994	ट्रेवोर हडलेस्टन (रंगभेद विरोधी नेता)
1995	ओलुसेगुन ओबसांजो (नाइजीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति)
1996	मेडिसिस सांस फ्रटियर्स (स्वयंसेवी संस्था)
1997	जिमी कार्टर (अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति)
1998	मोहम्मद यूनुस (बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक)
1999	एम. एस. स्वामीनाथन (भारत के कृषि वैज्ञानिक)
2000	मेरी रॉबिसन (आयरलैण्ड की पूर्व राष्ट्रपति)
2001	सदाको ओगाटा (जापान) (भूतपूर्व यू एन हाईकमिश्नर फॉर रिफ्यूजीस)
2002	श्रीदत्त रामफल (राष्ट्रमण्डल के द्वितीय महासचिव)
2003	कोफी अन्नान (यूएनओ के 7वें महासचिव)
2004	महाचक्री सिरिनधोर्न (थाइलैण्ड की राजकुमारी)
2005	हामिद करजई (अफगानिस्तान के राष्ट्रपति)
2006	वंगारी मथाई (कीनिया की पर्यावरणवादी)
2007	बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउण्डेशन (अमरीका की समाजसेवी संस्था)
2008	मोहमद अल बरदेई (मिस्र) (अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चौथे महासचिव)
2009	शेख हसीना (बांग्लादेश की प्रधानमंत्री)
2010	लुइस इनासियो लुला ड सिल्वा (ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति)
2011	इला भट्ट (भारत) 'सेवा' (SEWA) की संस्थापक
2012	एलन जॉनसन सरलीफ (लाइबेरिया की राष्ट्रपति)
2013	एंजेला मर्केल (जर्मनी की चांसलर)
2014	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
2015	शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) कार्यालय
2017	डॉ. मनमोहन सिंह
2018	सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट (CSE)
2019	सर डेविड एटनबरो
2021	प्रथम (कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था)
2022	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) व ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TNAI) (संयुक्त रूप से)

इंफोसिस पुरस्कार (2023)

इंफोसिस साइंस फाउंडेशन (ISF) के वर्ष 2023 के पुरस्कारों की घोषणा 15 नवम्बर, 2023 को की गई. यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों—इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर साइंस, मानविकी (Humanities), जीवन विज्ञान (Life Sciences), गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान (Physical Scinces) व सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं. वर्ष 2023 के पुरस्कार निम्नलिखित को दिए गए हैं—

इंजीनियरिंग व कम्प्यूटर साइंस के क्षेत्र का पुरस्कार—प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी, आईआईटी, कानपुर.

मानविकी (Humanities)—जान्हवी फाल्के, साइंस गैलरी, बेंगलूरू.

लाइफ साइंसेज़—प्रो. अरुण कुमार शुक्ला, आईआईटी, कानपुर.

फिजीकल साइंसेज़—मुकुंद थट्टाई, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ (बेंगलूरू).

सोशल साइंसेज़—प्रो. करुणा मंटेना (राजनीति विज्ञान), कोलम्बिया यूनीवर्सिटी (USA) तथा

गणित विज्ञान (Mathematical Sciences)—भार्गव भट्ट, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी एण्ड प्रिंसटन यूनीवर्सिटी (USA).

पुरस्कारों का वितरण बाद में किसी समारोह में किया जाएगा.

इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के यह पुरस्कार भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं. इन पुरस्कारों के तहत् शुद्ध सोने के पदक व प्रशस्ति-पत्र के साथ अब एक-एक लाख डॉलर (अथवा रुपए मूल्य में तुल्य राशि) की राशि प्रदान की जाती है.

STUDYPDF WALLAH

फ्रांस फुटबाल पत्रिका का बैलोन डि'ओर व अन्य पुरस्कार

इंटर मियामी के लियोनल मैसी बैलोन डि'ओर (2023) के विजेता

लियोनिल मैसी : रिकॉर्ड आठवीं बार बैलोन डि' ओर

*अमरीका के इंटर मियामी के लिए खेलने वाले अर्जेन्टीना के स्टार फुटबॉलर लियोनिल मैसी (Lionel Messi) वर्ष 2023 के बैलोन डि'ओर (Ballon d'Or) पुरस्कार के विजेता बने हैं. फ्रांसीसी फुटबाल पत्रिका फ्रांस फुटबाल द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रिकॉर्ड आठवीं बार उन्होंने जीता है. वर्ष 2023 का यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करने की घोषणा 'फ्रांस फुटबाल' द्वारा 31 अक्टूबर, 2023 को की गई. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अल्पसूचीबद्ध खिलाड़ियों में मैनचेस्टर सिटी के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैण्ड (नॉर्वे) व पेरिस सेंट जर्मेन के फ्रांसीसी खिलाड़ी केलियान मवापे भी शामिल थे, किन्तु इन्हें पीछे छोड़ते हुए मैसी ने यह पुरस्कार जीता. **पूर्व वर्षों में बार्सीलोना व पीएसजी के लिए खेल चुके लियोनिल मैसी ने इससे पूर्व 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 व 2021 में यह पुरस्कार जीता था. उनके बाद क्रिस्टियानों रोनाल्डो ने 5 बार इसे जीता है.***

विभिन्न वर्षों के बैलोन डि'ओर पुरस्कार

वर्ष	खिलाड़ी (क्लब)	देश	वर्ष	खिलाड़ी (क्लब)	देश
2005	रोनाल्डिन्हो (बार्सिलोना)	ब्राजील	2015	लियोनिल मैसी (बार्सिलोना)	अर्जेन्टीना
2006	फेबियो कैनावरो (रियल मैड्रिड)	इटली	2016	क्रिस्टियानो रोनाल्डो (रियल मैड्रिड)	पुर्तगाल
2007	काका (एसी मिलान)	ब्राजील	2017	क्रिस्टियानो रोनाल्डो (रियल मैड्रिड)	पुर्तगाल
2008	क्रिस्टियानो रोनाल्डो (मैनचेस्टर यूनाइटेड)	पुर्तगाल	2018	लूका मॉड्रिक (रियल मैड्रिड)	क्रोएशिया
2009	लियोनिल मैसी (बार्सिलोना)	अर्जेन्टीना	2019	लियोनिल मैसी (बार्सिलोना)	अर्जेन्टीना
2010	लियोनिल मैसी (बार्सिलोना)	अर्जेन्टीना	2020	किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया	
2011	लियोनिल मैसी (बार्सिलोना)	अर्जेन्टीना	2021	लियोनिल मैसी (पेरिस सेंट जर्मेन)	अर्जेन्टीना
2012	लियोनिल मैसी (बार्सिलोना)	अर्जेन्टीना	2022	करीम बेंजेमा (रियल मैड्रिड)	फ्रांस
2013	क्रिस्टियानो रोनाल्डो (रियल मैड्रिड)	पुर्तगाल	2023	लियोनिल मैसी (इंटर मियामी)	अर्जेन्टीना
2014	क्रिस्टियानो रोनाल्डो (रियल मैड्रिड)	पुर्तगाल			

महिला फुटबालरों का बैलोन डि'ओर फैमिनिन

एइताना बोनमाती : बैलोन डि' ओर फैमिनिन

*वर्ष 2018 से पहली बार महिला फुटबालरों के लिए भी यह पुरस्कार फुटबाल पत्रिका फ्रांस फुटबाल द्वारा शुरू किया गया था. इस वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाली स्पेन की एइताना बोनमाती (Aitana Bonmati) को दिया गया है. **यह लगातार दूसरा वर्ष है, जब यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है.** वर्ष 2018 में यह पहला बैलोन डि'ओर फेमिनिन (Ballon d'Or Feminin) पुरस्कार फ्रांस के ल्योंन (Lyon) क्लब के लिए खेलने वाली नॉर्वे की फुटबालर एडा हैगरबर्ग (Ada Hegerberg) को दिया गया था, जबकि 2019 के लिए यह (दूसरा) पुरस्कार अमरीका के रीन (Reign FC) क्लब के लिए खेलने वाली अमरीकी फुटबालर मेगन रैपिनो (Megan Rapinoe) को दिया गया था. वर्ष 2020 में यह पुरस्कार कोरोना महामारी के चलते किसी को नहीं दिया गया था, जबकि 2021 व 2022 दोनों ही वर्षों के लिए यह पुरस्कार स्पेन की ही एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया था.*

सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबालर के लिए कोपा ट्रॉफी

21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबालर के लिए कोपा ट्रॉफी (Kopa Trophy) की शुरूआत भी फ्रांस फुटबाल द्वारा वर्ष 2018 से की गई थी. इस वर्ष 2023 के लिए यह ट्रॉफी रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलने वाले ब्रिटेन के जूड बेलिंघम (Jude Bellingham) को दी गई है. पूर्व वर्षों में वर्ष 2018 के लिए यह पहली ट्रॉफी फ्रांस के कीलियन मबापे (Kylian Mbappe) को प्रदान की गई थी. वर्ष 2019 के लिए यह ट्रॉफी नीदरलैण्ड्स के मैथिस डि लिट (Matthijs de Ligt) को बैलोन डि'ओर पुरस्कारों के साथ ही प्रदान की गई थी. कोरोना महामारी के चलते 2020 में यह ट्रॉफी किसी को नहीं दी गई थी, जबकि 2021 के लिए यह बार्सिलोना क्लब के पेड्री को तथा पिछले वर्ष 2022 के लिए यह ट्रॉफी बार्सिलोना क्लब के ही युवा खिलाड़ी गावी को दी गई थी.

सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी

विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी (Yashin Trophy) की शुरूआत फ्रांस फुटबालर द्वारा वर्ष 2019 से की गई थी. इस वर्ष 2023 के लिए यह एस्टोन विला के लिए खेलने वाले अर्जेन्टीना के एमिलियानो मार्टिनेज को दी गई है, जबकि पिछले वर्ष 2022 के लिए यह ट्रॉफी रियल मैड्रिड के लिए खेलने वाले बेल्जियम के थिबाउट कोर्टोइस (Thibaut Courtois) को दी गई है. इससे पूर्व 2021 के लिए यह ट्रॉफी पेरिस सेंट जर्मेन के गियानलुइगी डोनाराम्मा को दी गई थी. 2020 के लिए यह ट्रॉफी किसी को नहीं दी गई थी, जबकि वर्ष 2019 के लिए यह पहली ट्रॉफी लिवरपूल क्लब के लिए खेलने वाले ब्राजीली खिलाड़ी एलिसन रामसेस बेकर (Alisson Ramses Becker) को प्रदान की गई थी.

रॉबर्ट लिवानडॉस्की
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर

स्ट्राइकर ऑफ द ईयर व बैस्ट क्लब ऑफ द ईयर

फ्रांस फुटबाल पत्रिका द्वारा यह दोनों पुरस्कार वर्ष 2021 से ही शुरू किए गए थे. *वर्ष 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर (Striker of the Year) का पुरस्कार (गर्ड मुलर ट्रॉफी) मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैण्ड को दी गई है. इससे पूर्व 2020 व 2021 के लिए यह पुरस्कार बेयर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले पोलैण्ड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान रॉबर्ट लिवानडॉस्की (Robert Lewandowski) को दिया गया था. 2021 में शुरू किया गया **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब** (Club of the Year) का पुरस्कार इस वर्ष इंगलैण्ड के मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है, जबकि महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार एफसी बार्सीलोना को दिया गया.*

STUDYPDF WALLAH

फ्रांस फुटबाल पत्रिका के वर्ष 2023 के बैलोन डि' ओर व अन्य पुरस्कार एक दृष्टि में

पुरस्कार	विजेता	देश	क्लब
बैलोन डि' ओर (वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबालर)	लियोनिल मैसी	अर्जेन्टीना	इंटर मियामी
बैलोन डि' ओर फेमिनिन (वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर)	एइताना बोनमाती	स्पेन	एफसी बार्सीलोना (महिला)
कोपा ट्रॉफी (21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबालर)	जूड बेलिंघम	इंगलैण्ड	रियल मैड्रिड
याशिन ट्रॉफी (वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर)	एमिलियानो मार्टिनेज़	अर्जेंटीना	एस्टोन विला
गर्ड मुलर ट्रॉफी (वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्ट्राइकर)	एर्लिंग हॉलैण्ड	नॉर्वे	मैनचेस्टर सिटी
सुकरात पुरस्कार	विनिसियस जूनियर	ब्राजील	रियल मैड्रिड
पुरुषों का क्लब ऑफ द ईयर	–	–	मैनचेस्टर सिटी
महिलाओं का क्लब ऑफ द ईयर	–	–	बार्सीलोना फेमिनिन

बुकर पुरस्कार–2023

आयरलैण्ड के साहित्यकार पॉल लिन्च (Paul Lynch) उनके उपन्यास प्रॉफेट साँग

बुकर पुरस्कार विजेता पॉल लिन्च

(Prophet Song) के लिए साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में एक कार्यक्रम में 26 नवम्बर, 2023 को प्रदान किया गया. यह उपन्यास एक ऐसे परिवार की कहानी बताता है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है, जिसमें वे लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं, जिनका वह आदी है.

इस पुरस्कार के तहत् 50 हजार पाउंड की राशि पुरस्कृत लेखक को प्रदान की गई.

वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार हेतु जिन 6 पुस्तकों को अल्पसूचीबद्ध (Short List) किया गया था. उनमें भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला ही उपन्यास **वेस्टर्न लेन** (Western Lane) भी शामिल था. अल्पसूचीबद्ध की गई. 6 पुस्तकों की घोषणा 21 सितम्बर, 2023 को की गई थी. इन सभी के नाम (लेखकों के नाम सहित) निम्नलिखित हैं–

पुस्तक	लेखक
वेस्टर्न लेन (Western Lane)	चेतना मारू (ब्रिटेन)
प्रोफेट साँग (Prophet Song)	पॉल लिन्च (आयरलैण्ड)
द बी स्टिंग (The Bee Sting)	पॉल मुरे (आयरलैण्ड)
स्टडी फॉर ओबीडिएंस (Study for Obedience)	सारा बर्नस्टीन (कनाडा)
इफ आई सर्वाइव यू (If I Survive You)	जोनाथन एस्कॉफ्री (अमरीकी)
दिस अदर ईडेन (This Other Eden)	पॉल हॉर्डिंग

बुकर पुरस्कार की शुरूआत 1969 में हुई थी तथा अब तक भारत के 3 व भारतीय मूल के 2 अन्य साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है.

बुकर पुरस्कार के विजेताओं में भारतीय/भारतीय मूल के उपन्यासकार

वर्ष	उपन्यासकार	पुरस्कृत उपन्यास/कृति
2008	अरविंद अडिग	द व्हाइट टाइगर
2006	किरण देसाई	द इनहैरिटेंस ऑफ लॉस
1997	अरुंधति रॉय	द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स
1981	सलमान रश्दी*	मिडनाइट्स चिल्ड्रेन
1971	वी. एस. नायपाल*	इन ए फ्रीस्टेट

* भारतीय मूल के उपन्यासकार

आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार

लगभग 1000 दिन तक चले आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों तथा तीन मंत्रालयों को प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है. इन्हें यह पुरस्कार 31 अक्टूबर, 2023 को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदान किए.

पुरस्कृत राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र हैं–

प्रथम–जम्मू और कश्मीर

द्वितीय–गुजरात

तृतीय–हरियाणा व राजस्थान (संयुक्त रूप से)

पुरस्कृत मंत्रालय निम्नलिखित हैं–

प्रथम–विदेश मंत्रालय

द्वितीय–रक्षा मंत्रालय

तृतीय–रेल मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय

एकता कपूर व वीरदास को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड (2023)

प्रसिद्ध कॉमेडियन वीरदास को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके शो 'वीरदास लैंडिंग' के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 20 नवम्बर, 2023 को न्यूयॉर्क सिटी में प्रदान किया गया. **इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एण्ड साइंसेज** (IATAS) के (51वें) पुरस्कारों के तहत् **सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरिज** का यह पुरस्कार ब्रिटेन के **डेरी गर्ल्स** (Derry Girls) को भी **वीरदास लैंडिंग** के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया.

इंटरनेशनल एमी पुरस्कार की ट्रॉफी के साथ एकता कपूर

- एकेडमी के इन पुरस्कारों के तहत् भारत की एकता कपूर को डायरेक्टोरेट अवॉर्ड समारोह में प्रदान किया गया.

एकेडमी (IATAS) के इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरिज का पुरस्कार जर्मनी के **द एम्प्रेस** (The Empress) के लिए दिया गया.

- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रिटेन के मार्टिन फ्रीमैन (Martin Freeman) को ब्रिटिश सीरियल 'द रेस्पोंडर' में भूमिका के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेक्सिको की कार्ला सोउजा (Karla Souza) को मैक्सिकन सीरियल में भूमिका के लिए दिया गया.

इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एण्ड साइंसेज (IATAS) के इंटरनेशनल एमी पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से भिन्न है. इंटरनेशनल एमी पुरस्कार अमरीका से बाहर निर्मित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं.

STUDYPDF WALLAH

निधन
(Death)

एस. वेंकटरमन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस. वेंकटरमन का 92 वर्ष की आयु में 18 नवम्बर, 2023 को मुम्बई में निधन हो गया. भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे वेंकटरमन दिसम्बर 1990 से दिसम्बर 1992 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे. उससे पूर्व 1985–89 के दौरान वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव भी वह रहे थे. Indian Economy : Reviews and Commentries (तीन खण्डों में) के वह लेखक थे.

एस. वेंकटरमन

डॉ. एस. एस. बद्रीनाथ

नेत्र चिकित्सा में ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉ. एस. एस. बद्रीनाथ, जिन्होंने सस्ती एवं सुलभ नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय की स्थापना चेन्नई में की थी, का 83 वर्ष की आयु में 21 नवम्बर, 2023 को चेन्नई में निधन हो गया. अनेक पुरस्कारों से सम्मानित एस. एस. बद्रीनाथ को चिकित्सा के क्षेत्र का डॉ. बी. सी. रॉय पुरस्कार 1991 में प्रदान किया गया था. वह **पद्मश्री** (1983) व **पद्म भूषण** (1996) से सम्मानित थे.

एस. एस. बद्रीनाथ

पी. वलसला

प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार पी. वलसला का 85 वर्ष की आयु में 21 नवम्बर, 2023 को काझिकोड में निधन हो गया. केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित साहित्य क्षेत्र के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वलसला द्वारा रचित उपन्यासों में **नेल्लु अग्नायम** व **वेनल** आदि शामिल हैं. वह केरल साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी रही थीं तथा अकादमी की फैलोशिप से भी सम्मानित थीं. केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार **एझूथाचन पुरस्कार** (Ezhuthachan Puraskaram) 2021 में ही उन्हें प्रदान किया गया था.

पी. वलसला

पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय

भारत सहित कई देशों में लग्जरी होटलों के संस्थापक ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का 94 वर्ष की आयु में 14 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया. ओबेरॉय ग्रुप के संस्थापक दिवंगत रायबहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय के पुत्र पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय ने ओबेरॉय व ट्राइडेंट होटल समूह की अध्यक्षता 1988 में सँभाली थी. इससे पूर्व इस होटल समूह की कमान सरदार मोहन सिंह ओबेरॉय के पास थी. बाद में पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय ने इन होटलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उद्योग व्यापार जगत् के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित पृथ्वीराज सिंह को 2008 में पदम् विभूषण से सम्मानित किया गया था.

पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय

वासुदेव आचार्य

वरिष्ठ माकपा (CPIM) नेता वासुदेव आचार्य का 81 वर्ष की आयु में 13 नवम्बर, 2023 को हैदराबाद में निधन हो गया. 1980 में पहली बार बांकुड़ा लोक सभा सीट से सांसद चुने गए वासुदेव आचार्य लगातार 2014 तक वहाँ के सांसद रहे थे.

केदारनाथ अग्रवाल

मिठाई और नमकीन की प्रतिष्ठित चेन बीकानेरवाला के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की आयु में 13 नवम्बर को नई दिल्ली में निधन हो गया. शुरू में भुजिया व रसगुल्ले टोकरी में रख कर दिल्ली की सड़कों पर बेचने वाले लाला केदारनाथ ने कारोबार बढ़ाते हुए कम्पनी की स्थापना की. वर्तमान में देश-विदेश में 60 से अधिक दुकानें इस समूह की हैं.

के. ए. फ्रांसिस

दक्षिण भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं चित्रकार के. ए. फ्रांसिस का 9 नवम्बर, 2023 को त्रिशूर में निधन हो गया. वह 76 वर्ष के थे. केरल ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष रहे फ्रांसिस मलयालम मनोरमा साप्ताहिक के लगभग दो दशकों तक सम्पादक रहे थे.

राजकुमार कोहली

बॉलीवुड के वरिष्ठ फिल्म निर्माता-निर्देशक राजकुमार कोहली का 93 वर्ष की आयु में 24 नवम्बर, 2023 को मुम्बई में निधन हो गया. प्रसिद्ध अभिनेता अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली ने नागिन, बीस साल बाद, जानी दुश्मन जैसी लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया था.

सुब्रत राय

सहारा समूह के संस्थापक उद्यमी सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में मुम्बई के एक अस्पताल में 14 नवम्बर, 2023 को निधन हो गया. सहारा फाइनेंस, एयरलाइंस रियल एस्टेट, मीडिया, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि सहित अनेक क्षेत्रों में पैर फैलाने वाले सुब्रत राय की गणना कभी देश के सबसे धनी एवं प्रभावशाली व्यक्तियों में होती थी, किन्तु बाद में करोड़ों रुपयों के घोटाले में वह कानून के शिकंजे में फँसे रहे. सहारा समूह की सहकारी समितियों में लगभग 3 करोड़ निवेशकों का करोड़ों रुपया अभी फँसा हुआ है, जिसकी वापसी का आदेश भी सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था. इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

सुब्रत राय

फातिमा बीवी

सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश रहीं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी (Fatima Beevi) का 96 वर्ष की आयु में 23 नवम्बर, 2023 को कोल्लम में निधन हो गया. केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहीं फातिमा बीवी को 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला थीं. अप्रैल 1992 तक वह इस पद पर रहीं. बाद में 1993-1997 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य तथा 1997-2001 के दौरान तमिलनाडु की राज्यपाल भी वह रही थीं.

फातिमा बीवी

पुस्तकें
(Books)

अगेन एण्ड अगेन (Again and Again) –जोनाथन एविसन

कॉमन येट अनकॉमन (Common Yet Uncommon) –सुधा मूर्ति

STUDYPDF WALLAH

वर्ष 2024 : अन्तर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष
(International Year of Camelids 2024)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अन्तर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में नामित किया

है, (कैमलिड्स से तात्पर्य ऊँट के बच्चों से है). यह देखते हुए कि कैमलिड्स पृथ्वी के सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका है, कैमलिड्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 को कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव खाद्य एवं कृषि संगठन (FAC) की संस्तुति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था.

वर्ष/दिवस/सप्ताह
(Year/Days/Week)

नवम्बर 2023

1 नवम्बर–7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल तथा 5 केन्द्रशासित क्षेत्रों–दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चण्डीगढ़ तथा अण्डमान-निकोबार के स्थापना दिवस.

7 नवम्बर–राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

9 नवम्बर–उत्तराखण्ड का स्थापना दिवस

(9 नवम्बर, 2023 को उत्तराखण्ड का 23वाँ स्थापना दिवस राज्य में मनाया गया.)

9 नवम्बर–राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस

10 नवम्बर–शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस

11 नवम्बर–राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

(भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस 11 नवम्बर, 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में देश में मनाया जा रहा है.)

11 नवम्बर–प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस

(1914–18 के प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर 11 नवम्बर, 1918 को हुए थे, जब आर्मिस्टिक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस उपलक्ष्य में 11 नवम्बर को 'रिमेम्ब्रेंस डे' के रूप में मनाया जाता है. कुछ देशों में इसे 'आर्मिस्टिक डे' व 'पॉपी डे' भी कहा जाता है.)

14 नवम्बर–बाल दिवस (भारत)

(दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस)

14 नवम्बर–विश्व मधुमेह दिवस

(इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म दिवस)

15 नवम्बर–झारखण्ड का स्थापना दिवस

(15 नवम्बर, 2000 को गठित झारखण्ड की स्थापना का 23वाँ स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2023 को मनाया गया.)

15 नवम्बर–बिरसा मुण्डा जयन्ती

15 नवम्बर–जनजातीय गौरव दिवस.

(आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव गाथा की स्मृति में 15 नवम्बर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 10 नवम्बर, 2021 की बैठक में किया गया था.)

16 नवम्बर–अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (International Day for Tolerance)

16 नवम्बर–राष्ट्रीय प्रेस दिवस

17 नवम्बर–राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस

19 नवम्बर–पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस

19 नवम्बर–विश्व शौचालय दिवस

20 नवम्बर–यूनीवर्सल चिल्ड्रन्स डे

21 नवम्बर–विश्व मत्स्यिकी दिवस

21 नवम्बर–विश्व टेलीविजन दिवस (संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसम्बर, 1996 को एक प्रस्ताव पारित कर 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया था.)

25 नवम्बर–महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

26 नवम्बर–राष्ट्रीय विधि दिवस (संविधान दिवस)

(भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था. इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवम्बर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है.)

अन्तरिक्ष
(Space)

स्पेसएक्स सुपर हेवी रॉकेट का दूसरा परीक्षण भी विफल

अंतरिक्ष यात्रियों को चन्द्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए विकसित किए गए एलन मस्क के स्पेसएक्स (SpaceX) सुपर हेवी रॉकेट स्टारशिप का दूसरा परीक्षण भी 18 नवम्बर, 2023 को प्रक्षेपण के कुछ मिनट बाद ही विफल हो गया. स्पेसएक्स द्वारा विकसित अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का प्रक्षेपण 18 नवम्बर को टेक्सास के बोका चीका के स्टारबेस लॉन्च साइट से किया गया था तथा 90 मिनट की इसकी उड़ान के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद कंट्रोल सेंटर से इसका सम्पर्क टूट गया. धमाके के साथ विस्फोट होते ही इस उड़ान का दूसरे चरण का महत्वपूर्ण डाटा खो दिया गया. विस्फोट के बावजूद स्टारशिप की इस दूसरी उड़ान के प्रति संतोष स्पेसएक्स ने यह कहते हुए व्यक्त किया है कि इस तरह की विफलताओं से आगे और अधिक सफलता के लिए सीख मिलती है. स्टारशिप की 18 नवम्बर की दूसरी उड़ान को इसकी पहली उड़ान से ज्यादा कामयाब बताया गया है. इसकी पहली उड़ान अप्रैल 2023 में विफल रही थी.

दुर्घटना
(Accident)

नेपाल में भीषण भूकम्प

अफगानिस्तान के बाद अब नेपाल भीषण भूकम्प का शिकार नवम्बर 2023 में हुआ है. 8 नवम्बर की रात्रि में आए भूकम्प की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6·4 आँकी गई है जाजरकोट जिले में बारेकोट भूकम्प का केन्द्र था, भूकम्प से आस-पास के इलाकों में ज्यादा क्षति हुई है कम-से-कम 157 लोगों के मरने की खबर प्रारम्भिक समाचारों में बताई गई थी. भूकम्प के झटके दूर-दूर तक महसूस किए गए. वर्ष 2015 के पश्चात् नेपाल में यह सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकम्प बताया गया है.

विविध
(Miscellaneous)

भारत-श्रीलंका मित्र शक्ति 2023 संयुक्त अभ्यास

भारत व श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का नौवाँ संस्करण पुणे में 16–29 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न हुआ. इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मराठा इन्फैंट्री रेजीमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया. इस संयुक्त अभ्यास का पिछला आठवाँ संस्करण अक्टूबर 2021 में श्रीलंका में अम्पारा में तथा सातवाँ संस्करण 2019 में पुणे में ही सम्पन्न हुआ था.

शेष पृष्ठ 38 पर

STUDYPDF WALLAH

खेलकूद

एथलेटिक्स

इंदिरा मैराथन (2023)

दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवम्बर को

जसवंत सिंह बघेल (पुरुष वर्ग में प्रथम)

प्रयागराज में आयोजित 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में सेना के सूबेदार जसवंत सिंह बघेल ने व महिला वर्ग में सीआईएसएफ की रीनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किए. पुरुषों में सेना के ही बुगाथा श्रीनू व प्रयागराज के अनिल कुमार क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे जबकि महिलाओं में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः दिल्ली की नूतन व प्रयागराज की शिप्रा कुमारी ने प्राप्त किया.

रीनू (महिला वर्ग में प्रथम)

पुरुषों में पहले स्थान पर रहे जसवंत सिंह बघेल ने 42·195 किमी की यह दौड़ 2 घण्टे 21 मिनट व 50 सेकण्ड में पूरी की, जबकि महिला वर्ग की विजेता रीनू ने यह दूरी तय करने में 2 घण्टे 58 मिनट व 16 सेकण्ड लिए. पहले स्थानों पर दोनों धावकों को ₹ 2-2 लाख की नकद राशि पुरस्कार में दी गई, जबकि दूसरे स्थान पर रहे धावक-धाविकाओं को ₹ 1-1 लाख तथा तीसरे स्थान पर रहे धावक-धाविकाओं को ₹ 75-75 हजार की राशि पुरस्कार में दी गई, आगे के 11-11 स्थानों पर रहे धावक-धाविकाओं को ₹ 10-10 हजार प्राप्त हुए.

ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इस दौड़ का आयोजन खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में किया जाता है.

न्यूयॉर्क सिटी मैराथन (2023)

न्यूयॉर्क सिटी में 5 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न (52वीं) वार्षिक मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में इथियोपिया के तमिरात तोला अबेरा (Tamirat Tola Abera) व महिला वर्ग में कीनिया की हेलन ओबीरी (Hellen Obiri) विजेता रहे. 42·195 किमी की यह दौड़ पूरी करने में 2 घण्टे 04 मिनट व 58 सेकण्ड तमिरात तोला ने लिए, जबकि हेलन ओबीरी ने यह दौड़ 2 घण्टे 27 मिनट 23 सेकण्ड में पूरी की.

वर्ष की 6 प्रमुख मैराथन दौड़ों में से अन्तिम इस मैराथन में कीनिया के एल्बर्ट कोरिर व इथियोपिया के शूरा किताता पुरुषों में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे. महिलाओं में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः लेटेसेनबेट गिडी (इथियोपिया) व शैरोन लोकेडी (कीनिया) ने प्राप्त किया.

विजेताओं के नाम एक दृष्टि में

पुरुष वर्ग
प्रथम–तमिरात तोला (इथियोपिया) 2:04: 58
द्वितीय–एलबर्ट कोरिर (कीनिया) 2:06:57
तृतीय–शूरा किताता (इथियोपिया) 2:10:21
महिला वर्ग
हेलन ओबीरी (कीनिया) 2:27:23
लेटेसेनबेट गिडी (इथियोपिया) 2:27:29
शैरोन लोकेडी (कीनिया) 2:27:33

बैडमिन्टन

चाइना मास्टर्स (2023) भारत के सात्विक साइराज रैंकिरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी उपविजेता

चीन में शेन झेन में 21–26 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न चाइना मास्टर्स बैडमिंटन (2023) में भारत क चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्द्धा में फाइनल मुकाबले में चीन के लियांग वीकेंग व वांग चैंग की जोड़ी से हार कर उपविजेता रहे.

इस टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः कोडई नारोका (जापान) व चेन यूफी (Chen Yufei) ने जीते.

शतरंज

फिडे ग्रांड स्विस शतरंज टूर्नामेंट (2023) : आर. वैशाली व विदित गुजराती ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भाग लेने की अर्हता प्राप्त की

कैंडिडेट्स फिडे विश्व शतरंज चैम्पियनशिप (2024) के लिए पात्र खिलाड़ियों के चयन के सिलसिले में पुरुष व महिला, दोनों ही वर्गों में फिडे ग्रांड स्विस शतरंज टूर्नामेंट्स का आयोजन आइल ऑफ मैन (Isle of Man) में अक्टूबर-नवम्बर 2023 में हुआ. इसमें पुरुष वर्ग में भारत के विदित गुजराती व महिला वर्ग में भारत की ही आर. वैशाली विजेता रहे. इससे इन दोनों ने ही अगले वर्ष के फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है.

आर. वैशाली व विदित गुजराती : फिडे ग्रांड स्विस शतरंज के विजेता

उल्लेखनीय है कि वैशाली का भाई आर. प्रगनांनदा पहले ही पुरुष वर्ग में कैंडिडेट्स टूर्नामेन्ट में भागीदारी के लिए अर्हता प्राप्त कर चुका है.

उल्लेखनीय है कि कैंडिडेट्स टूर्नामेन्ट का विजेता ही विश्व चैम्पियनशिप के लिए गत विजेता के साथ मुकाबला करता है।.

क्रिकेट

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : पंजाब पहली बार विजेता

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की टी-20 घरेलू क्रिकेट की 2023-24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला पंजाब व बड़ौदा की टीमों के बीच हुआ. मोहाली में 6 नवम्बर को खेले गए, इस मैच में बड़ौदा को 20 रनों से हराकर पंजाब ने पहली ही बार यह टूर्नामेन्ट जीतने में सफलता प्राप्त की. इस टूर्नामेन्ट में पंजाब टीम का नेतृत्व मंदीप सिंह ने किया था. पंजाब टीम के ही अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार मिला.

STUDYPDF WALLAH

इस खिताबी विजय के लिए ₹ 80 लाख की राशि बीसीसीआई द्वारा विजेता टीम (पंजाब) को प्रदान की जाएगी. इतनी ही राशि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भी पुरस्कारस्वरूप प्रदान करने की घोषणा की गई है.

भारत के दो और क्रिकेटर–डायना एडुल्जी व वीरेन्द्र सहवाग अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी (Diana Edulji) व बीते वर्षों के आक्रामक बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग उन तीन क्रिकेटरों में शामिल हैं, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICI) के हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा नवम्बर 2023 में की गई है. हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले तीसरे क्रिकेटर श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा हैं. ***इन्हें मिला कर आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटरों की संख्या 112 हो गई है, जबकि भारतीय क्रिकेटरों की कुल संख्या 9 हुई है.*** *इनमें डायना एडुल्जी व वीरेन्द्र सहवाग के अतिरिक्त सुनील गावस्कर विशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर व वीनू मनकड़ शामिल हैं. 1976–1993 के दौरान भारत के लिए 54 मैच (20 टेस्ट मैच + 34 ओडी-आई) खेलने वाली डायना एडुल्जी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं.*

डायना एडुल्जी
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान

वीरेन्द्र सहवाग

- *हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर व बिशन सिंह बेदी थे, जिन्हें 2009 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था. बाद में कपिल देव को 2010 में, अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में तथा वीनू मनकड़ को 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था.*
- *जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में विभिन्न देशों के कुल 112 क्रिकेटर्स को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, इनमें सर्वाधिक 32 क्रिकेटर इंगलैण्ड के व दूसरे स्थान पर 29 क्रिकेटर आस्ट्रेलिया के व 21 वेस्टइंडीज के हैं. 9 क्रिकेटर्स के साथ भारत का इस मामले में चौथा स्थान है.*

आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल विभिन्न देशों के क्रिकेटरों की संख्या

देश	(नवम्बर 2023 के अन्त की स्थिति) हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटरों की संख्या	देश	(नवम्बर 2023 के अन्त की स्थिति) हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटरों की संख्या
इंगलैण्ड	32	द. अफ्रीका	6
आस्ट्रेलिया	29	श्रीलंका	4
वेस्टइंडीज	21	न्यूजीलैण्ड	3
भारत	9	जिम्बाब्वे	1
पाकिस्तान	7	योग	112

विराट कोहली : ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतकों का विश्व रिकॉर्ड

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम : सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भंग

भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने 15 नवम्बर, 2023 को मुम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप 2023 के न्यूजीलैण्ड के विरुद्ध खेले गए सेमीफाइनल मैच में शतक बनाकर इतिहास रचा. एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका यह 50वाँ शतक था. इसके साथ ही ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 49 शतकों का सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने भंग कर दिया. विश्व कप का यह सेमीफाइनल मैच भारत ने 70 रन से जीत-कर फाइनल में प्रवेश किया.

इससे पूर्व इसी विश्व कप के दौरान 5 नवम्बर को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच में 49वाँ शतक बनाकर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के विश्व रिकॉर्ड की (एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में) बराबरी की थी.

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट दिया गया

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार 6 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में बांग्लादेश व श्रीलंका के बीच खेले गए विश्व कप 2023 के मैच में श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) को ***'टाइम आउट'*** *करार दिया गया.*

आईसीसी के नियमों के तहत् विश्व कप के किसी मैच में किसी बल्लेबाज के आउट अथवा रिटायर होने पर अगला बल्लेबाज यदि 2 मिनट के भीतर क्रीज़ पर अगली बाल नहीं खेलता है, तो वह टाइम आउट के दायरे में आ जाता है. *टाइम आउट का विकेट गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है तथा एक ही बाल पर दो बल्लेबाजों को आउट माना जाता है.*

विश्व कप 2023 में बांग्लादेश व श्रीलंका के बीच नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर 6 नवम्बर, 2023 को खेले गए मैच में श्रीलंका की पारी में सदीरा विक्रम सिंघा के आउट होने के पश्चात् अगले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज एक मिनट के भीतर क्रीज़ पर यद्यपि आ गए थे तथापि हेलमेट में किसी दिक्कत के कारण बिना स्ट्राइक लिए दूसरा हेलमेट पेवेलियन से मँगाया. इस प्रक्रिया में समय लगा तथा बांग्लादेश के कप्तान शाकिब की अपील पर अम्पायर ने मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया.

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट का यह पहला ही मामला बताया गया है.

तीरंदाजी

एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप (2023) में भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान : पैरा तीरंदाजी में शीर्ष स्थान

बैंकॉक (थाइलैण्ड) में 3–10 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न (23वीं) एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका

पैरा तीरंदाजी के दौरान शीतल देवी (बाएं) व राकेश कुमार (दाएं)

में दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया. 6 स्वर्ण, 2 रजत व 3 कांस्य सहित कुल 11 पदकों के साथ द. कोरिया का शीर्ष स्थान पदक तालिका में रहा.

STUDYPDF WALLAH

बाद में सम्पन्न पैरा तीरंदाजी में 9 पदक (4 स्वर्ण, 4 रजत व 1 कांस्य) जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. बैंकॉक में ही सम्पन्न पैरा तीरंदाजी में पुरुषों की कम्पाउंड तथा महिलाओं की कम्पाउंड ओपन डब्ल्स व कम्पाउंड ओपन मिक्स टीम में गोल्ड मेडल व 1 एकल सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते.

बिना भुजाओं वाली 16 वर्षीय शीतल देवी ने महिलाओं की कम्पाउंड ओपन में रजत जीतने के अतिरिक्त ज्योति के साथ मिलकर कम्पाउंड ओपन युगल तथा राकेश के साथ मिलकर कम्पाउंड ओपन मिक्स टीम ईवेंट में स्वर्ण जीते. इस प्रकार 16 वर्षीय शीतल देवी 3 पदक जीतने में कामयाब रही.

आगामी 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप का आयोजन अब 2025 में होगा.

महिलाओं की एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी : भारत विजेता

रांची में 27 अक्टूबर-5 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न महिलाओं के (सातवीं) एशियाई चैम्पियनशिप कप हॉकी में फाइनल मुकाबला भारत

खिताबी विजय के पश्चात् भारतीय टीम का उल्लास

व जापान की टीमों के बीच हुआ. 5 नवम्बर, 2023 को गत विजेता जापान को इस मुकाबले में 4–0 से हराकर भारत ने इसका खिताब जीता. ***भारत व जापान के अतिरिक्त चार अन्य टीमें (चीन, द. कोरिया, मलेशिया व थाइलैण्ड) इस टूर्नामेन्ट में शामिल थीं.*** *भारतीय टीम का नेतृत्व सविता पूनिया ने किया था.*

भारत ने दूसरी बार इस द्विवार्षिक टूर्नामेन्ट का खिताब जीता है. इससे पूर्व 2016 में भारत इसका विजेता रहा था, *जबकि जापान ने दो बार 2013 व 2021 में तथा द. कोरिया ने बार 2010, 2011 व 2018 में इसे जीता है.*

इस वर्ष की खिताबी विजय के लिए हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की प्रत्येक सदस्या को ₹ 3–3 लाख प्रदान करने की घोषणा की है.

महिलाओं की सीनियर अन्तर्विभागीय राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (2023)

हॉकी इंडिया की महिलाओं की तीसरी सीनियर अन्तर्विभागीय हॉकी चैम्पियनशिप का खिताब भारतीय तेल निगम (IOC) ने 21 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में फाइनल में गत विजेता रेलवे को हरा कर आपने नाम किया. निर्धारित समय तक दोनों टीमें 4-4 से बराबर थी तथा शूटऑउट दौर में तेल निगम की टीम ने 3-2 से विजय दर्ज की.

पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (2023) : पंजाब विजेता

हॉकी इंडिया के तत्वावधान में पुरुषों की (13वीं) सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में चेन्नई में 17–28 नवम्बर, 2023 को हुआ. इसका खिताब पंजाब ने फाइनल में गत विजेता हरियाणा को पेनल्टी शूट आउट दौर में हरा कर जीता. **पंजाब ने हॉकी इंडिया का यह खिताब चौथी बार अपने नाम किया है.** तीसरा व चौथा स्थान क्रमशः तमिलनाडु व कर्नाटक का रहा. **इस टूर्नामेन्ट में पंजाब की टीम के कप्तान हरमन प्रीत सिंह थे.**

कनाडा पहली ही बार महिलाओं की टीम टेनिस के बिली जीन कप का विजेता

महिला टीम टेनिस के वर्ष 2023 के बिली जीन किंग कप के लिए फाइनल मुकाबला कनाडा व इटली के बीच था. सेविले (स्पेन) में 7–12 नवम्बर को खेले गए फाइनल में कनाडा की टीम ने इटली को 2–0 से हरा

नोवाक जोकोविच (रिकॉर्ड आठवीं बार) वर्षांत पर नम्बर एक खिलाड़ी और महिलाओं में इगा स्वियातेक

सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2023 में टेनिस सत्र की समाप्ति नम्बर एक रैंक के साथ की. इटली में ट्यूरिन में एटीपी फाइनल्स की समाप्ति से पूर्व ही अपने अंकों की संख्या इतनी कर ली कि सत्रांत में उनका शीर्ष स्थान सुनिश्चित हो गया. वर्ष का समापन नम्बर एक खिलाड़ी के रूप में करने के लिए नम्बर एक की ट्रॉफी एटीपी अध्यक्ष आंद्रे गाउंदे जी ने उन्हें प्रदान की. ***जोकोविच ने यह रिकॉर्ड आठवीं बार वर्ष का समापन नम्बर एक खिलाड़ी रहते हुए किया है.***

नम्बर एक ट्रॉफी के साथ नोवाक जोकोविच

महिला टेनिस खिलाड़ियों में वर्ष 2023 के अन्त में नम्बर वन रैंक पोलैण्ड की इगा स्वियातेक (Iga Swiatek) ने प्राप्त की है.

पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की वर्षांत एकल एटीपी रैंकिंग (2023)

रैंक	खिलाड़ी	वर्षांत में अंक
1	नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic), सर्बिया	11245
2	कालोस अल्काराज (Carlos Alcaraz), स्पेन	8855
3	डेनिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev), रूस	7600
4	जेनिक सिनर (Jannik Sinner), इटली	6490
5	आन्द्रे रूबलेव (Andrey Rublev), रूस	4805
6	स्टेफानोस सितसिपास (Stefanos Tsetsipas), ग्रीस	4235
7	एलेक्जेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev), जर्मनी	3985
8	होल्गर रूने (Holger Rune), डेन्मार्क	3660
9	ह्यूबर्ट हर्काज (Hubart Hurkacz), पोलैण्ड	3245
10	टेलर फिट्ज (Taylor Fritz), अमरीका	3100

महिला टेनिस खिलाड़ियों की वर्षांत एकल डब्ल्यूटीए रैंकिंग (2023)

रैंक	खिलाड़ी	वर्षांत में अंक
1	इगा स्वियातेक (Iga Swiatek), पोलैण्ड	9295
2	आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka), बेलारूस	9050
3	कोको गौफ (Coco Gauff), अमरीका	6580
4	एलेना रिबाकिना (Elena Rybakina), कजाखस्तान	6365
5	जेसिका पेगुला (Jessica Pegula), अमरीका	5975
6	ओंस जेब्युर (Ons Jabeur), ट्यूनेशिया	4195
7	मार्केटा वोंड्रोसोवा (Marketa Vondrousova), चेक गणराज्य	4075
8	कैरोलिना मुचोवा (Karolina Muchova), चेक गणराज्य	3651
9	मारिया सकारी (Maria Sakkari), ग्रीस	3620
10	बारबोरा क्रेजीकोवा (Barbora Krejcikova), चेक गणराज्य	2880

STUDYPDF WALLAH

कर पहली ही बार यह टूर्नामेन्ट जीतने में सफलता प्राप्त की.

10 अप्रैल, 2023 से शुरू हुए बिली जीन कप का यह 60वाँ संस्करण था तथा कनाडा महिलाओं का टीम चैम्पियनशिप का यह कप जीतने वाला पहला ही देश है. सर्वाधिक 18 बार अमरीका इसका विजेता रहा है.

वर्षांत की डब्ल्यूटीए फाइनल्स (2023) वर्ष की सर्वोच्च रैंकिंग वाली 8 खिलाड़ियों के लिए

विमेन्स टेनिस एसोसिएशन (WTA) के मेक्सिको में सम्पन्न फाइनल्स (WTA Finals) में इगा स्वियातेक (Iga Swiatek) एकल खिताब की विजेता रही. विश्व की नम्बर एक खिलाड़ी पोलैण्ड की स्वियातेक ने इस खिताब के लिए अमरीका की जेसिका पेगुला को फाइनल में 6-1, 6-0 से पराजित किया. इगा स्वियातेक का फाइनल्स में यह पहला ही खिताब है.

इगा स्वियातेक ट्रॉफी के साथ

डब्ल्यूटीए फाइनल्स के युगल खिताब के लिए जर्मनी की लॉरा सीगेमुंड व रूस की वेरा ज्वोनारेवा की जोड़ी ने अमरीका की निकोल मेलिचर-मार्टिनेज व आस्ट्रेलिया की एलेन पेरेज़ की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया.

- सत्र की इस अन्तिम डब्ल्यूटीए चैम्पियनशिप में 8 शीर्ष खिलाड़ी एकल मुकाबले में व 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें युगल मुकाबले में भाग लेती हैं.
- इस वर्ष की यह प्रतियोगिता एकल खिताब के मामले में 52वाँ तथा युगल खिताब के मामले में 47वाँ संस्करण था.

डब्ल्यूटीए की वर्षांत एलाइट ट्रॉफी

विमेन्स टेनिस एसोसिएशन (WTA) की वर्षांत ट्रॉफी डब्ल्यूटीए एलाइट ट्रॉफी के लिए मैच चीन में झुहाई (Zhuhai) में 24–29 अक्टूबर, 2023 को खेले गए. इस टूर्नामेन्ट में एकल स्पर्द्धा में विश्व की शीर्ष 12 ऐसी खिलाड़ी तथा युगल स्पर्द्धा में विश्व की 6 शीर्ष ऐसी टीमें भाग लेती हैं, जो डब्ल्यूटीए फाइनल्स में स्थान नहीं बना सकीं.

वर्ष 2023 की एलाइट ट्रॉफी के लिए खेले गए मुकाबलों में ब्राजील की बीट्रिज हदाद माइया एकल व युगल दोनों में ही खिताब की विजेता रहीं. एकल स्पर्द्धा का खिताब चीन की झेंग किनवेन को फाइनल में हरा कर 27 वर्षीय बीट्रिज़ ने जहाँ जीता, युगल खिताब के लिए रूस की वेरोनिका कुद्रमेतोवा के साथ जोड़ी बना कर जापान की मियू कातो व इंडोनेशिया की ए. सुट-जियादी की जोड़ी को उन्होंने हराया.

भारत के रोहन बोपन्ना व आस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स टेनिस में युगल मुकाबले में उपविजेता

पेरिस में 30 अक्टूबर–5 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न पेरिस मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच एकल खिताब के विजेता रहे. पुरुषों के लेवल 1000 स्तर के इस टूर्नामेन्ट का यह 51वाँ संस्करण था. विश्व के नम्बर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इस खिताब के लिए बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को फाइनल में पराजित किया.

इस टूर्नामेन्ट के युगल मुकाबले में भारत के रोहन बोपन्ना व आस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी उपविजेता रही. मेक्सिको के सांटियागो गोंजालेज व फ्रांस के एडुवर्ड रोजर-वैसेलिन की जोड़ी से यह फाइनल में पराजित हुई.

पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल्स (2023) : नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड सातवी बार विजेता

सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों के लिए एटीपी के वर्ष 2023 के संत्रात एटीपी टूर्स फाइनल्स का आयोजन इटली में ट्यूरिन में 12–19 नवम्बर, 2023 को हुआ.

- *एटीपी के इस वर्षांत टूर्नामेन्ट का एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में इटली के जेनिक सिनर को हराकर जीता.*
- *युगल खिताब के लिए राजीव राम (अमरीका) व जो सैलिसबरी (ब्रिटेन) की गत विजेता जोड़ी ने मार्सेल ग्रेनोलर्स (स्पेन) व होरासियो जेबालॉस (अर्जेंटीना) की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया.*
- *एटीपी टूर्स फाइनल्स **एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स** (ATP) का सत्र का अन्तिम टूर्नामेन्ट होता है तथा यह प्रतिवर्ष नवम्बर माह में ही आयोजित होता है.*
- *वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ी की हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेन्ट की एकल स्पर्द्धा में भाग लेते हैं, जबकि युगल स्पर्द्धा में 8 जोड़ियाँ टूर्नामेन्ट में शामिल की जाती हैं.*
- *वर्ष 2023 का उपर्युक्त आयोजन एकल खिताब हेतु 54वाँ तथा युगल खिताब हेतु 49वाँ आयोजन था.*
- *नोवाक जोकोविच (सर्बिया) ने एटीपी टूर्स फाइनल्स का एकल खिताब सर्वाधिक 7 बार जीता है.*
- *इवान लेंडल (तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया) पीट सम्प्रास (अमरीका) 5-5 बार इसके युगल खिताब के विजेता रहे है.*

इटली 47 वर्ष पश्चात् डेविस कप का विजेता

इटली 47 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् पुरुषों के टीम टेनिस के डेविस कप का विजेता

नवम्बर 2023 में बना है. वर्ष 2023 के डेविस कप के लिए फाइनल मुकाबला आस्ट्रेलिया व इटली के बीच स्पेन में मालागा (Malaga) में हुआ. इस मुकाबले में पहले एकल में इटली के माटेओ अर्नाल्डी (Matteo Arnaldi) ने आस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को हरा कर 1–0 की बढ़त बना दी थी, दूसरे एकल में एलेक्स डि मिनोर को हरा कर जेनिक सिनर (Jannik Sinner) ने इटली की 2–0 से विजय सुनिश्चित की.

- ***123 वर्ष पुराने इस टूर्नामेंट में इटली की टीम दूसरी बार विजेता बनी है. इससे पूर्व 1976 में चिली को फाइनल में हरा कर इटली ने पुरुषों की टीम चैम्पियनशिप का यह टूर्नामेंट जीता था. आस्ट्रेलिया 28 बार इस टूर्नामेंट का विजेता रहा है.***
- *123 वर्ष पूर्व शुरू हुए इस टूर्नामेंट को अब तक कुल 16 टीमों ने ही जीता है. **इसमें सर्वाधिक 32 बार अमरीका इसका विजेता रहा है.***

स्क्वैश

राष्ट्रीय स्क्वाश चैम्पियनशिप (2023)

चेन्नई में 17–23 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न (79वीं) सीनियर राष्ट्रीय स्क्वाश चैम्पियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग के खिताब क्रमशः वेलावन सेंथिल कुमार (तमिलनाडु) व अनाहत सिंह (दिल्ली) ने जीता. दोनों ने ही पहली ही बार सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है.

वेलावन सेंथिल कुमार व अनाहत सिंह : राष्ट्रीय चैम्पियन

STUDYPDF WALLAH

पुरुष वर्ग में तमिलनाडु के ही गत विजेता अभय सिंह को फाइनल में 12–10, 11–3, 12–10 से हरा कर वेलावन यह खिताब जीतने में सफल रहे.

महिला वर्ग में फाइनल मुकाबला दिल्ली की 15 वर्षीय अनाहत व दिल्ली की ही तनवी खन्ना के बीच था. पहले राउंड में आगे चल रही तनवी खन्ना दूसरे सैट में चोटिल होने से वाकआउट कर गईं, जिससे अनाहत को विजेता घोषित किया गया. **15 वर्षीय अनाहत इस खिताब की दूसरी सबसे युवा विजेता हैं. उनसे कम उम्र में यह खिताब वर्ष 2000 में जोशना चिनप्पा ने केवल 14 वर्ष की उम्र में जीता था. जोशना बाद में 19 बार राष्ट्रीय खिताब की विजेता रही थीं.**

पंकज आडवाणी का 26वाँ व 27वाँ विश्व बिलियर्ड्स खिताब

भारत के पंकज आडवाणी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स व स्नूकर फेडरेशन (IBSF) के दोहा में नवम्बर (2023) में सम्पन्न बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप में दो प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने में सफल रहे. 21 नवम्बर को अपने ही देश के सौरव कोठारी को फाइनल में हरा कर विश्व बिलियर्ड्स लॉंग फॉर्मेट खिताब जहाँ उन्होंने अपने नाम किया, 24 नवम्बर को सौरव कोठारी को ही फाइनल में हरा कर पॉइंट फॉर्मेट चैम्पियनशिप जीतने में सफलता भी उन्होंने प्राप्त की. बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप में उनका यह क्रमशः 26वाँ व 27वाँ विश्व खिताब था.

वर्ष 2024 की फॉर्मूला-1 रेसों का कार्यक्रम

वर्ष 2024 में फॉर्मूला-1 रेसों का शुभारम्भ 2 मार्च, 2024 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स रेस से होगा. इस वर्ष 24 ऐसी रेसों के आयोजन का फॉर्मूला-1 का कार्यक्रम है. इन सभी की तिथियाँ एवं स्थान निम्नलिखित हैं–

क्र.	तिथि	ग्रांड प्रिक्स	स्थान
1.	29 फरवरी–2 मार्च	बहरीन	साखिर
2.	7–9 मार्च	सऊदी अरब	जेद्दा
3.	22–24 मार्च	आस्ट्रेलिया	मेलबोर्न
4.	5–7 अप्रैल	जापान	सुजुका
5.	19–21 अप्रैल	चीन	शंघाई
6.	3–5 मई	मियामी	मियामी
7.	17–19 मई	एमिलिया रोमाग्ना	इमोला
8.	24–26 मई	मोनाको	मोनाको
9.	7–9 जून	कनाडियन	मॉन्ट्रियल
10.	21–23 जून	स्पेनिश	बार्सिलोना
11.	28–30 जून	ऑस्ट्रियन	स्पीलबर्ग
12.	5–7 जुलाई	ब्रिटिश	सिल्वरस्टोन
13.	19–21 जुलाई	हंगेरियन	बुडापेस्ट
14.	26–28 जुलाई	बेल्जियम	स्पा
15.	23–25 अगस्त	डच	जैंडवूर्ट
16.	30 अगस्त–1 सितम्बर	इटालियन	मॉन्जा
17.	13–15 सितम्बर	अजरबैजान	बाकू
18.	20–22 सितम्बर	सिंगापुर	सिंगापुर
19.	18–20 अक्टूबर	यूनाइटेड स्टेट्स	ऑस्टिन
20.	25–27 अक्टूबर	मैक्सिकन	मेक्सिको सिटी
21.	1–3 नवम्बर	ब्राजीलियाई	साओ पाउलो
22.	21–23 नवम्बर	लास वेगास	लास वेगास
23.	29 नवम्बर–1 दिसम्बर	कतर	लुसैल
24.	6–8 दिसम्बर	आबूधाबी	यस मरीना

●●●

शेष पृष्ठ 33 का

मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट व ₹ 525 मूल्य का सिक्का

भगवान कृष्ण की भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में

डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उ.प्र. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

23 नवम्बर, 2023 को आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में उनके सम्मान में ₹ 5 मूल्य का स्मारक डाक टिकट ₹ 525 मूल्य का स्मारक सिक्का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जारी किया. यह पहला अवसर है जब ₹ 525 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है. 35 ग्राम वजन का सिक्का 50 प्रतिशत चाँदी, 40 प्रतिशत ताँबा, 5 प्रतिशत निकल व 5 प्रतिशत जस्ते से बना है. सिक्के के एक ओर मीराबाई के चित्र के नीचे 1498-2023 तथा दूसरी ओर अशोक स्तम्भ के नीचे ₹ 525 अंकित है. यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा.

●●●

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

उपकार हरियाणा सामान्य ज्ञान एक दृष्टि में

कोड : 1059 मूल्य : ₹ 105/-

हरियाणा CET/PCS/HTET पुलिस कॉंस्टेबिल/ एस.आई./हरियाणा एस.एस.सी. आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार टॉपिकवाइज अपडेट.
- बजट 2023-24 के आँकड़े.
- नवीन परीक्षोपयोगी समाचारों (2022-23) से अपडेट.
- 2022-2023 में घोषित योजनाओं के साथ.
- खेलकूद की नवीनतम घटनाएं
- प्रत्येक टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण व राजकीय रिपोर्टों से अपडेट.
- टॉपिकवाइज 700 से अधिक परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश.

लेखक : संजय सुमन

उपकार प्रकाशन, आगरा-5 • E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान : सेना व हरियाणा का क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान

37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर–9 नवम्बर, 2023 को गोवा में हुआ. 28 राज्यों व 8 केन्द्रशासित क्षेत्रों के अतिरिक्त सेना की टीम (37वीं टीम के रूप में) इन खेलों में शामिल थी. 43 खेलों की विभिन्न स्पर्द्धाओं का आयोजन इन खेलों में हुआ, जिनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 हजार से अधिक थी. खेलों की स्पर्द्धाएं गोवा के विभिन्न शहरों–

37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा

37वें राष्ट्रीय खेलों में ओवर ऑल चैम्पियन की राजा भालिन्दर सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र के लिए प्रदान करते हुए, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़

मापुसा, पणजी, पोंडा, वास्को व मर्गाओ में सम्पन्न हुई, जबकि साइक्लिंग व गोल्फ स्पर्द्धाएं दिल्ली में आयोजित की गई थीं. यह पहला ही अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ. मर्गाओं (गोवा) के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एक रंगारंग समारोह में इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अक्टूबर को किया. गोवा के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई व मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सांवत के अतिरिक्त केन्द्रीय युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर व भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पी. टी. ऊषा आदि भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे. Get Set Goa 15 दिन तक चले इन खेलों का आदर्श वाक्य (motto) था, जबकि भारतीय बाइसन (biosen) अर्थात् गौर, जो भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो गोवा का राजकीय पशु (State Animal) भी है, इन खेलों का शुभंकर (mascot) था. इसे **मोगा** (MOGA) नाम दिया गया था. (मोगा शब्द कोंकणी से बना है, जिसका अर्थ प्रेम होता है.)

80 स्वर्ण, 69 रजत व 79 कांस्य सहित सर्वाधिक 228 पदक जीत कर महाराष्ट्र ने इन खेलों की ओवर ऑल चैम्पियनशिप की **राजा भालिन्दर सिंह ट्रॉफी** अपने नाम की. महाराष्ट्र ने 1994 के पश्चात् यह उपलब्धि हासिल की है. इस मामले में सेना (SSCB–Services Sports Control Board) टीम, जो 2007 के बाद के चारों राष्ट्रीय खेलों में ओवरऑल चैम्पियन रही थी, को महाराष्ट्र ने अपदस्थ किया है. 66 स्वर्ण, 27 रजत व 33 कांस्य सहित कुल 126 पदकों के साथ सेना (SSCB) का स्थान इस बार दूसरा रहा. 192 पदकों (62 स्वर्ण, 55 रजत व 75 कांस्य) के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा.

पदक तालिका में पहले 10 राज्य/टीमें

क्र.	राज्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
1.	महाराष्ट्र	80	69	79	228
2.	सेना (SSCB)	66	27	33	126
3.	हरियाणा	62	55	75	192
4.	मध्य प्रदेश	37	36	39	112
5.	केरल	36	24	27	87
6.	कर्नाटक	32	32	37	101
7.	मणिपुर	30	22	30	82
8.	दिल्ली	29	26	67	122
9.	गोवा	27	27	38	92
10.	तमिलनाडु	19	26	32	77
	योग	555	546	779	1880

सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रीहरि नटराज को ट्रॉफी प्रदान करते हुए भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. ऊषा

- उत्तर भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश (चौथा स्थान) के पश्चात् पंजाब 11वें (17 स्वर्ण, 26 रजत व 32 कांस्य), राजस्थान 13वें (14 स्वर्ण, 18 रजत व 34 कांस्य), उत्तर प्रदेश 15वें (11 स्वर्ण, 24 रजत व 36 कांस्य), झारखण्ड 20वें (6 स्वर्ण, 5 रजत व 14 कांस्य), हिमाचल प्रदेश 24वें (4 स्वर्ण, 2 रजत व 5 कांस्य), उत्तराखण्ड 25वें (3 स्वर्ण, 7 रजत व 14 कांस्य), छत्तीसगढ़

भारत के राष्ट्रीय खेलों के आयोजन वर्ष एवं स्थल

क्र.	वर्ष	आयोजन स्थल (मुख्य)
1.	1924	लाहौर
2.	1926	लाहौर
3.	1928	लाहौर
4.	1930	इलाहाबाद
5.	1932	मद्रास
6.	1934	दिल्ली
7.	1936	लाहौर
8.	1938	कलकत्ता
9.	1940	बम्बई
10.	1942	पटियाला
11.	1944	लाहौर
12.	1946	लाहौर
13.	1948	लखनऊ
14.	1952	मद्रास
15.	1953	जबलपुर
16.	1954	दिल्ली
17.	1956	पटियाला
18.	1958	कटक
19.	1960	दिल्ली
20.	1962	जबलपुर
21.	1964	कलकत्ता
22.	1966	बंगलौर
23.	1968	मद्रास
24.	1970	कटक
25.	1979	हैदराबाद
26.	1985	दिल्ली
27.	1987	केरल
28.	1994	मुम्बई-पुणे
29.	1997	बंगलौर
30.	1999	मणिपुर (इम्फाल)
31.	2001	पंजाब (लुधियाना)
32.	2002	हैदराबाद
33.	2007	गुवाहाटी
34.	2011	झारखण्ड (रांची)
35.	2015	केरल
36.	2022	गुजरात
37.	2023	गोवा
38.	2024	उत्तराखण्ड

नोट–1924 से 1938 तक इन खेलों को इण्डियन ओलम्पिक गेम्स के नाम से जाना जाता था. 1985 से यह खेल आधुनिक 'ओलम्पिक खेलों की तर्ज पर आयोजित किए जा रहे हैं.

शेष पृष्ठ 42 पर

STUDYPDF WALLAH

आस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप (2023) का विजेता : लगातार 10 मैच जीतने के पश्चात् अंतिम फाइनल मैच में भारत पराजित

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) का एकदिवसीय मैचों का 13वाँ विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेन्ट भारत को 6 विकेट से फाइनल में हराकर आस्ट्रेलिया ने जीता है. भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर–19 नवम्बर, 2023 को खेले गए. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच भारत व आस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर 19 नवम्बर को खेला गया, जिसमें पैट कमिंस (Pat Cummins) के नेतृत्व वाली आस्ट्रेलियाई टीम 6 विकेट से विजयी रही. दोनों टीमें विश्व कप के फाइनल में दूसरी बार आमने-सामने थीं (इससे पूर्व 2003 में भारत को ही फाइनल में हराकर आस्ट्रेलियाई टीम आईसीसी विश्व कप की विजेता बनी थी) **आस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप का विजेता बना है. इससे पूर्व 1987 में इंगलैण्ड को फाइनल में हराकर, 1999 में पाकिस्तान को 2003 में भारत को, 2007 में श्रीलंका को तथा 2015 में न्यूजीलैण्ड को फाइनल में हराकर आस्ट्रेलिया विश्व कप विजेता रहा था.**

आस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस को विश्व कप की ट्रॉफी प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स

2023 के विश्व कप में भारत के लिए अत्यधिक हताशा की स्थिति यह रही कि राउण्ड रॉबिन लीग में अपने सभी 9 मैच तथा सेमीफाइनल जीतने के पश्चात् केवल फाइनल मैच में ही पराजय का सामना टीम ने किया. **इस विश्व कप में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ही ऐसी अकेली टीम थी जिसने सेमीफाइनल व उससे पूर्व अपने सभी 9 लीग मैच जीते थे तथा केवल फाइनल में ही पराजय का सामना टीम ने किया.** 19 नवम्बर को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम पर 1·30 लाख दर्शकों की उपस्थिति में पहले खेलते हुए 50 ओवर में 240 रन भारतीय टीम ने बनाए तथा विजय के लिए 241 रनों का लक्ष्य आस्ट्रेलिया को दिया. जिसे आस्ट्रेलिया टीम ने 43 ओवर में ही 6 विकेट शेष रहते प्राप्त कर लिया. भारतीय टीम की 240 रनों की पारी में सर्वाधिक 66 रनों का योगदान के. एल. राहुल का रहा, वहीं आस्ट्रेलिया की ओर से सर्वोच्च 137 रन की शतकीय पारी (फाइनल में एकमात्र शतक) ट्रेविस हेड ने खेली. **फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ट्रेविस हेड को ही मिला.**

ट्रॉफी के साथ आस्ट्रेलियाई टीम का उल्लास

46 दिन तक चले इस टूर्नामेन्ट में सर्वाधिक 765 रन भारत के विराट कोहली ने बनाए. उन्हें ही मैन ऑफ द टूर्नामेन्ट का पुरस्कार भी मिला. सर्वाधिक 24 विकेट लेने के लिए पुरस्कार भारत के मोहम्मद शमी को दिया गया. 1 करोड़ डॉलर इनामी राशि के इस टूर्नामेन्ट में 40 लाख डॉलर की राशि विजेता टीम को तथा 20 लाख डॉलर की राशि उपविजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई.

भारत सहित कुल 10 टीमें इस टूर्नामेन्ट में शामिल थीं, जिसमें भारत को मेजबान होने के नाते जहाँ अर्हता प्राप्त थी, 7 टीमें (अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया बांग्लादेश, इंगलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान व द. अफ्रीका) का चयन आईसीसी विश्व कप सुपर लीग के आधार पर तथा दो टीमों (नीदरलैण्ड व श्रीलंका) को जिम्बाब्वे में जून-जुलाई 2023 में खेले गए विश्व कप क्वालिफायर के आधार पर चुना गया था. इस विश्व कप में 2 सेमी फाइनल व फाइनल सहित कुल 48 मैच खेले गए. यह मैच 10 विभिन्न शहरों–अहमदाबाद, बेंगलूरू, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई व पुणे में खेले

विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी	देश	मैच	रन
विराट कोहली	भारत	11	765
रोहित शर्मा	भारत	11	597
क्विंटन डिकॉक	द. अफ्रीका	10	594
रचिन रवींद्र	न्यूजीलैण्ड	10	578
डेरिल मिशेल	न्यूजीलैण्ड	10	552

विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

खिलाड़ी	देश	मैच	विकेट
मोहम्मद शमी	भारत	7	24
एडम जंपा	आस्ट्रेलिया	11	23
दिलशान मदुशंका	श्रीलंका	9	21
जसप्रीत बुमराह	भारत	11	20
गेराल्ड कोएट्ज	द. अफ्रीका	8	20

विश्व कप 2023 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी	देश	मैच	छक्के
रोहित शर्मा	भारत	11	31
डेविड वार्नर	आस्ट्रेलिया	11	24
श्रेयस अय्यर	भारत	11	24
डेरिल मिशेल	न्यूजीलैण्ड	10	22
ग्लेन मैक्सवेल	आस्ट्रेलिया	9	22

गए. **आगामी 14वें विश्व कप का आयोजन 2027 में द. अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होगा.**

विश्व कप 2023 : अन्य महत्वपूर्ण आँकड़े

- **सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज**–क्विंटन डिकॉक (द. अफ्रीका) 4 शतक
- **सर्वाधिक अर्द्धशतक**–विराट कोहली (9 अर्द्ध-शतक)
- **सबसे तेज गति से शतक**–ग्लेन मैक्सवेल (आस्ट्रेलिया) (40 गेंदों पर शतक)
- **सर्वाधिक चौके**–विराट कोहली (68 चौके)
- **सर्वाधिक कैच**–डेरिल मिशेल (11 कैच)
- **सर्वोच्च वैयक्तिक पारी**–ग्लेन मैक्सवेल (आस्ट्रेलिया) (201 रन अविजित पारी)
- **सर्वोच्च टीम स्कोर**–428 रन/5 विकेट पर द. अफ्रीका (श्रीलंका के विरुद्ध)
- **न्यूनतम टीम स्कोर**–55 रन (भारत के विरुद्ध)

विश्व कप 2023 में शामिल सभी 10 टीमों के कप्तान

टीम	कप्तान
भारत	रोहित शर्मा
आस्ट्रेलिया	पैट कमिंस (Pat Cummins)
इंगलैण्ड	जोस बटलर
पाकिस्तान	बाबर आजम
न्यूजीलैण्ड	केन विलियमसन
द. अफ्रीका	तेंबा बावुमा
श्रीलंका	दासुन शनाका
बांग्लादेश	शाकिब अल हसन
अफगानिस्तान	हशमतुल्ला शाहिदी
नीदरलैण्ड्स	स्कॉट एडवर्ड्स

STUDYPDF WALLAH

विश्व कप : विभिन्न आयोजनों में भारत का प्रदर्शन

विश्व कप क्रमांक	मेजबान देश	वर्ष	मैच खेले	जीते	हारे	अनिर्णीत/टाई	स्थिति
1.	इंगलैण्ड	1975	3	1	2	—	पहले दौर में प्रतिस्पर्द्धा से बाहर
2.	इंगलैण्ड	1979	3	—	3	—	पहले दौर में प्रतिस्पर्द्धा से बाहर
3.	इंगलैण्ड	1983	8	6	2	—	भारत चैम्पियन बना (वेस्टइण्डीज को फाइनल में हराकर)
4.	भारत-पाकिस्तान	1987	7	5	2	—	सेमीफाइनल में इंगलैण्ड से पराजित
5.	आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैण्ड	1992	8	2	5	1	पहले दौर में प्रतिस्पर्द्धा से बाहर
6.	भारत-पाकिस्तान-श्रीलंका	1996	7	4	3	—	सेमीफाइनल में श्रीलंका से पराजित
7.	इंगलैण्ड	1999	8	4	4	—	सुपर सिक्स में स्थान
8.	द. अफ्रीका	2003	11	9	2	—	उपविजेता (आस्ट्रेलिया से फाइनल में पराजित)
9.	वेस्टइण्डीज	2007	3	1	2	—	पहले दौर में प्रतिस्पर्द्धा से बाहर
10.	भारत-श्रीलंका-बांग्लादेश	2011	9	7	1	1	भारत चैम्पियन बना (श्रीलंका को फाइनल में हराकर)
11.	आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैण्ड	2015	8	7	1	–	भारत सेमीफाइनल में पराजित हुआ
12.	इंगलैण्ड-वेल्स	2019	10	7	2	1	भारत सेमीफाइनल में पराजित
13.	भारत	2023	11	10	1	—	**भारत फाइनल में पराजित (सभी 10 मैच जीतने के पश्चात्)**
	कुल		**96**	**63**	**30**	**3**	

सर्वोच्च पारी–413 रन (5 विकेट खोकर, 50 ओवर में) बरमूडा के विरुद्ध पोर्ट ऑफ स्पेन में 19 मार्च, 2007 को, 410 रन (4 विकेट खोकर), नीदरलैण्ड्स के विरुद्ध, 2023 विश्व कप में

न्यूनतम पारी–125 रन (41·4 ओवर में) आस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेंचुरियन में 15 फरवरी, 2003 को

सर्वोच्च वैयक्तिक पारी–183 रन, सौरभ गांगुली विरुद्ध श्रीलंका, टांटन में 26 मई, 1999 को

विश्व कप के इतिहास में दो हैट्रिक लगाने वाले गेंदबाज–चेतन शर्मा, 1987 में चौथे विश्व कप में न्यूजीलैण्ड के विरुद्ध तथा मोहम्मद शमी 2019 में 12वें विश्व कप में अफगानिस्तान के विरुद्ध.

आईसीसी विश्व कप : विभिन्न आयोजनों के विजेता एवं उपविजेता

क्रमांक	वर्ष	मेजबान	विजेता	उपविजेता
1.	1975	इंगलैण्ड	वेस्टइंडीज	आस्ट्रेलिया
2.	1979	इंगलैण्ड	वेस्टइंडीज	इंगलैण्ड
3.	**1983**	**इंगलैण्ड**	**भारत**	**वेस्टइंडीज**
4.	1987	भारत व पाकिस्तान	आस्ट्रेलिया	इंगलैण्ड
5.	1992	आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड	पाकिस्तान	इंगलैण्ड
6.	1996	भारत, पाकिस्तान व श्रीलंका	श्रीलंका	आस्ट्रेलिया
7.	1999	इंगलैण्ड	आस्ट्रेलिया	पाकिस्तान
8.	2003	दक्षिण अफ्रीका	आस्ट्रेलिया	भारत
9.	2007	वेस्टइंडीज	आस्ट्रेलिया	श्रीलंका
10.	2011	भारत, श्रीलंका व बांग्लादेश	भारत	श्रीलंका
11.	2015	आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड	आस्ट्रेलिया	न्यूजीलैण्ड
12.	2019	इंगलैण्ड व वेल्स	इंगलैण्ड	न्यूजीलैण्ड
13.	2023	भारत	आस्ट्रेलिया	भारत
14.	2027	द. अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे	–	–

STUDYPDF WALLAH

विश्व कप में सर्वोच्च वैयक्तिक पारियाँ

रन/पारी	बल्लेबाज	विरुद्ध	विश्व कप वर्ष
237*	मार्टिन गुप्तिल (न्यूजीलैण्ड)	वेस्टइंडीज	2015
215	क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)	जिम्बाब्वे	2015
201*	ग्लेन मैक्सवेल (आस्ट्रेलिया)	अफगानिस्तान	2023
188	गैरी किर्स्टन (द. अफ्रीका)	यूएई	1996
183	**सौरभ गांगुली (भारत)**	**श्रीलंका**	**1999**

विश्व कप में टीम के न्यूनतम स्कोर

टीम	स्कोर	खिलाफ	स्थान	वर्ष
कनाडा	36	श्रीलंका	पर्ल	2003
कनाडा	45	इंगलैण्ड	मानचेस्टर	1979
नामीबिया	45	आस्ट्रेलिया	पोचेफस्ट्रूम	2003
श्रीलंका	55	भारत	वानखेड़े	2023
बांग्लादेश	58	वेस्टइंडीज	ढाका	2011

विश्व कप में हैट्रिक्स

क्रमांक	गेंदबाज	बनाम	स्थान	वर्ष
1.	चेतन शर्मा (भारत)	न्यूजीलैण्ड	नागपुर	1987
2.	सकलेन मुश्ताक (पाकिस्तान)	जिम्बाब्वे	ओवल	1999
3.	चामिंडा वास (श्रीलंका)	बांग्लादेश	पीटरमारित्जबर्ग	2003
4.	ब्रेट ली (आस्ट्रेलिया)	केन्या	किंग्समीड	2003
5.	लसित मलिंगा (श्रीलंका)	द. अफ्रीका	प्रोविडेंस	2007
6.	केमार रोच (वेस्टइण्डीज)	नीदरलैण्ड्स	दिल्ली	2011
7.	लसित मलिंगा (श्रीलंका)	केन्या	कोलम्बो	2011
8.	स्टीवेन फिन (इंगलैण्ड)	आस्ट्रेलिया	मेलबर्न	2015
9.	जेपी डुमिनी (द. अफ्रीका)	श्रीलंका	सिडनी	2015
10.	मोहम्मद शमी (भारत)	अफगानिस्तान	साउथैम्पटन	2019
11.	ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैण्ड)	आस्ट्रेलिया	लॉर्ड्स	2019

(2023 विश्व कप में कोई हैट्रिक नहीं)

विश्व कप में दस विकेट से जीत

देश	विरुद्ध	स्थान	वर्ष
न्यूजीलैण्ड	श्रीलंका	कार्डिफ	2019
पाकिस्तान	वेस्टइण्डीज	ढाका	2011
श्रीलंका	इंगलैण्ड	कोलम्बो	2011
न्यूजीलैण्ड	जिम्बाब्वे	अहमदाबाद	2011
न्यूजीलैण्ड	केन्या	चेन्नई	2011
आस्ट्रेलिया	बांग्लादेश	न्यू साउण्ड	2007
दक्षिण अफ्रीका	केन्या	पोचेफस्ट्रूम	2003
श्रीलंका	बांग्लादेश	पीटरमारित्जबर्ग	2003
दक्षिण अफ्रीका	बांग्लादेश	ब्लोम-फाउण्टेन	2003
वेस्टइण्डीज	पाकिस्तान	मेलबर्न	1992
वेस्टइण्डीज	जिम्बाब्वे	बर्मिंघम	1983
भारत	ईस्ट अफ्रीका	लीड्स	1975

विश्व कप में टाई मैच

देश	विरुद्ध	स्थान	वर्ष
आस्ट्रेलिया	दक्षिण अफ्रीका	बर्मिंघम	1999
दक्षिण अफ्रीका	श्रीलंका	डरबन	2003
आयरलैण्ड	जिम्बाब्वे	जमैका	2007
भारत	इंगलैण्ड	बेंगलूरू	2011

2019 विश्व कप का 14 जुलाई, 2019 को लॉर्ड्स के मैदान पर इंगलैण्ड व न्यूजीलैण्ड के बीच खेला गया फाइनल मैच निर्धारित 50-50 ओवरों में टाई रहने के पश्चात् सुपर ओवर में भी टाई रहा था. इस मैच में हार-जीत का निर्णय मैच के दौरान लगाई गई बाउंड्रियों के आधार पर किया गया.

शेष पृष्ठ 39 का

28वें (2 स्वर्ण, 2 रजत व 16 कांस्य) व बिहार 30वें (0 स्वर्ण, 3 रजत व 5 कांस्य) स्थान पदक तालिका में रहा.

- 9 नवम्बर को खेलों के समापन समारोह को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने सम्बोधित किया तथा मुख्य पुरस्कारों का वितरण भी उन्होंने किया.
- खेलों में ओवरऑल चैम्पियनशिप की **राजा भालिन्दर सिंह ट्रॉफी** जहाँ महाराष्ट्र को मिली, दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः सेना व हरियाणा का रहा.
- **खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज, जिन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य सहित सर्वाधिक 10 पदक इन खेलों में जीते, को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार महाराष्ट्र की संयुक्ता प्रसेनकाले व ओडिशा की प्रणति नायक को संयुक्त रूप से दिया गया.** इन दोनों ही जिमनास्ट्स ने 4 स्वर्ण व 1 रजत सहित 5-5 पदक जीते.
- आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखण्ड में होगा.

●●●

UPKAR'S

Towards New Horizons

MODERN ESSAYS

(For Academic and Competitive Examinations, particularly for Indian Civil Services and State Services Examinations)

Code : 387
Price : ₹ 140/-

By : Brij Kishore Goyal

It Contains Essays

- Political and Historical
- Socio-Political, Social, Economic, Educational, Scientific and Environmental
- Reflective, Literary and Personality Development
- Biographical

UPKAR PRAKASHAN, AGRA–5

STUDYPDF WALLAH

रोजगार समाचार

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा–2023

छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा, वित्त सेवा, खाद्य अधिकारी व नायब तहसीलदार आदि सिविल सेवा आदि के अन्य कुल 242 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन राज्य में चुने हुए केन्द्रों पर 11 फरवरी, 2024 को किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 30 दिसम्बर, 2023 है (केवल ऑनलाइन आवेदन ही इसके लिए किया जा सकता है). प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही इन सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए सम्भावित तिथियाँ 13, 14, 15 व 16 जून, 2024 हैं.

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–स्नातक अथवा समकक्ष.

आयु सीमा– (1 जनवरी, 2023 को)– 21-30 वर्ष. (पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु आयु सीमा–(21-28 वर्ष) निर्धारित है. छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों व अन्य विभिन्न मामलों में उच्च आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 200-200 अंकों के दो प्रश्न-पत्र क्रमशः सामान्य अध्ययन व योग्यता परीक्षा के होंगे. मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम व परीक्षा सम्बन्धी अन्य जानकारियों के लिए आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in देखें.

Suggested Books Code–1437, 2221

भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकीय संवर्ग में जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एण्ड सेल्स) की भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकीय संवर्ग में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एण्ड सेल्स) के कुल मिलाकर 8283 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन 7 दिसम्बर, 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ओबीसी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों की संख्या इनसे अलग है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान ताजा रिक्तियों में भी उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता–स्नातक

आयु सीमा (1 अप्रैल, 2023 को)– 20–28 वर्ष. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन जनवरी 2024 में सम्भावित है. एक घण्टे की अवधि की इस ऑनलाइन परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी व रीजनिंग एबिलिटी के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे. प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया जाएगा. मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ किस्म की ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें जनरल/ फाइनेंशियल अवेयरनैस, जनरल इंगलिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तथा रीजनिंग एबिलिटी व कम्प्यूटर एप्टीट्यूड के कुल 190 प्रश्न 200 अंकों के होंगे. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व ऑनलाइन आवेदन हेतु बैंक की वेबसाइट http://bank.sbi/careers अथवा http://www. sbi.co.in/careers देखें.

उपर्युक्त परीक्षा के लिए **उपकार प्रकाशन** द्वारा नई प्रकाशित **स्टेट बैंक लिपिकीय संवर्ग परीक्षा** से सम्बन्धित पुस्तकों का अध्ययन करें.

उपयोगी पुस्तकें– कोड नं. 2435, 2436, 1424, 1906, 1907, 1646

भारतीय स्टेट बैंक में सर्किल बेस्ड ऑफीसर्स की रिक्तियाँ

भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न सर्किल्स में सर्किल बेस्ड अधिकारियों के 5447 रिक्त पदों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र 12 दिसम्बर, 2023 तक आमन्त्रित किए गए हैं. उपलब्ध रिक्तियों में बैकलॉग पदों की 167 रिक्तियाँ शामिल हैं. इन रिक्तियों में भी कुछ रिक्तियाँ विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आरक्षित हैं. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कॉस्ट एकाउंटेंट, चार्टर्ड एकाउंटेंट सहित स्नातक भी आवेदन के पात्र हैं. साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारी के रूप में कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव.

आयु सीमा–31 अक्टूबर, 2023 को 21–30 वर्ष. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. 120 अंकों के ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी जिसके पश्चात् अन्तिम चरण इंटरव्यू का होगा. 2 घण्टे के ऑनलाइन टेस्ट में (i) इंगलिश लैंग्वेज (ii) बैंकिंग नॉलेज (iii) जनरल अवेयरनैस/ इकोनॉमी तथा (iv) कम्प्यूटर एप्टीट्यूट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे. इसके साथ ही 50 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा में अंग्रेजी भाषा (लैटर राइटिंग व निबन्ध) की परीक्षा होगी. ऑनलाइन टेस्ट जनवरी 2024 में सम्भावित है.

इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए रोजगार समाचार तथा बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/careers अथवा https://www.sbi.co.in/careers देखें. इन्हीं वेबसाइट्स पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

उपर्युक्त परीक्षा के लिए **उपकार प्रकाशन** द्वारा प्रकाशित **स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफीसर्स प्रारम्भिक परीक्षा** की पुस्तकों का अध्ययन लाभकारी होगा. पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध हैं.

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कॉन्स्टेबिल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफल मैन (सामान्य ड्यूटी) के 26 हजार से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती परीक्षा, 2024

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों–बीएसएफ, सीआईएसएफ, इंडो-तिब्बत बार्डर पुलिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) सचिवालय सुरक्षा बल (SSF) में कॉन्स्टेबिल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफल मैन (सामान्य ड्यूटी) में सिपाहियों के कुल मिलाकर 26,146 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा. इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं. 31 दिसम्बर, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम

STUDYPDF WALLAH

तिथि 1 जनवरी, 2024 है, इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्तियों में 23,347 रिक्तियाँ पुरुषों के लिए तथा 2799 रिक्तियाँ महिलाओं के लिए हैं. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता– मैट्रिकुलेशन अथवा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण.

आयु सीमा (1 जनवरी, 2024 को)—18-23 वर्ष. विभिन्न मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) में वस्तुनिष्ठ किस्म का 160 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी, प्रारम्भिक गणित तथा अंग्रेजी/हिन्दी के 20-20 प्रश्न चार खण्डों में होंगे. यह परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में सम्भावित है.

इस भर्ती के सम्बन्ध में आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट http://www.ssc.nic.in देखें.

उपर्युक्त परीक्षा के लिए **उपकार प्रकाशन** द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन लाभकारी होगा.

Suggested Books Code–2085, 2344, 2380, 2713, 1703

हरियाणा राज्य सिविल सेवा परीक्षा–2023 HCS (Executive Branch) and other Allied Services-2023

हरियाणा राज्य सिविल सेवा, पुलिस सेवा व अन्य कार्यकारी सेवाओं के कुल 121 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन राज्य में चुने हुए केन्द्रों पर 11 फरवरी, 2024 को किया जाएगा. इस प्रारम्भिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 21 दिसम्बर, 2023 है. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही इन सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया जाएगा. 30-31 मार्च, 2024 को सम्भावित है.

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातक अथवा समकक्ष है.

आयु सीमा (1 जनवरी, 2023 को)– 18-42 वर्ष. (DSP के पद हेतु अधिकतम आयु 27 वर्ष). विभिन्न मामलों में उच्च आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100-100 अंकों के दो प्रश्न-पत्र क्रमशः सामान्य अध्ययन व सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट के होंगे. सीसैट का यह दूसरा प्रश्न-पत्र केवल अर्हता निर्धारक होगा. मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम व परीक्षा सम्बन्धी अन्य जानकारियों व ऑनलाइन आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in देखें.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभागीय/स्थानीय/स्वायत्त निकायों में विभिन्न रिक्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न विभागीय/स्थानीय/स्वायत्त निकायों में सब स्टेशन अटेंडेंट, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर, नर्स ग्रेड-ए, स्पेशल एज्यूकेशन टीचर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर व लैबोरेटरी असिस्टेंट आदि कुल 863 विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) द्वारा 20 दिसम्बर, 2023 तक आमंत्रित किए गए है. उपलब्ध रिक्तियों में से कुछ रिक्तियाँ विभिन्न वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षित हैं. इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमाओं एवं विभिन्न मामलों में इनमें मिलने वाली छूटों आदि की जानकारी के लिए DSSSB की वेबसाइट www.dsssb.delhi.gov.in देखें.

इन पदों पर चयन के लिए एक/दो चरणों की परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इन भर्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु DSSSB की वेबसाइट http:/dsssbonline.nic.in देखें.

उपकार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन लाभकारी होगा.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वेलफेयर ऑफिसर/प्रोबेशन ऑफिसर/प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के रिक्त पद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सामाजिक कल्याण विभाग में वेलफेयर ऑफिसर/प्रोबेशन ऑफिसर/प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के क्रमशः 43 व 37 पदों सहित कुल 80 पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) द्वारा 3 जनवरी, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 80 है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता–सोशल वर्क अथवा समाजशास्त्र में मास्टर्स उपाधि अथवा क्रिमिनोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि.

आयु सीमा (आवेदन की अन्तिम तिथि 3 जनवरी, 2024 को) अधिकतम 30 वर्ष. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली एक चरण की प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के पहले खण्ड में मानसिक योग्यता व तर्कशक्ति का संख्यात्मक अभिरुचि, हिन्दी भाषा अंग्रेजी भाषा, सामान्य जानकारी आदि के प्रश्न होंगे, जबकि 200 अंकों का दूसरा खण्ड सोशल वर्क/समाजशास्त्र से सम्बन्धित प्रश्नों का होगा.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु DSSSB की वेबसाइट https://dssbonline.nic.in देखें.

आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर तथा एक्जीक्यूटिव सेल्स एण्ड ऑपरेशन के रिक्त पद

आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) ग्रेड ओ के 800 तथा एक्जीक्यूटिव्स-सेल्स एण्ड ऑपरेशंस (ESO) के 1300 पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन बैंक द्वारा 6 दिसम्बर, 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 800 + 1300 हैं. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता– (i) जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) पद हेतु–न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (SC/ST/PWBD) मामलों में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक)

(ii) एक्जीक्यूटिव-सेल्स एण्ड ऑपरेशंस हेतु)–स्नातक

आयु सीमा (1 नवम्बर, 2023 को)–20-25 वर्ष. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन टेस्ट में लॉजिकल तर्कशक्ति, एवं डाटा एनेलिसिस, संख्यात्मक अभिरुचि, सामान्य अंग्रेजी, जनरल/इकोनॉमी/ बैंकिंग/ अवेयरनैस/कम्प्यूटर/ आईटी आदि के प्रश्न होंगे.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु बैंक की वेबसाइट https://www.idbi.bank.in देखें.

STUDYPDF WALLAH

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जलवायु गर्म होने से विकराल हुई समुद्री लहरें

एक नवीन शोध से पता चला है कि कैलिफोर्निया के प्रशान्त महासागर के तट पर लहरें विकराल होने लगी हैं. अध्ययन में बताया गया है कि लहरें 13 फीट (4 मीटर) की ऊँचाई तक ऊपर उठने लगी हैं. शोध दल के अनुसार वायुमण्डलीय ताप में वृद्धि से ऐसा दुष्प्रभाव सामने आया है.

भयावह समुद्री लहरें

स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के समुद्र-वैज्ञानिक पीटर ब्रोमिरस्की ने जानकारी दी है कि 1931 के भूकम्पीय रिकॉर्ड के गहन विश्लेषण से पता चला है कि धरती के गर्म होने का समुद्र की लहरों के ऊँचा उठने के बीच गहरा सम्बन्ध है. अध्ययन में बताया गया है कि समुद्र गतिशीलता और तटीय इलाकों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है.

13 फीट तक की ऊँचाई तक उठने लगी हैं, समुद्र की लहरें.

ब्रोमिरस्की द्वारा समुद्री लहरों की ऊँचाई में परिवर्तन को दिखाने के लिए भूकम्पनीय रिकॉर्ड का अध्ययन करने में विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई गई. उन्होंने बताया कि जब समुद्री लहर तट से टकराती है, तो वह समुद्र तल के जरिए ऊर्जा की प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तब भूकम्पीय गतिविधियों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया सिस्मोग्राफ को एक संकेत प्राप्त होता है. इस संकेत की तीव्रता का सम्बन्ध समुद्री लहरों की ऊँचाई से होता है.

राष्ट्रीय समुद्री और वायुमण्डलीय संचालन (एनओएए) द्वारा तैनात किए गए प्लावों से लहरों की ऊँचाई का डेटा प्राप्त किया गया, जो सीमा से अधिक पाया गया.

विश्व के महासागरों का तापमान बढ़ने का पिछले सात वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है और यह एक नई ऊँचाई पर पहुँच गया है. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई. इस वर्ष विश्व के महासागरों का औसत तापमान 20·96 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जिसने वर्ष 2016 के 20·95 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पूरी दुनिया में महासागरों के तापमान में बढ़ोतरी की वजह से धरती की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई है.

वैज्ञानिकों ने बताया कि समुद्र की लहरों की बढ़ती ऊँचाई केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, इनका असर व्यापक पैमाने पर आबादी पर भी पड़ता है. जब जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की लहरों की ऊँचाई बढ़ती है, तो कटाव, तटीय बाढ़ और बुनियादी ढाँचों को नुकसान जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है. समुद्री वैज्ञानिक ब्रोमिरस्की ने इस बात पर जोर दिया कि ये परिवर्तन विनाशकारी घटनाओं की आशंका और उनकी आवृत्ति बढ़ाते हैं, जिससे मानव जीवन के लिए भी जोखिम बढ़ता है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में समुद्री वैज्ञानिक गैरी ग्रिग्स ने कहा कि आधे दशक के समय अन्तराल में समुद्री लहर में एक फुट की ऊँचाई में बढ़ोतरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए. दुनिया के समुद्रों के लिहाज से इसका व्यापक असर देखा जाना चाहिए.

कृत्रिम एवं सुरक्षित गर्भाशय का विकास–मानव जाति के लिए वरदान

वैज्ञानिकों को कृत्रिम गर्भाशय विकसित करने में सफलता मिल गई है. यह मानव सभ्यता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. निश्चय ही कृत्रिम गर्भाशय का भविष्य उज्ज्वल है. इसके विकास में वैज्ञानिक वर्षों से लगे थे.

इस अभियान का नेतृत्व भ्रूण सर्जन डॉ. एलेन फ्लेक ने किया. उनके अनुसार कृत्रिम गर्भाशय से गर्भधारण करने और शिशु के जन्म के बाद की सभी समस्याओं से निपटा जा सकेगा.

कमजोर नवजात शिशु जन्म के तुरन्त बाद वेंटिलेटर पर पहुँचने के बजाय इसी कृत्रिम गर्भाशय में पहुँचकर नया जीवन पाएंगे, पूर्ण विकसित होकर जन्म लेंगे. यह सच है कि बड़ी संख्या में कमजोर शिशुओं की मौत हो जाती है. कई बार किसी शिशु का जीवन गर्भ के अन्दर ही संकट में पड़ जाता है, उसे बचाने में चिकित्सक भी विफल हो जाते हैं, इस विफलता ने ही चिकित्सकों को प्रेरित किया है कि वे कृत्रिम गर्भाशय विकसित करें, ताकि संकट में पड़े शिशुओं को नया जीवन दिया जा सके. इस कृत्रिम गर्भाशय को **एक्सटेंड** नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों को लगता है कि सरकारें इस प्रयोग को मानवता के हित में मंजूरी दे देंगी. खासकर, जो शिशु 28 सप्ताह के गर्भकाल से पहले ही जन्म लेते हैं, उनका जीवन बचाना बहुत आसान हो जाएगा.

कृत्रिम गर्भाशय

वर्ष 2019 से इस प्रयोग में काफी तेजी आई है और इसके लिए फिलाडेल्फिया स्थित एक स्टार्ट-अप कम्पनी, विटारा बायोमेडिकल ने 10 करोड़ अमरीकी डॉलर जुटाए हैं. न्यूयॉर्क शहर के कोलम्बिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की बायोएथिसिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट केली वर्नर का कथन है, 'यह निश्चित रूप से एक रोमांचक, कदम है.'

वर्ष 2020 में दुनिया भर में लगभग 13·40 करोड़ ऐसे शिशुओं का जन्म हुआ, जिनमें समय से पहले जन्म लेने के कारण जटिलताएं थीं. ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2019 में दुनिया में लगभग 9,00,000 मौतें इसी वजह से हुई थीं. ऐसे में, एक सुरक्षित कृत्रिम गर्भाशय मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

वैज्ञानिक सोच के साथ निर्णायक विद्वानों की सोच का मिलना जरूरी है, ताकि इस पर नैतिकता या मानवता पर कोई बुरा असर नहीं पड़े.

पिघलते ग्लेशियर से निकले वायरस तबाही मचाएंगे

आस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय के शोध दल के अनुसार जलवायु-परिवर्तन के कारण ग्लेशियर में दबे पुराने वायरस और जीवाणु पृथ्वी और मानव दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं.

प्रमुख शोधकर्ता जियोवानी स्ट्रोना का कहना है कि पहली बार इस तरह के नतीजे

STUDYPDF WALLAH

देखने को मिले हैं. दुनिया भर में गम्भीर तरह के रोग फैलने की सम्भावना बढ़ जाएगी. ऐसे में जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी को सतर्क होना होगा. वायरस और जीवाणु कितने अधिक घातक हो सकते हैं. इसका सटीक आकलन बेहद कठिन होगा.

पिघलते ग्लेशियर

1 प्रतिशत वायरस भी निकले, तो मच सकती है पृथ्वी पर तबाही.

1-5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में तेजी से खतरा बढ़ेगा.

वर्ष 2100 तक तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि इस खतरे को और भयावह बना देगी.

पीएलओएस कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ठण्डे क्षेत्रों में भी पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है. अनुमान है कि बर्फ में दबे जीवाणु उतने ही हो सकते हैं, जितने अंतरिक्ष में तारे हैं. हजारों वर्ष से दफन ये वायरस, जीवाणु बेहद खतरनाक हो चुके हैं. बर्फ के नीचे दबे बैठे वायरस में से अगर एक प्रतिशत भी बाहर आते हैं, तो पृथ्वी पर तबाही मचा सकते हैं.

सॉफ्टवेयर से शोध में पुराने वायरस और बैक्टीरिया को सिमुलेशन के जरिए आधुनिक दुनिया के साथ सम्पर्क कराकर यह आकलन हुआ है. इसमें देखा गया है कि बर्फ में दफन जीवाणु आसानी से आधुनिक दुनिया में ढलकर भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं.

दिमाग में चिप लगाने के लिए मानव-परीक्षण को मंजूरी

एलन मस्क की कम्पनी न्यूरालिंक को अपने मानव-परीक्षण के लिए अन्तिम मंजूरी मिल गई है. अब यह ब्रेन चिप कम्पनी न्यूरालिंक मानव पर इसके परीक्षण के लिए

मानव-मस्तिष्क

लोगों का चयन कर पाएगी. यदि यह परीक्षण सफल रहा, तो दृष्टिहीन भी इसके माध्यम से देख सकेंगे. इस परीक्षण को पूरा होने में लगभग 6 वर्ष का समय लगेगा.

1. *सोचने भर से ऑपरेट हो जाएगा कम्प्यूटर.*
2. *दिमाग में सोचकर की-बोर्ड से टाइप और माउस का कर्सर चला सकेंगे.*
3. *दृष्टिहीन इंसान भी देख सकेंगे.*
4. *बन्दरों में सफल रहा है न्यूरालिंक का परीक्षण.*

न्यूरालिंक चिप के तीन प्रमुख हिस्से हैं. इसमें एन-1 इम्प्लांट, आर-1 रोबोट और एन-1 यूजर ऐप शामिल है. आइए जानते हैं कि यह किस तरह काम करेंगे–

एन-1 इम्प्लांट–मरीजों में सर्जरी के जरिए एन-1 इम्प्लांट को मस्तिष्क के उस क्षेत्र में लगाया जाएगा, जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है.

आर-1 रोबोट–एन-1 इम्प्लांट सर्जरी आर-1 रोबोट के जरिए होगी. इस ट्रायल में यह भी परखा जाएगा कि आर-1 रोबोट सर्जरी के लिए कितना सुरक्षित है ?

एन-1 यूजर ऐप–एन-1 इम्प्लांट के संचालन के लिए एक एन-1 यूजर ऐप भी होगा. इसके बाद लोगों को इस पूरे सिस्टम का फीडबैक देना होगा.

इस परीक्षण के जरिए कम्पनी यह देखना चाहती है कि यह डिवाइस मरीजों पर कैसे काम कर रहा है. इसके अलावा इसकी सुरक्षा को भी परखा जाएगा. हालाँकि कम्पनी ने अभी यह नहीं बताया है कि परीक्षण कब शुरू होगा और इसमें कितने प्रतिभागी शामिल होंगे. इससे पहले, कम्पनी को ट्रायल के लिए अमरीका के फूड, एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिली थी.

1. *अदृश्य है चिप.*
2. *डिवाइस को चार्ज करने की भी जरूरत होगी.*
3. *ऐप से ऑपरेट कर सकेंगे.*

न्यूरालिंक ने कहा कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की चोट या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस) से पीड़ित है, वे इस मानव परीक्षण में हिस्सा ले सकते हैं. उनकी उम्र कम-से-कम 22 वर्ष होनी चाहिए. इस परीक्षण को पूरा होने में करीब 6 वर्ष लगेंगे. इस दौरान प्रतिभागियों को परीक्षण से जुड़े खर्चे जैसे साइट तक आने-जाने का किराया आदि कम्पनी की ओर से दिया जाएगा.

ओजोन प्रदूषण से गेहूँ की उपज 14% तक घट रही है

भारत में वायु प्रदूषण न सिर्फ लोगों की सेहत खराब कर रहा है, बल्कि इससे हमारी खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है. एक ताजा अध्ययन में यह दावा किया गया है.

गेहूँ की फसल

रिपोर्ट के मुताबिक, ओजोन प्रदूषण से भारत में गेहूँ की पैदावार हर वर्ष 14% तक घट रही है. यह अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अशोका यूनिर्सिटी, एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट और जर्मनी के सेंटर फॉर लैण्डस्केप रिसर्च ने मिलकर किया है. फसल की उपज और आर्थिक मॉडल के अनूठे संयोजन का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि वायु से, ओजोन से छुटकारा पाकर, देश की गेहूँ की उपज 14% तक बढ़ सकती है. वहीं खाद्य कल्याण लाभ को प्रतिवर्ष 400 करोड़ से अधिक तक बढ़ा सकती है. इसके अलावा, गेहूँ की आपूर्ति में वृद्धि से खाद्य कीमतों में 43% की भारी गिरावट आ सकती है. अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री डॉ. भरत राम स्वामी ने कहा, ओजोन प्रदूषण को हटाने से मानव स्वास्थ्य और खाद्य कल्याण दोनों के लिए दूरगामी लाभ होंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है.

●●●

उपकार

नवीन प्रस्तुति

उत्तर प्रदेश

सामान्य ज्ञान

एक दृष्टि में

(नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित)

लेखक : डॉ. मानिक लाल गुप्त

कोड 2451 ₹ 50/-

अति विशिष्ट सामग्री के साथ

उपकार प्रकाशन, आगरा-5

E-mail : care@upkar.in Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

कॅरियर लेख

सिविल सेवा परीक्षा चुनौतीपूर्ण, दें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास!

—अतुल कपूर

सिविल सेवा परीक्षा, एक भीषण प्रतियोगिता, निस्संदेह कठिन और आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक लम्बी यात्रा में अपने प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता है. जो लोग जिज्ञासा और रुचि के साथ अपने सपने का पीछा करते हैं, वे तैयारी के प्रत्येक चरण का आनंद लेते हैं; उनमें से कुछ अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँचते हैं और दुनिया को अपनी योग्यता दिखाते हैं.

प्राय:, बड़े परिणाम वह उम्मीदवार ला पाते हैं जिनमें सच्ची रुचि होती है और बड़ी सफलता को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को सार्थक बनाते हैं. उनके लिए, परीक्षा की आवश्यकताओं को सँभालना और तैयारी यात्रा के दौरान प्रेरित रहना आवश्यक है.

जो उम्मीदवार परीक्षा की प्रकृति, इसकी तैयारी के स्तर और लक्ष्य-केंद्रित कड़ी मेहनत को समझता है, उसके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होता है.

तो, कई अज्ञात, आकस्मिक और अप्रत्याशित आश्चर्यों का सामना करने के लिए तैयार रहें.

शुरूआत में, उम्मीदवारों के मन में सुखद व प्रेरक भावनाएं होती हैं, जो आपको अपनी तैयारी-योजना से जोड़े रखती हैं.

लेकिन यह कोई सहज यात्रा नहीं है; कभी-कभी कठिन समय में संघर्ष से सामना करना पड़ता है. इसीलिए कहा जाता है कि इस भीषण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आपको साहस दिखाने की जरूरत है.

यदि यह आपका पहला प्रयास है, तो ध्यान केंद्रित रखें और मन में कोई भी बात नकारात्मक नहीं होनी चाहिए.

आप जो तैयारी कर रहे हैं बस उस परीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सोचें और परीक्षा के प्रत्येक चरण का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए तैयार हो जाएं.

सफलता का मंत्र: सही निर्णय, सही कार्य और सही क्रियान्वयन

आप एक खुली प्रतियोगिता में हैं; शुरूआत से ही दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखना आवश्यक है. यहाँ, यह सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में है जो आपके भाग्य का निर्धारण करेगा. एक बार परिणाम आ जाए, तभी आपको स्पष्ट पता चलेगा कि आप स्वयं को किस पक्ष में पाते हैं—सफलता या असफलता और हाँ, निराशाएँ बड़ी संख्या में होने वाली हैं.

यदि आपका भाग्य चमका और आप विजयी हुए, तो आप कुछ सौ उम्मीदवारों में से होंगे और यह वास्तव में आश्चर्यजनक और समृद्ध अनुभव होगा.

फिर भी एक मोड़ आएगा; भले ही आप सफल हो जाएं, कुछ लोगों के लिए यह लक्ष्य की प्राप्ति होगी. कुछ उम्मीदवार अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे और उनका नाम उस रैंक से जुड़ा हुआ पाया गया जो योग्यता-सूची में नीचे है और प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा में पद पाने के लिए पर्याप्त नहीं है.

बड़ी सफलता के लिए निरन्तर सीखना और ज्ञान प्राप्त करना मायने रखता है

अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि, असमान शैक्षिक पृष्ठभूमि, विभिन्न परिस्थितियाँ, विविध वैकल्पिक विषय और विरोधाभासी व्यक्तित्व; ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेल खाता हो, लेकिन जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की बात आती है, तो उनके द्वारा चुने गए विकल्पों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं.

जब पुस्तकों, अध्ययन सामग्री के चयन, कोचिंग संस्थानों से मार्गदर्शन लेने, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग और उनकी तैयारी-योजनाओं में फोकस, कड़ी मेहनत, निरंतरता और समय प्रबंधन के महत्व की बात आती है, तो आपको कई चीजें समान दिखती हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पहले प्रयास में सफलता प्राप्त कर रहा है या छठे प्रयास में; पहला प्रयास 21 वर्ष की उम्र में या शायद 32 वर्ष की उम्र में; स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद या उच्च डिग्री के बाद परीक्षा में शामिल होने की योजना बनाना; तैयारी के लिए पूरा समय समर्पित करना या पूर्णकालिक काम कर नौकरी के साथ तैयारी के लिए समय निकालना.

प्राय:, मैं नए स्नातकों से मिलता हूँ जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की और शीर्ष रैंक प्राप्त की. मैं कई ऐसे सफल उम्मीदवारों से भी सम्पर्क में रहा हूँ जो कार्यरत् रहे, कुछ ऐसे भी जो वर्षों से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं; फिर भी, असाधारण प्रयास करने में कामयाब रहे और उनको यूपीएससी द्वारा उनके उच्च प्रदर्शन के लिए उचित पुरस्कृत किया गया.

प्रत्येक उम्मीदवार अलग है—अद्वितीय, विशिष्ट; और इनकी परिस्थिति, अवस्था और परिवेश सभी अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं; जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते तब तक आपको बस एक विजेता की मानसिकता और अथक् प्रयासों की आवश्यकता होती है. अपने निर्णयों में दृढ़ विश्वास दिखाना और सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए जुनूनी होना मायने रखता है; यह और कुछ नहीं बल्कि आपकी योग्यताएं, मानसिक शक्ति और दृढ़ता ही है, जो आपको इस परीक्षा में सफल होने में मदद करती है.

यह परीक्षा गौरवशाली अनिश्चितताओं के लिए जानी जाती है.

पाठ्यक्रम को कवर करने के उद्देश्य से, लगभग सभी उम्मीदवार प्रासंगिक पुस्तकें और अध्ययन-सामग्री खरीदते हैं, कुछ उम्मीदवार मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कोचिंग संस्थानों में शामिल होते हैं और ऐसा करके वे सोचते हैं कि वे आई.ए.एस. बनने की राह पर हैं. लेकिन सच तो यह है कि यही गैर-गम्भीर उम्मीदवार भी करते हैं.

जो बात मायने रखती है वह है परीक्षा-योजना के बारे में आपकी स्पष्ट समझ, पाठ्यक्रम के प्रत्येक शब्द को समझना, आपकी अपनी तैयारी-रणनीति और एक प्रभावी अध्ययन-योजना. इसमें शामिल जटिलताओं को समझकर और कुछ सामान्य गलतियों से बचकर आप कह सकते हैं कि आपने अपनी यात्रा सही दिशा में तय की है. केंद्रित कड़ी मेहनत के साथ तैयारी में निरंतरता बनाये रख आप सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं.

सिविल सेवा परीक्षा गौरवशाली अनिश्चितताओं के लिए जानी जाती है; चाहे वह नया उम्मीदवार हो या पहले भी परीक्षा में शामिल हो चुका हो, हर कोई कुछ अंतर्दृष्टि की तलाश में रहता है, जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में मदद कर सके.

पाठ्यक्रम पर टिके रहने से आपको यह महसूस होता है कि तैयारी का स्तर अच्छा है, लेकिन परीक्षा में कुछ विशिष्ट रुझान उभर रहे हैं जहाँ आयोग की अपेक्षाएं सामान्य से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि कुछ उभरते मुद्दे, समसामयिक समस्याएं और विषयों के साथ अंतर-सम्बन्धित

STUDYPDF WALLAH

मुद्दे आपको एक ऐसा अनुभव देते हैं जहाँ आप महसूस करते हैं कि परीक्षक की अपेक्षा और आपकी तैयारी के बीच अंतराल मौजूद है.

अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपको समसामयिक घटनाक्रम और ज्वलंत मुद्दों के लिए एक कदम आगे बढ़कर तैयारी करने की जरूरत है. करेंट अफेयर्स पर पकड़ और आस-पास की चीजों के बारे में जागरूकता समाचार-पत्र पढ़ने की आदतों के महत्व को दर्शाती है जो परीक्षा भवन में प्रश्न-पत्र हल करते समय काम आती है.

इस परीक्षा की तैयारी में कोचिंग की भूमिका पर आते हैं और आपको इसे कैसे देखना चाहिए.

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में कोचिंग आवश्यकता है या उम्मीदवार सिर्फ एक प्रवृत्ति का पालन करते हैं?

सिविल सेवा परीक्षा केंद्रित कोचिंग संस्थान 50-60 वर्ष पहले भी मौजूद थे, लेकिन जैसे-जैसे सिविल सेवा परीक्षा विकसित हुई और यूपीएससी ने नियमित अंतराल पर बदलाव पेश किए, कोचिंग संस्थानों की भूमिका बढ़ती रही. व्यावसायीकरण के साथ, पिछले 2 दशकों में कुछ विशिष्ट महानगरीय शहरों में तेजी से वृद्धि देखी गई, जो कोचिंग संस्थानों के केन्द्र के रूप में उभरे और रिक्तियों और उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने इस विस्तार को बढ़ावा दिया.

यदि आप प्रभावी ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, सीमित समय-सीमा में अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं और कुछ सहायता या यूं कहें कि मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए कोचिंग एक आवश्यकता है.

इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते समय सबसे बड़ा डर यह होता है कि अन्य उम्मीदवारों और उनकी गतिविधियों का सामना कैसे किया जाए. कोचिंग संस्थान आपको एक ऐसा माहौल देते हैं जहाँ आपका और आपके साथियों का लक्ष्य एक समान है और हर कोई परीक्षा में सफल होने के लिए कौशल और दृष्टिकोण सीखता है. आपको कोचिंग संस्थान में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने और परीक्षा के बारे में आपके मन में उभर रहे विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है. समकक्ष उम्मीदवारों के समूह का प्रदर्शन, उनकी वृद्धि, उन्नति और तैयारी में निरंतरता दूसरे उम्मीदवारों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और बड़ी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है.

सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों में परीक्षा के प्रत्येक चरण में सफलता के लिए महत्वपूर्ण कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं. उचित मार्गदर्शन के साथ, उम्मीदवार समय प्रबंधन कौशल विकसित करते हैं, क्योंकि कोचिंग अपेक्षाकृत कम अवधि में तैयारी करना संभव बनाते हैं; संपूर्ण पाठ्यक्रम एक निश्चित समय अवधि में कवर हो जाता है. उत्तर-लेखन अभ्यास और समय पर प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आप परीक्षकों की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम हैं और अभ्यास के साथ कौशल में निखार आता रहें.

अत्याधुनिक दृष्टिकोणों के अमूल्य अनुभव के माध्यम से ये संस्थान उम्मीदवारों को अनुशासित माहौल से जोड़ते हैं और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ कोचिंग वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं और कई उम्मीदवार बड़ी सफलता में उनके योगदान को स्वीकार भी करते हैं.

जब वैकल्पिक विषय की बात आती है, तो अधिकांश उम्मीदवार क्रॉस-डोमेन बदलाव करते हैं और अपने विषय को छोड़ एक नया विषय चुनते हैं. यहाँ, सीमित समय में एक नया विषय तैयार करना रणनीतिक हो जाता है और इसलिए, कोचिंग की विशेष उपयोगिता सामने आती है.

भले ही उम्मीदवार यूपीएससी के उन्मुखीकरण के अनुसार पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में अध्ययन किया गया अपना स्वयं का विषय चुनते हैं, फिर भी वे विशेषज्ञ मार्गदर्शन चाहते हैं. इसका कारण आपके स्नातक के दौरान संचित ज्ञान और वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम में शामिल कुछ अतिरिक्त टॉपिक्स आपसे कुछ अधिक प्रयास की आपेक्षा रखते हैं जहाँ कोचिंग का रोल ऊभर कर आता है.

इसके अलावा, उत्तर-लेखन एक और चुनौती है, क्योंकि आपको शब्द सीमा का पालन करने के लिए सटीक और संक्षिप्त होना होगा.

यह कोचिंग संस्थाएं क्या ऑफर करते हैं

कोचिंग सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अधिक संभावना सुनिश्चित करती है.

याद रहे—आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह आपका है और आप अपने प्रत्येक कार्य के लिए जवाबदेह हैं.

यूपीएससी—सिविल सेवा परीक्षा केंद्रित कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में न रखते हुए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो उन्हें निरन्तर सीखने, नए दृष्टिकोण प्रदान करने और प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाते हैं और विषयों/टॉपिक्स की स्पष्ट समझ विकसित करने में मदद करते हैं. वे आपको ढेर सारे संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं. आपकी प्रथमिकताओं के अनुकूल नोट्स और अध्ययन-सामग्री, करंट अफेयर्स अपडेट, प्रीलिम्स मॉक-टेस्ट, मेन्स टेस्ट-सीरीज के अलावा संरचित अध्ययन-योजना प्रदान करने वाली कक्षाएं जो उम्मीदवारों के प्रदर्शन को बढ़ाती हैं.

इनका उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा—उन्मुख दृष्टिकोण प्रदान करना, आलोचनात्मक नजर विकसित करना और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना है. उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट रखने में निरन्तर कार्य करते हैं जिससे सभी प्रश्न-पत्रों को आत्मविश्वास से हल करने में मदद मिलती है. चाहे वह प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा, इनके लगातार विकसित हो रहे प्रारूप को समायोजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सरल शब्दों में वे उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जो उन्हें उनकी अंतिम सफलता में मदद करता है. ये संस्थान उम्मीदवारों को उनके सबल-पक्ष समझाने और कमजोरियों की पहचान करने पर काम करते हैं, जिससे उन्हें सुधार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है. वे समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उम्मीदवारों को अंतर्दृष्टि और उचित रणनीतियाँ प्रदान करते हैं.

प्रत्येक कोचिंग संस्थान प्रभावी शिक्षा-वितरण के लिए विविध शिक्षण तकनीक विकसित करते हैं और यही उनकी खासियत बन हमारे सामने आती है. वे लगातार नए तरीकों पर काम करते हैं और कई संगठित कोचिंग संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग भी बढ़ रहा है. फोकस उनके पढ़ाने के तरीके पर है; जो अवधारणाएं स्पष्ट समझाए और पाठ्य-सामग्री को समझना आसान बनाए जो अंततः उम्मीदवारों को उनके बेहतर प्रदर्शन में मदद करें. आखिरकार उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवारों को सीमित दिनों और महीनों में पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, जिसकी तैयारी वे आमतौर पर अपनी शिक्षा के दौरान तीन वर्षों में करते हैं. कोचिंग संस्थानों की आवधिक परीक्षण और मूल्यांकन पद्धतियाँ उम्मीदवारों के अध्ययन के साथ तालमेल बिठाती हैं और नियमित मूल्यांकन प्रत्येक उम्मीदवार के विकास पर नजर रखता है.

सटीकता के साथ गति बढ़ाने के लिए प्रीलिम्स मॉक-टेस्ट आवश्यक हैं. ये आपको मजबूत और कमजोर क्षेत्र के बारे में एक वास्तविक तस्वीर देते हैं जो आपको अपनी अध्ययन-योजना को प्राथमिकता देने में मदद

STUDYPDF WALLAH

करता है. यह आपको किसी विशेष क्षेत्र में की गई गलती और उसे दोहराने के बारे में जानकारी देता है जिस पर आप कार्य कर सकते हैं.

इसी तरह, मेन्स टेस्ट-सीरीज आपको प्रेजेंटेशन–कौशल को निखारने और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करती है. इससे समय-प्रबंधन में भी मदद मिलती है, क्योंकि आप लगातार तीन घण्टे तक लिखने का अभ्यास विकसित करते हैं. चाहे प्रीलिम्स मॉक-टेस्ट हों या मेन्स टेस्ट-सीरीज, ये आपको प्रेरक परिस्थितियों में वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव प्रदान करते हैं.

कोचिंग संस्थानों की अनूठी विशेषता यह है कि वे अनुसंधान करते हैं और पिछले वर्षों के प्रश्नों के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति को अपनाते हैं और बदलते रुझानों पर नजर रखते हैं.

सैकड़ों कोचिंग संस्थान, लेकिन बड़ा सवाल यह है किसमें शामिल हों

केवल दावों पर मत जाइए; यहाँ कुछ गलतियाँ हैं जिनसे बचना चाहिए

1. सही संस्थान चुनें–सीखने का सबसे अच्छा मंच है कोचिंग, बशर्ते आप सही जगह पर हों. वहाँ आपको वह सहायता मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं. ऐसे संस्थान का चयन करें, जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो.

इसी तरह, प्रायः बड़े/लोकप्रिय नाम हमेशा आपकी सम्भावनाओं को पूरा नहीं करते और ऐसे में केवल लोकप्रियता के पैमाने पर जुड़ना आपके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है. ऐसे संस्थानों का चयन करें जहाँ उच्च योग्य संकाय सदस्य यूपीएससी की आवश्यकताओं से अच्छी तरह वाकिफ हों.

2. कम फीस के भ्रम में न पड़ें–कभी-कभी केवल कुछ रुपये बचाने के लिए औसत या घटिया कोचिंग संस्थानों के लिए समझौता करना सही निर्णय नहीं है. पैसा अनमोल है; दुनिया को यह दिखाने के लिए इसे बर्बाद न करें कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं.

यहाँ, आपको अनुसंधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके दिमाग में मौजूद विकल्प को छोड़ लागत-लाभ के आधार पर किसी संस्थान में शामिल होना शायद काम नहीं करेगा.

3. कोचिंग किस समय–यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है. आजकल, यह देखा गया है कि 9वीं-10वीं कक्षा में पढ़ रहे किशोर भी सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं और गम्भीर तैयारी शुरू कर देते हैं. यह एक बड़ी परीक्षा है और इसकी परीक्षा-योजना काफी लम्बी है. कोचिंग का समय संभवतः परीक्षा के जितना करीब हो सके उतना होना चाहिए ताकि आप तैयारी का, विशेष रूप से पाठ्यक्रम के गतिशील भाग की तैयारी पर किए गए प्रयासों का पूरा लाभ उठा सकें.

4. कोचिंग पर अत्यधिक निर्भरता–यदि आप सब कुछ कोचिंग संस्थान पर छोड़ देते हैं, तो आप आत्मसंतुष्टि दिखा रहे हैं और एक बड़ी आपदा को बुलावा दे रहे हैं. कोचिंग से मिल रही सहायता के साथ, आपको अपने स्वयं के प्रयास करने होंगे और अवधारणा को समझने के लिए इसका उपयोग करना होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि कक्षा में हर चीज विस्तार से पढ़ाना सम्भव नहीं प्रायः अधिकांश विषयों, टॉपिक्स में रूपरेखा प्रदान की जाती है और उम्मीद की जाती है कि सही से समझने और याद करने के लिए उम्मीदवार इसे घर पर संशोधित करे और इसका विस्तृत अध्ययन और अद्यतन करने के लिए प्रयास करें.

5. कोर्स खत्म होने के बाद कोचिंग से नाता तोड़ लेना–यदि आप वास्तविक कोचिंग संस्थान ढूँढ़ने में सक्षम हैं, तो यह एक बार की घटना नहीं है; यह एक ऐसा रिश्ता है जो तब तक चलता है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती. आपका पाठ्यक्रम समय के साथ समाप्त हो सकता है, लेकिन समर्थन और मार्गदर्शन आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में और उससे आगे भी मदद करता रहेगा.

6. अपनी तैयारियों को मापें–आप कहाँ खड़े हैं, कितनी प्रगति हुई है यह जानने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन आवश्यक है और क्या आप यूपीएससी परीक्षकों की अपेक्षाओं से सामंजस्य बिठा पाने की स्थिति में हैं.

यह आप पर निर्भर है कि आप एक व्यापक पैकेज ले रहे हैं या कक्षाएं अलग और प्रीलिम्स मॉक-टेस्ट या मेन्स टेस्ट-सीरीज में अलग से शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं. हमारे पास प्रभावी मूल्यांकन और वास्तविक फीडबैक के लिए अनुकूलित उत्पाद पेश करने वाले कई विशिष्ट कोचिंग संस्थान हैं.

7. इसे जीवन भर के लिए सीख वाली तैयारी बनाएं–यह आपके इस परीक्षा में शामिल होने के उद्देश्य और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण के बारे में है. यह परीक्षा अद्वितीय है और इस प्रक्रिया में आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ऐसा है जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल होने पर भी आपकी मदद करता है.

यह सीखने और समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के बारे में है. अध्ययन की आदतें, प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने के लाभ और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली समय-प्रबंधन तकनीक आपको जीवन भर मदद करेगी.

अपने निर्णय में तर्कसंगत रहें

दुखद बात यह है कि अवमानक कोचिंग संस्थान कई गुना बढ़ गए हैं जो छात्र समुदाय को लाभ पहुँचाने की बजाय नुकसान ही अधिक पहुँचाते हैं. वे नए उम्मीदवारों के बीच अपर्याप्त जागरूकता, छोटे शहरों और अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों का फायदा उठाते हैं, जो विज्ञापनों, होर्डिंग्स को देख ज्वाइन कर लेते हैं. कम-आय वर्ग के उम्मीदवारों भी जो थोड़ी कम फीस चाहते हैं ऐसे संस्थानों की ओर आकर्षित होते हैं.

कोचिंग संस्थानों के लिए चयन मानदंड हमेशा वहाँ पढ़ रहे उम्मीदवारों का संतुष्टि-स्तर होना चाहिए जो उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहते हैं. परीक्षा में अंतिम चयन एक बड़ा आकर्षण बन जाता है जो कोचिंग की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है.

जो चीज लोकप्रिय संस्थानों को अलग करती है, वह है टॉपर्स का समर्थन, जिसने कोचिंग संस्थानों के लिए अद्भुत काम किया और परिणामस्वरूप उम्मीदवारों का विश्वास जीतते रहे हैं. यहाँ भी एक पेंच है जहाँ कई कोचिंग संस्थान केवल साक्षात्कार कार्यक्रम के आधार पर विज्ञापन देते हैं, जो उन्हें मुफ्त में दिया जाता है और टॉपर्स का अपने संस्थान से होने का दावा करते हैं. मैंने प्रतियोगिता दर्पण के दिसम्बर 2023 अंक में अपने लेख में इस बारे में बात की थी.

आपके संदर्भ के लिए कुछ नकारात्मक पहलु

1. शिक्षण की गुणवत्ता; प्रभावशीलता हर संस्थान की भिन्न होती है

2. उच्च शुल्क संरचना

3. यदि आप अपने शहर से बाहर कोचिंग का विकल्प चुनते हैं तो भोजन/आवास

4. कोचिंग पर निर्भरता विकसित हो जाती है

5. बड़े-बड़े दावे; दावों का अतिशयोक्ति; झूठे वादे

6. संकुचित सीखने के माहौल पर निर्भरता आपके समझ और रचनात्मक/कल्पनाशील कौशल के दायरे को प्रभावित कर सकती है

7. ऐसे माहौल का प्रभाव रटने और याद रखने में हो सकता है, जिससे ज्ञान संचय और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. यह उम्मीदवारों की रचनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की क्षमता को बाधित करता है.

STUDYPDF WALLAH

8. कोचिंग का समायोजन रुख (नए या कमजोर उम्मीदवारों के लिए) प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के लिए सीखने की गति से समन्वय बैठाने के लिए मजबूर करता है

9. एक आकार-सभी के लिए फिट दृष्टिकोण समान परिणाम नहीं देता है; एक नए उम्मीदवार के लिए कोई विषय-वस्तु बहुत विस्तृत लग सकती है, वहीं एक सुशिक्षित उम्मीदवार के लिए यह बहुत बुनियादी लग सकता है

10. मानकीकृत दृष्टिकोण कभी-कभी परीक्षा की माँग (अप्रत्याशितता से निपटने के लिए) को पूरा करने में विफल रहता है

11. बैच का बड़ा आकार उम्मीदवार-संकाय सम्बन्ध को कमजोर करता है

12. विभिन्न संकायों द्वारा साझा की गई विविध राय/रणनीतियाँ

13. प्रीलिम्स मॉक-टेस्ट और मेन्स टेस्ट-सीरीज में शामिल प्रश्नों की गुणवत्ता

14. कभी-कभी, कोचिंग जाना एक निरर्थक प्रयास बन जाता है जो उम्मीदवारों को अपनी शारीरिक/मानसिक कुशल-क्षेम को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करता है.

यदि आप अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में संतुलन नहीं बैठा पाते हैं, तो आपको इसका फल मिलने की संभावना कम ही रहती है.

15. साथियों का प्रदर्शन कभी-कभी चिंता और निराशा पैदा करता है और उम्मीदवारों में कभी-कभी हार मानने की भावना विकसित हो जाती है.

सबसे पहले तो यह पता कर लें कि क्या आपको कोचिंग की बिलकुल भी जरूरत है?

यदि हाँ, तो किस चरण (प्रारंभिक, मुख्य या साक्षात्कार) और क्षेत्र (सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय, निबंध) के लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है या आत्म-संदेह और परीक्षा भय पर काबू पाने के लिए आपको इन सभी प्रश्न-पत्रों के लिए कोचिंग की आवश्यकता है. यदि आप नए हैं, तो कोचिंग संस्थान आपको परीक्षा-योजना, इसमें शामिल जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं और एक अच्छी संरचना अध्ययन-योजना के साथ मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह प्रदान करते हैं जो उम्मीदवारों को विशाल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से कवर करने में मदद करता है.

उन लोगों के लिए जो एक या दो प्रयास करने के बाद कोचिंग में शामिल होते हैं और सफल होने में कठिनाई महसूस करते हैं, यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहाँ आत्मनिरीक्षण के साथ वे उन क्षेत्रों को जान पाते हैं जो कमजोर हैं और तद्नुसार निर्णय लेते हैं.

कड़ी प्रतिस्पर्धा में, यह स्पष्ट है कि कोचिंग सीखने और चरण-दर-चरण विशिष्ट कौशल विकसित करने के बारे में है जो सिविल सेवा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है.

याद रखें, जो आप करने जा रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश है. तो, एक तर्कसंगत निर्णय लें—आप इसे वास्तविक आवश्यकता के रूप में देखते हैं या एक प्रवृत्ति?

फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक-सह-मुख्य परीक्षा को कवर करना)

इतने सारे लोकप्रिय कोचिंग संस्थान एक ही छत के नीचे पाठ्यक्रम के लगभग हर क्षेत्र की पेशकश करते हैं, उम्मीदवार ऐसे फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में शामिल होना पसंद करते हैं. ऐसा करने से, उनका समय और मेहनत बचती है क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर सब कुछ मिल जाता है और कक्षा की समय-सारणी ऐसी होती है कि कोई ओवरलैप नहीं होता है. वे पूरे पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित अध्ययन-योजना के साथ कवर करते हैं और इंटरैक्टिव शिक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पाठ्यक्रम को छोटे भागों में तोड़कर विषय-वार कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम को सीमित समय में प्रबंधनीय बनाया जा सकता है.

व्यवस्थित दृष्टिकोण पूरे पाठ्यक्रम को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ कवर करता है.

हालाँकि, यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक विषय के लिए, कोचिंग में सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों में विशेषज्ञता रखने वाले अच्छे संकाय हों; कुछ उत्कृष्ट हो सकते हैं, कुछ औसत और कुछ रिक्तियों को भरने वाले भी.

विशिष्ट विषय आधारित मॉड्यूल

हाल के दिनों में, उम्मीदवार स्मार्ट हो गए हैं और लागत और समय बचाने के लिए अनुकूलित पेशकश की तलाश में हैं. विभिन्न संस्थानों से अलग-अलग घटक पढ़ने का निर्णय—यह गुणवत्ता और किफायती शुल्क भी सुनिश्चित करता है.

यदि आपको लगता है कि आपको विशिष्ट क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था और नैतिकता में कुछ सहायता की आवश्यकता है, तो पूर्ण फाउंडेशन पाठ्यक्रम में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है; आपके लाभ उठाने के लिए प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट अनुकूलित पेशकशें उपलब्ध हैं. विशिष्ट आवश्यकता के लिए उपयुक्त मॉड्यूल की बढ़ती आवश्यकता के साथ, अधिकांश कोचिंग संस्थान ऐसे छोटी अवधि के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं. यह आपको प्रसिद्ध संकायों तक पहुँचने और आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक मॉड्यूल के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता का लाभ उठाने का अवसर देता है.

आईएएस की तैयारी पर उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो भी देख सकते हैं. इसके अलावा, मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में बहुत सारी जानकारी www.iaspassion.com पर साझा कर रहा हूँ जहाँ मैं नियमित रूप से योगदान देता हूँ. आई.ए.एस. परीक्षा से परिचित होने या अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए आप मुझे ट्विटर हैंडल @atulkpr पर फॉलो कर सकते हैं. मेरा उद्देश्य और प्रयास उभरती जरूरतों को समझना और अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उन्हें सम्बोधित करने का प्रयास करना है. इसलिए, यदि कोई सुझाव, टिप्पणियाँ हों या कोई प्रश्न साझा करने के लिए आप atul@pdgroup.in पर ई-मेल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं.

अस्वीकरण: यह सब एक चेतावनी के साथ आता है कि मैंने जो भी बात यहाँ की है वह कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है; यह उन लोगों के लिए एक सलाह है जो कोचिंग संस्थानों से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं.

क्या कोचिंग जाना जरूरी है?

नहीं, बिलकुल नहीं. बहुत से उम्मीदवार स्वयं-सहायता से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं.

परीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में इतनी जागरूकता उपलब्ध है कि इसके साथ, आप पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए आसानी से एक योजना और रणनीति बना सकते हैं. आपको बस आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ, व्यवस्थित दृष्टिकोण और सही दिशा की आवश्यकता है.

परीक्षा-योजना, पाठ्यक्रम, क्या और कहाँ से पढ़ना है और प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषयों/विषयों में महत्वपूर्ण ओवरलैप को समझना चीजों को प्रबंधनीय बनाता है. स्वयं-सहायता से तैयारी करते समय आपके पास स्वतंत्रता है और अपनी जरूरत के अनुकूल कार्य करने का लचीलापन, लेकिन पुस्तकों और अध्ययन-सामग्री को व्यवस्थित करने, विभिन्न स्रोतों की मदद से नोट्स विकसित करने में काफी समय लग सकता है. पाठ्यक्रम ऐसा है कि आपको कई स्रोतों का संदर्भ लेना होगा और इसे समय-समय पर अद्यतन करना होगा.

स्व-मूल्यांकन के साथ, आप अपने सामर्थ्य, योग्यता, विषय-ज्ञान जो पाठ्यक्रम के क्षेत्रों से मेल खाता है और सुधार की आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं. आप अपने सबल-पक्षों और कमजोरियों की

शेष पृष्ठ 184 पर

STUDYPDF WALLAH

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "लक्ष्य के प्रति ध्रुव निष्ठा, दृढ़ता और लगन के साथ निरन्तर कठिन परिश्रम."

– मुकेश कुमार यादव
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में नौवें स्थान पर चयनित

..... प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता से सम्बन्धित रत्नों का भण्डार है. इसके राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं अद्यतन प्रासंगिक लेख वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है. यह विश्लेषणयुक्त एवं अत्यन्त सारगर्भित पत्रिका है. इसकी समसामयिक वार्षिकी में पूरे वर्ष भर की घटनाओं का संक्षिप्त संग्रह होता है, जो कम समय में दोहराने के लिए सर्वोत्तम है.

प्र. द.–बिहार सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री मुकेश–प्रतियोगिता दर्पण परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद.

प्र. द.–किस तरह और कब आपको सिविल सेवाओं की गरिमा एवं महत्व का अनुभव हुआ ?

श्री मुकेश–जब मैं 2015 में ग्रेजुएशन बाद बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत् था, तभी वहाँ पदाधिकारियों को देखकर सिविल सेवा के पद, महत्व, प्रतिष्ठा, सम्मान व समाज के बेहतरी हेतु उनके योगदान को जाना. तभी से सिविल सेवा में जाने की इच्छा हुई.

प्र. द.–वह क्षण कब आया जब आपने सिविल सेवाओं में कॅरियर की सम्भावनाएं तलाशने का फैसला किया ?

श्री मुकेश–हालाँकि मैं सिपाही पद पर कार्य करते हुए आगे की तैयारी व सिविल सेवा में जाने का फैसला लिया. मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी. इसीलिए मुझे नौकरी के साथ परिवार को मदद करते हुए तैयारी करना था.

प्र. द.–अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या आप पिछले वर्षों की परीक्षा के टॉपर्स के साक्षात्कारों का कोई असर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में अनुभव करते हैं ? इन टॉपर्स में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया ?

श्री मुकेश–इस परीक्षा में Top-10 के अन्दर आने से पूर्व मैं यही समझता था कि टॉपर्स बचपन से सभी सुख-सुविधा सम्पन्न विभिन्न उच्च परिवेश में पले-बढ़े अद्भुत प्रतिभावान लोग होते हैं, लेकिन UPSC में सफल दिव्या तंवर मैम ने मुझे बेहद प्रभावित किया और इस मिथक् को तोड़ दिया, जिससे मैं भी Top-10 में जगह बना पाया.

प्र. द.–सिविल सेवा-केवल यही एक लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री मुकेश–सिविल सेवा की तैयारी नौकरी करते हुए कर रहा था. मैं 2015 में बिहार पुलिस में बतौर सिपाही में चयनोपरांत, 2020 में SSC-CGL-Auditor ज्वाइन करने तक सिर्फ one-day exam. की तैयारी करता था.

प्र. द.–अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री मुकेश–अपने दादा जी को समर्पित करना चाहता हूँ. साथ ही सम्पूर्ण श्रेय अपने माता-पिता, मामा, नाना, गुरुजनों, सगे-सम्बन्धियों के साथ-साथ राज IAS फाउण्डेशन के सन्तोष सर, GCS IAS के अवधेश सर एवं आपके प्रतियोगिता दर्पण मैंगजीन को देना चाहता हूँ.

प्र. द.–इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम क्या रहा ? तैयारी हेतु दिशा एवं सही मार्गदर्शन कहाँ से मिला ?

श्री मुकेश–सर्वप्रथम इसका Syllabus और Previous Year के प्रश्न-पत्रों का गहन अध्ययन किया. साथ ही खुद विभिन्न संदर्भों से अपना सारगर्भित संक्षिप्त नोट्स तैयार किए.

प्र. द.–क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थे और सफलता के प्रति आशावान थे ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री मुकेश–66वीं की तुलना में, 67वीं BPSC का Mains मेरा बेहतर गया था. इससे Final Result में नाम को लेकर तो आश्वस्त था, परन्तु जब Top-10 में अपना नाम देखा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ.

प्र. द.–इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है ?

श्री मुकेश–बिहार प्रशासनिक सेवा > बिहार पुलिस सेवा > बिहार शिक्षा सेवा.

प्र. द.–बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में आज सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी गम्भीरता से तैयारी में लगे रहे. किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

श्री मुकेश–2015 के बाद लगातार किसी-न-किसी नौकरी में रहा हूँ. इसीलिए मैं कभी बेरोजगारी का दंश नहीं झेला, जिसके कारण कभी भी निजी क्षेत्र के बारे में सोचा ही नहीं.

प्र. द.–यह सफलता कितने प्रयासों में प्राप्त की और आप अपने पिछले प्रयासों को किस प्रकार देखते हैं ?

श्री मुकेश–यह मेरा दूसरा प्रयास था. पिछले प्रयास में चयनोपरान्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के रूप में कार्यरत हूँ. पिछले प्रयास ही हमारे सभी कमियों की सीख दे गई, जिसमें लगातार सुधार कर 231 रैंक से 9वीं रैंक हासिल की.

प्र. द.–समय-प्रबन्धन–चाहे वह तैयारी हो या फिर परीक्षा में उत्तर लिखते समय-समय एक महत्वपूर्ण कारक है. क्या आपने इस दौरान समय को लेकर कोई कठिनाई महसूस की ? यदि हाँ, तो कैसे आपने इसका सामना किया ?

STUDYPDF WALLAH

श्री मुकेश–मैं जॉब करते हुए इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था. इसीलिए मैं सुबह, रात एवं छुट्टियों के दिनों में समय का पूर्णतया सदुपयोग करता था. परीक्षा में ससमय उत्तर लिखने की प्रैक्टिस में अलार्म लगाकर तीन घण्टे में उत्तर लेखन पूर्ण करने का प्रयास करता था.

व्यक्ति परिचय

नाम–मुकेश कुमार यादव
पिता का नाम–श्री रामनन्दन यादव
माता का नाम–श्रीमती रामबीसर देवी
जन्मतिथि–10 नवम्बर, 1995
शैक्षिक योग्यता–
हाईस्कूल–2010, BSEB, 81·40%
इण्टरमीडिएट–2012, BSEB, MLAcademy, Darbhanga, 76·20%
बी.ए. –2015, LNMU, Darbhanga, 61·12%
एम.ए.–2020, DDE LNMU, 60·65%

प्र. द.–आपका ऐच्छिक विषय क्या था एवं इसके चुनाव का क्या आधार था ?

श्री मुकेश–मेरा ऐच्छिक विषय हिन्दी साहित्य था. इस विषय में मेरी गहरी रुचि रही एवं UPC-NET भी क्वालीफाई किया हूँ.

प्र. द.–आपने सभी प्रयासों में ऐच्छिक विषय यही रहा या कोई बदलाव रहा ?

श्री मुकेश–66वीं एवं 67वीं दोनों परीक्षाओं में मेरा वैकल्पिक विषय हिन्दी साहित्य ही रहा है.

प्र. द.–आपने प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए क्या योजनाएं बनाईं ?

श्री मुकेश–प्रारम्भिक परीक्षा हेतु मेरी पूर्व से तैयारी रही है. सिर्फ बिहार से सम्बन्धित अध्ययन करना पड़ा. मुख्य परीक्षा हेतु प्रीवियस ईयर के प्रश्न-पत्रों से टॉपिक को एकत्रित कर कुछ गुरुजनों एवं नोट्सों से अपने खुद सारगर्भित नोट्स तैयार किए और इसे बार-बार रिवीजन किया, फिर ऑनलाइन माध्यम से ही टेस्ट दिए. वहीं साक्षात्कार हेतु अपने व्यक्तित्व पर कुछ काम किया. साथ ही दैनिक न्यूज पेपर व घटनाओं से अवगत रहा. इसके अलावा अपना हेजिटेशन दूर करने हेतु कुछ कोचिंग संस्थानों में मॉक भी दिए.

प्र. द.–आपने निबन्ध के लिए किस प्रकार की तैयारी की ? आपने किस विषय पर निबन्ध लिखा एवं उस विषय को ही चुनने का क्या कारण था ?

श्री मुकेश–67वीं BPSC तक वैकल्पिक विषय था. इसकी जगह निबन्ध 68वीं BPSC से लागू हुआ.

प्र. द.–प्रारम्भिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय में किस प्रकार सन्तुलन बनाया ?

श्री मुकेश–मेरी प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी लगभग पूर्व से ही अच्छी रही है. सिर्फ बिहार स्पेशल हेतु सन्दर्भित किताबों का अध्ययन किया. वहीं ऐच्छिक विषय की तैयारी प्रारम्भिक परीक्षा से पूर्व ही कर लिया था.

प्र. द.–निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्या सावधानी एवं रणनीति की जरूरत है ?

श्री मुकेश–निश्चित रूप से गहन अध्ययन करने की जरूरत है. साथ ही परीक्षा में तुक्केबाजी से भी बचना चाहिए.

प्र. द.–साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे की और आपका साक्षात्कार कब था, किस बोर्ड में था एवं क्या-क्या प्रश्न पूछे गए ? क्या आप अपने साक्षात्कार से सन्तुष्ट थे ?

श्री मुकेश–साक्षात्कार हेतु मैं अपने DAF पर मुख्य फोकस रखा. साथ ही समसामयिकी घटनाओं को गहराई से अध्ययन किया. मेरा साक्षात्कार 19-10-2022 को, बोर्ड (अध्यक्ष–सर्व नारायण सर) में था. मुझसे भौतिकी, हिन्दी साहित्य (Optional) एवं राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, समसामयिकी से प्रश्न पूछे गए थे.

व्यक्तिगत विशेषताएं

आपका पसंदीदा व्यक्तित्व	*– डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम.*
सबल पक्ष	*– कठिन परिश्रमी व दृढ़ निश्चयी.*
दुर्बल पक्ष	*– सभी को खुश रखने की कोशिश करना और काम करने की जिद पकड़ लेना.*
रुचियाँ	*– मूवी देखना.*

प्र. द.–किस शैक्षिक स्तर पर सिविल सेवाओं की तैयारी के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए ? आपके अनुसार इस परीक्षा की पूर्ण तैयारी में कितना समय लगना चाहिए ?

श्री मुकेश–एक कहावत है–"जब जागो तभी सवेरा." इसीलिए जब भी समय मिले, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. इस प्रतियोगिता के दौर में कम-से-कम दो से तीन साल निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत करने पर सफलता निश्चित मिलेगी.

प्र. द.–आपके अनुसार विज्ञान और मानविकी विषयों में से किस विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं ?

श्री मुकेश–कहा जाता है विज्ञान विषय ज्यादा अंकदायी रहा है, परन्तु मानविकी विषयों में भी बेहतर अंक प्राप्त किए जा सकते हैं.

प्र. द.–आपके अनुसार इस परीक्षा में हिन्दी माध्यम को लेकर तैयारी करने एवं सफलता प्राप्त करने के बारे में क्या विचार हैं ?

श्री मुकेश–मैं बचपन से लेकर अभी तक हिन्दी माध्यम का ही छात्र रहा हूँ. इस परीक्षा में भी मेरा माध्यम हिन्दी ही था, जिसमें मेरी रैंक-9 रही है और सम्भवतः मैं हिन्दी माध्यम से टॉपर रहा हूँ.

प्र. द.–क्या अभ्यर्थी के परिवार की शैक्षिक, आर्थिक और जनांकिकीय स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है ? यदि हाँ, तो कैसे ?

श्री मुकेश–निश्चित रूप से शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है.

प्र. द.–एक मानक प्रतियोगिता पत्रिका में क्या विशेष सामग्री एवं संकलन की अपेक्षा रखते हैं ?

श्री मुकेश–समसामयिक घटनाओं का विस्तृत व्याख्या, वर्तमान परीक्षाओं का प्रश्न-पत्र, निबन्ध, विचारकों के सारगर्भित विचार आदि का संकलन.

प्र.द.–भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली प्रतियोगिता पत्रिका, प्रतियोगिता दर्पण, को इन मानकों के कितने करीब पाते हैं ? इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे ?

श्री मुकेश–प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका ही मेरी तैयारी का आधार रही है. इसके लेखन को प्वाइंट वाईज लिखकर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए.

प्र. द.–क्या आपने सामान्य अध्ययन के अतिरिक्तांकों की सीरीज का उपयोग किया जो पिछले कई वर्षों से अभ्यर्थियों के बीच बहुत पसन्द की जा रही है ?

श्री मुकेश–अतिरिक्तांक में प्रारम्भिक परीक्षा के समय, समसामयिकी वार्षिकांक एवं मुख्य परीक्षा के समय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया.

प्र. द.–भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या आपने तैयारी और प्रयासों हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की थी ?

श्री मुकेश–नहीं, मैं इस बार 67वीं मेंस परीक्षा देने के बाद अपनी उत्तर लेखन से पूर्ण आश्वस्त था कि फाइनल लिस्ट में कोई-न-कोई पोस्ट मिलेगा, लेकिन रैंक-9 को लेकर आश्वस्त नहीं था.

प्र. द.–आपकी सफलता का मूल-मंत्र क्या है ?

श्री मुकेश–निरन्तर प्रयास, लक्ष्य के प्रति समर्पण, धैर्य व हमेशा ज्ञान अर्जन करने की इच्छा.

शेष पृष्ठ 55 पर

STUDYPDF WALLAH

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "बुलंद इरादा, लक्ष्य-केन्द्रित प्रयास तथा निरन्तर लेखन-अभ्यास"

—महेशानन्द

67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर श्री महेशानन्द ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूलरूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—बिहार लोक सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री महेशानन्द—जी, धन्यवाद.

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है ?

श्री महेशानन्द—मेरी पहली प्राथमिकता बी. ए. एस. थी और दूसरी ए. डी. एस. एस. थी जो अंततः मुझे मिल गई.

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था ?

वैकल्पिक विषय—इतिहास

प्र. द.—आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या रहा ?

श्री महेशानन्द—इतिहास मेरा स्नातक का विषय है. सबसे महत्वपूर्ण कारक विषय में मेरी रुचि थी.

प्र. द.—वैकल्पिक विषय क्वालीफाईंग हो गया है, BPSC का यह कदम उम्मीदवारों को कैसे प्रभावित करेगा ?

श्री महेशानन्द—यह उनकी रुचि पर ही निर्भर करेगा.

प्र. द.— आपने बी पी एस सी के नए पैटर्न को कैसे समझा; इसका उम्मीदवारों की तैयारी के तरीके पर क्या बदलाव पड़ेगा ?

श्री महेशानन्द—अब यह अधिक विश्लेषणात्मक हो गया है. जरूरत एन.सी. ई.आर.टी. पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों पर ध्यान देने की है.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री महेशानन्द—यह मेरा पहला प्रयास था.

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थे और उच्च सफलता के प्रति आशावान थे ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री महेशानन्द—मैं इतना आश्वस्त नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं सफल उम्मीदवारों में से एक होने जा रहा हूँ.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या इनमें से किसी टॉपर से आप प्रभावित हुए ?

श्री महेशानन्द—टॉपर अपनी मेहनत से ही 'टॉपर' बनते हैं. हमें इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए.

प्र. द.—क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आपको सिविल सेवाओं के महत्व का एहसास हुआ था ?

श्री महेशानन्द—जब मैं रक्षा मंत्रालय में कार्यरत् था, उस दौरान मैं सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित हुआ.

प्र. द.—आखिर किस समय आपने 'सिविल सर्विसेज' में कॅरियर बनाने का मन बनाया ?

श्री महेशानन्द—स्नातक के द्वितीय वर्ष में मैंने 'सिविल सर्विसेज' में कॅरियर बनाने का निर्णय लिया.

प्र. द.— क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री महेशानन्द—हाँ निश्चित रूप से मैंने पहले ही प्रयास में इसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था.

प्र. द.—समय प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई ?

श्री महेशानन्द—मुख्य परीक्षा के लिए घर पर उत्तर-लेखन आपकी गति के साथ-साथ विषय-वस्तु को बनाने की कुँजी है. समय प्रबंधन यूपीएससी/बीपीएससी परीक्षा में सफलता का एक बड़ा कारक है.

प्र. द.—इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है शुरू में तैयारी के लिए आपको सही सलाह कहाँ से मिली ?

श्री महेशानन्द—टॉपर्स के इंटरव्यू से मुझे इस परीक्षा के बारे में पता चला और उसी को आधार बनाकर मैंने अपनी रणनीति बनाई.

प्र. द.—प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही ?

श्री महेशानन्द—प्रारंभिक परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों और एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों पर आधारित तैयारी सहायक रही.

प्र. द.—शुरू से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना क्या रही ?

श्री महेशानन्द—मैं प्रीलिम्स से पहले ही मुख्य परीक्षा के लिए तैयार था. यह प्रयास मानक पाठ्य पुस्तकों और बहुत सारे अभ्यास पर आधारित था जिससे मुझे सफलता में मदद मिली.

प्र. द.—आपने निबन्ध के लिए किस प्रकार तैयारी की ?

श्री महेशानन्द—मुख्य परीक्षा से छह महीने पहले एक सप्ताह में एक निबंध लिखने का अभ्यास किया.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की ?

श्री महेशानन्द—मैंने अपना डी.ए.एफ. पूरी तरह से तैयार किया और मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ.

शेष पृष्ठ 55 पर

STUDYPDF WALLAH

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "अटल आत्मविश्वास, अध्ययन की असाधारण रणनीति एवं अथक परिश्रम"

—रजनीश शंकर झा
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, में चयनित होकर श्री शंकर झा ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूलरूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—बिहार सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री रजनीश—जी, धन्यवाद.

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है ?

श्री रजनीश—BAS, BPS, BES, BFS

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था ?

वैकल्पिक विषय—मैथिली साहित्य

प्र. द.—आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या रहा ?

श्री रजनीश—पहले से साहित्यिक अभिरुचि होने के कारण तथा सहज मार्गदर्शन के कारण मैंने मैथिली साहित्य विषय का चयन किया.

प्र. द.—वैकल्पिक विषय क्वालीफाइंग हो गया है, BPSC का यह कदम उम्मीदवारों को कैसे प्रभावित करेगा ?

श्री रजनीश—मैंने जो परीक्षा पास की है, उसमें वैकल्पिक विषय के अंक जुड़ते थे. अब यह क्वालीफाइंग प्रकृति का है, परन्तु छात्रों को इसमें सजग होकर तैयारी करनी चाहिए.

प्र. द.—67वीं BPSC प्रीलिम्स का प्रश्न-पत्र लीक हो गया, इसका आपकी तैयारी के गेम-प्लान पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री रजनीश—मैंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहले ही कर ली थी, जिससे कि मुझ पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री रजनीश—यह मेरा चतुर्थ प्रयास था. इससे पहले मैं साक्षात्कार स्तर तक पहुँचा था.

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थे और उच्च सफलता के प्रति आशावान थे ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री रजनीश—सफलता के मायने सभी के लिए अलग-अलग होते हैं. मेरे लिए सफल होना मेरा अंतिम लक्ष्य था. परिणाम देखने के तुरन्त बाद मैंने अपनी माताजी को यह सूचना दी.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या इनमें से किसी टॉपर से आप प्रभावित हुए ?

श्री रजनीश—सफलता प्राप्त करने से पहले मुझे यह लगता था कि टॉपर्स अलग प्रकृति के होते होंगे, लेकिन अब लगता है कि सभी लोग सामान्य ही होते हैं.

प्र. द.—क्या आप वह क्षण याद कर सकते हैं जब आपको सिविल सेवाओं के महत्व का एहसास हुआ था ?

श्री रजनीश—कक्षा 8 में जब मैं पहली बार DM सर से पुरस्कृत हुआ, तभी से मैंने यह प्रण किया कि मुझे भी एक दिन DM बनना है.

प्र. द.—किस समय आपने 'सिविल सर्विसेज' में कॅरियर बनाने का मन बनाया ?

श्री रजनीश—ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए विधिवत् तैयारी शुरू कर दी थी.

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री रजनीश—मैंने यह ठान लिया था कि जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक प्रयास करते रहना है.

प्र. द.—समय प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई ?

श्री रजनीश—परीक्षा के तीनों स्तर पर समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में आवश्यक होता है कि आप परीक्षा की प्रकृति को समझते हुए अपनी तैयारी की दिशा तैयार करें. प्रारम्भिक परीक्षा के सारे सम्बन्धित टॉपिक्स को कवर करना, मुख्य परीक्षा में उत्तर-लेखन का समग्र अभ्यास और साक्षात्कार में मॉक-इंटरव्यू के माध्यम से बेहतर तैयारी की जा सकती है.

प्र. द.— इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है. शुरू में तैयारी के लिए आपके सही सलाह कहाँ से मिली ?

श्री रजनीश—मैंने इसके लिए आस्था आई. ए. एस. संस्थान से मदद ली तथा प्रतियोगिता दर्पण का भी निरन्तर अध्ययन किया.

प्र. द.—प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही ?

श्री रजनीश—मैंने इसके लिए सारे विषयों की मानक पुस्तकों का अध्ययन किया तथा बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए.

प्र. द.—शुरू से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना क्या रही ?

श्री रजनीश—मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले मैंने विगत् वर्षों के प्रश्नों की प्रकृति को समझा तथा तदनुरूप तैयारी की.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की ?

श्री रजनीश—मैंने कई कोचिंग संस्थानों में मॉक-इंटरव्यू दिए.

STUDYPDF WALLAH

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व	– मेरे माता–पिता
आपका सबल पक्ष	– एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखता
आपका दुर्बल पक्ष	– अधिक भावनात्मक होना
आपकी रुचियाँ	– तबला बजाना, क्रिकेट खेलना

प्र. द.–सिविल सेवा–केवल यही एक मात्रा लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री रजनीश–मैं पहले से ही बिहार में शिक्षक के पद पर कार्यरत् था.

प्र. द.–आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद, आप सिविल सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी, गंभीरता से तैयारी में लगे रहे. आखिर किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

श्री रजनीश–मुझे लगता है कि आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है, परन्तु अगर आप दृण निश्चयी हैं, तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से रोक नहीं सकती.

व्यक्ति परिचय

नाम–श्री रजनीश शंकर झा
पिता का नाम–श्री उमा शंकर झा
माता का नाम–श्रीमती लालिमा देवी
शैक्षिक योग्यता–
10वीं–बीएसईबी, एसबीएचएस सकरा, (2003), (62%)
12वीं–बीएसईबी, बीएस कॉलेज, करूआ, (2007), (52%),
बी.ए./बी.एस.सी–बीआरएबीयू, एलएस कॉलेज, मुजफ्फरपुर, (2010), (67·5%)

प्र. द.–आपकी राय में सिविल सेवा की तैयारी किस शैक्षिक स्तर से शुरू करनी चाहिए और बी पी एस सी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना न्यूनतम समय रखना चाहिए ?

श्री रजनीश–ग्रजुएशन के बाद आप विधिवत् तैयारी कर सकते हैं.

प्र. द.–क्या आपने तैयारी के दौरान प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया ?

श्री रजनीश–मैंने समसामयिकी की तैयारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण का सहारा लिया, जो मेरे लिए गागर में सागर सिद्ध हुआ.

प्र. द.–आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

श्री रजनीश–निरन्तर लगे रहना और किसी भी परिस्थिति में हटना नहीं.

प्र. द.–अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री रजनीश–अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों, गुरुजनों एवं दोस्तों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा.

प्र. द.–कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री रजनीश–अगर आपने एक बार यह सोच लिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो किसी भी परिस्थिति में आप पीछे नहीं हटें. मेरा यह विश्वास है कि अगर मैं सफल हो सकता हूँ तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है.

प्र. द.–आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ●●●

शेष पृष्ठ 52 का

प्र. द.–आपने सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए कौन-कौनसी पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का उपयोग किया ?

श्री मुकेश–ऑनलाइन माध्यम से कई Notes मँगाकर अपने परीक्षा के जरूरत अनुसार टॉपिक की तैयारी के साथ-साथ आपके प्रतियोगिता दर्पण मासिक और वार्षिकांक के साथ-साथ एक दैनिक न्यूज पेपर का अध्ययन किया.

प्र. द.–अपनी दैनिक दिनचर्या के कुछ कार्यों के बारे में बताएं जो तैयारी का अनिवार्य अंग रहे.

श्री मुकेश–मैंने हमेशा नौकरी में रहने के साथ-साथ तैयारी की, इसीलिए सुबह मैं ऑफिस जाने से पूर्व व शाम को ऑफिस के बाद अध्ययन करता था.

प्र. द.–कोई सुझाव या संदेश आगामी अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे.

श्री मुकेश–परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता. हमेशा धैर्य के साथ सही दिशा में तैयारी करते रहे. देर-सबेर सफलता जरूर मिलेगी.

प्र. द.–आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

श्री मुकेश–बहुत-बहुत धन्यवाद.

●●●

शेष पृष्ठ 53 का

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व	– महात्मा गांधी
सबल पक्ष	– मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ
दुर्बल पक्ष	– भावुक होना
रुचियाँ	– क्रिकेट खेलना

प्र. द.–सिविल सेवा–केवल यही एक मात्र लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री महेशानन्द–मैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी कर रहा हूँ.

प्र. द.–आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी गम्भीरता से तैयारी में लगे रहे. आखिर किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

श्री महेशानन्द–सिविल सेवाओं के प्रति मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य था.

व्यक्ति परिचय

नाम–महेशानन्द
पिता का नाम–श्री ओम प्रकाश तिवारी
माता का नाम–श्रीमती ऊषा देवी
शैक्षिक योग्यता–
10th 2014 : सीबीएसई, केवीएस, 97%
12th 2016 : सीबीएसई, केवीएस, 90%
BA/B.Sc. : 2021 डीयू, एसओएल, 85%

प्र. द.–आपकी राय में सिविल सेवा की तैयारी किस शैक्षिक स्तर से शुरू करनी चाहिए और बी पी एस सी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना न्यूनतम समय रखना चाहिए?

श्री महेशानन्द–ग्रेजुएशन के उत्तरार्ध में तैयारी शुरू कर सकते हैं.

प्र. द.–क्या आपने तैयारी के दौरान प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया ?

श्री महेशानन्द–हाँ, प्रतियोगिता दर्पण सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है.

प्र. द.–आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

श्री महेशानन्द–प्रेरित रहना और अंतिम लक्ष्य पर नजर रखना.

प्र. द.–अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री महेशानन्द–मेरे माता-पिता और शिक्षकों के साथ-साथ, मेरे प्रभारी अधिकारी डीडीई एसडब्ल्यूबी-द्वितीय श्री अनिल कुमार को विशेष श्रेय.

प्र. द.–कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री महेशानन्द–

- एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों से कॉन्सेप्ट क्लियर करें.
- रटने रहने के बजाय विश्लेषण करें.

प्र. द.–आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ●●●

STUDYPDF WALLAH

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "दृढ़ इच्छा-शक्ति, उत्साही स्वभाव अनवरत कठिन परिश्रम तथा उसका सूक्ष्म विश्लेषण"

—मोहम्मद फैसल चाँद

67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर श्री मोहम्मद फैसल चाँद ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूलरूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—बिहार लोक सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री फैसल चाँद—प्रतियोगिता दर्पण टीम को धन्यवाद.

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है?

श्री फैसल चाँद—सेवाओं में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार पुलिस सेवा है जिसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा है.

मेरे पिता एक पुलिस अधिकारी (अब सेवानिवृत्त) थे, इसलिए मैंने पुलिस व्यवस्था को करीब से देखा और मुझे समझ में आया कि पुलिस ही वह पहला हाथ है, जो संकट में फँसे किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ती है, इस प्रकार मुझे पुलिस सेवा में सेवा करने के लिए प्रेरणा मिली.

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था ?

वैकल्पिक विषय—मेरा वैकल्पिक विषय मानव विज्ञान था.

प्र. द.—आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या रहा ?

श्री फैसल चाँद—मैं एक ऐसा वैकल्पिक विषय चाहता था, जो मेरे दृष्टिकोण को व्यापक बना सके और साथ ही जिसे सीमित समय में पूरा किया जा सके और ऑनलाइन पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, क्योंकि मैं अपने गृहनगर से स्वयं तैयारी कर रहा था. इस प्रकार मैंने पाया कि मानव विज्ञान मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह स्कोरिंग भी है.

प्र. द.—आपने बी पी एस सी के नए पैटर्न को कैसे समझे; इसका उम्मीदवारों की तैयारी के तरीके पर क्या बदलाव पड़ेगा ?

श्री फैसल चाँद—मैंने 69वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न-पत्र को देखा है और मेरी राय में यह वर्तमान घटनाओं के साथ-साथ बुनियादी बातों को समझने की माँग करता है और यह यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न-पत्र की तरह होता जा रहा है. इसलिए छात्रों को अब अपनी अध्ययन सामग्री में सुधार करने और तथ्यों को रटने से बचने की जरूरत है. मुख्य परीक्षा के लिए भी यही बात लागू होती है, क्योंकि अब सामान्य अध्ययन में निबंध और नए प्रकार के प्रश्न व्यापक ज्ञान आधार की माँग करते हैं.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री फैसल चाँद—यह मेरा पहला प्रयास था.

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थे और उच्च सफलता के प्रति आशावान थे ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री फैसल चाँद—बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बाद मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि लगभग उसी समय मैंने यूपीएससी सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. हालाँकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली होऊँगा कि मुझे 15वीं रैंक मिलेगी. अब मुझे मेरी सपनों की सेवा मिल गई है और मुझे इस परीक्षा में दोबारा शामिल नहीं होना पड़ेगा. उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे केवल उस पल महसूस किया जा सकता है. आप अपने परिवार और दोस्तों की आँखों में जो खुशी देखते हैं, वह आपको और अधिक खुश और संतुष्ट बनाती है.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॅपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या इनमें से किसी टॉपर से आप प्रभावित हुए ?

श्री फैसल चाँद—जीवन बदलने वाली इस घटना से पहले मैंने सोचा था कि टॉपर्स असाधारण होते हैं और मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकता क्योंकि वे प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अब मैं उन उम्मीदवारों तक पहुँचना चाहता हूँ कि अगर मैं टॉपर हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हैं.

वास्तव में यह हासिल करने योग्य है क्योंकि मैंने कभी भी कोई अन्य प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन मैं बीपीएससी टॉपर बन गया, यह केवल मेरी तैयारी में किए गए प्रयासों के कारण हैं.

प्र. द.—क्या आप वह क्षण याद कर सकते हैं जब आपको सिविल सेवाओं के महत्व का एहसास हुआ था ?

श्री फैसल चाँद—कोविड-19 वह घटना थी जब मैंने सिविल सेवकों के काम और प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन में इसके महत्व को देखा. इससे मुझे इस तैयारी के लिए बहुत प्रेरणा मिली.

प्र. द.—आखिर किस समय आपने 'सिविल सर्विसेज' में कॅरियर बनाने का मन बनाया ?

श्री फैसल चाँद—कोविड 19 के दौरान (2020 के अंत में) मैंने सिविल सेवा की तैयारी करने का मन बनाया और तैयारी के लिए अपना पूरा प्रयास देने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी.

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री फैसल चाँद—हाँ, मैंने प्रयास की सीमा 3 के साथ 3-4 वर्ष की समय सीमा रखी थी.

प्र. द.—समय-प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई ?

STUDYPDF WALLAH

श्री फैसल चाँद—मैंने अपने घर पर टेबल घड़ी का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निर्धारित करने का अभ्यास किया. मैंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सैकड़ों टेस्ट सीरीज का अभ्यास किए, इससे मुझे समय प्रबंधन और अपने प्रयास की गति बढ़ाने में मदद मिली.

व्यक्ति परिचय

Name : Md. Faisal Chand
Father's Name : Mr. Md Chand
Mother's Name : Mrs. Shahina Perween
Educational Qualification :
10th : 2012, Jamia Millia Islamia Board. Syed Abid Hussain Senior Secondary School, (89·4%)
12th : 2015, Jamia Millia Islamia Board. Syed Abid Hussain Senior Secondary School, (85%)
B.Tech. : 2019, Jamia Millia Islamia. Jamia Millia Islamia. (9·23/10 [CPI])

प्र. द.—इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है शुरू में तैयारी के लिए आपको सही सलाह कहाँ से मिली ?

श्री फैसल चाँद—मेरे लिए इंटरनेट सलाह का स्रोत है. मैंने विशेषज्ञ सलाह के लिए विभिन्न यूट्यूब चैनलों और टॉपर्स टेलीग्राम चैनल का अनुसरण किया. मेरी प्रारंभिक रणनीति श्री अक्षत जैन आई.ए.एस. 2019 बैच की सलाह पर आधारित थी.

प्र. द.—प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही ?

श्री फैसल चाँद—मेरा दृष्टिकोण बीपीएससी के हाल के पिछले वर्षों के प्रारंभिक प्रश्न-पत्रों का अध्ययन और हल करके वर्तमान पेपर पैटर्न को समझना था. पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों में दिए गए प्रत्येक विकल्प के पीछे के तर्क को समझना और उन्मूलन तकनीक का उपयोग करना.

सबसे महत्वपूर्ण बात ज्ञान का आधार है, जिसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी आदि अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों को पढ़कर और हल करके बढ़ाया जा सकता है.

प्र. द.—शुरू से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना क्या रही ?

श्री फैसल चाँद—मुख्य परीक्षा में मेरा ध्यान अपने उत्तरों के मूल्यवर्धन करने पर था क्योंकि परीक्षा में हर कोई लगभग एक जैसे ही उत्तर लिखने वाला था. इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशें, भारत और बिहार के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आदि परीक्षा में अधिक अंक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

प्र. द.—आपने निबन्ध के लिए किस प्रकार तैयारी की ?

श्री फैसल चाँद—मैंने 68वीं एवं 69वीं बीपीएससी परीक्षा में प्रयास नहीं किया इसलिए मैं इसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. हालाँकि यूपीएससी सीएसई में मैंने टॉपर्स की लेखन शैली और विभिन्न शैलियों के आधार पर दिए गए पुरस्कारों को समझने के लिए मॉक निबंध प्रतियों का उपयोग किया.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की ?

श्री फैसल चाँद—साक्षात्कार की तैयारी अवधि के दौरान मैंने अपने बायोडेटा की प्रत्येक पंक्ति पर शोध किया और सबसे सम्भावित प्रश्नों के तार्किक उत्तर दिए. दूसरे, मैंने दो राष्ट्रीय समाचार पत्र और राज्य समाचारों के लिए एक समाचार पत्र पढ़ा और फिल्टर की गई मुख्य परीक्षा सामग्री को संशोधित किया. आखिरकार मैंने आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी बोलने की शैली में सुधार के लिए मॉक इंटरव्यू भी दिए.

प्र. द.—सिविल सेवा–केवल यही एक मात्र लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री फैसल चाँद—नहीं, मैं सिविल सेवक बनने के अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित था.

प्र. द.—आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी, गम्भीरता से तैयारी में लगे रहे. आखिर किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

श्री फैसल चाँद—मेरे पिताजी के सिविल सेवा कार्य के मेरे करीबी अनुभव ने मुझे आकर्षक और उच्च वेतन वाली कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने और सिविल सेवा परीक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया.

प्र. द.—आपकी राय में सिविल सेवा की तैयारी किस शैक्षिक स्तर से शुरू करनी चाहिए और बी पी एस सी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना न्यूनतम समय रखना चाहिए?

श्री फैसल चाँद—यदि किसी के मन में स्पष्टता है कि मैं सिविल सेवाओं में अपना कॅरियर बनाना चाहता हूँ, तो उसे स्नातक अवधि के दौरान तैयारी के लिए सोचना चाहिए. मेरी राय में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक न्यूनतम समय एक वर्ष है, लेकिन यह अभ्यर्थियों के कौशल के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व —महात्मा गांधी
आपका सबल पक्ष —आत्मविश्वासी और समस्या सुलझाने वाला मनोभाव
आपका दुर्बल पक्ष —टालमटोल करना
आपकी रुचियाँ —समकालीन थ्रिलर और विज्ञान-फंतासी फिल्में और टीवी शृंखला देखना

प्र. द.—क्या आपने तैयारी के दौरान प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया ?

श्री फैसल चाँद—विभिन्न टॉपर्स के सुझावों से मुझे प्रतियोगिता दर्पण के बारे में पता चला. हाँ, मुझे लगता है कि यह मेरी उम्मीद के करीब है.

प्र. द.— आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

श्री फैसल चाँद—मेरी राय में मेरी सफलता का कोई रहस्य नहीं है. यह सब कड़ी मेहनत, स्मार्ट अभिवृति और आत्मविश्वास के साथ लम्बे समय तक की गई पढ़ाई है.

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री फैसल चाँद—मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं गुरुजनों को देता हूँ.

प्र. द.—कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री फैसल चाँद—अपनी तैयारी के पहले दिन से ही आश्वस्त रहें कि आपका नाम अंतिम परिणाम पीडीएफ में होगा और जब आप इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विफलता का सामना करें, तो कभी भी आशा न खोएं, क्योंकि यह अगली बार सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपके लिए एक सीख के रूप में काम करेगा.

प्र. द.—आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ●●●

उपकार कॅरियर डेवलपमेंट सीरीज
महान व्यक्तित्व
महान व्यक्तियों के जीवन पर प्रेरणादायक सामग्री
Code 226 ₹ 140.00
उपकार प्रकाशन, आगरा–2
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

दिव्य दर्पण

संघ एवं राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण

"नियतं कुरू कर्म त्वं कर्म, ज्यायो ह्याकर्मण:.
शरीरयात्रापि च ते न, प्रसिद्धयेदकर्मण:".

अर्थात्—तुम अपने निर्धारित कर्म करो, क्योंकि अकर्म रहने से अच्छा है कि कर्म किए जाएं. तुम्हारे अकर्म होने से इस शरीर, इस जीवन का उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होगा.

सिविल सेवा अभ्यर्थियों हेतु उद्धरण प्रसंग का महत्व : सिविल सेवा में अपना भविष्य देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह उद्धरण एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है, क्योंकि अनेकों बार हम किसी विशेष उद्देश्य/लक्ष्य (सिविल सेवा परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन) से मैदान में तो आ जाते हैं, लेकिन पूरे मनोयोग से मैदान में अपना खेल नहीं खेलते हैं.

अर्थात् अधूरे प्रयास या कर्म से जब हम एक लम्बे समय तक अपने उद्देश्य या लक्ष्य में सफल नहीं होते, तो प्राय: हम अपने आस-पास छोटी-छोटी कमियों को इसके लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं, और स्वयं का मूल्यांकन करना दरकिनार कर देते हैं, जबकि असल कमी उद्देश्य के प्रति हमारे समर्पण, कर्म और जिजीविषा की रहती है. अत: हम जिस भी छोटे-बड़े लक्ष्य को निर्धारित करें उसे पूरे मनोयोग और मेहनत से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए.

राष्ट्रीय घटना

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न—भारत के महानगरों में बढ़ती तलाक की दर के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए इसके कारणों और प्रभावों की चर्चा करें.

उत्तर— भारत में तलाक की दर महानगरों (मेट्रोपोलिटन) में अधिक तेजी से बढ़ रहीं है. उदाहरण के लिए, देश की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष 8 से 9 हजार तलाक के मामले आते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद मुम्बई और बेंगलूरू में सबसे ज्यादा 4 से 5 हजार तलाक के मामले सामने आते हैं. यहाँ पिछले एक दशक में आँकड़े दोगुने हुए हैं.

- वही वैश्विक स्तर पर देखे तो पुर्तगाल में लगभग 10 में से 8 जोड़ों का तलाक होता है. वहीं 2020 के UNIDO सर्वेक्षण से पता चलता है कि पुर्तगाल में तलाक की दर प्रति 100 विवाहों में 91·5 प्रतिशत थी, जो यूरोपीय देशों में सबसे अधिक है.
- वैश्विक तलाक दर के सम्बन्ध में भारत की तुलना करे तो यह दर भारत में मात्र 1·1% ही है. वहीं स्वीडन में यह 54·9%, संयुक्त राज्य अमरीका में 54·8% और रूस में 43·3% है.

भारत में तलाक की दर

- वर्ष 2018 में 1,60,000 परिवारों के सर्वेक्षण से पता चला कि 93% विवाहित भारतीयों ने 'अरेंज मैरिज' की थी, जबकि वैश्विक औसत लगभग 55% था.
- भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 1·1% की वार्षिक तलाक दर अपेक्षाकृत कम है, प्रत्येक 1,000 विवाहों में से केवल 13 विवाह के परिणामस्वरूप तलाक होता है. और पुरुष आमतौर पर इसके शुरूआतकर्ता होते हैं.

भारत में बढ़ते तलाक दर के कारण

- वर्तमान में जैसे-जैसे महिलाएं अपने अधिकारों और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो रही है. वे अधिक स्वतंत्रता और अपने तरीके से जीवन जीने का निर्णय लेती है. ऐसे में स्वाभाविक है कि वे किसी भी दबाव या सामाजिक बँधनों को दरकिनार कर तलाक का निर्णय लेना ही उचित समझती हैं.
- इसके साथ ही तेजी से बढ़ता शहरीकरण और विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूकता के साथ विभिन्न लैंगिक समानता अभियान भी इसके उत्प्रेरक कारणों में प्रमुख है. उदाहरण के लिए 1950 के दशक में संसद में हिन्दू विवाह बिल पारित हुआ, जिसने महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार दिया, बहु-विवाह पर रोक लगाई और तलाक माँगने का अधिकार दिया. इसके बाद वर्ष 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया और पति-पत्नी के बीच सहमति से तलाक की अनुमति दी गई.
- ऐसे क्षेत्र जहाँ मात्र परिवार के सदस्यों की सुलह से अरेंज मैरिज की जाती है वहाँ अनेकों बार ऐसा देखा जाता है कि लड़का या लड़की की किसी बीमारी, मानसिक स्थिति या अन्य जानकारियों को छुपाया जाता है, जो आगे शादी के बाद पता चलने पर तलाक का एक कारण बनता है.
- इसके साथ ही एकल परिवारों की बढ़ती अवधारणा की वजह से देश में दम्पत्तियों वाले परिवारों की तादाद बढ़ रही है. तलाक के बढ़ते मामलों की वजह से सिंगल मदर वाले परिवारों की तादाद भी बढ़ रही है. देश में ऐसे परिवारों की तादाद 5·4 प्रतिशत तक पहुँच गई है. ऐसी महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा है जिनको शादी के बाद पारिवारिक बाधाओं व दूसरी वजहों के चलते काम करने की इजाजत नहीं मिलती. यही वजह है कि एशिया के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले भारत में शादी के बाद काम करने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम है.
- भारत में दहेज की प्रथा अभी भी अभिशाप बनी हुई है. यह भी तलाक का प्रमुख कारण हैं.
- घरेलू हिंसा : पति-पत्नी के बीच होने वाले झगड़े, हिंसा और मारपीट.
- पुरुषों द्वारा अत्यधिक नशा करना जैसे—शराब, ड्रग्स आदि का सेवन करना भी विवाह विच्छेद का एक कारण है.

तलाक और उसके प्रभाव

- वैवाहिक सम्बन्ध के विघटन का उन महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो तलाक के दीर्घकालिक तनाव से पीड़ित हैं, जिसमें घरेलू आय में अनुपातहीन हानि, घर के स्वामित्व को खोने का उच्च जोखिम, पुन: शादी की कम संभावना या सामाजिक डर से पुन: शादी का निर्णय न लेना और अपने बच्चों को एकल पालन-पोषण की अधिक जिम्मेदारियाँ शामिल हैं.
- वर्तमान सामान्य स्थिति से दूसरी विपरीत स्थिति में कोई भी परिवर्तन जीवन में व्यवधान उत्पन्न करता है. तलाक दोनों भागीदारों के लिए एक मनोवैज्ञानिक और मानसिक परेशानी का कारण बनता है. इन तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
- तलाक, एक या दोनों पक्षों के लिए वित्तीय कठिनाइयाँ भी पैदा कर सकता है.

निष्कर्ष

- भारत जैसे देश में अभी भी जहाँ अधिकांश जनसंख्या विशेषता गैर-कामकाजी महिलाएं अपने पुरुष पार्टनर पर वित्तीय रूप से अधिक निर्भर है, इसके साथ ही व्याप्त लैंगिक भेदभाव, अपने अधिकारों के प्रति कम जागरूकता के साथ कानूनी प्रक्रिया में अधिक समय जैसे व्यधान देश में तलाकशुदा महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बनता है. अत: इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर, उनकी शिक्षा, मनपसन्द शादी के लिए समाज

STUDYPDF WALLAH

में स्वीकार्यता और कानूनी रूप से अधिक स्पष्ट और उनके त्वरित किर्यान्वयन जैसे सुधार किए जाने चाहिए.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारत में सर्वाधिक तलाक की दर क्रमशः मुम्बई, दिल्ली और बेंगलूरू में है.
2. वैश्विक स्तर पर यूरोपीय देशों में पुर्तगाल में सबसे अधिक तलाक की दर है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(B)

स्पष्टीकरण

- भारत में तलाक की दर महानगरों (मेट्रोपोलिटन) में अधिक तेजी से बढ़ रहीं है. उदाहरण के लिए देश की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष 8 से 9 हजार तलाक के मामले आते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद मुम्बई और बेंगलूरू में सबसे ज्यादा 4 से 5 हजार तलाक के मामले सामने आते हैं.

राजव्यवस्था

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–वर्तमान में लोक सभा आचार समिति चर्चा में है, इस समिति का इतिहास, इसके कार्य और सीमाओं का उल्लेख करते हुए वर्तमान में सुधार के क्या उपाए हो सकते हैं?

हाल ही में लोक सभा की आचार समिति ने पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जाँच शुरू की है. सांसद पर आरोप है कि उन्हें संसद में सवाल रखने के लिए पैसे मिले थे. इसी आरोप के आधार पर लोक सभा अध्यक्ष ने शिकायत को जाँच और रिपोर्ट के लिए आचार समिति को भेजा है.

लोक सभा की आचार समिति

- लोक सभा की आचार समिति को वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, जिसे सांसदों के अनैतिक आचरण से सम्बन्धित शिकायत की जाँच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था. इसे सांसदों के लिए आचार संहिता तैयार करने का भी काम सौंपा गया था.
- हालाँकि, समिति ने कहीं भी 'अनैतिक आचरण' शब्द को परिभाषित नहीं किया है. आचरण के किसी विशेष कार्य की जाँच करना और यह तय करना कि यह अनैतिक है या नहीं, यह पूरी तरह से समिति पर छोड़ दिया गया है. इस समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और इसके सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता हैं.

नैतिक समितियों का इतिहास

- संसद के दोनों सदनों के लिए ऐसे पैनल के गठन का विचार पहली बार अक्टूबर 1996 में नई दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में रखा गया था. इस बैठक में, कई विधायी अध्यक्षों ने संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों में आचार समितियाँ स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया. सर्वप्रथम राज्य सभा ने 4 मार्च, 1997 को अपना पहला नैतिक पैनल गठित किया, जिसकी शुरूआत 30 मई, 1997 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति के.आर. नारायणन ने किया.
- हालाँकि, लोक सभा को पैनल बनाने में 3 वर्ष का अधिक समय लगा, क्योंकि उस अवधि के दौरान राजनीतिक उथल-पुथल के कारण (भारत ने 1996 और 1998 के बीच तीन प्रधानमंत्रियों को देखा) ऐसे पैनल की स्थापना में देरी हुई.
- आगे लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने नैतिकता पैनल बनाने के लिए 31 जनवरी, 1997 को एक अध्ययन समूह का गठन किया. हालाँकि, अब भी रिपोर्ट को पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि लोक सभा 4 दिसम्बर, 1997 को भंग कर दी गई थी, जबकि रिपोर्ट बाद में 28 मार्च, 1998 को प्रस्तुत की गई थी, 12वीं लोक सभा भी 1999 में भंग कर दी गई थी. अंततः, 13वीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर 16 मई, 2000 को, तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी ने पहली आचार समिति का गठन किया.

शिकायतों के लिए प्रक्रिया

- कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य के खिलाफ किसी अन्य लोक सभा सांसद के माध्यम से कथित कदाचार के सबूत और एक हलफनामे के साथ शिकायत कर सकता है, और यदि ऐसी कोई शिकायत संसद सदस्य स्वयं शिकायत करता है, तो शपथ-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है.
- अध्यक्ष किसी सांसद के खिलाफ कोई भी शिकायत समिति को भेज सकता है. शिकायत की जाँच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, जो सदन से पूछता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए. रिपोर्ट पर आधे घण्टे की चर्चा का भी प्रावधान है.

सांसदों के निष्कासन की प्रक्रिया

- यदि कोई सांसद संसद में प्रश्न रखने के लिए पैसे लेता है, तो वे विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी होंगे. ऐसी शिकायतों को जाँच के लिए हमेशा विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है.
- यह समिति उचित जाँच के बाद सम्बन्धित सांसद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती है.
- यदि संसदीय कार्य के संचालन के लिए अवैध परितोषण से जुड़ा मामला साबित हो जाता है, तो सांसद को सदन से निष्कासित भी किया जा सकता है.
- उदाहरण के लिए, 2005 में एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में लोक सभा के 10 सदस्यों को संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेते हुए दिखाया गया था. शिकायत पर एक विशेष समिति नियुक्त की गई जिसने उन्हें ऐसे आचरण का दोषी पाया और उनके निष्कासन की सिफारिश की, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया. सभी सांसदों को निष्कासित कर दिया गया.

आचार समिति की सीमाएं और चुनौतियाँ

- 'अनैतिक आचरण' के लिए स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव
- समिति कदाचार या कानून के उल्लंघन के अधिक गम्भीर मामलों को सम्बोधित नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अक्सर विशेषाधिकार समिति के पास जाते हैं, जिसके पास अधिक शक्तियाँ और अधिकार हैं.
- समिति स्पीकर द्वारा भेजी गई शिकायतों पर निर्भर करती है और उसके पास स्वतः संज्ञान लेकर पूछताछ या जाँच शुरू करने की शक्ति नहीं है.
- समिति की कार्यवाही गोपनीय है और जनता या मीडिया के लिए खुली नहीं है, जो इसके कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावित कर सकती है.

संसदीय नैतिक आचरण की आवश्यकता

- नैतिकता, वे नैतिक सिद्धांत हैं, जो समाज में व्यक्तियों और समूहों के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं. भारत में, संसद सदस्य (सांसद) लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिन पर कानून बनाने, कार्यपालिका की देखरेख करने और सार्वजनिक हित की सेवा करने की जिम्मेदारी होती है. उनके कार्यों और

STUDYPDF WALLAH

आचरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वे कानून को प्रभावित करते हैं, सार्वजनिक चर्चा को आकार देते हैं और राष्ट्र के लिए नैतिक मानक स्थापित करते हैं. अतः सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संसदीय और सार्वजनिक कर्तव्यों में नैतिकता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखें और हितों के किसी भी टकराव, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से बचें.

वैश्विक स्तर पर पहल

- यूके ने वर्ष 1995 में अपना नैतिक कोड स्थापित किया, जबकि कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी एक समर्पित नैतिकता आयुक्त है. ऐसे ही जर्मनी में 1972 से, संयुक्त राज्य अमरीका में 1968 से अपना कोड है. पाकिस्तान भी सीनेट सदस्यों के लिए एक कोड रखता है. ये वैश्विक प्रथाएं लोकतंत्रों में नैतिक शासन के महत्व को रेखांकित करती हैं.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–आचार समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें–

1. आचार समिति के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है.
2. आचार समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट पर आवश्यकता के आधार पर सदन में 'आधे घण्टे की चर्चा' का प्रावधान किया गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(C)

स्पष्टीकरण

- आचार समिति के सदस्यों का चयन लोक सभा में अध्यक्ष व राज्य सभा में सभापति के द्वारा होता है.
- आचार समिति जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा में सभापति को प्रस्तुत करता है. यदि आवश्यकता है, जो इस पर सदन में 1 घण्टे की चर्चा की जा सकती है.

अन्तर्राष्ट्रीय

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–वर्तमान में चर्चित बेन गुरियन नहर परियोजना की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह कैसे वर्तमान स्वेज नहर का एक विकल्प प्रदान कर सकता है. साथ ही इस प्रस्तावित मार्ग के आर्थिक प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष सम्भावित चुनौतियाँ और इसकी व्यवहार्यता को स्पष्ट करें ?

उत्तर–वर्तमान में बेन गुरियन नहर परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है. यह प्रस्तावित 160 मील लम्बी समुद्र-स्तरीय नहर जिसे स्वेज नहर के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. इस प्रस्तावित नहर परियोजना के तहत भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी (लाल सागर का पूर्वी भाग) से जोड़ने की योजना है.

उल्लेखनीय है कि, 1960 के दशक में उभरी, बेन गुरियन नहर परियोजना की कल्पना एक अभिनव बुनियादी ढाँचा परियोजना के रूप में की गई थी. इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए, इसका नाम इजराइल के संस्थापक पिता और पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन (1886–1973) के नाम पर रखा गया था. इसका उद्देश्य स्वेज नहर का विकल्प प्रदान करते हुए लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच एक वैकल्पिक मार्ग बनाना है. यह यूरोप और एशिया के बीच वर्तमान मौजूदा सबसे छोटे मार्ग स्वेज नहर पर मिस्र के एकाधिकार को चुनौती देकर वैश्विक महासागर की गतिशीलता को फिर से आकार देने की कल्पना करता है.

बेन गुरियन नहर का आर्थिक प्रभाव

- इजरायल के इस प्रस्तावित परियोजना के आलोचकों का मानना है कि इजरायल गाजा पर नियंत्रण करने और हमास को हटाने के बाद इस नहर परियोजना के माध्यम से अपने भविष्य के आर्थिक अवसरों के विकास को तलाश रहा है. एक बार पूरा होने पर, बेन गुरियन नहर परियोजना का वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.

बेन गुरियन नहर के समक्ष चुनौतियाँ और व्यवहार्यता

- राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियाँ बड़ी बाधाएं हैं, जिससे इस नहर का निर्माण कार्य अत्यधिक जटिल और निषेधात्मक रूप से महँगा हो जाता है, जिसका अनुमान $100 बिलियन तक है. राजनीतिक स्थिरता की तात्कालिकता और निरन्तर सैन्य खतरा प्रमुख सुरक्षा चिंताएं हैं. एक अन्य चुनौती इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति है. गाजा पट्टी एक सम्भावित सुरक्षा खतरा है.

स्वेज नहर

- स्वेज नहर एक मानव निर्मित नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण और छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है. नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 10 वर्ष लग गए. नहर का स्वामित्व और रखरखाव स्वेज नहर प्राधिकरण (एससीए) के पास है, जो मिस्र सरकार के अधीन है. स्वेज नहर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है जो वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो सभी वैश्विक कंटेनर यातायात का 30% और प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य का माल का प्रतिनिधित्व करता है.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. वर्तमान में स्वेज नहर का स्वामित्व और रखरखाव स्वेज नहर प्राधिकरण (एससीए) के पास है, जिसका स्वामित्व स्वेज नहर से भूमि साँझा करने वाले सभी देशों के पास है.
2. बेन गुरियन नहर परियोजना को चीन के 'वन रोड, वन बेल्ट' परियोजना के ही एक संयुक्त विस्तारित परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(D)

स्पष्टीकरण

स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसका निर्माण वर्ष 1859 में शुरू हुआ था. वर्तमान में नहर का स्वामित्व और रखरखाव स्वेज नहर प्राधिकरण (एससीए) के पास है, जो मिस्र सरकार के अधीन है. वर्तमान प्रस्तावित बेन गुरियन नहर परियोजना को चीन के 'वन रोड, वन बेल्ट' परियोजना के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है हालाँकि यह इसके संयुक्त विस्तारित परियोजना के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों में अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए सीटीबीटी संधि की पृष्ठभूमि और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए ?

उत्तर–प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 दिसम्बर, 2009 को अपने 64वें सत्र में की गई थी. हालाँकि 16 जुलाई, 1945 को दुनिया के पहले परमाणु बम परीक्षण के बाद से अब तक लगभग 2000

STUDYPDF WALLAH

से भी अधिक परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा चुका है.

वर्तमान में यह सन्दर्भ इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच अनेकों बार परमाणु हथियारों से लैस युद्धरत देशों या किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाले देशों ने परमाणु हथियारों के प्रयोग तक की धमकी दी है.

परमाणु परीक्षण के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि

- 2 दिसम्बर, 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में, संकल्प 64/35 को सर्वसम्मति से अपनाकर 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया.
- इस संकल्प का सार था कि "परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर इसके विनाशकारी और हानिकारक प्रभावों को रोका जा सके" साथ ही 'परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य' को प्राप्त किया जा सके.
- उल्लेखनीय है कि इसकी पहल कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी. उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त, 1991 में सेमिपालाटिंस्क परमाणु परीक्षण स्थल (सोवियत रूस के अधिकार में) के बंद होने के साथ इस तारीख को संरेखित करने के लिए इसका चयन किया गया था. हालाँकि, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस की शुरूआत 2010 में हुई.

परमाणु परीक्षण के खिलाफ महत्वपूर्ण पहल

- 1950 के दशक में, चिकित्सकों और महिला समूहों ने बच्चों के दाँतों में रेडियो आइसोटोप की उपस्थिति सहित वायुमंडलीय परीक्षण के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई. इस अभियान ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि का नेतृत्व करने में मदद की, जो पानी के नीचे, वातावरण और बाहरी अंतरिक्ष में परीक्षण को प्रतिबंधित करती है, लेकिन इसमें भूमिगत परीक्षण प्रतिबंध शामिल नहीं थे.
- परमाणु परीक्षण के खिलाफ एक बड़ा कदम वर्ष 1996 में उठाया गया जब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) को लागू किया गया.

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)

- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) या कांप्रेहेन्सिव टेस्ट बैन ट्रीटी एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है. यह संधि 24 सितम्बर, 1996 को अस्तित्व में आई.

सीटीबीटी : पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने 16 जुलाई, 1945 में दुनिया का पहला सफल परमाणु हथियार परीक्षण किया. इसके 4 वर्ष बाद, सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया. इन दोनों परीक्षणों का परिणाम यह रहा कि इसने दो महाशक्तियों के बीच दशकों से चली आ रही हथियारों की दौड़ को शुरू कर दिया.
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 1945 और 1996 के बीच, 2,000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए जिसमें से अकेले 1,032 संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा और 715 सोवियत संघ द्वारा किए गए. इसमें अन्य देशों जैसे–ब्रिटेन ने 45, फ्रांस ने 210 और चीन ने 45 परीक्षण किए.
- हालाँकि इन परीक्षणों का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इसकी आलोचना और विरोध शुरू हो गया. परिणामस्वरूप, विस्फोटक परीक्षणों पर अंकुश लगाने के कई प्रयास किए गए जिसमें 1963 की सीमित परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (एलटीबीटी) ऐसे पहले प्रयासों में से एक थी. इसने वायुमण्डल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन भूमिगत परीक्षणों की अभी भी अनुमति थी.
- एलटीबीटी की सीमाओं से निपटने के लिए, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि की बातचीत के दौरान एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध पर चर्चा की गई थी. हालाँकि, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ.
- 6 वर्ष बाद, यानि 1974 में अमरीका और सोवियत संघ थ्रेसहोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि (टीटीबीटी) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए, जिसने दोनों देशों को 150 किलोटन से अधिक की क्षमता वाले परीक्षणों पर रोक लगाकर एक परमाणु 'सीमा' स्थापित की. हालाँकि, यह संधि भी अपने परिणामों में अधिक सफल सिद्ध नहीं हुई.
- आगे 1990 के आस-पास जब शीत युद्ध समाप्त होने और सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति का लाभ उठाया और सीटीबीटी को अपनाया, जिसने 10 सितम्बर, 1996 को परमाणु हथियारों के विस्फोटक परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसे 24 सितम्बर, 1996 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया.

क्या सीटीबीटी संधि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने में सफल सिद्ध हुई ?

- सीटीबीटी संधि के बाद से अब तक 10 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संधि के बाद भारत और पाकिस्तान ने 1998 में दो-दो, उत्तर कोरिया ने 2006, 2009, 2013, 2016 (दो बार) और 2017 में परीक्षण किए. संयुक्त राज्य अमरीका ने आखिरी बार 1992 में, चीन और फ्रांस ने 1996 में और सोवियत संघ ने 1990 में परीक्षण किया था. सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अब तक कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है.

किन प्रमुख देशों ने सीटीबीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं ?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संधि को लागू करने के लिए, इसे 44 विशिष्ट परमाणु प्रौद्योगिकी धारक देशों द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिनमें से 8 देशों (चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमरीका) ने अभी तक समझौते की पुष्टि नहीं की है.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के सन्दर्भ में कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?

1. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) भूमिगत परीक्षणों को छोड़कर वायुमण्डल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है.
2. वर्तमान में भारत सहित पाकिस्तान मात्र दो ऐसे देश हैं, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही नहीं है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(D)

स्पष्टीकरण

- सीटीबीटी संधि, परमाणु परीक्षण के सभी माध्यमों पर रोक लगाती है.
- वर्तमान में कुल 8 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

अर्थव्यवस्था

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) समूह की चर्चा करते हुए इस

STUDYPDF WALLAH

समूह में भारत की पूर्ण सदस्यता के सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हुए भारत की व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक रणनीतियों के साथ इसकी सदस्यता कैसे मेल खाती है, अपने तर्कों के आधार पर विश्लेषण करें ?

उत्तर–हाल ही में सयुंक्त राज्य अमरीका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) का शिखर सम्मेलन का समापन हुआ. इस शिखर सम्मलेन में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया. इस सम्मेलन की थीम (2023) 'सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना' रखी गई थी. इसी शिखर सम्मलेन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इससे इतर अमरीका और चीन के बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास में सैन्य-से-सैन्य संचार शुरू करने पर सहमति जताई हैं. उल्लेखनीय है कि भारत एपेक समूह का सदस्य नहीं है. हालाँकि, भारत ने वर्ष 1991 में इस समूह में शामिल होने के लिए अपना आवेदन किया था, लेकिन वर्तमान समय तक भारत को इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है.

एपेक समूह क्या है ?

- एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, या APEC, का गठन 1989 में आस्ट्रेलिया में एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था. इसकी पहली वार्षिक बैठक वर्ष 1993 में सिएटल, वाशिंगटन में हुई थी. जिसकी मेजबानी तत्कालीन अमरीका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने की थी.
- वर्तमान समय में कुल 21 सदस्य हैं.
- **सदस्यता के लिए मानदंड**–प्रत्येक सदस्य को एक सम्प्रभु राज्य के बजाय एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई होना चाहिए.

APEC का महत्व

- अपने गठन के बाद से, समूह ने व्यापार शुल्कों को कम करने, मुक्त व्यापार और आर्थिक उदारीकरण का समर्थन किया है. सियोल घोषणा (1991) में, APEC सदस्य अर्थव्यवस्थाओं ने संगठन के मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रशांत रिम के आस-पास एक उदारीकृत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की है. उल्लेखनीय है कि APEC का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में 47% योगदान है. 1994 में बोगोर, इंडोनेशिया में आयोजित एक बैठक में संगठन का लक्ष्य क्षेत्र के लिए 'मुक्त और खुले व्यापार और निवेश' की उपलब्धि निर्धारित किया गया, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2010 और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2020 की लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई.

APEC समूह और भारत की सदस्यता

- वर्तमान में भारत एपेक का पूर्ण सदस्य न होकर इसको 'पर्यवेक्षक' का दर्जा प्राप्त है. भारत को पहली बार नवम्बर 2011 में पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था. उल्लेखनीय है की भारत ने वर्ष 1991 में APEC में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी. भारत का यह औपचारिक अनुरोध उसकी भौगोलिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के बड़े आकार और एशिया-प्रशांत के साथ व्यापार सम्पर्क के आधार पर किया गया था.

APEC समूह में अब तक भारत के एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल न हो पाने का कारण

- वर्तमान में APEC समूह के अधिकांश सदस्य भारत को एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ देश अपने आर्थिक सुधारों का हवाला देते हुए इस विचार का विरोध करते हैं और उनका आरोप है कि इससे 'संरक्षणवादी प्रवृत्ति' को बढ़ावा मिलेगा. विरोध करने वाले देशों का तर्क है कि APEC का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों द्वारा संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करना और सम्बद्ध एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार उदारीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, और इस उद्देश्य के आधार पर भारत इसकी पूर्ण सदस्य के लिए इसमें फिट नहीं बैठता था. विरोध प्रकट करने वाले सदस्य भारत के आर्थिक सुधारों और डब्ल्यूटीओ की भागीदारी पर भारत के रिकॉर्ड को पर्याप्त नहीं मानता है. इसके अतिरिक्त भारत को समूह का हिस्सा न बनाने का एक अन्य कारण समूह द्वारा वर्ष 1997-98 में और अधिक सदस्यता को बढ़ाने पर रोक भी थी.

भारत की सदस्यता के समर्थन में तर्क

- वर्तमान में समूह के अधिकांश सदस्य यह मानते हैं कि भारत को इसमें एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था में विशेषता 1991 के बाद सुधार और उदारीकरण में प्रगति दिखाई है. साथ ही भारत को पूर्ण सदस्यता का दर्जा देना उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम कर सकता है. इसके अलावा, सदस्य देशों का मानना है कि भारत की समुद्री ताकत और क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत रणनीतिक सम्बन्धों का इस्तेमाल समूह के भीतर रणनीतिक सन्तुलन लाने के लिए किया जा सकता है.

निष्कर्ष

- भारत को इस समूह की पूर्ण सदस्यता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार वार्ता में और अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है. साथ ही भारत को घरेलू संरक्षणवादी और व्यापार सुधार के लिए एक मजबूत, विश्वसनीय, दीर्घकालिक घरेलू क्षेत्र का निर्माण करना होगा. APEC वर्तमान सदस्यों के बीच चिंताओं को कम करने के लिए अपने वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के साथ मुद्दों को सुलझाकर सदस्यता के लिए पुनः अनुरोध कर सकता है. हालाँकि, इस सभी उपायों के बीच भारत को अपने व्यक्तिगत हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संकट के समय भारत के विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार टिकाऊ और न्यायसंगत विकास को प्रभावित न करें.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) समूह के सन्दर्भ में कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?

1. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) समूह की स्थापना और इसकी पहली वार्षिक बैठक वर्ष 1989 में सयुंक्त राज्य अमरीका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी.
2. इसके सदस्यों को एक सम्प्रभु राज्य के साथ एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में समूह की सभी प्रतिबद्धताओं को मानना बाध्यकारी होता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही नहीं है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(D)

स्पष्टीकरण

एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, या APEC, का गठन वर्ष 1989 में आस्ट्रेलिया में एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था. इसकी पहली वार्षिक बैठक वर्ष 1993 में सिएटल, वाशिंगटन में हुई थी. जिसकी मेजबानी तत्कालीन अमरीका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने की थी. यह समूह स्वैच्छिक आधार पर प्रतिबद्धताओं और सर्वसम्मति के माध्यम से लिए गए निर्णयों के साथ गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के आधार पर कार्य करता है.

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–हाल ही में चर्चित 70 घण्टे कार्यसप्ताह के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा करते हुए इसके कार्य-जीवन सन्तुलन, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए सम्भावित चुनौतियों का विश्लेषण करें?

STUDYPDF WALLAH

उत्तर–इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सुझाव दिया कि देश की उत्पादकता में सुधार के लिए भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घण्टे काम करना चाहिए. उन्होंने उदाहरण के तौर पर जर्मनी और जापान का हवाला देते हुए भारत की कार्य उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया. 70 घण्टे का कार्य सप्ताह यानी 6 दिनों के लिए लगभग 12 घण्टे का काम का यह सुझाव जहाँ एक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और भारत जैसे देश जहाँ वर्तमान में उसकी कार्यशील श्रम शक्ति का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् है, इसके कार्य-जीवन सन्तुलन, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर चर्चा का सन्दर्भित करता है.

भारत की श्रम उत्पादकता और कार्य घण्टों की स्थिति

- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डेटा के अनुसार भारतीय श्रम उत्पादकता $8·47 (प्रति घण्टा) है. भारतीय, प्रति सप्ताह औसतन लगभग 48 घण्टे काम करते हैं.
- भारत में समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 के आँकड़ों से पता चलता है कि 15-29 आयु वर्ग के युवा भारतीय वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 7·2 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 8·5 घण्टे काम करते हैं. ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में काम पर खर्च किए गए समय की राज्यवार तुलना ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है. देश में सबसे अधिक कार्य घण्टे उत्तराखण्ड के लोग (प्रतिदिन औसतन 9·6 घण्टे काम) करते हैं.
- वैश्विक स्तर पर देखा जाएं तो फ्रांस में जहाँ औसत कार्यसप्ताह लगभग 30 घण्टे प्रति सप्ताह ही है, लेकिन वहाँ प्रति घण्टा उत्पादकता भारत से कई गुना अधिक (लगभग $58) है. अत : सवाल उठता है कि मात्र कार्य घण्टे बढ़ाने से यह आवश्यक नहीं कि श्रम उत्पादकता में भी वृद्धि होगी.

अधिकाधिक कार्य अवधि की आवश्यकता क्यों ?

- उत्पादकता में वृद्धि.
- उच्च आर्थिक विकास.
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि.
- सरकार के लिए उच्च कर राजस्व की सम्भावना.
- कौशल विकास का अवसर.

अधिकाधिक कार्य करने से नुकसान

- लम्बे कार्य घण्टों के साथ उत्पादकता में गिरावट.
- बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य.
- पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव.
- कम रचनात्मकता और नवीनता.
- काम की गुणवत्ता.
- लैंगिक असमानताओं का बढ़ना.
- शोषण का खतरा.
- समुदाय और समाज पर नकारात्मक प्रभाव.

कार्य-जीवन सन्तुलन और मानसिक स्वास्थ्य

- **प्रौद्योगिकी को अपनाना**–हमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और स्वचालन में निवेश करना चाहिए.
- **कौशल संवर्धन**–श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए कौशल भारत मिशन को ठीक से लागू किया जाना चाहिए.
- **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन**–हमें आवागमन के समय को कम करने और कार्यस्थलों तक पहुँच बढ़ाने के लिए बेहतर परिवहन बुनियादी ढाँचे का विकास करना चाहिए.
- **नवाचार को बढ़ावा देना**–हमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उत्पादों और सेवाओं में सुधार होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी.
- **स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना**–उन गतिविधियों के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें जो आराम और तरोताजा होने में मदद करती हैं, जैसे–व्यायाम, मनोरंजन और प्रियजनों के साथ समय बिताना.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारतीय राज्यों की श्रम उत्पादकता के मामले में केरल की औसत श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है.
2. शहरी क्षेत्रों में काम पर खर्च किए गए समय की राज्यवार तुलना श्रम गहन कृषि क्षेत्र की अधिकता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अभी भी कम है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(D)

स्पष्टीकरण

भारतीय राज्यों की श्रम उत्पादकता में उत्तराखण्ड राज्य की सबसे अधिक श्रम उत्पादकता है. वहीं वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में काम पर खर्च किए गए समय की अवधि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है.

पर्यावरण

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–राजधानी दिल्ली में शीतकालीन धुँध से वायु प्रदूषण के संकट की चर्चा करते हुए इसके लिए जिम्मेदार कारण और मानव स्वास्थ्य पर इसके पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करे. साथ ही इसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए ?

उत्तर–हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली अपने बढ़े हुए वायु प्रदूषण के कारण चर्चा का विषय रहा है. यह वायु प्रदूषण इतना अधिक हो गया कि दिल्ली सरकार को अपने स्कूलों, फुटबाल प्लेग्राउंड आदि तक को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा. कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के उच्चतम पैमाने पर 400 से अधिक हो गया. एक नए अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण संकट का सामना करने वाले भारत के 8 प्रमुख राज्यों की राजधानियों में से, दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में अक्टूबर में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2·5 का स्तर सबसे अधिक रहा है. वर्ष 2021 के बाद से, शहर में पीएम 2·5 के स्तर में लगातार वृद्धि देखी गई है इसमें पिछले वर्ष की तुलना में अक्टूबर 2023 में 4·4% की वृद्धि हुई है.

दिल्ली में होने वाले शीतकालीन प्रदूषण के उत्तरदायी कारण

- पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर बढ़ती जनसंख्या और सम्बन्धित विकासात्मक गतिविधियाँ–इस क्षेत्र का विकास काफी हद तक अनियोजित रहा है और अक्सर, वायुमण्डल में हानिकारक रसायन फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयाँ आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित होती हैं, न कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में.
- वाहन यातायात में वृद्धि (जो दिल्ली मेट्रो के बावजूद कम नहीं हुई है) और इसके परिणामस्वरूप वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है.
- पंजाब और हरियाणा में खेतों में पराली जलाया जाना–रबी की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने और कीटों से निपटने के लिए फसल अवशेषों को जलाने के परिणामस्वरूप–घने धुंध के बादल इस वायु प्रदुषण के प्रमुख कारकों में से एक है, जो हर सर्दियों में उत्तर भारत को घेर लेती है.

शेष पृष्ठ 70 पर

STUDYPDF WALLAH

फोकस 1

तेजी से बढ़ते असुरक्षित उपभोक्ता ऋणों पर लगाम

✍ डॉ. बी. के. अग्रवाल

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2023 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2023 में खुलासा हुआ है कि वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों तथा फिनटेक कम्पनियों द्वारा विगत दो वर्षों में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता ऋण वितरित किए गए हैं और उनमें से एक-चौथाई से भी अधिक बिना किसी जमानत के दिए गए हैं. असुरक्षित ऋण ऋणदाता निकाय के जोखिम को बड़ा देते हैं. वैश्विक स्तर पर अनेक बैंकों और वित्तीय निकायों को असुरक्षित ऋणों के बढ़ते बोझ ने दिवालियापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया.

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2023 के अनुसार मार्च 2021 से मार्च 2023 के बीच खुदरा ऋण 24·8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़े, जो इसी अवधि के दौरान सकल अग्रिमों के लिए 13·8 प्रतिशत की सीएजीआर से लगभग दोगुना है. यह कुल बैंकिंग प्रणाली के सकल ऋण और अग्रिम का लगभग एक-तिहाई हिस्सा था. इस अवधि के दौरान सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिमों की संरचना भी बदल गई है, कुल ऋणों में असुरक्षित खुदरा ऋण का हिस्सा मार्च 2021 में 22·9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 25·2 प्रतिशत हो गया है और इसी अवधि में सुरक्षित ऋणों का हिस्सा 77·1 प्रतिशत से घटकर 74·8 प्रतिशत रह गया है. हालाँकि मार्च 2023 में सिस्टम स्तर पर खुदरा ऋणों का सकल गैर निष्पादनीय आस्ति (जीएनपीए) अनुपात 1·4 प्रतिशत के अपेक्षाकृत निचले स्तर पर था, विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की हिस्सेदारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 7·4 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत अधिक थी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह खुदरा परिसम्पत्तियों के पोर्टफोलियो का दसवाँ हिस्सा था.

कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, ऋण, विशेषकर व्यक्तिगत ऋण की माँग काफी बढ़ गई. वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कम्पनियों ने ऋण चाहने वालों का खुले दिल से स्वागत किया. इसका निबल परिणाम उपभोक्ता ऋणों की उच्च वृद्धि थी और उनमें से असुरक्षित उपभोक्ता ऋणों का अनुपात बढ़ गया.

कुल मिलाकर खुदरा ऋण मार्च 2021 से मार्च 2023 तक 24·8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या सीएजीआर से बढ़े, जबकि समग्र बैंक ऋण के लिए सीएजीआर 13·8 प्रतिशत था. हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों में ऋण वितरण में औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में खुदरा ऋण वितरण को प्राथमिकता प्रदान करने की होड़ लग गई. अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि खुदरा ऋणों में एकाग्रता का निर्माण प्रणालीगत जोखिम का स्रोत बन सकता है.

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय हैं :

- ₹ 50,000 से कम के ऋण के लिए उधारकर्ताओं की 31 से 180 दिनों के बीच ऋण चुकाने में असमर्थता के संदर्भ में मापी गई चूक जून 2023 में बढ़कर 8·1 प्रतिशत हो गई.
- तकनीकी रूप से, यदि उधारकर्ता ने 30 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान किस्त का भुगतान नहीं किया है, तो ऋण विशेष उल्लेख खाता 1 (एसएमए-1) में, 60 दिनों से अधिक भुगतान न करने पर एसएमए-2 में; और 90 दिनों के बाद भी पुनर्भुगतान नहीं करने पर गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति (एनपीए) में बदल जाता है.
- मूलतः, विशेष उल्लेख खाता 1 (एसएमए-1) और विशेष उल्लेख खाता (एसएमए-2) से सम्बन्धित ऋण बढ़ रहे हैं.
- मार्च 2023 तक खुदरा क्षेत्र में खराब ऋण का स्तर 1·4 प्रतिशत था.
- सीआरआईएफ हाईमार्क डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 10,000 से कम के अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) का कुल परिमाण 37 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि ₹10,000-50,000 परिमाण का अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) 48 प्रतिशत बढ़ गया. क्रेडिट ब्यूरो ₹ 50,000 तक के ऋण को अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) मानता है.
- वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 8·6 मिलियन अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) वितरित किए गए, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में वितरित सभी व्यक्तिगत ऋणों में से लगभग 80 प्रतिशत अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) थे और ऐसे 60 प्रतिशत ऋणों का आकार बहुत छोटा था. ₹ 10,000 से कम.
- जून 2023 तक कुल व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो ₹ 11·16 ट्रिलियन का था. मार्च 2020 (कोविड-पूर्व) के स्तर से दोगुने से भी अधिक.

Read Upkar's

LEARN TO WRITE CORRECT ENGLISH

(English-Hindi Medium)

Code 394 ₹ 295.00

CORRECT ENGLISH : HOW TO WRITE IT

(English Medium)

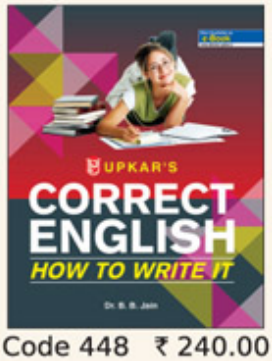

Code 448 ₹ 240.00

LEARN TO WRITE CORRECT ENGLISH

(English-Bangla)

Code 481 ₹ 275.00

By : Dr. B.B. Jain

As the Latest and All Comprehensive Books for All Competitive Examinations.

Purchase from nearest bookseller or get the copy by V.P.P. sending M. O. of ₹100/- on the following address

UPKAR PRAKASHAN, AGRA–5

STUDYPDF WALLAH

- अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) में छोटे शहरों का योगदान अपेक्षाकृत अधिक रहा है. जुलाई 2022 जून 2023 की अवधि के दौरान ₹ 10,000 तक के एसटीपीएल के लगभग 38 प्रतिशत ऋण भारत के शीर्ष 100 शहरों से बाहर के शहरी क्षेत्रों से थे. इसके विपरीत, 29 प्रतिशत अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण (एसटीपीएल) शीर्ष 8 शहरों में वितरित किए गए.
- इस तथ्य का समर्थन करने के लिए कि छोटे शहर इस सेगमेंट में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्रेडिट ब्यूरो का कहना है कि जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच स्वीकृत ₹ 10,000 से ₹ 50,000 के बीच एसटीपीएल का 35 प्रतिशत शीर्ष 100 शहरों से इतर अन्य छोटे शहरों से था, जबकि शीर्ष 8 शहरों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत ही रही है.
- एनबीएफसी ऐसे ऋणों की उत्पत्ति और पोर्टफोलियो पर हावी हैं. उत्पत्ति मात्र के हिसाब से निजी बैंकों की हिस्सेदारी पूर्व-कोविड स्तर से बढ़ी है, लेकिन मार्च 2022 के सापेक्ष इसमें गिरावट आई है.
- स्विस ब्रोकरेज यूबीएस की अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर गम्भीर चिंता व्यक्त की, रिपोर्ट में कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने समकक्ष निजी बैंकों की तुलना में अधिक भुगतान न करने की अधिक चूक दर्ज की. ऐसा माना जा रहा है कि असुरक्षित खुदरा ऋण से क्रेडिट हानि 2024-25 में 50-200 आधार अंक बढ़ सकती है. जून 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने बकाया व्यक्तिगत ऋण का 52 प्रतिशत 644 (मध्यम से उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं) से नीचे क्रेडिट स्कोर वाले उधारकर्ताओं को दिया था, जबकि एनबीएफसी में ऐसे ऋण प्राप्तकर्ता 49 प्रतिशत और बड़े निजी बैंकों में लगभग 31 प्रतिशत थे.
- जनवरी 2022 के बाद से, ₹ 50,000 से कम के छोटे आकार वाले व्यक्तिगत ऋण, कुल खुदरा शेष के बहुत छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए, कुल लगभग एक-चौथाई हो गए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 की जून तिमाही में, छोटे आकार वाले व्यक्तिगत ऋण लेने वाले 51 प्रतिशत उपभोक्ताओं के पास एक और नया ऋण लेने के समय पहले से ही चार से अधिक क्रेडिट उत्पाद थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 की जून तिमाही में यह केवल 17 प्रतिशत था.
- डेलॉयट के सहयोग से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि पिछले 5 वर्षों में 47 प्रतिशत व्यक्तियों ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसियों को सरेंडर कर दिया है. इस बीच, आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की कुल संख्या बढ़ रही है, लेकिन करदाताओं की संख्या कम हो रही है.

असुरक्षित ऋणों में वृद्धि मुख्य रूप से अंडरराइटिंग क्षमताओं में सुधार, डिजिटलीकरण और फिनटेक के बढ़ते उपयोग के कारण हुई है, इनके कारण ऋण देना आसान हो गया है, लेकिन इससे जोखिम भी बढ़ गए हैं. विशेष रूप से एनबीएफसी डिजिटल चैनलों का आक्रामक रूप से उपयोग कर रहे हैं.

स्थिति बद-से-बदतर होती जा रही है. चाहे नियामक-आरबीआई, सरकार-वित्त मंत्रालय या अर्थशास्त्री इसे पसंद करें या नहीं, स्पष्ट रूप से असुरक्षित उधारकर्ताओं के क्षेत्र में तनाव है. अत्यधिक लीवेरेज के लिए कौन जिम्मेदार है ? एनबीएफसी ? फिनटेक ? या फिर बैंक ?

असुरक्षित ऋण में वृद्धि से उपजी चिंता

जैसाकि अतीत में हो चुका है, देश के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ-साथ शाखा स्तर के प्रबंध तंत्र ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋणों की बढ़ती लहर को रोकने के लिए इस आधार पर कोई ठोस प्रयास नहीं किया कि असुरक्षित खुदरा ऋण वाणिज्यिक बैंकों की समग्र क्रेडिट बुक का एक छोटा सा हिस्सा है. अंततः मुख्य नियामक–भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आगे आना पड़ा और सुधारात्मक उपायों की घोषणा करनी पड़ी क्योंकि वह कोई मौका नहीं लेना चाहता है.

अक्टूबर 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के महत्व पर जोर देते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने व्यक्तिगत ऋण के कुछ घटकों की बहुत उच्च वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की. शुरूआती तनाव के किसी भी संकेत के लिए आरबीआई उन पर बारीकी से नजर रख रहा है.

दास ने कहा था, "बैंकों और एनबीएफसी को अपने आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने, जोखिमों के बढ़ने यदि कोई हो, को सम्बोधित करने और अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी जाएगी. बैंकों को जोखिम प्रबंधन और मजबूत हामीदारी मानक (Under Writing स्टैण्डर्ड) अपनानाने के सलाह भी दी. आरबीआई के डिप्टी–गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने भी बताया कि असुरक्षित ऋण अपनी सीमा से बाहर चले गए हैं. असुरक्षित खुदरा ऋण पिछले दो वर्षों में 23 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि निगमों और छोटे और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण जैसे अन्य खण्ड 12-14 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं. छोटे उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता पर बढ़ती चिंताओं के बीच, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने छोटे ऋण पोर्ट फोलियो की समीक्षा करने और इस क्षेत्र में मामलों की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. हालाँकि, बैंकरों ने मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि उन्हें छोटे असुरक्षित ऋणों से उत्पन्न होने वाला कोई प्रणालीगत जोखिम दिखाई नहीं दिया है क्योंकि असुरक्षित खुदरा ऋणों का समग्र जोखिम आकार छोटा है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण (आवास, शिक्षा, वाहन और स्वर्ण ऋण को छोड़कर) के लिए जोखिम भार बढ़ाया.

आरबीआई ने 16 नवम्बर, 2023 को वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए.

(A) उपभोक्ता ऋण जोखिम

(a) वाणिज्यिक बैंकों का उपभोक्ता ऋण जोखिम–वाणिज्यिक बैंकों पर लागू मौजूदा निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ता ऋण पर 100% जोखिम भार लगता है. समीक्षा करने पर, वाणिज्यिक बैंकों के उपभोक्ता ऋण जोखिम (बकाया और साथ ही नए) के सम्बन्ध में जोखिम भार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण भी शामिल हैं, लेकिन आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण सोने के आभूषणों और सोने द्वारा सुरक्षित ऋण को छोड़कर, जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़कर 125% कर दिया गया है.

(b) गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों का उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर–मौजूदा मानदंडों के संदर्भ में, एनबीएफसी के ऋण एक्सपोजर पर आम तौर पर 100% का जोखिम भार लगता है. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि आवास ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, सोने के आभूषणों के विरुद्ध ऋण और माइक्रोफाइनेंस/एसएचजी ऋणों को छोड़कर, खुदरा ऋण के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी (बकाया और साथ ही नए) के उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर पर जोखिम भार 100% से बढ़ा कर 125% कर दिया गया है.

(c) क्रेडिट कार्ड प्राप्य–मौजूदा निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के क्रेडिट कार्ड प्राप्य पर 125% जोखिम भार लगता है, जबकि एनबीएफसी पर 100% का जोखिम भार लगता है. समीक्षा करने पर, एससीबी और एनबीएफसी के लिए ऐसे एक्सपोजर पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर क्रमशः 150% और 125% करने का निर्णय लिया गया है.

(B) एनबीएफसी को बैंक ऋण

मौजूदा मानदंडों के संदर्भ में, मुख्य निवेश कम्पनियों को छोड़कर, एनबीएफसी

STUDYPDF WALLAH

को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एक्सपोजर, मान्यता प्राप्त बाहरी क्रेडिट मूल्यांकन संस्थानों (ईसीएआई) द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित होता है. समीक्षा करने पर, उन सभी मामलों में एससीबी के ऐसे एक्सपोजर पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंक (दिए गए बाहरी रेटिंग से जुड़े जोखिम भार से अधिक) तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जहाँ एनबीएफसी की बाहरी रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100% से नीचे है. इस प्रयोजन के लिए, आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) को दिए गए ऋण और एनबीएफसी को दिए गए ऋण जो मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र है, को बाहर रखा जाएगा.

(C) क्रेडिट मानकों को मजबूत करना

(a) विनियमित संस्थाएं (आरईएस) उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी मौजूदा क्षेत्रीय जोखिम सीमाओं की समीक्षा करेंगी और यदि पहले से मौजूद नहीं है, तो उपभोक्ता ऋण के तहत् विभिन्न उप-खंडों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में लागू की जाएंगी, जैसाकि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है. विशेष रूप से, सभी असुरक्षित उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए सीमाएँ निर्धारित की जाएंगी. जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा और निरंतर आधार पर निगरानी की जाएगी.

(b) विनियमित संस्थाओं (आरईएस) द्वारा चल संपत्ति, जो स्वाभाविक रूप से मूल्यह्रास प्रकृति की है, जैसे वाहनों के खिलाफ दिए गए सभी टॉप-अप ऋण को क्रेडिट मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमा और एक्सपोजर उद्देश्यों के लिए असुरक्षित ऋण के रूप में माना जाएगा.

प्रस्तर सी(ए) के अलावा उपर्युक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. सभी विनियमित संस्थाएँ जल्द से जल्द **प्रस्तर** 2सी(ए) के प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रयास करेंगे.

जोखिम भार एक उपकरण है, जिसका उपयोग प्रायः आरबीआई द्वारा कुछ प्रकार के ऋण देने में ऋणदाताओं के अति-उत्साह पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, जब रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ते जोखिम ने सम्पत्ति की गुणवत्ता और संभावित प्रणालीगत जोखिमों के बारे में चिंताएं पैदा कीं, तो वाणिज्यिक अचल संपत्ति के जोखिम पर बैंकों के जोखिम भार को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर जुलाई 2005 में 125 प्रतिशत और फिर अप्रैल 2006 में 150 प्रतिशत कर दिया गया. इससे पहले, दिसंबर 2004 में आवास ऋण पर जोखिम भार 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था. यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी द्वारा किया गया था. उन्होंने उपभोक्ता ऋण और बैंकों के पूँजी बाजार एक्सपोजर के लिए जोखिम भार को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया था.

आरबीआई के निर्णय के निहितार्थ

वित्तीय विवरण में बताई गई कुल सम्पत्ति और कुल जोखिम भारित सम्पत्ति अलग-अलग घटक हैं. प्रत्येक परिसम्पत्ति वर्ग का जोखिम भार अलग-अलग होता है. उदाहरण के लिए, होम लोन के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हो सकता है, गोल्ड लोन के लिए यह 75 प्रतिशत है. कॉर्पोरेट ऋणों पर जोखिम को देखते हुए 100 प्रतिशत जोखिम भार है. जोखिम भार यदि कम होता है, तो ब्याज दर नीची रहती है. इसलिए, जोखिम भार ऋणदाताओं पर प्रत्यक्ष रूप से और उधारकर्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और ऋण की लागत के रूप में महसूस किया जाता है. उदाहरण के लिए, खुदरा उत्पादों के बीच होम लोन की ब्याज दर सबसे कम है, क्योंकि इस सेगमेंट में नीचा जोखिम भार बैंकों को पूँजी खपत का लाभ देने की अनुमति देता है. व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड पर उनकी अवधि और पूँजी पर अधिक जोखिम भार के कारण ब्याज दर सबसे अधिक होती है. नई जोखिम भार सीमा के कारण मौजूदा स्तर से 35-100 बीपीएस अधिक पूँजी की आवश्यकता हो सकती है. हालाँकि, चूंकि ऋणदाता अच्छी तरह से पूँजीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूँजी पर्याप्तता मार्च 2023 में 17·1 प्रतिशत के स्तर पर थी (8 प्रतिशत वैधानिक सीमा से कम-से-कम 800-900 बीपीएस ऊपर) जब कि निजी बैंकों की पूँजी पर्याप्तता मार्च 2023 में 18·6 प्रतिशत के स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 15·5 प्रतिशत के स्तर पर थी. इस लिए वर्तमान मानकों के अनुसार जोखिम भार के अनुरूप पूँजी रखने लिए अतिरिक्त पूँजी जुटाने के आवश्यकता सम्भवतया नहीं होगी.

आरबीआई के नवीनतम निर्णय से वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के अलावा, फिनटेक संस्थाओं को हानि हो सकती है, क्योंकि इन संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला अधिकांश ऋण असुरक्षित ऋण श्रेणी में आता है. सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एण्ड लर्निंग (कैफ्राल)–आरबीआई प्रवर्तित निकाय ने अपनी प्रथम 'इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट (आईएफआर) में कहा है कि फिनटेक कंपनियों ने उपभोक्ता और खुदरा बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है. उनका ऋण "2030 तक पारम्परिक बैंक ऋण से अधिक होने" का अनुमान है, अब, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) के मामले के विपरीत, फिनटेक द्वारा खंडित ऋण डेटा प्राप्त करना कठिन है. नए जमाने की ये कम्पनियाँ ज्यादातर क्रेडिट इतिहास वाले नए ग्राहकों का लाभ उठाती हैं. वे अच्छी स्थिति में हैं : फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के अनुसार, इसके सदस्यों ने Q1 FY24 में ₹ 29,875 करोड़ का ऋण दिया, जो साल-दर-साल 81·41 प्रतिशत अधिक है.

वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी को ऋण देने में सावधानी बरतनी होगी, विशेषकर उन लोगों को जो समय पर पुनर्भुगतान की गारंटी दिए बिना सार्वजनिक धन का उपयोग करना चाहते हैं. चूँकि फिनटेक कम्पनियाँ बैंकों और एनबीएफसी से क्रेडिट के जरिए फण्ड माँगती हैं, इसलिए उन्हें आरबीआई के नए फैसले का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आरबीआई ने उन सभी मामलों में जहाँ मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम है, एनबीएफसी में बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक (दिए गए बाहरी रेटिंग से जुड़े जोखिम भार से अधिक) बढ़ा दिया है. वर्तमान में, 'एएए,' 'एए,' और 'ए' रेटिंग वाले एनबीएफसी के लिए ये 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है. आरबीआई का सर्कुलर कम रेटिंग वाली एनबीएफसी (इस समूह में फिनटेक कम्पनियाँ आती हैं) पर चुप है, लेकिन इसकी सम्भावना नहीं है कि बैंक उन्हें इसमें शामिल करेंगे.

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूँजी पर्याप्तता ₹ 15·2 लाख करोड़ से अधिक है भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति बैंको क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड प्राप्य और गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियाँ (एनबीएफसी) के जोखिम भार को बढ़ाने के फैसले के बाद इसमें लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी जिससे बैंकिंग उद्योग को लगभग ₹ 84,000 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी.

आरबीआई परिपत्र सामान्य रूप से उपभोक्ता ऋण को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और सोने और सोने के आभूषणों द्वारा सुरक्षित ऋण शामिल नहीं हैं. इन क्षेत्रों में ऋण की मात्रा को छोड़कर, उपभोक्ता ऋण मई 2022 से 25 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रहा था. आरबीआई के कदम से प्रभावित ये असुरक्षित ऋण (₹ 14·8 लाख करोड़) सितम्बर 2023 तक कुल बकाया ऋण (₹ 151·5 लाख करोड़) का केवल 9·8 प्रतिशत है. व्यक्तिगत ऋण श्रेणी का प्रभावित हिस्सा कुल व्यक्तिगत ऋण ₹ 48·3 लाख करोड़ का केवल 31 प्रतिशत है.

आरबीआई द्वारा उठाए गए वर्तमान नियामक कदमों को प्रतिचक्रीय उपाय कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाहियाँ

शेष पृष्ठ 89 पर

STUDYPDF WALLAH

फोकस 2

1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा

✍ डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान

राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी. पात्रा का आकलन है कि जनसांख्यिकीय लाभ और वित्तीय क्षेत्र के विकास की गति से सहायता प्राप्त, भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और बाजार विनिमय दर के मामले में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. इस लक्ष्य को अकेले केन्द्र सरकार के प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता. भारतीय अर्थव्यवस्था को इस स्तर तक पहुँचाने में देश के 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों की भी भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी. वर्तमान में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक प्राचलों के मामलों में बड़े स्तर की विभिन्नताएं हैं. तटीय राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जहाँ औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विकास के मामले सहित उच्च विकास दर के मामले में अग्रणी राज्य हैं, तो कृषि विकास के मामले में में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है. भौगोलिक आकार, श्रम बल का आकार, उच्चस्तरीय आधारिक अवसंरचना की उपलब्धता को देखते हुए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता और आकांक्षा रखते हैं. हालाँकि यह लक्ष्य बड़ा है, और संसाधन सीमित हैं, लेकिन यदि इन राज्यों की सरकारों की नीतियों में दूरदर्शिता, एकाग्रता, पारदर्शी शासन, लक्ष्यों के प्रति समर्पण है, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि इस महती लक्ष्य को प्राप्त न किया जा सके.

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन राज्यों को रुपए के सामान्य अवमूल्यन के दृष्टिगत 30 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करनी होगी. यदि रुपए की विनिमय दर में गिरावट का यही दौर रहता है, तो इन राज्यों को इससे भी ऊँची विकास दर हासिल करनी होगी. यह आकांक्षा काल्पनिक लग सकती है. फिर भी, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य राज्यों को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासन की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं.

विकास के प्राचल

1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की इस आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित प्राचलों पर विचार किया जाना चाहिए–

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का स्तर और इसकी संरचना, जिसमें पिछले दशक में हासिल की गई सर्वोत्तम सम्भव वृद्धि शामिल है.
- श्रम बल का स्तर और उसकी संरचना.
- जीएसडीपी के सापेक्ष संस्थागत ऋण.
- राज्य का पूँजीगत व्यय.
- नीतिगत गतिशीलता.
- प्रशासनिक तंत्र की प्रभावशीलता.

तालिका-1 में इन प्राचलों के आधार पर राज्यों की विकास सम्भाव्यता का आकलन किया गया है–

तालिका 1 से ज्ञात हो रहा है कि वर्ष 2021-22 में ₹ 3124746 करोड़ की जीएसडीपी के साथ महाराष्ट्र न केवल इन 5 राज्यों में वरन सारे देश में शीर्ष स्थान पर है, महाराष्ट्र की जीएसडीपी अन्य 4 राज्यों की जीएसडीपी से लगभग डेढ़ गुना है. 2011-12 से 2021-22 के दौरान इन राज्यों की जीएसडीपी वृद्धि का औसत सीएजीआर महाराष्ट्र के लिए 9·3 प्रतिशत से लेकर कर्नाटक के लिए 13 प्रतिशत तक रहा है. अखिल भारतीय सीएजीआर 10·3 प्रतिशत की तुलना में यह उत्तर प्रदेश में 10·2 प्रतिशत, तमिलनाडु में 11·2 प्रतिशत और गुजरात में 11·8 प्रतिशत रहा है. इतना ही नहीं, इनमें से प्रत्येक राज्य ने बीच के वर्षों के दौरान जीएसडीपी में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो इस बात का सूचक है कि ये राज्य भविष्य में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की सम्भाव्यता रखते हैं.

वृद्धिशील उत्पादन गम्भीर रूप से निवेश पर निर्भर करता है. चूँकि राज्य माँग पक्ष से जीएसडीपी का अनुमान प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए संस्थागत ऋण प्रवाह के अलावा राज्य के पूँजीगत व्यय के प्रॉक्सी चर के माध्यम से निवेश स्तर की गणना की जा सकती है. संस्थागत ऋण प्रवाह के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं, जबकि पूँजीगत व्यय के मामले में उत्तर प्रदेश समूह के अन्य राज्यों से बहुत आगे है. वर्तमान में, इन सभी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निजी निवेश का स्तर नीचा है. जहाँ तक इन राज्यों की आर्थिक प्रोफाइल का सवाल है, गुजरात और तमिलनाडु में अपेक्षाकृत जीवंत द्वितीयक क्षेत्रक है, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेवाएं क्षेत्रक प्रमुख हैं. उत्तर प्रदेश

तालिका–1 : अर्थव्यवस्था का ढाँचा

प्राचल			महाराष्ट्र	तमिलनाडु	कर्नाटक	गुजरात	उत्तर प्रदेश
सकल राज्य घरेलू उत्पाद		2021-22 ₹ करोड़	3124746	2065436	2049379	1886106	1863221
प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर		2021-22 %	14·00	13·80	17·4	17·7	14·4
राज्य सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रक हिस्सा	प्राथमिक क्षेत्र	2021-22 %	15·6	13·1	14·7	20·1	28·4
	द्वितीय क्षेत्र		24·4	32·1	19·2	44·2	24·4
	सेवा क्षेत्र		60·1	54·7	66·5	35·7	47·2
राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	पूँजीगत व्यय	%	1·62	2·12	2·26	1·81	3·75
	गैर-खाद्य साख		102·4	53·7	38·9	33·8	29·6
साख जमा अनुपात		%	90·9	101·6	60·6	69·9	43·6
कार्य बल सहभागिता दर WPR		%	42·6	46·0	43·5	43·3	34·5
नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2020-21 का स्कोर		स्कोर	70·0	74·0	72·0	69·0	60·0

STUDYPDF WALLAH

की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान है. विगत् 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आधारिक अवसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. उत्तर प्रदेश को अब देश में एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में एक नई पहचान मिली है. यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश का लगभग प्रत्येक जनपद विश्व स्तरीय राजमार्गों के माध्यम से देश के सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों, बंदरगाहों से जुड़ गया है. उत्तर प्रदेश के 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे–लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर (निर्माणाधीन) तथा अयोध्या (निर्माणाधीन) एवं 6 घरेलू हवाई अड्डे प्रदेश के विभिन्न भागों को देश और विदेश के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों से जोड़ते हैं. आधारिक अवसंरचना के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात पहले से ही विकसित राज्य हैं चूँकि ये सभी राज्य तटीय राज्य हैं, देश के 8 बड़े बन्दरगाह–कांडला (गुजरात), मुंद्रा (गुजरात), मुम्बई (महाराष्ट्र), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (महाराष्ट्र), न्यू मंगलोर पोर्ट (कर्नाटक), तूतीकोरिन (तमिलनाडु), एन्नोर (तमिलनाडु) तथा चेन्नई (तमिलनाडु) समूह के चार राज्यों–गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में हैं, जो इन्हें उत्तर प्रदेश की तुलना में लोजिस्टिक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं. ऐतिहासिक साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि समुद्र और महासागरों के माध्यम से शेष विश्व के साथ जुड़ कर यूरोप के अनेक देशों में आर्थिक और सैन्य शक्ति हासिल कर तीसरे विश्व के अनेक देशों पर शासन किया.

कमजोर निजी निवेश को देखते हुए, राज्यों का उच्च पूँजीगत व्यय केवल विकास को सीमित गति प्रदान करता है. इसके अलावा, संस्थागत ऋण की कम पहुँच और कम ऋण-जमा अनुपात राज्यों को बैंकिंग प्रणाली के लिए अधिक नकदी संग्रह का केन्द्र मात्र बनाता है और यह संकेत भी देता है कि नीचे साख-जमा अनुपात वाले राज्यों के बैंक ऐसे ग्राहकों को खोज पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, जो निवेश के लिए अधिक पूँजी की माँग करते हैं.

कार्यबल सहभागिता दर

उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए एक अन्य योगदान कारक कार्यबल सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) है. उत्तर प्रदेश में कार्यबल सहभागिता दर 34·5 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 39·8 प्रतिशत से नीचा है. उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता दर 16·2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 24·2 प्रतिशत से भी कम है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उच्च विकास दोनों के लिए उच्च कार्यबल भागीदारी आवश्यक है.

इन राज्यों में नीतिगत गतिशीलता की कमी नहीं है. बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2020 के अनुसार, सात राज्यों–आंध्र प्रदेश, **गुजरात**, हरियाणा, **कर्नाटक**, पंजाब, तेलंगाना और **तमिलनाडु**–को राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 'शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था. हिमाचल प्रदेश, **उत्तर प्रदेश**, ओडिशा और मध्य प्रदेश रैंकिंग में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किए गए अन्य राज्य हैं.

इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश पहले 7 राज्यों में शामिल हैं, जबकि गुजरात 14वें स्थान पर है. उत्तर प्रदेश ने एक नई औद्योगिक और निवेश नीति की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश का बोझ साझा करते हुए निवेश दर को 43-47 प्रतिशत तक बढ़ाना है.

प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को अपने प्रदेश में निवेश करने के लिए अनेक प्रकार की रियायतों के साथ विशेष शिखर सम्मेलनों का आयोजन करती रहती है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को इसका लाभ भी मिला है निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, लेकिन घोषणाओं से अधिक, वास्तविक प्रवाह मायने रखता है. उत्तर प्रदेश का 38% हिस्सा भारत के पहले दो समर्पित माल ढुलाई गलियारों के प्रभाव क्षेत्र में आता है–दिल्ली और मुम्बई के बीच चलने वाला पश्चिमी गलियारा और लुधियाना और कोलकाता के बीच चलने वाला पूर्वी गलियारा, जो इसे देश के दूरदराज के हिस्सों से जोड़ता है. केन्द्रीय बजट 2023-24 के रेल बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा आवंटन ₹ 17,507 करोड़ का मिला है.

उत्तर प्रदेश में कई स्थानीय रूप से विशिष्ट व्यवसाय समूह हैं जैसेकि मेरठ में खेल के सामान, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, कन्नौज में इत्र, कानपुर में चमड़ा, आगरा में जूते, वाराणसी में कढ़ाई वाली साड़ियाँ, भदोही में हाथ से बुने हुए कालीन, लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई आदि.

उत्तर प्रदेश ताजमहल, सारनाथ और कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थस्थलों और प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थस्थानों की उपस्थिति के साथ भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. 2022 में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में राज्य क्रमशः दूसरे और सातवें स्थान पर था.

उत्तर प्रदेश को भारत की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कई खाद्य पदार्थों का अग्रणी उत्पादक है. यह भारत में शीर्ष विनिर्माण गंतव्य भी है, जो राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन में 8% से अधिक का योगदान देता है. राज्य देश में एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यातक है और सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सेवाओं सहित आईटी/आईटीईएस और सेवा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी उभरा है.

उत्तर प्रदेश निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में छठे स्थान पर है और इसे डीपीआईआईटी द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS 2022) में लैंडलॉक्ड राज्यों के बीच 'अचीवर' के रूप में मान्यता दी गई है.

17 सतत् विकास लक्ष्यों में से प्रत्येक को 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 169 लक्ष्यों के एक सेट के साथ मैप किया गया है. इनका उपयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स के निर्माण के लिए नींव के रूप में किया गया था. नीति आयोग ने 62 प्राथमिकता संकेतकों की एक सूची का चयन किया, जो भारत के राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे द्वारा निर्देशित थी. एसडीजी संकेतक, कार्यान्वयन के लिए प्रॉक्सी प्राचल है. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए दम

तालिका–2 : क्षेत्रकवार श्रम बल : 2020-21 (कुल श्रम बल के % रूप में)

क्षेत्रक	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	कर्नाटक	गुजरात	उत्तर प्रदेश
प्राथमिक क्षेत्र	49·51	29·9	47·18	46·66	55·16
विनिर्माण एवं उपयोगिताएं	11·89	17·62	11·89	19·06	8·94
निर्माण	6·46	16·63	7·95	6·45	12·57
व्यापार एवं होटल	11·66	14·7	12·23	12·57	11·74
परिवहन	4·67	4·93	5·79	4·42	3·17
वित्त एवं पेशेवर सेवाएं	2·98	2·42	2·13	2·25	0·97
शिक्षा एवं स्वास्थ्य	3·94	4·57	4·77	4·07	3·19
प्रशासन, प्रतिरक्षा एवं सपोर्ट सेवाएं	3·06	2·84	2·35	2·47	1·68
अन्य	5·83	6·29	5·71	3·05	2·58
कुल श्रम बल	**100·00**	**100·00**	**100·00**	**100·00**	**100·00**

STUDYPDF WALLAH

भरने वाले राज्यों में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है. 75 स्कोर के साथ केरल पहले तथा 74 के स्कोर के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर हैं. स्पष्ट है कि सतत् विकास लक्ष्य के मामले में शीर्ष राज्यों के बराबरी पर आने के लिए उत्तर प्रदेश को लम्बी यात्रा तय करनी है.

एक अन्य महत्वपूर्ण कारक श्रम बल की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जहाँ वे कार्यरत् हैं और जहाँ वृद्धिशील कार्यबल को आने वाले दिनों में रोजगार मिल सकता है. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय श्रम बल सहभागिता यह संकेत देती है किन क्षेत्रों में जनांकिकीय लाभांश को भुनाने की सम्भाव्यता अधिक है. तालिका–2 2020-21 में इन राज्यों में विभिन्न व्यवसायों में कार्यबल का प्रतिशत प्रदान करती है.

जीवंत विनिर्माण और उपयोगिताओं में लगभग 20% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात सबसे अनुकूल स्थिति में है. भले ही वहाँ 46·66 प्रतिशत कार्यबल अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में रोजगाररत है. तमिलनाडु में 29·9 प्रतिशत कामगार प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं. 17·62 प्रतिशत कामगार विनिर्माण एवं उपयोगिताओं में 16·63 प्रतिशत निर्माण में तथा 14·7 प्रतिशत कामगार व्यापार एवं होटल में कार्यरत् हैं. श्रम बल की इस प्रकार की सहिभागिता आर्थिक विकास की उच्च सम्भाव्यता का संकेत देती है. महाराष्ट्र की स्थिति कुछ विशिष्ट प्रकार की है. महाराष्ट्र का लगभग आधा श्रम बल प्राथमिक क्षेत्र में, 11·89 प्रतिशत विनिर्माण एवं उपयोगिताओं में मात्र 6·46 प्रतिशत निर्माण में (समूह में सबसे कम) तथा 11·66 प्रतिशत व्यापार और होटल में कार्यरत् है. किन्तु इसके बावजूद महाराष्ट्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, सम्भवतया इसका प्रमुख कारण उच्च स्तरीय निवेश वाली गतिविधियाँ देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुम्बई में संकेन्द्रित होना है. उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अभी भी प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता वाला राज्य है. उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 28·7 प्रतिशत (महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से लगभग दोगुना) एवं 55·16 प्रतिशत कामगारों का प्राथमिक क्षेत्र में रोजगाररत् होना है. ज्ञातव्य है कि कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र की विकास दर 4-5 प्रतिशत के बीच ही रहती है. और वह भी अच्छे मानसून के दौरान. इसके विपरीत औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विकास दर 20 प्रतिशत के स्तर तक ऊँची जा सकती है. इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वारा 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना उस समय तक सम्भव नहीं होगा, जब तक कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का उच्च स्तरीय विकास नहीं हो जाता. कृषि से श्रम को नए क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में समय लग सकता है और लेन-देन लागत भी अधिक हो सकती है.

जहाँ तक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का प्रश्न है, वे निचले स्तर पर उद्यमता और रोजगार अवसरों का खुलासा करते हैं. गुजरात और महाराष्ट्र अन्य राज्यों की तुलना में प्रति श्रमिक, प्रति एमएसएमई इकाई और निवेशित पूँजी में मूल्य वर्धन के मामले में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं. पीएम कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और अन्य के तहत् शिल्पकारों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी तक जीएसडीपी संख्याओं में परिलक्षित नहीं हुआ है.

इसके अलावा, इन राज्यों में पीएम कौशल विकास योजना के तहत् प्लेसमेंट स्तर नीचा है. यह महाराष्ट्र के लिए 5·9 प्रतिशत, कर्नाटक के लिए 12·9 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश के लिए 18·2 प्रतिशत, गुजरात के लिए 18·5 प्रतिशत और तमिलनाडु के लिए 25 प्रतिशत है (जनवरी 2021 तक कुल डेटा के लिए).

हालाँकि महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन आँकड़ों के वर्तमान स्वरूप से यही संकेत मिलता है कि अभी बहुत लम्बी डगर तय करनी है. निवेश, विशेष रूप से निजी निवेशकों से, कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि, जीवंत और नवीन क्षेत्रों में श्रमिकों का स्थानांतरण, विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक होगा. 4-5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर जीएसडीपी लक्ष्य को पूरा करना निस्संदेह एक कठिन काम है. ●●●

शेष पृष्ठ 64 का

प्रदूषण से जनसामान्य पर पड़ने वाले प्रभाव

- लैंसेट रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 12·5 प्रतिशत मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती है.
- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,16,000 से अधिक शिशुओं की 2019 में बाहरी और इनडोर वायु प्रदूषण के कारण जन्म के एक महीने के भीतर मृत्यु हो गई.
- अध्ययन कहते हैं कि गर्भवती माँ के बहुत अधिक प्रदूषण स्तर के सम्पर्क में आने से वास्तव में नाल और भ्रूण पर असर पड़ता है.
- उद्योगों/कारखानों का बंद होना, निर्माण गतिविधि आदि पर सीमाएं लगाया जाना.

दिल्ली के प्रदूषण के निवारण हेतु सरकारी पहलें

- ग्रीन वॉर रूम.
- प्रदूषण विरोधी अभियान.
- ग्रीन दिल्ली ऐप.
- बायो-डीकंपोजर.
- पानी का छिड़काव.
- उद्योग प्रदूषण.
- पीयूसी प्रमाण-पत्र.
- स्मॉग टावर्स.
- प्रदूषण हॉटस्पॉट.

निष्कर्ष

बढ़ती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य आपदा का सामना करते हुए, प्रदूषण विरोधी प्रयासों को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन सफल होने के लिए, सरकार के विभिन्न स्तरों को अधिक निवेश करने, सीमाओं के पार समन्वय करने और व्यवसायों और निवासियों को अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का उपयोग करना चाहिए.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–वायु गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित 8 प्रमुख वायु प्रदूषक गैसों में कौनसी गैस सम्मिलित है ?

1. कार्बन डाइऑक्साइड
2. कार्बन मोनोऑक्साइड
3. अमोनिया
4. वायुमण्डल के ऊपर स्थित ओजोन गैस
5. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

कूट :

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 5
(C) 1, 2, 3 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर–(B)

स्पष्टीकरण

दैनिक आधार पर वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट करने के लिए एक सूचकांक, हवा में मौजूद 8 प्रमुख प्रदूषकों जैसे–पार्टिकुलेट मैटर (PM2·5 और PM10), जमीनी ओजोन (O_3), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), सीसा (Pb) और अमोनिया (NH_3) के उत्सर्जन को मापकर प्राप्त किया करता है. इसकी शुरूआत राजधानी दिल्ली में वर्ष 2014 में की गई थी. ●●●

उपकार नवीन प्रस्तुति
वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी
(विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी)
Code No. 2685 ₹ 50/-
सम्पादक मण्डल
उपकार प्रकाशन, आगरा–5
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

फोकस 3

जलवायु परिवर्तन के उपजे खतरे : कॉप 28 (COP28) से अपेक्षाएं

✍ मधूलिका सिंह

आर्थिक विकास की अन्धी दौड़ में विकास के लिए ईंधन का काम करने वाले ऊर्जा के पारम्परिक स्रोतों–कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सान्द्रण ने मानव सहित समस्त जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों का जीवन संकट में डाल दिया है. वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वाष्प कण) की बढ़ती सान्द्रता से पृथ्वी के सामान्य तापक्रम लगातार वृद्धि हो रही है. इससे पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, चिकित्सक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, भू-वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ आदि सभी चिंतित हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों एवं मीडिया प्लेटफार्मों पर सम्पूर्ण पृथ्वी और उसके संघटकों के समक्ष आसन्न संकट पर चिन्ता जताते रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है.

यूरोपीयन सेन्टर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट्स के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार 17 नवम्बर, 2023 को पृथ्वी का तापमान औद्योगिक क्रान्ति काल से पहले (सन् 1850–1900) के दौरान रहे औसत तापमान की तुलना में 2·06 C अधिक दर्ज किया गया. 17 नवम्बर, 2023 को वैश्विक तापमान 1991–2020 के दौरान रहे औसत तापमान की तुलना में 1·17 C अधिक था.

स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही लगातार वृद्धि इस बात का संकेत है कि पृथ्वी और प्रकृति की प्रणालियाँ खतरनाक रूप से अस्थिरता की ओर जा रही हैं. क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के संस्थापक पीटर कार्टर के अनुसार, गोलार्द्ध में जाड़े के मौसम में बढ़ता तापमान गर्मियों की तुलना में अधिक है. विगत 12 महीनों में पृथ्वी पिछले एक लाख पच्चीस हजार वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहे हैं. इस दौरान वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1·32 C अधिक दर्ज किया गया है. वैज्ञानिकों का आकलन है 2023 में सर्वाधिक गर्म महीना यदि अक्टूबर रहा है, तो वर्ष 2023 सबसे अधिक गर्म वर्ष होगा.

पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि के कारणों की खोज के लिए किसी वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता नहीं है. ये तो हम सबके इर्द-गिर्द मौजूद है. संक्षेप में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं.

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आई औद्योगिक क्रान्ति के दौरान Industry 2·0, Industry 3·0 तथा Industry 4·0 में मानव गतिविधियों–उत्पादन से जुड़ी तथा सुख-सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी–के परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की बहुत बड़ी मात्रा वायुमण्डल में छोड़ी गई है, जिसने पृथ्वी की जलवायु को परिवर्तित किया है. सूर्य की ऊर्जा एवं ज्वालामुखियों के फटने तथा लम्बे समय तक धधकते रहने जैसे प्राकृतिक कारणों से भी पृथ्वी की जलवायु प्रभावित हुई है.

- ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तथा
- सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण एवं परावर्तकता

के माध्यम से मानव गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन में बड़ी सीमा तक योगदान दिया है.

जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कतिपय कारण निम्नलिखित प्रकार हैं–

* **ग्रीनहाउस गैसों**–कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, (HFC_s) सल्फर हेक्साफ्लोराइड, (SF_6) नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, (NF_3) परफ्लोरोकार्बन (PFC_s) (फ्लोरीनेटेड गैसें) आदि का उत्सर्जन.
* **सूर्य की ऊर्जा की परावर्तकता एवं अवशोषण**–कृषि, सड़क निर्माण तथा वनों की कटाई पृथ्वी के सतह की परावर्तकता में परिवर्तन लाती है. यह प्रभाव उष्म द्वीपों (Heat Islands)–शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो आस-पास के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हैं. प्राकृतिक सतहों की तुलना में पक्की सड़कें, भवन, पटरियाँ, छतें, सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को कम परावर्तित करती है. घने वनों के अन्तर्गत लम्बे पेड़ लगाकर सूर्य की ऊर्जा की परावर्तकता को बढ़ाया जा सकता है.
* **ज्वालामुखियों का फटना तथा लम्बे समय तक धधकते** रहने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें तथा कार्बन कण वायुमण्डल में फैलते रहते हैं.
* **बढ़ता उत्सर्जन**–(i) कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन; (ii) बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई; (iii) नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों का खेतीबाड़ी में बढ़ता उपयोग, (iv) तेजी से बढ़ता पशुपालन, (v) एरोसोल स्प्रे, एयर-कण्डीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, इन्स्यूलेशन, विद्युत् पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत स्विचगेयरों के प्रयोग से फ्लोरीनेटेड गैसों का उत्सर्जन.

पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के संकट से बचाने की अन्तर्राष्ट्रीय मुहिम

कारण चाहे मानव निर्मित हों या प्राकृतिक पृथ्वी के वायुमण्डल के तापमान में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप जलवायु में हो रहे वैश्विक परिवर्तनों से मानव, जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया है. औद्योगिक कृषि एवं सेवा क्षेत्र का विकास जितना अधिक हो रहा है. पृथ्वी का तापमान उतनी ही गति से बढ़ता जा रहा है, जिससे सारा विश्व लगातार बढ़ती गर्मी, लू, असामयिक वर्षा, बाढ़ों, बर्फवारी या हिमशीतों के पिघलने से किसी-न-किसी रूप में संकट में है. वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर चिन्ता पृथ्वी सम्मेलन (1992) में मुखर होकर सामने आई और उसी के निर्णयों को कार्यरूप देते हुए 21 मार्च, 1994 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) अस्तित्व में आया. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की सदस्यता वाले इस निकाय की सम्पुष्टि 198 देशों द्वारा की जा चुकी है और इन्हें सामूहिक रूप से 'पार्टीज टु द कन्वेंशन' कहा जाता है.

कन्वेंशन का उद्देश्य ग्रीन हाउस सान्द्रता को "उस स्तर पर स्थिर करना है, जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित (मानव प्रेरित) हस्तक्षेप को रोक सकें." इस तरह के स्तर को समय-सीमा के भीतर हासिल किया जाना चाहिए, ताकि पारिस्थितिक तन्त्र प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सके, यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्य उत्पादन को खतरा न हो और आर्थिक विकास को स्थायी तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके." विचार यह है कि वे अधिकांशतया अतीत और वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्रोत है, इसलिए औद्योगिक देशों–जो विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश हैं–में घरेलू स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सर्वाधिक प्रयास किए जाने की अपेक्षा की जाती है. औद्योगिक देश जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई

STUDYPDF WALLAH

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तनरोधी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कन्वेंशन के तहत् सहमत हैं.

विश्व के निर्धन देशों के लिए आर्थिक विकास विशेषरूप से महत्वपूर्ण है. जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिलताओं के बिना भी ऐसी प्रगति हासिल कर पाना मुश्किल है. इसमें किसी को भी सन्देह नहीं है कि पिछड़े तथा विकासशील देश जैसे-जैसे आर्थिक प्रगति करेंगे, वैसे-वैसे इन देशों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ेगा. दूसरी ओर विकसित देशों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के परिमाण में कोई सार्थक कमी नहीं आएगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों पर उनकी निर्भरता अभी भी बनी हुई है.

इन परिस्थितियों के बीच विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तनरोधी उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सिद्धान्ततः तो सहमत हैं, लेकिन उसे कार्यरूप देने में हीला-हवाली करते रहते हैं. यूएनएफसीसीसी के तत्वावधान में कन्वेंशन से जुड़े देशों के वार्षिक सम्मेलन का सिलसिला सन् 1995 में बर्लिन (जर्मनी) से प्रारम्भ हुआ और प्रतिवर्ष CoP के आयोजन के रूप में आज भी जारी है. इस दिशा में अब तक की सबसे सार्थक पहल क्योटो प्रोटोकॉल (1997) के रूप में मानी जाती है, जिसमें कन्वेंशन से जुड़े सभी देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन विडम्बनात्मक वास्तविकता यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल में आम सहमति से की गई अनेक प्रतिबद्धताएं अभी भी पाइपलाइन में हैं.

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (CoP)

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने तथा पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए 1994 में गठित UNFCCC के तहत् 1995 से CoP सदस्य राष्ट्रों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है. CoP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन

विभिन्न वर्षों में आयोजित CoP सम्मेलन

CoP	शहर/देश	दिनांक
CoP 1	बर्लिन (जर्मनी)	28 मार्च–7 अप्रैल, 1995
CoP 2	जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)	8–19 जुलाई, 1996
CoP 3	क्योटो (जापान)	1–10 दिसम्बर, 1997
CoP 4	ब्यूनस एरिस (अर्जेंटीना)	2–13 नवम्बर, 1998
CoP 5	बॉन (जर्मनी)	25 अक्टूबर–5 नवम्बर, 1999
CoP 6	दी हेग (नीदरलैण्ड्स)	13–24 नवम्बर, 2000
CoP 6, 2	बॉन (जर्मनी)	जुलाई 2001
CoP 7	मराकेश (मोरक्को)	29 अक्टूबर–10 नवम्बर, 2001
CoP 8	नई दिल्ली (भारत)	23 अक्टूबर–1 नवम्बर, 2002
CoP 9	मिलान (इटली)	1–12 दिसम्बर, 2003
CoP 10	ब्यूनस एरिस (अर्जेंटीना)	6–17 दिसम्बर, 2004
CoP 11	मॉन्ट्रियल (कनाडा)	28 नवम्बर–9 दिसम्बर, 2005
CoP 12	नैरोबी (केन्या)	6–17 नवम्बर, 2006
CoP 13	बाली (इण्डोनेशिया)	3–17 दिसम्बर, 2007
CoP 14	पोजनॉन (पोलैण्ड)	1–12 दिसम्बर, 2008
CoP 15	कोपेनहेगन (डेनमार्क)	7–18 दिसम्बर, 2009
CoP 16	कैनकुन (मेक्सिको)	28 नवम्बर–10 दिसम्बर, 2010
CoP 17	डर्बन (दक्षिण अफ्रीका)	28 नवम्बर–9 दिसम्बर, 2011
CoP 18	दोहा (कतर)	26 नवम्बर–7 दिसम्बर, 2012
CoP 19	वारसा (पोलैण्ड)	11–23 नवम्बर, 2013
CoP 20	लीमा (पेरू)	1–12 दिसम्बर, 2014
CoP 21	पेरिस (फ्रांस)	30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2015
CoP 22	मराकेश (मोरक्को)	7–18 नवम्बर, 2016
CoP 23	बॉन (जर्मनी)	6–17 नवम्बर, 2017
CoP 24	कैटोविस (पोलैण्ड)	3–14 दिसम्बर, 2018
CoP 25	मैड्रिड (स्पेन)	2–13 दिसम्बर, 2019
CoP 26	ग्लासगो (यू.के.)	31 अक्टूबर–12 नवम्बर, 2021
CoP 27	शर्म अलशेख (मिस्र)	6–18 नवम्बर, 2022
CoP 28	दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2023
CMA5 (पेरिस समझौते से जुड़े पक्षों की पाँचवीं बैठक)	दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2023
CMP18 (क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षों की 18वीं बैठक)	दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2023
SBI59 (क्रियान्वयन हेतु अनुषंगी निकाय की 59वीं बैठक)	दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2023
SBSTA59 (वैज्ञानिक एवं तकनीकी परामर्श हेतु अनुषंगी निकाय की 59वीं बैठक)	–	30 नवम्बर–12 दिसम्बर, 2023

STUDYPDF WALLAH

कन्वेंशन (UNFCCC) का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है. कन्वेंशन के पक्षकार सभी राष्ट्रों को CoP में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जहाँ वे कन्वेंशन के निर्णयों के कार्यान्वयन और CoP द्वारा अपनाए गए किसी भी अन्य कानूनी उपकरणों की समीक्षा करते हैं और संस्थागत तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं सहित कन्वेंशन के निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए यथोचित निर्णय लेते है.

CoP की बैठक प्रतिवर्ष होती है, जब तक कि सदस्य राष्ट्र अन्यथा निर्णय न लें. CoP की बैठक उस देश या शहर में होती है, जो सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश करता है. यदि अगली बैठक के लिए कोई पेशकश न हो, तो वार्षिक सम्मेलन UNFCCC के सचिवालय बॉन जर्मनी में ही होगी. CoP की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त पाँच क्षेत्रों में–अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमरीका और कैरेबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप तथा अन्य के बीच घूमती है.

CoP 28 (2023)

जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव औद्योगिक विकास के सम्पूर्ण काल में दिखाई दिए हैं तथा उनका परिमाण भी बढ़ता जा रहा है. वर्ष 2023 को अब तक के इतिहास में सर्वाधिक गर्म वर्ष माना जा रहा है. इससे पूर्व 2016 सर्वाधिक गर्म वर्ष था. इस बढ़ती गर्मी के दंश सम्पूर्ण विश्व यहाँ तक कि विश्व के वे देश जिसमें सारे वर्ष मौसम ठण्डा रहता था के सभी देश झेल रहे हैं. विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2023 सहित अगले चार वर्षों में कम-से-कम एक वर्ष में तापमान में 1·5 C से अधिक की वृद्धि हो जाएगी.

वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसे रोकने या नियन्त्रित करने के लिए वैश्विक अनुक्रिया में अपेक्षित तेजी दिखाई नहीं दे रही है. देशों की जलवायु कार्ययोजनाओं पर नवीन संश्लेषण रिपोर्ट में हालिया आकलन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई पर देशों द्वारा अब तक व्यक्त की गई सहमति के अति आशावादी परिदृश्य में 2019 के स्तर से 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मात्र 2 प्रतिशत की कमी आएगी. अन्तर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल का आकलन है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1·5 C तक सीमित रखता है, तो उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कमी लानी होगी. वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह दिवा स्वप्न ही है.

मिस्र के शर्म-अल-शेख में आयोजित CoP27 में मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे–

- जलवायु परिवर्तन से हुई हानि एवं विनाश हेतु कोष (Loss and Damage Fund) की स्थापना.
- वैश्विक तापमान वृद्धि को 1·5 C तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2025 में अधिकतम स्तर को देखते हुए उत्सर्जन में 2030 तक 43 प्रतिशत की कमी लाना.
- व्यवसायों एवं संस्थाओं की जबावदेही तय करना.
- विकासशील देशों के लिए अधिक वित्तीय सहायता जुटाना.
- क्रियान्वयन हेतु सतत् एवं ठोस प्रयास.

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं. उसके केन्द्र में वित्त सर्वाधिक प्रमुख है. जलवायु परिवर्तनों को रोकना, यथोचित स्वच्छ प्रौद्योगिका एवं उपाय अपनाना, नुकसान एवं विनाश, जलवायु परिवर्तन आदि सभी के लिए बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है.

2009 में सदस्य राष्ट्रों के बीच सहमति बनी थी कि विकसित देश प्रतिवर्ष विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता मुहैया कराएंगे, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकें और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकें. पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया.

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन इस सहायता को 'ऊँट के मुँह में जीरा' की भाँति मानता है. इसके हालिया विश्लेषण में विकासशील देशों को अपने मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के आधे से भी कम को पूरा करने के लिए 2030 तक कम-से-कम 6 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है.

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से विकसित देश 2021 में विकासशील देशों की जलवायु शमन और अनुकूलन आवश्यकताओं के लिए संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने के अपने वायदे से पीछे रह गए. विकसित देशों द्वारा 2021 में मात्र 89·6 बिलियन डॉलर ही जुटाए गए. पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाने में विफलता विकासशील देशों में जलवायु शमन (जैसे–नवीकरणीय ऊर्जा के साथ उत्सर्जन में कमी) को सम्बोधित करने की क्षमता को कम करती है और अनुकूलन की आवश्यकताएं (जैसे जलवायु लचीली कृषि को विकसित करना और प्रोत्साहित करना) और दुनिया के निर्धन देशों के बीच इस विश्वास को कम कर देती है कि विकसित देश जलवायु संकट से निपटने के बारे में गम्भीर हैं.

अब विश्व के 198 देशों–विकसित (अमीर), विकासशील, अल्पविकसित (निर्धन) के प्रतिनिधि 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 2023 तक मध्य-पूर्व के अतिविकसित एवं सम्पन्न देश संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एकत्रित हुए हैं.

अन्य सम्मेलनों की भाँति इस सम्मेलन में चर्चा निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित रहने वाली हैं–

- सम्पोषणीय भविष्य हेतु जेण्डर एवं पर्यावरणीय आँकड़े.
- विद्यार्थियों और युवाओं को ऊर्जा सम्बन्धित मुद्दों से जोड़ना.
- जलवायु वित्त रूपान्तरण.
- जलवायु नवोन्मेषी फोरम.
- जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में खाद्य प्रणालियों का रूपान्तरण.
- जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में मानवीय आवश्यकताओं को कम करना. एकीकृत लचीलेपन कार्यों को बढ़ाकर लोगों तथा पृथ्वी की रक्षा करना.
- अन्तिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करना.
- नेट जीरो ट्रांजीशन.
- खाद्य एवं कृषि प्रणालियों के लिए पुनर्योजी परिदृश्य.
- ऊर्जा दक्षता.

जैसाकि प्रत्येक CoP में होता आया है. संयुक्त राज्य अमरीका और उनके सहयोगी विकसित देश CoP28 में भी ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन का ठीकरा भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के सिर फोड़ते रहेंगे. विकासशील एवं पिछड़े देश एक स्वर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दबाव विकसित देशों पर डालेंगे. नुकसान एवं विनाश हेतु कोष अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है. इसकी कार्यप्रणाली भी तय नहीं हो पायी है. भारत जैसे विकासशील देशों को आपत्ति है कि उन्हें इस कोष की परिधि से बाहर रखा गया है.

CoP28 से विश्व के विकासशील देशों और निर्धन देशों को अनेक अपेक्षाएं हैं. ये देश विकासोन्मुख हैं और अपनी ऊर्जा, जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख संसाधन है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को यकायक समाप्त नहीं कर सकते. ऐसे देशों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास की सार्थक रणनीति बनानी होगी.

●●●

STUDYPDF WALLAH

स्मरणीय तथ्य

राष्ट्रीय

1. भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के किस वकील को 11 सितम्बर, 2023 तक जीवित रहते हुए सर्वाधिक समय तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है ? **–पी. बालसुब्रमण्यन मेनन**
   ☞ 97 वर्षीय पी. बालसुब्रमण्यन मेनन को जीवित रहते हुए 73 वर्ष 60 दिन तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है.
2. भारतीय वायु सेना की ईस्टर्न एअर कमांड (EAC) ने 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2023 तक किस नाम से वार्षिक युद्ध अभ्यास किया ? **–पूर्वी आकाश**
   ☞ इस अभ्यास में भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने भी भाग लिया तथा दोनों ने मिलकर पूर्वी क्षेत्र के चुनौती पूर्ण इलाकों में अभ्यास किया.
3. भारत ने 7 नवम्बर, 2023 को ओडिशा के अब्दुल कलाम आईलैंड से डी आर डी ओ द्वारा विकसित किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) का सफल परीक्षण किया ? **–प्रलय**
   ☞ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सतह-से-सतह पर प्रहार करने वाली प्रलय मिसाइल का यह तीसरा परीक्षण था. इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किमी तक है.
4. भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टेंडिंग के लिए उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया : इंगलैंड, मुगल इंडिया एण्ड दी ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 11वाँ ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 1 नवम्बर, 2023 को देने की घोषणा की है ? **–नंदिनी दास**
   ☞ नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंगलिश में अर्ली मॉर्डन लिट्रेचर की प्रोफेसर हैं. उन्होंने कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इंगलैंड में पढ़ाई की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डॉक्टरेट प्राप्त की थी.
5. यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर, 2023 को जारी 55 देशों की नई क्रिएटिव सिटीज में भारत के किन शहरों को क्रमशः सिटी ऑफ लिटरेचर तथा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है ? **–कोझीकोडे (केरल), ग्वालियर (मध्य प्रदेश)**
   ☞ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने इसकी घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर की. कोझीकोडे, जो पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, में 500 से अधिक पब्लिक लाइब्रेरी हैं. ग्वालियर संगीतज्ञ बैजू बावरा, तानसेन और ग्वालियर घराने के लिए प्रसिद्ध है.
6. भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी की मूर्ति का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुम्बई में 1 नवम्बर, 2023 को किया गया ? **–सचिन तेंदुलकर**
   ☞ सचिन की ताँबे की मूर्ति शिल्पकार प्रमोद काम्बले ने बनाई है जिसका अनावरण उनके जीवन के 50वें वर्ष में किया गया. भारत रत्न से सम्मानित सचिन के नाम अनेक रिकॉर्ड हैं
7. भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पांसिबिल टूरिज्म अवार्ड 2023 नवम्बर, 2023 में प्राप्त किया ? **–केरल**
   ☞ रिस्पांसिबिल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबिल टूरिज्म (ICRT) द्वारा प्रारम्भ किए गए बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग–क्राफ्ट एण्ड फूड कैटेगरी में केरल को यह अवार्ड मिला है.
8. 6 नवम्बर, 2023 को किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) पद की शपथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दिलाई ? **–हीरा लाल सामरिया**
   ☞ भारतीय प्रशासनिक सेवा के हीरा लाल सामरिया दलित वर्ग से पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं. यह पद वाई. के. सिन्हा के 3 अक्टूबर, 2023 को रिटायर होने के बाद से रिक्त था.
9. रेलवे के किस अधिकारी को 2 नवम्बर, 2023 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) का डाइरेक्टर नियुक्त किया गया है ? **–डॉ. संचित त्यागी**
   ☞ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) के अधिकारी संचित त्यागी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है. संचित 2021 से नेशनल बुक ट्रस्ट में एक निदेशक पद पर कार्यरत् थे.
10. भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से 13 से 25 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न हुआ ? **–त्रिशक्ति प्रहार**
    ☞ संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास जैसलमेर में हुआ जिसमें लगभग 25000 सैनिकों ने भाग लिया.
11. अमरीका में न्यूयार्क में 20 नवम्बर, 2023 को आयोजित एमी (Emmy) इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में भारत की किस महिला फिल्म एवं टेलीविजन शृंखला निर्माता को डाइरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया ? **–एकता कपूर**
    ☞ एकता कपूर एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला निर्माता हैं. साथ ही वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर कॉमेडी उनके नेटफिलिक्स कॉमेडी स्पेशल शो को मिला.
12. किस राज्य में 21 नवम्बर, 2023 से सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है ? **–बिहार**
    ☞ बिहार में की गई जातिगत जनगणना के आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 से 65 प्रतिशत की गई है. पहले से जारी कुल 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत आरक्षण किया गया है जिसमें 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है.
13. किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के हॉल ऑफ फेम में नवम्बर 2023 में शामिल किया गया है ? **–वीरेंद्र सहवाग, डाएना एदुलजी**
    ☞ डाएना एदुलजी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं. वीरेंद्र सहवाग के साथ श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी सम्मिलित किया गया है.
14. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवम्बर को किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को राज्य का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है ? **–सौरभ गांगुली**
    ☞ बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. इन्होंने शाहरुख खान का स्थान लिया है.

STUDYPDF WALLAH

अन्तर्राष्ट्रीय

1. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता 10 नवम्बर, 2023 को निलंबित कर दी ? **–श्रीलंका**
   ☞ आई सी सी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका की सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी है. इसके कारण श्रीलंका की टीम किसी भी आई सी सी टूर्नामेंट में फिलहाल भाग नहीं ले सकेगी.
2. जी-7 देशों कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, यू के, अमरीका के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की 7-8 नवम्बर, 2023 को मीटिंग कहाँ सम्पन्न हुई ? **–टोक्यो, जापान**
   ☞ जी-7 देशों का 49वाँ सम्मेलन मई 2023 में सम्पन्न हुआ था. इसका आगामी सम्मेलन जून 2024 में इटली में प्रस्तावित है.
3. भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं बांग्लादेश के बीच किस पहली रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवम्बर, 2023 को किया ? **–अखौरा (बांग्लादेश) अगरतला (त्रिपुरा, भारत)**
   ☞ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से निर्मित परियोजनाओं अखौरा-अगरतला रेलवे लिंक, खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश में रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पॉवर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया.
4. फाल्गुनी शाह एवं गौरव शाह द्वारा गाया गया कौनसा गाना 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है ? **–एबंडेंस इन मिलैट्स (Abundance in Millets)**
   ☞ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज भी इस गाने में सम्मिलित है तथा यह बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है.
5. किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवम्बर, 2023 को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है ? **–डेविड कैमरून**
   ☞ डेविड कैमरून 2010-16 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे. विदेश मंत्री जेम्स ब्रेवरमेन की जगह कैमरून ने पद सँभाला है. ब्रेवरमेन को गृहमंत्री बनाया गया है.
6. श्रीलंका के किस क्रिकेट बल्लेबाज को 6 नवम्बर, 2023 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में अम्पायरों द्वारा टाइम आउट किया गया जिससे यह इस प्रकार आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने ? **–एंजिलो मैथ्यूज (Angelo Mathews)**
   ☞ आईसीसी के नियम 40·1·1 (टाइम आउट नियम के) अनुसार किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ी को अगले दो मिनट में क्रीज पर पहुँचना होता है, यदि नया बल्लेबाज ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसे टाइम आउट कर दिया जाता है.
7. किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के अंत में रिकॉर्ड आठवीं बार ए टी पी नम्बर एक रैंक प्राप्त किया ? **–नोवाक जोकोविच**
   ☞ सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 13 नवम्बर, 2023 को इटली के ट्यूरिन में ए टी पी टूर फाइनल में विजय प्राप्त कर वर्षांत के नम्बर एक खिलाड़ी का खिताब जीता. जोकोविच ने रिकॉर्ड 24 एकल ग्रांड स्लैम खिताब जीते हैं.
8. इंडोनेशिया की किस पुलिस अधिकारी को 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 16 नवम्बर, 2023 को प्रदान किया गया ? **–रेनिटा रिसमयंती (Renita Rismayanti)**
   ☞ इंडोनेशिया की पुलिस अधिकारी रेनिटा रिसमयंती यू. एन. पीसकार्पिंग मिशन इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (MINUSCA) में कार्यरत् हैं.
9. तुर्किए से भारत जा रहे किस कार्गो शिप को यमन के हूती विद्रोहियों ने 16 नवम्बर, 2023 को लाल सागर में बंधक बना लिया ? **–गेलेक्सी लीडर**
   ☞ हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने एक इजरायली जहाज को बंधक बनाया है. जहाज एक ब्रिटिश कम्पनी के तहत् पंजीकृत है जिसे एक जापानी कम्पनी चलाती है. एक समाचार के अनुसार इसका आंशिक स्वामित्व इजराइल के अब्राहम उंगर के पास था जिसने जापानी कम्पनी को लीज पर दे दिया है.
10. एल साल्वाडोर में 18 नवम्बर को आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में कौन मिस यूनिवर्स चयनित किया गया ? **–शेयन्निस पेलेसिऔस (Sheynnis Palacios)**
    ☞ निकारागुआ की शेयन्निस पेलेसिऔस मिस यूनिवर्स, थाइलैण्ड की एंटोनिया पोरसिल्ड (Anntonia Porsild) और आस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन (Moraya Wilson) क्रमशः प्रथम व द्वितीय रनर अप चुनी गईं.
11. किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज (Cargo Ship) 19 नवम्बर, 2023 को काले सागर में डूब गया ? **–तुर्किए**
    ☞ तुर्किए का मालवाहक जहाज काफ्कामेटलर (Kafkametler) खराब मौसम के कारण इस्तांबुल से 200 किमी दूर इरेगलि (Eregli) टाउन के तट के बाहरी समुद्र में डूब गया. जहाज पर 12 क्रू मेंबर सवार थे.
12. अमरीका की टाइम (Time) मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवम्बर, 2023 को जारी की है, जिसमें किस भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया है ? **–अजय बंगा**
    ☞ भारत या भारतीय मूल के अन्य व्यक्तियों में ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल, राजीव जे शाह (रॉकफेलर फाउंडेशन), गीता अय्यर (बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट), जिगर शाह (यू एस ऊर्जा विभाग), मनोज सिन्हा (हस्क पॉवर सिस्टम्स), सीमा बाघवा (कैसर परमानेंट) और अमित कुमार सिन्हा (महिंद्रा लाइफस्पेसेज) सम्मिलित हैं.
13. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी (BBC) द्वारा 21 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित विश्व की 100 प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है ? **–दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव**
    ☞ फिल्म अभिनेत्री एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा,भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्वतंत्र फोटोग्राफर एवं लेखक आरती कुमार राव को विश्व की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है.
14. 28वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया ? **–दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात**
    ☞ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP28) ऑफ दी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) का आयोजन नवम्बर–दिसम्बर 2023 में एक्सपो सिटी, दुबई में किया गया.
15. 5 अक्टूबर से 19 नवम्बर, 2023 तक भारत में आयोजित आई सी सी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज घोषित किया गया ? **–विराट कोहली (भारत)**
    ☞ विराट कोहली ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 765 रन बनाएं. भारत के मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 24 विकेट लिए. आस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में हराकर विश्व कप जीता. ●●●

STUDYPDF WALLAH

विश्व परिदृश्य

✍ डॉ. अरुणोदय बाजपेयी

भारत तथा जी-20 सम्मेलन

भारत की मेजबानी में जी-20 देशों का शिखर सम्मेलन सितम्बर 2023 में, नई दिल्ली में, आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन के लिए भारत द्वारा एक वर्ष से तैयारी की जा रही थी. सम्मेलन के आयोजन की तैयारी में वर्ष भर में करीब 200 बैठकें आयोजित की गई. देश की शिक्षण संस्थाओं तथा मीडिया में वर्ष भर जी-20 आयोजन की चर्चा होती रही. अन्त में विशेष रूप से नवनिर्मित भारत मण्डपम भवन 9-10 सितम्बर, 2023 को जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को छोड़कर सभी शासनाध्यक्षों ने भाग लिया. विश्व की ताकतों की उपस्थिति के हिसाब से देखा जाए, तो यह भारत के कूटनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन था, लेकिन शासनाध्यक्षों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन 1983 को गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है, जिसमें 70 से अधिक देशों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था. यह सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था. जहाँ तक जी-20 सम्मेलन की बात है, तो भारत ने इसके आयोजन को नया कलेवर प्रदान किया तथा इसके सन्देश को जन-जन तक पहुँचाया. इसीलिए, इस शिखर सम्मेलन को जनता का जी-20 सम्मेलन भी कहा जाता है.

इस जी-20 सम्मेलन में, पूर्व सम्मेलनों की भाँति तमाम वैश्विक चुनौतियों जैसे—तीव्र आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, जीवन्त विकास लक्ष्यों की प्राप्ति आदि पर गहन चर्चा हुई. इन मुद्दों पर बने वैश्विक दृष्टिकोण को अन्तिम घोषणा-पत्र में स्थान भी दिया गया है. इस विश्लेषण के बीच यह प्रश्न अकसर उठाया जाता है कि आखिरकार इस आयोजन से भारत को क्या लाभ हुआ तथा भारत ने इस आयोजन में अपनी क्या छाप छोड़ी? इन प्रश्नों को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है—

पहला, यह कि जी-20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपनी 5,000 वर्ष पुरानी विरासत को विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर था. भारत ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया. भारत ने अन्तिम सम्मेलन ही नहीं वरन् वर्ष भर चली तैयारी बैठकों में भी अपनी कला व संस्कृति की एक अलग छाप छोड़ी है. अन्तिम सम्मेलन के समय भारत ने आयोजन स्थल, भारत मण्डपम में, अपने ऐतिहासिक कला व संस्कृति की प्रदर्शनी का आयोजन किया. इसमें भारत की क्षेत्रीय विविधता व हस्त-कला का उत्कर्ष साफ तौर पर दिखाई दे रहा था. आयोजन स्थल पर ही विश्व में लोकतंत्र के विकास तथा भारत में उसके ऐतिहासिक विकास पर एक अलग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. इसमें जी-20 के सदस्य देशों व आमंत्रित सदस्यों द्वारा लोकतंत्र में अपने योगदान को प्रदर्शित किया गया था उदाहरण के लिए, अमरीका ने जहाँ 1215 के मैग्नाकार्टा का प्रदर्शन किया वहीं अमरीका ने 1776 के स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र का प्रदर्शन किया. भारत द्वारा विगत कुछ वर्षों से लोकतंत्र की जननी होने का दावा किया जा रहा है.

भारत ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के गणराज्यों तथा बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला. यह तथ्य भारत के लोकतंत्र की जननी होने के दावे को मजबूत करते हैं. भारत ने जी-20 मेहमानों की उत्कृष्ट मेहमानवाजी से 'अतिथि देवो भव' के भारतीय आदर्श को चरितार्थ किया है. भारत ने अपनी संस्कृति के एक उच्च विचार वसुधैव कुटुम्बकम को तो इस सम्मेलन की थीम में ही शामिल कर दिया था. इस सम्मेलन की थीम 'वन अर्थ वन फेमिली वन फ्यूचर' वास्तव में वसुधैव कुटुम्बकम का ही एक रूपान्तर है. इस प्रकार जी-20 शिखर सम्मेलन भारत की साफ्ट पॉवर को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है. यह भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है.

दूसरा, भारत ने इस आयोजन के माध्यम से अपनी कुशल व सन्तुलित कूटनीति की छाप भी विश्व में छोड़ी है. यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच ध्रुवीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था. एक ओर अमरीका तथा पश्चिमी देश थे, तो दूसरी ओर रूस व चीन थे. रूस व चीन का तर्क था कि जी-20 सम्मेलन आर्थिक विषयों पर विचार करने का का मंच है इसमें यूक्रेन युद्ध अथवा रूस की आलोचना का विषय शामिल नहीं होना चाहिए. दूसरी तरफ अमरीका तथा पश्चिमी देशों का तर्क था कि चूँकि यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं. अतः सम्मेलन में इसे शामिल किया जाना आवश्यक है. इस गतिरोध के कारण सर्वसम्मति से जी-20 घोषणा-पत्र का जारी किया जाना असम्भव प्रतीत हो रहा था. ऐसा इसलिए भी कि इसके पहले वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इसी विषय के कारण आम सहमति नहीं बना पाई थी.

उल्लेखनीय है कि जी-20 के घोषणा-पत्र बहुमत से नहीं, वरन् आम सहमति से जारी किए जाते हैं. यदि आम सहमति नहीं बनती तो कोई सम्मेलन बिना घोषणा-पत्र के ही समाप्त हो जाता है. भारत के लिए एक नई चुनौती यह भी थी कि 2008 से लेकर अब तक जी-20 को कोई सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें आम सहमति से घोषणा-पत्र नहीं जारी किया गया हो. यह भारतीय कूटनीति के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन भारत ने अपनी सन्तुलित कूटनीति तथा सूझ-बूझ से आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की इसमें घोषणा-पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो किया गया, लेकिन रूस की आलोचना करते हुए उसे आक्रमणकारी नहीं घोषित किया गया. इसकी बजाए इसमें संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया जिसमें सैन्य ताकत का प्रयोग कर किसी देश पर अधिकार करने की मनाही है. वास्तव में यह भारतीय कूटनीति के लिए बड़ी सफलता थी. भारत अपनी सन्तुलित नीति से विश्व की अन्य चुनौतियों के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है. यह आश्चर्य की बात नहीं कि चाहे यूक्रेन युद्ध हो अथवा वर्तमान में जारी हमास-इजरायल संघर्ष हो, भारत को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया जाता है.

तीसरा, आजादी के समय से ही भारत वैश्विक-दक्षिण सहयोग तथा विकासशील देशों के साथ सहयोग का हिमायती रहा है. यह भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भी यह एक प्रमुख थीम थी. उत्तर-शीत युद्ध काल में भी भारत विभिन्न मंचों पर सदैव विकासशील व गरीब देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता रहा है. भारत ने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं तथा वैश्विक व्यापार वार्ताओं में विकासशील

STUDYPDF WALLAH

देशों से सम्बन्धित मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है. अब जी-20 की मेजबानी में भारत ने विकासशील देशों के सरोकारों को प्राथमिकता देकर जी-20 के अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया है. आज विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है. भारत ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को जी-20 के एजेण्डा में शामिल करने के लिए जनवरी 2023 में ग्लोबल साउथ के देशों का एक अलग सम्मेलन बुलाया था. इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के मुद्दों को समझना तथा उन्हें जी-20 के एजेण्डे में शामिल करना था. इस प्रकार जी-20 के अन्तिम एजेण्डे में विकासशील देशों से सम्बन्धित मुद्दों जैसे—जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, इनर्जी सुरक्षा आदि को प्रमुखता से शामिल किया गया है, लेकिन भारत ने इस बार ग्लोबल साउथ के लिए सबसे अलग करके दिखाया है. भारत ने अफ्रीका के 54 देशों के संगठन अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से जी-20 में पारित कराने में सफलता पाई है. अब जी-20 में 20 नहीं वरन् 21 सदस्य होंगे. यह भारत की ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में बडी सफलता है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन के 54 देश ग्लोबल साउथ के ही सदस्य है. इस प्रकार भारत ने ग्लोबल साउथ देशों के नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है. चीन भी इस स्थिति के लिए लम्बे समय से भारत के साथ प्रतियोगिता में संलग्न था.

जी-20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा-पत्र

लीडर्स घोषणा-पत्र जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज होता है. नई दिल्ली घोषणा-पत्र को भी वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श वाक्य के साथ जारी किया गया. घोषणा की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम जी-20 देश एक पृथ्वी तथा एक परिवार के सदस्य हैं तथा हमारा साझा भविष्य है. वास्तव में यह घोषणा-पत्र एक बड़ा दस्तावेज है. यह दो भागों में विभाजित है—पहले भाग में घोषणा के मुख्य बिन्दु शामिल हैं तथा इसमें 82 पैराग्राफ है. दूसरे भाग में 26 संलग्न है, जो वर्ष भर में होने वाली विभिन्न बैठकों व समूहों द्वारा पारित अन्तिम प्रस्ताव है.

भाग एक—मुख्य घोषणा-पत्र

इस भाग में वैश्विक मुद्दों जैसे विश्व अर्थव्यवस्था का समेकित व सन्तुलित विकास, जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा, यूएन जीवन्त विकास लक्ष्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन वित्तीय सुधार, स्वास्थ्य, वैश्विक आपूर्ति शृंखला की मजबूती आदि विषयों पर विचार किया गया है. मुद्दों के आधार पर मुख्य घोषणा 10 भागों विभक्त हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. एक मजबूत, टिकाऊ, सन्तुलित तथा समेकित आर्थिक विकास—जी-20 संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर एक मजबूत, टिकाऊ, सन्तुलित तथा समेकित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है. इस सम्बन्ध में देशों ने कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. ये प्राथमिकता क्षेत्र हैं—विकास के लिए व्यापार को बढ़ाना, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ाना, वित्तीय समेकीकरण तथा भ्रष्टाचार निवारण आदि. इस प्रकार के दृष्टिकोण से महँगे जीवन स्तर की समस्या से भी निजात मिलेगी.

2. यूएन के टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्रगति को बढ़ावा—यूएन महासभा ने 2015 में 17 सतत् विकास लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों का निर्धारण किया था, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है. एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर केवल 12 प्रतिशत लक्ष्य ही सही प्रगति कर रहे हैं. अन्य लक्ष्य पीछे छूट रहे हैं. अतः जी-20 देशों ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक स्तर पर इन लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं. इसके साथ ही 10 घोषणा में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु विकसित देशों से विकास सहायता प्रदान करने का आह्वान किया गया है.

3. टिकाऊ विकास के लिए ग्रीन विकास सहमति—सदस्य देशों ने यह रेखांकित किया कि विश्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण के लिए किन नीतियों को अपनाया जाता है. अतः सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में एक समग्र सन्तुलित व समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है. इस सम्बन्ध में जी-20 ने भारत की पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE–Lifestyle for Environment) की पहल का स्वागत किया है. इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के कार्य में आम जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा.

4. 21वीं शताब्दी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं—लगभग सभी देश सिद्धान्त के तौर पर स्वीकार करते हैं कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएं न तो प्रतिनिधात्मक है और न ही समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है. विश्व संस्थाओं के वर्तमान ढाँचे को द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में अपनाया गया था, जो आज पुराना हो गया है. अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है. अतः जी-20 देशों ने यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिपूर्ण बनाने तथा प्रभावी बनाने की वकालत की है. बहुपक्षीयता की भावना से ही इन संस्थाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि भारत भी विश्वव्यवस्था के संचालन में बहुपक्षीयतावाद के सिद्धान्त का समर्थक है.

5. तकनीकी विकास तथा डिजिटल ढाँचागत सुविधाएं—सदस्य देशों का मानना है कि डिजिटल तकनीकी को विकास करने में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए डिजिटल असमानता को दूर किए जाने की आवश्यकता है. इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकारी स्तर पर डिजिटल ढाँचागत सुविधाओं (Digital Public Infrastructure) का विकास किया जाए. इस सम्बन्ध में वैश्विक स्तर पर डेटा के आदान-प्रदान तथा विनियमतीकरण की व्यवस्था की जानी आवश्यक है.

6. अन्तर्राष्ट्रीय टैक्स व्यवस्था में सुधार—सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सरल विश्वसनीय व आधुनिक वैश्विक टैक्स प्रणाली की आवश्यकता है. अतः सभी देशों ने टैक्स सुधारों के प्रयासों में गति लाने की आवश्यकता पर बल दिया. टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यापार, निवेश तथा वित्तीय आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सके तथा भ्रष्ट गतिविधियों पर नियंत्रण लग सके.

7. लैंगिक समानता तथा महिलाओं व लड़कियों का सशक्तिकरण—गत् कुछ वर्षों से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी जी-20 में स्थान पा चुका है. भारत ने भी इस सम्मेलन में इस मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान की थी. देशों ने स्वीकार किया कि लैंगिक समानता एक आधारभूत सिद्धान्त है. इसके अपनाने से टिकाऊ विकास लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है. अतः सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि महिला सशक्तिकरण के आर्थिक व राजनीतिक उपायों को मजबूती प्रदान की जाए.

8. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे—इसमें मुख्य रूप से बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के मुद्दे शामिल है. सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि घरेलू स्तर पर सेविंग बैंकों में सुधार कर उन्हें मजबूती प्रदान की जाए ताकि भविष्य में 2008 जैसे वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े. स्वीकर किया गया कि सेविंग बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः विकास में उनकी भूमिका को भी मजबूत किया जाए.

9. आतंकवाद तथा मनी लांडरिंग की रोकथाम—सदस्यों ने माना कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है. आतंकवादी समूह काले धन का प्रयोग करके अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हैं. अतः आवश्यकता है कि आतंकवाद के प्रत्येक रूप तथा अतिवादी विचारों पर प्रभावी रोक लगाई जाए. इसके लिए विश्व स्तर एक समग्र नीति बनाने देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने की

STUDYPDF WALLAH

आवश्यकता है. इस बात को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी देश में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह न मिल सके और न ही वे अपने नेटवर्क का विस्तार कर सके. अतः वर्तमान में आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों तथा उनके भर्ती नेटवर्क पर रोक लगाए जाने की अधिक आवश्यकता है.

10. एक अधिक समेकित विश्व का निर्माण—जी-20 नेताओं ने एक ऐसे समेकित विश्व के निर्माण की वकालत की जिसमें गरीब व विकासशील देशों व उनके हितों को उचित स्थान मिल सके. इस सम्बन्ध में सदस्यों ने नई दिल्ली सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का स्वागत किया. उन्होंने विश्वास जताया कि इससें अफ्रीका में विकास व औद्योगीकरण को गति प्राप्त होगी तथा अफ्रीकी देशों को विश्व विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा. ऐसा किया जाना एक समेकित विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक है.

निष्कर्ष

जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के लिए एक खास अवसर था. इस आयोजन में भारत ने अपनी खास छाप छोड़ी है. इस सम्बन्ध में भारत की तीन उपलब्धियाँ उल्लेखनीय है. **पहला**, भारत ने अपनी मृदुल शक्ति का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर किया है. **दूसरा**, भारत ने अपनी कुशल व सन्तुलित कूटनीति का परिचय दिया है. **तीसरा**, भारत ने ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने की अपनी स्थिति को मजबूत किया है. इसके अलावा सम्मेलन के एजेण्डा व उसके निष्कर्षों में भी भारत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है. इसमें सन्तुलित व समेकित विकास, आतंकवाद-रोधी उपाय, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य व इनर्जी सुरक्षा जैसे मुद्दों को स्थान दिया गया है. इससे जी-20 भविष्य में अधिक प्रभावी व समेकित भूमिका का निर्वाह कर सकेगा.

भारत व फ्रांस-सम्बन्धों की समृद्ध विरासत

यूरोप के अन्य देशों की तुलना में भारत व फ्रांस के सम्बन्ध सबसे अलग व अधिक घनिष्ठ है. दोनों देश इन विशेष सम्बन्धों को निरन्तर आगे बढ़ाने तथा मजबूत करने के लिए प्रयासरत् है. इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जुलाई 2023 में फ्रांस की यात्रा, एक अहम् पड़ाव है. इस यात्रा से सिद्ध होता है कि दोनों देश इस सम्बन्धों को विशेष महत्व प्रदान करते हैं. फ्रांस द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. फ्रांस यह सम्मान अनेक घनिष्ठ मित्र देशों को ही प्रदान करता है. फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाता है जिसका ऐतिहासिक महत्व है. इसी दिन 1789 में फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने निरंकुशता की प्रतीक बैस्टिल जेल पर आक्रमण कर उसमें कैदियों को आजाद करा दिया था. अतः, 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. फ्रांस की क्रान्ति के तीन नारों—स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख स्थान दिया गया है. इन आदर्शों से भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी भी प्रभावित रहे है. अतः ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण इस बात का प्रतीक है कि फ्रांस भारत के साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूती प्रदान करना चाहता है. दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री ने जी-20 के आयोजन की व्यस्तताओं के बीच फ्रांस की अपनी यात्रा को अंजाम देकर द्विपक्षीय सम्बन्धों के महत्व को रेखांकित किया है.

मोदी की फ्रांस यात्रा, 2023

मोदी की 13-14 जुलाई, 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रोन ने, विश्व मामलों में भारत को एक बड़ी ताकत की संज्ञा दी थी. इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े अवार्ड 'ग्रांड क्रास ऑफ लेजन डि ऑनर' से भी सम्मानित किया. मोदी के सम्मान में फ्रांस ने राजकीय भोज का भी आयोजन किया. राष्ट्रीय दिवस की सैनिक परेड में फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमानों ने भी भागीदारी की. इस यात्रा के दौरान मोदी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों तथा वहाँ के व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल से भी मुलाकात की तथा सम्बन्धों को मजबूत बनाने के विषयों पर चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने फ्रांस में निवास कर रहे भारतीयों से भी संवाद किया.

इसके अतिरिक्त इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि दोनों देशों ने सम्बन्धों का दायरा बढ़ाने के लिए 12 समझौतों तथा चार महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए. ये 4 दस्तावेज हैं—1. संयुक्त घोषणा-पत्र, 2. होराइजन 2047—भारत-फ्रांस रणनीतिक सम्बन्धों की 25वीं वर्षगाँठ : भारत-फ्रांस सम्बन्धों की एक शताब्दी 3. सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्ति के लिए साझी प्रतिबद्धता, तथा 4. भारत व फ्रांस का हिन्द-प्रशान्त रोड मैप. इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है.

1. संयुक्त वक्तव्य—भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं—

(अ) दोनों देशों ने 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की लोचशीलता तथा मजबूती को रेखांकित करते हुए माना कि उनकी साझेदारी कतिपय साझा मूल्यों जैसे—सम्प्रभुता तथा सामरिक स्वायत्तता का सम्मान, यूएन चार्टर के सिद्धान्तों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान तथा बहुपक्षीयतावाद में विश्वास आदि पर आधारित है.

(ब) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण तथा डिजिटल नवोन्मेष दोनों की साझेदारी के महत्वपूर्ण आयाम हैं तथा इन क्षेत्रों में दोनों के सहयोग की अपार सम्भावनाएं निहित हैं.

(स) दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के सन्दर्भ में कई क्षेत्रों जैसे—विखण्डित विश्व में एकता स्थापित करना, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को मजबूत बनाना, हिन्द-प्रशान्त में सुरक्षा व शान्ति की स्थापना, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान आदि के सन्दर्भ में दोनों देशों की साझेदारी का विशेष महत्व है.

(द) दोनों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को 2047 तथा उसके बाद तक ले जाने के लिए उच्च लक्ष्यों को अपनाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की ताकि दोनों 2047 में भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ तथा दोनों की रणनीतिक साझेदारी की 50वीं वर्षगाँठ पर इसकी सफलता का समारोह मना सके.

2. होराइजन 2047— भारत-फ्रांस रणनीतिक सम्बन्धों की 25वीं वर्षगाँठ तथा भारत-फ्रांस सम्बन्ध एक शताब्दी की ओर.

इस दस्तावेज में अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी के तीन आयामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है—

(अ) सुरक्षा तथा सम्प्रभुता के लिए साझेदारी—साझेदारी के सुरक्षा आयाम में 6 बिन्दुओं को शामिल किया गया है—

1. साथ-साथ दोनों की प्रतिरक्षा क्षमताओं का विकास.

STUDYPDF WALLAH

भारत व फ्रांस के बीच विशिष्ट सम्बन्धों की पृष्ठभूमि

भारत की आजादी से लेकर आज तक भारत व फ्रांस के सम्बन्ध अलग प्रकार के रहे हैं. वैसे सम्बन्ध भारत ने किसी अन्य यूरोपीय देश के साथ विकसित नहीं किए हैं. इनका उल्लेख निम्नलिखित है–

***प्रथम,** भारत ने जब 1974 में परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया में परमाणु तकनीकी के क्षेत्र में अलग-थलग पड़ गया, क्योंकि अमरीका सहित अधिकांश यूरोपीय देशों ने भारत के विरुद्ध कई तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने इन प्रतिबन्धों की परवाह न करते हुए काफी हद तक भारत को परमाणु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई. वर्ष 2008 में जब भारत व अमरीका के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही थी, तो फ्रांस भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता करने वाला पहला देश बना गया. बाद में अक्टूबर 2008 में अमरीका के साथ भारत ने इसी प्रकार का समझौता किया.*

***दूसरा,** जब भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो अमरीका व यूरोपीय देशों ने भारत के विरुद्ध दोबारा प्रतिबन्ध लगाएं. उस समय फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने भारत के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया तथा भारत के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग करना जारी रखा.*

***तीसरा,** आज भारत ने कई देशों के साथ सामरिक साझेदारी के सम्बन्ध स्थाापित कर लिए है, लेकिन 1998 में फ्रांस पहला देश था जिसके साथ भारत ने सामरिक साझेदारी के सम्बन्ध स्थापित किए थे आज दोनों देश इस साझेदारी की 25वीं वर्षगाँठ मना रहे है.*

***चौथा,** भारत, रूस व अमरीका के बीच सन्तुलित सम्बन्धों का पालन करने के लिए 'सामरिक स्वायत्तता' की नीति का अनुसरण करता है. फ्रांस भी में यूरोप में अमरीकी प्रभाव से बचने के लिए तथा अन्य देशों के साथ सन्तुलित सम्बन्ध बनाने के लिए सामरिक स्वायत्तता की नीति का समर्थक है. स्वायत्तता की इसी नीति के चलते ही फ्रांस ने भारत के साथ शीत युद्ध काल में भी अच्छे सम्बन्ध बनाए रखे जब भारत व अमरीका के बीच कई मामलों में मतभेद व्याप्त था. अन्य यूरोपीय देशों से अलग शीत युद्ध काल में भारत व फ्रांस के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहे हैं. यही भारत व फ्रांस के बीच सम्बन्धों की विशिष्टता है.*

2. हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थायित्व व विकास के लिए ठोस समाधानों पर विचार करना.

3. अन्तरिक्ष सहयोग को मजबूती प्रदान करना.

4. नागरिकों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर.

5. वैश्विक मामलों में बहुपक्षीयतावाद को मजबूत करना.

6. विज्ञान, तकनीकि तथा शैक्षणिक क्षेत्र में नवोन्मेष के क्षेत्र में भागीदारी.

(ब) पृथ्वी प्लानेट के लिए साझेदारी– इस साझेदारी में 4 बिन्दुओं को शामिल किया गया है–

1. जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना.

2. जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता का क्षरण तथा प्रदूषण के तिहरे संकट के समाधान हेतु संयुक्त प्रयास करना.

3. भारत में शहरी, पर्यावरण तथा सामाजिक समावेशीकरण की संक्रमण को मजबूत करना.

4. दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना.

(स) जनता के लिए साझेदारी– फ्रांस व भारत के बीच अगले 25 वर्षों की साझेदारी का तीसरा आयाम जनता के लिए साझेदारी से सम्बन्धित है. इसमें दोनों देशों की जनता के कल्याण व विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है. इसके दो बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. जनता के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना. फ्रांस ने अपने यहाँ 2025 तक 20000 भारतीय छात्र तथा 2030 तक 30000 भारतीय छात्रों के समायोजन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

2. दोनों देशों के बीच नियमित आधार पर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना.

3. सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्ति के लिए साझी प्रतिबद्धता

प्लास्टिक प्रदूषण सारी दुनिया विशेषकर समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा खतरा बन गया है. विभिन्न देशों के अलावा वैश्विक स्तर पर भी प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं. इस सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस ने भी संयुक्त प्रयास करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए है. इसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. दोनों देशों ने उपलब्ध आँकडों के आधार पर माना कि प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक पर्यावरण विशेषकर समुद्री पर्यावरण के लिए एक गम्भीर खतरा है. इसमें कहा गया है कि 1950 से लेकर अब तक 9·2 बिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्सर्जन हुआ है. वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्सर्जन होता है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन कचरा समुद्रों में चला जाता है. चूँकि कुल प्लास्टिक कचरे में सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा एक-तिहाई है. अतः इसके रोकने के संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए.

2. दोनों देशों ने प्लास्टिक कचरे की रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयासों की भी सराहना की. इस सम्बन्ध में स्थायी प्रदूषकों को रोकने के लिए स्टाकहोम सन्धि तथा समुद्री जहाजों द्वारा कचरा फैलाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के एक्शन प्लान का विशेष उल्लेख किया गया.

3. दोनों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने तथा उसके विकल्प खोजने के प्रयासों पर सहमति व्यक्त की. मार्च 2019 में यू. एन. पर्यावरण असेम्बली ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया है.

4. दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कम महत्व वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लोगों के सहयोग से धीरे-धीरे समाप्त किया जाना आवश्यक है. इसके लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धान्तों को भी अपनाया जाएगा.

5. दोनों देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन को कम करने पर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. फ्रांस ने फरवरी 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक के कई उत्पादों पर रोक लगा दी है. वर्ष 2040 तक इसें उपयोग व उत्पादन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. इधर भारत ने भी 12 अगस्त, 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है. भारत ने 2022 में इस सम्बन्ध में उद्योगों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों को एकस्टेण्डेड प्रोड्यूसर रिस्पान्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है. सिद्धान्त रूप में इसे 2016 में ही भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था.

4. भारत व फ्रांस का हिन्द-प्रशान्त रोड मैप

हिन्द महासागर में फ्रांस के नियंत्रण में मेयाटे तथा रियूनियन नामक द्वीप है. इसी प्रकार पूर्वी प्रशान्त महासागर में उसके कई द्वीप स्थित हैं. अतः स्वाभाविक तौर पर हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में फ्रांस के सामरिक हित निहित है. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में आपसी सहयोग का एक रोड मैप जारी किया है, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं–

1. दोनों देशों ने 2019 में हिन्द-प्रशान्त में आपसी सहयोग हेतु जारी विजन दस्तावेज को

शेष पृष्ठ 83 पर

STUDYPDF WALLAH

ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823)

- गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में भारत आया. उसने अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनायी. इसने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया.
- प्रथम ऑग्ल-नेपाल युद्ध (1814-1816) लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया, जो सगौली की संधि (1816) के बाद समाप्त हुआ.
- सगौली की संधि की शर्तों के अनुसार गढवाल तथा कुमायूँ अंग्रेजों के अधिकार में आ गए. गोरखाओं ने काठमाण्डू में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया. शिमला, रानीखेत, नैनीताल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए.
- **तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध** (1817-1818) लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया. हेस्टिंग्स ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर अपने उद्देश्य, आकांक्षा एवं स्वप्न को साकार किया.
- पिण्डारियों का दमन लॉर्ड-हेस्टिंग्स के समय में हुआ. पिंडारी' बर्बर लुटेरों का एक दल था ये मराठों की सेना में सहायक सैनिक के रूप में कार्यरत् थे. इन्हें सिंधिया तथा होल्कर जैसे मराठा सरदार सुरक्षा प्रदान करते थे. सिंधिया द्वारा पिंडारियों को 1794 में नर्मदा के समीप मालवा क्षेत्र में कुछ बस्तियाँ प्रदान की गईं. अंग्रेज लेखक **जॉन मैलकौम** ने पिण्डारियों को 'मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों' की उपमा दी. पिण्डारी आमने सामने की लड़ाई से बचते थे. इनका प्रमुख लक्ष्य लूट-पाट होता था.
- 19वीं शताब्दी के आरम्भिक दिनों में चीतू, वासिल मुहम्मद, करीम खाँ तथा हीरू जैसे पिण्डारी नेता थे.
- पिण्डारियों के पूर्ण दमन के लिए हेस्टिंग्स ने 1816 में कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स से अनुमति प्राप्त की. साथ ही कुछ भारतीय शक्तियों से भी समझौता किया. दौलतराव सिंधिया इस समय तक एक मात्र पिण्डारियों का सरदार था, इसलिए हेस्टिंग्स पिण्डारियों के साथ-साथ सिंधिया को भी कुचलना चाहता था.
- दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु हेस्टिंग्स ने 113,000 सैनिकों तथा 300 तोपों के साथ आक्रमण की योजना बनाई. उत्तरी सेना की कमान हेस्टिंग्स ने अपने पास तथा दक्कनी सेना सर टॉमस हिस्लॉप को सौंपी. मैलकौम हिस्लौप का सहायक था.
- 18 फरवरी, 1818 को करीम खाँ ने मैलकौम के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया उसे 'गौसपुर' (उ.प्र.) की जागीर मिली. वासिल मुहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण ली जिसे सिंधिया ने अंग्रेजों को सौंप दिया. उसने गाजीपुर में कैद अवस्था में आत्महत्या कर ली. चीतू को असीरगढ़ के जंगलों में शेर खा गया. 1824 तक पिण्डारियों का पूर्ण उन्मूलन हो गया.
- लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूत राज्यों तथा कुछ मध्य भारत के राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की. उसने निम्नलिखित राजपूताना राज्यों के साथ प्रतिरक्षात्मक मेल, स्थायी मित्रता, रक्षा एवं अधीन सहयोग की संधि की–

कोटा	–	26 दिसम्बर, 1817
उदयपुर	–	16 जनवरी, 1818
बूँदी	–	10 फरवरी, 1818
किशनगढ़	–	मार्च 1818
बीकानेर	–	मार्च 1818
जयपुर	–	अप्रैल 1818
प्रतापगढ़	–	दिसम्बर 1818
बाँसवाड़ा	–	दिसम्बर 1818
डूँगरपुर	–	दिसम्बर 1818
जैसलमेर	–	दिसम्बर 1818
सिरोही	–	1823

- लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट् के काल्पनिक पद को समाप्त कर दिया. शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय को हेस्टिंग्स ने यह निर्देश दिया कि वह ऐसा कोई उत्सव या समारोह न करे जिससे उसकी प्रभुता कम्पनी सरकार पर समझी जाए.
- हेस्टिंग्स के समय में ही टामस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी तथा एलफिंस्टन ने बम्बई में महालबाड़ी एवं रैयतबाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू किया. बंगाल में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1822 में बंगाल काश्तकारी (Bengal Tenacy Act) अधिनियम हेस्टिंग्स के समय में ही लागू किया गया.

बाजीराव प्रथम (1720-1740 ई.)

- प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत मराठा शासक शाहू ने उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा का पैतृक (वंशानुगत) हो गया.
- बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई. उसने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए **उत्तर दिशा** में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया ताकि "मराठों की पताका कृष्णा से लेकर अटक तक फहराए."
- बाजीराव, मुगल साम्राज्य के तेजी से हो रहे पतन और विघटन के घटनाक्रम से परिचित थे तथा वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते थे.
- मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उसने कहा **"हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगीं."**
- 23 जून, 1724 ई. में **शकूरखेड़ा** के युद्ध में मराठों की सहायता से **निजामुल-मुल्क** ने दक्कन के मुगल सूबेदार **मुबारिज खाँ** को हराकर दक्कन में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की.
- निजामुल-मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत होने पर पुनः मराठों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी तथा चौथ देने से इनकार कर दिया. इसके परिणामस्वरूप 1728 ई. में बाजीराव ने निजामुल-मुल्क को **पालखेड़ा** के युद्ध में पराजित किया. युद्ध में परास्त होने के बाद निजामुल-मुल्क सन्धि के लिए बाध्य हुआ. 6 मार्च, 1728 ई. में दोनों के बीच **मुंशी शिवगाँव** की सन्धि हुई जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया. इस सन्धि के परिणामस्वरूप **दक्कन** में **मराठों की सर्वोच्चता** स्थापित हो गई.
- मुंशी शिवगाँव सन्धि से शाहू को मराठों के एकमात्र नेता के रूप में मान्यता देने आदि सभी शर्तें मंजूर की गई, किन्तु उसने शम्भा जी को शाहू को सौंपने से इनकार कर दिया.
- 1731 ई. हुए डभोई के युद्ध में बाजीराव ने **त्रियम्बकराव** को पराजित कर सारे प्रतिद्वन्द्वियों का अन्त कर दिया.
- 1731 ई. में हुई **वार्ना की सन्धि** द्वारा शम्भा द्वितीय ने शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली.

STUDYPDF WALLAH

- 1737 ई. में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, परन्तु इस बार भी बाजीराव निजाम को **भोपाल** के पास युद्ध में पराजित किया.
- भोपाल युद्ध के परिणामस्वरूप 1738 ई. में **दुरई-सराय** की सन्धि सम्पन्न हुई. इस सन्धि की शर्तें पूर्णतः मराठों के अनुकूल थीं. संधि के अनुसार निजाम ने सम्पूर्ण **मालवा** का प्रदेश तथा **नर्मदा से चम्बल के इलाके की पूरी सत्ता** मराठों को सौंप दी.
- 1739 ई. में बेसीन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कौशल एवं सूझबूझ का प्रतीक थी. इस युद्ध में बाजीराव ने पुर्तगालियों से **सालसीट** तथा **बेसीन** छीन ली. यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी.
- पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, बलात् धर्म परिवर्तन, लूटपाट तथा अत्याचारों के कारण तटवर्ती मराठा समुदाय में उनके प्रति घृणा की भावना आ गई थी. पुर्तगाली साम्राज्य की **उत्तरी** क्षेत्र की राजधानी **बेसीन** तथा **दक्षिणी** क्षेत्र की राजधानी **गोआ** थी. पुर्तगालियों द्वारा सभी जहाजों को परमिट लेने व अपने क्षेत्र के बन्दरगाहों में शुल्क चुकाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता था.
- बाजीराव ने **1733 ई. में जंजीरा के सिद्दियों** के विरुद्ध एक लम्बा शक्तिशाली अभियान आरम्भ किया और अन्ततः उन्हें उनके राज्य से निकाल बाहर कर दिया. सिद्दी जो पहले **निजामशाह** तथा बाद में **आदिलशाह** राज्य में सैनिक अधिकारी थे, 1670 के बाद से **मुगलों** की सेवा में आ गए.
- बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है (सैनिक पेशवा तथा शक्ति के अवतार के रूप में) वह शिवाजी के बाद **गुरिल्ला युद्ध** के सबसे बड़े प्रतिपादक थे.
- शाहू ने बाजीराव प्रथम को 'योग्य पिता का योग्य पुत्र' कहा है.
- बाजीराव प्रथम ने 'हिन्दू पादशाही' का आदर्श रखा. यद्यपि बालाजी बाजीराव ने इसे खत्म कर दिया.
- 1732 ई. में बाजीराव ने एक वसीयत तैयार की जिसमें होल्कर, सिन्धिया, आनन्दराव तथा तुकोजी पवार आदि के हिस्सों की व्याख्या की गई थी. इसी समझौते ने मालवा में भावी चार मराठा रियासतों की आधारशिला रखी.

इल्तुतमिश (1211-1236 ई.)

- कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था.
- इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था. ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूँ का सूबेदार था.
- इल्तुतमिश ने दिल्ली को लाहौर के स्थान पर सल्तनत की राजधानी बनाया.
- अपने शासन के प्रारम्भिक दस वर्षों में उसको अपने दो प्रबलतम् विरोधियों ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कूबाचा के विरोध का सामना करना पड़ा.
- 1221 ई. में भारत पर सम्भावित मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश कूटनीतिक दूरदर्शिता के साथ हल किया. उसने चंगेज खाँ की नाराजगी से बचने के लिए मांगबरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी. जिससे नवोदित दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमण से बच गई.
- अपने सैन्य अभियानों के अन्तर्गत इल्तुतमिश ने 1226 में रणथम्भौर, 1227 में परमारों की राजधानी मंदौर, 1231 में ग्वालियर के शासक मंगलदेव, 1234-35 में उज्जैन और भिलसा के शासकों को पराजित किया.
- 'बामियान' पर किया गया आक्रमण उसका अंतिम सैन्य अभियान था. इसी अभियान के समय घातक बीमारी होने के कारण इल्तुतमिश की 29 अप्रैल, 1236 को मृत्यु हो गई.
- 1229 ई. में बगदाद के खलीफा 'अल मुस्तनसिर बिल्लाह' द्वारा 'खिलअत' प्रदान किए जाने के बाद इल्तुतमिश ने खुद को दिल्ली सल्तनत का वैध एवं स्वतंत्र शासक घोषित किया.
- खलीफा से वैधता मिलने के बाद इल्तुतमिश ने 'नासिर अमीर उल मोमिन' की उपाधि धारण की.
- भारत में मुस्लिम सत्ता के इतिहास की शुरूआत वस्तुतः इल्तुतमिश के शासनकाल के साथ प्रारम्भ होती है. उसने सल्तनत को एक सम्प्रभुता-सम्पन्न राज्य तथा एक राजतंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान की.
- इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन या गुट तैयार किया जिसे 'तुर्कान-ए-चिहालगानी'. 'चालीसा' या 'चरगान' कहा जाता था.
- इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को अनेक छोटी-बड़ी इक्ताओं (प्रशासनिक इकाई) में विभाजित किया. सल्तनत कालीन 'इक्ता' का अर्थ था नकद वेतन के बदले किसी को कृषि योग्य भूमि का लगान हस्तांतरित करना.
- इल्तुतमिश ने 'इक्ता व्यवस्था' का आरम्भ सम्भवतः भारतीय समाज में व्याप्त सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ स्थित क्षेत्रों को केन्द्र के साथ संयुक्त करने के साधन के रूप में किया.
- मध्यकालीन 'मुद्रा प्रणाली' में इल्तुतमिश का योगदान अविस्मरणीय है. वह शुद्ध अरबी पद्धति पर चाँदी का 'टंका' और ताँबे का 'जीतल' नामक सिक्का प्रचलन में लाया.
- इल्तुतमिश ने 'मि-हास-उस-सिराज' तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया.
- इल्तुतमिश ने ऐबक द्वारा शुरू किए 'कुतुबमीनार' का निर्माण पूर्ण कराया. उसने भारत के प्रथम मकबरे 'सुल्तान-गढ़ी मकबरे' का निर्माण कराया.
- इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुनने की परम्परा में एक नई शुरूआत की. उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज के स्थान पर अपनी पुत्री 'रजिया' को अपना उत्तराधिकारी चुना.
- **डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार** "इल्तुतमिश निःसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था."

चन्द्रगुप्त द्वितीय (380-413 ई.)

- समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 380 ई. से 413 ई. तक शासन किया.
- चन्द्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था. विक्रमांक विक्रमादित्य, परम्भागवत आदि इसकी प्रसिद्ध उपाधियाँ थीं.
- चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी नाग वंश की राजकुमारी कुबेरनाग से, प्रभावती गुप्त नामक पुत्री पैदा हुई, कालांतर में उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय से हुआ.
- चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शकों का उन्मूलन किया तथा इस उपलक्ष्य में उसने 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की.
- शकों को पराजित करने के अवसर पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चाँदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया.
- इतिहासकार मेहरौली (दिल्ली) स्थित स्तम्भ लेख का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त द्वितीय से स्थापित करते हैं.
- चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की सीमाएं पश्चिम में पंजाब पूर्व में बंगाल, दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात और काठियावाड़ तक विस्तृत थी.

STUDYPDF WALLAH

- चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी **'पाटिलपुत्र'** थी. वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उज्जयिनी पर भी उसका अधिकार हो गया जिसे उसने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई.
- चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी 'अश्वमेध यज्ञ' का आयोजन भी किया.
- चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान भारत आया, जो 405 से 412 ई. तक भारत में रहा. फाह्यान भारत बौद्ध पाण्डुलिपियों तथा पाठों का संग्रह करने एवं उनके अध्ययन करने के उद्देश्य से आया था.
- अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्रियों आम्रकार्दव, शाब वीरसेन, शिखर स्वामी आदि का उल्लेख मिलता है.
- अभिलेखों में उसके अधिकारियों में बलाधिकृत (सेनापति), दंडपाशिक (पुलिस विभाग), महादंडनायक (न्यायाधीश मुख्य), उपरिक (राज्यपाल) आदि का उल्लेख मिलता है.
- चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गोविंदगुप्त तीरभुक्ति और घटोत्कच गुप्त एरिकिण प्रदेश (एरण) का राज्यपाल था.
- चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धर प्रकार, पीठिकारुढ़ प्रकार, छत्र प्रकार, सिंह-हंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाए.
- चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैष्णव धर्मावलम्बी होने के कारण 'परमभागवत्' की उपाधि धारण की.
- चंद्रगुप्त का संधि विग्रहक वीरसेन, शैव, आम्रकार्दव (सेनापति) बौद्ध मतावलम्बी था.
- चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे.
- चंद्रगुप्त के दरबार में विद्वानों को संरक्षण मिला था. उसके नवरत्नों में शामिल थे–कालिदास, अमरसिंह, धनवन्तरि, क्षपणक, शंकु वेलाभट्ट, बराहमिहिर, घटकर्ण, वरचि आदि.
- चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था.
- चंद्रगुप्त द्वारा प्रचलित किए गए ताँबे के सिक्के के मुख्य-भाग पर 'श्री विक्रम' तथा पृष्ठभाग पर गरुढ़ की आकृति के साथ चंद्रगुप्त खुदा था.
- चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों का उन्मूलन किए जाने का विवरण उदयगिरी अभिलेख से मिलता है.

ऐतिहासिक स्थल

पोखरण

- वर्तमान राजस्थान में स्थित जैसलमेर के भाटी शासकों की यह एक प्राचीन राजधानी के रूप में जाना जाता है. इस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को हुआ. इसके बाद भारत सरकार ने 11–18 मई, 1998 को लगातार दो परमाणु परीक्षण किए, जो भारत की परमाणु ताकत को विश्व में प्रदर्शित करता है.
- पोखरण में जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस स्थान को **'खैतोलाई'** नाम दिया.
- पोखरण के समीप बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ का मन्दिर स्थित है.
- जैसलमेर में पेयजल स्रोत गडसीसर झील स्थित है, जिसका निर्माण जैसलमेर के महारावल गणसी सिंह ने कराया. इस झील के किनारे एक प्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संग्रहालय बना हुआ है.
- जैसलमेर में ही बादल विलास एवं जवाहर विलास महल स्थित है. बादल महल की ऐतिहासिकता इस बात में निहित है कि राजस्थान का सबसे बड़ा **'पाँच मंजिला ताजिया'** स्थित है.
- जैसलमेर शहर का एक अन्य भव्य स्थान **'बड़ा भाग'** की छतरियाँ हैं. ये छतरियाँ जैसलमेर के भाटी शासकों की बनी हुई हैं, इन्हें भाटी शासकों की प्राचीन स्मारक कहते हैं.
- जैसलमेर के समीप भारती बाबा का मठ बना हुआ है. यह मठ जैसलमेर की गजरूप सागर झील के किनारे बना है.
- जैसलमेर की मूल सागर झील के किनारे हमें कश्मीर के निशान्त बाग व शालीमार बाग देखने को मिलते हैं, जो हमें कश्मीर की याद दिलाते हैं. कश्मीर में इन बागों का निर्माण मुगल सम्राट् जहाँगीर ने कराया था, ऐसे ही कृत्रिम बाग इस झील के किनारे बने हैं.
- मूलसागर झील के किनारे ही राज्य का प्रसिद्ध रोकड़िया गणेश मन्दिर बना हुआ है, जो पूर्ण सफेद पत्थरों से युक्त है.

  नोट–राजस्थान का प्रसिद्ध गणेश मन्दिर रणथम्भौर सवाई माधोपुर में स्थित है. इसे **'त्रिनेत्र गणेश मन्दिर'** कहते हैं. राज्य का सबसे प्रसिद्ध गणेश मेले का आयोजन इसी स्थान पर किया है.
- राजस्थान में खड़े गणेश की मूर्ति कैथून (कोटा) में स्थित है. भारत का एकमात्र विभीषण मन्दिर भी इसी स्थान पर बना हुआ है.
- राजस्थान में नृत्य करते हुए गणेश की मूर्ति सरिस्का अलवर में स्थित है.
- राजस्थान में एक प्रसिद्ध गणेश मन्दिर जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है. इस गणेश मन्दिर की विशेषता यह है कि इस मन्दिर में गणेशजी को मूषक पर सवार न दिखाकर सिंह पर सवार दिखाया गया है, जो अपने आप में अनुपम उदाहरण है.

झूंसी

- यह स्थल प्रयागराज के पूर्व दिशा में लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के पार स्थित है.
- इसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर मिलता है.
- मूलतः यहाँ एक ठोस टीला था, जो अब बरसाती नालियों तथा लोगों के अतिक्रमण के कारण कई टीलों में विभक्त हो गया है. समुद्रकूप नामक टीला, जो भूतल से सोलह मीटर ऊँचा है, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित अवस्था में है.
- रामायण काल में प्रतिष्ठान चन्द्रवंशी राजाओं की राजधानी था. इसकी स्थापना इला नामक पौराणिक राजा ने की थी.
- कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय का दृश्यांकन यहीं किया था.
- अभिलेखीय साक्ष्यों से सूचित होता है, कि बारहवीं शती तक प्रतिष्ठान का महत्व था. प्रतिहार नरेश त्रिलोचनपाल का लेख (1027 ई.) यहाँ से मिलता है जिसमें उसके द्वारा यहाँ के ब्राह्मणों को भूमिदान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है. गहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र के दानपत्र (1126 ई.) में भी श्रीप्रतिष्ठान का उल्लेख मिलता है, जो प्रयाग क्षेत्र के अन्तर्गत आता था.
- यह निश्चित नहीं है कि इस नगर का नाम प्रतिष्ठान से झूंसी कैसे हो गया ?
- स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर हरवेंग नामक मूर्ख एवं मन्दबुद्धि राजा था उसके राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई जिससे प्रजा अक्रान्त हो गई. गोरखनाथ तथा उनके शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ के शाप से नगर में भीषण अग्निकाण्ड हुआ और यह जलकर भस्म हो गया. इसी के ध्वंसावशेष झूंसी कहे गए, जिसका शाब्दिक अर्थ है जला हुआ नगर (A burnt town).

STUDYPDF WALLAH

- झूंसी के टीले का उत्खनन एवं अन्वेषण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा समय-समय पर करवाया गया.
- परिणामस्वरूप यहाँ से मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियाँ, सिक्के, मुहरें, मुद्राएं, ताम्र एवं हाथी दाँत की वस्तुएं आदि प्राप्त हुईं. इनका समय प्राक् एन बी पी से मध्यकाल तक निर्धारित किया गया है.

तालगुण्ड

- कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में यह स्थान स्थित है.
- यहाँ का प्रणवेश्वर शिव मन्दिर कर्नाटक का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है. इसका निर्माण हलेविड के होयसलेश्वर मन्दिर की शैली पर हुआ है.
- तालगुण्ड से एक स्तम्भ के ऊपर उत्कीर्ण कदम्ब नरेश शान्तिवर्मन (450-475 ई.) का लेख मिलता है जिसमें इस वंश के राजाओं तथा उनके इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है.
- इस वंश का सबसे प्रतापी राजा काकुत्सवर्मन था. तालगुण्ड लेख के अनुसार उसने अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त तथा वाकाटक वंशों में किया था. तालगुण्ड में उसने एक विशाल सरोवर भी खुदवाया था. यह लेख कदम्ब नरेशों के इतिहास का एकमात्र स्रोत है.

तन्जौर

- तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली जिले में स्थित तन्जौर नामक नगर प्राचीन समय में सुप्रसिद्ध चोल शासकों की राजधानी था. यह नगर कावेरी नदी के दक्षिण की ओर बसा है.
- चोल राजाओं के काल में इसकी महती उन्नति हुई.
- प्रसिद्ध चोल शासक राजराज ने 1000 ई. के लगभग यहाँ के वृहदीश्वर (राज-राजेश्वर) मन्दिर का निर्माण करवाया था.
- यह 500′ × 500′ के आकार वाले विशाल प्रांगण में स्थित है. इसमें मध्य-कालीन वास्तुकला के सभी लक्षण मिलते हैं. मन्दिर के गर्भगृह, मण्डप तथा विमान सभी आकर्षक हैं. विमान 190 फीट ऊँचा है. मन्दिर की तीन बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी-देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं बनी हुई हैं. गर्भगृह को भी अनेक सुन्दर मूर्तियों तथा चित्रों से अलंकृत किया गया है. यह मन्दिर दक्षिणी भारत का सर्वश्रेष्ठ हिन्दू मन्दिर माना जाता है.
- **प्रो. नीलकण्ठ शास्त्री** के शब्दों में "भारत के मन्दिरों में सबसे बड़ा तथा लम्बा यह मन्दिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है, जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करती है. द्रविड़ शैली का यह सर्वोत्तम नमूना है."
- **वृहदीश्वर (शिव)** के मन्दिर के अति-रिक्त तन्जौर से कई अन्य मन्दिरों के भी उदाहरण मिलते हैं. इनमें सुब्रह्मण्यम मन्दिर तथा रामानाथस्वामी का मन्दिर उल्लेखनीय है.
- कुल मिलाकर यहाँ 75 से भी अधिक छोटे-बड़े मन्दिर यहाँ विद्यमान हैं. ●●●

शेष पृष्ठ 79 का

रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र, खुले तथा सुरक्षित हिन्द-प्रशान्त की स्थापना दोनों का साझा लक्ष्य है. दोनों इस क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा इसके संतुलित व जीवन्त विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं.

2. इस सम्बन्ध में फ्रांस ने भारत की सागर परियोजना का स्वागत किया जिसमें इस क्षेत्र में सभी की सुरक्षा व विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस की हिन्द-प्रशान्त रणनीति का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य भी इस क्षेत्र में सुरक्षा का विकास करना है.

3. दोनों ने इस क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने तथा क्षमता विकास में सहयोग करने का निर्णय लिया. दोनों समुद्री क्षेत्र की जानकारी बढ़ाने में सहयोग को बढ़ाएंगे.

4. फ्रांस न भारत द्वारा 2019 में शुरू किए गए हिन्द-प्रशान्त समुद्री पहल का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य साझा सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करना है.

5. इस क्षेत्र में दोनों ने स्वच्छ इनर्जी तथा पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया.

6. दोनों देश इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के लिए लोचशील ढाँचागत सुविधाओं के विकास में सहयोग को बढ़ाएंगे.

7. दोनों ने माना कि फ्रांस व भारत की साझेदारी इस क्षेत्र में शान्ति व स्थिरता की स्थापना में सहायक सिद्ध होगी.

महत्वपूर्ण समझौते

इस यात्रा के दौरान भारत व फ्रांस ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से 6 प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं–

1. भारत में नए राष्ट्रीय म्यूजियम की स्थापना में सहयोग का समझौता.

2. डिजिटल तकनीकी में आपसी सहयोग बढ़ाने का समझौता.

3. भारत व फ्रांस के सहयोग से लागू किए जाने वाले दूर संवेदी मिशन के संचालन का समझौता.

4. सैटेलाइट लॉन्च वाहनों के संयुक्त विकास पर समझौता.

5. स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बनाने का समझौता.

6. समुद्री विज्ञान व पृथ्वी विज्ञान में सहयोग का समझौता.

निष्कर्ष

भारत व फ्रांस के सम्बन्धों के उक्त विशिष्ट पृष्ठभूमि के आलोक में प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान यात्रा की उपलब्धियों से स्पष्ट है कि वर्तमान में यूरोप में फ्रांस वास्तव में भारत का सबसे मजबूत व विश्वसनीय साझीदार देश है. दोनों ने शीतयुद्ध काल में अपने सम्बन्धों की घनिष्ठता को बनाए रखा. यह दोनों के सम्बन्धों की मजबूती व लोचशीलता का संकेत है. व्यापार, निवेश तथा सांस्कृतिक सहयोग के अलावा दोनों देशों का प्रतिरक्षा व हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में सामरिक सहयोग उल्लेखनीय है. प्रतिरक्षा के क्षेत्र में फ्रांस सदैव भारत के लिए उच्च तकनीकी उत्पादों का स्रोत रहा है. भारत ने फ्रांस से ही उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की है. दोनों देश वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के आलोक में स्वच्छ इनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग कर रहे हैं. भारत व फ्रांस दोनों ने मिलकर ही इण्टरनेशनल सोलर एलायन्स की 2015 में स्थापना की थी. इसी प्रकार चीन की सामरिक चुनौती का सामना करने के लिए फ्रांस व भारत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में भी अपने सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं. जी-20 सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे में भी फ्रांस एक साझीदार देश है. अब दोनों देशों ने अगले 25 वर्षों यानि कि 2047 तक रणनीतिक साझेदारी में नए आयामों को जोड़ने का प्रयास किया है. अतः हम कह सकते हैं कि रणनीतिक साझेदारी का भविष्य उज्ज्वल है. ●●●

UPKAR'S
Multi-Dimensional
REASONING
(VERBAL & NON-VERBAL)
Useful for Various Competitive Exams.
By : Dr. Lal, Mishra & Kumar
Code No. 1624 ₹ 380/-
UPKAR PRAKASHAN, AGRA-5
E-mail : care@upkar.in Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति

ओधुवर (Odhuvars)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के शैव मंदिरों में भजन और स्तुति गाकर देवी-देवताओं की पूजा-वंदना करने के लिए 15 ओधुवरों (जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं) की नियुक्ति के आदेश दिए हैं.

प्रमुख तथ्य

ओधुवर

- ओधुवर तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में विशेषकर धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के दौरान भक्ति संगीत प्रस्तुत करने वाले संगीतज्ञ हैं, किन्तु वे पुजारी की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा उन्हें पवित्र गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है.
- वे पुरुष और महिला दोनों वर्गों से हो सकते हैं. वे न केवल नियमित पूजा के दौरान, बल्कि विशेष कार्यों और त्योहारों के दौरान थिरुमुराई गायन की प्रस्तुति देते हैं. इस परम्परा का उद्देश्य प्राचीन तमिल भक्ति परम्परा का संरक्षण और प्रसार करना है.
- थेवरम और थिरुवसागम दो प्राचीन तमिल ग्रंथ हैं, यह भगवान शिव के भजन तथा स्तुतियों का संकलन है, इन गीतों के गायन का कार्य प्राचीन काल से ओधुवर ही करते आए हैं.
- प्राचीनकाल से ही ओधुवरों की परम्परा रही है, भक्ति आन्दोलन दौरान इनकी मान्यता का पता चलता है. तमिलनाडु में 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच ओधुवर परम्परा अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी.
- इस अवधि के दौरान अलवार और नयनार के नाम से प्रचलित अनेक संत-कवियों ने क्रमशः भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की स्तुति में भजनों के रूप में भक्ति काव्य की रचना की. ओधुवर इस समृद्ध संगीत व भक्ति विरासत के संरक्षक के रूप में उभरे.

अलवार और नयनार

अलवार :

- *अलवर को अलवरकल भी कहा जाता है. ये वैष्णव (भगवान विष्णु के भक्त) संत-कवियों का एक समूह था. उनकी रचनाएं मुख्य रूप से भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा-भक्ति पर केन्द्रित थीं और इन रचनाओं में मोक्ष प्राप्त करने हेतु ईश्वर के प्रति समर्पण (प्रपत्ति) की अवधारणा पर बल दिया गया था.*
- *आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि अलवार 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे. हालाँकि, एक अन्य अध्ययन से इनके 4200 और 2700 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं.*
- *आलवारों के भक्ति भजन और कविताएं प्रमुख वैष्णव ग्रंथ, 'नालयिर दिव्य प्रबंधम' में संकलित हैं. तमिल भाषा में रचित इन रचनाओं में भगवान विष्णु के दिव्य गुणों एवं रूपों का वर्णन है.*
- *प्रमुख अलवार संत हैं–श्री अंडाल, थिरुमाझीसाई अलवार, तिरुप्पन लवार,नम्माव्वार, कुलसेकरा लवार. दक्षिण भारत के 12 आलवार संतों में आंडाल एकमात्र महिला अलवार थीं.*

नयनार :

- *नयनार शैव (भगवान शिव के भक्त) संत-कवियों का एक समूह था. इनकी संख्या 63 थी. ये भगवान शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और उनकी स्तुति में भजन व काव्य की रचना करते थे, ये रचनाएं भक्ति मार्ग तथा परमात्मा के प्रति प्रेम पर केन्द्रित थीं.*
- *नयनारों के भजन और काव्य रचनाएं **शैव धर्मग्रंथों के संग्रह थिरुमुराई** में संकलित की गईं. तमिल भाषा में लिखित इन रचनाओं में भगवान शिव की विभिन्न रूपों तथा दिव्य गुणों का वर्णन है.*
- *नयनार संतो की संख्या 63 है. उनमें से, ज्ञानसंपंदर, अप्पार, और सुंदरार (जिन्हें अक्सर त्रिमूर्ति कहा जाता है) को दक्षिण भारतीय मंदिरों में उनकी छवियों के माध्यम से संत के रूप में पूजा जाता है.*
- *नयनार संतों में केवल 3 महिलाएं-मंगायार्कक्करसियर (50वीं नयनमार), इसैग्ननियार (63वीं नयनमार) और कराईकल अम्मैयर (24वीं नयनमार) थीं.*

वर्तमान सन्दर्भ में ओधुवरों की प्रासंगिकता

- ओधुवरों ने तमिल भाषा के संरक्षण और प्रसार में अहम योगदान दिया है. अपने भक्ति काव्य के माध्यम से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन तमिल ग्रंथों की समझ व पठन-पाठन को सरल बनाया है.
- अधिकांशतः ओधुवर संगीतज्ञ बहिष्कृत समुदायों से सम्बन्धित होते हैं और मंदिरों में किसी भी कार्य के लिए उनकी भूमिका का निर्धारण किया जाना उनके लिए सामाजिक एवं आर्थिक समुन्नयन का अवसर है. इसके साथ ही उनकी कला स्थानीय समुदाय को एकजुट करने के साथ ही एकता व अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है.

ओधुवरों से सम्बन्धित मुद्दे व चिंताएं

- ओधुवरों को अक्सर आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के दान और चढ़ावे पर निर्भर करता है. ओधुवरों की निश्चित आय का न होना इस भक्ति परम्परा के पतन का कारण भी बन सकती है.
- ओधुवरों की आर्थिक असुरक्षा के कारण इस बात की काफी सम्भावना है कि युवा पीढ़ी के बीच ओधुवर परम्परा में रुचि में कमी आ सकती है. यह इस परम्परा की निरन्तरता के लिए चिंता का विषय है.
- सरकारी संस्थानों से समर्थन एवं सहयोग न मिलना भी ओधुवरों की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, जबकि सरकारी संस्थानों के सहयोग से ओधुवर समुदायों की पीड़ाओं को काफी कम किया जा सकता है.
- डिजिटल मीडिया और समकालीन संगीत रूपों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना ओधुवरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है.

राजनीति, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय

सरोगेसी (Surrogacy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि भारत में सरोगेसी की अनुमति देने या न देने के लिए महिलाओं की पात्रता (वैवाहिक स्थिति, उम्र या लिंग मानदंड) क्यों हैं ?

STUDYPDF WALLAH

प्रमुख तथ्य

सरोगेसी

- सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई महिला (सरोगेट) संतान के इच्छुक किसी अन्य दम्पत्ति की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है.
- इस पूरी प्रक्रिया में सरोगेट (गर्भकालीन वाहक), वह महिला होती है, जो किसी दम्पत्ति (इच्छित माता-पिता) हेतु गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है.
- सरोगेसी की अनुमति तब दी जाती है जब–(i) उन इच्छुक जोड़ों के लिए, जो सिद्ध बांझपन से पीड़ित हैं; (ii) परोपकारी; (iii) व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं; (iv) बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, और (v) विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी बीमारी या स्थिति के लिए.

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021–सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के साथ, भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह केवल 'परोपकारी सरोगेसी' (निःस्वार्थ किया गया सेरोगेसी) की अनुमति देता है, जहाँ चिकित्सा व्यय और बीमा के अलावा सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं मिलता है. एकल पुरुष, विषमलैंगिक जोड़ों, समान-लिंग वाले जोड़ों और एलजीबीटीक्यू व्यक्ति ऐसी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रावधान निम्नलिखित है–

प्रावधान

- सरोगेसी के इच्छित दम्पत्ति विधिक रूप से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा. इस अधिनियम के अनुसार पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच होगी तथा महिला की आयु 25-50 वर्ष के बीच होगी और उनकी पहले से कोई जैविक, गोद ली हुई या सरोगेट संतान नहीं होगी.
- यह अधिनियम व्यावसायिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध लगाता है. व्यावसायिक सरोगेसी के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कारागृह और ₹ 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
- यह अधिनियम केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहाँ कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता है.
- सरोगेसी का विकल्प चुनने वाले जोड़े का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए. सरोगेट बनने के लिए सहमत होने वाली कोई भी महिला अपने जीवन में एक से अधिक बार सरोगेट नहीं हो सकती है और उस समय उसे चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस के लिए प्रमाणित होना चाहिए.
- सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी/प्राधिकरण की लिखित अनुमति होनी चाहिए. यह प्राधिकरण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के अनुरूप होना चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरोगेसी पर दिया गया निर्णय

मार्च 2023 में एक सरकारी आदेश ने प्रदाता युग्मकों (Donor Gametes) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून में संशोधन किया. इस आदेश में कहा गया था कि 'इच्छुक जोड़ों' को सरोगेसी के लिए अपने स्वयं के युग्मकों (Gametes) का उपयोग करना होगा. इस संशोधन को महिला के मातृत्व के अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी.

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शिशु का माता या पिता से आनुवंशिक सम्बन्ध होना चाहिए. न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गर्भकाल में सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून 'महिला-केन्द्रित' है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट शिशु को जन्म देने का निर्णय महिला की चिकित्सीय या जन्मजात स्थिति के कारण माँ बनने में असमर्थता पर आधारित है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब सरोगेसी नियमों का नियम 14(a) लागू होता है, जो चिकित्सा या जन्मजात स्थितियों को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को गर्भकालीन/जेस्टेशनल सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छित जोड़े, विशेषकर पिता से सम्बन्धित होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिए सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के नियम 7 को प्रतिबंधित किया है, जो मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सिंड्रोम (एक असामान्य जन्मजात विकार, जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता डिम्ब/अंडाणु का प्रयोग करके सरोगेसी के क्रियान्वयन की अनुमति दी जा सके.

सरोगेसी अधिनियम का नियम 7 प्रक्रिया के लिए प्रदाता डिम्ब/अंडाणु के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है.

- अधिनियम, सरोगेसी और सरोगेट माँ का चयन करने वाले जोड़े दोनों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड भी निर्धारित करता है.जोड़ों के पास 'सभी अनिवार्य शर्तों' का होना आवश्यक है, जिसमें एक या दोनों व्यक्तियों के प्रमाणित बांझपन का प्रमाण-पत्र, सरोगेट के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की परवरिश और देखभाल के विषय में अदालत का आदेश और 16 महीने के लिए सरोगेट माँ के लिए बीमा कवरेज शामिल है, (जिसमें पोस्ट-पार्टम डिलीवरी जटिलताओं की परिस्थिति भी शामिल है.)

जेस्टेशनल सरोगेसी

जेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिए एक बच्चे को जन्म देती है. इसमें सरोगेट मदर बच्चे की जैविक माँ नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है. इस गर्भाधान में होने वाले अथवा डोनर/प्रदाता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का टेस्ट-ट्यूब के तहत् निषेचन कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है.

सरोगेसी से सम्बन्धित चुनौतियाँ

- भारत की तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बहस इसके आर्थिक लाभ के बजाय सरोगेसी की नैतिकता पर केन्द्रित है. दूसरी ओर, सरोगेसी के अभ्यास के पीछे आर्थिक लाभ मुख्य मानदंड है. सरोगेट बनने वाली अधिकांश महिलाएं गरीबी, वित्तीय संसाधनों की कमी, कम शैक्षिक स्तर के कारण बेहद कमजोर होती हैं. उनके लिए वित्तीय लाभ प्रमुख कारक है. यह उनके आर्थिक शोषण को बहुत आसान बनाता है.
- व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे महिलाओं की अपने प्रजनन सम्बन्धी निर्णय लेने की स्वायत्तता और मातृत्व का अधिकार समाप्त हो जाता है.
- सरोगेसी एक परिवार के मूल्यों और निष्ठा में बच्चों की धारणा को प्रभावित कर सकती है. गोपनीयता और गुमनामी एक नकारात्मक वातावरण बनाते हैं, जो परिवारों के भीतर और बाहर मानव सम्बन्धों को प्रभावित करता है. इसमें माता-पिता की पहचान के बारे में जानकारी के लिए बच्चों के अधिकार के मुद्दे भी शामिल हैं. इसके कारण गोपनीयता और गुमनामी, को 'रक्त सम्बन्धों' की प्रधानता जैसे सामाजिक मूल्य में भी जोड़ा जाता है.
- सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अविवाहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लिव-इन पार्टनर्स और समान-लिंग वाले

STUDYPDF WALLAH

युग्मों को बाहर रखा गया है. यह वैवाहिक स्थिति लिंग एवं यौन रुझान के आधार पर भेदभाव है और उन्हें अपनी इच्छा का परिवार बनाने के अधिकार से वंचित करता है.

- परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ के रूप में कोई दोस्त अथवा रिश्तेदार न केवल भावी माता-पिता के लिए बल्कि सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सरोगेसी की अवधि और जन्म के बाद बच्चे से उनके रिश्ते को लेकर समस्याएं हो सकती हैं.

पर्यावरण एवं प्रदूषण

अनुकूलन गैप रिपोर्ट, 2023 (The Adaptation Gap Report, 2023)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2023 का नवीनतम संस्करण जारी किया है. दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली COP28 जलवायु वार्ता से पहले यह रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को सार्थक अनुकूलन कार्यों हेतु इस दशक में प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 215 बिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता है. वर्ष 2021 में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को लगभग 21 बिलियन अमरीकी डॉलर दिए गए, जो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम था. इस वर्ष की रिपोर्ट अनुकूलन अथवा अनुकूलन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता पर केन्द्रित है.

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

अनुकूलन वित्त अन्तर

- रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूलन वित्त अंतर बढ़ रहा है. यह अब प्रति वर्ष $194 बिलियन से $366 बिलियन के बीच है.
- अनुकूलन अन्तर के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह से 10-18 गुना अधिक होने की सम्भावना है, जो विगत अनुमानों की तुलना में लगभग 50% अधिक है.
- अनुकूलन वित्त अन्तर का आशय अनुमानित अनुकूलन वित्त पोषण आवश्यकताओं तथा लागत व वित्त प्रवाह के बीच के अन्तर से है, जो समय के साथ और बढ़ गया है.

अनुकूलन एवं न्यूनीकरण

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण रणनीतियों और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच अन्तर यह है कि न्यूनीकरण का उद्देश्य जहाँ जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटना और सम्भावित प्रभावों को कम करना है, वहीं अनुकूलन यह देखता है कि इसके नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए और किसी भी अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए. जहाँ न्यूनीकरण रणनीतियाँ उत्सर्जन नियंत्रण लक्ष्यों तक पहुँचने में विफल रहती हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पृथ्वी के बाकी निवासियों के साथ-साथ हमारे अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जलवायु अनुकूलन महत्वपूर्ण होगा.

वित्तपोषण के लिए लैंगिक समानता

- वित्तपोषण के लिए लैंगिक समानता अनुकूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तपोषण का केवल 2%, जिसमें लैंगिक समानता को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, का मूल्यांकन लैंगिक रूप से उत्तरदायी के रूप में किया गया है, शेष 24% या तो लिंग-विशिष्ट अथवा एकीकृत है.

वित्तपोषण बढ़ाने हेतु 7 उपाय

- सम्भावित रूप से घरेलू व्यय एवं निजी वित्तपोषण अनुकूलन वित्त के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, घरेलू बजट विकासशील देशों में अनुकूलन के लिए वित्तपोषण का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, जो सरकारी बजट का 0·2% से लेकर 5% तक हो सकता है.
- बड़ी कम्पनियों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा 'आंतरिक निवेश', एवं अनुकूलन में योगदान देने वाली गतिविधियों के लिए वित्त एवं सेवाओं के प्रावधान की आवश्यकता है.
- रिपोर्ट में वैश्विक वित्तीय ढाँचे में सुधार का आह्वान किया गया है, जिससे बहुपक्षीय एजेंसियों यथा विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जलवायु-सम्बन्धी उद्देश्यों हेतु वित्त की अधिक और आसान पहुँच सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह का मौजूदा स्तर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है.
- जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए अनुकूलन आवश्यक है, विशेष रूप विकासशील तथा आर्थिक रूप से कमजोर देशों में, क्योंकि इनके पास जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए कोई तत्काल समाधान नहीं है. इन अनुकूलन उपायों के लिए पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता होती है. देश अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न अनुकूलन उपाय करते हैं जिनमें समुद्र तटीय क्षेत्रों को सुदृढ़ करना, द्वीपीय राष्ट्रों में समुद्री अवरोधों का निर्माण करना, उष्म प्रतिरोधी फसलों के साथ प्रयोग करना, जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना, जल स्रोतों को सुरक्षित करना और स्थानीय आबादी को बढ़ते तापमान तथा उनके दुष्परिणाम से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करने के लिए इसी तरह के प्रयास शामिल हैं, लेकिन ये अनुकूली उपाय सरकारों की बजटीय पहुँच से परे वित्तीय दायित्व थोपते हैं.
- अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के अनुसार, विकसित देश जलवायु परिवर्तन

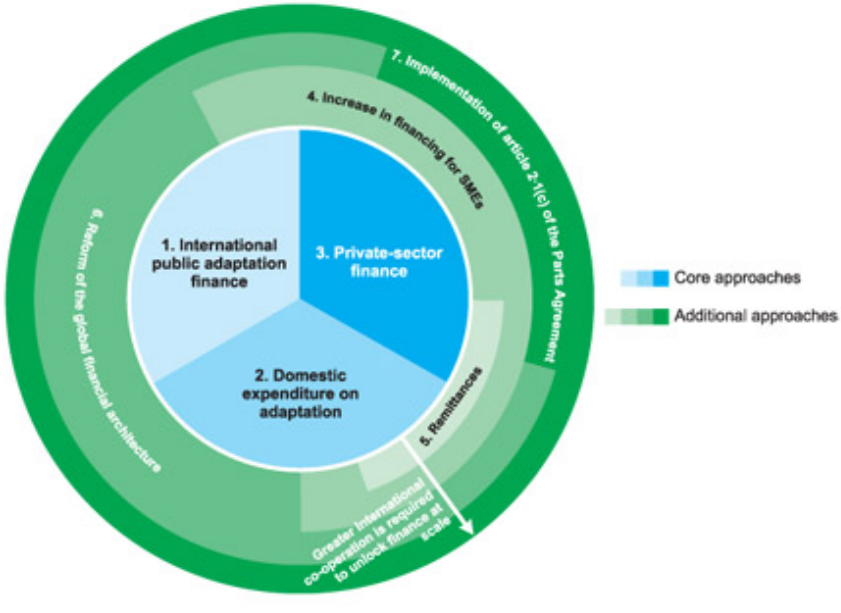

STUDYPDF WALLAH

के अनुकूल विकासशील देशों के समर्थन हेतु वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए बाध्य हैं. विकसित देश विभिन्न सम्मेलनों और संधियों के बावजूद अपेक्षित धन जुटाने में विफल रहे हैं.

- अधिकांश विकासशील देशों ने अपनी अनुकूलन आवश्यकताओं को अपनी जलवायु कार्य योजनाओं में सूचीबद्ध किया है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हर देश के योगदान का दस्तावेजीकरण करना चाहते हैं.

भारत और अनुकूलन अन्तराल

- बढ़ते जलवायु जोखिमों और कार्यान्वित अनुकूलन के बीच बढ़ते अन्तर को लेकर जिस तर्क को दक्षिण के देश पिछले एक दशक से अधिक समय दे रहे थे, अनुकूलन गैप रिपोर्ट, 2023 उनके उस तर्क की पुनः पुष्टि करती है,
- बढ़ते जलवायु जोखिमों और कार्यान्वित अनुकूलन के बीच यह अन्तर समान रूप से महसूस नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाली आबादी को सबसे अधिक प्रभावित करता है.
- कुछ देशों को व्यापक अन्तर का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार–अफ्रीका, दक्षिण और मध्य एशिया के देशों में व्यापक अनुकूलन अन्तर दिखाई देता है. भारत में भी जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं और नुकसान बढ़ रहे हैं.
- उच्च उत्सर्जकों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के अपर्याप्त शमन के कारण ये जोखिम बढ़ रहे हैं. इसके अलावा, इन बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिए वित्त बहुत कम है. जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे का निर्माण, जटिल जोखिम प्रबंधन की तैयारी के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करना और तकनीकी नवाचारों को सक्षम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और भारतीय वैश्विक वित्तपोषण तंत्र सबसे कमजोर लोगों तक पहुँचने में विफल हो रहे हैं.
- रिपोर्ट अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन की अपर्याप्त प्रगति पर प्रकाश डालती है, साथ ही यह प्रत्याशित, न्यायसंगत और प्रभावी अनुकूलन कार्रवाई और समर्थन पर अधिक ध्यान देने का भी आह्वान करती है.
- यह भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न जलवायु जोखिमों का सामना करता है.
- अनुकूलन गैप रिपोर्ट, 2023 भारत के लिए अपने जलवायु अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है और अनुकूलन वित्त अंतर को कम करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन की माँग करती है.
- यह भारत और दुनिया के लिए अधिक लचीला और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को साथ मिलकर काम करने का एक आह्वान है.

आर्थिक एवं वित्तीय अवधारणाएं

लुईस मॉडल और भारत (Lewis Model & India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में चीन और भारत की अर्थ-व्यवस्था के तुलनात्मक सन्दर्भ में लुईस मॉडल की चर्चा हो रही है. लुईस मॉडल जहाँ चीन के लिए सफल साबित हुआ है वहीं कृषि से औद्योगीकरण में संक्रमण के दौरान चुनौतियों का सामना करने के कारण भारत इसके कार्यान्वयन से जूझ रहा है.

प्रमुख तथ्य

लुईस मॉडल

- 1954 में, नोबेल पुरस्कार विजेता सर आर्थर लुईस ने अपने निबंध 'श्रम की असीमित आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास' में एक आर्थिक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा. यह सिद्धांत एक द्वैत अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है. इसमें दो क्षेत्र हैं–
  1. पूँजीवादी क्षेत्र
  2. जीवन निर्वाह क्षेत्र
- लुईस के मॉडल ने तर्क दिया कि श्रम की अधिकता वाले अविकसित देश श्रमिकों को कृषि से विनिर्माण क्षेत्र में स्थानांतरित करके, आर्थिक विकास का एक अच्छा चक्र बनाकर तेजी से औद्योगीकरण प्राप्त कर सकते हैं.
- मॉडल के सार ने सुझाव दिया कि कृषि में अतिरिक्त श्रम को विनिर्माण क्षेत्र में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, इसके लिए श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से दूर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मजदूरी का प्रस्ताव देना आवश्यक है. यह बदलाव, सैद्धांतिक रूप से, औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.

चीन और लुईस मॉडल

- चीन द्वारा इस मॉडल का अपनाए जाने के बाद वहाँ इसका अनुप्रयोग सफल रहा. चीन ने अपनी जनसंख्या लाभ और अधिशेष ग्रामीण श्रम का उपयोग करते हुए, राज्य की योजना के साथ बाजार की शक्तियों को जोड़ा. इस रणनीति से न कॉल विदेशी निवेश को आकर्षित किया बल्कि निर्यात एवं घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा दिया.
- साथ ही चीन ने बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास में व्यापक निवेश ने उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से

लुईस मॉडल के प्रमुख तत्व

विशेष विवरण	विवरण
श्रम की असीमित आपूर्ति	• कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, आमतौर पर कृषि क्षेत्र में श्रम की बहुतायत होती है. • कम कृषि उत्पादकता के कारण इस श्रम शक्ति को अल्प-रोजगार या अधिशेष माना जाता है.
औद्योगीकरण की ओर बढ़ें	• जैसे ही औद्योगीकरण शुरू होता है, कृषि से अधिशेष श्रम औद्योगिक क्षेत्रा में चला जाता है जिससे उत्पादन और औद्योगिक विकास में वृद्धि होती है. • श्रम और पूँजी संचय का यह हस्तांतरण आर्थिक विकास को चलाने में मदद करता है.
वेतन दर गतिशीलता	• प्रारम्भ में, अधिशेष श्रम बल के कारण औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी कम रह सकती है.हालाँकि, जैसे-जैसे यह श्रम अवशोषित होता है, मजदूरी बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ती है.
अर्थव्यवस्था का परिवर्तन	• समय के साथ, जैसे-जैसे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है और श्रमिक कृषि से दूर जाते हैं, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान से अधिक औद्योगिक और आधुनिक में बदल जाती है.

STUDYPDF WALLAH

औद्योगीकरण हुआ, गरीबी में कमी आई और अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया.

भारत और लुईस मॉडल

- भारत के कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का है. 1993-94 और 2011-12 के बीच कृषि में लगे कार्यबल का प्रतिशत 64·6% से गिरकर 48·9% हो गया, उसी अवधि के दौरान रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी केवल मामूली रूप से बढ़ी, 10·4% से 12·6% हो गई तथा 2022-23 में घटकर 11·4% हो गई. अपेक्षाओं के विपरीत, इस बदलाव से मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, जिसने रोजगार के हिस्से में केवल मामूली वृद्धि का अनुभव किया है.
- विनिर्माण रोजगार में कमी मुख्य रूप से सेवाओं और निर्माण में श्रम के बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो अर्थशास्त्री लुईस द्वारा उल्लिखित अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन के विपरीत है.

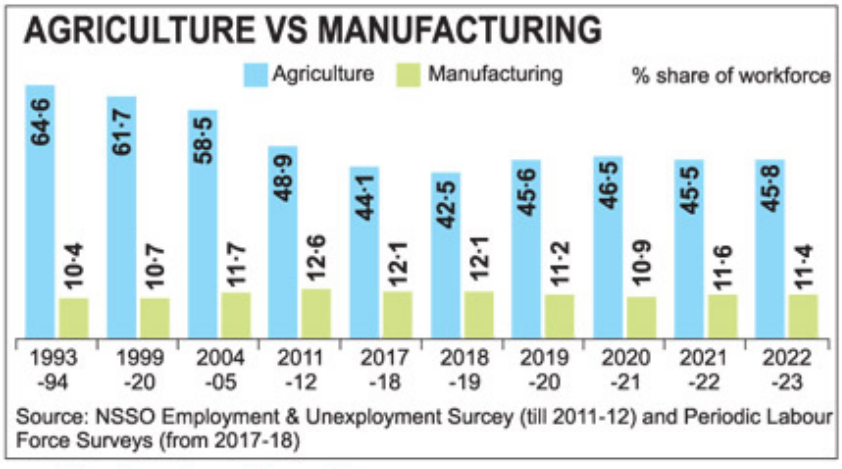

Source: NSSO Employment & Unexployment Surcey (till 2011-12) and Periodic Labour Force Surveys (from 2017-18)

भारत में लुईस मॉडल के कार्यान्वयन में विरोधाभास

- भारत में कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है, जिसके कारण अतिरिक्त श्रमिक उन गतिविधियों में संलग्न है, जो उत्पादकता अथवा आय में वृद्धि में योगदान नहीं देती. अतिरिक्त श्रम की इस स्थिति के कारण श्रमिकों का अन्य उद्योगों में स्थानांतरण जटिल हो जाता है.
- विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वेतन, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तथा शहरी जीवन की उच्च लागत को देखते हुए, ग्रामीण कृषि मजदूरों को स्थानांतरित करने के लिए लुभाने में विफल रही है तथा इसने लुईस मॉडल के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है.
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाजार की माँगों के अनुरूप श्रमिकों को प्रशिक्षित नहीं कर पा रही है, जिसके परिणामस्वरूप कौशल में अन्तर की स्थिति उत्पन्न होती है, जो उद्योगों में श्रमिकों के नियोजन में बाधा डालता है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डीप फेक टेक्नोलॉजी (Deep Fake Technology)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में डीपफेक तकनीक का उपयोग से एक भारतीय अभिनेत्री की अश्लील वीडियो के वायरल होने से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुरुपयोग को लेकर चिंता का माहौल बन गया है.

प्रमुख तथ्य

- 'डीपफेक', कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर मनोरंजन/मीडिया का वह अवास्तविक रूप है, जिसका उपयोग ऑडियो और विजुअल सामग्री के द्वारा लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जा सकता है.
- डीपफेक शब्द का उद्भव वर्ष 2017 में हुआ था, जब एक अनाम Reddit उपयोगकर्ता ने खुद को 'डीप फेक' कहा था. इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन-सोर्स, डीप-लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया.
- शाब्दिक रूप से डीप फेक, 'डीप लर्निंग' और 'फेक' का सम्मिश्रण है. इसके अन्तर्गत पॉवरफुल ग्राफिक्स वाले कम्प्यूटरों की सहायता से उपलब्ध डाटा का सम्मिश्रण करके फेक वीडियो, फोटो अथवा ऑडियो तैयार किए जाते हैं.
- इस तकनीक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एल्गोरिदम का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर इस सहजता के साथ स्थानांतरित किया जाता है कि यह पता करना कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत फोटो/वीडियो असली है या डीपफेक.
- डीपफेक बनाने में लोगों की मदद करने के लिए अब बहुत सारे टूल उपलब्ध हैं, तथा कई कम्पनियां इसे एक सेवा के रूप में पेश करती हैं.

डीपफेक के अनुप्रयोग

- सभी डीपफेक दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि कुछ मनोरंजक और जीवन को सुगम बनाने में सहायक भी होते हैं.
- डीपफेक के प्रयोग से वीडियो गैलरी और संग्रहालयों को सजीव किया जा सकता है.
- वर्तमान में मनोरंजन उद्योग के लिए, विदेशी भाषा की फिल्मों पर डबिंग को बेहतर बनाने के लिए डीपफेक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है.
- यदि किसी व्यक्ति की किसी गम्भीर बीमारी या अन्य किसी कारण से आवाज चली जाती है, तो डीपफेक के प्रयोग द्वारा उसे दोबारा तैयार किया जा सकता है.

डीपफेक के दुष्प्रभाव

- डीपफेक के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय और यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कई प्रकार से क्षति पहुँचाई जा सकती है.
- अति-यथार्थवादी डिजिटल मिथ्याकरण होने के कारण, डीपफेक को प्रामाणिक मीडिया से अलग करना बहुत कठिन हो जाता है.
- डीपफेक के माध्यम से मीडिया फाइल में व्यापक हस्तक्षेप (जैसे–चेहरे बदलना, लिप सिंकिंग या अन्य शारीरिक गतिविधि) किया जा सकता है और इससे जुड़े अधिकांश मामलों में लोगों की पूर्व अनुमति नहीं ली जाती, जो मनोवैज्ञानिक, सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और व्यावसायिक व्यवधान का खतरा उत्पन्न करता है.
- डीपफेक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पोर्नोग्राफी के मामलों में देखा गया है, जो भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के साथ कुछ मामलों में व्यक्तिगत हिंसा को भी बढ़ावा देता है.
- डीपफेक जैसी तकनीकों के दुरुपयोग से राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है.

STUDYPDF WALLAH

भारत में डीपफेक के विरुद्ध कानूनी प्रावधान

- *हालाँकि भारत में डीपफेक तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानूनी नियम नहीं हैं. इस तकनीक के दुरुपयोग के सम्बन्ध में विशिष्ट कानूनों की माँग की जा सकती है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और साइबर अपराध आदि शामिल हों.*
- *देश में साइबर अपराधों के मामलों में वर्ष 2000 में पारित 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000' तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.*
- *साइबर अपराधों से निपटने के लिए वर्ष 2018 केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत् 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र' (Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C) की स्थापना की गई.*
- *साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Ministry of Electronics and Information Technology-MEITy) के तहत् 'साइबर स्वच्छता केन्द्र' भी स्थापित किया गया है.*
- *नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2019 में **'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019'** (Personal Data Protection Bill–2019) लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है.*

- आतंकवादी या चरमपंथी समूहों द्वारा डीपफेक का प्रयोग राष्ट्र-विरोधी भावना फैलाने के लिए किया जा सकता है.
- डीपफेक लोकतांत्रिक संवाद को बदलने और महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रति लोगों में अविश्वास फैलाने के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है.
- डीपफेक का प्रयोग चुनावों में जातिगत द्वेष, चुनाव परिणामों की अस्वीकार्यता या अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं के लिए किया जा सकता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.
- डीपफेक तथ्यात्मक सापेक्षवाद (Factual Relativism) को बढ़ावा देता है तथा यह किसी अधिनायकवादी शासक को सत्ता में बने रहने, लोगों के दमन को सही ठहराने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने में सहायक हो सकता है.

समाधान

- उपभोक्ताओं के लिए मीडिया साक्षरता दुष्प्रचार और गहरी जालसाजी से निपटने का सबसे प्रभावी उपकरण है. प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग के बारे में जितनी अधिक सार्वजनिक जागरूकता होगी, उतना ही अधिक वे अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले मीडिया के बारे में गम्भीरता से सोचने में सक्षम होंगे और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सावधानी बरतेंगे.
- डीपफेक मीडिया सामग्री के निर्माण और इसके वितरण की चुनौती से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कम्पनियों, नागरिक समाज, नीति निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों को चर्चा के माध्यम से इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की विनियमन नीति की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए.
- डीपफेक मीडिया सामग्री की पहचान करने, इसे प्रमाणित करने और इसके आधिकारिक स्रोतों तक पहुँच को सुलभ बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध तथा उपयोग किए जा सकने वाले तकनीकी आधारित समाधान के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
- एक ब्लॉकचेन खाता प्रणाली का प्रयोग करके वीडियो, चित्रों और ऑडियो से सम्बन्धित छेड़छाड़ का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, इसके माध्यम से उसकी उत्पत्ति और किसी भी हेरफेर को जाँचा जा सकता है.
- घटनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने में मदद करने के लिए प्रामाणिक और आधिकारिक स्रोतों को और अधिक दृश्यमान बनाया जाना चाहिए, इससे डीपफेक के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी. ●●●

शेष पृष्ठ 67 का

उन उपायों (मौद्रिक और राजकोषीय दोनों) को संदर्भित करती हैं, जो तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधि पर लगाम लगाकर और मंदी के दौरान इसे मजबूत करके व्यापार चक्र को स्थिर करती हैं. एक संयम के अलावा असुरक्षित ऋणों की कुल वृद्धि में, उपायों का प्रभाव बैंकों और एनबीएफसी द्वारा असुरक्षित ऋणों पर ली जाने वाली दरों में भौतिक वृद्धि और बड़े और छोटे एनबीएफसी (फिनटेक सहित) के लिए प्रबंधन के तहत् उनकी परिसंपत्तियों में असुरक्षित खुदरा ऋण उधार लेने की उच्च लागत के रूप में दिखाई देगा.

इससे अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनबीएफसी द्वारा असुरक्षित ऋण देने के लिए अधिक पूँजी जुटानी होगी. उपभोक्ता ऋण बाजार से बैंकों और एनबीएफसी द्वारा स्वयं को सीमित कर लेने से इस क्षेत्र में जोखिम बढ़ सकता है.

इस प्रकार, घटनाओं के घटित होने के बाद चूक (यदि कोई हो) को प्रबंधित करने के बजाय सक्रिय रूप से इसे प्रबंधित करना सबसे अच्छा नीति विकल्प लगता है. ये उपाय विनियमित संस्थाओं के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) संचालित तनाव पहचान प्रणाली की ओर झुकाव और ऊपरी परत एनबीएफसी को अधिक नियामक जाँच के अधीन करने के आरबीआई के हालिया कदम की निरन्तरता में हैं. ●●●

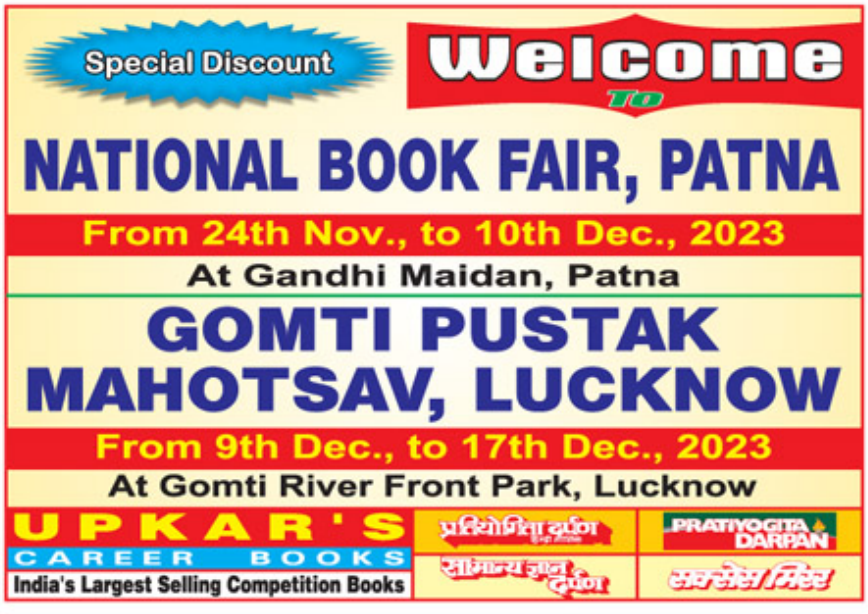

STUDYPDF WALLAH

बुनियादी बचत बैंक खाता (Basic Saving Bank Account)

वर्तमान समय में भारत सरकार के वित्तीय समावेशन अभियान के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उन लोगों के लिए बुनियादी बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है, जो बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं. इस खाते को 'No Frills Saving Account' के नाम से भी पुकारा जाता है अर्थात् इस खाते को संचालित करने हेतु न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं है. शून्य शेष के साथ संचालित किए जाने वाले नो फ्रिल्स बचत खातों का धारक सभी प्रकार की सामान्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकता है. इस खाते से ली जाने वाली सेवाएं निःशुल्क होती हैं.

न्यूनतम औपचारिक दस्तावेजों की सहायता से खोले जाने वाले नो फ्रिल्स बचत खातों में प्रतिदिन ₹ 5 हजार तक जमा या आहरण किया जा सकता है, किन्तु एक माह में चार आहरण ही निःशुल्क हैं. एटीएम की सुविधा देने वाले इस खाते के पुनः संचालन पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, किन्तु गौरतलब तथ्य यह भी है कि बुनियादी बचत बैंक खाते का धारक उसी बैंक में दूसरा बचत खाता नहीं खोल सकता. प्रन्यास, सोसाइटी तथा अनिवासी भारतीय के अलावा कोई भी भारतीय नागरिक इस खाते का संचालन कर सकता है. चैक बुक की सुविधा देने वाले इस खाते में सरकारी योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि पर संग्रहण शुल्क भी वसूल नहीं किया जाता है.

सीमान्त निक्षेप सुविधा दर (Standing Deposit Facility Rate—SDFR)

वर्ष 2022-23 से आरबीआई द्वारा प्रारम्भ की गई एसडीएफआर का मूल उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में विद्यमान अतिरेक तरलता को अव-शोषित करना है. बैंकों की ओर से आरबीआई के पास अपने अतिरिक्त कोषों को जमा कराने की इस नवीन योजनान्तर्गत रिवर्स रेपो रेट की भाँति ही आधिक्य तरलता को अन्तरित किया जाता है, किन्तु इस योजना के तहत् आरबीआई बैंकों के पास गिरवी के रूप में सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-sec.) रखने के लिए बाध्य नहीं है. जबकि रिवर्स रेपो रेट के तहत् आरबीआई द्वारा बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी के रूप में रखी जाती है.

प्रायः एसडीएफआर रेपो दर से 0·25 प्रतिशत नीचे ही रहती है. **अक्टूबर 2023** में आरबीआई द्वारा घोषित नीतिगत दरों में एसडीएफआर 6·25 प्रतिशत थी, जबकि रेपो रेट 6·50 प्रतिशत थी.

भारतीय डिजिटल मुद्रा (Indian Digital Currency)

डिजिटल भुगतान प्रणाली को व्यापक व सुगम बनाने के उद्देश्य से 1 नवम्बर, 2022 से 'भारतीय डिजिटल मुद्रा' अर्थात् ई-रुपया (e-Rupee) का संचालन किया गया है, जिसे **'केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा'** (Central Bank Digital Currency – CBDC) के नाम से भी पुकारा जाता है. प्रारम्भ में होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 9 बैंकों को चिह्नित किया गया है. कागजी मुद्रा की भाँति विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इस डिजिटल मुद्रा को भी 'लीगल टेण्डर' का दर्जा प्राप्त है. सम्पर्क रहित व्यवहारों को अंजाम देने वाली यह डिजिटल मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है.

आज वैश्विक स्तर पर करीब 110 देशों द्वारा सीबीडीसी जारी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसे क्रिप्टो करेंसी का सुरक्षित विकल्प मानते हुए विनिमय माध्यम के बतौर प्रयुक्त करने की तैयारी की जा रही है. यद्यपि सीबीडीसी 'ब्याज सहित' अथवा 'ब्याज रहित' दोनों स्वरूपों में जारी की जा सकती है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'ब्याज रहित' भारतीय डिजिटल मुद्रा को प्राथमिकता दी गई है. विषय विशेषज्ञों की मान्यता है कि 'ब्याज सहित' डिजिटल मुद्रा को जनसाधारण द्वारा जमाओं का आकर्षक विकल्प माना जा सकता है, फलस्वरूप न केवल बैंकों में ऋण सृजन का कार्य कठिन हो सकता है, बल्कि देश की सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

उल्लेखनीय है कि उपयोग की दृष्टि से सीबीडीसी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

- **CBDC – Retail**—इसका उपयोग कम्पनियों, निगमों, निकायों के साथ-साथ जन-साधारण लोगों द्वारा भी किया जा सकता है. (e ₹ R पाइलट 1 दिसम्बर, 2022 को लॉन्च)
- **CBDC – Wholesale**—इसका उपयोग कुछ चयनित बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा ही किया जा सकता है. (e ₹ W पाइलट 1 नवम्बर, 2022 को लॉन्च)

आशा है भारतीय डिजिटल परिवेश को सुरक्षा व सुदृढ़ता प्रदान करने वाली यह भारतीय डिजिटल मुद्रा (e-rupee) देश में सस्ती मुद्रा प्रबन्धन व्यवस्था को आधार उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न किए जाने वाले वित्तीय लेन-देनों को भी सुगम व सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगी.

इन्फ्रा बॉण्ड (Infra Bond)

सरकार और निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले 'अवसंरचना बॉण्ड' (Infrastructure Bond) से आशय उस बॉण्ड से है, जो किसी विशिष्ट परियोजना के लिए धन संग्रहण हेतु निर्गमित किए जाते हैं. बैंकों में की जाने वाली सावधि जमा (FD) की भाँति सुरक्षित तथा दीर्घकालीन समझे जाने वाले इन्फ्रा बॉण्ड का निवेश एक उत्तम विकल्प सिद्ध हो रहा है. प्रायः 10 से 15 वर्ष की अवधि वाले इन्फ्रा बॉण्ड्स उन निवेशकों के लिए उचित माना जाता है, जो आय के विश्वसनीय स्रोत की खोज में संलग्न रहते हैं. लगभग 10·50 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने वाले इन्फ्रा बॉण्ड्स को Credit Rating Agencies द्वारा रेटिंग भी दी जाती है. उल्लेखनीय है कि 'AAA' रेटिंग वाले इन्फ्रा बॉण्ड्स को सदैव श्रेष्ठ माना जाता है. वैसे निजी बॉण्ड्स की तुलना में सरकारी बॉण्ड्स को उत्तम व सुरक्षित माना जाता है.

प्रमुख उदाहरण :

- 5·75% National Highways Authority of India
- 12% Munjal Hospitility Private Ltd.
- 6·83% Power Finance Corporation Ltd.
- 8·18% NABARD
- 14% Aftaab Solar Pvt. Ltd.
- 8·90% Power Grid Corporation of India Ltd. आदि.

सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में अन्तर

आधार	सीबीडीसी (ई-रुपया)	क्रिप्टो करेंसी
वैधता	यह एक प्रकार की वैध मुद्रा (Legal Tender) है.	इसे लीगल टेण्डर अर्थात् वैध मुद्रा नहीं कहा जा सकता.
प्रबन्धन	इसका प्रबन्धन सम्बन्धित राष्ट्र की सरकार द्वारा किया जाता है.	इसका प्रबन्धन पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है.
नियंत्रण	इस पर आरबीआई जैसे केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण रहता है.	इस पर किसी भी केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है.
उच्चावचन	इसकी मूल्य दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता है.	इसकी मूल्य दर कम या ज्यादा होती रहती है.

STUDYPDF WALLAH

वित्तीय बाजार में प्रयुक्त अद्यतन शब्दावली

✍ डॉ. ओ. पी. शर्मा

उपभोग-निधि (Consumption Fund)

'साझा कोष उद्योग' में निरन्तर लोकप्रिय बनती जा रही 'विषयगत निवेश रणनीति' (Thematic Investing Strategy) का एक अभिन्न अंग है 'उपभोग-निधि'. वस्तुतः उपभोग-निधि एक प्रकार से ऐसी म्यूचुअल फण्ड स्कीम है जिसमें एकत्रित धनराशि को उपभोक्ता-उन्मुखी (Consumer Oriented) कम्पनियों में ही निवेशित किया जाता है. इन कम्पनियों में मुख्य रूप से फार्मा, फूड, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, सेवा प्रदाता, विनिर्माण, मोबाइल सेवा आपूर्ति, एफ एमसीजी (Fast Moveable Consumer Goods-FMCG) आदि को सम्मिलित किया जाता है. 'उपभोग-निधि' में संग्रहित पूरा धन इन कम्पनियों की समता अंश पूँजी में निवेश किया जाता है.

प्रमुख उपभोक्ता-उन्मुखी कम्पनियों के उदाहरण—मारूति सुजुकी, नेस्ले, आईटीसी, हिन्दुस्तान युनिलीवर, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, वर्लपुल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक आदि. लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई ऐसी कम्पनियों में जहाँ एक ओर विकास सम्भावनाएं भरपूर होती हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी गतिविधियों पर वैश्विक परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है. सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाली इन कम्पनियों के द्वारा प्रायः उच्च दर से प्रतिफल दिया जाता है.

प्रमुख उदाहरण :

- Tata India Consumer Fund
- Nippon India Consumption Fund
- SBI Consumption Opportunities Fund
- Aditya Birla Sun Life India Gen Next Fund
- Sundram Consumption Fund
- Baroda BNP Paribas India Consumption Fund
- Canara Robeco Consumer Trends Funds
- Mirae Asset Great Consumer Fund
- UTI India Consumer Fund
- HDFC Non-Cyclical Consumer Fund
- ICICI Prudential Bharat Consumption Fund आदि

क्राउड फण्डिंग (Crowd Funding)

इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन धन-संग्रहण की प्रक्रिया को 'क्राउड फण्डिंग' कहा जाता है. वस्तुतः इस निवेश योजनान्तर्गत अनेक निवेशकों को सामूहिक रूप से निवेश करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है. यह निवेश दान आधारित, इक्विटी आधारित, ऋण आधारित, इनाम आधारित, वाद आधारित या मुकदमेबाजी आधारित हो सकता है.

वर्तमान समय में नवाचार आधारित स्टार्टअप कम्पनियों के स्वामियों द्वारा भी क्राउड फण्डिंग के माध्यम से धनराशि एकत्रित की जाती है. इन कम्पनियों के द्वारा भावी निवेशकों के समक्ष अपने उत्पाद, व्यवसाय तथा भावी विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से विचार रखे जाते हैं, फलस्वरूप निवेशक उनके विचारों से प्रभावित होकर निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं. गैर-सरकारी संगठनों (Non-Govt. Organisations – NGO's), सामाजिक कार्य-कर्ताओं, धर्मार्थ संस्थानों आदि के द्वारा भी धन संग्रहण हेतु क्राउड फण्डिंग का सहारा लिया जाता है. वैश्विक महामारी **'कोविड-19'** से उत्पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ क्राउड फण्डिंग काफी चर्चा में रही थी. इस महामारी के रोगियों के उपचार हेतु बेंगलुरू की एक 10 वर्षीय लड़की द्वारा क्राउड फण्डिंग की सहायता से करीब ₹ 20 लाख एकत्रित किए गए थे.

हमारे देश में क्राउड फण्डिंग पूर्णतः 'प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा शासित और विनियमित होता है. सेबी द्वारा 'इक्विटी आधारित क्राउड फण्डिंग' को गैर-कानूनी घोषित किया हुआ है. भारत में **'केटो, ओ आर जी', 'मिलाप ओ आर जी', 'रंग दे आर्ग'** आदि प्रमुख क्राउड फण्डिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं.

नोस्टरो खाता (NOSTRO Account)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में प्रयुक्त किए जाने वाले लेटिन शब्द 'NOSTRO' का शाब्दिक अभिप्राय 'OURS' होता है. जब कोई भारतीय बैंक अन्य देश में वहाँ की प्रचलित मुद्रा में कोई खाता संचालित करता है, तो उसे 'नोस्टरो खाता' कहा जाता है. इसके विपरीत किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में यदि कोई खाता स्थानीय प्रचलित मुद्रा (रुपए) में संचालित किया जाता है, तो उसे 'VOSTRO Account' कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अभिप्राय 'YOURS' होता है.

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दोनों प्रकार के खाते जहाँ एक ओर खातों में विद्यमान शेष की नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये विनिमय दरों में व्याप्त जोखिमों की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं.

कासा खाता (CASA Account)

वह खाता, जो बैंकों में संचालित किए जाने वाले **चालू खाते (Current Account)** और **बचत खाते (Saving Account)** दोनों के संयुक्त लक्ष्यों, लाभों व परिणामों को प्रदर्शित करता है, 'कासा खाता' कहलाता है. बैंकों द्वारा इस खाते पर नाममात्र का ब्याज दिया जाता है, फलस्वरूप यह खाता बैंकों की लाभदायकता बढ़ाने में मदद करता है.

वर्तमान समय में बैंकों द्वारा कासा अनुपात की गणना निम्नांकित सूत्र की सहायता से की जाती है–

कासा अनुपात

$$= \frac{\text{कासा खाते में जमा धनराशि}}{\text{कुल जमा धनराशि}}$$

टिप्पणी–निम्न कासा अनुपात बैंक की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है, जबकि उच्च कासा अनुपात बैंक की श्रेष्ठ निष्पादन क्षमता और प्रभावी लाभदायकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है. आजकल बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को CASA खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाता है और यह खाता बैंकों के लिए वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है.

राफा खाता (RAFA Account)

वह खाता, जो बैंकों के **आवर्ति जमा खातों (Recurring Deposit Accounts)** और **सावधि जमा खातों (Fixed Deposit Accounts)** दोनों का संयुक्त प्रतिनिधित्व करता है 'राफा खाता' कहलाता है 'कासा खाते' की तुलना में 'राफा खाते' पर ब्याज की दर अधिक होती है.

राफा अनुपात की गणना हेतु बैंकों द्वारा निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है–

राफा अनुपात

$$= \frac{\text{आवर्ति जमा व सावधि जमा धनराशि}}{\text{कुल जमाराशि}}$$

टिप्पणी–निम्न राफा अनुपात बैंक की उत्तम लाभदायकता की ओर संकेत करता है, जबकि उच्च राफा अनुपात बैंक की न्यून लाभदायकता को प्रदर्शित करता है.

STUDYPDF WALLAH

फ्रेक्शनल शेयर्स (Fractional Shares)

वह प्रक्रिया जिसमें एक निवेशक द्वारा किसी उच्च बाजार मूल्य वाले शेयर का एक हिस्सा खरीदा जाता है, **'भिन्नात्मक अंश प्रक्रिया'** कहलाती है और उसके अंशों को भिन्नात्मक अंश कहा जाता है. इस प्रक्रिया में अंशों का क्रय किराना सामग्री की भाँति किया जा सकता है.

किन्तु भारत में भिन्नात्मक अंशों को खरीदने व बेचने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, क्योंकि भारतीय कम्पनी अधिनियम में आंशिक शेयर्स की खरीद और बिक्री से सम्बन्धित कोई प्रावधान व नियम नहीं है. अमरीका में महँगे अंशों को खरीदकर आंशिक या भिन्नात्मक स्वामित्व प्राप्त करने की परम्परा बनी हुई है. अनेक खुदरा भारतीय निवेशकों द्वारा अल्फाबेट, एप्पल, मेटा आदि ख्याति प्राप्त कम्पनियों के आंशिक अंश क्रय किए जाते रहे हैं.

सेबी की चेयरपर्सन श्रीमती माधवी पुरी बुच द्वारा अक्टूबर 2023 में एक वक्तव्य में स्पष्टतः कहा गया है कि भारत में भी फ्रेक्शनल शेयर्स के क्रय-विक्रय की अनुमति देना समय की माँग बन चुकी है, किन्तु इसके भारतीय कम्पनी अधिनियम और सेबी अधिनियम दोनों में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत है.

आशा है शीघ्र ही हमारे देश में भिन्नात्मक अंशों की क्रय-विक्रय प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी और खुदरा निवेशक भी अधिक कीमत वाले अंशों का एक हिस्सा खरीदकर भिन्नात्मक स्वामित्व (Fractional Ownership) प्राप्त कर सकेंगे. इस संदर्भ में विधि सम्मत अनुमति प्राप्त होने के बाद रिटेल निवेशक भी एमआरएफ, श्री सीमेंट, एबॉट इण्डिया, नेस्ले इण्डिया, पेज इण्डस्ट्रीज, हनीवेल ऑटोमेशन आदि महँगे अंशों का आंशिक स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे.

उल्लेखनीय है कि यदि भारत में फ्रेक्शनल शेयर्स के क्रय-विक्रय की वैधानिक अनुमति मिल जाती है, तो भारतीय कम्पनियों को 'स्टॉक स्पिलट' करने की जरूरत नहीं होगी.

स्टॉक स्प्लिट (Stock Split)

महँगे अंशों की विभाजन प्रक्रिया को स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है वस्तुतः जब किसी कम्पनी के अंशों की बाजार कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस कम्पनी के अंशों को छोटे या खुदरा निवेशक खरीदने में असमर्थ रहते हैं, ऐसी स्थिति में कम्पनी द्वारा छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने शेयर को विभाजित करने हेतु स्टॉक स्प्लिट प्रक्रिया की सहायता ली जाती है. ऐसा करने से वर्तमान निवेशक का कुल निवेश मूल्य तो यथावत् बना रहता है, किन्तु उसके अधीन अंशों की संख्या बढ़ जाती है. दूसरी ओर कम्पनी का बाजार पूँजीकरण (M-cap) तो यथावत् बना रहता है, किन्तु उसके अंशों को तरलता उपलब्ध हो जाती है. स्टॉक स्प्लिट के कारण प्रति अंश मूल्य कम हो जाता है और छोटे निवेशक अंशों को खरीदने हेतु तत्पर हो जाते हैं. ऐसे अंशों की अचानक माँग बढ़ने के कारण अंशों की कीमत भी बढ़ने लग जाती है.

उदाहरणार्थ–श्री अमृतनाथ लि. कम्पनी द्वारा 1 : 5 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया, तो इसका अभिप्राय हुआ कि वर्तमान अंशधारी को प्रत्येक 1 अंश के बदले में 5 अंश प्राप्त होंगे. अंशधारी का कुल निवेशित मूल्य यथावत् बना रहेगा, किन्तु प्रति अंश बाजार मूल्य कम हो जाएगा.

उल्लेखनीय है कि स्टॉक स्प्लिट प्रक्रिया बोनस अंश आवंटन से पूर्णतः भिन्न प्रक्रिया है. इसी प्रकार जब हमारे देश में भिन्नात्मक स्वामित्व प्रक्रिया को शेयर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा, तो कम्पनियों को स्टॉक स्प्लिट की सहायता नहीं लेनी होगी, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से महँगी तथा जटिल होती है.

रीट्स और इनविट्स (REITs and INVITs)

'रीट्स' (Real Estate Investment Trusts – REITs) से अभिप्राय ऐसे विनियोग प्रन्यासों (Trusts) से है जो निवेशकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग गोदामों, कार्यालयों, मॉल्स आदि के निर्माण में किया जाता है. इनके द्वारा निवेशकों को लाभांश के बतौर नियमित आय के रूप में किराए का भुगतान किया जाता है अथवा अन्य पक्षकारों से भी निवेशकों को नियमित किराया मिल सकता है. साझा कोषों की तर्ज पर रीट्स भी फण्ड मैनेजर, ट्रस्ट, स्पोंसर आदि की सहायता से अपना कार्य निष्पादित करते हैं.

उल्लेखनीय है कि भारत में संचालित अधिकांश रीट्स के द्वारा अपना अधिकांश एकत्रित धन कार्यालय प्रोपर्टीज में निवेशित किया जाता है. हमारे देश में मुख्य रूप से समता रीट्स, निजी रीट्स, बन्धक रीट्स, हाइब्रिड रीट्स, आदि प्रकार के रीट्स का संचालन किया जाता है.

इनविट्स (Infrastructure Investment Trusts – INVITs) से आशय उन प्रन्यासों से है, जो निवेशकों से प्राप्त राशि का निवेश आकर्षक एवं लाभप्रद परियोजनाओं में किया जाता है. ये परियोजनाएं पॉवर प्लांट्स, वेयर हाउस, सड़कें, रेलवे लाइन्स, पाइपलाइन्स आदि से सम्बन्धित हो सकती हैं. दीर्घकालीन पूँजी संवर्द्धन को बढ़ावा देने वाले इनविट प्रबन्धकों द्वारा निवेशकों को नियमित आय के रूप में लाभांश दिया जाता है. हमारे देश में सर्वप्रथम 2017 में पहले इनविट का पंजीयन हुआ था और आज हमारे देश में कुल 19 इनविट्स पंजीकृत हैं. स्कन्ध विनिमय केन्द्र में पंजीकृत या सूचीबद्ध इनविट्स में कोई भी निवेशक 'INVIT UNITS' का स्वतंत्रतापूर्वक क्रय-विक्रय कर सकता है, वहीं दूसरी ओर असूचीबद्ध इनविट्स में प्रायः बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा ही लेन-देन किया जाता है.

सेबी द्वारा जारी नवीनतम प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध इनविट्स को प्रतिवर्ष अर्जित आय का कम-से-कम 90 प्रतिशत भाग अपने यूनिटधारकों को अनिवार्य रूप से वितरित करना होगा. इसी प्रकार कुल संग्रहित धन का कम-से-कम 80 प्रतिशत भाग नियमित आय सृजित करने वाली परियोजनाओं अथवा आधारिक संरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं में निवेशित करना अनिवार्य है. इनविट्स द्वारा एकत्रित धनराशि का शेष 20 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों, प्रगतिशील परियोजनाओं, मुद्रा बाजार के उपकरणों, रोकड़ समान परिसम्पत्तियों आदि में निवेशित किया जा सकता है.

सेबी द्वारा प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार सूचीबद्ध रीट्स और इनविट्स के द्वारा संयुक्त रूप से अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 की अवधि में ₹ 18,658 करोड़ की राशि एकत्रित की गई है. यह तथ्य भारत में बुनियादी संरचना में निवेश की सुदृढ़ माँग को प्रदर्शित करता है.

मेमे स्टॉक(Meme Stock)

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 'चर्चा' से लोकप्रियता प्राप्त करने वाले मेमे स्टॉक या अंशों की कीमतें अचानक कम या ज्यादा हो

शेष पृष्ठ 98 पर

रीट्स और 'इनविट्स' के प्रमुख उदाहरण

रीट्स (REITs)	इनविट्स (INVITS)
● Bookfield India Real Estate Trust	● Power Grid INVIT
● Embassy Office Parks REIT	● India Grid Trust
● Mindspace Business Parks REIT	● National Highways Infra Trust
● Kotal International REIT FOF	● India Infrastructure Trust
● L&T Infrastructure Fund	● IRB Invit Fund
● SBI Infrastructure Fund	● Intelligent Supply Chain Infra Trust
● Tata Infrastructure Fund etc.	● Oriented Infra Trust etc.

STUDYPDF WALLAH

आर्थिक लेख

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अद्यतन प्रवृत्तियाँ

'भारतीय बैंकिंग प्रणाली' की निष्पादन क्षमता तथा प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए नियोजनकाल से ही अनवरत् प्रयास किए जाते रहे हैं, किन्तु कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात् देश में नवाचार आधारित बैंकिंग अवसंरचना का विकासमान परिदृश्य किसी से छुपा हुआ नहीं है. स्टार्टअप पारितंत्र तथा डिजिटल क्रान्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हरित बैंकिंग और विशाल फिनटेक समर्थित परिवेश के दम पर आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार निरन्तर प्रगति पथ की ओर अग्रसर हो रही है. महामारी उपरान्त पुनः परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर अमरीका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के पतन का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ. सुदृढ़ व आकर्षक परिदृश्य के साथ आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली निरन्तर सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है. **निरन्तर प्रगति के लिए प्रतिबद्ध वर्तमान भारतीय बैंकिंग प्रणाली की दशा और दिशा को अभिव्यक्त करने वाली कुछ अद्यतन प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार हैं–**

- **क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में निरन्तर अभिवृद्धि**–डिजिटल क्रान्ति के संघटक के रूप में देश में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय निरन्तर बढ़ता जा रहा है. आरबीआई द्वारा जारी अद्यतन आँकड़ों के अनुसार 2018-19 में केवल 4·7 करोड़ क्रेडिट कार्ड निर्गमित किए गए थे, जबकि 2022-23 में 8·5 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं. 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 10·4 करोड़ और 12·7 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी करने का अनुमान लगाया गया है. 2021-22 की तुलना में 2022-23 में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय से बैंकों और कम्पनियों की आय में करीब 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में होने वाली निरन्तर अभिवृद्धि को दी गई तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है.

वर्ष	क्रेडिट कार्डस की संख्या	क्रेडिट कार्डस से लेन-देन
2018-19	4·7 करोड़	₹ 6·03 लाख करोड़
2019-20	5·8 करोड़	₹ 7·00 लाख करोड़
2020-21	6·2 करोड़	₹ 6·00 लाख करोड़
2021-22	7·4 करोड़	₹ 9·70 लाख करोड़
2022-23	8·5 करोड़	₹ 14·30 लाख करोड़
2023-24 (अनुमानित)	10·4 करोड़	₹ 19·70 लाख करोड़
2024-25 (अनुमानित)	12·7 करोड़	₹ 27·20 लाख करोड़

- **कैशलैश इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम**–रोकड़ लेन-देनों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को न्यून करने के उद्देश्य से भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था अर्थात् कैशलैश इकोनॉमी बनाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए जा रहे हैं. इन प्रयासों के फलस्वरूप आज भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है. अद्यतन सरकारी आँकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में देश में ₹ 2086 लाख करोड़ के 8·95 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुए, जबकि 2021-22 में यह राशि मात्र ₹ 1,744 लाख करोड़ ही थी. 2022-23 में वैश्विक स्तर पर रीयल-टाइम भुगतानों में भारत का 46 प्रतिशत हिस्सा रहा. भारत के बाद ब्राजील, चीन और दक्षिण कोरिया में सर्वाधिक डिजिटल लेन-देन सम्पन्न हुए.

आज डिजिटल भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत अनेक प्रकार के उपकरण और तकनीक यथा–इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग कार्डस, पीओएस, आईपीएस, माइक्रो एटीएम, भीम एप, यूएसएसडी, यूपीआई आदि उपलब्ध हैं. इन सभी तकनीकों में यूपीआई अर्थात् **'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम'** सर्वाधिक लोकप्रिय तकनीक है. इस तकनीक का उपयोगकर्ता बिना बैंक विवरण के भी यूपीआई एप की सहायता से किसी भी समय पर भुगतानों का लेन-देन कर सकता है. वर्तमान में सेवा योग्य यूपीआई एप्पस के प्रमुख उदाहरण हैं–फोनपे, पेटीएम, गूगलपे, मोबीक्विक, भीम आदि. जुलाई 2020 में देश में यूपीआई भुगतान ₹ 149·73 लाख करोड़ था, जो बढ़कर जुलाई 2022 में ₹ 628·93 लाख करोड़ तथा जुलाई 2023 में ₹ 99 लाख करोड़ तक पहुँच गया. उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि आज भारत में सम्पन्न होने वाले कुल डिजिटल भुगतानों में से 85 प्रतिशत भुगतान यूपीआई एप्पस के माध्यम से हो रहे हैं. डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक **पीओएस अर्थात् 'पॉइन्ट ऑफ सेल'** भी प्रतिदिन लोकप्रिय बनती जा रही है. इस 'विक्रय बिन्दु तकनीक' में निजी, सरकारी व अन्य बैंकों की सहायता से मशीनों के माध्यम से भुगतानों का लेन-देन होता है.

- **खुदरा ऋण में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति**–हाल ही में 6 अक्टूबर, 2023 को सम्पन्न मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में उजागर हुआ कि देश में कोविड महामारी के बाद अगस्त 2023 तक खुदरा ऋण करीब 1·75 गुना बढ़ चुका है. साथ ही बैंकों के कुल पोर्टफोलियो में एक-तिहाई हिस्सा खुदरा ऋण का ही है जिसका एक बड़ा भाग असुरक्षित ऋण का है. आरबीआई के आँकड़ों के अनुसार 2013 से 2023 (10 वर्ष) की अवधि में खुदरा ऋण में 425 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि औद्योगिक ऋण में केवल 49·5 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई है. सारांशतः यह कहा जा सकता है कि 2019 से 2023 तक की 4 वर्ष की अवधि में भारतीय बैंकों का खुदरा ऋण लगभग दोगुना हो गया है. मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में खुदरा ऋण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने पर बल दिया गया है. तथ्यों के अनुसार मार्च 2022 से अगस्त 2023 के मध्य खुदरा ऋण में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि में खुदरा ऋण में हुई वृद्धि को अंग्राकित तालिका में स्पष्ट किया गया है–

उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ते हुए खुदरा ऋण वितरण में निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों की अहम् भूमिका बनी हुई है. मार्च 2022 से अगस्त 2023 के दौरान एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के खुदरा ऋण वितरण में क्रमशः 11·6 प्रतिशत और 14·4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, किन्तु पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रमशः 22·4 और 20·6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है.

STUDYPDF WALLAH

वर्ष	खुदरा ऋण का वितरण
2018	₹ 19·08 लाख करोड़
2019	₹ 22·20 लाख करोड़
2020	₹ 27·12 लाख करोड़
2021	₹ 30·01 लाख करोड़
2022	₹ 33·86 लाख करोड़
2023	₹ 47·70 लाख करोड़

- **असुरक्षित ऋणों में वृद्धि का रुझान–** साख नीति की समीक्षा बैठक से चौंकाने वाला तथ्य विदित हुआ है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में असुरक्षित ऋणों में होने वाली निरन्तर वृद्धि नकारात्मक संकेत प्रस्तुत कर रही है. 2020-21 से लेकर 2022-23 के मध्य असुरक्षित ऋण 22·9 प्रतिशत से बढ़कर 25·2 प्रतिशत हो गया है. दूसरी ओर सुरक्षित ऋण 77 प्रतिशत से घटकर 74·8 प्रतिशत ही रह गया है. असुरक्षित ऋणों में प्रति वर्ष लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जबकि अन्य साख वृद्धि 12 से 14 प्रतिशत की दर से ही दर्ज हो रही है. अगस्त 2023 तक देश में कुल ₹ 48 लाख करोड़ के असुरक्षित ऋण प्रदर्शित हो रहे थे. देश में असुरक्षित ऋणों में वृद्धि के रुझान को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकार के बैंकों तथा ऋण वितरकों को सतर्क रहने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. 23 जून, 2023 को खुदरा ऋणों का परिमाण ₹ 90 लाख करोड़ था, जिसमें से ₹ 22 लाख करोड़ के असुरक्षित खुदरा ऋण थे. क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो लि. (CIBIL) के अनुसार ₹ 50,000 से कम के खुदरा ऋण संवर्ग में गैर-निष्पादनीय आस्तियों का अनुपात 30 जून, 2022 के सापेक्ष 30 जून, 2023 को बढ़कर 5·4% हो गया.
- **सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंकों में रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी–** आरबीआई द्वारा जारी आँकड़े के अनुसार 2022-23 के दौरान निजी बैंकों में 98,518 रोजगार के अवसर सृजित हुए, जबकि देश के सरकारी बैंकों में 3,385 रोजगार के अवसर कम हुए हैं. उल्लेखनीय है कि विलय और अधिग्रहण नीति को अपनाने के कारण देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है. फलस्वरूप आज हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या केवल 12 ही रह गई है, जोकि विगत दशक में 27 हुआ करती थी. दूसरी ओर निजी क्षेत्र में 22 बैंक संचालित किए जा रहे हैं. मार्च 2023 में निजी बैंकों में 7,56,644 कर्मचारी कार्यरत् थे, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,45,612 कर्मचारी कार्यरत् थे, किन्तु गौरतलब तथ्य यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रति कार्मिक औसत व्यवसाय ₹ 23·80 करोड़ है, जबकि निजी बैंकों में यह आँकड़ा ₹ 15·02 करोड़ ही बना हुआ है.
- **फिनटेक क्रान्ति की ओर बढ़ते कदम–** प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाले भारतीय फिनटेक बाजार का आकार 2022 में ₹ 48·64 लाख करोड़ था जिसके 2030 तक ₹ 174·88 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है. वस्तुतः फिनटेक कम्पनियों से अभिप्राय उन कम्पनियों से है, जो वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. वर्तमान में भारत में करीब 4200 फिनटेक स्टार्टअप कम्पनियाँ कार्य कर रही है, जिनमें 23 यूनिकॉर्न कम्पनियाँ भी सम्मिलित है, जबकि चीन में केवल 13 फिनटेक यूनिकॉर्न कम्पनियाँ ही हैं. उल्लेखनीय है कि 1 अरब यूएस डॉलर (करीब ₹ 8,328 करोड़) से ज्यादा बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैप) वाली स्टार्टअप कम्पनी को यूनिकॉर्न कम्पनी कहा जाता है. फिनटेक कम्पनियों के कार्यक्षेत्र में बीमा, निवेश, नियो बैंकिंग, पेमेन्ट्स, लेण्डिग्स आदि सेगमेंट्स को सम्मिलित किया जाता है.

भारतीय फिनटेक कम्पनियों की वर्तमान तथा भावी प्रगति को निम्नांकित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है–

सेक्टर	2022	2030	वार्षिक वृद्धि दर
लेण्डिग्स	₹ 22·49 लाख करोड़	₹ 108·26 लाख करोड	22 प्रतिशत
बीमा	₹ 7·25 लाख करोड़	₹ 25·57 लाख करोड़	17 प्रतिशत
पेमेंट्स	₹ 13·74 लाख करोड़	₹ 21·07 लाख करोड़	5 प्रतिशत
नियो बैंकिंग	₹ 4·00 लाख करोड़	₹ 24 लाख करोड़	18 प्रतिशत
निवेश	₹ 0·77 लाख करोड़	₹ 1·16 लाख करोड़	30 प्रतिशत

- **कुल बैंक ऋण में गृह ऋण तथा वैयक्तिक ऋण की ओर बढ़ता हुआ रुझान–** आरबीआई द्वारा जारी सेक्टरोल क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 में कुल बैंक ऋण में 19·7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है, जोकि जुलाई 2022 में 14·5 प्रतिशत थी, किन्तु इस समयावधि में कुल बैंक ऋण में वैयक्तिक ऋण में 31·7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जोकि जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के दौरान केवल 18·7 प्रतिशत की दर से ही बढ़ा था. इसी प्रकार जुलाई 2022 में गृह ऋण में केवल 16·1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, जो जुलाई 2023 में बढ़कर 37·4 प्रतिशत तक पहुँच गई. **जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई ऋण वृद्धि को निम्नांकित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है–**

सेक्टर	जुलाई 2022	जुलाई 2023
वैयक्तिक ऋण	18·7 प्रतिशत	31·7 प्रतिशत
सर्विसेज	16·7 प्रतिशत	23·1 प्रतिशत
गृह ऋण	16·1 प्रतिशत	37·4 प्रतिशत
कृषि ऋण	13·2 प्रतिशत	16·8 प्रतिशत
इण्डस्ट्री ऋण	10·5 प्रतिशत	5·8 प्रतिशत
ह्वीकल ऋण	19·2 प्रतिशत	21·2 प्रतिशत

- **अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए 'इंक्रीमेंटल सीआरआर' का प्रयोग–** भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश में ₹ 2000 का नोट चलन से बाहर होने के कारण जनता द्वारा बैंकों में ₹ 2000 के नोट बहुतायत में जमा कराए गए, परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2023 तक भारतीय बैंकों के पास ₹ 3·14 लाख करोड़ की अतिरिक्त धनराशि एकत्रित हो गई थी. ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा इस अतिरिक्त धनराशि के एक हिस्से को **इंक्रीमेंटल सीआरआर** (Incremental Cash Reserve Ratio or ICRR) के माध्यम से अपने पास मँगवाने का अस्थायी निर्देश जारी कर दिया गया, ताकि आवश्यकता से ज्यादा रोकड़ आपूर्ति के कारण देश में महँगाई नहीं बढ़ पाए. इस निर्देश की अनुपालना में प्रत्येक बैंक द्वारा हर ₹ 100 की डिपॉजिट वृद्धि पर आरबीआई के पास ₹ 4 के स्थान पर ₹ 10 अतिरिक्त रोकड़ जमा कराया गया. परिणामस्वरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दायरे से करीब ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक की अधिशेष तरलता को अवशोषित करने में मदद मिली. **वर्तमान में आरबीआई द्वारा इंक्रीमेंटल**

STUDYPDF WALLAH

सीआरआर की बाध्यता को हटा दिया गया है.

- **'हरित वित्त पोषण पारितंत्र' विकसित करने पर जोर**—भारत में 'हरित वित्त पोषण पारितंत्र' (Green Financing Eco-system) विकसित करने के उद्देश्य से सावधि जमा योजनाओं की तर्ज पर **1 अप्रैल, 2023 को 'हरित निक्षेप योजना'** घोषित की गई है. इस योजन. ान्तर्गत जमा धनराशि का उपयोग केवल हरित परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, सुस्थिर जल परियोजनाओं, हरित एवं स्वच्छ परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, ईको फ्रेंडली उत्पादों तथा सेवाओं के विनिर्माण और हरित भवनों के निर्माण के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है. देश में बढ़ते जा रहे कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित व न्यून करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अनचाहे पारिस्थितिकीय असन्तुलन को रोकने में सहायक सिद्ध होने वाली इस योजना को अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योजना माना जा रहा है. 1 जून, 2023 से लागू **'हरित निक्षेप योजना'** की अनुपालना देश में संचालित किए जा रहे बैंकों, एनबीएफसी आदि के लिए अनिवार्य कर दी गई है.

  इस योजनान्तर्गत **'हरित निक्षेप'** एक विनियमित इकाई द्वारा प्राप्त ब्याज सहित सावधि जमा योजना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे केवल भारतीय रुपए में ही मूल्यवर्गित किया जा सकता है. 'हरित निक्षेप' के अन्तर्गत जमा धनराशि का आवंटन हरित गतिविधियों और परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों यथा—नवीकरणीय ऊर्जा, सुस्थिर जल परियोजना, हरित एवं स्वच्छ परिवहन, अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव विविधता परियोजना, ईको फ्रेंडली उत्पादों तथा सेवाओं का विनिर्माण, हरित भवनों, सड़कों का निर्माण, ऊर्जा दक्षता परियोजना, जलवायु अनुकूलन परियोजना, आदि में ही किया जा सकता है. कोई भी विनियमित इकाई 'हरित निक्षेप योजना' के अन्तर्गत प्राप्त निवेशित धनराशि का आवंटन परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, तम्बाकू, हथियार विनिर्माण आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक परियोजनाओं में नहीं कर सकती. विनियमित इकाई को अनुमोदित वित्त पोषण ढाँचा सृजित करना होगा, जिसका वार्षिक आधार पर अंकेक्षण अनिवार्य है. 'हरित निक्षेप योजना' में निवेश की न्यूनतम अवधि 18 माह तथा अधिकतम अवधि 10 वर्ष सुनिश्चित की गई है. 'हरित निक्षेप योजना' के अन्तर्गत हालाँकि निवेशित धन पर अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु अधिविकर्ष की राशि प्राप्त करने के बाद 'हरित निक्षेप' को सावधि जमा में परिवर्तित करने का प्रावधान बनाया गया है. 'हरित निक्षेप योजना' के अन्तर्गत देश का कोई भी नागरिक, निगम, निकाय, प्रन्यास, क्लब, परिषद्, एकाकी, व्यापारी, साझेदारी फर्म आदि अपना धन निवेश कर सकते हैं.

- **रेपो दर सहित अन्य नीतिगत दरों में स्थिरता की प्रवृत्ति**—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अक्टूबर, 2023 को सम्पन्न एमसीपी की समीक्षात्मक बैठक में रेपो दर सहित अन्य गतिमान दरों को अपरिवर्तित रखा गया है अर्थात् रेपो दर 6·50 प्रतिशत ही बनी हुई है. रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण अन्य सम्बद्ध दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. उल्लेखनीय है कि रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई द्वारा देश के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है. वर्तमान नीतिगत दरों को निम्नांकित सारणी की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है—

आरबीआई की वर्तमान नीतिगत दरों पर एक नजर

(6 अक्टूबर, 2023 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार)

प्रमुख नीतिगत दरें	प्रतिशत
• रेपो दर	6·50 प्रतिशत
• रिवर्स रेपो दर	3·35 प्रतिशत
• बैंक दर	6·75 प्रतिशत
• नकद आरक्षण अनुपात (सीआरआर)	4·50 प्रतिशत
• सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	18·0 प्रतिशत
• स्टैडिंग डिपोजिट फैसिलिटी रेट (एसडीएफ दर)	6·25 प्रतिशत
• मार्जिनल स्टैडिंग फैसिलिटी रेट (एमएसएफ दर)	6·75 प्रतिशत

- **'हल्के भुगतान और निपटान पद्धति' की ओर बढ़ता हुआ रुझान**—देश में उत्पन्न होने वाली अनचाही व अवांछित प्राकृतिक आपदाओं के समय **'आकस्मिक भुगतान अवधारणा'** की धरातल पर लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'हल्के भुगतान और निपटान पद्धति' (Lightweight Payment and Settlement System–LPSS) को प्रारम्भ करने पर बल दिया गया है. आरटीजीएस, यूपीआई और नेफ्ट से सर्वथा भिन्न इस एलपीएसएस का उपयोग उस समय पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जब भुगतान करने के सभी तरीके विफल हो जाते हैं. भूकम्प, बाढ़, तूफान व अन्य आकस्मिक तथा प्राकृतिक आपदाओं के अलावा आन्तरिक व बाह्य युद्ध की स्थिति में कम-से-कम कार्मिकों के सहयोग से कहीं से भी एलपीएसएस को संचालित किया जा सकता है. निर्बाध आवश्यक भुगतान सेवाओं को जारी रखने में मदद करने वाले **एलपीएसएस** का मुख्य उद्देश्य आपदाजनक दशाओं के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में तरलता को कायम रखना है. विशेषज्ञों के मतानुसार न्यूनतम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की सहायता से संचालित किए जाने वाले एलपीएसएस की सहायता से न केवल सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित त्वरित भुगतानों को अंजाम देना सम्भव होगा, बल्कि यह देश के वित्तीय बाजार की भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध होगा. आरटीजीएस, यूपीआई, नेफ्ट आदि परम्परागत भुगतान पद्धतियों को संचालित करने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना तकनीक और सम्प्रेषण नेटवर्क तथा आधारिक संरचना की आवश्यकता होती है, जिनकी कार्य क्षमता तथा प्रभावशीलता प्राकृतिक आपदाओं के समय पर अस्थायी तौर पर क्षीण तथा विफल हो सकती है. इसलिए ऐसी अनचाही परिस्थितियों में भी आवश्यक तथा छोटे भुगतान कार्यों को निष्पादित करने हेतु एलपीएसएस को लागू करना समय की माँग बन चुकी है.

- **इरादतन चूककर्ताओं (Willful Defaulters) की संख्या में निरन्तर अभिवृद्धि**—हमारे देश में हालाँकि गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों में प्रतिवर्ष गिरावट दर्ज हो रही है, किन्तु जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले लोगों (Willful

STUDYPDF WALLAH

Defaulters) की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है. ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा जारी अद्यतन आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष विलफुल डिफॉल्ट में करीब ₹ 50,000 करोड़ की वृद्धि दर्ज हो रही है. वर्ष 2022 में 14,899 खातों से जुड़े इरादतन चूककर्ताओं पर बकाया धनराशि ₹ 3,04,03 करोड़ थी, जो बढ़कर 2023 में 16,883 खातों से जुड़कर ₹ 3,53,874 करोड़ तक पहुँच गई है. इसमें सर्वाधिक डिफॉल्ट राशि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदर्शित की जा रही है.

उल्लेखनीय है कि आरबीआई द्वारा जारी नवीन प्रावधानों के अनुसार ऋण के एनपीए होने के 6 माह के अन्दर इरादतन चूककर्ता के रूप में श्रेणीबद्ध करना अनिवार्य है. विशेषज्ञों के मतानुसार नवीन प्रावधानों के लागू होने के बाद इरादतन चूककर्ताओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है. ₹ 1 करोड़ से ऊपर के ऋण का जानबूझकर भुगतान नहीं करने वाले ऋणी को लॉर्ज विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है.

गैर-निष्पादनीय आस्तियों में कमी का दौर—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 जून, 2023 को जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादनीय आस्तियों का अनुपात 31 मार्च, 2023 को 3·9 प्रतिशत के स्तर पर आ गया. यह पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है. 31 मार्च, 2023 को निवल गैर-निष्पादनीय आस्ति अनुपात घटकर 1·0 प्रतिशत रह गया है.

- **इंटरबैंक कॉलमनी मार्केट में ई-रूपी का शुभारम्भ**—आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2023 में इंटरबैंक कॉलमनी मार्केट में होलसेल डिजिटल रुपए (ई-रूपी) की प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ कर दी गई है. इस परियोजना में प्रारम्भ में कुल 9 बैंकों (5 निजी क्षेत्र और 4 सार्वजनिक क्षेत्र) के बैंक सहभागी बैंकों के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं. अति अल्पावधि ऋणों के लिए लोकप्रिय कॉलमनी मार्केट से जुड़े इन सहभागी बैंकों में अब आरटीजीएस के स्थान पर 'टी प्लस जीरो' (T+0) मोड़ पर केन्द्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा की सहायता से व्यवहारों का निष्पादन किया जाएगा. यहाँ पर 'टी प्लस जीरो' मोड प्रोसेस से अभिप्राय व्यवहारों के समान दिन निपटान प्रक्रिया से है.
- **लघु या सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका**—वर्तमान समय में सूक्ष्म ऋण आवंटन तथा वितरण क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों द्वारा उल्लेखनीय भूमिका रेखांकित की जा रही है. रेटिंग एजेंसी **क्रिसिल के अनुसार 2023 और 2025** के मध्य लघु वित्त क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 18 से 20 प्रतिशत तक रह सकती है. गौरतलब तथ्य यह भी है कि इस क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से जुड़ी हुई लघु वित्त संस्थानों की वार्षिक वृद्धि दर अपेक्षा से अधिक दर्ज हो सकती है. मार्च 2023 में इन संस्थानों के द्वारा ₹ 1·38 लाख करोड़ का सूक्ष्म ऋण वितरित किया गया था, जबकि लघु वित्त बैंकों द्वारा केवल ₹ 1·19 लाख करोड़ ही वितरित किए गए थे. लघु वित्त बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से जुड़ी हुई लघु वित्त संस्थानों के साथ-साथ गैर-लाभकारी संस्थानों के द्वारा भी सूक्ष्म ऋण आवंटन तथा वितरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है. अप्रैल 2002 में आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म ऋण प्रदाता ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा साथ ही ये सब व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य आदि कार्यों के लिए भी ऋण प्रदान कर सकते है.
- **विशुद्ध पारिवारिक वित्तीय बचत में गिरावट की प्रवृत्ति**—भारतीय रिजर्व बैंक के नवीन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान देश के विशुद्ध घरेलू वित्तीय बचत में अपेक्षा के विपरीत गिरावट दर्ज हुई है. वर्ष 2021-22 में यह विशुद्ध घरेलू वित्तीय बचत जीडीपी के 7·2 प्रतिशत के बराबर थी, जो गिरकर 2022-23 में 5·1 प्रतिशत ही रह गई है. विगत अनेक दशकों में सर्वाधिक निम्न स्तर को छूने वाली यह गिरावट सम्पूर्ण आर्थिक जगत् में चिन्ता और चर्चा का विषय बन चुकी है. वित्तीय वर्ष 2021 में विशुद्ध पारिवारिक वित्तीय बचत ₹ 22·8 लाख करोड़ थी, जो 2022 में गिरकर ₹ 16·96 लाख करोड़ हो गई थी. तत्पश्चात् 2023 में यह पुनः कम होकर ₹ 13·7 लाख करोड़ ही रह गई. दूसरी ओर भारतीय परिवारों की वित्तीय देनदारियाँ भी 2022-23 में जीडीपी की 5·8 प्रतिशत हो गई है, जोकि विगत वर्ष 2021-22 में यह केवल 3·8 प्रतिशत ही थी. दोनों नकारात्मक परिणामों अर्थात् विशुद्ध पारिवारिक वित्तीय बचत में गिरावट और परिवारों की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि के लिए कोविड महामारी के पश्चात्वर्ति प्रभाव, बढ़ती हुई महँगाई, अचल परिसम्पत्तियों में निवेश की प्रवृत्ति आदि अनेक कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. घरेलू वित्तीय बचत में दर्ज हुई इस चिन्ताजनक गिरावट के कारण न केवल निवेश पर, बल्कि ब्याज दरों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. ●●●

STUDYPDF WALLAH

प्रौद्योगिकी लेख

सिंथेटिक मानव भ्रूण : विज्ञान की नई उपलब्धि

—डॉ. दीपक कोहली

स्टेम कोशिकाओं का उपयोग कर सिंथेटिक मानव भ्रूण (Synthetic Human Embryos–SHE) का सृजन करने की हाल की घोषणा ने वैज्ञानिक और नैतिकतावादी समुदायों के बीच में अत्यंत रूचि उत्पन्न की है और एक बहस छेड़ दी है. सिंथेटिक मानव भ्रूण ऐसी संरचनाएं हैं, जो आरम्भिक मानव भ्रूण के सदृश होती हैं, लेकिन इनका सृजन अंडाणु या शुक्राणु कोशिकाओं के प्रत्यक्ष योगदान के बिना स्टेम कोशिकाओं से किया जाता है. इन संरचनाओं में मानव विकास, आनुवंशिक विकारों और गर्भावस्था हानि के विषय में मूल्यवान अन्तर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन इसके साथ ही उनकी स्थिति, उपयोग और विनियमन के बारे में गम्भीर नैतिक एवं विधिक प्रश्न भी खड़े होते हैं.

ये अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से नहीं बनते हैं, बल्कि प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं (Pluripotent Stem Cells) से बनाए जाते हैं. स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं, जो शरीर में लगभग किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं.

ये स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त की जा सकती हैं या त्वचा कोशिका या रक्त कोशिकाओं जैसी वयस्क कोशिकाओं से 'रि-प्रोग्राम' की जा सकती हैं.

सिंथेटिक मानव भ्रूण का निर्माण—शोधकर्ता 'कल्चर' की दशाओं और कोशिका विभेदन (Cell Differentiation) का मार्गदर्शन करने वाले संकेतों में हेरफेर कर स्टेम कोशिकाओं को त्रि-आयामी संरचनाओं (three-densional structures) में स्व-व्यवस्थित होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो आरम्भिक भ्रूण विकास के कुछ पहलुओं की नकल करते हैं. उदाहरण के लिए, ये संरचनाएं एक ब्लास्टोसिस्ट सदृश गुहा (blastocyst-like cavity), एक प्लेसेंटा सदृश ऊतक (placenta-like tissue) और एक आदिम स्ट्रीक सदृश संरचना (streak-like structure) का निर्माण कर सकती हैं, जो गैस्ट्रुलेशन (gastrulation) की शुरूआत को चिह्नित करती है. गैस्ट्रुलेशवह प्रक्रिया जिसके द्वारा तीन जर्म लेयर्स (एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म) का निर्माण होता है.

विश्व का पहला सिंथेटिक मानव भ्रूण—विश्व का पहला सिंथेटिक मानव भ्रूण कथित तौर पर कैंब्रिज विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम द्वारा बनाया गया तथा उनके इस शोध को जून 2023 में 'इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च' के समक्ष प्रस्तुत किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, इन सिंथेटिक मानव भ्रूणों को उस चरण तक विकसित किया गया, जो लगभग 14 दिनों की अवधि के बराबर था, जो कि कई देशों में प्राकृतिक मानव भ्रूणों के अध्ययन के लिए तय कानूनी सीमा है.

सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से सम्बन्धित नियम

सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से सम्बन्धित कानून और नियम दुनिया के विभिन्न देशों एवं भूभागों में व्यापक रूप से भिन्न हैं.

पूर्ण निषेध—कुछ देशों में सख्त विनियमन लागू हैं जो किसी भी प्रकार के मानव भ्रूण अनुसंधान को प्रतिबंधित या निषिद्ध करते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, आयरलैण्ड, पोलैण्ड और स्लोवाकिया.

अनुसंधान की अनुमति—कुछ अन्य देशों में अधिक अनुमेय विनियमन मौजूद हैं जो कुछ शर्तों और निरीक्षण के अधीन मानव भ्रूण अनुसंधान के कुछ रूपों की अनुमति प्रदान करते हैं, जैसे आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस. हालाँकि, इनमें से अधिकांश विनियमन स्पष्ट रूप से सिंथेटिक मानव भ्रूण या अन्य प्रकार के स्टेम सेल-आधारित भ्रूण मॉडल को सम्बोधित नहीं करते हैं.

भारतीय सन्दर्भ—भारत में सिंथेटिक मानव भ्रूण अनुसंधान को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट विधान मौजूद नहीं है. हालाँकि, कुछ दिशा-निर्देश मौजूद हैं, जो सामान्य रूप से स्टेम सेल अनुसंधान पर लागू होते हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने वर्ष 2017 में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए, जो मनुष्यों या पशुओं से जुड़े स्टेम सेल अनुसंधान के संचालन के लिए नैतिक सिद्धांत एवं मानदंड प्रदान करते हैं.

SHE के विकास से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई बाध्यकारी संधि या कन्वेंशन मौजूद नहीं है जो सिंथेटिक मानव भ्रूण अनुसंधान को नियंत्रित करते हों. हालाँकि, कुछ गैर-बाध्यकारी घोषणाएं और अनुशंसाएं मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के लिए कुछ मार्गदर्शन एवं मानक प्रदान करती हैं. उदाहरण के लिए—

यूनेस्को (UNESCO) की मानव जीनोम और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights), 1997—इसमें कहा गया है कि "ऐसे अभ्यास जो मानवीय गरिमा के विपरीत हैं, जैसे कि मानवों की प्रजनन क्लोनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी" और यह कि "मानव जीनोम पर हस्तक्षेप केवल निवारक, नैदानिक या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और सम्बद्ध व्यक्ति की सूचित सहमति से किया जाना चाहिए".

यूनेस्को की जैवनैतिकता और मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights), 2005—इसमें कहा गया है कि मानव से जुड़े किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में "मानव गरिमा, मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए" और यह भी कि "व्यक्ति के हितों और कल्याण को विज्ञान या समाज के एकमात्र हित के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए".

'इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च' द्वारा जारी दिशा-निर्देश—इसे वर्ष 2021 में स्टेम सेल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रांसलेशन के लिए जारी किया गया, जो मानव भ्रूण, स्टेम सेल, ऑर्गनॉइड और अन्य मॉडलों से जुड़े नैतिक एवं उत्तरदायी स्टेम सेल रिसर्च के संचालन के लिए विस्तृत अनुशंसाएं प्रदान करता है.

सिंथेटिक मानव भ्रूण का महत्व

मानव विकास का अध्ययन करना—सिंथेटिक मानव भ्रूण (SHE), मानव विकास का अध्ययन करने के लिए (विशेष रूप से आरम्भिक चरण का अध्ययन है जहाँ प्राकृतिक भ्रूणों में अवलोकन कठिन होता है) एक प्रभावशाली उपस्कर प्रदान कर सकता है. इससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिल सकती है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, जीन कैसे नियंत्रित होते हैं, बीमारियाँ कैसे होती हैं या उन्हें कैसे रोका जा सकता है और गर्भावस्था कैसे स्थापित होती है या किस तरह उसकी हानि होती है?

अनुसंधान के लिए मानव भ्रूण का विकल्प—सिंथेटिक मानव भ्रूण अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक मानव भ्रूण का एक मूल्यवान विकल्प या पूरक प्रदान कर सकते हैं. ये IVF भ्रूणों पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो प्रायः दुर्लभ या अनुपलब्ध होते हैं और यह उनके उपयोग या विनाश से जुड़ी कुछ नैतिक चिंताओं को टाल सकता है.

पुनर्योजी चिकित्सा में अनुप्रयोग—सिंथेटिक मानव भ्रूण पुनर्योजी चिकित्सा (Regenerative Medicine) और जैव प्रौद्योगिकी के लिए नवीन अनुप्रयोगों को सक्षम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, सिंथेटिक

STUDYPDF WALLAH

मानव भ्रूण का उपयोग प्रत्यारोपण या थेरेपी के लिये विशिष्ट कोशिका प्रकार या ऊतकों के सृजन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं आदि. सिंथेटिक मानव भ्रूण का उपयोग औषधी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग के लिए रोग या आघात के मॉडल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है.

सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से सम्बद्ध प्रमुख मुद्दे

अस्पष्ट विनियमन—सिंथेटिक मानव भ्रूण अपनी नैतिक स्थिति, उपयोग और विनियमन के सम्बन्ध में नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सिंथेटिक मानव भ्रूण इस बारे में सवाल खड़े करते हैं कि क्या उनके कोई हित या अधिकार हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका उपयोग एवं विनियमन कैसे किया जाना चाहिए, उन तक किन लोगों की पहुँच होनी चाहिए और उनके उपयोग की निगरानी किसे करनी होगी. अवास्तविक अपेक्षाओं/झूठी धारणाओं की स्थापना: सिंथेटिक मानव भ्रूण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं. वे समाज के कुछ वर्गों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें अप्राकृतिक, अनैतिक या खतरनाक मान सकते हैं.

सिंथेटिक मानव भ्रूण कुछ रोगियों या उपभोक्ताओं के बीच अवास्तविक अपेक्षाएं या झूठी उम्मीदें भी पैदा कर सकते हैं जो अप्रमाणित या अनुचित उद्देश्यों के लिए उनकी माँग कर सकते हैं.

क्लोनिंग और सिंथेटिक जीवन रूपों से सम्बन्धित मुद्दे—सिंथेटिक भ्रूण कुछ सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकते हैं. स्टेम कोशिकाओं में हेरफेर करने और सिंथेटिक जीवन रूप या क्लोनिंग निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों एवं परिणामों के बारे में अभी भी व्यापक अनिश्चितता व्याप्त है. इन प्रौद्योगिकियों को मानवों या पशुओं पर लागू करने से पहले वृहत एवं कठोर परीक्षण और निगरानी की आवश्यकता है.

सिंथेटिक मानव भ्रूण से सम्बन्धित मुद्दे पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता—सिंथेटिक मानव भ्रूण के विकास से सम्बन्धित नैतिक प्रश्नों का कोई सरल या निश्चित उत्तर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनसे जटिल और विविध दृष्टिकोण एवं हित संलग्न हैं. इस प्रकार, शोधकर्ताओं, नैतिकतावादियों, नीति-निर्माताओं, नियामकों, चिकित्सकों, रोगियों, दाताओं, पक्ष-समर्थकों, मीडिया और जनता जैसे विभिन्न अभिकर्ताओं और क्षेत्रों के बीच वृहत संवाद एवं विमर्श की आवश्यकता है.

विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता—विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग एवं समन्वय की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों से वैश्विक निहितार्थ और अनुप्रयोग संलग्न हैं. अधिक सामंजस्यपूर्ण और मानकीकृत कानूनों एवं दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र में क्रियान्वित अभ्यासों और परिणामों के सम्बन्ध में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है.

जोखिमों को सन्तुलित करने की आवश्यकता—इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के विषय में अधिक सन्तुलन और सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ अवसर और जोखिम दोनों ही मौजूद हैं. सृजित सिंथेटिक भ्रूणों के साथ-साथ इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले या इससे प्रभावित होने वाले प्राकृतिक भ्रूणों के प्रति अधिक सम्मान और दायित्व की आवश्यकता है. इस क्षेत्र का उपयोग करने में अधिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मानवता के लिए लाभ और लागत दोनों निहित हैं.

निष्कर्ष

सिंथेटिक मानव भ्रूण विज्ञान का एक नया मोर्चा है जो अवसर और जोखिम दोनों प्रदान करता है. उनमें मानव विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और हमारे स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, लेकिन वे नैतिक दुविधाएं और सामाजिक चुनौतियाँ भी रखते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उपयोग अच्छाई के लिए किया जाए न कि बुराई के लिए, उन पर सावधानीपूर्वक विचार और विनियमन की आवश्यकता है. समाज उन्हें स्वीकार करे और उनका सम्मान करे, इसके लिए उन पर वृहत संवाद एवं विमर्श किया जाना चाहिए. इसके साथ ही, वे मानव जीवन पर हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों पर पुनर्विचार करने की चुनौती भी पेश करते हैं. ●●●

शेष पृष्ठ 92 का

सकती हैं, क्योंकि इनका सीधा सम्बन्ध सटोरियों की अभिरुचि से होता है. वास्तविक कीमत से दूरी रखने वाले ऐसे स्टॉक या अंशों को अत्यधिक जोखिमपूर्ण माना जाता है अर्थात् नए निवेशकों को इनसे सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए.

मूलत: 'मेमे' शब्द का अभिप्राय सोशल मीडिया पर बड़े स्वरूप में साझा किए जाने वाले मनोरंजक दृश्य या मजाक या कॉमिक से है, जो अति अल्प समय में ही बहुचर्चित हो जाता है. ऐसे कॉमिक्स की तर्ज पर मेमे स्टॉक या अंश भी सोशल मीडिया पर अत्यधिक लोकप्रिय एवं चर्चित हो जाते हैं. प्राय: सटोरियों द्वारा ऐसे मेमे स्टॉक या अंशों की कीमतों को बनावटी ढंग से खूब बढ़ाया जाता है और जब कीमतें चरम बिन्दु पर पहुँच जाती हैं, तो सटोरियों द्वारा ऐसे अंशों को बेचना शुरू कर दिया जाता है. ऐसे सटोरियों को मेमे समुदाय नाम से पुकारा जाता है और इस समुदाय के सदस्यों की इच्छा पर मेमे स्टॉक या अंशों की कीमतों का निम्न या उच्च स्तर निर्भर करता है. मेमे समुदाय के सदस्यों द्वारा अनोखी भाषा को साझा किया जाता है जिसका भावार्थ गैर-सदस्यों की समझ से बाहर होता है. सटोरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख शब्द – 'बाय द डिप', बैगहोल्डर्स, वानर, डीडी, डायमण्ड, पतित, पेपर हैण्ड्स, फोमो, लाइन पकड़ो, योलो (YOLO), टेंडीज, 'टू द मून' आदि हैं.

प्रमुख उदाहरण :

- Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
- SoFi Technologies Inc. (SOFI)
- Netflix Inc (NFLX)
- Palantir Technologies Inc (PLTR)
- Manchester United PIc (MANU)
- Gamestop Corp (NYSE : GME)
- BlackBerry (NYSE : BB)

आई-सीआरआर (Incremnetal Cash Reserve Ratio or I-CRR)

हालाँकि, हमारे देश में आरबीआई के द्वारा नकदी प्रारक्षित अनुपात (CRR) से सम्बन्धित प्रावधान पहले से ही लागू किए गए थे. इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय बैंकों को अपने कुल जमा धन का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के अधीन रोकड़ जमा कराना होता है, किन्तु हाल ही में ₹ 2000 का नोट चलन से बाहर होने के कारण बैंकों में बहुतायत में धन जमा हो गया. करीब ₹ 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त धनराशि बैंकों में जमा होने के कारण अतिरिक्त तरलता की स्थिति बन गई थी. ऐसी स्थिति को नियन्त्रित करने तथा अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **'वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात'** (I-CRR) की अनुपालना के लिए बैंकों को बाध्य किया गया. नवीन प्रावधान के अनुसार प्रत्येक बैंक द्वारा ₹ 100 की जमा वृद्धि पर ₹ 4 के स्थान पर ₹ 10 अतिरिक्त रोकड़ आरबीआई के पास जमा कराया गया. ऐसा करने से करीब ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक की अधिशेष तरलता को अवशोषित करने में मदद मिली. तत्पश्चात् जब बैंकों के समक्ष तरलता का संकट उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न होने लगी, तो आरबीआई द्वारा वृद्धि-शील रोकड़ आरक्षित अनुपात की व्यवस्था को भारतीय बैंकों को मुक्त कर दिया गया अर्थात् करीब तीन माह (अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2023) की अल्प समयावधि के लिए लागू दिए किए आई-सीआरआर के अस्थायी आदेश को आरबीआई द्वारा हटा दिया गया है. ●●●

STUDYPDF WALLAH

प्रौद्योगिकी लेख

डीपफेक : उपयोग और चुनौतियाँ

हाल ही में एक फैक्ट-चेकर वेबसाइट ने खुलासा किया कि लिफ्ट में प्रवेश करती अभिनेत्री रश्मिका की वायरल वीडियो वस्तुतः 'डीपफेक' (Deepfake) है. इस वीडियो ने एक बहस छेड़ दी है अभिनेताओं द्वारा डीपफेक वीडियो के कानूनी विनियमन की माँग की जा रही है. इसकी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) राज्य मंत्री ने आईटी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत मौजूद विनियमनों का हवाला दिया है, जो ऐसे वीडियो के प्रसार से निपट सकते हैं. डीपफेक के विनियमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के तहत् प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence–AI) विनियमन के बीच की अंतःक्रिया और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षा उपायों को अधिक व्यापक रूप से शामिल करने के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा.

डीपफेक

डीपफेक शब्द सिंथेटिक मीडिया को सन्दर्भित करता है जहाँ किसी व्यक्ति की सदृश्ता को दूसरे व्यक्ति की सदृश्ता से बदलने के लिए डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है. डीपफेक मशीन लर्निंग और AI के प्रभावशाली तकनीकों जैसे कि डीप लर्निंग (Deep learning) और जेनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क (Generative Adversarial Networks–GANs) का उपयोग कर सृजित किए जाते हैं. डीपफेक तकनीक का उपयोग मनोरंजन, शिक्षा, कला और सक्रिय गतिविधियों (Activism) जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. हालाँकि, यह गम्भीर नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे– फेक न्यूज सृजित करना, भ्रामक सूचना का प्रसार करना, निजता/गोपनीयता का उल्लंघन करना और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना. इसका उपयोग नकली या फेक वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है; इसका उपयोग स्कैमर्स द्वारा मित्रों या प्रियजनों का रूप धारण कर लोगों से छद्म तरीके से धन प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है.

डीपफेक टेक्नोलॉजी के उपयोग

फिल्म डबिंग–डीपफेक तकनीक का उपयोग विभिन्न भाषाएं बोलने वाले अभिनेताओं के लिए यथार्थपरक लिप-सिंकिंग (Lip-syncing) के सृजन के लिए किया जा सकता है, जिससे उक्त फिल्म वैश्विक दर्शकों के लिए अधिक अभिगम्य (Accessible and immersive) हो जाती है. उदाहरण के लिए, मलेरिया के उन्मूलन का आह्वान करने के लिए एक याचिका शुरू करने के लिए एक वीडियो बनाया गया था, जहाँ डीपफेक तकनीक का उपयोग कर डेविड बेकहम, ह्यूज जैकमैन और बिल गेट्स जैसी मशहूर हस्तियों से विभिन्न भाषाओं में आह्वान कराया गया था.

शिक्षा–डीपफेक तकनीक कक्षा में ऐतिहासिक व्यक्तियों को जीवंत करने या विभिन्न परिदृश्यों के इंटरैक्टिव सिमुलेशन बनाने के रूप में शिक्षकों के लिए आकर्षक पाठ प्रदान करने में मदद कर सकती है. उदाहरण के लिए, अब्राहम लिंकन के प्रसिद्ध गेटिसबर्ग सम्बोधन के डीपफेक वीडियो का उपयोग छात्रों को अमरीकी गृह युद्ध के बारे में शिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है.

कला–डीपफेक तकनीक का उपयोग कलाकारों के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करने, विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करने या अन्य कलाकारों के साथ सहयोग करने के लिए एक रचनात्मक साधन के रूप में किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा में साल्वाडोर डाली के संग्रहालय को बढ़ावा देने के लिए डाली का एक डीपफेक वीडियो सृजित किया गया था, जहाँ उन्होंने आगंतुकों के साथ संवाद किया और अपनी कृतियों पर टिप्पणी की.

स्वायत्तता और अभिव्यक्ति–डीपफेक तकनीक लोगों को अपनी डिजिटल पहचान को नियंत्रित करने, अपनी गोपनीयता की रक्षा करने या विभिन्न तरीकों से अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए सशक्त बना सकती है. उदाहरण के लिए, रिफेस नामक एक डीपफेक ऐप उपयोगकर्ताओं को मनोरंजन या वैयक्तिकरण के लिए वीडियो या जिफ (Gifs) के रूप में मशहूर हस्तियों या चरित्रों के साथ अपना चेहरा बदलने की अनुमति देता है.

सन्देश और उसकी पहुँच का विस्तार–डीपफेक तकनीक उन लोगों की आवाज और प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है जिनके पास साझा करने के लिए महत्वपूर्ण सन्देश हैं, विशेष रूप से वे लोग, जो भेदभाव, सेंसरशिप या हिंसा का सामना कर रहे हैं.

उदाहरण के लिए, सऊदी सरकार द्वारा हत्या करा दिए गए एक पत्रकार का डीपफेक वीडियो बनाया गया जहाँ उसने अपना अन्तिम संदेश दिया और न्याय की गुहार लगाई.

डिजिटल पुनर्निर्माण और सार्वजनिक सुरक्षा–डीपफेक तकनीक गुम या क्षतिग्रस्त डिजिटल डेटा के पुनर्निर्माण में मदद कर सकती है, जैसे–पुरानी तस्वीरों या वीडियो का पुनर्निर्माण या निम्न गुणवत्ता वाले फुटेज को बेहतर बनाना. यह आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सैन्य कर्मियों के लिए यथार्थवादी प्रशिक्षण सामग्री का सृजन कर सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार लाने में भी मदद कर सकता है. उदाहरण के लिए, स्कूल में गोली-चालन (शूटिंग) का एक डीपफेक वीडियो बनाया गया ताकि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके कि वे ऐसे परिदृश्य में किस प्रकार प्रतिक्रिया दें.

नवाचार–डीपफेक तकनीक मनोरंजन, गेमिंग या मार्केटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है. यह स्टोरीटेलिंग, इंटरैक्शन, डायग्नोसिस या प्रत्यायन/अनुनय (Persuasion) के नए रूपों को सक्षम कर सकता है. उदाहरण के लिए, सिंथेटिक मीडिया की क्षमता और समाज पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए मार्क जुकरबर्ग का एक डीपफेक वीडियो बनाया गया था.

डीपफेक प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध चुनौतियाँ

झूठी सूचना का प्रसार–डीपफेक का उपयोग जानबूझकर झूठी जानकारी या गलत सूचना के प्रसार के लिए किया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भ्रम पैदा कर सकता है. उदाहरण के लिए, राजनेताओं या मशहूर हस्तियों के डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल जनता की राय को प्रभावित करने या चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. उत्पीड़न और धमकी: डीपफेक को लोगों को परेशान करने, भयभीत करने, नीचा दिखाने और कमजोर करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है.

उदाहरण के लिए, डीपफेक तकनीक अन्य अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि रिवेंज पोर्न बनाना, जिससे महिलाएं असंगत रूप से हानि उठाती हैं. डीपफेक पोर्न पीड़ितों की निजता एवं सहमति का भी उल्लंघन कर सकता है और मनोवैज्ञानिक संकट एवं आघात का कारण बन सकता है. डीपफेक प्रौद्योगिकी का उपयोग ब्लैकमेल या फिरौती की सामग्री के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जैसे–किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करने, प्रेम प्रसंग रखने या खतरे में होने के नकली वीडियो बनाना. उदाहरण के लिए, एक

STUDYPDF WALLAH

राजनेता का डीपफेक वीडियो बनाया गया और इसे सार्वजनिक नहीं करने के बदले धन की माँग की गई.

झूठे साक्ष्य गढ़ना—डीपफेक का उपयोग झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग फिर जनता को धोखा देने या राज्य की सुरक्षा को हानि पहुँचाने के लिए किया जा सकता है. डीपफेक साक्ष्य का उपयोग कानूनी कार्यवाही या जाँच में हेर-फेर करने के लिए भी किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, डीपफेक ऑडियो या वीडियो का उपयोग किसी की पहचान या आवाज का प्रतिरूपण करने और झूठे दावे करने या आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है.

प्रतिष्ठा धूमिल करना—डीपफेक का उपयोग किसी व्यक्ति की ऐसी छवि बनाने के लिए किया जा सकता है जैसा वह नहीं है या किसी को कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखाने के लिए जैसा उसने कभी नहीं किया या किसी व्यक्ति की आवाज को ऑडियो फाइल में संश्लेषित करने के लिए किया जा सकता है, जिसका दुरुपयोग फिर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया जा सकता है.

उदाहरण के लिए, डीपफेक मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति या संगठन की विश्वसनीयता या विश्वस्तता को हानि पहुँचाने और प्रतिष्ठा सम्बन्धी या वित्तीय नुकसान करने के लिए किया जा सकता है.

वित्तीय धोखाधड़ी—डीपफेक तकनीक का उपयोग अधिकारियों, कर्मचारियों या ग्राहकों का रूप धारण करने और उन्हें संवेदनशील जानकारी प्रकट करने, धन हस्तांतरित करने या गलत निर्णय लेने के लिए भ्रमित करने हेतु किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, एक CEO के डीपफेक ऑडियो का इस्तेमाल एक कर्मचारी को भ्रमित करने और धोखाधड़ीपूर्ण खाते में 2,43,000 अमरीकी डॉलर हस्तांतरित करने के लिए किया गया था.

डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रवर्तित नियम

आईटी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021—आईटी अधिनियम और आईटी नियम दोनों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जो सोशल मीडिया मध्यस्थों पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के डीपफेक वीडियो या फोटो को जल्द-से-जल्द हटा दिया जाएगा. ऐसा न करने पर 3 वर्ष तक की कैद और ₹ 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है.

आईटी अधिनियम की धारा 66D—आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66D में कहा गया है कि जो कोई भी संचार उपकरण या कम्प्यूटर संसाधन का उपयोग कर प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी (Cheating by Personating) करता है, उसे 3 वर्ष तक की कैद और ₹ 1 लाख तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है.

नियम 3(1)(b)(vii)—यह नियम कहता है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता किसी भी ऐसी सामग्री को होस्ट न करें, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती हो.

नियम 3(2)(b)—ऐसी किसी सामग्री के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना आवश्यक है.

डीपफेक के खतरे से निपटने हेतु उपाय

अन्य देशों के अनुभव से सीखना—डीपफेक के जीवनचक्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है—निर्माण, प्रसार और इसका पता लगाना. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन का उपयोग गैर-कानूनी या गैर-सहमति वाले डीपफेक के निर्माण के शमन के लिए किया जा सकता है. चीन जैसे देश जिन तरीकों से इस तरह के विनियमन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से एक यह है कि डीपफेक प्रौद्योगिकियों के प्रदाताओं को अपने वीडियो में मौजूद लोगों की सहमति प्राप्त करने, उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने और उन्हें साधन या अवलंब (Recourse) प्रदान करने की आवश्यकता है. डीपफेक से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कनाडा का दृष्टिकोण यह रहा है कि व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं और ऐसे विधान बनाए जाएं, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से डीपफेक के सृजन एवं वितरण को अवैध बना देंगे.

सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित वीडियो में वॉटरमार्क जोड़ना—कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित वीडियो में वॉटरमार्क जोड़ना प्रभावी पहचान और श्रेय (Attribution) के लिए आवश्यक है. वॉटरमार्क विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हुए सामग्री के उद्गम और स्वामित्व को प्रकट करते हैं. वे सामग्री के निर्माता या स्रोत को स्पष्ट करके इसकी पहचान में सहायता करते हैं, विशेष रूप से जब इन्हें विभिन्न सन्दर्भों में साझा किया जाता है. दृश्यमान वॉटरमार्क अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध एक निवारक के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामग्री के स्रोत या उद्गम का पता लगाया जा सकता है. इसके अलावा, वॉटरमार्क मूल निर्माता के अधिकारों का प्रमाण प्रदान कर जवाबदेही का समर्थन करते हैं; इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित सामग्री के लिए कॉपीराइट और बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा के प्रवर्तन को सरल बनाते हैं.

उपयोगकर्ताओं को अनुचित सामग्री अपलोड करने से रोकना—ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को उनकी सामग्री नीतियों के बारे में शिक्षित और सूचित करने के लिए कदम उठाने चाहिए तथा उन्हें अनुचित सामग्री अपलोड करने से रोकने के लिए उपाय भी लागू करने चाहिए.

डीपफेक डिटेक्शन तकनीकों का विकास और सुधार—इसमें अधिक परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करने के साथ ही नए तरीकों को विकसित करना शामिल हो सकता है, जो डीपफेक के सन्दर्भ, मेटाडेटा या अन्य कारकों के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हैं.

डिजिटल शासन और विधान को सुदृढ़ करना—यह ऐसे स्पष्ट एवं संगत कानूनों एवं नीतियों को संलग्न कर सकता है, जो डीपफेक के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को परिभाषित एवं प्रतिबंधित करते हैं, साथ ही डिजिटल नुकसान के पीड़ितों और अपराधियों के लिए प्रभावी उपचार एवं प्रतिबंध प्रदान करते हैं.

मीडिया साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना—इसमें जनता और मीडिया को डीपफेक के अस्तित्व एवं सम्भावित प्रभाव के बारे में शिक्षित करना, साथ ही उन्हें संदिग्ध सामग्री को सत्यापित करने और रिपोर्टिंग करने के लिए कौशल एवं साधन प्रदान करना शामिल हो सकता है.

डीपफेक प्रौद्योगिकी के नैतिक और उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना—इसमें डीपफेक प्रौद्योगिकी के सृजनकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के लिए आचार संहिता एवं मानकों की स्थापना और कार्यान्वयन के साथ ही इसके सकारात्मक एवं लाभकारी अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है.

●●●

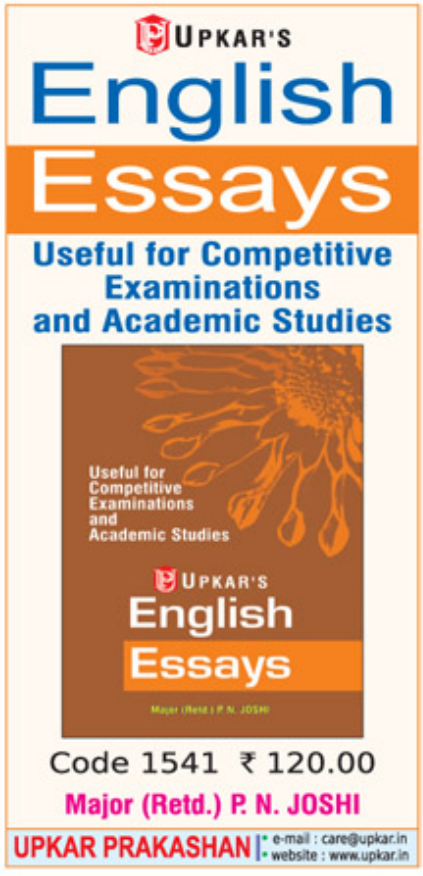

STUDYPDF WALLAH

वैश्विक संस्था लेख

पुनर्गठन से ही रहेगी सुरक्षा परिषद् प्रभावी

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रतिद्वंद्वी संयुक्त राज्य अमरीका और रूसी प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए गाजा में इजरायल-हमास युद्ध को सम्बोधित करने में एक बार पुनः विफल रही. इसके पूर्व रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रारम्भ होने के डेढ़ वर्ष पश्चात् भी इसके समाप्ति के सन्दर्भ में कोई सर्वस्वीकार्य निर्णय लेने में अक्षम रहने तथा सम्बन्धित पक्षों के मध्य सहमति बनाने में असफल रहने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद् को अपने 'वर्तमान स्वरूप' में 'पंगु' और 'निष्क्रिय' संस्था की संज्ञा से सम्बोधित किया था.

गौरतलब है कि परिषद् संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था है, जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का उत्तरदायित्व है, लेकिन इसके विभाजनों तथा स्थायी सदस्यों द्वारा अपने रणनीतिक तथा सामरिक हितों की पूर्ति की महत्वाकांक्षा ने इसे निष्प्रभावी तथा दंतविहीन संस्था बना दिया है. वर्तमान में यह संस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों, संघर्षों, तनावों का सर्वस्वीकार्य समाधान खोजने के प्रयास में संघर्ष कर रही है.

सुरक्षा परिषद्-एक सूक्ष्म दृष्टि

संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सुरक्षा परिषद् सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की. यह अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद् को देता है. इसकी शक्तियों एवं कार्यों में शांति स्थापना अभियानों की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई का प्राधिकरण, महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देना शामिल है. यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों को बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है.

चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार उद्देश्य हैं–

- अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना;
- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना;
- अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना;
- राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केन्द्र बनना.

संघटन

- सुरक्षा परिषद् में 15 सदस्य होते हैं. रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका-संस्था के 5 स्थायी सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं.
- इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद् में 10 गैर-स्थायी सदस्य भी होते हैं, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं. भारत का वर्तमान कार्यकाल 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर, 2023 तक चलेगा.
- निकाय की अध्यक्षता अपने सदस्यों के बीच मासिक रूप से बदलती रहती है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य राष्ट्रों का 'वीटो' विशेषाधिकार

- संयुक्त राष्ट्र 'वीटो' को एक 'विशेष मतदान शक्ति' के रूप में परिभाषित करता है, जो यह प्रावधान करता है कि 'यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी (सुरक्षा परिषद्) में नकारात्मक वोट डालता है, तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी'.
- उल्लेखनीय है कि 'वीटो शक्ति' संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के P5 सदस्य देशों तक ही सीमित है. सुरक्षा परिषद् के गैर-स्थायी सदस्य इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं.
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि यूएनएससी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा और 'प्रक्रियात्मक मामलों' पर निर्णय के लिए 15 सदस्यों में से नौ के सकारात्मक वोट से अधिक की आवश्यकता नहीं होगी.
- किसी भी अन्य मामले पर निर्णय के लिए न केवल 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट की आवश्यकता होती है, बल्कि स्थायी सदस्यों के सहमति वाले वोटों की भी आवश्यकता होती है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के मुख्य मुद्दे

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् का प्रमुख उद्देश्य/कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है, परन्तु पिछले कुछ दशकों में स्थायी सदस्यों के मध्य विश्वास एवं मैतक्य का अभाव तथा व्यक्तिगत रणनीतिक, सामरिक एवं भूराजनीतिक हितों की पूर्ति की महत्वाकांक्षा ने संस्था के इस उद्देश्य की प्राप्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है तथा वर्तमान उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों के मध्य लगभग आप्रासंगिक बना दिया है.
- उदाहरण के लिए सुरक्षा परिषद् सीरिया, गाजा और यूक्रेन के हालिया संकट से निपटने में विफल रहा है. वर्तमान विश्व व्यवस्था को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, P5 सदस्यः संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और चीन विश्व की परिधि पर 3 ध्रुव हैं. इन तीनो ध्रुवों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए मंच का उपयोग करने के कारण यह संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है तथा इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा तथा खाद्य संकट (विशेष रूप से तृतीय विश्व के देशों में) उत्पन्न होने के कारण मानवता के समक्ष गहरा संकट उत्पन्न हो गया है.
- ईरान तथा उत्तर कोरिया पर आरोपित प्रतिबंधों की विफलता के साथ-साथ सुरक्षा परिषद् ने तख्तापलट के लिए म्यांमार जुंटा के खिलाफ न ही कोई कार्रवाई की और न ही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं की रिहाई के लिए कोई दबाव बनाया. इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में किसी नये प्रतिबन्ध की घोषणा भी नहीं की गई. जिम्मेदारी की आड़ में लीबिया और सीरिया में इसके हस्तक्षेप सहित विभिन्न मुद्दों ने संस्था की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् चीन को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में विफल रही, डब्ल्यूएचओ टीम वायरस की उत्पत्ति पर निष्कर्ष निकालने या चीनी प्रयोगशालाओं तक पहुँच हासिल करने में सक्षम नहीं रही है.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की एक प्रमुख आलोचना के रूप में यह कहा जाता है कि इस संस्था ने आतंकवाद के खिलाफ उस तरह से आवाज नहीं उठाई है, जैसी उठनी चाहिए थी. इसका प्रमुख कारण वैश्विक शक्तियों के अपने भूराजनैतिक हित तथा आतंकवाद के सन्दर्भ में मैतक्य का अभाव है. उदाहरण के लिए अमरीका अलकायदा को एक आतंकवादी संगठन मानता है, परन्तु उसने सीरिया के गृह युद्ध में बशर-अल-असद शासन के विरुद्ध अल-नुशरा फ्रंट (अलकायदा की एक अन्य शाखा) को वित्तीय तथा

STUDYPDF WALLAH

सैन्य समर्थन प्रदान किया. वही रूस ने अमरीका का ध्यान रूस-यूक्रेन युद्ध से भटकाने के लिए तथा उसे अन्यत्र व्यस्त करने के लिए इजराइल-हमास संघर्ष के दौरान हमास, हौथी विद्रोही (अंसार-अल्लाह) तथा हेजबोल्ला जैसे चरमपंथी संगठनों को समर्थन प्रदान कर रहा है. कुछ ऐसा ही परिदृश्य हमें मसूद अजहर मामले में देखने को मिला था.

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् 2022 में सीरिया सीमा पार प्रस्ताव को नवीनीकृत करने में विफल रही, जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन, आश्रय, पानी, सुरक्षा, महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं और अन्य जीवनरक्षक सहायता उत्तर पश्चिमी सीरिया में लाखों जरूरतमंदों तक पहुँचती रहे. ध्यातव्य रहे कि उत्तर पश्चिमी सीरिया के लोग 11 वर्ष के संघर्ष के दौरान सबसे गम्भीर एवं भयावह त्रासदी के साक्षी रहे हैं. यूक्रेन में चल रही शत्रुता, जलवायु परिवर्तन तथा इसके परिणामवरूप सूखा, आर्थिक संकट एवं युद्ध के कारण भोजन तथा ईंधन की कीमतों पर प्रभाव सीरियाई लोगों के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना रहा है.
- संयुक्त राष्ट्र एक बड़ी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है. सुरक्षा परिषद् की वर्तमान संरचना (15 सदस्य) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है. सुरक्षा परिषद् में केवल 5 स्थायी सदस्यों के कारण शक्तियों का संकेन्द्रण हो गया है. समकालीन उभरते जटिल मुद्दों के सन्दर्भ में सुरक्षा परिषद् के कम प्रभावी होने का प्रमुख कारण युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व की कमी है. एक उल्लेखनीय आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 54 देशों के महाद्वीप अफ्रीका की स्थायी सदस्यता के पैनल में कोई उपस्थिति नहीं है.
- इसके अतिरिक्त सुदूर पूर्वी एशिया, दक्षिण अमरीका जैसे क्षेत्रों का परिषद् की स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. वर्तमान वैश्विक मुद्दे जटिल और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधित्व की कमी के कारण वैश्विक राय का एक बड़ा हिस्सा सर्वोच्च सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखने से वंचित रह जा रहा है. भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण देश जो वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, फिर भी सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की सूची में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.
- वर्ष 1963 में सुरक्षा परिषद् के गैर स्थायी सदस्यों की संख्या में 4 सदस्यों को जोड़ने के सन्दर्भ में इसका केवल एक बार विस्तार किया गया था. हालाँकि संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता 113 से बढ़कर 193 हो गई है, लेकिन UNSC की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् से सम्बन्धित अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विवादित मुद्दा 5 स्थायी सदस्यो को प्राप्त वीटो विशेषाधिकार है. वीटो शक्ति की इसकी अलोकतांत्रिक प्रकृति के लिए आलोचना की जाती है. स्थायी सदस्यों ने इस शक्ति का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किया है. एक एकल वीटो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बहुमत के निर्णयों के क्रियान्वयन को रोक सकता है. उदाहरण के लिए, रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण की निंदा के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया तथा चीन की वीटो शक्ति के कारण ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है. कई विशेषज्ञों के साथ-साथ अधिकांश राष्ट्रों द्वारा इसे 'विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का स्व-चयनित क्लब' की संज्ञा दी जाती है.

समकालीन वैश्विक चुनौतियों के सन्दर्भ में सुरक्षा परिषद् को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के कई आलोचकों का तर्क यह है कि यह प्रभावी नहीं है और इसमें मौलिक सुधार की आवश्यकता है. भारत सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए दशकों से चल रहे प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, उसका कहना है कि 1945 में स्थापित संरचना 21वीं सदी की समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है और वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त है.
- वर्तमान वार्ता प्रक्रिया निर्णय 62/557 पर आधारित है जिसे 2008 में अपनाया गया था. यह सुधार के लिए 5 प्रमुख मुद्दों को परिभाषित करता है–
  1. सदस्यता की श्रेणियाँ,
  2. वीटो का प्रश्न,
  3. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व,
  4. विस्तारित सुरक्षा परिषद् का आकार और इसकी कार्य पद्धतियाँ, और
  5. सुरक्षा परिषद् और महासभा के बीच सम्बन्ध.
- निर्णय 62/557 यह भी निर्धारित करता है कि किसी भी समाधान को 'व्यापक सम्भव राजनीतिक स्वीकृति' प्राप्त होनी चाहिए, हालाँकि 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा पहले ही सहमत थी कि संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य देशों का समर्थन पर्याप्त है. फिर भी अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो भी P5 में से कोई भी अन्तिम प्रस्ताव को वीटो करने में सक्षम होगा.
- सुधारित बहुपक्षवाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करता है. भारत लम्बे समय से परिषद् में स्थायी सीट की माँग कर रहा है. इसके साथ-साथ यह अन्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधारों का भी समर्थक है–जैसे स्थायी (वर्तमान में पाँच) और गैर-स्थायी (वर्तमान में 10) सीटों की संख्या बढ़ाना और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना.
- भारत समेत अन्य राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनाये जाने की स्थिति में इन नए शामिल सदस्यों को युद्ध और शांति के मामलों में प्रभावी ढंग से अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा. इस सुधार के परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद् समावेशी तथा लोकतांत्रिक संस्था की ओर अग्रसर होगी, जहाँ भारत जैसे देश अपने साझेदार देशों के समर्थन से क्षेत्रीय, वैश्विक तथा तृतीय विश्व के देशों से सम्बन्धित मामलों/मुद्दों को अधिक मजबूती और जोरदार ढंग से रख सकते हैं.
- यदि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन जाता है तो यह विकासशील देशों के हित पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है, जो कि विश्व गतिशीलता में पश्चिम से एशिया की ओर ध्यान में स्पष्ट बदलाव के कारण वर्तमान माँग है. इसके अतिरिक्त वर्तमान में वीटो शक्ति क्षेत्रीय सन्दर्भ में स्थायी सदस्यों का एक अनूठा विशेषाधिकार है, चीन इस शक्ति का प्रयोग अपने हित में युद्ध और शांति के मामलों में कर सकता है. भारत को वीटो शक्ति मिलने से एशिया (विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया) में चीन की कुलीन स्थिति कमजोर हो जाएगी और भारत को अपने एवं पड़ोसी राष्ट्रों के हितों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी.
- सुरक्षा परिषद् में G-4 द्वारा प्रस्तावित सुधार इस बात पर बल देता है कि अफ्रीका महाद्वीप के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए अफ्रीका को यूएनएससी की स्थायी और गैर-

शेष पृष्ठ 110 पर

STUDYPDF WALLAH

प्रौद्योगिकी लेख

शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्भावित लाभ

—शिवम चतुर्वेदी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)—यह मशीन-आधारित प्रणाली, कम्प्यूटर विज्ञान की एक शाखा है और इसका सम्बन्ध कम्प्यूटर प्रोग्राम के रूप में बुद्धिमान एजेंटों के निर्माण और तैनाती के साथ-साथ इनके व्यवहार को समझने से है. एआई का मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य बुद्धिमान व्यवहार के बुनियादी सिद्धांतों को समझना है जो जानवरों और कृत्रिम प्रणालियों पर समान रूप से लागू होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति सटीक चिकित्सा, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण जैसे क्षेत्रों के लिए भी बहुत लाभ प्रदान कर रही है. एआई सिस्टम का विकास मानवीय हस्तक्षेप के अभाव में नहीं हो सकता है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सभी रूप, जिनमें स्व-चालित वाहन और रोबोटिक्स, साथ ही कम्प्यूटर दृष्टि और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी अधिक जटिल प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, मानव बुद्धि पर निर्भर हैं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीन प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है.

1. विश्लेषणात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता
2. मानव-प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और
3. मानवीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संक्षिप्त इतिहास एक नजर में

एआई (AI) को 1950 के दशक में एक अकादमिक अनुशासन के रूप में पेश किया गया था. 1970 और 1975 के बीच, एआई ने शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और इसने कुछ उपलब्धियाँ हासिल कीं. इससे इस विचार को बल मिला कि एआई विज्ञान की अन्य शाखाओं, जैसे मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा में भी विस्तार कर सकता है. यह 2000 के दशक तक अनुसंधान के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में रहा. 20वीं सदी के मध्य में यूनाइटेड किंगडम में शोधकर्ताओं ने कई वर्षों तक मशीन इंटेलिजेंस के निर्माण की खोज की और फिर 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की स्थापना की. इस क्षेत्र की शुरूआत एलन ट्यूरिंग और शोधकर्ताओं के एक समूह, रेशियो क्लब के सदस्यों द्वारा की गई थी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाम ह्यूमन इंटेलिजेंस

	मानव बुद्धि	कृत्रिम बुद्धि
1.	सोचने, तर्क करने, मूल्यांकन करने आदि की संज्ञानात्मक क्षमताएं मनुष्य में उनके स्वभाव से ही निर्मित होती हैं.	नॉर्बर्ट वीनर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास में महत्वपूर्ण प्रारम्भिक योगदान देने का श्रेय दिया जाता है.
2.	मानव बुद्धि का उद्देश्य नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए संज्ञानात्मक गतिविधियों की एक शृंखला को संयोजित करना है.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लक्ष्य ऐसे कम्प्यूटर बनाना है जो इंसानों की तरह व्यवहार करने में सक्षम हों और उन कार्यों को पूरा करने में सक्षम हों जो आमतौर पर इंसान करते हैं.
3.	मनुष्य स्मृति, प्रसंस्करण क्षमताओं और संज्ञानात्मक प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं जो उनका मस्तिष्क प्रदान करता है.	एआई-संचालित उपकरणों के संचालन के लिए डेटा और कमांड का प्रसंस्करण आवश्यक है.
4.	मानव बुद्धि विभिन्न अनुभवों और स्थितियों से सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है.	रोबोट सोचने या अतीत के अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं. वे केवल सामग्री के सम्पर्क और निरन्तर अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं.
5.	यह व्यक्तिपरक कारकों के लिए सम्भव है जो मनुष्यों द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने के लिए केवल संख्याओं पर आधारित नहीं हैं.	एआई निर्णय लेने में असाधारण रूप से उद्देश्यपूर्ण होता है.
6.	मानव मस्तिष्क अपने परिवेश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने में सक्षम है.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अनावश्यक परिवर्तनों के अनुकूल ढलने में बहुत अधिक समय लगता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा

एआई भविष्य में छात्रों के लिए संभावित लाभ ला सकता है, जिससे उनके सीखने, समझने और अकादमिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग इस प्रकार है—

- एआई सिस्टम प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को आसानी से अनुकूलित कर सकता है और उनकी ताकत और कमजोरियों के आधार पर निर्देश को लक्षित कर सकता है.
- एआई उत्तर कुंजी का उपयोग करके ग्रेड परीक्षाओं में मदद कर सकता है और निबन्ध जैसे अधिक अमूर्त मूल्यांकन को भी ग्रेड कर सकता है.
- एआई के साथ, छात्र सीखने के लिए आवश्यक गलतियाँ करने में सहज महसूस कर सकते हैं और सुधार के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं.
- शिक्षा केन्द्रों में एआई के लिए कल्पना की गई अधिकांश संभावनाएं शिक्षकों द्वारा कठिन कार्यों पर खर्च किए गए समय को कम करके अधिक सार्थक कार्यों के लिए समय खाली करना है.
- प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करना भी एआई के संभावित लाभों में से एक है, जो यू.एस. में शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में 2017-2021 तक 47·5% की वृद्धि का अनुमान लगाने वाले आँकड़ों का हवाला देते हैं.
- एआई शिक्षकों के लिए खतरा नहीं है और यह शिक्षकों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए है. वह एक भविष्य के हाइब्रिड मॉडल की कल्पना करते हैं जिसे हमारे कृत्रिम रूप

STUDYPDF WALLAH

से बुद्धिमान-सक्षम सिस्टम और हमारे शिक्षकों से सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अधिकांश तकनीकों की स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में तत्काल प्रासंगिकता हैं. स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तेजी से लागू किया जाएगा. भुगतानकर्ताओं और देखभाल प्रदाताओं तथा जीवन विज्ञान कम्पनियों द्वारा पहले से ही कई प्रकार के एआई का उपयोग किया जा रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)

भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) पर वैश्विक साझेदारी की अध्यक्षता सँभाली, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और मानव-केन्द्रित विकास और उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पहल है. यह भारत द्वारा इंडोनेशिया के बाली में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लीग जी20 की अध्यक्षता सँभालने के ठीक बाद आया है.

GPAI अमरीका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैण्ड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है. भारत 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ था. एआई के आसपास चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है. यह एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार पर आधारित एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए भागीदारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए सटीक माँग पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है. एआई एल्गोरिदम ग्राहक व्यवहार, बाजार के रुझान और यहाँ तक कि मौसम के पैटर्न जैसे बाहरी कारकों जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक और वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण कर सकता है.
- एआई इन्वेंट्री स्तर, उपभोग पैटर्न और लीड समय में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे व्यवसायों को कम संचालन प्राप्त करने और लागत कम करने में सक्षम बनाया जा सकता है.
- एआई-संचालित प्रौद्योगिकियाँ भंडारण परिदृश्य को बदल रही हैं. कम्प्यूटर विजन और मशीन लर्निंग क्षमताओं से लैस बुद्धिमान रोबोट गोदाम संचालन को बढ़ा सकते हैं, छँटाई, चयन और पैकिंग जैसे कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं. ये रोबोट मानव कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, दक्षता बढ़ा सकते हैं और त्रुटियाँ कम कर सकते हैं.
- उपकरण टूटने और रख-रखाव सम्बन्धी समस्याएं आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती हैं और महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती हैं. एआई पूर्वानुमा. नित रखरखाव रणनीतियों को लागू करके ऐसे जोखिमों को कम कर सकता है. वास्तविक समय सेंसर डेटा का विश्लेषण करके, एआई एल्गोरिदम पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, विसंगतियों का पता लगा सकते हैं और उपकरण विफलताओं की भविष्यवाणी उनके घटित होने से पहले ही कर सकते हैं.
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइस, आरएफआईडी टैग और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, एआई कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर अंतिम उत्पाद वितरण तक एण्ड-टू-एण्ड दृश्यता प्रदान कर सकता है.

भारत का एआई विजन

भारत में राष्ट्रीय एआई पोर्टल (INDIAai Portal) की शुरूआत वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में की गई थी. यह एक ही स्थान पर सभी हितधारकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रदान करने और देश में एआई पर जागरूकता और संचार को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है. 31 अक्टूबर, 2022 तक, इसने एआई से सम्बन्धित 1520 लेख, 799 समाचार, 262 वीडियो, 114 शोध रिपोर्ट और 120 सरकारी पहलें प्रकाशित की हैं.

भारत एआई स्तम्भ

1. शासन में एआई—सरकारी प्रक्रियाओं में एआई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को उजागर करना, बेहतर निर्णय लेने, दक्षता और पारदर्शिता को लक्षित करना.

2. एआई आईपी और इनोवेशन—प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए एआई, बौद्धिक सम्पदा और नवीन प्रथाओं के अंतर्संबन्ध को प्रदर्शित करना.

3. एआई कम्प्यूटर और सिस्टम—एआई की गणना और निष्पादन आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बुनियादी ढाँचे का अनुकूलन.

4. एआई में कौशल—व्यक्तियों को एआई ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और विभिन्न उद्योगों में एआई कौशल की माँग को पूरा करना.

5. एआई नैतिकता और शासन—निष्पक्षता, जवाबदेही और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए एआई सिस्टम के जिम्मेदार और पारदर्शी विकास और तैनाती का मार्गदर्शन करना.

6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)—प्रौद्योगिकी और नवाचार में मौजूदा निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक गतिशील प्रवर्तक है. भारत आधुनिक साइबर कानूनों और ढाँचे का एक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जो खुलेपन, सुरक्षा और विश्वास और जवाबदेही की तीन सीमा स्थितियों से संचालित होता है.

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिक्षा को नया आकार देने, अधिक व्यक्तिगत, सुलभ और प्रभावी बनाने की क्षमता है. अनुकूल शिक्षण पथों से लेकर आभासी वास्तविकता के अनुभवों और भविष्य कहने वाला विश्लेषण तक, एआई प्रौद्योगिकियाँ छात्रों के सीखने, बढ़ने और सफल होने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं. शिक्षा में एआई को अपनाकर, छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस कर सकते हैं जो तेजी से तकनीकी प्रगति पर निर्भर है. यह कुछ क्षेत्रों में मनुष्यों की जगह ले सकता है. एआई दोहराए जाने वाले, डेटा-संचालित कार्यों को सँभालने और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है. हालाँकि, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जटिल समस्या-समाधान जैसे मानव कौशल को अभी भी एआई द्वारा अधिक मूल्यवान और आसानी से दोहराए जाने की आवश्यकता है.

एआई को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखना आवश्यक है जो उत्पादकता बढ़ा सकता है और मानवीय भागीदारी के पूर्ण विकल्प के बजाय नई सम्भावनाओं को सुविधाजनक बना सकता है. ●●●

STUDYPDF WALLAH

सामयिक लेख

जलवायु वित्त की आवश्यकता

—डॉ. दीपक कोहली

जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए जलवायु वित्त (Climate Finance) महत्वपूर्ण है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के दुबई में आहूत 'कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज' (COP 28) में जलवायु वित्त का एक प्रमुख मुद्दा बनने की उम्मीद की जा रही है.

जलवायु वित्त—जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के अनुसार, जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण है, जो जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन कार्यों के समर्थन का ध्येय रखता है.

आवश्यक घटक

- **वित्त पोषण स्रोत**—जलवायु वित्त, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक स्रोत (जैसे—सरकारी वित्त पोषण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहायता) और निजी स्रोत (जैसे—वित्तीय और कॉर्पोरेट क्षेत्रों से प्राप्त निवेश) शामिल हैं.
- **वित्तीय साधन**—जलवायु वित्त को प्रसारित करने के लिए कई वित्तीय साधनों (Financial Instruments) का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें अनुदान, ऋण, इक्विटी निवेश और कार्बन क्रेडिट जैसे वित्तीय साधन शामिल हैं.
- **प्राप्तकर्ता**—सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न प्राप्तकर्ताओं (Recipients) को जलवायु वित्त प्रदान किया जा सकता है.
- **परियोजनाएं और गतिविधियाँ**—जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तन, शमन एवं अनुकूलन में योगदान करने वाली विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों का समर्थन कर सकता है. इनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ऊर्जा दक्षता उपाय और ऐसे परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति प्रत्यास्थता (Resilience) के निर्माण में मदद करती हैं.
- **शासन और निरीक्षण**—जलवायु वित्त के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और प्रभावी शासन एवं निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई पहल और तंत्र स्थापित किए गए हैं, जैसे कि हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) और स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism).

जलवायु वित्त के प्राथमिक उद्देश्य

- **शमन (Mitigation)**—ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने से सम्बद्ध परियोजनाओं एवं पहलों को वित्त पोषित करना. इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत् कृषि और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने वाली अन्य गतिविधियों में निवेश करना शामिल है.
- **अनुकूलन (Adaptation)**—उन उपायों का समर्थन करना जो समुदायों और राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल बनने में मदद करते हैं. इसमें आधारभूत संरचना, आपदा प्रत्यास्थता, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु सम्बन्धी जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने हेतु अन्य रणनीतियों में निवेश करना शामिल हो सकता है.
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer)**—विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर पर्यावरण के अनुकूल एवं संवहनीय प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, ताकि विकासशील देशों को निम्न-कार्बन, जलवायु-प्रत्यास्थी विकास मार्गों पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके.
- **क्षमता निर्माण (Capacity Building)**—जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने एवं सम्बोधित करने, जलवायु नीतियों एवं रणनीतियों को विकसित करने एवं लागू करने और जलवायु वित्त तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने एवं इसका प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रों एवं समुदायों की क्षमता का निर्माण करना.

जलवायु वित्त की आवश्यकता

अनुकूलन वित्त पोषण अंतराल (Adaptation Financing Gap)—वैश्विक अनुकूलन वित्त पोषण अंतराल बड़ा है और बढ़ता जा रहा है. विकासशील देशों में अनुकूलन लागत वर्ष 2030 तक लगभग 340 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष और वर्ष 2050 तक 565 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है.

शमन वित्त पोषण अंतराल (Mitigation Financing Gap)—शमन प्रयासों के लिए अंतराल और भी बड़ा है, जिसके वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 850 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है.

- **ट्रिलियन-डॉलर जलवायु वित्त की चुनौती**—'ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट जीरो' का अनुमान है कि शुद्ध शून्य—उत्सर्जन हासिल करने के लिए वर्ष 2050 तक कम-से-कम 125 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर, यानी प्रति वर्ष लगभग 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी.
- **विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त**—विकासशील देशों द्वारा, विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के देशों द्वारा, अपने NDCs जो वित्तीय आवश्यकताएं प्रकट की गई हैं, वे मात्रा में बड़ी हैं और वर्ष 2030 तक 6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच सकती हैं.
- **100 बिलियन अमरीकी डॉलर का वार्षिक लक्ष्य**—वर्ष 2009 में UNFCCC के COP15 में विकसित देशों ने संयुक्त रूप से जलवायु संकट को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने के लिए शमन एवं अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करने हेतु प्रति वर्ष कम-से-कम 100 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था.

जलवायु वित्त के प्रमुख स्रोत

साधनों के प्रकार (Types of Instruments)—

हरित बॉण्ड (Green bonds)—हरित बॉण्ड एक प्रकार का ऋण है, जो किसी सार्वजनिक या निजी संस्थान द्वारा पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करने हेतु जारी किया जाता है.

ऋण अदला-बदली (Debt swaps)—इसमें ऋणदाता देश (Creditor Country) द्वारा किसी निवेशक को विदेशी मुद्रा ऋण (Foreign Currency Debt) की बिक्री करना शामिल है, जो शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं के विकास के लिए ऋण-प्राप्तकर्ता देश (Debtor Country) के साथ ऋण की अदला-बदली कर सकता है.

- **गारंटी (Guarantees)**—ये ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं जिनके तहत् कोई

STUDYPDF WALLAH

गारंटर जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के सन्दर्भ में उधारकर्ता (Borrower) द्वारा उधारदाता (Lender) के प्रति किए गए दायित्वों को पूरा करने का वादा करता है.

- **रियायती ऋण (Concessional Loans)**—यह जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन गतिविधियों के लिए प्रदत्त ऋण हैं, जो पारम्परिक ऋणों से इस मामले में भिन्न होते हैं कि इनमें अन्य अधिमान्य शर्तों के साथ सुदीर्घ पुनर्भुगतान अवधि और निम्न ब्याज दरें शामिल होती हैं.
- **अनुदान और दान (Grants and donations)**—यह जलवायु आपात स्थितियों (Climate Emergency) के विरुद्ध संघर्ष से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए दी गई राशि है, जिसे वापस चुकाने की आवश्यकता नहीं होती.

प्रमुख जलवायु वित्त कोष

- **हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund–GCF)**—UNFCC द्वारा GCF का गठन वर्ष 2010 में किया गया था. यह विश्व का सबसे बड़ा जलवायु कोष है, जो विकासशील देशों को उनके GHG उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए समर्पित है, जहाँ सर्वाधिक संवेदनशील देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. GCF पेरिस समझौते के अनुपालन में महती भूमिका निभाता है जहाँ विकासशील देशों की ओर जलवायु वित्त का प्रसार करता है.
- **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (Special Climate Change Fund–SCCF)**—वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility–GEF) द्वारा प्रशासित SCCF चार अलग-अलग तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है—जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी एवं अपशिष्ट प्रबंधन; और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देशों के लिए आर्थिक विविधीकरण.
- **अल्पविकसित देश कोष (Least Developed Countries Fund–LDCF)**—वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा प्रशासित LDCF का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पविकसित देश के रूप में वर्गीकृत लगभग 50 देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी उच्च संवेदनशीलता से निपटने और उनकी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को लागू करने के लिए समर्थन प्रदान करना है.
- **UN-REDD कार्यक्रम**—इसे वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में गठित किया गया. इसका उद्देश्य विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करना है, जिससे सरकारों को राष्ट्रीय REDD+ रणनीतियों को तैयार करने और उन्हें लागू करने में मदद मिलती है.
- **द्विपक्षीय जलवायु वित्त कोष (Bilateral Climate Finance Funds)**—इसमें USAID (United States Agency for International Development), यूरोपीय संघ का GCCA+ (Global Climate Change Alliance+) और JICA (Japan International Cooperation Agency) जैसे संस्थान शामिल हैं.

जलवायु वित्त पोषण से सम्बद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **धन की कमी**—जलवायु वित्त पोषण में प्राथमिक चुनौती जलवायु परियोजनाओं के लिए धन की अपर्याप्त उपलब्धता है, विशेष रूप से निम्न-आय देशों में. विकसित देश 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके और वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में केवल 79·6 बिलियन अमरीकी डॉलर ही जुटा सके. 2022 में यह राशि 83 बिलियन डॉलर थी. संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार स्वच्छ तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीयन की धनराशि 2021 में 21·3 बिलियन डॉलर ही रही, जो 2020 में 25·2 बिलियन डॉलर थी. यूएनईपी के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु प्रभावों का सामना करने के लिए विकासशील देशों को वर्तमान दशक में प्रति वर्ष 215 बिलियन डॉलर से 387 बिलियन डॉलर तक के वित्त की आवश्यकता होगी.

संस्थागत क्षमता में कमी—कई निर्धन देशों में जलवायु परियोजनाओं में पर्याप्त विदेशी निवेश को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकने और आवंटित कर सकने के लिए आवश्यक वित्तीय अवसंरचना की कमी है, जिससे निवेशकों के अन्दर आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं और संवेदनशील अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हो सकती हैं. कुछ विशेषज्ञ विश्व की जलवायु वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में बहुपक्षीय विकास बैंकों (Multilateral Development Banks–MDBs) की क्षमता के बारे में, विशेष रूप से जलवायु सम्बन्धी मामलों में उनकी सीमित विशेषज्ञता के बारे में, चिंता जताते हैं. बहुपक्षीय विकास बैंकों की आलोचना मुख्य रूप से इस बात के लिए की जाती है कि वे अपना वित्त पोषण जलवायु शमन पर केन्द्रित करते हैं, जनकी व्यवसायों एवं समुदायों को जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूल होने में सहायता करने पर अधिक ध्यान नहीं देते.

जवाबदेह तंत्र—वर्तमान में सरकारों और संस्थानों को उनकी जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए कोई स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है. धनी देशों को या तो अपने निवेश अनुमानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहने के लिए जाना जाता है.

'ग्रीन फण्ड' जो निजी निवेशकों को पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (Environmental, Social, and Governance–ESG) निवेश में भागीदारी की अनुमति देते हैं, उनके निवेश के कार्बन फुटप्रिंट या उत्सर्जन के प्रकटीकरण को अनिवार्य नहीं बनाते हैं, जिससे 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) की समस्या पैदा होती है. ग्रीनवॉशिंग वह स्थिति है जब कोई संगठन वास्तव में अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की तुलना में स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल प्रचारित करने पर अधिक समय एवं धन खर्च करता है.

जलवायु वित्त का मापन—जलवायु वित्त प्रवाह पर डेटा का संग्रहण विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर किया जाता है और इसकी अलग-अलग व्याख्याएं होती हैं. जलवायु वित्त की दोहरी गिनती की स्थिति बन सकती है जब एक ही वित्त पोषण की रिपोर्टिंग कई पक्षों द्वारा की जाती है, जिससे वास्तविक वित्तीय प्रवाह का अनुमान अधिक हो जाता है.

तात्कालिकता की अनदेखी—वर्ष 2009-10 में वैश्विक वित्तीय संकट पर जिस तरह तीव्र प्रतिक्रिया दी गई, उसके विपरीत वर्तमान में जलवायु वित्त हस्तांतरण में वैसी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, अनुमानित तात्कालिकता और वैश्विक सहयोग का अभाव दिखाई देता है जैसा वित्तीय संकट प्रतिक्रिया में नजर आता है.

जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषण के लिए प्रमुख भारतीय पहलें

- **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund–NAF)**—इस कोष का गठन वर्ष 2014 में ₹ 100 करोड़ के आरम्भिक कोष के साथ आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतराल को दूर करने के उद्देश्य से किया गया

STUDYPDF WALLAH

था. यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF-CC) के अन्तर्गत क्रियान्वित है.

- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष (National Clean Energy and Environment Fund–NCEEF)**—NCEFF की स्थापना भारत में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. यह उन पहलों को वित्त पोषित करता है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं. कोष को कोयला उत्पादन और उपयोग पर उपकर अधिरोपित कर समर्थित किया गया है.
- **हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund–GCF) और अनुकूलन कोष (Adaptation Fund–AF)**—भारत GSF और AF जैसे अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु कोषों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की पात्रता रखता है. ये कोष देश में जलवायु शमन एवं अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करते हैं.
- **नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण**—भारत ने सौर और पवन ऊर्जा सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है. सरकार इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है.
- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (National Clean Energy Fund–NCEF)**—राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष को स्वच्छ ऊर्जा पहलों और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए गठित किया गया था. यह नवोन्वेषी परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है, जो निम्न-कार्बन विकास में योगदान करते हैं.
- **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emission Trading System–ETS)**—भारत कार्बन व्यापार को बढ़ावा देने और उत्सर्जन में कटौती को प्रोत्साहित करने के लिए ETS स्थापित करने की सम्भावना तलाश रहा है.
- **कार्बन कर (Carbon Tax)**—भारत में कार्बन कर लागू करने के बारे में चर्चा हुई है, जो जलवायु पहल के लिए अतिरिक्त राजस्व प्रदान कर सकता है.
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते**—भारत जलवायु वित्त के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में संलग्न है और जलवायु परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पाने हेतु बहुपक्षीय वार्ताओं में भागीदारी करता रहा है.

आगे की राह

- **जलवायु वित्त लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता**—सभी द्विपक्षीय दाताओं को अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए. जलवायु वित्त को राष्ट्रीय विकास योजनाओं और नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है.
- **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना**—राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. सभी देशों को पुनर्प्राप्ति/रिकवरी और रूपांतरण का समर्थन करने के लिए निम्न-कार्बन जलवायु प्रत्यास्थी अवसंरचना और अन्य जलवायु-सम्बन्धी निवेशों के अवसर तलाश करने की आवश्यकता है.
- **बहुपक्षीय विकास बैंकों में जवाबदेही लाना**—बहुपक्षीय विकास बैंकों को अपनी बैलेंस शीट का बेहतर लाभ उठाना चाहिए, अपने निजी क्षेत्र गुणकों (Private Sector Multipliers) में सुधार लाना चाहिए और एक प्रणाली के रूप में बेहतर ढंग से कार्य करना चाहिए. बहुपक्षीय विकास बैंकों को कॉप 25 में निर्धारित सामान्य ढाँचे पर आगे बढ़ते हुए पेरिस समझौते के साथ अपने वित्तीय समर्थन एवं गतिविधियों के संरेखण में तेजी लाने की आवश्यकता है.
- **कमजोर समुदायों का समर्थन करना**—ऋण संकट और अत्यधिक ऋण संकट से निपटना, विशेष रूप से निर्धन और जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों में, महत्वपूर्ण है. सबसे कमजोर या संवेदनशील समुदायों और देशों, विशेषकर जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का जोखिम रखते हैं, तक वित्त पोषण के प्रसार लिए लक्षित प्रयास किए जाने चाहिए.
- **नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र**—हरित बॉण्ड, कार्बन मूल्य निर्धारण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे नवीन वित्त पोषण तंत्र की खोज जलवायु परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन आकर्षित कर सकती है.

निजी पूँजी इतनी तेजी से प्रवाहित नहीं हो रही है कि निम्न-कार्बन और जलवायु-प्रत्यास्थी संक्रमण को वित्त पोषित कर सके और ये प्रायः पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप भी नहीं रही है. इसके अलावा, निजी क्षेत्र के जलवायु निवेश का अधिकांश मौजूदा स्टॉक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाता है.

- **पारदर्शिता और जवाबदेही**—जलवायु वित्त के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना और देशों को उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह बनाना महत्वपूर्ण है.
- **संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा देना**—संवहनीय अभ्यासों को प्रोत्साहित करना और हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण जलवायु वित्त के क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीति के अंग हैं.
- **ग्लोबल स्टॉकटेक**—जैसा कि पेरिस समझौते में उल्लिखित है, ग्लोबल स्टॉकटेक के माध्यम से जलवायु वित्त प्रयासों का लगातार आकलन करते रहना और उन्हें आगे बढ़ाना जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

निष्कर्ष

वैश्विक जलवायु वित्त के विषय में सहयोग को बढ़ावा देना न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तात्कालिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी अनिवार्य है. पर्याप्त वित्तीय आवश्यकताओं के साथ जलवायु सम्बन्धी मुद्दों की जटिलता विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, संगठनों और निजी क्षेत्रों के बीच एकजुट एवं सहयोगात्मक प्रयास की माँग रखती है. ●●●

STUDYPDF WALLAH

सागर-सम्पदा लेख

भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए सम्भावनाएं

—डॉ. दीपक कोहली

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. अब भारत अपनी तीव्र वृद्धि को जारी रखने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है. भारत की तटरेखा विश्व की सबसे विस्तृत तटीय रेखाओं में से एक है और यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है. ऐसे कई उद्योग हैं जिन्हें भारत अपने महासागरों के माध्यम से विकसित कर सकता है, जैसे—मछली पकड़ना, मुर्गी पालन, बंदरगाह और शिपिंग; ये उद्योग मिलकर नीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, और यह नीली अर्थव्यवस्था ही है, जो भारत के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी. हिन्द महासागर विशाल एवं विविध समुद्री जीवन का घर है, लेकिन प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्य ग्रहण और जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर दबाव भी बढ़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश, हिन्द महासागर की रक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक वित्त पोषण का अवसर पाने में मदद कर सकता है. 'ब्लू बॉण्ड' में हिन्द महासागर के सतत् विकास में उल्लेखनीय योगदान देने की क्षमता है. सेबी भारत में ब्लू बॉण्ड के लिए दिशा-निर्देश विकसित कर रहा है. नई नीतियों के क्रियान्वयन के बाद ब्लू बॉण्ड ऐसी कई परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकते हैं, जो भारतीय समुद्री पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाएंगे.

भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था का महत्व

खाद्य सुरक्षा और आजीविका—यह उन लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा, निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन में योगदान दे सकती है, जो अपनी आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं.

ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संवहनीयता—यह पवन, तरंग, ज्वार और समुद्री तापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सोतों की क्षमता का दोहन कर ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है. भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 5 गीगावाट अपतटीय पवन परियोजनाओं से प्राप्त होने की उम्मीद थी.

व्यापार और सम्पर्क—यह समुद्री सम्पर्क और अवसंरचना में सुधार कर अन्य देशों के साथ (विशेष रूप से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में) भारत के व्यापार एवं निवेश के अवसरों को बढ़ा सकती है. भारत ने अपने समुद्री व्यापार और सम्पर्क/कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना, अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North & South Transport Corridor) और चाबहार बंदरगाह के विकास जैसी कई पहलें शुरू की है.

पारिस्थितिक प्रत्यास्थता और जलवायु अनुकूलन—यह भारत को अपने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित एवं पुनर्स्थापित करने के माध्यम से पारिस्थितिक प्रत्यास्थता का निर्माण करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने में मदद कर सकती है. भारत अपने समुद्री पर्यावरण की संरक्षा के लिए जैविक विविधता पर कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity–CBD), सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea–UNCLOS) और पेरिस समझौता (Paris Agreement) जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों एवं समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित—यह भारत की समुद्री सीमाओं और परिसम्पत्तियों को बाहरी खतरों एवं चुनौतियों से सुरक्षित कर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को भी सुदृढ़ कर सकती है. भारत हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) में प्रबल नौसैनिक उपस्थिति रखता है और अपने समुद्री सहयोग एवं सुरक्षा को संवृद्ध करने के लिए हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) एवं मालाबार अभ्यास जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों और अभ्यासों में भागीदारी करता है.

खनिज संसाधन—पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) जो छोटे गोलाकार नोड्यूल्स होते हैं जिनमें निकिल, कोबाल्ट, लोहा एवं मैंगनीज मौजूद होता है और जो समुद्र तल पर लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं, प्रायः जल की गहराई में 4-5 किमी की दूरी पर पाए जाते हैं. वर्ष 1987 में भारत को मध्य हिन्द महासागर बेसिन (CIOB) में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का विशेष अधिकार प्रदान किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, तब से भारत ने 4 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र का अन्वेषण किया है और दो खदान स्थल स्थापित किए हैं. भारत द्वारा वर्ष 2019 में शुरू 'डीप ओशन मिशन' के प्रमुख उद्देश्यों में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स का अन्वेषण और बाहर निकालना भी है.

सम्भावनाएं

भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र में समुद्री संसाधनों, समुद्री अवसंरचना और तटीय क्षेत्रों को शामिल करती है. भारत में नौ तटीय राज्यों, चार केन्द्र-शासित प्रदेश और 1,382 द्वीपों के साथ 7,516·6 किमी लम्बी समुद्री तटरेखा मौजूद है. भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लगभग 2·37 मिलियन वर्ग किमी में विस्तृत है, जहाँ तेल और गैस जैसे मूल्यवान संसाधन मौजूद हैं. तटीय अर्थव्यवस्था 4 मिलियन मछुआरों और तटीय समुदायों का सम्पोषण करती है. भारत 2,50,000 मत्स्यग्रहण नौकाओं के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है. जलीय कृषि (Aquaculture) में भारत दूसरे स्थान पर है. भारत के 9 राज्य तट रेखा तक पहुँच रखते हैं और देश में 205 छोटे एवं मझोले तथा 13 बड़े बन्दरगाह [12 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा एक निजी क्षेत्र में] **पूर्वी तट पर**—(i) कोलकाता—हल्दिया सहित (श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन्दरगाह), (ii) पारादीप, (iii) विशाखापत्तनम, (iv) चेन्नै, (v) एन्नोर (कामराजार), (vi) तूतीकोरिन (वी.ओ. चिदम्बरानार बन्दरगाह), **पश्चिमी तट पर**—(vii) कोच्चि, (viii) मंगलोर, (ix) मारमुगावो, (x) न्हावा-शेवा (जवाहरलाल नेहरू बन्दगाह), (xi) मुम्बई, (xii) काण्डला (दीनदयाल बन्दरगाह)]. **निजी**—अडानी पोर्ट एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं. इन बंदरगाहों में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2023 में 795 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया और वर्ष 2022-23 में 137·80 मिलियन टन कार्गो सँभालकर जहाँ काण्डला बन्दरगाह देश में पहले स्थान पर रहा, वहीं 135·36 मिलियन टन कार्गो सँभालकर पारादीप दूसरे स्थान पर रहा. 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' के अनुसार, हिन्द महासागर दुनिया के महासागरीय प्रभागों में तीसरा सबसे बड़ा प्रभाग है. यह 70 मिलियन वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और अपने प्रचुर तेल एवं खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है.

प्रमुख चुनौतियाँ

अवसंरचना की कमी—भारत को सम्पर्क/कनेक्टिविटी एवं दक्षता में सुधार के लिए अपने

STUDYPDF WALLAH

भारत के बड़े बन्दरगाहों की विशिष्टताएं

क्र. सं.	बन्दरगाह का नाम	बन्दरगाह का नया नाम	बन्दरगाह की विशिष्टता
	पूर्वी तट के बन्दरगाह		
1.	कोलकाता (हल्दिया सहित)	श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन्दरगाह	नदी बन्दरगाह (Riverine Port)
2.	पारादीप		प्राकृतिक बन्दरगाह
3.	विशाखापत्तनम		प्राकृतिक बन्दरगाह एवं देश का सबसे गहरा बन्दरगाह
4.	चेन्नै		देश का तीसरा सबसे बड़ा बन्दरगाह; देश का सबसे पुराना कृत्रिम बन्दरगाह
5.	एन्नोर	कामराजार बन्दरगाह	पहला कॉर्पोरेट बन्दरगाह
6.	तूतीकोरिन	वी.ओ. चिदम्बरानार बन्दरगाह	सभी मौसमों के लिए उपयुक्त बन्दरगाह
	पश्चिमी तट के बन्दरगाह		
7.	कोचीन	कोच्चि बन्दरगाह	अरब सागर की रानी प्राकृतिक बन्दरगाह
8.	मंगलौर		
9.	मारमुगावो		
10.	न्हावाशेवा	जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह	मानव निर्मित सबसे बड़ा बन्दरगाह. देश का सबसे बड़ा कन्टेनर बन्दरगाह
11.	मुम्बई		देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक एवं व्यस्त बन्दरगाह
12.	काण्डला	दीनदयाल बन्दरगाह	ज्वारीय बन्दरगाह
	निजी क्षेत्र का बन्दरगाह		
13.	मुन्द्रा	अडानी पोर्ट एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्दरगाह	निजी क्षेत्र का बन्दरगाह

तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे और अन्य अवसंरचना में वृहत निवेश करने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (EAC-PM) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बंदरगाह क्षमता महज 1·5 बिलियन टन प्रति वर्ष है, जबकि इसका बंदरगाह यातायात वर्ष 2025 तक 2·5 बिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है.

समुद्री प्रदूषण—भारत का तटीय जल औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कृषि अपवाह, प्लास्टिक कचरा और तेल रिसाव जैसे विभिन्न स्रोतों से प्रदूषित है. समुद्री प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के स्वास्थ्य के साथ-साथ मछली और समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, 60 प्रमुख भारतीय शहरों से उत्पन्न 15,000 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट (जिनमें एक बड़ा भाग प्लास्टिक का होता है) प्रति दिन दक्षिण एशियाई समुद्र में निपटान किया जाता है.

संसाधनों का अति-दोहन—भारत के समुद्री संसाधन अत्यधिक मत्स्यग्रहण (Overfishing), अवैध मत्स्यग्रहण और अनियमित जलीय कृषि (Aquaculture) के दबाव में हैं. अत्यधिक मत्स्यग्रहण से मत्स्य भण्डार में कमी आ सकती है, मछुआरों की आय एवं आजीविका में कमी आ सकती है और लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुँच सकता है. अवैध मत्स्य ग्रहण भारत के समुद्री क्षेत्र की सम्प्रभुता एवं सुरक्षा को भी कमजोर कर सकता है.

जलवायु परिवर्तन—जलवायु परिवर्तन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, तूफान, बाढ़, लवणीकरण, प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching), महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) और समुद्री धाराओं एवं तापमान में परिवर्तन जैसे परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं. जलवायु परिवर्तन समुद्री प्रजातियों के वितरण एवं प्रचुरता के साथ-साथ उनके प्रवासन पैटर्न और प्रजनन चक्र को भी प्रभावित कर सकता है. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 20वीं सदी के दौरान वैश्विक औसत समुद्र स्तर में लगभग 15 सेमी की वृद्धि हुई है और वर्ष 2100 तक इसमें 26 से 82 सेमी तक वृद्धि हो सकती है.

समुद्री अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपाय

एक राष्ट्रीय लेखा ढाँचा विकसित करना—यह सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, व्यापार और अन्य संकेतकों में समुद्री अर्थव्यवस्था के योगदान की माप करेगा. इससे समुद्री अर्थव्यवस्था के महत्व एवं प्रभाव का आकलन करने और उचित नीतियों एवं हस्तक्षेपों को अभिकल्पित करने में मदद मिलेगी. तटीय और समुद्री स्थानिक नियोजन: एक ऐसे तटीय और समुद्री स्थानिक नियोजन (Coastal and Marine Spatial Planning) का क्रियान्वयन करना जो समन्वित तरीके से विभिन्न गतिविधियों और क्षेत्रों के लिए स्थान एवं संसाधन आवंटित करे. इससे संघर्षों से बचने, संसाधन उपयोग को इष्टतम करने और पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. महासागर शासन के लिए कानूनी और संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करना: यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा. इससे भारत की सम्प्रभुता एवं सुरक्षा की रक्षा करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी.

समुद्री अनुसंधान और नवाचार के लिए क्षमता और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना—यह साक्ष्य-आधारित निर्णयन में सहायता करेगा और विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देगा. इससे अपतटीय ऊर्जा, गहन समुद्र खनन, जैव प्रौद्योगिकी और जलीय कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों की क्षमता का पता लगाने में मदद मिलेगी.

सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना—हिन्द महासागर क्षेत्र में समान हितों एवं चुनौतियों को साझा करने वाले अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना. इससे आपसी विश्वास को बढ़ाने, सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने, तालमेल का लाभ उठाने और साझा खतरों से निपटने में मदद मिलेगी.

ब्लू बॉण्ड—ब्लू बॉण्ड भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहल, अपतटीय पवन फार्म, समुद्री संरक्षण प्रयास और प्रदूषण की रोकथाम एवं सफाई जैसे संवहनीय महासागरीय परियोजनाओं के लिए धन प्रदान कर सकते हैं. ये परियोजनाएं रोजगार सृजित कर सकती

STUDYPDF WALLAH

हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकती हैं.

ब्लू बॉण्ड क्या हैं?

ब्लू बॉण्ड (Blue Bonds) एक प्रकार के सतत् बॉण्ड (Sustainable Bonds) हैं, जो विशेष रूप से उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो महासागर और उसके संसाधनों की रक्षा और पुनर्स्थापन करते हैं. ब्लू बॉण्ड ग्रीन बॉण्ड (Green Bonds) और सोशल बॉण्ड (Social Bonds) जैसे अन्य सतत् बॉण्ड जैसे ही हैं. हालाँकि, वे विशेष रूप से महासागर संरक्षण और सतत् विकास पर केन्द्रित हैं.

इन्हें सरकारों, विकास बैंकों या अन्य संगठनों द्वारा जारी किया जा सकता है और व्यक्तिगत निवेशकों, संस्थागत निवेशकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इनकी खरीद की जा सकती है.

ब्लू बॉण्ड भारत के लिए सहायक

सतत् परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण—ब्लू बॉण्ड भारत में सतत् समुद्री परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त पोषण प्रदान कर सकते हैं. इसमें स्वच्छ ऊर्जा पहल, अपतटीय पवन फार्म, तरंग ऊर्जा कनवर्टर (Wave Energy Converters), समुद्री संरक्षित क्षेत्र और संवहनीय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि शामिल हैं.

ये परियोजनाएं रोजगार पैदा कर सकती हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकती हैं.

समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समर्थन—भारत सक्रिय रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है और इसकी तटरेखा अपतटीय पवन एवं तरंग ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है. ब्लू बॉण्ड इन परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकते हैं, जिससे भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन का शमन करने में मदद मिलेगी.

समुद्री संरक्षण—ब्लू बॉण्ड को समुद्री संरक्षण प्रयासों और प्रवाल भित्तियों, समुद्री वन्यजीवों एवं समग्र पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निर्देशित किया जा सकता है. ये परियोजनाएं जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यटन को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है.

प्रदूषण की रोकथाम और सफाई—ब्लू बॉण्ड समुद्री प्रदूषण से निपटने और समुद्र तट की सफाई से सम्बन्धित पहल को वित्त पोषित कर सकते हैं. यह भारत के महासागरों और समुद्र तटों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो पर्यटन और मात्स्यिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं.

जागरूकता और शिक्षा—ब्लू बॉण्ड समुद्र संरक्षण और संवहनीय अभ्यासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं. इससे आबादी के बीच अधिक उत्तरदायी व्यवहार और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है. ●●●

शेष पृष्ठ 102 का

स्थायी दोनों श्रेणियों में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है. इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित सुधार में सुरक्षा परिषद् को अधिक वैध, प्रभावी और प्रतिनिधि बनाने के लिए, स्थायी (5 से 11) और गैर-स्थायी (10 से 14) सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है.

- G-4 द्वारा प्रस्तावित सुधार स्थायी सीटों के चुनाव की प्रक्रिया भी प्रस्तावित करता है जिसके अनुसार दो सदस्य अफ्रीकी राष्ट्रों से; एशियाई राष्ट्रों से दो सदस्य; एक सदस्य लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई राष्ट्रों से; एक सदस्य पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राष्ट्रों से चुने जाएंगे. इसके साथ-साथ गैर-स्थायी सदस्यों को निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार चुना जाएगा: एक अफ्रीकी राष्ट्र से; एक एशियाई राष्ट्र से; पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों से एक; एक लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई राज्य से.
- **रजाली सुधार योजना**—योजना के तहत्, सुरक्षा परिषद् में वीटो शक्ति के बिना पाँच नए स्थायी सदस्य होंगे, इसके अलावा 4 अन्य गैर-स्थायी सदस्य होंगे, जिससे परिषद् की ताकत 24 हो जाएगी.
- पूर्व में प्रस्तावित सुधारों का सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों (पी5) ने विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने नए सदस्यों के लिए भी वीटो शक्ति की माँग की थी (रजाली योजना). हालाँकि, बाद में नए देशों ने वीटो शक्ति को त्यागने का निर्णय लिया जिसे P5 देशों (रजाली सुधार योजना) ने स्वीकार कर लिया.
- इसके अतिरिक्त समकालीन परिस्थितियाँ एवं व्याप्त चुनौतियाँ संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सुधार की माँग करती है, जो केवल अधिकारों की बात करता है, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की नहीं. व्यक्तिगत, सामुदायिक, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर भी बल देने की आवश्यकता है.
- संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षवाद के साथ दृढ़ता से जुड़ने की आवश्यकता है. इसके अतिरिक्त केवल पी5 ही नहीं, बल्कि उन सभी की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए जो मायने रखते हैं. इसके साथ-साथ पी5 देशों की निरंकुशता के बजाय बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है.

निसंदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली संस्था है, जिसने अपनी स्थापना के 75 वर्षों में अपने अनेक कार्यों के माध्यम से, {यथा—विभिन्न अशांत क्षेत्रों में शांति मिशनों के माध्यम से शांति एवं संवैधानिक सरकार की बहाली, आक्रामक राष्ट्रों पर प्रतिबंधों के माध्यम से नियंत्रण, विभिन्न आतंकवादी संगठनों तथा उनके प्रमुखों पर प्रतिबंधों (यात्रा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति की जब्ती इत्यादि) के माध्यम से उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना इत्यादि} अपनी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को सिद्ध किया है, परन्तु अब समय आ गया है जब उपर्युक्त सुझाए गए सुधारों को क्रियान्वित कर इस संस्था को परिवर्तित समय एवं चुनौतियों के सन्दर्भ में समावेशी एवं अधिक प्रतिनिधित्व आधारित एवं लोकतांत्रिक संस्था में परिणत किया जा सके. ●●●

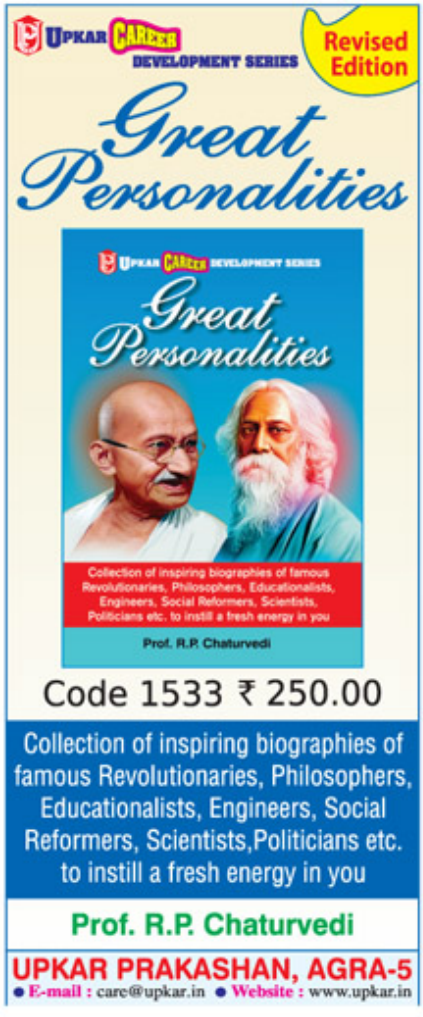

STUDYPDF WALLAH

उद्योग जगत् लेख

कॉर्पोरेट जगत् में ऊँचे पदों पर महिलाएं कम क्यों हैं

—मीनी सिंह

आज महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी की बात होती है. कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कंधे-से-कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है ? शायद नहीं, क्योंकि समानता और विविधता के बारे में तमाम बहसों के बावजूद, कॉपोरेट जगत में देश की आधी आबादी, यानि कि महिलाओं की भागीदारी आज भी कम है. हालाँकि, बिजनेस वर्ल्ड के ऊँचे पदों पर महिलाओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ अब भी पुरुषों का दबदबा ज्यादा है.

- एक सर्वे के मुताबिक, देश में महिलाएं 20% से भी कम टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं.
- कम्पनियों के बोर्ड्स में भी सिर्फ 17·1% ही महिलाएं हैं. वे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कानूनन जरूरी है कि लिस्टेड कम्पनियों के बोर्ड में कम-से-कम एक महिला तो होना ही चाहिए.
- साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ यानि STEM में सिर्फ 3% महिलाएं ही CEO पद पर हैं.
- स्टार्टअप्स में 20% से भी कम लीडरशिप पोजिशन पर महिलाएं बैठी हैं.

महिलाएं कितनी भी पढ़-लिख क्यों न जाएं, लेकिन उनके काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता. किसी संगठन में जब प्रमोशन या लीडरशिप की बात आती है, तो कम्पनियाँ आज भी पुरुषों को ही ज्यादा तरजीह देती हैं. सच तो यही है कि महिलाएं अगर ऊँचे उड़ान भरने की कोशिश करे भी तो उनके पंख कतर दिए जाते हैं. अपनी अलग पहचान बनाने से उन्हें रोक दिया जाता है.

Women of Influence नाम की कनाडा की एक कम्पनी ने 103 देशों की महिला लीडर्स का इंटरव्यू लिया और सर्वे में पाया गया कि जो महिलाएं सफल हैं उन्हें परेशान किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, उनकी कामयाबी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उनकी आलोचना होती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है. महिलाओं को यह एहसास कराया जाता है कि अपनी पहचान बनाना, इतना रुतबा रखना उनका हक नहीं है.

कार्पोरेट जगत् में महिलाओं और पुरुषों के बीच अब भी बड़ा फासला है. कम्पनी में ऊँचे लेवल पर भी महिलाओं से भेदभाव किया जाता है, उन्हें पुरुषों से कमजोर समझा जाता है. ज्यादातर लोग ऊँचे पद सँभाल रही महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि वो इतनी मजबूत नहीं कि सब सँभाल लेगी और लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि वो महिलाएं हैं.

'द टोलेस्ट पोपी स्टडी' के मुताबिक, 77% महिलाओं को अपनी उपलब्धि को कम आंक कर सामने रखना पड़ा.

- 72·4% को नजरंदाज किया गया या उन्हें शेष से अलग कर दिया गया.
- 70·7% ने शिकायत की कि उनकी काबलियत को कम आँका गया.
- 68·3% की कामयाबियों को सिरे से नकार दिया गया.
- 66·1% ने कहा कि उनके काम का श्रेय किसी और ने ले लिया.

सिर्फ कॉपोरेट जगत में ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी महिला नेताओं को ऊँची कुर्सियाँ नसीब नहीं होती. देश की आधी आबादी के हक की हकीकत कड़वी है. एक इंटरव्यू में स्व, शीला दीक्षित ने स्वीकार किया था कि महिला कार्यकर्ता से वरिष्ठ पद तक पहुँचने की राहें बहुत कठिन होती है. उनके लिए यह स्थिति आसान थी, लेकिन सब के साथ ऐसा नहीं होता. कांग्रेस नेता, अलका लांबा और भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने भी यह स्वीकारा था कि महिला नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछाल कर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है. उन्हें आगे बढ़ने के लिए कदम-कदम पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है. पार्टी में कोई भी हो, महिला नेताओं का रास्ता हमेशा काटों भरा रहा है.

जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती और शीला दीक्षित जैसे कुछ नाम को छोड़ दें, तो उच्च पदों पर महिला नेताओं को कम ही देखा गया है. मार्गरेट अल्वा, रेणुका चौधरी, गिरिजा व्यास, उमा भारती वे नाम हैं, जो नब्बे की दशक में कद्दावर महिला नेताओं के रूप में देखी जाती थीं, लेकिन जनता के बीच होते हुए भी ये नाम आज गुमनाम से क्यों हैं ? उनके बारे में जानने के लिए आज की पीढ़ी को गूगल का सहारा क्यों लेना पड़ता है ? कुछ चुनिंदा महिला नेता शीर्ष पर पहुँची तो सही, लेकिन राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकी. आलम यह है कि इन्दिरा गांधी के बाद देश में दूसरी कोई महिला प्रधानमंत्री बन ही नहीं पायी.

सुषमा स्वराज भाजपा के आक्रमक और दक्ष राजनेताओं में रहीं, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि उनकी प्रतिभा के साथ भी न्याय नहीं हो सका. ममता बनर्जी ने कांग्रेस में रहने के दौरान शायद यह भांप लिया था कि यहाँ रहने के दौरान उनके हाथ बहुत कुछ लगने वाला नहीं, शायद यही वजह था कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन कर अपनी योग्यता साबित की. इन्दिरा जी की तरह कई और महिला नेता प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज कई बार इसमें बाधा बन जाता है. समाज ही नहीं, घरों में बेटों का वर्चस्व देखा गया है. ऐसी सोच को कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासी व दलित महिलाएं वहीं की वहीं खड़ी हैं. आरक्षण से भी उनका कुछ खास भला नहीं हो पाया.

बात बराबरी की, पर दिखाई नहीं देती

उत्तर प्रदेश के बलिया के एक शख्स, हाथी सिंह, उम्र की ढलान पर इसलिए ब्याह रचाया ताकि अपनी बीवी को महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर खड़ा कर सके. अगर पत्नी जीतती है, तो पद और ताकत का असल सुख तो पति को ही मिलेगा. महिलाएं पंच-सरपंच बनती तो है, लेकिन काम उनके पति, भाई या पिता ही सँभालाते हैं. हर गाँव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर महिलाएं खड़ी तो होती हैं, लेकिन चुनाव वे नहीं, बल्कि उनके पति लड़ते हैं. वही चुनाव प्रचार भी करते हैं और हाथ जोड़कर लोगों से वोट भी माँगते हैं. पति को इस बात पर गर्व ही नहीं होता कि जनता ने वोट देकर उनकी पत्नी का सम्मान किया. उसे आगे बढ़ने का, लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर दिया है. पति को लगता है वह नासमझ कमाई कैसे कर पाएगी ? खुद पद जीत चुकी औरतें भी यही मानती हैं कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है और न ही उन्हें गाँव की जरूरतों का अंदाजा है. ऐसे में अगर पति उनकी जिम्मेदारी बाँट रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है. पति, अपनी पत्नी का पैर काट रहा है. ताकि वह कुछ सीख न सके और न ही आगे बढ़ सके, लेकिन पत्नी को लगता है उसका पति उसे सपोर्ट कर रहा है.

वर्ष 2005 की शुरूआत में ऐसे ही पतियों के लिए एक टर्म निकाला—'सरपंच पति' ये वो पति होते हैं, जो खुद को पत्नी के पद का असली मालिक होते हैं और पत्नी अपने पति के लिए खाना पकाती है, पानी भर कर लाती है.

अब जनता को खुद आगे आना होगा, क्योंकि ये उनके वोट का अपमान है जिसे वोट दिया वह कार्य न करे और उसके अधिकार कोई अहंकारी ले उड़े, जिसे चुना ही नहीं गया.

STUDYPDF WALLAH

पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर भी पॉलिटिक्स की शिकार महिलाएं

स्कॉटलैण्ड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इसी वर्ष फरवरी में इस्तीफा दिया. इनसे पहले न्यूजीलैण्ड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने 25 जनवरी को अपना पद छोड़ दिया था. दोनों मंत्रियों के पीछे हटने की वजह थी पुरुषों से सियासी चुनौती. एक शोध के अनुसार, महिलाओं को वर्कप्लेस पर मेल को-वर्कर की तुलना में ज्यादा दुश्मनी का सामना करना पड़ता है.

बॉलीवुड भी अछूता नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बेबाकी से कहा था की मुझे बॉलीवुड में कभी भी मेल एक्टर के बराबर फीस नहीं मिली. गैप आज भी बना हुआ है. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोट ने भी कहा कि फिल्म में सफलता की गारंटी कोई नहीं ले सकता तो पैसों के मामले में एक्टर-एक्ट्रेस के बीच इतना भेदभाव क्यों ? मैं मेल एक्टर्स से जायदा पैसे डीजर्व करती हूँ. सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फीमेल एक्टर्स को मेल एक्टर से कम पैसे मिलते हैं.

अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तो एक जैसे काम के लिए महिलाओं को कम सैलरी देने का देश और समाज का नुकसान मानते हैं.

भारत में IT सेक्टर में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव

IT सेक्टर में पुरुषों को महिलाओं से 26% ज्यादा वेतन मिलता है, वहीं मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में पुरुषों को महिलाओं से 24% ज्यादा सैलरी मिलती है. मजदूरी का 82% हिस्सा पुरुषों के खाते में जाता है, महिलाओं के हिस्से केवल 18% रकम मजदूरी आती है. यूरोप से लेकर अमरीका तक महिलाओं के साथ भेदभाव होता आया है. भारतीय महिलाओं को बराबर सैलरी न मिल पाने की कई दूसरी वजहें भी हैं, एक तो भारत में महिला आन्दोलन ने कभी इतना जोर नहीं पकड़ा. और महिलाओं की सैलरी कम होने के पीछे सोसायटी भी अहम् रोल अदा करती रही है. साथ ही जाति और जेंडर का भी इसमें योगदान रहा है.

एकजुट होकर न लड़ पाने के कारण, पावर गेम में महिलाएं खा रही हैं मात

पुरुष आसानी से यूनियन बनाकर अपनी माँगों के लिए लड़ते हैं. वे दूसरी कम्पनियों और आसपास हो रहे बदलावों की जानकारी रखते हैं, जबकि महिलाएं यहाँ पिछड़ जाती हैं. वे संगठित होकर अपनी माँग नहीं रख पाती हैं और न ही उनकी परिस्थिति उनका साथ देती है. जेंडर पे गैप की एक बड़ी वजह पावर गेम भी है. दुनिया भर में पुरुष महिलाओं के हाथ में ताकत नहीं आने देना चाहते हैं. भारत में यह पावर गेम बहुत भद्दी शक्ल ले लेता है. पुरुषों की कुंठा साफ नजर आती है जब वे पीरियड लीव और चाइल्ड केयर लीव को लेकर बहस करते हैं.

महिलाओं को कम्पनियों, फैक्ट्रियों में सेक्सुअल हैरासमेंट से बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है जिसका तोड़ निकाला गया है कि महिलाओं को नौकरी पर रखो ही मत. कोई महिला कर्मचारी शिकायत करेगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, मामला सोशल मीडिया में आ जाएगा. इस कारण सीनियर लेवल पर बैठे पुरुष महिलाओं को नौकरी देने से बचने लगे हैं. अगर कोई फीमेल केडीडेट दलित हो, तो उसके पीछे रह जाने की आशंका और बढ़ जाती है. उसकी रक्षा के लिए बने कानूनों का उल्टा असर भी होता है.

पुरुषों को नहीं पसंद फीमेल बॉस

कम्पनियों में जब डीसीजन मेकिंग का चार्ट तैयार किया जाता है, तो जान-बूझकर महिलाओं की संख्या वहाँ कम रखी जाती है. निर्णायक मंडल बनने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं ऊपर वे अपनी बराबरी में किसी महिला को देखना पसंद नहीं करते.

अगर महिलाएं टॉप पोजीशन पर पहुँच भी जाएं, फिर भी उन्हें पुरुषों से कम सैलरी मिलती है, भले हो दोनों बराबर काबिल हों. ऐसी स्थिति में महिलाएं विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वे मुश्किलें झेलते हुए इतनी महिलाओं के बीच में अकेले टॉप पर पहुँची होती है और यही उनके लिए अभूतपूर्व हो जाता है.

महिलाएं, पुरुषों के बराबर मेहनत करती है, फिर उनके कामों को अनदेखा क्यों कर दिया जाता है ? क्यों उनके साथ पुरुष लीडर्स के समान व्यवहार नहीं किया जाता ? अगर कोई पुरुष कोई काम को अपने हाथ में लेता है, तो उसे मजबूत, निर्णायक और ठोस कदम लेने वाला समझा जाता है, लेकिन वहीं अगर एक महिला कोई काम हाथ लेती है और वो कठोर बनती है, तो उसे अहंकारी समझा जाता है. उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बोलती है, सोचती बहुत है, उसमें काम की समझ नहीं है, महिलाओं वाले गुण नहीं उसमें, वो किसी की भावनाओं को नहीं समझती है और किसी से सहानुभूति नहीं रखती है.

भारतीय समाज में औरतों की स्थिति को अन्तिम चरण में रखा गया है. संसार के सारे बड़े फैसले आज भी पितृसत्ता के अधीन है. भले ही हम यह कह कर अपनी पीठ थपथपा लें कि महिला पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चल रही है. वह चाँद पर पहुँच गई है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, ओलम्पिक में देश के लिए मेडल जीत रही है, कोर्पोरेट जगत् में नाम कर रही है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें, तो यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है. हमारे समाज का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक और धार्मिक बंधनों के बेड़ियों को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है. आज भी वह यह सोच नहीं पा रही है कि हमारा पितृ-सत्तात्मक समाज हमें जन्म से ही एक ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बचाए रखने के लिए पुरुषों का सहारा चाहते हैं. जब-जब कोई स्त्री अपनी उपलब्धि दर्ज कराने लगती है उसे परिवार और रीति-रिवाज में उलझा दिया जाता है, ताकि वह आगे बढ़ ही न पाए. अपनी पहचान बनाने के लिए औरतें, पुरुषों से भले ही दोगुनी मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन फिर भी उसे वह सब नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए.

भारत जैसे पितृ सत्तात्मक देश में शिक्षा, मीडिया, कानूनी संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं सभी पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक है. यहाँ तक की धर्म भी पितृ सत्तामक है, क्योंकि इन धर्मों में पितृसत्ता को सर्वोच्च रूप से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए महिलाओं को हमेशा से धर्म के नाम पर नवीनीकरण का प्रयास किया जाता है और महिलाओं को बिना अधिकार की माँग के अपने पति, स्वामी का दर्जा दिया जाता है. उन्होंने इस बात पर जरा भी विचार नहीं किया कि अगर घर में पति मालिक है, तो पत्नी का क्या स्थान है ?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज के समय में महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर बाहर भी अपने परचम का झण्डा लहरा रही हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी आदि, लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार देखें, तो राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है. कोर्ट में भी महिलाओं की संख्या दर्ज नहीं है. पुरुषों के समान काबिल होने के बावजूद, कॉर्पोरेट जगत में महिलाएं ऊँचे पदों से दूर हैं. ऐसा भी नहीं है कि समय के साथ बदलाव नहीं आ रहा है या हमारी सोच महिलाओं को लेकर बेहतर नहीं हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि महिलाएं अभी भी मंजिल से कोसों दूर हैं. आज भी महिलाओं को भेदभाव से गुजरना पड़ता है, उसे समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है. हालाँकि, हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ का समाज अपने पूर्वजों के अनुसार, महिलाओं को संचालित करता है.

महिलाएं सदियों से पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए लम्बी लड़ाई लड़ रही हैं. शहरी महिलाओं को तो कुछ हद तक जीत मिली है, परन्तु ग्रामीण औरतें आज भी गुलामी

शेष पृष्ठ 165 पर

STUDYPDF WALLAH

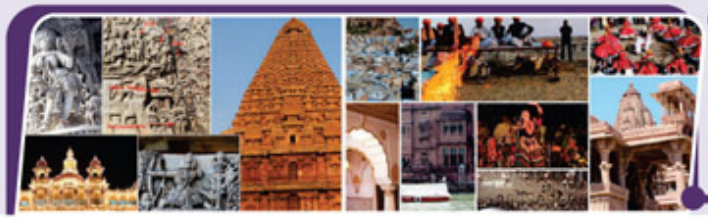

सार संग्रह

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति

1. कौनसी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी ?
– *तृतीय संगीति*
2. 'ब्लेड-ब्यूरिन' प्रकार के उपकरण किस काल की परम्परा के परिचायक लक्षण हैं ? – *उच्च पुरा पाषाण काल*
3. ऋग्वेद के किस मण्डल में चातुर्वर्ण्य की अवधारणा प्राप्त होती है ? – *दसवें मण्डल में*
4. किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी ? – *मुहम्मद तुगलक*
5. हड़प्पा संस्कृति में 'नाट्यकला' का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है ? – *मोहनजोदड़ो से*
6. राजसूय से सम्बन्धित अनुष्ठानों का वर्णन है – *यजुर्वेद में*
7. हाथीगुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है ? – *खारवेल*
8. मध्यकालीन भारत में 'दस्तार बन्दान' कौन कहलाते थे ?
– *उलेमा*
9. दिल्ली सल्तनत में किससे 'मुस्तौफी-ए-मुमालिक' का कार्य सम्बन्धित था ? – *लेखा परीक्षण*
10. फिरोजशाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यरोहण के उपरान्त समाप्त किए गए कृषि उपकर (Agrarian Cesses) क्या कहलाते थे ? – *अबवाब*

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन

11. 1946 में गठित अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे ? – *5*
12. 1916 में सम्पन्न 'लखनऊ समझौता' (Lucknow Pact) किसके बीच हुआ था ? – *कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच*
13. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं
– *एनी बेसेन्ट*
14. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के समय भारत का वाइसराय था
– *लॉर्ड चेम्सफोर्ड*
15. सन् 1882 में गठित इण्डियन एजुकेशन कमीशन (Indian Education Commission) की अध्यक्षता किसने की थी ?
– *डब्ल्यू.डब्ल्यू. हण्टर*
16. 1935 ई. के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे – *सर मोरिस ग्वेर*
17. सन् 1882 में गठित 'हण्टर कमीशन' (Hunter Commission) सम्बन्धित था – *शिक्षा से*
18. अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब था
– *वाजित अली शाह*
19. 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था – *कुँवर सिंह द्वारा*
20. 'मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर' का आह्वान किया था – *श्री नारायण गुरु ने*

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

21. संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ? – *सच्चिदानंद सिन्हा*
22. नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुच्छेदों में से कौनसा अनुच्छेद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्द्धन से सम्बन्धित है ?
– *अनुच्छेद 51*
23. ऐसे सभी व्यक्ति, जो ····· या उसके पश्चात् भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा. – *26 जनवरी, 1950*
24. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया ?
– *सम्पत्ति का अधिकार*
25. भारत के संविधान का कौनसा अनुच्छेद प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है ? – *अनुच्छेद 19*
26. संविधान का कौनसा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है ?
– *राज्य के नीति निदेशक तत्व*
27. यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा ?
– *सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश*
28. भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है ?
– *भारत का राष्ट्रपति*
29. स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे ?
– *डॉ. जॉन मथाई*
30. उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है ?
– *किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए*

भारत एवं विश्व का भूगोल

31. भारत के राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत (Silk Yarn) उत्पादित करता है ? – *कर्नाटक*
32. लूसिफर ····· ग्रह का एक अन्य नाम है. – *शुक्र*
33. पृथ्वी के कोर (केन्द्रीय भाग) को और किस नाम से जाना जाता है ? – *गुरुमण्डल*
34. एक खगोलीय इकाई (AU) ····· के बीच की दूरी को निरूपित करती है. – *पृथ्वी और सूर्य*
35. गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठण्डी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को ····· कहा जाता है.
– *वाताग्र वर्षा*
36. विषुव तब होता है, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर ····· के ऊपर होता है. – *भूमध्य रेखा*

STUDYPDF WALLAH

37. अक्षांश का 1 अंश ..... के बराबर होता है. – *111 किमी*
38. यूरोप के किस शहर को 'ऐड्रियाटिक की रानी' कहते हैं ?
– *वेनिस को*
39. भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है ? – *दोआब*
40. नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है, जहाँ मीठे (ताजे) और खारे जल का सम्मिलन होता है ? – *नदमुख*

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन

41. "वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एकपादप (Mono-culture) कृषि ..... की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है. इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपन के लिए विशाल भूखण्डों का निर्वनीकरण, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं. अलवण जल कोटरिकाएं (Fresh water pockets) त्वरित गति से सूख रही हैं, क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है." इस उदाहरण में निर्देशित स्थान है. – *सुन्दरबन*
42. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ?
– *लखीमपुर खीरी*
43. बाघों का प्रमुख रिजर्व 'सरिस्का' किस राज्य में अवस्थित है ?
– *राजस्थान के अलवर जिले में*
44. शुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है – *नेपाल में*
45. नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण-कटिबन्धीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है ?
– *नामदफा नेशनल पार्क*
46. जीवमण्डल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है
– *आनुवंशिक विभिन्नता के*
47. भारत के जैव भण्डारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है ? – *नोकरेक*
48. विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है
– *रेड डाटा बुक में*
49. किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है – *50 वर्ष से*
50. डुगोन्ग नामक समुद्री जीव, जोकि विलोपन की कगार पर है, क्या है ? – *स्तनधारी (मैमल)*

भारतीय अर्थव्यवस्था

51. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में किस प्रकार बदलाव किया है ? – *जुलाई-जून से बदल कर अप्रैल-मार्च करना*
52. किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय–
– *उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी*
53. उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूँजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है ? – *उच्च पूँजी-उत्पाद अनुपात के कारण*
54. 'बुलक कैपिटलिस्ट' (बैल-पूँजीपति) किसे कहा जाता है ?
– *उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं हैं*
55. भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है – *बासमती चावल*
56. 'जेएएम' त्रयी (JAM-Trinity) से क्या तात्पर्य है ?
– *जनधन योजना, आधार, मोबाइल नम्बर*
57. किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है
– *सकल घरेलू उत्पाद*
58. अटल नवोन्मेष मिशन (AIM) किस विभाग की प्रमुख पहल है ? – *नीति आयोग की*
59. भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आँकड़े कौनसा संस्थापन/कार्यालय जारी करता है ?
– *वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*
60. साख-पत्र (L/C) दिया जाता है – *एक निर्यातकर्ता द्वारा*

सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी

61. मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके ..... का आवर्त फलन है.
– *परमाणु भार*
62. कार के इंजन में नाकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है ? – *ब्यूटेन*
63. नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है ?
– *कॉपर सल्फेट ($CuSO_4$)*
64. 'ऑक्टेन संख्या' किसकी गुणवत्ता का माप है ? – *ईंधन की*
65. कौनसी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ? – *पारा (Hg)*
66. सोडियम वाष्प लैम्प प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ?
– *इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूँदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है*
67. DNA और RNA के बीच समानता यह है कि दोनों–
– *न्यूक्लिओटाइड के बहुलक होते हैं*
68. ऐसा जानवर, जो समुद्र के तल में रहता है, वह कहलाता है
– *नितलस्थ*
69. एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौनसा खमीर प्रयोग में लाया जाता है ? – *सैकरोमाइसीज सेरेविसी*
70. किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव को कहते हैं – *डॉप्लर प्रभाव*

शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान

71. किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता-पिता की सन्तान निम्न कोटि की होती है ?
– *प्रत्यागमन का नियम के अनुसार*
72. थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताएं हैं ? – *5*
73. "अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए." यह कथन है– – *फ्रॉबेल का*
74. शिक्षक, मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की
– *बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जान कर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है.*
75. समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अन्तर होता है. इस सन्दर्भ में विद्यालय की भूमिका है
– *सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें*

STUDYPDF WALLAH

76. किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिन्तन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया ? – *लेव वायगोट्स्की*

77. किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिन्तन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है ?
– *जीन पियाजे ने*

78. लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय सम्बन्ध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है ? – *सामाजिक-क्रम अवस्था*

79. कोहलवर्ग के अनुसार किस प्रकार 'एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है.'
– *नैतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श में उनको शामिल कर*

80. बुद्धिलब्धि (I.Q.) का प्रत्यय सर्वप्रथम किस मनोविज्ञानी द्वारा प्रयुक्त किया गया ? – *टरमैन द्वारा*

सम्प्रेषण/संचार

81. "सम्प्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्पत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय है" सम्प्रेषण की यह परिभाषा किसने दी ? – *न्यूमैन तथा समर ने*

82. लुइस ए. एलन ने सम्प्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं ?
– *4*

83. प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है ?
– *4 प्रकार का समतल, विकर्णीय, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी*

84. मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का सम्प्रेषण है ? – *यांत्रिक सम्प्रेषण*

85. जब दो व्यक्ति आपस में और आमने-सामने संचार करते हैं, तो इसे कहते हैं – *अन्तरवैयक्तिक संचार*

86. 'मुँह से निकला शब्द वापस नहीं आता' अन्तर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धान्त को इंगित करता है ?
– *अपरिवर्तनीयता का सिद्धान्त*

87. 'अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबन्धक पर हमला'–जैसी समस्या किस तरह हल हो सकती है ?
– *भावात्मक समझ द्वारा*

88. अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषण का एक अन्य नाम है
– *द्विक् सम्प्रेषण*

89. 'सम्प्रेषण अन्तःक्रिया के रूप में' परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि
– *कभी-कभी गैर-इरादतन होती है*

90. कालिक सम्प्रेषण का अध्ययन जाना जाता है
– *क्रोनेमिक्स के रूप में*

खेलकूद

91. पहला विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था ? – *1877 में*

92. यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरूआत किस वर्ष हुई थी ?
– *1881 में*

93. फ्रेंच ओपन की शुरूआत हुई थी – *1891 में*

94. आस्ट्रेलियन ओपन की शुरूआत कब हुई थी ? – *1905 में*

95. फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है ? – *रोलैंड गैरोस*

96. 'क्ले कोर्ट' तथा 'हार्ड कोर्ट' शब्द किस खेल से सम्बन्धित है ? – *लॉन टेनिस*

97. यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है ? – *हार्ड*

98. विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है ?
– *ग्रास*

99. फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है ?
– *क्ले*

100. आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है ? – *हार्ड*

कृषि

101. उस कृषि को क्या कहा जाता है, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ-साथ किए जाते हैं ? – *मिश्रित कृषि*

102. गेहूँ का काला टिक रोग (Black Tick Disease) किसके कारण होता है ? – *फफूँदी के कारण*

103. मटर में 'मार्श' रोग का क्या कारण है ?
– *मैंगनीज की कमी के कारण*

104. दलहन फसलों में कौनसा रंगद्रव्य (Pigment), नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen fixation) में सहायक होता है ?
– *लेगहिमोग्लोबिन*

105. 'बोनी' (Bonnie Species) किस फसल की प्रजाति है ?
– *टमाटर की*

106. धान का प्रसिद्ध 'खैरा' रोग (Khaira' Disease) का क्या कारण है ? – *जस्ते (Zn) की*

107. 'रजत क्रान्ति' किससे सम्बन्धित है ? – *अण्डा उत्पादन से*

108. 'भूरी क्रान्ति' किससे सम्बन्धित है ? – *उर्वरक उत्पादन से*

109. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी ?
– *1905 में*

110. पोमोलोजी में अध्ययन करते हैं – *फलों का*

कम्प्यूटर ज्ञान

111. MS-Word में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्ट-कट है – *Ctrl +*

112. Microsoft word फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है ? – *Ctrl + V का*

113. Cyber Law में 'DOS' का पूरा रूप (Full Form) क्या है ? – *डिनाइअल ऑफ सर्विस*

114. वह Memory Unit, जो CPU से सीधा सम्पर्क करता है, कहलाता है – *ऑक्सीलियरी मेमोरी*

115. अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली (Abuse Messaging System) का दुरुपयोग करना कहलाता है – *स्पाम (Spam)*

116. पहले से ऑन कम्प्यूटर को रि-स्टार्ट (Re-start) करने को क्या कहते हैं ? – *वार्म बूटिंग*

117. मोड्युलेटर-डी मोड्युलेटर का सामान्य नाम है – *मॉडेम*

118. ODBC का पूरा नाम है
– *Open Database Connectivity*

119. TFTP का पूरा नाम है
– *Trivial File Transfer Protocol*

शेष पृष्ठ 127 पर

STUDYPDF WALLAH

समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा भारत के किस गाँव को वर्ष 2023 में सर्वोत्तम पर्यटन गाँव के रूप में पुरस्कृत किया गया है ?
(A) धोरडो (जनपद कच्छ, गुजरात)
(B) नवॉपिण्ड सरदारान (जनपद गुरदासपुर, पंजाब)
(C) सरमोली (जनपद पिथोरागढ़, उत्तराखण्ड)
(D) पोचमपल्ली (जनपद हैदराबाद, तेलंगाना)

2. समाचारों की सुर्खियों में रहा 'नमो भारत' क्या है ?
(A) अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र
(B) भारतीय संस्कृति को उजागर करता एक कार्यक्रम
(C) भारत की नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (RRTS) पर चलाई गई Rapidx Train
(D) भारत श्रीलंका के बीच प्रारम्भ की गई यात्री सेवा का जहाज

3. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन को मानव रहित मिशन गगनयान TV D1 का परीक्षण कब किया गया ?
(A) 29 सितम्बर, 2023
(B) 6 अक्टूबर, 2023
(C) 21 अक्टूबर, 2023
(D) 31 अक्टूबर, 2023

4. समाचारों की सुर्खियों में रहा रफा बॉर्डर निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा है ?
(A) इजरायल और मिस्र
(B) इजरायल और जॉर्डन
(C) मिस्र और गाजा पट्टी
(D) लेबनॉन और इजरायल

5. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा भारत के गाँवों को सर्वोत्तम पर्यटन गाँवों की सूची 2023 में शामिल किया गया है–
I. माडिया (जनपद सागर, म. प्र.)
II. धोरडो (जनपद कच्छ, गुजरात)
III. मनडावा (राजस्थान)
IV. कुरुवाना (उत्तर प्रदेश)
उपर्युक्त में से सही हैं ?
(A) केवल I एवं II
(B) केवल III एवं IV
(C) केवल I एवं III
(D) केवल II एवं IV

6. अक्टूबर 2023 के अन्तिम सप्ताह में किस देश द्वारा भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक बीजा जारी करने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है ?
(A) श्रीलंका
(B) वियतनाम
(C) दक्षिण अफ्रीका
(D) ब्राजील

7. हुली वेशा नृत्य किस राज्य का लोकनृत्य है ?
(A) केरल (B) कर्नाटक
(C) आन्ध्र प्रदेश (D) तेलंगाना

8. निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विश्व में फुटबाल के सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार 'बैलोन डी'ओर' (Ballon d'or) से 2023 में आठवीं बार सम्मानित किया गया ?
(A) लियोनेल मेसी (अर्जेंटाइना)
(B) अर्लिंग हॉलैण्ड (नॉर्वे)
(C) केलियन म्बापे (फ्रांस)
(D) करीम बेंजेमा (फ्रांस)

9. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
I. बेंगलूरू–सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स
II. चण्डीगढ़–सिटी ऑफ डिजायन
III. कोझीकोड–सिटी ऑफ लिटरेचर
IV. ग्वालियर–सिटी ऑफ म्यूजिक
उपर्युक्त में से कितने युग्म यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड सिटी दिवस–31 अक्टूबर, 2023 को 55 नए सृजनकारी शहरों की सूची के सन्दर्भ में सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

10. निम्नलिखित में से किस भारतीय को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है ?
(A) रबीश कुमार
(B) भारत वातवानी
(C) रवी कन्नन आर.
(D) टी. एम. कृष्णा

11. इडेलगिव हुरुन इण्डिया फिलेन्थ्रॉफी सूची 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक दान भारत के किस दानदाता ने दिया है ?
(A) शिवनादर (एचसीएल टेक्नोलॉजी)
(B) अजीम प्रेमजी (विप्रो)
(C) मुकेश अम्बानी (रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि.)
(D) निखिल कामत (जीरोधा)

12. बिजनेसलाइन चेंजमेकर एवार्ड्स 2023 के सन्दर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
I. चेंजमेकर ऑफ दी ईयर –भारतीय रिजर्व बैंक
II. आइकॉनिक चेंजमेकर ऑफ दी ईयर –अमूल
III. चेंजमेकर सोशल ट्रांसफॉरमेशन – प्रथम
IV. चेंजमेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन – भीम एप
V. चेंजमेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर-मेशन – प्रधानमंत्री जनधन योजना
VI. यंग चेंजमेकर एवार्ड –श्रीनिधि आर. एस.
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल 2 (B) केवल 3
(C) केवल 4 (D) केवल 5

13. निम्नलिखित में से किस देश में 3 नवम्बर, 2023 की रात को आए भूकम्प से 150 से अधिक लोग मारे गए ?
(A) अफगानिस्तान
(B) पाकिस्तान
(C) नेपाल
(D) भूटान

14. किस भारतीय बल्लेबाज ने एक-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए हैं ?
I. सचिन तेंदुलकर
II. वीरेन्द्र सहवाग
III. विराट कोहली
IV. महेन्द्र सिंह धोनी
सही कूट हैं–
(A) केवल III
(B) केवल I
(C) केवल I एवं III
(D) केवल IV

15. चुनावी बॉण्ड के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. चुनावी बॉण्ड योजना 2018 में लॉन्च की गई थी.
II. चुनावी बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदे जा सकते हैं.

STUDYPDF WALLAH

III. चुनावी बॉण्ड कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताकर खरीद सकता है.

IV. चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिए लोक सभा/विधान सभा में कम-से-कम एक प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल ही अर्ह है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

16. CART कोशिका उपचार निम्नलिखित में से किस रोग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है ?

(A) हेमाटोलॉजिक मैलिगनेन्ट कैंसर
(B) मल्टी ड्रग उपचार से रजिस्टेंट क्षय रोग
(C) लम्बे समय से चले आ रहे कोविड
(D) सिकिल सेल अनीमिया

17. डेंगू बुखार के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?

I. इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है.
II. यह वायरस से होने वाला रोग है.
III. यह एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है.

कूट :

(A) केवल I
(B) केवल II एवं III
(C) सभी I, II एवं III
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

18. समाचारों की सुर्खियों में रहा क्लयूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ?

(A) चीन (B) मंगोलिया
(C) रूस (D) उत्तर कोरिया

19. 54वाँ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया ?

(A) गोवा (B) मुम्बई
(C) हैदराबाद (D) चेन्नई

20. स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया ?

(A) स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2·0
(B) दिल्ली सरकार
(C) उत्तर प्रदेश सरकार
(D) उत्तराखण्ड सरकार

21. निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए–

I. जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (PQLI)
II. मानव विकास सूचकांक (HDI)
III. लोक मामले सूचकांक, 2021 (PAI)
IV. सामाजिक शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

उपर्युक्त सूचकांकों में से कितने सूचकांकों में केरल पहले स्थान पर रहा ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

22. एकदिवसीय आईसीसी विश्वकप के इतिहास में ऐसा पहला बल्लेबाज कौन है, जो 'Timed Out' नियम के तहत् आउट हुआ ?

(A) एंजिलो मैथ्यूज (श्रीलंका)
(B) शाकिब हल हसन (बांग्लादेश)
(C) राशिद खान (अफगानिस्तान)
(D) हेजलवुड (आस्ट्रेलिया)

23. समाचारों की सुर्खियों में रहा 'डीफफेक' (Deepfake) के बारे निम्नलिखित में से कौनसे कथन सत्य हैं ?

I. यह नकली विषय वस्तु होती है.
II. आमतौर पर यह चित्र, फोटो, ऑडियो, वीडियो के रूप में पाई जाती है.
III. इसका सृजन शक्तिशाली कृत्रिम मेधा टूलों से किया जाता है.

उपर्युक्त में से सही हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

I. केन्द्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है.
II. मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 'सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत् भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.

उपर्युक्त में से सही हैं ?

(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

25. 10 नवम्बर, 2023 को इण्टरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता को निलम्बित कर दिया ?

(A) श्रीलंका
(B) जिम्बाब्वे
(C) अफगानिस्तान
(D) पाकिस्तान

26. 14 घण्टों के भीतर 800 से अधिक भूकम्प आने के कारण मध्य नवम्बर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई ?

(A) नेपाल (B) आइसलैण्ड
(C) तुर्किए (D) इराक

27. विश्व की ऐसी कौनसी पहली एयर-लाइन्स है जिसने 'जनरेटिव ए आई (कृत्रिम मेधा) आभासी एजेन्ट विकसित और तैनात किया है ?

(A) एयर इण्डिया
(B) ब्रिटिश एयरवेज
(C) इतिहाद
(D) सिंगापुर एयरलाइन्स

28. 9 नवम्बर, 2023 को किस राज्य की विधान सभा में शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़ी जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की उच्चतम सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर देने का कानून पारित किया है ?

(A) बिहार (B) झारखण्ड
(C) ओडिशा (D) आन्ध्र प्रदेश

29. हाल ही में किस स्थान पर दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक-बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव, 2023 का आयोजन किया गया है ?

(A) नई दिल्ली (B) बेंगलूरू
(C) चेन्नई (D) हैदराबाद

30. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

I. 1963 में एक संकल्प द्वारा स्थापित सीबीआई गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है.
II. सीबीआई अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट (डीएसपीई) अधिनियम से ग्रहण करता है.
III. सीबीआई भारत में इण्टरपोल के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

31. ईस्टर्न मैरीटाइम कोरीडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?

I. यह भारत के पूर्वी तट और रूस के सुदूर पूर्वी तट को जोड़ता है.

STUDYPDF WALLAH

II. इस मार्ग से पूर्व सोवियत संघ के दौर में भारत से रूस को जहाज आते जाते थे.
III. इस मार्ग से जहाजों को चेन्नई से व्लादीवोस्तक तक पहुँचने में केवल 17 दिन लगेंगे.
IV. इस मार्ग से मुख्य रूप से कोकिंग कोल, कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस तथा उर्वरक की ढुलाई होगी.
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

32. एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC) का सीईओ शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया ?
(A) शंघाई (चीन)
(B) मुम्बई (भारत)
(C) सैनफ्रांसिस्को (स. रा. अमरीका)
(D) टोकियो

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष 15 नवम्बर को मनाया जाता है.
II. 15 नवम्बर स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी भगवान विरसा मुण्डा का जन्म दिन है.
III. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस 2023 के अवसर पर झारखण्ड में विशिष्ट रूप से आरक्षित ट्राइवल समूहों (PVTG) के समग्र विकास हेतु एक विशेष योजना लॉन्च की.
उपर्युक्त में से सही हैं ?
(A) केवल I
(B) केवल I एवं III
(C) I, II एवं III सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

34. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा नवम्बर 2023 में मंत्रिमण्डल में किए गए फेरबदल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. गृह मंत्री सुएला ब्रेक्र्मन को मंत्रिमण्डल से बरखास्त कर दिया गया.
II. पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को यू. के. का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है.
III. अब तक विदेश मंत्री रहे जेम्स क्लेवरली को गृह मंत्री बनाया गया है.
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. जीपीएस ट्रेकर के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. जीपीएस ट्रेकर इसके धारक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सटीक जानकारी देने वाला उपकरण है.
II. सं. रा. अमरीका, यू. के. तथा मलेशिया सहित अनेक देशों में जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्तों पर जीपीएस लगाया जाना एक पूर्व शर्त है.
III. जम्मू-कश्मीर के एक कैदी गुलाम मुहम्मद भट को जीपीएस ट्रेकिंग डिवाइस के साथ टैग किए जाने के बाद ही जमानत पर रिहा किया गया.
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

36. 'समाचारों की सुर्खियों में रहे 'डीपफेक' वीडियो के सन्दर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए–
I. शरीर का हिलना-डुलना
II. चेहरे के हाव-भाव
III. आँखों का हिलना-डुलना
IV. आडियो की गुणवत्ता
उपर्युक्त में से कितनों के द्वारा डीपफेक वीडियो की पहचान की जा सकती है ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

37. विश्व में मधुमेह (Diabetes) के सर्वाधिक रोगी किस देश में पाए जाते हैं ?
(A) भारत
(B) इण्डोनेशिया
(C) सं. रा. अमरीका
(D) चीन

38. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' कहाँ से प्रारम्भ की गई ?
(A) खुण्टी (झारखण्ड)
(B) राँची (झारखण्ड)
(C) झाड़ग्राम (प. बंगाल)
(D) मलकानगिरि (ओडिशा)

39. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ लॉन्च किया गया ?
(A) कोरापुट (ओडिशा)
(B) राँची (झारखण्ड)
(C) खुण्टी (झारखण्ड)
(D) धनवाद (झारखण्ड)

40. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें विकसित भारत के चार 'अमृत स्तम्भों' के रूप में निरूपित किया गया है ?
I. नारी शक्ति
II. देश का युवा वर्ग
III. खाद्य उत्पादक
IV. नव-मध्य वर्ग एवं निर्धन
V. शिक्षक
VI. वैज्ञानिक और शोधकर्ता
उपर्युक्त में से सही है ?
(A) केवल I, II, III एवं IV
(B) केवल I, II, V एवं VI
(C) केवल II, IV, V एवं VI
(D) केवल I, IV, V एवं VI

41. कृत्रिम मेधा के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए–
I. आतंकवादी रोधी ऑप्रेशनों में सूचना प्राप्त करने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित वास्तविक समय अनुत्रवण सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जा रहा है.
II. कृत्रिम मेघा से युक्त दोनों से सीमाओं की निगरानी की जा रही है.
III. रक्षा कृत्रिम मेघा डायलोग हेतु यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच सहमति बनी है.
उपर्युक्त से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

42. अभी हाल में निम्नलिखित में से कौनसे देश ने इन्फैन्ट्री कामबैट वाहन (ICV) के सह-विनिर्माण पर सहमति जताई है ?
(A) संयुक्त राज्य अमरीका
(B) फ्रांस
(C) आस्ट्रेलिया
(D) यू.के.

उत्तर व्याख्या सहित

1. (A)
2. (C) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली-मेरठ खण्ड पर विकसित Regional Rapid Transit System (RRTS) के साहिबाबाद-दुहाई

STUDYPDF WALLAH

खण्ड के उद्घाटन के समय प्रारम्भ की गई अर्द्ध उच्च गति ट्रेन नमो भारत का भी शुभारम्भ किया गया.

3. (C)
4. (C) गाजा क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी गुट हमास तथा इजरायली सेनाओं के बीच चल रहे युद्ध से उपजी परिस्थितियों के बीच गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए गाजा-मिस्र सीमा पर स्थित रफा बार्डर को 22 अक्टूबर, 2023 को सीमित अवधि के लिए खोलकर 20 ट्रकों को गाजा क्षेत्र में जाने दिया गया.
5. (A)
6. (A) श्रीलंका के मंत्रिमण्डल ने पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए 24 अक्टूबर, 2023 को भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इण्डोनेशिया और थाइलैण्ड के यात्रियों के लिए तात्कालिक प्रभाव से मुफ्त वीजा जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की जो प्रायोगिक परियोजना के रूप में 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगी.
7. (B) दशहरा और नवरात्रि के अवसर पर मंगलूरू क्षेत्र में पारम्परिक तौर पर किया जाने वाला वाद्य नृत्य हुली वेशा कहा जाता है. नृत्य समूह में शामिल नर्तक अपने शरीर को वेसन से वाद्य के रूप में रंग लेते हैं.
8. (A) लियोनेल मेसी को 'गोल्डन बाल' के रूप में विख्यात यह पुरस्कार 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 तथा 2021 में मिल चुका है.
9. (B) यूनेस्को प्रति वर्ष विश्व शहर दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर सात सृजनात्मक क्षेत्रों–क्राफ्ट्स एवं लोक कलाओं, डिजायन, फिल्म, गैस्ट्रोनोमी, साहित्य, मीडिया आर्टस तथा संगीत में शहरों को टैग प्रधान करता है. वर्ष 2023 के लिए जारी 55 देशों की सूची में कोझीकोड (केरल) को साहित्य का शहर तथा ग्वालियर (म. प्र.) को संगीत का शहर का टैग प्रदान किया गया है.
10. (C) 65वाँ रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय कैंसर शल्यचिकित्सक डॉ. रवी कन्नन आर को प्रदान किया गया है वे कचर कैंसर हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (CCHRC) के डायरेक्टर हैं. उनके अतिरिक्त यह पुरस्कार लेमोस, यूजेनियो, कोरोनेल फेरेर मिरियम, रक्षानन्द कोरवी को भी प्रदान किया गया.
11. (A) इडेलिगिव हुरुन इण्डिया फिलेन्थ्रॉफी सूची 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक ₹ 2042 करोड़ का दान एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक चेयरमैन शिव नादर ने दिया जबकि ₹ 1,774 करोड़ का दान देकर विप्रो के अजीम प्रेमजी दूसरे तथा ₹ 376 करोड़ का दान देकर रिलायंस इण्डस्ट्रीज के मुकेश अम्बानी तीसरे स्थान पर रहे. ₹ 170 करोड़ का दान देकर रोहिणी नीलेकणि महिला दानदाताओं में पहले स्थान पर रहीं.
12. (C) चेंजमेकर सोशल ट्रांसफॉरमेशन अवार्ड महिला प्रतिभा पलायन को रोकने तथा बालिका शिक्षा प्रोन्नयन को समर्पित गैर-सरकारी संगठन हरके (Herkey) को तथा चेंजमेकर डिजिटल ट्रांसफॉरमेश अवार्ड डेयरी क्षेत्रक के डिजिटलीकरण को समर्पित एक स्टार्ट रूप–स्टेलाअप्स टेक्नोलॉजी को प्रदान किया गया है.
13. (C)
14. (A) एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैचों में विराट कोहली ने आईसीसी विश्व कप के सेमी फाइनल में न्यूजीलैण्ड के विरुद्ध 117 रन बनाकर कुल 50 शतक बनाकर सचिन तेन्दुलकर द्वारा बनाए 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
15. (C) चुनावी बॉण्ड खरीदने के लिए खरीदने वाले को अपनी पहचान उजागर करने की बाध्यता नहीं है.
16. (A) Chimeric Antigen Receptor (CAR) थेरेपीजा इस सम्भावना को तलाश रहीं हैं कि यह हेमाटोलॉजिक मैलिगनेन्ट कैंसर तथा ठोस मैलिगनेन्ट ट्यूमर के उपचार में किस सीमा तक कारगर है.
17. (C) 18. (C)
19. (A) 54वाँ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20-28 नवम्बर, 2023 को गोवा में आयोजित किया गया.
20. (A) 21. (D) 22. (A)
23. (C) यह 'डीपलर्निंग' तथा 'नकली' शब्दों से मिलकर बना है. जिसका अर्थ मौजूद फेस स्वैपिंग तकनीकों और प्रौद्योगिकी से मनगढंत वीडियो-ऑडियो, चित्र फोटो बनाया जाता है. डीपफेक शब्द की उत्पत्ति 2017 में उस समय हुई, जब 'डीपफेकस' नामक उपयोगकर्ता द्वारा मशहूर हस्तियों के अन्तरंग वीडियो जारी किए थे.
24. (C) सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत् मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. समिति में प्रधानमत्री, लोक सभा में नेता विरोधी दल (यदि कोई मान्यता प्राप्त नेता विरोधी दल न हो तो सबसे बड़े दल का नेता) तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक केन्द्रीय मंत्री सदस्य होता है.
25. (A) यह निलम्बन श्रीलंका क्रिकेट द्वारा श्रीलंका में क्रिकेट के विनियमन और प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वायत्तता बनाए रखने में असफल रहने के कारण किया गया है.
26. (B) 9-10 नवम्बर, 2023 को 800 से अधिक बार भूकम्प आने के कारण आइसलैण्ड में आपात्काल की घोषणा की गई. आइसलैण्ड के दक्षिण पश्चिमी रेयक-जेनेज़ प्रायद्वीप में रेक्टर पैमाने पर 5·2 तीव्रता के भूकम्प आए, जिन्हें ज्वालामुखी फटने का पूर्व संकेत माना गया है.
27. (A) एयर इण्डिया विश्व की पहली एयरलाइंस बन गई, जिसने जनरेटिव आर्टीफीशियल वर्चुअल एजेण्ट विकसित और तैनात किया है. टाटा संस स्वामित्व वाली कम्पनी एयर इण्डिया ने मार्च 2023 में जनरेटिव ए आई वर्चुअल एजेण्ट महाराजा पाइलट आधार पर तैनात किया था. Azure Open AI Service द्वारा संचालित महाराजा एजेण्ट एक दिन में चार भाषाओं–हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन में 6000 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकने में सक्षम है.
28. (A) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए 10% सीटों के आरक्षण के साथ अब आरक्षण की प्रभावी उच्चतम सीमा 75% हो गई है. नए कानून में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ा कर 25%, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 8% से 18%, अनुसूचित जातियों के लिए 14% से 20% कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10% से घटाकर 2% कर दिया गया है.
29. (A) 30. (B)
31. (D) भारत और रूस के बीच कोकिंग कोल, कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और रासायनिक उर्वरकों की ढुलाई के लिए स्वेज नहर के रास्ते सेंट पीटसबर्ग तक के समुद्री मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में ईस्टर्न मैरीटाइम कोरीडोर को प्रारम्भ किए जाने की वार्ताएं अन्तिम चरण में हैं.
32. (C) एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन 14-16 नवम्बर, 2023 को सैनफ्रांसिस्को (सं. रा. अमरीका) में आयोजित किया गया.
33. (C)
34. (C) पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवर्मन ने इज़रायल-हमास संघर्ष के सन्दर्भ में फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा किए गए आन्दोलनकारियों पर पुलिस कार्यवाही की निन्दा किए जाने पर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया.
35. (C) ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग आमतौर पर जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है (जैसे कि केरल में हाथियों पर तथा कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों पर) जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों (जैसेकि सं.रा. अमरीका, यू.के. तथा मलेशिया सहित कुछ देशों में) और अनेक बार वाहनों की जानकारी रखने के लिए किया जाता है.
36. (D) डीपफेक वीडियो की पहचान करने के लिए दृश्य और ऑडियो विसंगतियों के साथ अन्य स्पष्ट संकेतों–चेहरे के हाव-भाव और विसंगतियाँ, चेहरे के अप्राकृतिक भाव, बेमेल लिप-सिंक पलकों का अनियमित तरीके से झपकाना आदि पर भी ध्यान दिया जाता है.
37. (D) मधुमेह के सर्वाधिक रोगी चीन में पाए गए हैं. दूसरा स्थान भारत का है.
38. (A)

शेष पृष्ठ 167 पर

STUDYPDF WALLAH

सामान्य अध्ययन

(प्रश्न-पत्र-III)

खण्ड–अ

प्रश्न 1. खाद्य प्रसंस्करण और सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए. 8

उत्तर–खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार का विनिर्माण है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों या खाद्य वस्तुओं में संसाधित किया जाता है. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख उप-खंड फल और सब्जियाँ, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग आदि हैं. उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्य क्षेत्र अपने आकार के मामले में पाँचवें स्थान पर है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6%, भारतीय निर्यात का 13% और देश में समग्र औद्योगिक निवेश का 6% योगदान देता है. एएसआई डेटा के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 20·32 लाख लोग लगे हुए थे.

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीतियाँ

- **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना**– सरकार ने वर्ष 2016 से खाद्य उत्पादों के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना शुरू की है.
- **मेगा फूड पार्क**– सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए देश भर में मेगा फूड पार्क स्थापित किए हैं. उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिलकर सरकार द्वारा ₹ 2000 करोड़ का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया गया है.
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**–सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को उदार बनाया है. उदाहरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत् 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी की अनुमति दी गई है.
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन**–सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं.
- **निर्यात प्रोत्साहन**– सरकार ने खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) आदि.
- **मेक इन इंडिया**–सरकार द्वारा अपनी बहुउद्देशीय योजना मेक इन इंडिया पहल के तहत् भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

हालाँकि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देश के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है. उदाहरण के लिए चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक है, लेकिन अभी भारत मात्र 2% फसल ही संसाधित कर पाता है. इस क्षेत्र के सामने आने वाली अन्य कुछ प्रमुख चुनौतियों में अकुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की कमी, खराब गुणवत्ता नियंत्रण और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक सीमित पहुँच आदि शामिल है.

प्रश्न 2. किसानों की सहायता के लिए ई-तकनीक के प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए. 8

उत्तर–ई-प्रौद्योगिकी को सामान्यतः इंटरनेट और सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकियों के सम्मिलित उपयोग को समझा जाता है. किसानों की मदद के लिए ई-प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए वर्ष 2007 से आईसीटी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है. इसके लिए इसी वर्ष किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति शुरू की गई. इसके अतिरिक्त, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल एक्सेस पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, वर्ष 2012 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शुरू की गई थी.

किसानों की सहायता के लिए ई-तकनीक और उसके निहितार्थ

- **AGMARKNET**– कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (AGMARKNET) को वर्ष 2000 में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था.
- **ई-चौपाल**–आईटीसी की एक पहल वैकल्पिक विपणन चैनल, मौसम, कृषि पद्धतियों, इनपुट बिक्री आदि पर जानकारी प्रदान करती है.
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) केन्द्रीय कृषि पोर्टल**–इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया, डीबीटी कृषि पोर्टल देश भर में कृषि योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है.
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)**– राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम) राष्ट्रीय स्तर पर ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की शुरूआत करने और पूरे देश में विनियमित बाजारों में ई-मार्केटिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण का समर्थन करने की परिकल्पना करती है.
- **किसान कॉल सेंटर**–कृषि में आईसीटी की क्षमता का दोहन करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2004 में यह योजना शुरू की. परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के प्रश्नों का उनकी अपनी बोली में टेलीफोन कॉल पर उत्तर देना है.
- **ग्राम संसाधन केन्द्र**– ग्राम संसाधन केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान-आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं. वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) नेटवर्क और अर्थ ऑब्जर्वेशन (EO) का उपयोग करने वाली अनूठी पहलों में से एक हैं.
- **डिजिटल कृषि मिशन**–डिजिटल कृषि मिशन (2021–2025) का उद्देश्य एआई, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक और ड्रोन और रोबोट के उपयोग जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं का समर्थन करना और उनमें तेजी लाना है.
- **एग्रीस्टैक**–कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 'एग्रीस्टैक' बनाने की योजना बनाई है–जो कृषि में प्रौद्योगिकी–आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह है. यह किसानों के लिए कृषि खाद्य मूल्य शृंखला में शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करेगा.

अतः कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में ई-तकनीक न सिर्फ समय और लागत को कम करती है, बल्कि यह उत्पादकता और मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान को भी आसान बनाता है.

प्रश्न 3. भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ कौनसी हैं? इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु सुझाव दीजिए. 8

उत्तर–भारत के स्वतंत्र होने के बाद कम उत्पादकता, आयातित खाद्यान्न पर निर्भरता

STUDYPDF WALLAH

और ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से की तीव्र गरीबी जैसी स्थिति के बीच तत्कालीन सरकार ने कृषि संरचना और विशेष रूप से भूमि जोत में कुछ बड़े सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया. अतः वर्ष 1950 से 1970 के दशक तक, राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर भूमि सुधार कानूनों को पारित किया गया.

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार मोटे तौर पर 4 चरणों में किए गए. पहला और सबसे लम्बा चरण (1950-72), दूसरा चरण (1972-85) तीसरा चरण (1985-95) और चौथा और वर्तमान चरण (1995 से आगे).

भारत में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ

- भूमि सुधारों की विफलता में प्रमुख बाधा समवर्ती मूल्यांकन और विश्वसनीय (वर्तमान) रिकॉर्ड की कमी रही है.
- भूमि सुधार के मार्ग में खड़ी एक और बाधा वित्तीय सहायता की कमी है. उदाहरण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं ने विशेष रूप से भूमि सुधार के वित्तपोषण के लिए कोई विशेष धन उपलब्ध नहीं कराया.
- कई राज्यों ने अपनी बजटीय योजनाओं में सर्वेक्षण और रिकॉर्ड के निर्माण जैसी आवश्यक वस्तुओं की लागत को भी शामिल करने से इनकार कर दिया.
- एक एकीकृत दृष्टिकोण की अनुपस्थिति, जैसे कि मध्यस्थ कार्यकाल का उन्मूलन, किरायेदारी सुधार, जोत सीमा आदि.
- देश में भूमि सुधार कार्यान्वयन कानूनी मुद्दों और सीमाओं के कारण भी बाधित रहे हैं.
- भूमि सुधार राजस्व विभाग के अधिकारियों और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण भी बाधित रहे हैं.

इन चुनौतियों को दूर करने के सुझाव

अप्रैल 2016 में नीति आयोग द्वारा लाए गए मॉडल भूमि पट्टा कानून का अनुसरण करना, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा करके देश में पट्टा खेती को पुनर्जीवित करके कृषि उत्पादकता बढ़ाना है इससे किरायेदार किसानों को अपनी जमीन पट्टे पर देने में मदद मिलती है, जो बदले में संस्थागत ऋण तक पहुँच आसान होती है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय और रोजगार पैदा हो सके. इसके सम्बन्ध में टी हक समिति की रिपोर्ट में केरल के कुदुम्बश्री और एपी लाइसेंस प्राप्त कृषक अधिनियम, 2011 का भी अनुसरण किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसे आधुनिक भूमि सुधार उपायों को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाना चाहिए.

प्रश्न 4. भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाइए. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय में अन्तर स्पष्ट कीजिए. 8

उत्तर—अनुच्छेद 112 के अनुसार, बजट आय और व्यय पर आधारित एक वार्षिक वित्तीय विवरण है. भारत का पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था. स्वतंत्र भारत में पी. सी. महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है.

भारत सरकार की बजट निर्माण प्रक्रिया

आम तौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में शुरू होती है.

बजट निर्माण के चरण

- अनुमानों का विवरण-बजट निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण
- अनुमानों का विभागीय परीक्षण
- वित्तीय मंत्रालय द्वारा परीक्षण
- मंत्रिमण्डल की स्वीकृति
- **संसदीय प्रक्रिया**—(क) लोक सभा में सामान्य वाद विवाद (ख) मतदान प्रक्रिया, (ग) विनियोग विधयेक, (घ) राज्य सभा में प्रस्तुतीकरण, (ड) वित्त विधेयक
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति**—जब वित्त विधेयक को राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों से स्वीकृति मिल जाती है, तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है. जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा वित्त विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है, बजट निर्माण की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती है.

योजनागत व्यय और गैर-योजनागत व्यय के बीच अन्तर

- किसी देश की वर्तमान पंचवर्षीय योजना में जिन कार्यक्रमों का विवरण दिया जाता है उन पर किया गया व्यय योजना व्यय कहलाता है. उदाहरण के लिए, ऊर्जा, सिंचाई, संचार, परिवहन, कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, सामाजिक सेवाओं आदि पर व्यय.
- किसी देश की वर्तमान पंचवर्षीय योजना में वर्णित कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों पर किए गए व्यय को गैर-योजनागत व्यय के रूप में जाना जाता है. उदाहरण के लिए, रक्षा सेवाओं पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय आदि.
- **योजनागत व्यय के उदाहरण**—ऊर्जा, सिंचाई, संचार, परिवहन और कृषि पर व्यय.
- **गैर-योजनागत व्यय के उदाहरण**—रक्षा सेवाओं पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय.

हालाँकि सरकार ने वर्ष 2016 से इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है. सरकार के निर्णय के पीछे प्राथमिक कारण 2011 में सी. रंगराजन समिति द्वारा योजना और गैर-योजना व्यय के बीच अन्तर को हटाने के लिए दी गई सिफारिश थी.

प्रश्न 5. "एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं." विवेचना कीजिए. 8

उत्तर—आधार भूत संरचना से तात्पर्य उन बुनियादी प्रणालियों और सेवाओं से है जो किसी देश या संगठन के लिए मूलभूत आवश्यकता होती हैं, उदाहरण के लिए, भवन, परिवहन पानी और बिजली की आपूर्ति.

किसी देश के आर्थिक विकास में बुनियादी ढाँचे की भूमिका

- बुनियादी ढाँचा कई आपूर्ति और माँग-पक्ष चैनलों के माध्यम से विकास को प्रभावित करता है. उदाहरण के लिए यह अर्थव्यवस्था को आपूर्ति शृंखलाओं को जोड़ने और सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए विश्वसनीय बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है.
- ऊर्जा, दूरसंचार और परिवहन नेटवर्क में निवेश सीधे विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि सभी प्रकार के बुनियादी ढाँचे वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी उत्पादन में एक आवश्यक इनपुट का प्रतिनिधित्व करते हैं.
- इसके अलावा, बुनियादी ढाँचा वितरित वस्तुओं की लागत को भी कम कर सकता है, यह लोगों और उत्पादों की भौतिक गतिशीलता को सुविधाजनक बना सकता है, उत्पादकता बाधाओं को दूर कर सकता है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है.
- सामाजिक बुनियादी ढाँचे से श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है. जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है. स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान और ऐसी अन्य सुविधाएं श्रमिकों के कौशल का विकास करती हैं, जिससे उनकी काम करने की क्षमता और दक्षता बढ़ती है.

प्रश्न 6. 'ब्लड मून' (Blood Moon) किसे कहते हैं ? यह कब होता है ? 8

उत्तर—खगोलीय विशेषज्ञों के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान 'ब्लड मून' तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच

STUDYPDF WALLAH

से गुजरती है, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर पड़ने से बच जाता है. चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी की छाया में चला जाता है. इस दौरान चंद्रमा का रंग काफी चमकीला यानि लाल दिखाई देता है. इसे ब्लड मून कहा जाता है. चंद्रग्रहण के दौरान, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से होकर चंद्रमा तक पहुंचता है. प्रथ्वी के वातावरण में धूल और बादल जितना ज्यादा होगा चंद्रमा उतना अधिक लाल नजर आता है. के वायुमण्डल में जितने अधिक बादल या धूल होंगे, चंद्रमा उतना ही अधिक लाल दिखाई देगा.

'ब्लड मून' की घटना का समय

ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होता है. इस अवधि के दौरान चंद्रमा लाल या लाल भूरे रंग का दिखाई देता है. जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है. आखिरी ब्लड मून 8 नवम्बर, 2022 को दिखाई दिया था. ब्लड मून की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है.

प्रश्न 7. भारत के चन्द्रमा मिशन कार्यक्रम 'चन्द्रयान-3' के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? 8

उत्तर–भारत के तीसरे चंद्र मिशन (चंद्रयान-3) ने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया. इसके साथ, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा (रूस, अमरीका और चीन के बाद) देश बन गया.

चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य हैं–

- इसरो के मुताबिक, 'चंद्रयान-3' 'चंद्रयान-2' का अनुवर्ती (फॉलोऑन) मिशन है. इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है. इसरो ने इस प्रक्रिया को भविष्य के इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए एक अहम पहलू बताया है. इसके अलावा इस मिशन के उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर रोविंग कैपेबिलिटी (घूमने की क्षमता) का प्रदर्शन और इन-सीटू (यथास्थान) वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना भी शामिल है.

इस मिशन के तहत् चंद्रमा की मौलिक संरचना में क्या है, चंद्र सतह के प्लाज्मा का घनत्व कैसा है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज (तापीय गुण) क्या हैं, वहाँ सतह के नीचे की हलचल (भूकम्पीयता) कैसी होती है और रीगोलिथ (चंद्र परत) में क्या कुछ खास है, इन सभी प्रमुख बातों का पता चंद्रयान-3 के जरिये लगाया जाएगा. इसके लिए प्रज्ञान रोवर दो मुख्य उपकरणों इंडयूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS) और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (APXS) से लैस है. एलआईबीएस चंद्र सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों का पता लगाएगा, जिसमें मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्सियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की खोज करना शामिल है. इसके अलावा एपीएक्सएस के जरिए चंद्र सतह की मिट्टी और पत्थरों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाया जाएगा.

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन काफी सफल रहा है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

प्रश्न 8. साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है. इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है ? 8

उत्तर–साइबर अपराध ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कम्प्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क शामिल होता है. प्रमुख साइबर अपराधों में फिशिंग अपराध, गोपनीयता की चोरी, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग आदि. आँकड़ों के अनुसार प्रति दिन 2328 से अधिक हमलों के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि 2023 में लगभग 33 बिलियन खाता उल्लंघनों का सामना करना पड़ेगा.

साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है

- साइबर स्पेस वर्तमान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक कारकों में से एक है. प्रशासन, संचार, व्यापार और व्यावहारिक रूप से दैनिक जीवन की सभी आवश्यक चीजें इंटरनेट के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं. साइबर स्पेस की वास्तविकता आम जनता के लिए एक तरफ उपहार है, लेकिन जब इसका उपयोग गलत इरादे से किया जाता है तो इसे वर्तमान के सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है .
- आज आतंकवादी साइबर स्पेस की प्रगति का उपयोग राष्ट्र राज्यों के शांतिपूर्ण अस्तित्व को बाधित करने के लिए कर रहे हैं. साइबर आतंकवाद किसी देश की सम्पूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर सकता है.
- यह भारत जैसे विकासशील देशों को और अधिक प्रभावित करता है. साथ ही आम लोग इसके खतरे से ठीक से वाकिफ नहीं हैं.
- ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जब कम्प्यूटर सर्वर में रखे गए महत्वपूर्ण डेटा को चुरा लिया गया, गोपनीय डेटा में हेराफेरी की गई , सॉफ्टवेयर वायरस प्रोग्रामों द्वारा हमारे कम्प्यूटरों को संक्रमित किया गया और साइबर अपराधियों ने रक्षा वेबसाइट (आरएंडडी), आयकर विभाग सहित महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया.

साइबर अपराधों से सुरक्षा

व्यापक जन जागरूकता पैदा करके इससे बचा जा सकता है. उदाहरण के लिए, हाल ही में नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है. इसके साथ ही देश में साइबर अपराध से निपटने और लोगों को इसके खतरों से जागरूक कराने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं. इसके मद्देनजर 10 जनवरी 2020 को साइबर अपराध से 'समन्वित और व्यापक' तरीके से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C)' की स्थापना की गई थी. अन्य सुरक्षा उपायों के तहत् साइबर स्पेस नेटवर्क, सम्बन्धित हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर और उनमें निहित जानकारी की सुरक्षा के लिए अपनी तकनीकी क्षमता को भी बढ़ावा देकर इससे बचा जा सकता है.

प्रश्न 9. भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है ? अपने सुझाव दीजिए. 8

उत्तर–भारतीय सुरक्षा बल केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं वर्तमान में कुल सात सुरक्षा बल विभिन्न जिम्मदारियाँ और दायित्वों का निर्हिन करते हैं. इसमें असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITPP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं.

भारत के सुरक्षा बलों को मजबूत करने के सुझाव

- आधुनिक हथियार, उपकरण और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित करके, हम सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस इकाइयों को अद्यतन रख सकते हैं.
- विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन और अनुसंधान पर जोर दें. आधुनिकीकरण प्रयासों में तेजी लाने के लिए दीर्घकालिक रक्षा खरीद नीतियाँ स्थापित करें और

STUDYPDF WALLAH

अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें.

- सुरक्षा बल कर्मियों के कौशल, क्षमताओं और तत्परता में सुधार के लिए निरन्तर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में निवेश करें.
- आतंकवाद–निरोध, साइबर सुरक्षा और असममित युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करें.
- भर्ती और जनशक्ति प्रबंधन
- संयुक्त और एकीकृत संचालन में समग्र प्रभावशीलता में सुधार के लिए सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और समन्वय को बढ़ाना.

निष्कर्षत: ये रणनीतियाँ, जब दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ लागू की जाती हैं, तो भारत के सुरक्षा बलों को मजबूत करने और कई सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की देश की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

प्रश्न 10. आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है ? स्पष्ट कीजिए. 8

उत्तर–भारत सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राथमिकता देता रहा है और इसके लिए प्रतिबद्ध है. भारत परमाणु-बम-मुक्त दुनिया के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है. भारत का मानना है कि इस लक्ष्य को एक सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और एक सहमत वैश्विक और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय ढाँचे द्वारा लिखित चरण-दर-चरण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में निरस्त्रीकरण पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुत 'परमाणु निरस्त्रीकरण' नामक भारत के वर्किंग पेपर में भी उल्लिखित है. जहाँ तक परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (टीपीएनडब्ल्यू) का सवाल है, भारत ने टीपीएनडब्ल्यू पर वार्ता में भाग नहीं लिया और यह स्पष्ट किया है कि वह इस संधि का पक्ष नहीं बनेगा. भारत इस संधि का समर्थन नहीं करता है और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व से बँधा नहीं होगा. भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान या गठन नहीं करती है, न ही यह कोई नए मानक या मानदंड निर्धारित करती है.

हालाँकि, भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) और विखंडनीय सामग्री कट-ऑफ संधि (FMCT) का समर्थन करता है.

उल्लेखनीय है कि भारत ने आत्मरक्षा और प्रतिरोध के आधार पर 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था. भारत के इस कदम की कुछ लोगों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम परमाणु प्रसार में योगदान देता है और एनपीटी को कमजोर करता है. इस आलोचना पर भारत का तर्क है कि उसे अपने विरोधियों, खासकर पाकिस्तान और चीन के परमाणु खतरों का मुकाबला करने और किसी भी आक्रामकता की स्थिति में अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की आवश्यकता है. हालाँकि भारत ने इस सन्दर्भ में 'पहले प्रयोग नहीं' की रणनीति को अपनाया है

खण्ड–ब

प्रश्न 11. नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए. नीति आयोग के सिद्धान्त और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न हैं ? टिप्पणी कीजिए. 12

उत्तर–नीति आयोग की शुरूआत इसके पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से किया गया था. यह देश में सतत् विकास के लिए एक नीति थिंक टैंक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है. नीति आयोग में एक पदेन अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) और एक उपाध्यक्ष के साथ कार्यकारी प्रमुख होता है. इसकी गवर्निंग काउंसिल जिसमें सभी राज्यों और विधान सभाओं वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर) के उपराज्यपाल शामिल हैं.

नीति आयोग के उद्देश्य

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना.
- राज्यों के साथ निरन्तर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं.
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्र करने के लिए तंत्र विकसित करना.
- जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है, उन पर यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है.
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है.
- रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढाँचे और पहलों को डिजाइन करना और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना.
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना.
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना.
- विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अन्तर-क्षेत्रीय और अन्तर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना.
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना.

नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अन्तर

- **कार्य आधारित**–नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके पास राज्यों पर नीतियाँ थोपने की शक्ति नहीं है. योजना आयोग को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों पर नीतियाँ थोपने का अधिकार था.
- **निधि आवंटन**–निधि आवंटन की शक्ति नीति आयोग के पास नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के पास निहित है. योजना आयोग के पास विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी.
- **नीति निर्माण**–नीति आयोग में नीति निर्माण में राज्य सरकारों के साथ परामर्श शामिल होता है. योजना आयोग ने पहले नीतियाँ बनाईं और फिर कार्यक्रमों या परियोजनाओं के लिए धन आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया.

प्रश्न 12. समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए. भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियाँ हैं ? स्पष्ट कीजिए. 12

उत्तर–ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के अनुसार, समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है, जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है.

STUDYPDF WALLAH

समावेशी विकास की अवधारणा—समावेशी विकास के अन्तर्गत समग्र कल्याण, समावेशन, स्थिरता और समान अवसर आदि को केन्द्र में रखा जाता है.

भारत में समावेशी विकास के मुद्दे और चुनौतियाँ

- **गरीबी**—भारत में लगभग 373 मिलियन भारतीय अभी भी गम्भीर गरीबी का सामना कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, 8·8% आबादी गम्भीर बहुआयामी गरीबी में रहती है.
- **बेरोजगारी**—एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, शहरी कार्यबल के बीच बेरोजगारी दर 7·8% है, जबकि ग्रामीण कार्यबल के लिए बेरोजगारी दर 5·3% है, कुल बेरोजगारी दर 6·1% है.
- **कृषि पिछड़ापन**—भारत में लगभग 44% लोगों के पास कृषि से सम्बन्धित रोजगार है, लेकिन भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 16·5% है, जो व्यापक गरीबी का कारण बनता है.
- **कौशल विकास**— यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, कम-से-कम 47% भारतीय युवा 2030 में रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने की राह पर नहीं हैं.

निष्कर्ष

भारत में समावेशी विकास हासिल करना एक जटिल और दीर्घकालिक प्रयास है जिसके लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है. देश की प्रगति में कोई पीछे न रह जाए, इसके लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है.

प्रश्न 13. 'सतत् विकास लक्ष्यों' को प्राप्त करने के लिए भारत में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए. 12

उत्तर—सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) का उद्देश्य हमारी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे विकास को बढ़ावा देना है, जो गरीबी और असमानता को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि को प्राप्त कर सके. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत् विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा को अपनाया है. इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 169 उपलक्ष्य शामिल हैं.

भारत में 'सतत् विकास लक्ष्यों' को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं.

- भारत सरकार की वर्तमान प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने इस सम्बन्ध में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
- नीति आयोग भी देश में 17 एसडीजी में से 13 (राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में तुलनीय डेटा की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को छोड़कर) को सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक एकल मापने योग्य सूचकांक लेकर आया है. यह एसडीजी सूचकांक भारत की प्रगति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करता है.
- यह सूचकांक नीति निर्माण में मदद करता है, क्योंकि यह 62 चुनिंदा संकेतकों के एक सेट में राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों दोनों की स्थिति को दर्शाता है.
- एसडीजी 10 (कम असमानता) और एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन) प्राप्त करने के लिए भारत का विकास पथ अन्य एसडीजी की तुलना में प्रभावशाली है, क्योंकि कई राज्यों ने इन एसडीजी में 100 अंक हासिल किए हैं. .यह पीएमजेडीवाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति और हरित राजमार्ग नीति जैसी योग्य पहलों में प्रदर्शन के कारण हो सका है.

हालाँकि भारत को अभी भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, सभी तक न्याय जैसे पहलों पर विशेष प्रयासों की आवश्यकता है .

प्रश्न 14. "खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद वृहत चुनौतियाँ बनी हुई हैं." भारत के सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए. 12

उत्तर—भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा देश में चिंता का विषय बना हुआ है. उदाहरण के लिए, वर्ष 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को खाद्य सुरक्षा के मामले में 113 प्रमुख देशों में से 68वें स्थान पर रखा गया. साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है.

प्रमुख चुनौतियाँ

- **गरीबी**—विश्व बैंक के अनुसार, 2021 में 13·7% भारतीय राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे हैं.
- **कुपोषण**— राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 के अनुसार, 2019-20 में 5 वर्ष से कम उम्र के 35·5% बच्चे कुपोषित है.
- **जलवायु परिवर्तन**—जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और लू जैसी अधिक गम्भीर मौसमी घटनाएं हो रही हैं. ये घटनाएं फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और कृषि उत्पादकता को कम कर सकती हैं.
- **असमान भूमि वितरण**—2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में शीर्ष 10% भूस्वामियों के पास 57% कृषि भूमि है.
- **भोजन की बर्बादी**—संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, भारत प्रति वर्ष लगभग 68·7 मिलियन टन भोजन बर्बाद करता है.

सुधार के उपाय

- **काम के बदले अनाज कार्यक्रम**—काम के बदले अनाज कार्यक्रम लोगों को सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर उनके श्रम के बदले खाद्यान्न प्रदान करता है.
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना है.
- **पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन**—यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण सम्बन्धी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है.

प्रश्न 15. "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तथा उपभोक्ता की पहुँच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है." कथन की व्याख्या कीजिए. 12

उत्तर—सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के

STUDYPDF WALLAH

वितरण की एक प्रबंधन प्रणाली है. पिछले कुछ वर्षों में, पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है.

महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

- **मूल्य स्थिरता**—पीडीएस मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाता है और अनियमित खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकता है, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों को लाभ पहुँचाता है.
- **ग्रामीण विकास और रोजगार**— यह प्रणाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके कृषि को प्रोत्साहित करती है.
- **गरीबी उन्मूलन**—कम आय वाले परिवारों के लिए भोजन का खर्च कम करने से अन्य आवश्यकताओं के लिए संसाधन मुक्त हो जाते हैं, जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.
- **खाद्य सुरक्षा**—पीडीएस खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है, सबसे कमजोर वर्गों को भी बुनियादी प्रावधानों तक पहुँच की गारंटी देता है, जो गरीबी कम करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं.
- **भूख और कुपोषण में कमी**— खाद्य आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देकर, पीडीएस भूख और कुपोषण को कम करता है, विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं में, जिससे स्वस्थ, अधिक उत्पादक नागरिक बनते हैं.
- **राजनीतिक स्थिरता**—भोजन की पहुँच सुनिश्चित करने से सामाजिक अशांति और कमी या ऊँची कीमतों से जुड़े विरोध प्रदर्शन में कमी आती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता में योगदान होता है.
- **सामाजिक समानता**—कमजोर आबादी को लक्षित करने से यह सुनिश्चित होता है कि जरूरतमंदों को सहायता मिले, जिससे सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा मिलता है.

अंततः कहा जा सकता है कि पीडीएस सरकार के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जो किसानों को अपनी उपज लाभकारी कीमतों पर बेचने में मदद करता है और साथ ही समाज के गरीब वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न खरीदने में मदद करता है.

प्रश्न 16. भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के सन्दर्भ में चर्चा कीजिए. 12

उत्तर—1·3 अरब की आबादी के साथ, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की भारी माँग है. आजादी के समय बिजली की कमी वाले देश से भारत को ऊर्जा-स्वतंत्र बनाने के प्रयास सात दशकों से अधिक समय से जारी हैं. वर्तमान में हम 4 लाख मेगावाट से अधिक की कुल स्थापित बिजली क्षमता के साथ एक बिजली अधिशेष राष्ट्र हैं.

सतत् विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, भारत का बिजली उत्पादन मिश्रण तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक महत्वपूर्ण हिस्से. दारी की ओर बढ़ रहा है. आज, भारत नवीकरणीय ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसकी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है.

आजादी के समय एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत अपनी ऊर्जा माँगों को पूरा करने के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर था. हालाँकि, भारत हमेशा सतत् विकास के लिए अधिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश के लिए प्रतिबद्ध रहा है. शुरूआत जलविद्युत् से की गई थी, जिसमें प्रमुख जलविद्युत् परियोजनाएं भारत के ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई दे रही थीं. पिछले कुछ वर्षों में, कई नीति और नियामक पहलों ने जलविद्युत् विकास को बढ़ावा दिया है और निवेश की सुविधा प्रदान की है. आज हम अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित) में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है. पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है, ओर सौर ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है.

भारत ने धीरे-धीरे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग कर दिया है. उदाहरण के लिए, अकेले भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य से उत्सर्जन में सालाना 60 मिलियन टन की कमी आएगी. इसी तरह, भारत का विशाल उजाला एलईडी बल्ब अभियान सालाना 40 मिलियन टन उत्सर्जन कम कर रहा है. इन चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन केन्द्र बनाने के लिए 2013 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया.

भारत के निरन्तर प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन वैश्विक औसत से बहुत कम है. अमरीका प्रति व्यक्ति 14·7 टन उत्सर्जन करता है, चीन प्रति व्यक्ति 7·6 टन उत्सर्जन करता है, जबकि भारत का CO_2 उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 1·8 टन है.

तकनीकी नवाचारों और जलवायु परिवर्तन प्रोटोकॉल पर प्रतिक्रिया के कारण वैश्विक बिजली क्षेत्र त्वरित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. 2015 में पेरिस में COP21 में, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन में 40% हिस्सेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई. हमने यह लक्ष्य 2030 की समय सीमा से एक दशक पहले ही हासिल कर लिया है.

भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नेतृत्व में हमेशा अपनी इच्छा दिखाई है. देश का लक्ष्य अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अलावा, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है, जिसमें शामिल हैं—

- 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाना,
- ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना,
- 2030 तक संचयी उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी और
- 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना.

प्रश्न 17. जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियाँ कौनसी हैं ? इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी? 12

उत्तर—जैव प्रौद्योगिकी उद्योग ने एक अरब डॉलर के अनुसंधान एवं विकास खर्च को पार कर लिया है और यह 2020 में 320 मिलियन डॉलर से एक वर्ष के भीतर लगभग तीन गुना होकर 2022 में 1·02 बिलियन डॉलर हो गया है. पिछले 3 वर्षों में भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 56 पेटेंट दाखिल/अनुदान किए गए हैं. बढ़ते सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के कारण, पिछले 10 वर्षों में देश में बायोटेक स्टार्ट-अप की संख्या 50 से बढ़कर 5,300 से अधिक हो गई है. सरकार का लक्ष्य 2025 तक मजबूत प्रतिभा पूल से उत्पन्न होने वाले बायोटेक स्टार्ट-अप को 2 गुना बढ़ाकर 10,000 से अधिक करना है.

- भारत अब कई प्रगति के साथ वैक्सीन निर्माण और विकास में अग्रणी है.
- डीबीटी ने एक अभिनव नवजात श्रवण जाँच उपकरण 'सोहम' लॉन्च किया.
- 'बायोटेक-किसान' नामक एक नए, किसान-केन्द्रित कार्यक्रम की घोषणा की गई, जो ग्रामीण आजीविका पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा.

गरीबों के उत्थान पर प्रभाव

- **उन्नत कृषि**—बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास में विभिन्न फसलों

STUDYPDF WALLAH

की पोषण सामग्री में सुधार के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है. जेनेटिक इंजीनियरिंग विटामिन की उच्च सांद्रता वाली फसलें पैदा कर सकती है.

- **किफायती स्वास्थ्य देखभाल**—चिकित्सा उद्योग और फार्मास्युटिकल उद्योगों की तरह जैव प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य में व्यापक अनुप्रयोग पाया है. चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी-जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के तरीकों का उपयोग एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन (जैसे इंटरफेरॉन और इंसुलिन), एंजाइम, विटामिन, टॉक्सोइड्स आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है.
- **जैव ईंधन**—अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विपरीत, परिवहन ईंधन की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए बायोमास को सीधे तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे 'जैव ईंधन' कहा जाता है.
- पर्यावरणीय स्थिरता
- रोजगार एवं कौशल विकास
- रोग प्रबंधन

प्रश्न 18. प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अन्तर स्पष्ट करें. साथ ही, भारत में आपदा प्रबन्धन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करें. 12

उत्तर—आपदाएं प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती हैं, जो सामान्य जीवन में गम्भीर व्यवधान डालती हैं. आपदाएं प्राकृतिक, मानव निर्मित और तकनीकी खतरों के साथ-साथ विभिन्न कारकों के कारण हो सकती हैं, जो किसी समुदाय के जोखिम और भेद्यता को प्रभावित करते हैं.

- **मानव निर्मित आपदाएं**—प्राकृतिक खतरों के परिणामस्वरूप होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत, मानव निर्मित आपदाओं में मानव इरादे, लापरवाही या मानव निर्मित प्रणाली की विफलता से जुड़ी त्रुटि का तत्व होता है. ऐसी मानव निर्मित आपदाएं अपराध, आगजनी, नागरिक अव्यवस्था, आतंकवाद, युद्ध, जैविक/रासायनिक खतरा, साइबर हमले आदि हैं.
- **प्राकृतिक आपदा**—प्राकृतिक आपदा प्रकृति में एक अचानक और भयावह घटना है (जैसे कि तूफान, बवंडर या बाढ़) जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर गम्भीर आर्थिक और मानवीय क्षति होती है.

भारत में आपदा

भारत दक्षिण एशिया में खतरे की आशंका वाले देशों में से एक है. बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बर्फीला तूफान, तूफान और चक्रवात नियमित रूप से आते रहते हैं. इनमें भूकम्प, बाढ़ और सूखे का खतरा बेहद ज्यादा है.

भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली

संस्थागत और नीतिगत ढाँचा—राष्ट्रीय स्तर पर, गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन से सम्बधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है.

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी)
- आपदा प्रबंधन समूह.
- नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन परिचालन कक्ष)
- आकस्मिक कार्य योजना
- राज्य राहत मैनुअल फंडिंग तंत्र

प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली—भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सम्बन्ध में निगरानी करने और चेतावनी देने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही वर्तमान में देश में विभिन्न नदियों पर 166 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन हैं जिनमें 134 स्तरीय पूर्वानुमान और 32 नदी-वार प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशन शामिल हैं.

आपदा की रोकथाम और शमन—संवेदनशीलता में कमी लाने और आपदाओं के प्रति त्वरित पेशेवर प्रतिक्रिया के लिए शमन और तैयारी के उपाय साथ-साथ चलते हैं. भारत सरकार ने शमन और रोकथाम को अपनी विकास रणनीति के आवश्यक घटकों के रूप में अपनाया है. दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय है.

राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

पहचाने गए बहु-खतरे वाले आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति समुदायों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए 'आपदा जोखिम प्रबंधन' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अगस्त 2002 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. यह लक्ष्य है, प्राकृतिक आपदा जोखिम में सतत् कमी भारत के चयनित राज्यों में सबसे अधिक खतरा प्रवण जिलों में से कुछ ".

प्रश्न 19. "अवैध धन स्थानान्तरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गम्भीर खतरा है. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है." व्याख्या कीजिए. 12

उत्तर—इंटरपोल के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान छिपाना है ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वे वैध स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग किसी देश की आर्थिक सम्प्रभुता के लिए एक गम्भीर खतरा है.

- राजस्व की हानि सरकार को ई जिसके कारण सामाजिक सेवाओं को नुकसान होता है.
- अवैध धन के पंपिंग के कारण अर्थव्यवस्था की अप्रत्याशितता बढ़ रही है.
- अर्थव्यवस्था की स्थिरता को खतरा.
- देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न होता है.
- माप त्रुटि और संसाधनों के गलत आवंटन के कारण नीति विरूपण होता है.
- विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करता है.
- कर चोरी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है.
- विनिमय और ब्याज दरों में अस्थिरता का परिणाम.
- कानूनी लेन-देन को दूषित करता है.
- मनी लॉन्ड्रिंग से अर्थव्यवस्था में संग्रह के लिए उपलब्ध कर निधि और सरकार के राजस्व में कमी आती है.
- आर्थिक शक्ति को सही लोगों से गलत लोगों को हस्तांतरित करने में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करना. अच्छे नागरिकों और सरकार को उनके अधिकारों से बेदखल कर दिया जाता है, जिसका फायदा अपराधी अपनी आपराधिकता को फलने-फूलने में उठाते हैं.
- स्थानीय स्तर पर संगठित अपराध पनप सकता है.
- इससे व्यवसाय करने की लागत भी बढ़ जाती है.

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है

- **स्मर्फिंग**—यह प्लेसमेंट की एक विधि है जिसके तहत् नकदी को पैसे की छोटी जमाओं में तोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए कई व्यक्तियों (जिसे 'स्मर्फ्स' के रूप में जाना जाता है) द्वारा एक्सचेंज किया जाता है. इसे स्मर्फिंग इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई व्यक्ति (स्मर्फ्स) शामिल होते हैं.
- **शैल कम्पनियाँ**—ये ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनका व्यवसाय संचालन सक्रिय नहीं है. वे कथित वस्तुओं या सेवाओं के लिए 'भुगतान' के रूप में गंदा पैसा लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई सामान या सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं; वे केवल नकली चालान और बैलेंस शीट के माध्यम से वैध लेन-देन का दिखावा करते हैं.
- **तृतीय-पक्ष चेक**—विभिन्न संस्थानों पर आहरित काउंटर चेक या बैंकर ड्राफ्ट का उपयोग और भुगतान विभिन्न तृतीय-पक्ष खातों के माध्यम से किया जाता है. चूँकि

STUDYPDF WALLAH

ये कई देशों में परक्राम्य हैं, इसलिए स्रोत धन के साथ सांठगांठ स्थापित करना मुश्किल है.

- **थोक नकदी तस्करी**—इसमें भौतिक रूप से किसी अन्य क्षेत्राधिकार में नकदी की तस्करी करना और इसे अधिक बैंक गोपनीयता या कम कठोर मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन के साथ एक अपतटीय बैंक जैसे वित्तीय संस्थान में जमा करना शामिल है.
- **क्रेडिट कार्ड**—विभिन्न बैंकों के काउंटरों पर क्रेडिट और चार्ज कार्ड की शेष राशि साफ करना. ऐसे कार्डों के कई उपयोग होते हैं और इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी इस्तेमाल किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, सम्पत्ति खरीदने के लिए, प्राप्त सेवाओं या वस्तुओं के भुगतान के लिए या नकदी-वितरण मशीनों के वैश्विक नेटवर्क में.

अंततः कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भारत की आर्थिक सम्प्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन देश ने पीएमएलए के अधिनियमन और अन्य उपायों के माध्यम से इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं. अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों को और मजबूत करने के लिए, भारत को अपने नियामक ढाँचे में सुधार करने, सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने और अपनी पहचान और रोकथाम क्षमताओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए.

प्रश्न 20. भारत तथा विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं? राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है ? 12

उत्तर—मीडिया क्रांति हाल के मीडिया इतिहास में मास मीडिया की संस्कृति से सोशल मीडिया में परिवर्तन की प्रक्रिया है. मास मीडिया के युग में, 1950 के दशक से 20वीं सदी के अन्त तक टीवी संस्कृति के उदय तक, मीडिया का लोगों के दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा.

सकारात्मक परिवर्तन

- भारतीय मीडिया की वैश्विक पहुँच अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रभाव और भूमिका को बढ़ाती है.
- मीडिया और मनोरंजन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, नौकरियाँ पैदा करता है और विकास को प्रोत्साहित करता है.
- क्रांति ने सूचना तक पहुँच को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे लोगों को आसानी से समाचार और विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है.
- नागरिकों को राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी दी जाती है, जिससे एक सुविज्ञ नागरिक वर्ग को बढ़ावा मिलता है.
- सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता व्यक्तियों को घटनाओं की रिपोर्ट करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है.

नकारात्मक परिवर्तन

- झूठी सूचना तेजी से फैलती है, जिससे जनता में दहशत, सामाजिक अशांति और नुकसान होता है.
- कुछ रिपोर्टिंग चैनल अपने निजी हित और टीआरपी के लिए बिना तथ्यों के झूठी खबरों को प्रसारित कर देते हैं. जिससे पूर्वाग्रह और उन्माद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
- व्यक्तिगत डेटा तक आसान पहुँच डेटा उल्लंघनों और दुरुपयोग सहित गोपनीयता सम्बन्धी चिंताओं को बढ़ाती है.
- मीडिया विशिष्ट विचारधाराओं को बढ़ावा देकर, प्रतिध्वनि कक्षों को बढ़ावा देकर राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है.

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया की भूमिका

राष्ट्रीय सुरक्षा

- मीडिया किसी संकट के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाता है जो सार्वजनिक समझ और अधिकारियों के संचार में सहायता करता है.
- एक प्रहरी के रूप में, मीडिया पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए सरकारी कार्यों और नीतियों की जाँच करता है.
- मीडिया जागरूकता बढ़ाता है, आतंकवादी गतिविधियों पर रिपोर्ट करता है, और आतंकवाद से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करता है.

अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा

- मीडिया अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों, कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा को कवर करता है, जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करता है.
- मीडिया देशों के लिए विदेश नीति की स्थिति को संप्रेषित करने और अन्तर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित करने के लिए एक राजनयिक उपकरण के रूप में कार्य करता है.
- अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों के तहत् मीडिया संघर्ष समाधानों में सहायक और शांति प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाता है.

●●●

शेष पृष्ठ 115 का

120. जब Microsoft Excel वर्कशीट के प्रकोष्ठों (सेल्स) में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं, तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति (बाई डिफॉल्ट) द्वारा ..... होती हैं. – ***बाईं ओर संरेखित***

विविध

121. कश्मीर की महिला संत लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थीं ?
– ***कश्मीरी शैव धर्म***

122. सुप्रसिद्ध चित्र 'बणी-ठणी' किस शैली का है ? – ***किशनगढ़ शैली***

123. हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं ? – ***पश्चिम बंगाल***

124. एलीफैंटा की गुफाएं किस हिन्दू देवता को समर्पित हैं ? – ***शिव को***

125. उस स्थान का नाम बताइए, जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से 'त्यागराज आराधना त्योहार' मनाया जाता है – ***तंजावूर***

126. हिन्दी के पश्चात् भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है
– ***बांग्ला***

127. बैशाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है ?
– ***खालसा पंथ की स्थापना***

128. महाबलीपुरम में पल्लव शैली के पाँच एक चट्टानी रथ मन्दिरों में से सबसे बड़ा किसका है ? – ***धर्मराज***

129. अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थीं ? – ***एलिनार ओस्ट्रॉम***

130. केरल में विषु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है ?
– ***केरल में विषु नामक त्यौहार अप्रैल माह में मनाया जाता है***

●●●

STUDYPDF WALLAH

अर्थशास्त्र

1. यदि $x + y + z = 1$ है, तो $u = x^2 + y^2 + z^2$ का इष्टम मान ज्ञात करें–

(A) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

(B) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$

(C) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

(D) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

2. निम्नलिखित में से कौन-कौनसे प्रतिगमन मॉडल में भू-संरेखियता के लक्षण नहीं हैं ?

(a) हाई R^2 के साथ कुछ आकलन के महत्वपूर्ण t अनुपात.

(b) प्रतिगमनकर्ताओं में उच्च पैरावार सहसम्बन्ध.

(c) टोलरेंस (TOLj) शून्य के करीब होता है.

(d) चर के भिन्नता मुद्रास्फीति कारक (VIF) 10 से कम होता है.

(e) टोलरेंस (TOLj) एक के करीब होता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (c) और (d)

(B) केवल (d) और (e)

(C) केवल (a) और (c)

(D) केवल (b) और (d)

3. वालरैसियन प्रकार्य के बारे में निम्नलिखित में कौन-कौनसा/से सही है/हैं ?

(a) यदि किसी P, W और $a > 0$ के लिए X (aP, aW) = X (P, W) है, तो वालरैसियन माँग प्रकार्य X (P, W) शून्य डिग्री के सजातीय है.

(b) यदि किसी P, W और $a > 0$ के लिए X (aP, aW) = X (P, W) है, तो वालरैसियन प्रकार्य X (P, W) डिग्री एक के सजातीय है.

(c) यदि प्रत्येक $p >> 0$ और $w > 0$ के लिए हमारे पास सभी $X \in X$ (P, W) के लिए PX = W है, तो वालरैसियन माँग प्रकार्य वालरैसियन नियम को संतुष्ट करता है.

(d) वालरस का नियम कहता है उपभोक्ता अपनी सम्पदा पूरे तरह खर्च करता है.

(e) यदि कीमत और सम्पदा दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, तो व्यक्तिगत खपत विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं होता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b), (c), (d)

(B) केवल (b), (c), (d), (e)

(C) केवल (a), (b), (c), (e)

(D) केवल (a), (c), (d), (e)

4. वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों के आधार पर राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(a) कर्नाटक (b) मध्य प्रदेश

(c) तमिलनाडु (d) गुजरात

(e) महाराष्ट्र

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (c), (b), (d), (a), (e)

(B) (b), (c), (d), (a), (e)

(C) (c), (b), (a), (d), (e)

(D) (b), (c), (a), (d), (e)

5. कल्याणकारी अर्थशास्त्र के दूसरे सिद्धांत के मामले में निम्नलिखित में से कौनसा सही नहीं है ?

(A) यदि उपभोक्ता उत्तम विकल्प प्रदर्शित करते हैं, तो प्रत्येक पैरिटो दक्ष आबंटन विशुद्ध विनिमय अर्थव्यवस्था में सम्भव प्रतिस्पर्धा संतुलन होता है

(B) किसी उत्पादन वाली अर्थव्यवस्था में उत्पादन सेट की उत्तलता यह सुनिश्चित करती है कि पैरिटो दक्ष आबंटन को बाजार संतुलन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है

(C) यह लागू होता है, तब पैमाने के अनुसार उत्तरोत्तर प्रतिफल प्राप्त हो

(D) इसका अर्थ है कि बाजार प्रणाली में आबंटन भूमिका और वितरण भूमिका को परस्पर पृथक् किया जा सकता है

6. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : प्रथम डिग्री मूल्य अन्तर के अन्तर्गत एकाधिकारवादी उत्पाद की अलग-अलग इकाइयों को अलग-अलग मूल्यों पर बेचता है और ये मूल्य व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न हो सकता है.

कथन II : तृतीय डिग्री मूल्य अन्तर के अन्तर्गत एकाधिकारवादी उत्पाद की अलग-अलग इकाइयों को अलग-अलग मूल्यों पर बेचता है, लेकिन उत्पाद की सामान मात्रा खरीदने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामान मूल्य अदा करता है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) कथन I और II दोनों सही हैं

(B) कथन I और II दोनों गलत हैं

(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : फ्रीडमैन का धन की माँग का सिद्धांत आंशिक रूप से कीन्स समर्थकों और आंशिक रूप से गैर-कीन्स समर्थकों का सिद्धांत है.

कारण (R) : गैर-कीन्स समर्थकों में फ्रीडमैन कीन्स के धन रखने के प्रयोजनों के वर्गीकरण और धन की तदनुरूपी घटक माँगों को पूरी तरह नकारता है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(C) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है

(D) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

8. एल.एम. शेड्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

(A) एल. एम. शेड्यूल दायीं ओर ऊपर की ओर खिसकती है

(B) यदि धन की माँग की ब्याज लोच सापेक्ष रूप में अधिक (कम) होती है, तो एल.एम. शेड्यूल सापेक्ष रूप से समतल (खड़ी) होगी

(C) धन की मात्रा में वृद्धि होने पर एल.एम. शेड्यूल दायीं (बायीं) ओर नीचे (ऊपर) की ओर खिसकती है

(D) एल.एम. शेड्यूल वह शेड्यूल होते हैं, जिसमें निवेश के मान और ब्याज दर का संयोजन होना है जिसकी वजह से मुद्रा बाजार में संतुलन पैदा होता है

STUDYPDF WALLAH

9. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I

(a) कर चोरी
(b) प्रभावी कर भार
(c) विधि कर भार
(d) राजकोषीय विभ्रम

सूची-II

1. बॉण्ड वित्त प्रबन्धन
2. अनधिकृत मुफ्तखोर
3. सरकार को कर राजस्व प्रदान करने के लिए बाध्य
4. यह आवश्यक नहीं कि जिस पर कर लगाया गया है वह उसके अनुरूप हो

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	4	1
(B)	3	1	2	4
(C)	2	4	3	1
(D)	4	3	2	1

10. रॉबिन्सन के अनुसार हैरॉल्ड-डोमर मॉडल के संदर्भ में 'स्वर्ण युग' (गोल्डेन एज) शब्द का निम्नलिखित किस पर बल देने हेतु प्रयुक्त होता है ?

(A) इसके मिथकीय (काल्पनिक) प्रकृति पर
(B) इसकी श्रेष्ठता पर
(C) प्राकृतिक संवृद्धि दर पर
(D) अपेक्षित संवृद्धि दर पर

11. वर्ष 2021-22 में वस्तुओं के घरेलू आपूर्ति और सेवाओं पर जीएसटी के शीर्ष के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्यों को प्राप्त कुल राजस्व के आधार पर राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(a) ओडिशा (b) राजस्थान
(c) दिल्ली (d) पश्चिम बंगाल
(e) मध्य प्रदेश

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (d), (c), (e), (b), (a)
(B) (e), (b), (a), (c), (d)
(C) (b), (e), (c), (a), (d)
(D) (c), (e), (a), (d), (b)

12. ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) में सेवा क्षेत्र के घटक कौन-कौनसे हैं ?

(a) निर्माण
(b) व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण सम्बन्धी संचार
(c) बिजली, गैस जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवाएं
(d) लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं
(e) वित्तीय, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (b), (c) और (e)
(B) केवल (a), (b) और (c)
(C) केवल (a), (b), (d) और (e)
(D) केवल (a), (b), (c) और (e)

13. यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं. निम्नलिखित में से कौन-कौनसे संस्थाओं और उनके मुख्यालयों के सही संयोजन हैं ?

(a) GATT : जेनेवा
(b) IMF : वाशिंगटन डी सी
(c) विश्व बैंक : वाशिंगटन डी सी
(d) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) : न्यूयॉर्क
(e) एशियन विकास बैंक : मंडालुयांग

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b) और (c)
(B) केवल (a) और (b)
(C) केवल (c) और (d)
(D) केवल (a), (b), (c) और (e)

14. 1990 के दशक के पूर्वार्ध में भुगतान संतुलन (BOP) संकट के चलते भारत को निम्नलिखित शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार लेना पड़ा–

(a) रुपए का 22% अवमूल्यन
(b) सभी वस्तुओं के लिए 130% के तत्कालीन स्तर से 30% पर उच्चतम शुल्क में सीमा शुल्क में भारी कटौती
(c) सभी अप्रत्यक्ष करों का एक कर में आमेलन
(d) सीमा शुल्क कटौती के कारण राजस्व घाटे को निष्क्रिय करने के लिए उत्पाद शुल्क में 20% की वृद्धि की जाएगी.
(e) सरकारी व्यय में 10% वार्षिक की कटौती की जाएगी.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b), (c), (e)
(B) केवल (b), (c), (d), (e)
(C) केवल (c), (d), (e), (a)
(D) केवल (a), (b), (d), (e)

15. रैनडम वॉक बिना ड्रिफ्ट के में–

(A) प्रघात का प्रभाव पूरी समयावधि में बना रहता है
(B) प्रघात का प्रभाव समयांतर में समाप्त हो जाता है
(C) प्रघात का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है
(D) पिछले प्रघात का कोई प्रभाव नहीं होता है

16. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (नीति)

(a) राष्ट्रीय वन नीति
(b) समुद्र मत्स्य ग्रहण नीति
(c) नई खनिज लवण नीति
(d) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

सूची-II (वर्ष)

1. 2000 2. 1994
3. 2004 4. 1988

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	3	2	1
(B)	4	2	3	1
(C)	2	4	3	1
(D)	2	3	4	1

17. जब एमपीएस 0·25 और स्वायत्त खर्च में प्रारम्भिक वृद्धि 100 है, तो खर्च गुणांक और जीडीपी में परिणामी वृद्धि क्रमशः होगी–

(A) 1, 100 (B) 0·75, 75
(C) 4, 400 (D) 1·33, 133

18. F-test के सांख्यिकीय के लिए वैकल्पिक फॉर्मूले नीचे दिए गए हैं. हम $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + U$ में 5% महत्व स्तर पर X_3 के उत्तरोत्तर योगदान सांख्यिकीय महत्व की जाँच करना चाहते हैं. इसमें कौनसा उपयुक्त नहीं है जहाँ RSS का मतलब रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है और ESS का मतलब एक्सप्लैंड सम ऑफ स्क्वायर है ?

(A) $F = \dfrac{R^2_{UR} - R^2_R/d.f.}{(1 - R^2_{UR})/d.f.}$

(B) $F = \dfrac{ESS/d.f.}{RSS/d.f.}$

(C) $F = \dfrac{ESS_{new} - ESS_{old}/d.f.}{ESS_{new}/d.f.}$

(D) $F = \dfrac{R^2/d.f.}{(1 - R^2)/d.f.}$

19. सृजनात्मक विनाश (ध्वंस) का विचार निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है ?

(A) मार्क्स (B) एडम स्मिथ
(C) रिकार्डो (D) शुम्पिटर

20. आर्थिक समेकन की मात्रा (डिग्री) के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(a) सीमा संघ
(b) मुक्त व्यापार क्षेत्र
(c) आर्थिक संघ
(d) समान बाजार
(e) अधिमान्य व्यापार व्यवस्था क्रम

STUDYPDF WALLAH

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (a), (b), (c), (d), (e)
(B) (b), (c), (d), (a), (e)
(C) (e), (a), (b), (c), (d)
(D) (e), (b), (a), (d), (c)

21. निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर पुरातन से आरम्भ करके अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–
(a) भारतीय औद्योगिकीय ऋण और निवेश निगम (आईसी-आईसीआई).
(b) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड).
(c) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई).
(d) भारतीय औद्योगिकीय पुनर्गठन बैंक (आईआरबी).
(e) भारतीय निर्यात-आयात बैंक.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (a), (c), (e), (b), (d)
(B) (c), (a), (d), (e), (b)
(C) (e), (c), (a), (b), (d)
(D) (a), (d), (c), (b), (e)

22. कोई प्रशुल्क अधीन प्रस्तावक किस ओर झुकेगा ?
(A) आयात वस्तु अक्ष
(B) निर्यात वस्तु अक्ष
(C) मूल (उत्पत्ति)
(D) उपर्युक्त में से किसी भी एक की ओर

23. चौदहवें वित्त आयोग द्वारा समनुदेशित निम्नलिखित मापदंड के सापेक्षिक भारों को प्रतिशत में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए–
(a) आय दूरी
(b) क्षेत्रफल
(c) जनसंख्या (1971)
(d) जननांकीय परिवर्तन (2011 की जनसंख्या)
(e) वन क्षेत्र
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (b), (e), (d), (c), (a)
(B) (e), (d), (b), (c), (a)
(C) (a), (c), (d), (b), (e)
(D) (e), (b), (d), (c), (a)

24. प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के कौनसे राज्य का 2018–20 के दौरान आजीवन जोखिम स्तर सबसे ऊँचा है ?
(A) बिहार (B) उत्तर प्रदेश
(C) मध्य प्रदेश (D) छत्तीसगढ़

25. क्लार्क-विक्सटीड-वालरस के उत्पाद क्षय थ्योरम के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?
(a) समरूपी उत्पादन प्रकार्य की अवधारणा आवश्यक है.
(b) यह एक पहचान है, जो चरों के प्रतिमानों के लिए सही है.
(c) समरूपी उत्पादन प्रकार्य की अवधारणा आवश्यक नहीं है.
(d) यह एक पहचान नहीं है, क्योंकि यह दीर्घावधिक संतुलन के प्रतिमानों के लिए ही सही है.
(e) यह सभी प्रकार के उत्पादन प्रकार्यों के लिए सही है.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a) और (b)
(B) केवल (a) और (d)
(C) केवल (b), (c) और (e)
(D) केवल (c), (d) और (e)

26. मौद्रिक नीति में त्रिविद्या के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
(a) यह बंद अर्थव्यवस्था मॉडल से सम्बन्धित है.
(b) इसमें मुद्रा दर पूँजीगत संघटन और मौद्रिक नीति शामिल है.
(c) इसके उत्पनन होने के कारण यह है कि पूँजीगत संघटन घरेलू ब्याज दर और विश्व ब्याज दर से मेल खाता है.
(d) लचीली विनिमय दर का स्वतंत्र मौद्रिक नीति के साथ सामंजस्य है.
(e) यह पूँजीगत असंवरनता और लचीली विनिमय दर से सम्बन्धित है.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (b) और (c)
(B) केवल (c) और (d)
(C) केवल (a) और (d)
(D) केवल (b) और (e)

27. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I राज्य	**सूची-II खाद्यान्न उत्पादन (2021-22) (हजार टन)**
(a) तेलंगाना	1. 11266·0
(b) झारखण्ड	2. 4984·2
(c) छत्तीसगढ़	3. 8897·0
(d) आंध्र प्रदेश	4. 15095·4

अग्रलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	4	3	2	1
(C)	1	3	4	2
(D)	4	2	3	1

28. एडम स्मिथ का योगदान क्या-क्या है ?
(a) श्रम विभाजन
(b) बढ़ते प्रतिफलों का सिद्धांत
(c) घटते प्रतिफलों का सिद्धांत
(d) भाषायी भौतिकवाद
(e) सामाजिक रूप से आवश्यक सारगर्भित श्रम समय
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a) और (b)
(B) केवल (a) और (c)
(C) केवल (a) और (d)
(D) केवल (a) और (e)

29. मितव्यय-विरोधाभास के बारे में निम्नलिखित में से कौनसे सही हैं ?
(a) मितव्यय-विरोधाभास को जे. एम. कीन्स ने लोकप्रिय बनाया था.
(b) इसमें उल्लेख है कि व्यक्तिगत बचतें समग्र आर्थिक विकास के लिए बाधक हैं.
(c) इसमें उत्पाद वृद्धि और बेरोजगारी दर के बीच के सम्बन्ध को दर्शाया जाता है.
(d) इसमें मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच के सम्बन्ध को दर्शाया जाता है.
(e) इसमें उल्लेख है कि आर्थिक मंदी के दौरान व्यक्तिगत बचत के कारण औसत माँग में कमी आती है.
(A) केवल (a), (b), (c)
(B) केवल (b), (c), (d)
(C) केवल (c), (d), (e)
(D) केवल (a), (b), (e)

30. समुच्चय सिद्धांत के मामले में निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?
(a) $(A \cup B') \cap (A' \cup C) \cap (B \cup C') = (A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)$
(b) $(A \cup B') \cap (A' \cup C) \cap (B \cup C') = (A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)'$
(c) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
(d) $A \cap (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
(e) $(A \cup B') \cap (A' \cup C) \cap (B \cup C') = (A \cap B \cap C) \cup (A' \cup B' \cup C')$
आगे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

STUDYPDF WALLAH

(A) केवल (a), (c), (e)
(B) केवल (b), (d), (e)
(C) केवल (b), (c), (e)
(D) केवल (a), (b), (d)

31. बैसल III प्रतिमानों के पिल्लर I में किस पर ध्यान दिया गया ?
(a) पूँजी की गुणवत्ता और स्तर
(b) जोखिम आच्छादन
(c) उत्तोलन पर लगाम लगाना
(d) जोखिम प्रबन्धन और पर्यवेक्षण
(e) बाजार अनुशासन
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a) और (b)
(B) केवल (b) और (c)
(C) केवल (c) और (d)
(D) केवल (d) और (e)

32. व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर में क्या माँग की गई थी ?
(a) औद्योगिक सामान पर औसत प्रशुल्क में कटौती.
(b) प्रशुल्कों के स्थान पर कोटा तय किया जाए.
(c) कृषि निर्यात सब्सिडी में कटौती.
(d) औद्योगिक सब्सिडी में कटौती.
(e) एंटी डम्पिंग और सुरक्षा उपायों में ढील दी जाए.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a), (b), (c), (d)
(B) केवल (b), (c), (d), (e)
(C) केवल (c), (d), (e), (a)
(D) केवल (d), (e), (a), (b)

33. किसी कम्पनी में 140 कर्मचारी हैं, जिनमें से 30 सुपरवाइजर हैं. 80 कर्मचारी विवाहित हैं और 20% विवाहित कर्मचारी सुपरवाइजर हैं. यदि कम्पनी के एक कर्मचारी का औचक रूप से चयन है, तो क्या प्रायिकता है कि कर्मचारी विवाहित हो और सुपरवाइजर हो ?
(A) 0·1531 (B) 0·1253
(C) 0·0923 (D) 0·1143

34. निवेश के टोबिन Q सिद्धांत के अनुसार, किसी फर्म को निवेश कब करना चाहिए ?
(a) जब उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो.
(b) जब पूँजी के सीमान्त उत्पादन में वृद्धि हो.
(c) जब ब्याज दर में वृद्धि हो.
(d) जब मूल्य ह्रास दर में कमी हो.
(e) जब निवेश का सीमांत लाभ सीमांत लागत से अधिक हो.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (b), (c), (d), (e)
(B) केवल (a), (b), (d), (e)
(C) केवल (a), (b), (d), (e)
(D) केवल (a), (b), (c), (d)

35. निम्नलिखित में से किन कथनों द्वारा 'बहुत संवेदशीलता' और 'बहुल सुगमता' की अवधारणाओं का आभास होता है ?
(a) 'बहुल संवेदनशीलता' वह आस्था है जहाँ खपत अस्थायी आय परिवर्तनों से अधिक प्रभावित होती है.
(b) 'बहुल सुगमता' वह अवस्था है जहाँ खपत अस्थायी आय परिवर्तनों से कम प्रभावित होती है.
(c) बहुल संवेदनशीलता आय में प्रत्याशित वृद्धि का सम्बन्ध खपत में सापेक्ष रूप से होने वाला मामूली परिवर्तन है.
(d) बहुल सुगमता के कारण औसत आय में होने वाले परिवर्तनों का सम्बन्ध खपत में सापेक्ष रूप से होने वाले व्यापक परिवर्तनों से है.
(e) 'बहुल संवेदनशीलता' और 'बहुल सुगमता' का सम्बन्ध स्थायी आय प्राक्कल्पना के प्रयोगाश्रित साक्ष्यों से है.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a), (b), (c), (d)
(B) केवल (a), (b), (c), (e)
(C) केवल (a), (b), (d)
(D) केवल (a), (b), (e)

36. ग्लासगोव, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-26) के 26वें सत्र में लिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कौन-कौनसे कथन जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारत की रणनीति का हिस्सा है ?
(a) 2030 तक कोयला आधारित तापीय ऊर्जा उत्पादन को बंद करना.
(b) भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्बन घनत्व में 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक 45% तक की कटौती करना.
(c) भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल अंतिम ऊर्जा खपत को निरपेक्ष स्तरों पर रोकना.
(d) भारत के लिए 2070 तक निबल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना.
(e) जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पर्यावरण हेतु जीवन शैली को बढ़ाना.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a), (b), (d)
(B) केवल (b), (c), (d)
(C) केवल (b), (d), (e)
(D) केवल (c), (d), (e)

37. टैलर नियम क्या बताता है ?
(A) आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दर कैसे निर्धारित करता है
(B) मौद्रिक प्राधिकरण बैंक दर कैसे कायम रखता है
(C) मौद्रिक प्राधिकरण विनिमय दर कैसे कायम रखता है
(D) कर आधार में वृद्धि करने के लिए सरकार कर दर कैसे निर्धारित करती है

38. निम्नलिखित में से कौनसा एक मुद्रा बाजार का निरूपण (प्रतिनिधित्व) करने वाला एक समीकरण हो सकता है ?
(A) $300 = 2Y - 1{\cdot}5i$
(B) $i = 150 - Y$
(C) $Y = 100 - i$
(D) $i = (150 - 2Y)/2$

39. अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग (आईएलएस) के आकलन अनुमान के निम्नलिखित चरणों को आरम्भिक चरण से आरम्भ करके सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–
(a) संरचनात्मक समीकरणों की पहचान
(b) ओएलएस का अनुप्रयोग
(c) संरचनात्मक गुणांक प्राप्त करना
(d) समीकरण का न्यून रूप प्राप्त करना
(e) नीति हेतु मॉडल/प्रारूप का प्रयोग करना
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (a), (d), (b), (c) और (e)
(B) (a), (b), (d), (c) और (e)
(C) (b), (d), (a), (e) और (c)
(D) (b), (a), (c), (d) और (e)

40. सामाजिक वस्तुओं के मामले में निम्नलिखित में से कौन-कौनसे कथन सही हैं ?
(a) सामाजिक वस्तुएं गैर-विरोधी प्रकृति की होती हैं.
(b) सामाजिक वस्तुओं के सफल प्रावधान के लिए बजट निर्धारण की राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती हैं.

STUDYPDF WALLAH

(c) सामाजिक वस्तुओं के सफल प्रावधान में व्यक्ति की आभासी माँग रेखाओं में लम्बवत् की बजट क्षैतिज योग शामिल है.

(d) विशुद्ध रूप से निजी और विशुद्ध सामाजिक वस्तुओं में मिश्रित मामले होते हैं, जो लागत बाध्यताओं या लाभ का सृजन करते हैं.

(e) व्यक्ति उपभोक्ता सामाजिक वस्तुओं के लिए बोली नहीं लगाएंगे बल्कि मुफ्तखोर की तरह व्यवहार करेंगे.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (c), (d) और (e)
(B) केवल (a), (b), (c) और (e)
(C) केवल (a) और (b)
(D) केवल (a), (b), (d) और (e)

41. तरलता जाल की अत्यधिक स्थिति में–

(A) बंध (बॉण्डों) को खरीदने की प्रवृत्ति होगी
(B) अधिकांश निवेशक मंदडिया व्यवहार दर्शाते हैं
(C) नकदी (रोकड़) को कम पसंद (वरीय) किया जाएगा
(D) बंध-पत्र (बॉण्ड) की कीमत कम होगी

42. एक व्यापारी के 20 खातों में 6 बकाया और 14 गैर-बकाया खाते हैं. एक लेखापरीक्षक औचक रूप से 5 खातों की जाँच के लिए चयन करता है. इसकी क्या प्रायिकता है कि लेखापरीक्षक को 2 बकाया खाते ही प्राप्त हों ?

(A) 0·2562 (B) 0·3
(C) 0·3087 (D) 0·4526

43. यथेष्ट आकलको के क्या-क्या गुण होते हैं ?

(a) यह गैर-पूर्वाग्रही नहीं होता है.
(b) यह गैर-पूर्वाग्रही होता है.
(c) यह सदैव सुसंगत होता है.
(d) यह सदैव सुसंगत नहीं होता है.
(e) न्यूनतम विसंगत गैर-पूर्वाग्रही आकलक.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b) और (c)
(B) केवल (a), (c) और (e)
(C) केवल (a), (b), (c) और (b)
(D) केवल (a), (b), (c) और (e)

44. गुन्नार मिर्डल किस-किसके लेखक हैं ?

(a) एशियन ड्रामा
(b) एन अमरीकन डिलेमा
(c) थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट
(d) प्रिंसिपल ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी
(e) इकोनॉमिक थ्योरी एण्ड अंडरडव्लप्ड रीजन्स

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b) और (c)
(B) केवल (a), (c) और (d)
(C) केवल (a), (b) और (d)
(D) केवल (a), (b) और (e)

45. नरसिंहम समिति, 1991 की निम्नलिखित में से कौन-कौनसी सिफारिशें हैं ?

(a) ब्याज दर ढाँचे का अविनियमन
(b) सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग की आवश्यकता
(c) केवल निजी क्षेत्र के बैंकों को पूँजी सुविधा प्रदान की जाए.
(d) बैंकों के मुख्य कार्यकारी और अधिकारी नियुक्त करने की आजादी
(e) पूँजीगत पर्याप्तता प्रतिमानों को चरणों में कार्यान्वित किया जाए.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b) और (e)
(B) केवल (a), (c) और (d)
(C) केवल (a), (d) और (e)
(D) केवल (a), (d) और (e)

46. वर्ष 2011-12 के लिए नीति आयोग के गरीबी रेखा अनुमान के आधार पर 30% से अधिक ग्रामीण गरीबी रेखा वाले राज्य कौन-कौनसे हैं ?

(a) मणिपुर (b) बिहार
(c) सिक्किम (d) उत्तर प्रदेश
(e) नगालैंड

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a) और (b)
(B) केवल (b) और (d)
(C) केवल (b), (c) और (d)
(D) केवल (a), (b) और (d)

47. निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के आधार पर पुरातन से आरम्भ करके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(a) जनरल थ्योरी ऑफ एप्लयामेंट, इंटरेस्ट एण्ड मनी
(b) ए ट्रिटिज ऑन प्रॉबेबिलिटी
(c) एसेज इन परसुएशन
(d) दि एण्ड ऑफ लैसेज फेयर
(e) ए ट्रैक्ट ऑन मोनेटरी रिफार्म

आगे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (b), (c), (d), (a), (e)
(B) (b), (e), (d), (c), (a)
(C) (e), (b), (d), (c), (a)
(D) (d), (e), (b), (a), (c)

48. सफल कराधान के लिए रामसेस नियम के मामले में निम्नलिखित में से कौन-कौनसे कथन सही हैं ?

(a) जिन वस्तुओं की माँग लोच कम हो उन पर कर-दर अधिक होनी चाहिए.
(b) यदि बाजार में माँग लोच शून्य है, तो उसी बाजार में कर लगाए जाने चाहिए.
(c) रामसेस नियम, वस्तुओं के कराधान पर लागू होता है, लेकिन आय कराधान पर नहीं.
(d) रामसेस नियम सभी बाजारों के कराधान के अत्यधिक भार को न्यूनतम करता है.
(e) रामसेस नियम की वजह से अनिवार्य रूप से सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (c), (d) और (e)
(B) केवल (a), (b), (d) और (e)
(C) केवल (a), (b), (c) और (d)
(D) केवल (a), (c) और (d)

49. समाकलन करें–

$$\int x\sqrt{x^2+1}\ dx \quad x>0$$

(A) $\frac{1}{2}(x^2+1)^{3/2}+C$

(B) $\frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2}+C$

(C) $\frac{1}{3}(x^3+1)^{2/3}+C$

(D) $\frac{1}{2}(x^3+1)^{2/3}+C$

50. अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है ?

(A) जनता और बैंकों द्वारा भण्डार के रूप में धारित मुद्रा की राशि
(B) जनता द्वारा धारित मुद्रा राशि और माँग निक्षेप
(C) जनता द्वारा धारित मुद्रा राशि और समय निक्षेप
(D) मुद्रा निक्षेप अनुपात

51. जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर (7 वर्ष और अधिक आयु) के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(a) नगालैंड (b) त्रिपुरा
(c) सिक्किम (d) मणिपुर
(e) मेघालय

STUDYPDF WALLAH

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (d), (c), (b), (e), (a)
(B) (c), (b), (d), (a), (e)
(C) (b), (c), (a), (d), (e)
(D) (a), (c), (b), (e), (d)

52. विदेशी विनिमय स्वैप क्या है ?
(A) मुद्रा का तत्काल क्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र-पुनर्क्रम
(B) मुद्रा का तत्काल विक्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र-पुनर्क्रम
(C) वायदा (फॉरवर्ड) में मुद्रा की विक्रय एवं क्रय
(D) तत्काल बाजार में मुद्रा का क्रय

53. सामान्यीकृत निर्धनता अंतराल (एनपीजी) को निम्नलिखित में से किस एक के अनुपात के रूप में मापा जाता है ?
(A) निर्धनता रेखा तथा औसत निर्धनता अंतराल का अनुपात
(B) निर्धनता रेखा तथा कुल निर्धनता अंतराल का अनुपात
(C) कुल जनसंख्या तथा कुल निर्धनता अंतराल का अनुपात
(D) कुल जनसंख्या तथा औसत निर्धनता अंतराल का अनुपात

54. हौसमैन का विनिर्देशन त्रुटि परीक्षण का प्रयोग किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है ?
(A) बहिर्जात चर त्रुटि पद से सह सम्बन्धित है
(B) अंतर्जात चर त्रुटि पद से सह सम्बन्धित है
(C) दोनों बहिर्जात चर त्रुटि पद से सह सम्बन्धित है और अन्तर्जात चार त्रुटि पद से सम्बन्धित है
(D) एस.ई.एस. का अनुमान लगाने के लिए ओ.एल.एस. तरीका उपयुक्त है

55. व्यय प्रकार्यों (उपयोगिता सिद्धांत के सन्दर्भ में) के गुण हैं–
(a) कीमत P में समरूपता की श्रेणी एक
(b) किसी वस्तु *I* के लिए उपयोगिता *u* में पूर्णतः बढ़ते क्रम में और कीमत P में न घटने वाली
(c) P में अवतल
(d) P और *u* में निरन्तरता
(e) P में पूर्णतः उत्तल
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a), (c), (d), (e)
(B) केवल (a), (b), (d), (e)
(C) केवल (a), (b), (c), (d)
(D) केवल (b), (c), (d), (e)

56. यदि S सैम्पल स्पेस और E कार्य का प्रतीक है, तो प्रायिकता नियम को किस रूप में लिखा जा सकता है ?
(a) $P(A) \geq 0$
(b) $P(S) = 1$
(c) $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
(d) $P(A) \leq 0$
(e) $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(S_i)$
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a) और (b)
(B) केवल (a), (b) और (d)
(C) केवल (a), (b) और (e)
(D) केवल (a), (b) और (c)

57. राष्ट्रीय आय समता में $Y = C + I - G$. निवेश (I) किसका फलन होगा ?
(A) वास्तविक आय
(B) नामिक आय
(C) वास्तविक ब्याज दर
(D) नामिक ब्याज दर

58. कर भार के मामले में निम्नलिखित में से कौनसा सही नहीं है ?
(A) कर लगाने से कीमत बढ़ जाती है और गुणवत्ता में कमी आती है
(B) एकाधिकारी बाजार में यदि कर लगाया जाता है, तो परिणामी कर-वार मूल्य वृद्धि निरुत्साहित होगी
(C) यदि माँग गैर-लचीली और आपूर्ति लचीली हो, तो व्यक्ति कर से बचने के लिए बेहतर स्थिति में होगा और क्रेता के पास बड़ा हिस्सा बच जाएगा
(D) आपूर्ति शेड्यूल में एकक कर समानांतर उच्चवर्गामी शिफ्ट में प्रवेश करता है

59. प्रतिस्पर्धी उत्पाद बाजारों के अन्तर्गत बाह्यताओं को अंतः समावेश करने के लिए दीर्घावधि में सब्सिडी प्रभावी नीतिगत क्यों नहीं हैं ?
(A) सब्सिडी सीमान्त नुकसान के बराबर होती है, जो वास्तव में फर्म की निर्धारित लागतों में कमी करती है
(B) सब्सिडी भुगतान सभी फर्मों के लिए उपलब्ध होते हैं, जो अतिशय बाजार प्रवेश को प्रेरित कर सकते हैं
(C) इस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पाद को स्तर सामाजिक रूप से वांछित स्तर को पार कर जाएगा
(D) उपर्युक्त सभी

60. अग्रलिखित में से कौनसा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है ?
(A) राजस्व व्यय + पूँजीगत संवितरण – राजस्व प्राप्ति
(B) राजस्व व्यय + केन्द्र को ऋणों का प्रतिदान – राजस्व प्राप्ति
(C) राजस्व घाटा + पूँजीगत परिव्यय + शुद्ध ऋणद
(D) राजस्व व्यय + आंतरिक ऋण अदा करना – राजस्व प्राप्ति

61. मान लीजिए कि सतत् माँग वाला कोई दुर्लभ संसाधन 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा. यदि कोई वैकल्पिक संसाधन $ 40 की कीमत पर उपलब्ध होगा और ब्याज दर 10% है, तो दुर्लभ संसाधन की आज की कीमत क्या होगी ?
(A) $ 55·50 (B) $ 35·60
(C) $ 24·40 (D) $ 15·42

62. निम्नलिखित में से कौनसा बर्ट्रैंड ध्रुवीय मॉडल के लिए सही है ?
(a) प्रतिक्रिया वर्क रेखाएं समलाभ मानचित्रों से प्राप्त होती हैं, जो अक्ष के प्रतिकूल होते हैं.
(b) दो प्रतिक्रिया वर्क रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु संतुलन की दशा को दर्शाता है.
(c) प्रतिक्रिया वर्क रेखाएं समलाभ मानचित्रों से प्राप्त होती है, जो अक्षों के प्रतिकूल होती हैं.
(d) दो प्रतिक्रिया वर्क रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अस्थिर संतुलन को दर्शाता है.
(e) फर्म का व्यवहार सम्बन्धी पैटर्न ऐसा कि वे विअग्त अनुभव से सीखते हैं.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल (a) और (b)
(B) केवल (c) और (d)
(C) केवल (a), (d) और (e)
(D) केवल (b), (c) और (e)

63. अवैध धन की रोकथाम (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था ?
(A) 2001 (B) 2002
(C) 2003 (D) 2004

64. कारक कीमत समकरण प्रमेय किसने प्रस्तुत किया था ?
(A) डेविड रिकार्डो
(B) जे. एस. मिल
(C) पॉल सैम्युएल्सन
(D) एडम स्मिथ

65. सुरक्षात्मक व्यय पद्धति इस समझ पर आधारित है कि–
(a) उपभोक्ता बुरी चीजों के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए धन व्यय करता है.

STUDYPDF WALLAH

(b) किया गया सुरक्षात्मक व्यय बुरी चीजों के स्तर में कमी करने के लिए उपभोक्ता की भुगतान करने की तत्परता को दर्शाता है.

(c) किया गया सुरक्षात्मक व्यय बुरी चीजों से बचने के लिए तत्परता की ऊपरी सीमा है.

(d) सुरक्षात्मक व्यय में वांछित पर्यावरणीय गुणवत्ता का प्रावधान करने के अलावा कोई अतिरिक्त सेवाओं का प्रावधान नहीं होता है.

(e) किया गया सुरक्षात्मक व्यय बुरी चीजों से बचने के लिए तत्परता की निचली सीमा है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल (a), (b) और (c)
(B) केवल (c), (d) और (e)
(C) केवल (a), (b), (c), (d) और (d)
(D) केवल (a), (b), (d) और (e)

66. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषता बाजार ढाँचे की नहीं है ?
(A) क्रेताओं की संख्या
(B) विक्रेताओं की संख्या
(C) प्रवेश की शर्तें
(D) लम्बवत् एकीकरण

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I : श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का आरम्भिक बिन्दु है.
कथन II : यह श्रम का विभाजन है जिससे श्रम के उत्पादनकारी अधिकार में अधिकतम सुधार होता है.
उपर्युक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं
(B) कथन I और II दोनों असत्य हैं
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है

68. सामान मौद्रिक आधार के साथ, निम्नलिखित में कौनसा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि के ओर प्रेरित करेगा ?
(A) जमा नकदी के रूप में परिवर्तन करने सम्बन्धी उच्च संव्यवहार लागत (मूल्य)
(B) एसएलआर के अन्तर्गत उच्चतर (बड़ी मात्रा में) निवेश
(C) नकदी का बड़े (उच्च) पैमाने पर प्रयोग
(D) वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग आदत (व्यवहार) में वृद्धि

69. निम्नलिखित किस वर्ष में, आई. एम. एफ. ने दीर्घकालीन विशेषता (प्रकृति) वाली भुगतान संतुलन कठिनाइयों में संरचनात्मक सुधारों का समाधान करने हेतु सदस्यों की सहायता के लिए विस्तारित कोष सुविधा (ई. एफ. एफ.) की स्थापना की थी ?
(A) 1974 (B) 1997
(C) 1963 (D) 2009

70. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–
सूची-I
(a) लागत प्रभावी (किफायती)
(b) प्रदूषण परमिट व्यापार प्रणाली
(c) बाजार अवधारणा
(d) कमांड और कंट्रोल अवधारणा
सूची-II
1. मानकों के प्रयोग द्वारा प्रदूषकों को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करने वाली नीति.
2. प्रोत्साहित आधारित नीति जो संरक्षण प्रथाओं या प्रदूषण कटौती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करते हों.
3. जो यह अपेक्षा करती हो कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम-से-कम संसाधनों का प्रयोग किया जाए.
4. वह बाजार उपाय जो प्रदूषकों के अधिकारों के लिए बाजार स्थापित करे.

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	3	4	1	2
(C)	4	3	2	1
(D)	3	4	2	1

71. दिए गए आय गुणांक सूत्र में $m = \frac{1}{1 - MPC}$, बचत की सीमान्त प्रवृत्ति कम होने पर–
(A) गुणांक प्रभाव उच्चतर होगा
(B) गुणांक प्रभाव निम्नतर होगा
(C) गुणांक अपरिमित होगा
(D) गुणांक शून्य होगा

72. भारत में इक्विटी व्यापार की निम्नलिखित घटनाओं को पुरातन से आरम्भ करके सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–
(a) बीएसई ने स्क्रीन आधारित व्यापार आरम्भ किया.
(b) विदेश संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति दी गई.
(c) एनएसई ने थोक ऋण बाजार में कार्य संचालन आरम्भ किया.
(d) एसईबीआई (सेबी) ने बीएसई के बदलाव व्यापार को प्रतिबंधित किया.
(e) एनएसई ने व्यापार के परिमाप की ही अधिक रूप से बड़े बीएसई स्टॉक एक्सचेंज का अधिग्रहण किया.

नीच दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (a), (b), (d), (e), (c)
(B) (b), (d), (c), (e), (a)
(C) (d), (b), (e), (c), (a)
(D) (c), (b), (d), (e), (a)

73. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–
सूची-I
(a) कलेन्स का व्यावहारिक सिद्धांत
(b) लंग बॉक्स (एलबी) स्टैटिसटिक
(c) KPSS (केपीएसएस)
(d) बाई-पेरोन
सूची-II
1. ढाँचागत विभाजन
2. यूनिट रूट
3. स्व सहसम्बन्ध गुणांक का सांख्यिकी महत्व
4. मल्टीकोलिनियरिटी (बहुसंरेखीयता)

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	3	2	1
(B)	4	3	1	2
(C)	2	4	1	3
(D)	2	3	4	1

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I : किसी देश के व्यापार की शर्तें उसकी निर्यात वस्तुओं की लागत और उसकी आयात वस्तुओं के मूल्य के अनुरूप में परिभाषित की जाती हैं.
कथन II : व्यापारिक साझेदार की व्यापार शर्तें, अन्य देश की व्यापार शर्तों के प्रतिलोम के बराबर होती हैं.
उपर्युक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) कथन I और II दोनों सही हैं
(B) कथन I और II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

STUDYPDF WALLAH

75. 'ह्वाई नेशन्स फेल' द ओरिजिन ऑफ पॉवर, प्रॉसपरिटी एण्ड पॉवर्टी' नाम शीर्षक वाली पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है ?

(A) अभिजित बनर्जी

(B) दारोन एक्मोग्लु और जेम्स ए. रॉबिन्सन

(C) अमर्त्य सेन

(D) जोसेफ स्टिगलिज

76. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (भारत के जनसंख्या वृद्धि दर का प्रकार)

(a) तीव्र उच्च वृद्धि

(b) स्थिर जनसंख्या

(c) उच्च वृद्धि धीमी गति के निश्चित संकेतों के साथ

(d) सतत् वृद्धि

सूची-II (अवधि)

1. 1981–2011 2. 1921–1951
3. 1951–1981 4. 1891–1921

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	2	3	1
(B)	3	4	1	2
(C)	3	4	2	1
(D)	4	3	2	1

77. जी-20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य (मोटो) क्या है ?

(A) एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य

(B) एक पृथ्वी, एक प्रकृति, एक जीवन

(C) एक विश्व, एक परिवार, एक जीवन

(D) एक पृथ्वी, एक प्रकृति, एक भविष्य

78. मान लीजिए वस्तु 1 को क्षैतिज रेखा और वस्तु 2 को लंबतः रेखा पर दर्शाया गया है, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा यदि वस्तु 1 की कीमत दोगुनी और वस्तु 2 की कीमत तिगुनी हो जाए–

(A) बजट रेखा अधिक खड़ी हो जाती है

(B) बजट रेखा अधिक समतल हो जाती है

(C) बजट रेखा लम्बवत् हो जाती है

(D) बजट रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है

79. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I

(a) जे. एम. कीन्स

(b) केडलैण्ड प्रिसकोट

(c) बौमल टोबिन

(d) फ्रीडमैन स्वार्च

सूची-II

1. धन के लिए लेन-देन माँग की सामान सूची सैद्धांतिक अवधारणा
2. तरलता अधिमान
3. समय की असंगतता की समस्या
4. अमरीका का मौद्रिक इतिहास

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	4	1
(B)	3	2	1	4
(C)	3	1	2	4
(D)	2	3	1	4

80. निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के आधार पर पुरातन से आरम्भ करके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(a) विदेश विनिमय विनियमन अधिनियम

(b) प्रतिस्पर्धा अधिनियम

(c) एमआरटीपी अधिनियम

(d) विदेश विनियमन अधिनियम

(e) विदेश विनियमन प्रबन्धन अधिनियम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (c), (b), (a), (d), (e)

(B) (c), (a), (b), (e), (d)

(C) (b), (a), (d), (e), (c)

(D) (a), (b), (c), (d), (e)

81. निम्नलिखित में कौनसा किसी पर्यावरण नीति में परिवेश मानकों को परिभाषित करता है ?

(A) वह मानक जो प्राप्त की जाने वाले प्रदूषण सीमा को निर्दिष्ट करता है, लेकिन प्रौद्योगिकी को नहीं

(B) वह मानक जो कुछ कटौती स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण या तरीके को इंगित करता हो

(C) वह मानक जो प्राप्त किए जाने वाले पर्यावरण के कुछ तत्वों के गुणवत्ता स्तर को इंगित करता हो

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

82. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I

(a) $f'(x) > 0$ और $f''(x) > 0$

(b) $f'(x) > 0$ और $f''(x) < 0$

(c) $f'(x) < 0$ और $f''(x) < 0$

(d) $f'(x) < 0$ और $f''(x) > 0$

सूची-II

1. 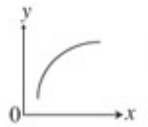

2. 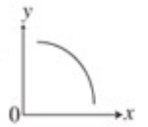

3. 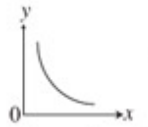

4. 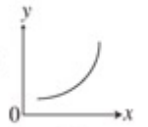

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	3	2
(B)	1	3	2	4
(C)	4	1	2	3
(D)	4	2	3	1

83. केन्द्रीय बजट 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हेतु आवंटित की गई राशि है–

(A) ₹ 2·25 लाख करोड़

(B) ₹ 1·25 लाख करोड़

(C) ₹ 1·78 लाख करोड़

(D) ₹ 1·68 लाख करोड़

84. मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का निम्नलिखित में से कौनसा एक आयाम नहीं है ?

(A) लम्बा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता

(B) ज्ञानार्जन की क्षमता

(C) शानदार जीवनस्तर प्राप्त करने की क्षमता

(D) स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति (पहुँच) हेतु योग्यता

85. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I

(a) सेंट्रल बैंक लोस फंक्शन

(b) मौद्रिक नियम (MR)

(c) फिलिप्स वर्क रेखा (PC)

(d) डायनेमिक IS वर्क रेखा

सूची-II

1. $y_1 = A - ar_{t-1}$
2. $\pi_t = \pi_{t-1} + \alpha(y_t - y_e)$
3. $(y_t - y_e) = -\alpha\beta(\pi_t - \pi^T)$
4. $L = (y_t - y_e)^2 + \beta(\pi_t - \pi^T)^2$

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	4	1
(B)	3	2	4	1
(C)	4	3	2	1
(D)	4	3	1	2

STUDYPDF WALLAH

86. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I

(a) कुजनेट (b) नर्कसे

(c) लेबेन्सटीन (d) शूम्पीटर

सूची-II

1. नवीनता और उद्यमशीलता
2. संतुलित वृद्धि सिद्धांत
3. उल्टा U वक्र प्राक्कल्पना
4. क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	3	2
(B)	3	2	4	1
(C)	4	3	2	1
(D)	2	1	4	3

87. गहन जिला कृषि कार्यक्रम (आईएडीपी) को किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया था ?

(A) 1960-61 (B) 1961-62

(C) 1962-63 (D) 1963-64

88. किसी उपभोक्ता का उपयोगिता फलन $U = f(q_1, q_2) = q_1 \cdot q_2$ दिया गया है. मान लीजिए q_1 की कीमत $P_{q_1} = 1$ और q_2 का मूल्य $P_{q^2} = 2$ है. उपभोक्ता k यूनिट की ही राशि ही खर्च करना चाहता है. q_1 और q_2 के लिए उसकी माँग कितनी होगी ?

(A) $(q_1 \cdot q_2) = \left(k, \frac{k}{2}\right)$

(B) $(q_1, q_2)\left(\frac{k}{4}, \frac{k}{6}\right)$

(C) $(q_1, q_2)\left(\frac{k}{2}, \frac{k}{4}\right)$

(D) $(q_1, q_2)\left(\frac{k}{2}, \frac{k}{3}\right)$

89. निम्नलिखित में से कौनसा पर्यावरणीय फायदों के मूल्यांकन के लिए भौतिक संयोजन अवधारणा पर लागू होता है ?

(A) वे तरीके जो पर्यावरणीय परिवर्तनों से सम्बन्धित स्तरों का तत्काल मूल्यांकन करें

(B) वे तरीके जो पर्यावरण से जुडी वस्तुओं का नहीं बल्कि इससे सम्बद्ध बाजार परिस्थितियों के बारे में प्रतिक्रियाओं की जाँच करें

(C) वे तरीके जो यथार्थ बाजारों में बरताव की टिप्पणियों की सहायता से फायदों का अनुमान लगाते हों

(D) वे तरीके जो किसी पर्यावरणीय संसाधन और उस संसाधन के प्रयोक्ता के बीच के तकनीकी सम्बन्ध के आधार पर फायदों का अनुमान लगाते हों

90. आगे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : यदि सरकारें संरक्षणवादियों के लगान का ध्यान नहीं रखती हैं, तो वे सभी आयात शुल्कों के स्थान पर बिक्री कर लगा देंगी.

कारण (R) : बिक्री कर आयात प्रशुल्क की बनिस्पत राजस्व जुटाने का अधिक कारगर साधन है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(C) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है

(D) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

निर्देश–(प्रश्न 91 से 95 तक) नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

कोविड संकट के प्रति भारत सरकार की मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया में एक ओर खाद्य एवं ऊर्वरकों पर बढ़ती सब्सिडी और दूसरी ओर ईंधन एवं कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती का न्यायसंगत मिश्रण शामिल है. इन अतिरिक्त मौद्रिक दबावों के बावजूद, संघ सरकार पटरी पर लौट आयी है. गतिविधि में प्रतिप्राप्ति, प्रत्यक्ष करों, सामान और सेवा-कर (जीएसटी) से राजस्व में प्रफुल्लता और बजट में यथार्थवादी पूर्वानुमानों की वजह से संघ सरकार के मौद्रिक कार्य निष्पादन में नव शक्ति का संचार हुआ है. प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में जबरदस्त वृद्धि के चलते अप्रैल से नवम्बर 2022 से सकल कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 15·5% की वृद्धि दर्ज हुई. इसी अवधि के दौरान सकल जीएसटी समाहरण में वर्ष-दर-वर्ष 24·8% की वृद्धि हुई है. उच्च राजस्व व्यय के बावजूद पूँजीगत व्यय पर वर्ष के दौरान संघ सरकार का बल जारी रहा है. केन्द्र के पूँजीगत व्यय में सकल घरेलू उत्पाद में 1·7 प्रतिशत के दीर्घावधिक औसत (वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2020) से वित्तीय वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद में 2·5% तक सतत् रूप से बढ़ोतरी हुई है. केन्द्र ने ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके और उधार लेने की अधिक सीमा तय कर के राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया ताकि वे पूँजीगत व्यय पर अपने व्यय की प्राथमिकताएं तय कर सकें. सरकार ने पूँजीगत व्यय को प्रभावित करने वाले बुनियादी सुविधाओं की बहुलता वाले क्षेत्रों जैसे–सड़क और राजमार्ग, आवासन एवं शहरी कार्यों पर नियतनों को भी प्रोत्साहन दिया है. पूँजीगत व्यय में इस वृद्धि के मध्यावधि वृद्धि जीडीपी अनुपात में सतत् सरकारें ऋण के प्रति निहितार्थ होंगी.

91. पूँजीगत व्यय पर राज्यों के व्यय की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौनसी रणनीतियाँ अपनाई गई थीं ?

(A) उच्चतर राजस्व व्यय के लिए प्रोत्साहन देना

(B) ब्याज रहित ऋणों और अधिक कर्ज सीमा

(C) उच्चतर ब्याज के भुगतान को प्रोत्साहित करना

(D) कर समाहरण पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना

92. वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2020 के संघ सरकार का पूँजीगत व्यय औसतन कितना था ?

(A) सकल घरेलू उत्पाद का 2·5 प्रतिशत

(B) राजस्व प्राप्ति का 15·5 प्रतिशत

(C) जीएसटी राजस्व का 24·8 प्रतिशत

(D) सकल घरेलू उत्पाद का 1·7 प्रतिशत

93. निम्नलिखित में से कौनसी रणनीतियाँ कोविड संकट के प्रति भारत की मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं हैं ?

(A) खाद्य सब्सिडी में वृद्धि करना

(B) उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि करना

(C) कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती करना

(D) ईंधन पर करों में वृद्धि करना

94. संघ सरकार के मौद्रिक कार्य निष्पादन में नवशक्ति के संचार को लेकर निम्नलिखित में से कौनसा सही नहीं है ?

(A) आर्थिक गतिविधियों में प्रतिप्राप्ति

(B) उत्साहवर्धक जीएसटी राजस्व

(C) खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी से सम्बन्धित व्यय मितव्ययता उपाय

(D) बजट में यथार्थवादी पूर्वानुमान

95. पूँजीगत व्यय अधिक वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किस बुनियादी क्षेत्र के नियतन में वृद्धि नहीं हुई ?

(A) बन्दरगाह और जलमार्ग

(B) सड़क और राजमार्ग

(C) रेलवे

(D) आवासन और शहरी कार्य

निर्देश–(प्रश्न 96 से 100 तक) नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का व्यापक रूप से सर्वाधिक प्रयोग विस्तृत आर्थिक

STUDYPDF WALLAH

प्रगति के निर्णय हेतु सूक्ष्म आर्थिक संकेतक के रूप में किया जाता है. ऐसे संकेतक के आधार पर किए गए निर्णय के निष्कर्ष बार-बार निराश करते रहे हैं, क्योंकि संसाधनों के प्रयोग की पहचान के असफलताओं के कारण वे अपोषणीय हो जाते हैं. समायोजित निवल बचत (एएनएस) नीति-प्रभावित गतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ग्रहण करते हुए सम्पदा में परिवर्तनों को न कि प्रति व्यक्ति सम्पदा को समझने में सहायता के लिए एक पूरक संकेतक प्रदान करती है. राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एस.एन.ए.) की प्रचलित प्रथाओं पर आधारित विधियों के अनुसार, एएनएस की माप सकल राष्ट्रीय बचत से पूँजीगत उत्पाद के अवमूल्यन, उप भू-परिसम्पत्तियों और टिम्बर संसाधनों के अपक्षय और मानव स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने वाले वायु प्रदूषण को घटाकर और शिक्षा व्यय जमा को योजित करके की जाती है. यदि एएनएस ऋणात्मक है, तो देश का पूँजी भण्डार कम हो रहा है और सम्भवतः भावी भौतिक कल्याण भी घटा रहा है. जब एएनएस धनात्मक है, तो देश की सम्पदा और भौतिक कल्याण का संवर्धन होता है. जब प्राकृतिक संसाधन क्षीणता को सम्पदा पोर्टफोलियो के अन्य परिसम्पत्तियों में निवेश नहीं किया जाता है, तो इस क्षीणता की प्रतिपूर्ति करने में देशों की सकल बचत पर्याप्त नहीं हो सकती है जिसके कारण निबल वचत ऋणात्मक होती है. यद्यपि, उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों में ऋणात्मक एएनएस प्राप्त करने की सम्भावना कम होती है. यह तर्क दिया जाता है कि यदि सततता के संकेतक उच्च नहीं हैं, तो एएनएस अपोषणीयता के एक संकेतक के रूप में उपयोगी होगा. अतः एएनएस के अनुमान और संकल्पना निर्माण सीमाओं से मुक्त नहीं हैं.

96. निम्नलिखित में कौन एएनएस का संघटक नहीं है ?
(A) शिक्षा पर लोक व्यय
(B) वायु प्रदूषण क्षति
(C) धातुओं और खनिजों का अपक्षय
(D) जैव-विविधता का ह्रास

97. निम्नलिखित में कौन एएनएस की कमियों को प्रतिबिंबित करता है ?
(A) यह पूँजी के विभिन्न रूपों के बीच पूरक की अनुमति देता है
(B) यह प्रति व्यक्ति सम्पदा का एक व्यापक संकेतक नहीं है
(C) यह किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से प्रभावित होता है
(D) उपर्युक्त सभी

98. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सतत् वृद्धि कर रहे देशों में एएनएस में ह्रास की व्याख्या निम्नलिखित में कौन करता है ?
(A) किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का बढ़ता समानुपात
(B) अपक्षयित परिसम्पत्तियाँ जो मानव तथा भौतिक पूँजी में पर्याप्त निवेश द्वारा अनुचित्रित न हों
(C) सकल बचत दरों में वृद्धि
(D) नवीकरणीय प्राकृतिक पूँजी के उत्पादन में वृद्धि

99. एएनएस की अवधारणा को किसके लिए सर्वोत्तम रूप में प्रयोग करना चाहिए ?
(A) पारिस्थितिकीय इष्टतम सतत् मापन का मार्गदर्शन
(B) असतता के संकेतक के रूप में प्रयोग
(C) आर्थिक प्रगति के माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिस्थापन
(D) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

100. समायोजित निवल बचत (एएनएस) है–
(A) प्रति व्यक्ति सम्पदा में परिवर्तन का परोक्षी
(B) स्टॉक चर
(C) प्रवाह चर
(D) नीति-प्रभावित गतिशीलता को अभिग्रहण करने में असमर्थता

उत्तर व्याख्या सहित

1. (D)
2. (B) बहुसंरेखता एक नमूना घटना है. इस प्रकार बहुसंरेखता का पता लगाने की कोई एक विशेष विधि खोजना कठिन है. यहाँ नीचे बहुसंरेखता का पता लगाने के लिए कई औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों को सूचीबद्ध किया गया है, हालाँकि ये सभी सामान्य नियम हैं.
   - उच्च R2 लेकिन कुछ महत्वपूर्ण t अनुपात.
   - प्रतिगामी के बीच उच्च जोड़ी-वार सहसम्बन्ध
   - सहायक प्रतिगमन
   - आइजन मूल्यों और स्थिति सूचकांक का अध्ययन करना
   - सहनशीलता और विचरण मुद्रास्फीति कारक

   इस प्रकार कथन (d) & (e) गलत है.
3. (D) 4. (A)
5. (C) कल्याणकारी अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमेय तब सत्य होता है जब कम्पनियाँ पैमाने के स्थिर प्रतिफल के साथ वस्तु का उत्पादन करती है.
6. (C) प्रथम-डिग्री विभेद या पूर्ण कीमत विभेद, तब होता है जब कोई व्यवसाय उपभोग की गई प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम सम्भव मूल्य वसूलता है, ग्राहक सेवाओं से जुड़े कई उद्योग प्रथम-डिग्री कीमत विभेद को अपनाते हैं, जहाँ एक कम्पनी बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा के लिए एक अलग कीमत वसूलती है. कथन I सही है. तृतीय-डिग्री कीमत विभेद तब होता है जब कोई कम्पनी विभिन्न उपभोक्ता समूहों से अलग-अलग कीमत वसूलती है. कथन II गलत है.
7. (A) फ्रीडमैन के सिद्धांत के अनुसार "मुद्रा की माँग तीन प्रमुख कारकों पर निर्भर मानी जाती है–(क) सम्पत्ति के विभिन्न रूपों में रखी जाने वाली कुल सम्पत्ति (ख) अन्य रूपों की तुलना में धन के एक रूप की सापेक्ष कीमत और प्रतिफल (ग) धन धारकों की रुचि और पसंद." यहाँ यह कीनेसियन सिद्धांत से भिन्न है, इसलिए कथन II सही है. हालाँकि, फ्रीडमैन भी नकदी शेष पर निर्भर थे और कीन्स के मामले में भी ऐसा ही था. कथन I सही है.
8. (D) LM अनुसूची (वक्र), या मुद्रा बाजार संतुलन अनुसूची, ब्याज दरों और आय के स्तरों के सभी संयोजनों को दर्शाती है जैसे कि मुद्रा की माँग इसकी आपूर्ति के बराबर है. कथन (D) गलत है.
9. (C)
10. (A) जोन रॉबिन्सन ने उस स्थिति का उल्लेख किया जहाँ $g = g_w = n$ और बेरोजगारी अंतराल शून्य है, इसे 'स्वर्ण युग' विकास पथ कहा जाता है, "इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि यह मामलों की एक पौराणिक स्थिति (Mythical State) का प्रतिनिधित्व करता है जिसके किसी भी वास्तविक अर्थव्यवस्था में प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है."
11. (B) 2021-22 के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर SGST (एसजीएसटी) मद के तहत् राज्यों को प्राप्त कुल राजस्व मध्य प्रदेश में 9433 करोड़, राजस्थान में 11329 करोड़, ओडिशा में 12743 करोड़, दिल्ली में 13443 करोड़ और पश्चिम बगाल में 18164 था.
12. (*) सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में सेवाओं के घटक हैं (b) व्यापार, होटल, परिवहन और संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं, (d) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य प्राप्तियाँ; (e) वित्तीय, रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं. अतः कोई भी उत्तर सही नहीं है.
13. (D)
14. (D) वित्त वर्ष 1991-92 में भारत को ऋण देते समय सभी अप्रत्यक्ष करों को एक कर में समाहित करना आईएमएफ की शर्त नहीं थी.
15. (A) यह तथाकथित रैंडम-वॉक-विदाउट-ड्रिफ्ट मॉडल है : यह मानता है कि समय के प्रत्येक बिंदु पर, शृंखला केवल अपनी अंतिम रिकॉर्ड की गई स्थिति से एक

STUDYPDF WALLAH

यादृच्छिक कदम दूर लेती है, जहाँ चरणों के साथ जिनका औसत मान शून्य है. सामान्य तौर पर चरण अलग-अलग या निरन्तर यादृच्छिक चर हो सकते हैं और समय का पैमाना भी अलग-अलग या निरन्तर हो सकता है. रैंडम वॉक पैटर्न आमतौर पर वित्तीय परिसम्पत्तियों की मूल प्रवृत्तियों में देखा जाता है, जिसके लिए सट्टा बाजार मौजूद होते हैं, जैसे–स्टॉक और मुद्राएं.

16. (A)

17. (C) हम जानते हैं कि गुणक K = 1/MPS. इस प्रकार वर्तमान स्थिति में K = 1/0·25 = 4; हम यह भी जानते हैं कि K = आय में वृद्धि/निवेश में वृद्धि $\left(\frac{\Delta y}{\Delta I}\right)$ वर्तमान स्थिति में $K = 4 = \frac{\Delta y}{100}$
इस प्रकार Δy (GDP में वृद्धि) = 400

18. (C)

19. (D) सृजनात्मक विनाश अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर द्वारा शुरू की गई एक अवधारणा है, जो नवाचार और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जो मौजूदा आर्थिक संरचनाओं, जैसे–उद्योगों, फर्मों और नौकरियों को विनाश की ओर ले जाती है.

20. (D) डब्ल्यूटीओ में तरजीही व्यापार व्यवस्था (पीटीए) एकतरफा व्यापार प्राथमिकताएं हैं; मुक्त व्यापार क्षेत्र (केवल सदस्य देशों के बीच टैरिफ में कमी); सीमा शुल्क संघ (सामान्य बाह्य टैरिफ); साझा बाजार (विभिन्न राष्ट्रीय नियमों के साथ पूँजी और सेवाओं का मुक्त आवागमन); आर्थिक संघ (आंतरिक व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं, श्रम का मुक्त आवागमन, सुसंगत कर दरें, सामान्य मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ).

21. (B) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (1 जुलाई, 1948); भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (5 जनवरी, 1955); भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (1971); निर्यात-भारतीय आयात बैंक (1 जनवरी, 1982) नाबार्ड (12 जुलाई, 1982).

22. (A)

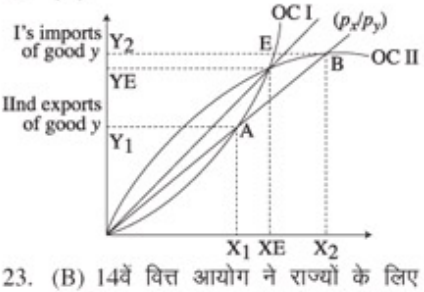

23. (B) 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए निर्धारित 42 प्रतिशत हिस्से में विभिन्न राज्यों के हिस्से के निर्धारण के लिए निम्नलिखित तरीकों से विभिन्न मानदंडों को महत्व दिया–वन आवरण (7·5%), जनसांख्यिकीय परिवर्तन [2011 की जनसंख्या (10%), क्षेत्रफल (15%), जनसंख्या (1971) (17·5%), आय दूरी (50%)].

24. (C) एसआरएस बुलेटिन 2018–20 के अनुसार विभिन्न राज्यों में मातृ मृत्यु दर पर आधारित जीवनकाल जोखिम है : मध्य प्रदेश (0·53%), उत्तर प्रदेश (0·50%), बिहार (0·39%), छत्तीसगढ़ (0·35%).

25. (D)

26. (A) त्रिधापाश एक आर्थिक सिद्धांत है, जो मानता है कि देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति समझौतों के बारे में मौलिक निर्णय लेते समय तीन विकल्पों में से चुन सकते हैं. हालाँकि, एक निश्चित समय में त्रिधापाश का केवल एक ही विकल्प प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि त्रिधापाश के तीन विकल्प पारस्परिक रूप से अनन्य हैं.

27. (D)

28. (A) एडम स्मिथ के कुछ सबसे प्रभावशाली योगदानों में श्रम विभाजन, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और अदृश्य हाथ का सिद्धांत शामिल है. श्रम विभाजन बढ़ते रिटर्न का एक महत्वपूर्ण स्रोत है.

29. (D) पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जे. एम. कीन्स द्वारा दी गई एक अवधारणा है, जो बताती है कि व्यक्ति आर्थिक मंदी के दौरान अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं, जिससे अनिवार्य रूप से कुल माँग में गिरावट आती है और इसलिए आर्थिक विकास में गिरावट आती है.

30. (C)

31. (*) बेसल III मानदंड 2008 के क्रेडिट संकट के बाद 2009 में पेश किए गए थे. बेसल III का पहला संस्करण 2009 के अंत में प्रकाशित हुआ था. इसमें बेसल III आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 वर्ष की विंडो अवधि दी गई थी.
    1. बेसल III मानदंडों ने न्यूनतम टियर 1 पूँजी को 4% से बढ़ाकर 6% और न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी को 4% से बढ़ाकर 4·5% करके मजबूत पूँजी अनुपात हासिल करना.
    2. बैंक की नियामक पूँजी को टियर 1 और टियर 2 में विभाजित किया गया है. टियर 1 पूँजी को सामान्य इक्विटी टियर 1 और अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में विभाजित किया गया है.
    3. बेसल II मानदंड बैंकों को अधिक लचीला बनाने और वैश्विक बैंकिंग मुद्दों से झटके के जोखिम को कम करने के लिए हैं.
    4. वित्तीय संकट के दौरान पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए, बेसल III मानदंड बैंकों द्वारा अत्यधिक उधार लेने के खिलाफ सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट करते हैं.

    इस प्रकार विकल्प (A) और (B) दोनों सही हैं.

32. (A) उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ताओं में 'एंटीडंपिंग और सुरक्षा उपायों में ढील देने' पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था.

33. (D) विवाहित कर्मचारियों की संख्या
    = 80
    विवाहितों की संख्या, जो पर्यवेक्षक हैं
    = 80 का 20%
    = 80 का 20%
    = 16
    इसलिए, आवश्यक प्रायिकता
    = 16/140
    = 0·11428 या 0·1143

34. (C) टोबिन के निवेश के क्यू सिद्धांत के अनुसार, एक फर्म को तब निवेश नहीं करना चाहिए जब ब्याज दर में वृद्धि हो, क्योंकि इससे उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी (संचालन).

35. (D)

36. (D) भारत सरकार ने ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26वें सत्र में विकासशील देशों की चिंताओं को स्पष्ट किया और उनके सामने रखा. इसके अलावा, भारत ने भारत की जलवायु कार्यवाही के निम्नलिखित 5 अमृत तत्व (पंचामृत) प्रस्तुत किए–
    (i) 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना.
    (ii) 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करना.
    (iii) अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना.
    (iv) 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी करना.
    (v) 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना.

    इस प्रकार कथन a & c COP 26 में भारत के रुख का हिस्सा नहीं थे.

37. (A) टेलर नियम एक ब्याज दर पूर्वानुमान मॉडल है जिसका आविष्कार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन टेलर ने 1992 में किया था और इसे 1993 के अपने अध्ययन, 'विवेकाधीन *बनाम* नीति नियम व्यवहार में' में रेखांकित किया था. यह सुझाव देता है कि केन्द्रीय बैंकों (मौद्रिक प्राधिकरण) को मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कैसे बदलाव करना चाहिए.

38. (D) LM सम्बन्ध सबसे पहले मुद्रा की आपूर्ति को मुद्रा की माँग के साथ निर्धारित किया जाता है–
    $(M/P)^s = (M/P)^d$
    $300 = 2Y - 1{\cdot}5\,i$

39. (A) अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग (आईएलएस) के अनुमान में अपनाए गए चरणों का सही क्रम है : संरचनात्मक समीकरणों की पहचान - समीकरण का न्यून रूप प्राप्त करना - ओएलएस का अनुप्रयोग -

STUDYPDF WALLAH

संरचनात्मक गुणांक प्राप्त करना - नीति के लिए मॉडल का उपयोग करना.

40. (D) सामाजिक वस्तुओं के कुशल प्रावधान में व्यक्तिगत छद्म माँग का क्षैतिज जोड़ के बजाए ऊर्ध्वाधर शामिल है, इसलिए कथन (C) गलत है.

41. (B) तरलता जाल के चरम मामले में (ऐसी स्थिति जहाँ ब्याज दरें इस हद तक नीची होती हैं कि निवेशक निवेश करने के बाजाए नकदी को अपने पास रखना पसंद करते हैं) अधिकांश निवेशक मंदी का व्यवहार दिखाएंगे.

42. (C)

43. (D) पर्याप्त अनुमानक हमेशा सुसंगत नहीं होता है.

44. (D)

45. (C) बैंकिंग को बाजार-उन्मुखीकरण बनाने के लिए, नरसिम्हम समिति-I ने सिफारिश की थी कि अब किसी भी वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा और यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी बाजार में अपनी इक्विटी को 49% बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही, यह सुझाव दिया गया कि अब पिछड़े क्षेत्रों में किसी भी बैंक शाखा का विस्तार नहीं किया जाएगा यदि इसे व्यावसायिक रूप से गैर-व्यवहार्य पाया गया हो, तो इसी तरह, नरसिम्हम समिति-I ने माना कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, सांविधिक तरलता अनुपात (SCR) तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात, जो सार्वजनिक निधियों को पहले से ही खाली कर देते हैं, में कमी लायी जाएगी तथा ब्याज दरों को विनियन्त्रित किया जाएगा.

46. (D) नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर मणिपुर में 38·80%, बिहार में 34·06%, सिक्किम में 9·85%, उत्तर प्रदेश में 30·40%, नगालैंड में 19·93% थी.

47. (B) प्रकाशन का सही कालानुक्रम ए ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी (1921) - ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म (1923) - द एंड ऑफ लेजेज फेयर (1926) - एसेज इन पर्सुएशन (1931)-, - ए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी (1936) है.

48. (B) रैमसे नियम केवल वस्तुओं पर कराधान पर लागू होता है.

49. (B)

50. (A) किसी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक आधार में प्रचलन में मौजूद सभी भौतिक कागजी मुद्रा और सिक्का मुद्रा, साथ ही केन्द्रीय बैंक द्वारा रखे गए बैंक भण्डार शामिल होते हैं. मौद्रिक आधार को कभी-कभी उच्च-शक्ति वाली मुद्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इसे आंशिक आरक्षित बैंकिंग प्रणाली के धन गुणक प्रभाव के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है.

51. (C) 2011 में साक्षरता दर त्रिपुरा में 87·2%, सिक्किम में 81·4%, नगालैंड में 79·6%, मणिपुर में 79·2% और मेघालय में 74·4% थी.

52. (B) 53. (A) 54. (A)

55. (C) व्यय फलन के गुण यदि $u(x)$ RL + और $p >> 0$ पर निरन्तर और स्थानीय रूप से गैर-संतृप्त है, तो $e(p, u)$ l p व्यय प्रकार्य $\rightarrow$ कीमत P डिग्री एक का समरूप है (कथन A); किसी वस्तु 1 के लिए उपयोगिता u में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी नहीं होती (कथन B); P में अवतल है (कथन C); p और u में निरन्तरता है (कथन D) कथन (E) गलत है.

में डिग्री 1 का सजातीय है. (B) u में सख्ती से वृद्धि और किसी भी वस्तु 1 के लिए p में गैर-ह्रासमान. (C) p और u में निरन्तर. (D) p में अवतल.

56. (D) 57. (C)

58. (C) करापात आपूर्ति और माँग की सापेक्ष कीमत लोच पर निर्भर करता है. जब आपूर्ति माँग से अधिक लोचदार होती है, तो खरीदार कर का अधिकांश बोझ वहन करते हैं. जब माँग आपूर्ति की तुलना में अधिक लोचदार होती है, तो उत्पादक कर की अधिकांश लागत वहन करते हैं.

59. (D) 60. (C)

61. (D) मान जोड़ने पर, हमें मिलता है;

$$\text{PV (वर्तमान मूल्य)} = \frac{40}{(1+10\%)^{10}}$$

$$= \frac{40}{(1{\cdot}1)^{10}}$$

$$= \frac{40}{2{\cdot}59374}$$

$$= 15{\cdot}421$$

चूँकि दुर्लभ संसाधन 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज इसकी कीमत वैकल्पिक संसाधन के वर्तमान मूल्य के बराबर होनी चाहिए, जोकि $ 15·42 है.

62. (A) बर्ट्रेंड का मॉडल एक स्थिर संतुलन की ओर ले जाता है, जो दो प्रतिक्रिया वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा परिभाषित होता है; इसलिए, कथन (a) और (b) सही हैं.

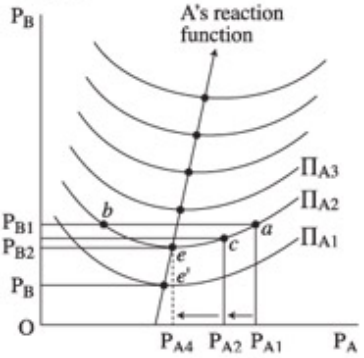

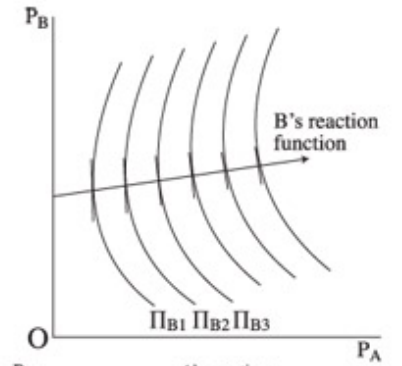

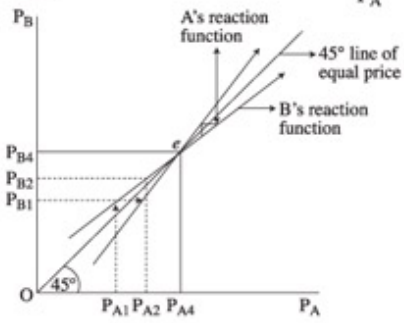

63. (B) 64. (C)

65. (D) रक्षात्मक व्यय तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज पर धन खर्च करते हैं, जो हमारे कल्याण में वृद्धि नहीं करती है, या कल्याण में कमी से बचने के लिए आवश्यक है. उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य बीमा पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है कि हम बेहतर स्थिति में हों, लेकिन यह हमें भविष्य की लागतों से बचाने में मदद करता है, जो हमारी भलाई पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे.

66. (D) ऊर्ध्वाधर एकीकरण बाजार संरचना की विशेषता नहीं है. वर्टिकल इंटीग्रेशन वह व्यावसायिक व्यवस्था है, जिसमें एक कम्पनी आपूर्ति शृंखला के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करती है. बाहरी आपूर्ति-कर्ताओं पर निर्भर रहने के बजाय, कम्पनी उत्पादन प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण के लिए प्रक्रियाओं को अपने भीतर लाने का प्रयास करती है.

67. (A)

68. (D) वित्तीय साक्षरता में वृद्धि और बेहतर बैंकिंग आदतें अधिक-से-अधिक लोगों को बैंकिंग मोड के माध्यम से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी. इसके परिणाम-स्वरूप व्यापक मुद्रा में वृद्धि होगी.

69. (A) 70. (A)

71. (A) m = 1/1-MPC या m = 1/MPS; यदि MPS कम है, तो गुणक प्रभाव अधिक होगा.

72. (B) भारत में इक्विटी ट्रेडिंग की घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है– एफआईआई को भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई - सेबी ने बीएसई पर बदला ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया - एनएसई ने थोक ऋण बाजार खंड में परिचालन शुरू किया - वॉल्यूम ट्रेडिंग के मामले में सबसे बड़ा स्टॉक

शेष पृष्ठ 154 पर

STUDYPDF WALLAH

आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा/अधिकारी परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न

सामान्य अध्ययन

1. मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है?
   (A) गेहूँ (B) दाल
   (C) चावल (D) जौ
2. पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है?
   (A) नृत्य (B) शराब
   (C) बुनाई (D) ये सभी
3. निम्नलिखित में से राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है?
   (A) उत्तर प्रदेश (B) गुजरात
   (C) बिहार (D) ओडिशा
4. केन्द्रीय तम्बाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
   (A) हिमाचल
   (B) आंध्र प्रदेश
   (C) जम्मू और कश्मीर
   (D) लद्दाख
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूँजी में राज्य सरकार का हिस्सा है–
   (A) 50% (B) 15%
   (C) 30% (D) 35%
6. 'हेरुका' सम्बन्धित है–
   (A) जैन धर्म से (B) बौद्ध धर्म से
   (C) शैववाद से (D) वैष्णववाद से
7. निम्नांकित में से तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था?
   (A) अलबरूनी
   (B) फारुखी
   (C) मिनहाज-उस-सिराज
   (D) बरनी
8. वर्तमान में मणिपुर के/की राज्यपाल कौन हैं?
   (A) आर. एन. रवि
   (B) अनुसुइया उइके
   (C) बेबी रानी मौर्या
   (D) पी.एस. श्रीधरन पिल्लई
9. निम्नलिखित राज्यों में से कौनसे राज्य कावेरी जल विवाद से सम्बन्धित हैं?
   (A) तमिलनाडु और कर्नाटक
   (B) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
   (C) तेलंगाना और मध्य प्रदेश
   (D) छत्तीसगढ़ और तेलंगाना
10. किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुँचता है?
    (A) विसरण
    (B) दहन
    (C) प्रकाश संश्लेषण
    (D) किण्वन
11. निम्नलिखित में से नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अधिकार किसे है?
    (A) राज्य सभा
    (B) लोक सभा
    (C) शिक्षा मंत्रालय
    (D) श्रम और रोजगार मंत्रालय
12. अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौनसी भव्य उपाधि धारण की?
    (A) तूती-ए-हिन्द
    (B) कैसर-ए-हिन्द
    (C) जिल्ल-ए-इलाही
    (D) दीन-ए-इलाही
13. 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' क्या है?
    (A) सेबी-पंजीकृत दलालों की गति-विधियाँ
    (B) आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री
    (C) सरकार द्वारा गिल्ट-एजेड प्रति-भूतियों की बिक्री
    (D) एफआईआई द्वारा शेयर की बिक्री
14. द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है?
    (A) पी.सी. महालनोबिस
    (B) हैरोड डोमर मॉडल
    (C) कैम्ब्रिज मॉडल
    (D) डी. पी. धर मॉडल
15. निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था?
    (A) ग्रेट निकोबार
    (B) नीलगिरी
    (C) मन्नार की खाड़ी
    (D) नंदा देवी
16. निम्नलिखित में से ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
    (A) ओटावा (B) नागासाकी
    (C) कैनबरा (D) एम्सटर्डम
17. भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है–
    (A) वनस्थली विद्यापीठ
    (B) एलएसआर महिला विश्वविद्यालय
    (C) श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय
    (D) एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय
18. निम्नलिखित में से देश के कितने शहरों में कुम्भ का मेला लगता है?
    (A) 2 (B) 4
    (C) 3 (D) 5
19. मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है?
    (A) एस्ट्रोजन (B) प्रोजेस्टरॉन
    (C) रिलैक्सिन (D) पोजीट्रॉन
20. नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
    (A) मदर टेरेसा
    (B) अमर्त्य सेन
    (C) रवीन्द्र नाथ टैगोर
    (D) कैलाश सत्यार्थी
21. यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है, तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा?
    (A) 76 किग्रा (B) 7·60 किग्रा
    (C) 12·9 किग्रा (D) 14·4 किग्रा
22. भारतीय संविधान के कौनसे अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों से सम्बन्धित है?
    (A) अनुच्छेद 35 से 50
    (B) अनुच्छेद 36 से 51
    (C) अनुच्छेद 34 से 45
    (D) अनुच्छेद 25 से 51
23. निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के आठ सुल्तानों के शासनकाल के गवाह थे?
    (A) अमीर खुसरो
    (B) शम्स-ए-सिराज आफिफ़
    (C) बरनी
    (D) उत्बी
24. बंगाल का विभाजन कब किया गया था?
    (A) जून 1905
    (B) अक्टूबर 1905
    (C) जून 1906
    (D) अक्टूबर 1906
25. प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट् कौन था?
    (A) अहमद शाह
    (B) आलमगीर द्वितीय
    (C) शाह आलम II
    (D) मुहम्मद शाह
26. निम्नलिखित में से ..... एक कायान्तरित शैल नहीं है.
    (A) सैंडस्टोन (B) हीरा
    (C) संगमरमर (D) क्वार्टजाइट
27. निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तटीय द्वीप है?
    (A) श्रीहरिकोटा (B) परिकूद
    (C) एलीफेंटा (D) पंबम

STUDYPDF WALLAH

28. रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है?
(A) असम (B) कर्नाटक
(C) मध्य प्रदेश (D) हिमाचल प्रदेश

29. पृथ्वी के चुम्बकत्व के लिए..... उत्तरदायी है.
(A) मेंटल (B) वाह्य कोर
(C) क्रस्ट (D) आंतरिक कोर

30. निम्नलिखित में से किस राज्य में चित्रकोट जलप्रपात स्थित है?
(A) उत्तर प्रदेश (B) मध्य प्रदेश
(C) झारखण्ड (D) छत्तीसगढ़

31. विधि आयोग.....प्रकार का निकाय है.
(A) न्यायिक निकाय
(B) कार्यकारी निकाय (Executive Body)
(C) संवैधानिक निकाय
(D) वैधानिक निकाय (Statutory Body)

32. किस अनुच्छेद के तहत् सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है?
(A) अनुच्छेद 124
(B) अनुच्छेद 137
(C) अनुच्छेद 144
(D) अनुच्छेद 141

33. कैबिनेट सचिव का कार्यकाल.....का होता है.
(A) 2 वर्ष (B) 3 वर्ष
(C) 4 वर्ष (D) 5 वर्ष

34. हमारे संविधान में, जनगणना को किस सूची में एक विषय के रूप में शामिल किया है?
(A) राज्य सूची
(B) संघ सूची
(C) समवर्ती सूची
(D) उपर्युक्त सभी

35. .....किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है.
(A) गामा (B) अल्फा
(C) एक्स (D) बीटा

36. अकबर.....वर्ष का था, जब वह सम्राट् बना था.
(A) 16 (B) 19
(C) 13 (D) 10

37. सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है?
(A) नारंगी (B) सफेद
(C) लाल (D) पीला

38. स्वतंत्र रूप से लटकती हुई एक चुम्बकीय सुई किस दिशा में रुकेगी?
(A) दक्षिण-पश्चिम
(B) उत्तर-पूर्व
(C) पूर्व-पश्चिम
(D) उत्तर-दक्षिण

39. निम्नलिखित में से किस सिद्धान्त पर टीवी रिमोट काम करता है?
(A) इन्फ्रारेड तरंगों
(B) अल्ट्रासोनिक तरंगें
(C) लेजर तकनीक
(D) ब्लूटूथ तकनीक

40. बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है?
(A) रेयान (कृत्रिम रेशम)
(B) विन्योन
(C) सारन
(D) केवलर

41. निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौनसी है?
(A) डिस्प्रोसियम
(B) ऑस्मियम
(C) गैडोलीनियम
(D) पैलेडियम

42. निम्नलिखित में से किस विद्युत् चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है?
(A) रेडियो तरंगें
(B) माइक्रो तरंगें
(C) गामा तरंगें
(D) पराबैंगनी किरणें

43. प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में .... में परिवर्तित होता है.
(A) गैस, ठोस (B) ठोस, गैस
(C) तरल, गैस (D) गैस, तरल

44. .....पृथ्वी के वायुमण्डल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है.
(A) आर्गन
(B) सल्फर ऑक्साइड
(C) कार्बन डाइऑक्साइड
(D) नाइट्रोजन

45. ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौनसी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है?
(A) क्रिप्टन
(B) ऑक्सीजन
(C) कार्बन डाइऑक्साइड
(D) नाइट्रोजन

46. कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ कौनसी गैस मिलाई जाती है?
(A) जेनान (B) हीलियम
(C) हाइड्रोजन (D) आर्गन

47. .....का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जाँच करने के लिए किया जाता है.
(A) तरल नाइट्रोजन
(B) सोडियम क्रोमेट
(C) पोटैशियम डाइक्रोमेट
(D) लिथियम डाइक्रोमेट

48. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए–

ज्वालामुखी	देश
(a) कातला	1. इटली
(b) क्राकाटोआ	2. इंडोनेशिया
(c) माउंट विसुवियस	3. तंजानिया
(d) किलिमंजारो	4. आइसलैण्ड

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	4	2	1	3
(C)	4	1	2	3
(D)	1	3	2	4

49. सोना निम्नलिखित में से किस रसायन में घुलनशील है?
(A) हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड
(B) एक्वा रेजिया
(C) हाइड्रो क्लोरिक एसिड
(D) उपर्युक्त सभी

50. तोमर राजपूतों को बारहवीं शताब्दी के मध्य में कहाँ के चौहानों ने हराया था?
(A) अयोध्या (B) अजमेर
(C) द्वारका (D) ग्वालियर

51. एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है?
(A) 0·1 सेकंड (B) 0·2 सेकंड
(C) 0·4 सेकड (D) 0·8 सेकंड

52. निम्नलिखित में से कौनसा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है?
(A) सिरोसिस (B) एड्स
(C) सिफलिस (D) हेपेटाइटिस बी

53. किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है?
(A) विटामिन बी5
(B) विटामिन बी2
(C) विटामिन बी7
(D) विटामिन बी9

54. निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है?
(A) पार्थेनोकार्पी (B) एपोमिक्स
(C) हाइब्रिड (D) गैमेटोगैमी

55. .....आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है.
(A) रेटिना
(B) सिलैरी मांसपेशी

STUDYPDF WALLAH

(C) कॉर्निया
(D) पुतली

56. समुद्री शैवाल से ..... प्राप्त किया जाता है.
(A) आर्गन (B) आयोडीन
(C) सल्फर (D) आयरन

57. 1930 में ..... की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था.
(A) अब्दुल गफ्फार खान
(B) अबुल कलाम आजाद
(C) जाकिर हुसैन
(D) मुजफ्फर अहमद

58. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के ..... मुख्य न्यायाधीश हैं.
(A) 48वें (B) 52वें
(C) 47वें (D) 50वें

59. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही सुमेलित है?
(A) रसिया-ब्रजभूमि क्षेत्र
(B) कजरी-पूर्वान्चल
(C) आल्हा-मिर्जापुर
(D) बिरहा-बुन्देलखण्ड

60. निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए–
(A) लखनऊ घराना–उस्ताद विलायत खान
(B) आगरा घराना–बख्शूर खान
(C) शरणपुर घराना–बहराम खान
(D) इटावा घराना–उस्ताद फैय्याज

61. उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के प्रस्ताव के तहत् कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे?
(A) 10 (B) 14
(C) 12 (D) 16

62. 'गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स' एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे–
(A) विजय केलकर
(B) मोंटेक सिंह अहलूवालिया
(C) अरुण जेटली
(D) नरसिम्हम

63. प्रसिद्ध काव्यग्रंथ 'रश्मिरेखा' के लेखक कौन हैं?
(A) रामधारी सिंह 'दिनकर'
(B) गजानन माधव मुक्तिबोध
(C) बाल कृष्ण शर्मा नवीन
(D) हरिशंकर परसाई

64. दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए–
1. माँडा 2. कालीबंगन
3. हड़प्पा 4. धेलावीरा
(A) 2, 3, 4, 1 (B) 1, 2, 4, 3
(C) 4, 2, 3, 1 (D) 3, 2, 1, 4

65. वैदिक काल के निम्नलिखित देवी/देवता से उनके सम्बन्धित शीर्षकों का मिलान कीजिए–

देवी/देवता	शीर्षक
(a) अश्विन	1. चक्रवात के देवता
(b) ऊषा	2. वन देवी
(c) आर्यनी	3. प्रातः की देवी
(d) मारुत	4. बीमारियों को दूर करने वाले देवता

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	4	3	2	1
(C)	4	1	2	3
(D)	1	3	2	4

66. निम्नलिखित पर विचार कीजिए–
1. नागार्जुन सागर
2. इडुक्की
3. अल्माटी
4. अमरावती
उपर्युक्त बाँध/बाँधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 2 और 4
(D) केवल 1 और 2

67. भारत सरकार के वर्तमान तथा 18वें सीईए (मुख्य आर्थिक सलाहकार) कौन हैं?
(A) जे. जे. अंजारिया
(B) वी. अनंत नागेश्वरन
(C) अरविंद सुब्रमण्यन
(D) कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन

68. नाबार्ड किस समिति की सिफारिश द्वारा स्थापित किया गया था?
(A) तेंदुलकर समिति
(B) शिवरमन समिति
(C) नरसिम्हन समिति
(D) रंगराजन समिति

69. स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस/किन वर्ष/वर्षों में विमुद्रीकरण हुआ?
1. 1978 2. 1976
3. 2017 4. 2016
(A) केवल 3
(B) केवल 4
(C) 1 और 4 केवल
(D) 2 और 4 केवल

70. निम्नलिखित में से कौनसे RBI गवर्नर का क्रमशः सबसे लम्बा और सबसे छोटा कार्यकाल है?
(A) बेनेगल रामा राव और अमिताव घोष
(B) अमिताव घोष और बिमल जालान
(C) बिमल जालान और डी.सुब्बाराव
(D) डी.सुब्बाराव और उर्जित पटेल

71. निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है?
(A) विटामिन (B) कार्बोहाइड्रेट
(C) प्रोटीन (D) वसा

72. निम्नलिखित में से कौनसा खाने का सोडा और धावन सोडा का क्रमशः रासायनिक नाम है?
(A) सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड
(B) सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट
(C) सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट
(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड

73. मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है?
(A) तंत्रिका तंत्र (B) यकृत
(C) अग्न्याशय (D) माँसपेशियाँ

74. निम्नलिखित पर विचार कीजिए–
1. डूरंड कप
2. आगा खान कप
3. सुब्रतो कप
4. संतोष ट्रॉफी
उपर्युक्त में से कौनसी ट्रॉफियाँ फुटबाल से सम्बन्धित हैं?
(A) 1, 2 और 3 केवल
(B) 1, 2 और 4 केवल
(C) 2, 3 और 4 केवल
(D) 1, 3 और 4 केवल

75. प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौनसा रंग अधिक क्रियाशील है?
(A) लाल (B) बैंगनी
(C) हरा (D) नारंगी

76. भारत में सफेद संगमरमर की खानों के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है?
(A) राजनगर (B) कटनी
(C) बिडसर (D) मकराना

77. निम्नलिखित में से कौनसा पेड़ भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक पर मुद्रित है?
(A) नीम (B) बरगद
(C) ताड़ (D) पीपल

78. निम्नलिखित में से कौनसा शहर विश्व की लहसुन राजधानी के रूप में जाना जाता है?

STUDYPDF WALLAH

(A) कैलिफोर्निया
(B) मुल्तान
(C) नैरोबी
(D) आंध्र प्रदेश

79. निम्नलिखित में कौनसी पुस्तक/पत्रिका सही सुमेलित नहीं है?

पुस्तकें/पत्रिका	लेखक
(A) गीता रहस्य	बाल गंगाधर तिलक
(B) आनंद मठ	बंकिम चंद्र चटर्जी
(C) दिव्य जीवन	महर्षि अरविंदो घोष
(D) अन्हैपी इंडिया	दादा भाई नैरोजी

80. निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था?
(A) पदशाहनामा
(B) मज्म उल-बहरैन
(C) शाहनामा
(D) मुताक्हब-उल-लुबाब

81. गिआक और किरी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है?
(A) नगालैण्ड (B) अल्मोड़ा
(C) ओडिशा (D) लद्दाख

82. पृथ्वी घूमती है–
(A) 1 मिनट में 2 डिग्री
(B) 4 मिनट में 1 डिग्री
(C) 6 मिनट में 1 डिग्री
(D) 10 मिनट में 2 डिग्री

83. वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौनसी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है?
(A) ऑक्सीजन
(B) नाइट्रस ऑक्साइड
(C) हाइड्रोजन सल्फाइड
(D) कार्बन डाइऑक्साइड

84. निम्नलिखित में से किस शैवाल को 'ग्रीन मोल्ड' के नाम से जाना जाता है?
(A) म्यूकस
(B) अस्कोमायकोटा
(C) एस्परजिलस
(D) पेनिसिलियम

85. एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है?
(A) क्षय (B) मलेरिया
(C) कुष्ठ रोग (D) पोलियो

86. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) किस केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है?
(A) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(B) गृह मंत्रालय
(C) कानून और न्याय मंत्रालय
(D) रक्षा मंत्रालय

87. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(A) जी वी रामकृष्ण समिति–विनिवेश
(B) भगवती समिति–कृषि ऋण प्रणाली
(C) राजा चेलैया समिति–भारत में कर सुधार
(D) धारिया समिति–सार्वजनिक वितरण प्रणाली

88. निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए–

राज्य	उ.प्र. की सीमा को स्पर्श करने वाले उनके जिले
(A) राजस्थान	– करौली
(B) छत्तीसगढ़	– बलरामपुर
(C) झारखण्ड	– गढ़वा
(D) हिमाचल प्रदेश	– सिरमौर

89. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?

प्रमुख स्थल	जिले
(A) गोला गोकर्णनाथ मन्दिर	–लखीमपुर खीरी
(B) झारखण्डेश्वर मन्दिर	–महोबा
(C) गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह	–बहराइच
(D) रेणुकेश्वर महादेव मन्दिर	–सोनभद्र

90. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?

शहर	– उपनाम
(A) जालौन	– शिराज-ए-हिन्द
(B) बदायूँ	– निजामुद्दीन औलिया नगर
(C) अमेठी	– छत्रपति शाहू जी महाराज नगर
(D) गाजीपुर	– काशी की बहन

91. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

नदियाँ	प्रमुख शहर
(A) गंगा नदी	– गढ़मुक्तेश्वर
(B) यमुना नदी	– बटेश्वर
(C) हिंडन नदी	– लखीमपुर खीरी
(D) राप्ती नदी	– संत कबीर नगर

92. 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' के सम्बन्ध में गलत कथन का चयन कीजिए?
(A) यह लगभग 340·8 किमी लम्बा एक्सप्रेसवे है.
(B) यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है.
(C) यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के नौ जिलों से होकर गुजरता है.
(D) यह एक्सप्रेसवे मऊ जिले से नहीं गुजरता है.

93. हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?
(A) इसकी स्थापना 1986 में की गई थी.
(B) यह 2073 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है.
(C) यह उत्तर प्रदेश के सात जिलों में फैला हुआ है.
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

94. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(A) श्रावण झूला मेला – अयोध्या
(B) गोविंद साहब मेला – अम्बेडकर नगर
(C) संकट मोचन संगीत समारोह – चित्राकूट
(D) नौचंदी मेला – मेरठ

95. उत्तर प्रदेश की 'एक जिला एक उत्पाद योजना' के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(A) आजमगढ़ – काली मिट्टी के बर्तन
(B) बस्ती – काष्ठ शिल्प
(C) फर्रुखाबाद – वस्त्र उत्पाद
(D) महोबा – गौरा पत्थर शिल्प

96. निम्नलिखित में से चंगेज खाँ के अधीन मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया?
(A) मुहम्मद-बिन-तुगलक
(B) बलबन
(C) फिरोजशाह तुगलक
(D) इल्तुतमिश

97. निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है?
(A) बरुआ सागर झील, झाँसी
(B) चित्तोरा झील, बहराइच
(C) समसपुर झील, रायबरेल
(D) बेलासागर झील, महोबा

98. विशेष आहरण अधिकार (SDR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. यह 1969 में IMF द्वारा बनाई गई एक अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित सम्पत्ति है.
2. इसका अपना मूल्य है यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं है.
3. यह न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा है.

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौनसे सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

STUDYPDF WALLAH

99. किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ?
(A) रोजगार की शर्तें
(B) उद्यमों का स्वामित्व
(C) कच्ची सामग्रियों का प्रयोग
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

100. 2028 ओलम्पिक के सम्बन्ध में निम्न-लिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. यह पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा.
2. अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने हाल ही में क्रिकेट को 2028 ओलम्पिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी है.

उपर्युक्त से कौनसा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

101. निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए–
(i) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73 प्रतिशत थी.
(ii) साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या पर मापा जाता है.
(A) केवल (i)
(B) केवल (ii)
(C) दोनों (i) और (ii)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

102. जनगणना, 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नतम साक्षरता दर वाले शीर्ष तीन जिलों का चयन कीजिए–
(i) श्रावस्ती (ii) बहराइच
(iii) बलरामपुर (iv) बदायूँ
(v) रामपुर
(A) (ii), (iii), (iv)
(B) (iii), (iv), (v)
(C) (i), (iii), (iv)
(D) (i), (ii), (iii)

103. निम्नलिखित में से कौनसी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में पाई जाती है?
(i) सहरिया जनजाति
(ii) पहरिया जनजाति
(iii) बैगा जनजाति
(iv) अगरिया जनजाति
(A) (i)] (ii) और (iii)
(B) (ii), (iii) और (iv)
(C) (i), (iii) और (iv)
(D) उपर्युक्त सभी

104. हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department–IMD) द्वारा जारी हीट इंडेक्स (Heat Index) को दर्शाने के लिए उपयोग किए गए रंग कोड (Colour Codes) में निम्नलिखित किस रंग का उपयोग नहीं किया गया है?
(A) लाल (Red)
(B) ऑरेंज (Orange)
(C) नीला (Blue)
(D) पीला (Yellow)

105. 2028 ओलम्पिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा?
(A) टेस्ट प्रारूप
(B) एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) प्रारूप
(C) टी 20 प्रारूप
(D) टी 10 प्रारूप

106. "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है?
(A) संयुक्त राष्ट्र
(B) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(C) विश्व खाद्य संगठन
(D) खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)

107. श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
(A) क्लाउडिया गोल्डिन
(B) कातालिन कारिको
(C) पियरे एगोस्टिनी
(D) फ़ेरेन्क क्राउज

108. पीएम स्वनिधि योजना के तहत् दी जाने वाली कार्यशील पूँजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है?
(A) ₹ 10 हजार
(B) ₹ 25 हजार
(C) ₹ 50 हजार
(D) ₹ 1 लाख

109. एशियाई खेलों में महिलाओं के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता?
(A) तेजस्विन शंकर
(B) प्रवीण चित्रवेल
(C) अन्नू रानी
(D) मोहम्मद अफ़सल

110. 1 अक्टूबर, 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया?
(A) डॉ इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
(B) डॉ. मोहम्मद मुइज्ज़ू
(C) अब्दुल्ला यामीन
(D) आरिफ अल्वी

111. हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का नाम क्या है?
(A) सनसाइकिल
(B) इकोपेडल
(C) सोलरराइड
(D) हेल्थवे

112. वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है?
(A) 81वाँ (B) 40वाँ
(C) 132वाँ (D) 23वाँ

113. भारतीय वायु सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति-2023 की सह-मेजबानी कब और कहाँ की गई?
(A) नई दिल्ली, भारत, अक्टूबर 2023 में
(B) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सितम्बर 2023 में
(C) मुम्बई, महाराष्ट्र, नवम्बर 2023 में
(D) बेंगलूरू, कर्नाटक, अगस्त 2023 में

114. दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
(A) मेगास्टार चिरंजीवी
(B) रेखा
(C) वहीदा रहमान
(D) रजनी कान्त

115. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी किस तिथि को मनाई जाती है?
(A) श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि
(B) माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि
(C) कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि
(D) भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि

116. नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं?
(A) राज पाल रेवल
(B) बिमल पटेल
(C) अनुपमा एस कुंडू
(D) बी वी दोशी

117. 21 से 25 सितम्बर, 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना

STUDYPDF WALLAH

(B) अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादों का प्रदर्शन करना
(C) उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना
(D) सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना

118. चंद्रयान-3 रोवर पर लगे लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) उपकरण का उद्देश्य क्या है?
(A) चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना
(B) चंद्र क्रेटर की उच्च-रिजॉल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए
(C) तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना
(D) चंद्रमा पर पानी की पूर्व उपस्थिति के संकेतों की खोज करना

119. कौनसा विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 को बदलने का प्रस्ताव करता है?
(A) भारतीय न्याय संहिता, 2023
(B) भारतीय न्याय प्रकृति संहिता, 2023
(C) भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

120. फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैम्पियन कौनसा देश बना?
(A) जर्मनी (B) स्पेन
(C) यूएसए (D) फ्रांस

121. आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है?
(A) वह दर जिस पर बैंक RBI को पैसा उधर देते हैं
(B) वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है
(C) वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को पैसा उधार देता है
(D) वह दर जिस पर बैंक एक-दूसरे को पैसा उधार देते हैं

122. 31वें विश्व विश्वविद्यालय खेल किस शहर में आयोजित हुए?
(A) नई दिल्ली, भारत
(B) बीजिंग, चीन
(C) चेंगदू, चीन
(D) टोक्यो, जापान

123. लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
(A) अमित शाह
(B) नरेंद्र मोदी
(C) नितिन गडकरी
(D) मेधा पाटकर

124. 29 जुलाई, 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है?
(A) 2,500 (B) 3,167
(C) 3,682 (D) 3,925

125. एशियाई क्रिकेट परिषद् (एसीसी) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
(A) जय शाह
(B) सौरव गांगुली
(C) एहसान मणि
(D) डेविड रिचर्डसन

126. लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाएं छोर से 864वें स्थान पर है, जबकि गीता दाएं छोर से 915वें स्थान पर है. जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो रीता का नया स्थान दाएं छोर से 915वाँ हो जाता है. पंक्ति में कितनी लड़कियाँ हैं?
(A) 1777
(B) 1778
(C) 1779
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

127. निर्देश सादृश्य को पूरा करने के लिए सम्बन्धित अक्षरों का पता लगाएं.
xxyzyy : ccbabb :: xyyzzy : ?
(A) abbacc
(B) bbacca
(C) abbcca
(D) cbbaab

128. निम्नलिखित में से कौनसी उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई शृंखला को पूरा कर सकती है?

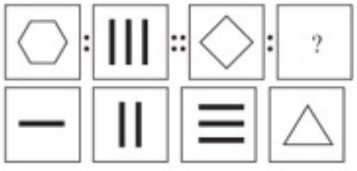

(A) (B) (C) (D)

129. दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित कर सकता है.

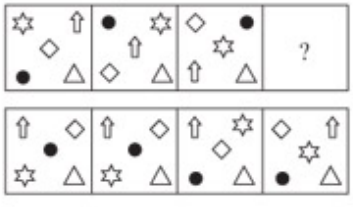

(A) (B) (C) (D)

130. A, B, C, D, E, F, G और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केन्द्र की ओर मुख करके बैठे हैं. C, G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है. E, A के ठीक बाएं बैठा है, जिसका मुख C की ओर है. H, A के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और B और F का निकटतम पडोसी नहीं है. D, E के बाएं से छठे स्थान पर बैठा है. B G के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है और F, B और C का निकटतम पडोसी है.
H के दाएं से पाँचवें स्थान पर कौन बैठा है?
(A) E (B) D
(C) A (D) F

131. उस आकृति का चयन कीजिए, जो शेष से भिन्न है.

S R E J K B V M W	V W K M E S J B R	K B W R U M S V E	E M S J V B K W R

(A) (B) (C) (D)

132. किसी निश्चित कूट भाषा में, U को C लिखा जाता है, K को H लिखा जाता है, L को U लिखा जाता है, N को E लिखा जाता है, S को L लिखा जाता है, E को K लिखा जाता है, C को N लिखा जाता है. उस भाषा में 'KNUCKLES' को कैसे लिखा जाएगा?
(A) KECNKUHL
(B) HECNHUKL
(C) HECNHULK
(D) CHUECKN

133. नीचे एक संख्या शृंखला दी गई है, जिसमें एक लुप्त संख्या है, जिसे 'a' द्वारा दर्शाया गया है, संख्या ज्ञात कीजिए.
2, 6, 12, a, 30, 42, 56
(A) 20 (B) 21
(C) 23 (D) 28

134. यदि 'x' का अर्थ 'जोड़', 'y' का अर्थ 'घटाना', 'z' का अर्थ 'भाग', 'p' का अर्थ 'गुणा' है, तो 10 x 10 y 5 z 5 के लिए क्या मान होगा?
(A) 21 (B) 23
(C) 17 (D) 19

135. दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शृंखला को पूरा करें.
AC XV EG TR IK ?
(A) PO (B) OM
(C) PN (D) QO

136. दिए गए वेन आरेख में 'समूह A' उनको दर्शाता है, जो 'अंग्रेजी' बोल सकते/सकती हैं, 'समूह B' उनको दर्शाता है, जो 'हिन्दी' बोल सकते/सकती हैं और 'समूह C' उनको दर्शाता है, जो 'मराठी' बोल सकते/सकती हैं. आरेख में दी गई

STUDYPDF WALLAH

संख्या उस खास श्रेणी में मौजूद व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है.

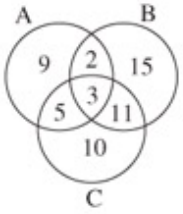

तो कितने व्यक्ति केवल दो ही भाषाओं में बोल सकते हैं?

(A) 16 (B) 24
(C) 12 (D) 18

137. जून 1984 को गुरुवार था. 7 जून, 1983 को कौनसा दिन था?
(A) मंगलवार (B) रविवार
(C) बुधवार (D) सोमवार

138. एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीष ने जीवन से कहा, "मैं उस तस्वीर में महिला का इकलौता बेटा हूँ और उसकी बेटी आपकी बुआ है" जीवन के दादा मनीष से कैसे सम्बन्धित हैं?
(A) पिता (A) भाई
(A) चाचा (A) दादा

139. इजरायल में फँसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है?
(A) 'ऑपरेशन विजय'
(B) 'ऑपरेशन सम्राट'
(C) 'ऑपरेशन गंगा'
(D) 'ऑपरेशन अजय'

140. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है?
(A) रोहित शर्मा
(B) डेविड वार्नर
(C) मोहम्मद रिजवान
(D) विराट कोहली

उत्तर व्याख्या सहित

1. (C) मधुबनी पेंटिंग को चावल के पेस्ट से बनाया जाता है और रंग के लिए हल्दी भी मिलाई जाती है. मधुबनी पेंटिंग एक लोक कला है, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न हुई है. मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों की जाती है. इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंग आमतौर पर चावल के पाउडर, हल्दी, चंदन, पराग, वर्णक, पौधों, गाय का गोबर, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जो चित्रकार खुद बनाता है. ये रंग प्रायः चमकदार होते हैं.
2. (C) पोचमपल्ली कपड़ा बुनने के लिए प्रसिद्ध है. पोचमपल्ली, तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है और इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, जिसे इकत (Ikat) नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है. पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक (GI Status) के रूप में दर्ज किया गया. पोचमपल्ली की अनूठी बुनाई शैलियों और पैटर्न पर प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) के उद्देश्य के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के एक भाग के रूप में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है.
3. (D) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) भारत के ओडिशा राज्य के राउरकेला में स्थित है. यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है. इसकी स्थापना 3 फरवरी, 1959 को हुई थी. इसका उद्घाटन पूर्व भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में किया था.
4. (B) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है.
केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 में (राजमुंदरी) आंध्र प्रदेश में हुई. यह कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत् भारत सरकार ने तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की.
5. (B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूँजी में भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और सम्बन्धित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है.
6. (B) हेरुका क्रोधी देवताओं की एक श्रेणी का नाम है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में प्रबुद्ध प्राणी जो भावुक प्राणियों को लाभान्वित करने के लिए उग्र रूप धारण करते हैं. पूर्वी एशिया में, इन्हें विजडम किंग्स कहा जाता है. हेरुका अविभाज्य आनंद और शून्यता के अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं.
7. (C) तबकात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाज-उस-सिराज हैं. इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरम्भिक इतिहास की लगभग 1260 ई. तक की जानकारी मिलती है. मिनहाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था.
8. (B) वर्तमान में सुश्री अनुसुइया उइके मणिपुर की राज्यपाल हैं. मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन ने 22 फरवरी, 2023 को नई राज्यपाल अनुसुइया उइके को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकीं सुश्री उइके मणिपुर की 19वीं राज्यपाल हैं. मणिपुर के तात्कालिक राज्यपाल रहे ला गणेशन को नगालैण्ड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया.
9. (A) कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है.
कावेरी जल विवाद—इसमें तीन राज्य और एक केन्द्रशासित प्रदेश (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी) शामिल हैं. वर्ष 1974 के बाद से कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना अपने चार नए जलाशयों में पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विवाद उत्पन्न हो गया है. इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में 'कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण' की स्थापना की गई, जिसने 17 वर्ष बाद यह निर्णय दिया कि कावेरी नदी के जल को सामान्य वर्षा की स्थिति में 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिए.
10. (A) विसरण के कारण ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुँचता है. किसी ठोस, द्रव्य या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता (Concentrations) वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है.
11. (C) नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की शुरूआत राज्य सभा के द्वारा की जा सकती है.
नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से हल करने के बाद ही बनाई जा सकती है. अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित है. अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) शामिल हैं.
12. (C) बलबन ने जिल्ल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी. गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में वंश का एक सम्राट् था. उसने 1265 से 1287 तक शासन किया. बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया. उन्हें 'जिल-ए-इलाही' की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया.

STUDYPDF WALLAH

13. (C) ओपन मार्केट ऑपरेशंस—सरकारी प्रतिभूति को बेचना और खरीदना.
ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के तहत् केन्द्रीय बैंक सरकारी सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल की खरीद और बिक्री करते हैं. भारत में यह काम आरबीआई करता है. आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है. आरबीआई जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है तो वह बाजार में सरकारी सिक्योरिटी खरीदता है. जब उसे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति घटाने की जरूरत महसूस होती है तो वह बाजार में सरकारी सिक्योरिटी बेचता है. इससे सिस्टम में लिक्विडिटी (पैसा) घट जाती है. सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की एक साथ बिक्री और खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रूप में जाना जाता है.

14. (A) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधरित थी. इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4·5% की वृद्धि दर के साथ घरेलू औद्योगिक उत्पादन पर जोर देना था. पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसके तहत् कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य था.

15. (B) भारत का सबसे पहला जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी है.
नीलगिरि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था. यह पश्चिमी घाटों में स्थित है और इसमें भारत के 10 जैव-भौगोलिक प्रान्तों में से 2 शामिल हैं. नीलगिरि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मालाबार वर्षा वन के जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

16. (D) ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के 'एम्सटर्डम' में स्थित है. ग्रीनपीस एक पर्यावरण संगठन है, लेकिन यह सरकारी संगठन नहीं है. इसकी स्थापना 1971 में कनाडा, वैनकूवर में हुई थी, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है.

17. (D) श्रीमती नाथीबाई दामोदार थाकेर्सेय (एसएनडीटी), भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय है. एसएनडीटी की स्थापना 5 जुलाई, 1916 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की. यह विश्वविद्यालय मुम्बई में स्थित है.

18. (B) भारत के चार शहरों (प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार) में कुम्भ का मेला लगता है.
कुंभ मेलों के प्रकार

महाकुंभ मेला	इस मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है. यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद आता है.
पूर्णकुंभ मेला	यह हर 12 वर्ष में आता है. इसे भारत में 4 कुंभ यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है. 12 वर्ष के अंतराल में इन 4 कुंभ में इस मेले का आयोजन बारी-बारी से होता है.
अर्ध कुंभ मेला	इसका अर्थ है आध कुंभ मेला जोकि हर 6 वर्ष में दो स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में होता है.
कुंभ मेला	इस मेले का आयोजन चार अलग-अलग स्थानों पर हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है.
माघ कुंभ मेला	माघ कुंभ मेला हर वर्ष माघ के महीने में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है.

19. (C) मनुष्यों में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है. अण्डाशय एक मादा जनन ग्रन्थि होती है. यह ग्रन्थि रिलेक्सिन हार्मोन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा करती है. रिलेक्सिन हार्मोन का कार्य शिशु के जन्म के समय प्यूबिस सिम्फायसिस के जोड़ में शिथिलता लाना होता है. अतः यह एक महत्वपूर्ण सहायक हार्मोन है, जो शिशु जन्म में सहायता प्रदान करता है.

20. (C) नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रबीन्द्र नाथ टैगोर थे. रवीन्द्र नाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया. रबीन्द्र नाथ टैगोर एकमात्र कवि थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनीं. भारत का राष्ट्रगान जन-गण-मन जिसे मूल रूप से बांग्ला भाषा में गुरुदेव रबीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा था और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला..... जिसमें बांग्लादेश का गुणगान है, गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की ही रचना है.

21. (D) यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है, तो आपका बुध ग्रह पर 14·4 किग्रा होगा, क्योंकि बुध पर सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सतह के गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% है.

22. (B) भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है. इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है.

23. (A) अमीर खुसरो आठ दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के गवाह थे. उन्हें तूती-ए-हिन्द और उर्दू साहित्य के पिता और कव्वाली के पिता के रूप में भी जाना जाता था.

24. (B) जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और अक्टूबर 1905 में इसे लागू किया गया.

25. (B) आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट् था. आलमगीर द्वितीय जिसे ऐज-उद-दीन के नाम से भी जाना जाता है, 1754 से 1759 के बीच भारत का सोलहवाँ मुगल सम्राट् था. प्लासी का यह युद्ध 23 जून, 1757 को हुआ था. इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना. कम्पनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नबाव सिराजुद्दौला को हरा दिया था.

26. (A) सैंडस्टोन एक कायान्तरित शैल नहीं है. कायान्तरित शैल के कुछ उदाहरण ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर आदि हैं.

27. (C) एलीफेंटा एक पश्चिमी तट द्वीप है. श्रीहरिकोटा, परिकुड़, पंबम पूर्वी तटीय द्वीप हैं.
एलीफेंटा द्वीप भारत के मुंबई हार्बर के पूर्व में कई द्वीपों में से एक है. यह द्वीप के गुफा मंदिरों, एलिफेंटा गुफाओं के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिन्हें चट्टानों पर तराशा गया है.

28. (A) रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, असम राज्य में स्थित है. असम के मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस-2021 (5 जून) के अवसर पर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान (Raimona National Park) को असम का छठवाँ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था.

29. (B) पृथ्वी के चुम्बकत्व के लिए वाह्य कोर उत्तरदायी है. पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र बाहरी कोर में पाया जाता है, बाहरी कोर तरल अवस्था में है. पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण तरल बाहरी कोर के अंदर का लोहा चारों ओर घूमकर एक चुम्बकीय क्षेत्र का निर्माण

STUDYPDF WALLAH

करता है. कई प्रकार की चट्टानों में लोहे के समान गुणधर्म वाले खनिज होते हैं जो छोटे चुम्बकों की तरह कार्य करते हैं. मैग्मा या लावा के शांत होने के बाद यह खनिज चुम्बकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होकर चट्टानों को संरक्षित करता है. लावा प्रवाह चुम्बकीय क्षेत्र के आदर्श परिचायक होते हैं.

30. (D) चित्रकोट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इन्द्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है. जलप्रपात की ऊँचाई लगभग 29 मीटर (95 फीट) है. यह भारत का सबसे चौड़ा झरना है, जिसकी चौड़ाई मानसून के दौरान लगभग 300 मीटर (980 फीट) तक पहुँच जाती है. इसकी चौड़ाई और मानसून में इसके व्यापक घोड़े की नाल के आकार के कारण, इसे प्रायः "भारत का नियाग्रा फॉल्स" भी कहा जाता है.

31. (B) भारत का विधि आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है, अतः यह एक कार्यकारी निकाय नहीं है. विधि आयोग केन्द्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित या स्वतः किसी मुद्दे पर कानून में शोध या भारत में विद्यमान कानूनों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने और नया कानून बनाने हेतु सिफारिश करता है. न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु यह अध्ययन और शोध का कार्य भी करता है ताकि प्रक्रिया में देरी को समाप्त किया जा सके, मामलों का त्वरित निपटारा हो और मुकदमों के खर्च में कमी की जा सके.

32. (B) अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुन-र्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है.यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है.

33. (A) कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है. कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन रहता है.
राजीव गौबा एक भारतीय सिविल सेवक हैं जो 2019 से भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत् हैं. वह झारखण्ड कैडर के 1982 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले, वह भारत के गृह सचिव थे.

34. (B) हमारे संविधान में जनगणना को संघ सूची में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत् जनगणना संघ का विषय है. यह संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है.

35. (C) ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग एक्स-रे की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किया जाता है.
ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर निर्माण में सामान्य ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर के समान है.ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार सर विलियम हेनरी ब्रैग ने किया था. सर विलियम हेनरी ब्रैग एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ, गणितज्ञ और सक्रिय खिलाड़ी थे, जिन्होंने विशिष्ट रूप से अपने बेटे लॉरेंस ब्रैग के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया था. उन्हें एक्स-रे के माध्यम से क्रिस्टल संरचना के विश्लेषण में उनके शोध के लिए 1915 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला. खनिज ब्रैगाइट का नाम उनके और उनके बेटे के नाम पर रखा गया है. 1920 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई.

36. (C) अकबर 13 वर्ष की उम्र में 1556 में राजा बना था. बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था. सत्ता में आने के तुरन्त बाद अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अफगान सेनाओं के जनरल हेमू को हरा दिया.

37. (B) सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है. यह प्रकाश के सभी दृश्य आवृत्तियों का एक सम्मिश्रण है.

38. (D) पृथ्वी भी एक चुम्बक के समान व्यवहार करती है तथा उसके भी दो भौगोलिक ध्रुव होते हैं. यदि एक चुम्बकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए, तो वह उत्तर-दक्षिण दिशा में ही रुकेगी, क्योंकि चुम्बक के उत्तर ध्रुव के सामने पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण तथा चुम्बक के दक्षिण ध्रुव के सामने पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर स्थित होता है.

39. (A) टीवी रिमोट इन्फ्रारेड तरंगों (अवरक्त प्रकाश तरंग) के सिद्धान्तों पर काम करता है. वर्तमान में टीवी रिमोट कंट्रोल वॉल्यूम, चैनल, प्लेबैक आदि को नियंत्रित करने के लिए विकिरण के डिजिटल-कोडित संदेशों को भेजने के लिए अवरक्त प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है. रिमोट कंट्रोल में ट्रांसमीटर उपयोगकर्ता द्वारा अवरक्त प्रकाश की किरणों की एक धारा भेजता है. हैंडसेट पर एक बटन दबाता है. डिवाइस में रिसीवर पैटर्न को पहचान और डिवाइस तदनुसार प्रतिक्रिया करता है.

40. (D) बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर केवलर नामक सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है. केवलर तरल रासायनिक मिश्रण से एक ठोस धागा कताई द्वारा उत्पादित किया जाता है. एक अन्य फाइबर, डाइनीमा है जिसे पॉलीथीन बेस से बनाया जाता है. यह बहुत मजबूत होने के साथ-साथ बहुत हल्का भी होता है. बुलेटप्रूफ जैकेट में दो परतें (Layers) होती हैं; सबसे ऊपर सैरैमिक पर्त होती है उसके बाद बैलिस्टिक पर्त लगाई जाती है.

41. (B) ऑस्मियम सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व (22·61 ग्राम प्रति घन सेमी) है. ऑस्मियम की खोज 1803 में स्मिथसन टेनेंट और विलियम हाइड वोलास्टन ने लंदन, इंगलैण्ड में की थी. लिथियम (0·534 ग्राम प्रति घन सेमी) सबसे हल्की धातु है.

42. (C) गामा-किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है. उनके पास उच्चतम ऊर्जा और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य भी हैं. रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्तियों और उच्चतम तरंगदैर्ध्य होते हैं. इन तरंगों का उच्चतम से निम्नतम ऊर्जाओं का क्रम है–**गामा किरणें > एक्स किरणें > यूवी किरणें > दृश्य प्रकाश > अवरक्त विकिरण > रेडियो तरंगें.**

43. (A) प्रति उर्ध्वपातन की अभिक्रिया में एक गैस बिना तरल अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में बदल जाती है.
उर्ध्वपातन (Sublimation) एक भौतिक-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है.

44. (A) पृथ्वी के वायुमण्डल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस आर्गन है. नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रचुर गैस है और ऑक्सीजन दूसरी सबसे प्रचुर गैस है.

45. (C) कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है. पृथ्वी के वायुमण्डल में प्राथमिक ग्रीनहाउस गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन हैं.

46. (B) अस्थमा के रोगी को कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है. समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर ऑक्सीजन-हीलियम मिश्रण का उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है, क्योंकि

STUDYPDF WALLAH

जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाता है, तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन उच्च दाब पर रक्त में विलेय हो जाती है. जब वह सतह पर आता है, तो दाब में कमी के कारण रक्त से नाइट्रोजन के बुलबुले बाहर निकल जाते हैं, जिससे दर्द की स्थिति उत्पन्न होती है. इस बीमारी को 'बेंड्स' कहा जाता है.

(D) लिथियम डाइक्रोमेट

47. (C) श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जाँच करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटैशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है. पोटैशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र $K_2Cr_2O_7$ है. पोटैशियम डाइक्रोमेट का उपयोग अनुसंधान सुविधाओं और उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है. इसका उपयोग काँच के बर्तनों को साफ करने और नक्काशी सामग्री के रूप में किया जाता है. इसका उपयोग बछड़े की खाल उद्योग में क्रोम टैनिंग के लिए किया जाता है. इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में वॉल्यूमेट्रिक परीक्षण के लिए भी किया जाता है.

48. (B) **सही सुमेल है–**

	ज्वालामुखी		देश
1.	कातला	(d)	आइसलैंड
2.	क्राकाटोआ	(b)	इंडोनेशिया
3.	माउंट विसुवियस	(a)	इटली
4.	किलिमंजारो	(c)	तंजानिया

49. (B) गोल्ड और प्लैटिनम जैसी नोबेल धातुएं एक्वा रेजिया नामक रसायन में घुलनशील हैं.
एक्वा रेजिया को किंग्स वाटर के रूप में भी जाना जाता है. यह 1: 3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है.

50. (B) तोमरों ने 736 पूर्वाह्न में दिल्ली शहर की स्थापना की थी. वे प्रतिहारों के सामंती प्रमुख थे, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया. 1043 में महिपाल तोमर ने थानेश्वर, हांसी और नगरकोट पर कब्जा जमाया. 12 वीं शताब्दी के मध्य में वे अजमेर के चौहानों की सुजैती के अधीन आए जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया.

51. (D) कार्डियक चक्र द्वारा एक चक्र पूरा करने के लिए लिया गया समय 0·8 सेकण्ड है. कार्डियक चक्र के तीन प्रमुख चरण हैं और वे हैं–(i) कार्डिक डायस्टोल, (ii) आर्टियल सिस्टोल, (iii) वेंट्रिकुलर सिस्टोल.

52. (A) सिरोसिस को लिवर सिरोसिस या हेपेटिक सिरोसिस के रूप में भी जाना जाता है. लिवर सिरोसिस धीमी गति से बढ़ने वाली लिवर की बीमारी है जिसमें संक्रमित व्यक्ति का लिवर अपने वास्तविक आकार में न रहकर सिकुड़ने लगता है और लचीलापन खोकर कठोर हो जाता है. इस रोग से ग्रसित मनुष्य के लिवर की कोशिकाएं (Parenchyma) बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तन्तुओं (Scarring) का निर्माण हो जाता है. इससे लिवर की कार्यप्रणाली में दिक्कते पैदा हो जाती हैं. ये स्कार ऊतक रक्त प्रवाह को रोक देते हैं (Portal hypertension) तथा पोषण और हार्मोन की प्रक्रियाओं को धीमा कर देते हैं.

53. (D) विटामिन बी 9 को फोलिक एसिड भी कहा जाता है. यह पानी में घुलनशील होने के साथ शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने और नए सेल्स बनाने में भी मददगार होता है. फॉलिक एसिड की कमी से हमेशा थकान, कमजोरी, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन, कब्ज, भोजन में अरुचि, वजन घटना, लूज मोशन, सिरदर्द, मुँह में छाले और असमय बाल सफेद होने जैसे लक्षण नजर आते हैं. शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं घटने लगती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों, मूँगफली, सूरजमुखी के बीज, ड्राई फ्रूट्स, पपीता, केला, संतरा, एवाकाडो, बींस, मटर, चुकंदर, अण्डे और सी फूड में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है.

54. (A) कुछ पौधों में बिना निषेचन के अण्डाशय से फल का निर्माण हो जाता है. इस तरह बिना निषेचित हुए फल के विकास को अनिषेकफलन या पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहते हैं. उदाहरण: केला, ककड़ी, अंगूर, संतरा, पपीता, नाशपाती, अनन्नास आदि.

55. (D) पुतली (नेत्र तारा), आईरिस में एक छोटा-सा छिद्र है, जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है. पुतली के आकार को अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है और यही कारण है कि जब हम एक अँधेरे कमरे से बाहर सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हम अपनी आँखों में चमक महसूस करते हैं वहीं अगर हम तेज धूप से अँधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ समय के बाद चीजें स्पष्ट दिखाई दे पाती हैं.

56. (B) आयोडीन समुद्री शैवाल (समुद्री घास) से प्राप्त होता है. आयोडीन के प्राकृतिक तेल स्रोत-सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है. इसके प्राकृतिक स्रोत हैं. (i) समुद्री घास (ii) चीली साल्ट पीटर या कैलिश (iii) प्राकृतिक ब्राइन. लैमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है. समुद्री घास को अच्छी तरह सूखाकर इसे गहरे गड्डों में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है. ताकि उपस्थित आयोडीन नष्ट नहीं हो.

57. (A) 23 अप्रैल, 1930 को जब महात्मा गांधी के अनुयायी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो नाराज भीड़ ने बख्तरबंद कारों और पुलिस फायरिंग का सामना करते हुए पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया. उन्हें ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का आग्रह करते हुए उत्मंजई में भाषण देने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अहिंसा के प्रति समझौतावादी निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए गफ्फार खान की प्रतिष्ठा ने अधिकांश स्थानीय नगरवासियों को विरोध में खुदाई खिदमतगार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया.

58. (D) न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (जन्म 11 नवम्बर, 1959) वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और 9 नवम्बर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुम्बई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं.

59. (A)

लोक संगीत	क्षेत्र
रसिया	ब्रजभूमि
कजरी	मिर्जापुर
आल्हा	बुंदेलखण्ड
बिरहा	पूर्वांचल

60. (C)

घराने	सम्बद्ध आँकड़ा
लखनऊ घराना	बख्शू खान
आगरा घराना	उस्ताद फैय्याज खान
सहारनपुर घराना	बहराम खान
इटावा घराना	उस्ताद विलायत खान

61. (B) उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए ₹ 2491 करोड़ का आवंटन किया गया है.

STUDYPDF WALLAH

62. (A) 2003 में वाजपेयी सरकार ने कर सुधारों की सिफारिश करने के लिए विजय केलकर के अधीन एक टास्क फोर्स का गठन किया था. इस समिति की प्रमुख सिफारिशें आयकर छूट सीमा बढ़ाने और धन कर आदि की समाप्ति से सम्बन्धित थीं.

63. (C) प्रसिद्ध काव्यग्रंथ 'रश्मिरेखा' के लेखक बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन' हैं. उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1960 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था. बाल कृष्ण शर्मा 'नवीन' एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. अपनी जेल यात्राओं के दौरान उन्होंने बहुत से साहित्यिक ग्रन्थों की रचना की जिनमें कुछ प्रमुख हैं– कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासि, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण तथा हम विषपायी जन्म के.

64. (C) **दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही क्रम है–**

	स्थल	स्थान
4	धोलावीरा	गुजरात
2	कालीबंगन	राजस्थान
3	हड़प्पा	पंजाब
4	माँडा	जम्मू

65. (B) **वैदिक काल के देवी/देवता से उनके सम्बन्धित शीर्षकों का सही मिलान है–**

	देवी/देवता		शीर्षक
1.	अश्विन	(d)	बीमारियों को दूर करने वाले देवता
2.	ऊषा	(c)	प्रातः की देवी
3.	आर्यनी	(b)	वन देवी
4.	मारुत	(a)	चक्रवात के देवता

66. (A)

	बाँध	नदी
1	नागार्जुन सागर	कृष्णा नदी (तेलंगाना)
2	इडुक्की	पेरियार (केरल)
3	अल्माटी	कृष्णा नदी (कर्नाटक)
4	अमरावती	अमरावती नदी (तमिलनाडु)

67. (B) वेंकटरामन अनंत नागेश्वरन एक भारतीय अर्थशास्त्री और भारत सरकार के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं. उन्होंने एशिया के अनुसंधान प्रमुख के रूप में कार्य करने के बाद स्विट्जरलैंड में बैंक जूलियस बेयर में वैश्विक मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया. सरकार ने जनवरी 2022 में डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था.

68. (B) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई, 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना की गई थी.

69. (C) जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बन्द कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तो विमुद्रीकरण कहते हैं. **यह स्वतंत्रता के बाद भारत में दो बार हुआ–**
(i) भारत का विमुद्रीकरण अधिनियम 1978, भारतीय संसद में पारित कानून है, जिसमें 5000, 10000 के उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का उपयोग बन्द कर दिया गया था.
(ii) 8 नवम्बर, 2016 को, भारत सरकार ने सभी 500 और 1,000 नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की.

70. (A) बेनेगल रामा राव 1 जुलाई, 1949 से 14 जनवरी, 1957 तक भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर थे जिनका अब तक का सबसे लम्बा कार्यकाल था, जबकि 16वें गवर्नर अमिताव घोष का 16 जनवरी से 4 फरवरी, 1985 तक मात्रा 20 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल था.

71. (B) मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है. शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइट में टूटकर तुरन्त ऊर्जा प्रदान करते हैं. उसके बाद प्रोटीन टूटता है. सबसे अन्त में वसा टूटती है. खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है. विटामिन्स शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है.

72. (B) सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र रासायनिक सूत्र $NaHCO_3$ है और सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है.

73. (A) ग्लाइकोलिपिड्स वे जटिल लिपिड हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से लेकर तंत्रिका तंत्र सिग्नलिंग तक कई जैविक कार्यों में शामिल होते हैं.
ग्लाइकोलिपिड्स जानवरों और पौधों जैसे यूकेरियोट्स में कोशिका झिल्ली के अभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं. विशिष्ट ग्लाइकोलिपिड दो मुख्य घटकों से बना होता है–लिपिड और कार्बोहाइड्रेट. लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ, पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले तीन मुख्य मैक्रोमोलेक्यूल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं. लिपिड बायोमोलेक्यूल्स हैं जो गैर-ध्रुवीय (औपचारिक चार्ज की कमी) और हाइड्रोफोबिक (पानी में अघुलनशील) दोनों हैं.

74. (D) डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबाल टूर्नामेंट है और दुनिया में सबसे पुराना है. इसका नाम इसके संस्थापक सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया. आगा खान कप हॉकी से सम्बन्धित है.

75. (A) प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का लाल रंग अधिक क्रियाशील है, क्योंकि सभी लाल रंग के प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होते हैं और प्रभावी रूप से उपयोग किए जाते हैं.
लाल रंग के प्रकाश में दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, जबकि बैंगनी में उच्चतम आवृत्ति और प्रकाश के दृश्यमान रंगों की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती है.

76. (D) मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान के नागौर जिले में स्थित हैं. ताजमहल के निर्माण में मकराना संगमरमर का उपयोग किया गया था. मकराना की सफेद मूर्तियाँ भी विशेष महत्व रखतीं हैं, क्योंकि यह केवल मकराना में ही बनती हैं. साथ ही इस पत्थर की क्वालिटी बाकी अन्य मार्बलों की तुलना में अलग होती है.

77. (C) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक प्रतीक में एक ताड़ का पेड़ और एक बाघ मुद्रित है. यह चिह्न औपनिवेशिक अतीत की निशानी है और इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतीक चिह्न से लिया गया है. ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतीक चिह्न में शेर और ताड़ का पेड़ था. शुरूआत में, RBI के प्रतीक चिह्न में शेर और ताड़ के पेड़ शामिल थे, लेकिन बाद में शेर को बाघ के साथ बदलने का निर्णय लिया गया.

78. (A) कैलिफ़ोर्निया अपनी लहसुन की फसल और वार्षिक लहसुन महोत्सव के लिए जाना जाता है, जिसमें लहसुन की आइसक्रीम जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं, इसीलिए शहर का

STUDYPDF WALLAH

उपनाम विश्व की लहसुन की राजधानी है.

79. (D) अन्हैपी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है, जबकि दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी (Poverty of India) और अनब्रिटिश रूल लिखा है जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया था.

80. (B) फारसी में लिखी गई पुस्तक 'मज्म-उल-बहरीन' दारा शिकोह द्वारा लिखी गई है. जिसका हिन्दी अर्थ 'दो महासागरों का संगम'.

81. (D) गियक और कियारी नामक नव-पाषाण स्थल भारत के लद्दाख में स्थित हैं. वे सिंधु नदी के बाएं किनारे पर समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है. 1990 के दशक की शुरूआत में डॉ. मासाटो ओटा के नेतृत्व में जापानी पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा खुदाई की गई थी. उत्खनन से एक नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं जो लद्दाख में 6000 और 3000 ईसा पूर्व के बीच पनपी थी. इस संस्कृति के लोग गड्डे वाले घरों में रहते थे, फसलें उगाते थे और पशुओं को पालते थे. उन्होंने मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और आभूषण भी बनाए.

82. (B) पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है इसलिए यह 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी.

83. (C) वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग खराब हो जाता है. हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र H_2S है.

84. (D) कुछ सामान्य प्रकार के शैवाल जो हरे दिखाई देते हैं वे निम्न हैं—क्लैडोसपोरियम, एस्परगिलस और पेनिसिलियम.
हरी शैवाल शैवाल का एक बड़ा, अनौपचारिक समूह है जिसमें क्लोरोफाइटा और चारोफाइटा/स्ट्रेप्टोफाइटा शामिल हैं. हरे शैवाल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, जो उन्हें एक चमकीले हरे रंग के साथ-साथ स्टैक्ड थायलाकोइड्स में सहायक वर्णक बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल प्रदान करते हैं. हरे शैवाल की कोशिका भित्ति में आमतौर पर सेल्यूलोज होता है, और वे स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करते हैं.

85. (C) कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए मल्टीड्रग थेरेपी (एमडीटी) का उपयोग किया जाता है.
कुष्ठ रोग को हेन्संस रोग भी कहा जाता है और यह धीमी गति से बढ़ने वाले एक जीवाणु मायकोबैक्टीरिया लेप्रे की वजह से होता है. जीवाणु के सम्पर्क में आने के बाद इसके लक्षण दिखने में 3-5 वर्ष लग जाते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1995 में विकसित मल्टी-ड्रग थेरेपी इस संक्रमण के इलाज में बेहद प्रभावी पाई गई है. भारत सरकार कुष्ठ रोग का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराती है.

86. (B) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है.
इसकी स्थापना 16 अक्टूबर, 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और आंतरिक विद्रोह से राज्यों की रक्षा के लिए की गई थी. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 के तहत् भारत की संसद में औपचारिक रूप दिया गया. यह भारत के सात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है.

87. (B) भगवती समिति बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण से सम्बन्धित है. इसका गठन मई 1976 में न्यायमूर्ति भगवती की अध्यक्षता में हुआ था. इस समिति ने गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के सम्बन्ध में जोरदार सिफारिश की. जिसके बाद संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में जोड़ा गया.

88. (A) राजस्थान का करौली जिला मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है.
राज्यों जिले, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करतें हैं—

राज्य	उ.प्र. की सीमा को स्पर्श करने वाले उनके जिले
राजस्थान	भरतपुर और धौलपुर
छत्तीसगढ़	बलरामपुर
झारखण्ड	गढ़वा
हिमाचल प्रदेश	सिरमौर

89. (B) सही सुमेल हैं—

प्रमुख स्थल	जिले
गोला गोकर्णनाथ मन्दिर	लखीमपुर खीरी
झारखण्डेश्वर मन्दिर	हापुड़
गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह	बहराइच
रेणुकेश्वर महादेव मन्दिर	सोनभद्र

90. (A) सही सुमेल है—

शहर	उपनाम
जौनपुर	शिराज–ए–हिन्द
बदायूँ	निजामुद्दीन औलिया नगर
अमेठी	छत्रपति शाहू जी महाराज नगर
गाजीपुर	काशी की बहन

91. (C) लखीमपुर खीरी से होकर गोमती नदी प्रवाहित होती है.
सही सुमेल है—

नदियाँ	प्रमुख शहर
गंगा नदी	गढ़मुक्तेश्वर
यमुना नदी	बटेश्वर
हिंडन नदी	गाजियाबाद
राप्ती नदी	संत कबीर नगर

92. (D) यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के नौ जिलों—**लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ** और गाजीपुर से होकर गुजरता है.
यह एक 6-लेन का (प्रत्येक दिशा में 3-लेन) एक्सप्रेसवे है जिसे आठ लेन तक बढाए जा सकने लायक बनाया गया है. इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में यूपीडा के द्वारा इसके भूमि अधिग्रहण के समाप्ति और प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद शुरू हुआ और 16 नवम्बर, 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने के बाद जनता को समर्पित हुआ. बाद में इस एक्सप्रेसवे को एक लिंकवे द्वारा आजमगढ़ में सलारपुर गाँव के पास से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा गोरखपुर के जैतपुर गाँव से और आजमगढ़-वाराणसी राजमार्ग से भी जोड़ा जाना है.

93. (D) हस्तिनापुर अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी.
2073 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में मृग, सांभर, चीतल, नीलगाय, तेंदुआ, हैना, जंगली बिल्ली आदि पशुओं के अलावा पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं.
यह अभ्यारण्य उ. प्र. के सात जिलों—मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद तथा गाजियाबाद में फैला हुआ है.

94. (C) सही सुमेल है—

मेला	जनपद
श्रावण झूला मेला	अयोध्या

STUDYPDF WALLAH

गोविंद साहब मेला	अम्बेडकर नगर
संकट मोचन संगीत समारोह	चित्राकूट
नौचंदी मेला	मेरठ

95. (C) उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्रुखाबाद की ब्लाक प्रिंटिंग को "एक जिला एक उत्पाद" योजना में शामिल किया है. फर्रुखाबाद (पीतल तथा लकड़ी की बनी डाइयों) ब्लाक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है. ये ब्लाक कम्बलों के आवरण, शालों, साड़ियों, सूट, स्कार्फ, स्टोल्स आदि पर प्रयोग लिए जाते हैं. यहाँ निर्मित उत्पादों की माँग न केवल भारत बल्कि अमरीका, ब्राजील एवं बहुत से एशियाई व यूरोपीय देशों में है.
'एक जिला एक उत्पाद' योजना की शुरूआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस पर की थी.

96. (D) मंगोलों ने भारत पर आक्रमण चंगेज खाँ के नेतृत्व में किया, उस समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था.
मंगोल साम्राज्य ने वर्ष 1221 से 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने के कई प्रयास किए. मंगोलों का उदय मंगोल नेता चंगेज खाँ के आगमन के साथ शुरू हुआ, जो खुद को 'ईश्वर का अभिशाप' कहने में गर्व महसूस करता था. मंगोलों ने 1218 में ख्वारिज्मी साम्राज्य पर हमला किया. मंगोल आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर गम्भीर प्रभाव पड़ा. इल्तुतमिश, जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, ने मंगोलों को शांत कराने करने की कोशिश की. इसके परिणामस्वरूप मंगोलों के हमलों की एक श्रृंखला हुई और सिंधु नदी भारत की पश्चिमी सीमा नहीं रही. अंततः इल्तुतमिश लाहौर और मुल्तान दोनों को जीतने में सक्षम था, इस प्रकार मंगोलों के खिलाफ रक्षा की काफी मजबूत रेखा बन गया.

97. (D) उ.प्र. के महोबा जनपद में स्थित बेलासागर झील एक कृत्रिम झील है.
बेलासागर की इस झील का निर्माण जैतपुर के राजा परीक्षित ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अपनी पत्नी बेला की प्रेमपूर्ण स्मृति में करवाया था और यह 8 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है.

98. (C) विशेष आहरण अधिकार (SDR) एक अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित सम्पत्ति है, जिसे 1969 में आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भण्डार के पूरक के लिए बनाया गया था. अतः कथन I सही है. इसका मूल्य अमरीकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की पाँच मुद्राओं की टोकरी पर आधारित है. अतः कथन 2 सही नहीं है. यह न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा है.

99. (B) उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है. निजी क्षेत्र या उद्यम वे व्यवसाय हैं जिनका स्वामित्व एक निजी समूह या एक व्यक्ति के पास होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र या उद्यम ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है.

100. (B) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने हाल ही में 2028 लॉस एंजिल्स ओलम्पिक के लिए क्रिकेट को मंजूरी दे दी है. बेसबाल/सॉफ्टबाल, फ्लैग फुटबाल, स्क्वैश और लैक्रोस के साथ क्रिकेट को 2028 लॉस एंजिल्स (LA) ओलम्पिक में शामिल किया जाएगा.

101. (C) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73 प्रतिशत थी. साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या पर मापा जाता है. साक्षरता दर उन व्यक्तियों की संख्या है जो 7 वर्ष या उससे अधिक हैं और किसी भी भाषा में पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता रखते हैं. यह किसी देश की सामाजिक–आर्थिक प्रगति को दर्शाता है.

102. (D) सबसे कम साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 जिले–
श्रावस्ती<बहराइच<बलरामपुर<बदायूँ<रामपुर

103. (B) सहरिया एक अनुसूचित जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जिले में पाई जाती है. उन्हें बनारावत, रावत, सोरेन और बनारखा भी कहा जाता है.
सोनभद्र जिले में बड़ी संख्या में बैगा, पहरिया जनजाति, भील, अगरिया जनजाति, गोंड, खरवार, मुसहर, परजा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं.

104. (C) हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department–IMD) द्वारा जारी हीट इंडेक्स (Heat Index) को दर्शाने के लिए उपयोग किए गए रंग कोड (Colour Codes) में नीले रंग का उपयोग नहीं किया गया है.

रंग कोड	हीट इंडेक्स
हरा	प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 35 डिग्री सेल्सियस से कम.
पीला	36–45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक गर्मी सूचकांक.
ऑरेंज	प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 46–55 डिग्री सेल्सियस की सीमा में.
लाल	प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक

105. (C) टी 20 प्रारूप
2028 के ओलम्पिक में क्रिकेट को शामिल किया जाना तय है. 13 अक्टूबर, 2023 को, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (IOC के कार्यकारी बोर्ड ने कार्यक्रम में क्रिकेट को शामिल करने के लॉस एंजिल्स खेल आयोजकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. क्रिकेट, टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. चार अन्य खेलों बेसबाल-सॉफ्टबाल, फ्लैग फुटबाल, लैक्रोस सिक्स और स्क्वैश को भी आईओसी कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी मिल गई, जिसकी मुंबई में अध्यक्ष थॉमस बाख की अध्यक्षता में बैठक हुई.

106. (B) वर्ल्ड फूड इंडिया, 3 नवम्बर से 5 नवम्बर, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होने वाला है. यह कार्यक्रम भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है.

107. (A) अमरीकी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर उनके शोध के लिए 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार का आधिकारिक नाम 'Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences' है.

108. (C) 1 जून, 2020 को शुरू की गई यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को ₹ 50 हजार तक का सम्पार्श्विक–मुक्त कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करती है.

109. (C) अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक फाइनल में 62·92 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता. अन्नू रानी ने 69·92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता. वह एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. अन्नू ने 2020

STUDYPDF WALLAH

टोक्यो ओलम्पिक (2021 में खेला गया था) के लिए क्वालिफाई किया था इसके अलावा वह राष्ट्रमण्डल खेलों में भी भाला फेंक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट भी हैं. 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल खेलों में अन्नू ने कांस्य जीता था.

110. (B) डॉ. मोहम्मद मुइज्जू को 1 अक्टूबर, 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था. उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की.

111. (D) भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक, जिसका नाम 'हेल्थवे' है, का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 2023 को हैदराबाद में किया गया. 23 किमी लम्बा साइक्लिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर स्थित है, जो मुख्य कैरिजवे और सर्विस सड़क के बीच स्थित है.

112. (B) भारत ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी है. रैंकिंग विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी, और जीआईआई रैंकिंग में भारत के लगातार सुधार पर प्रकाश डाला गया था.

113. (B) भारत ड्रोन शक्ति-2023 की सह-मेजबानी 25 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायु सेना के एयरबेस पर भारतीय वायु सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई.

114. (C) बॉलीवुड की मशहूर अदाकार वहीदा रहमान को इस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है. इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन, फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है. इस पुरस्कार में 10 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है. यह पुरस्कार पहली बार 1969 में शुरू किया गया था.

115. (D) हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करते हैं. लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति को विराजमान करते हैं. अनंत चतुर्दशी के लिए गणपति को विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है.

116. (B) नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल हैं. भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया. इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था. 19 सितम्बर, 2023 को इस नवीन संसद भवन में प्रवेश किया गया. और एक ऐतिहासिक बिल महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया. जिसने संसद के एक नए अध्याय की शुरूआत की. यह बिल 27 वर्षो से लम्बित था. जो सर्व सम्मति से पारित हुआ.

117. (C) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 सितम्बर, 2023 को ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया. यह कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया, जो 25 सितम्बर, 2023 तक चला.

118. (C) चंद्रयान-3 रोवर पर लगे लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) उपकरण का उद्देश्य 'तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना' है.
लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) रोवर प्रज्ञान पर लगे लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चन्द्रमा की सतह की मौलिक संरचना पर पहली बार इन-सीटू मेजरमेंट लिया गया है. ये इन-सीटू मेजरमेंट स्पष्ट रूप से क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करता है. यह कुछ ऐसा है जो ऑर्बिटर पर लगे उपकरणों द्वारा सम्भव नहीं था.

119. (A) केन्द्र ने 11 अगस्त, 2023 को लोक सभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं. तीन विधेयक भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी), 1860 को बदलने के लिए निर्धारित हैं; दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872.

120. (B) स्पेन ने 20 अगस्त, 2023 को सिडनी के स्टेडियम आस्ट्रेलिया में फाइनल में इंगलैण्ड को 1–0 से हराकर अपना पहला फीफा महिला विश्व कप खिताब जीता.

121. (B) रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार तीसरी बार प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित बनाए रखा है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 10 अगस्त, 2023 को सर्वसम्मति से रेपो दर को 6·5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया.

122. (C) चीन के चेंगदू में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए 31वें विश्व विश्व-विद्यालय खेलों में भारत के एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. उन्होंने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीते.

123. (B) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार उन्हें तिलक स्मारक मन्दिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक द्वारा प्रदान किया गया. लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि पर देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है.

124. (D) भारत में बाघों की आबादी 6·1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 होने का अनुमान है. यह रिपोर्ट 29 जुलाई, 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा जारी की गई थी.

125. (A) जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष हैं.
एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद् की स्थापना 1983 में की गई थी. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् के अधीनस्थ, परिषद् महाद्वीप का क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय है, और वर्तमान में इसमें 25 सदस्य संघ शामिल हैं. वर्तमान एसीसी का मुख्यालय कोलम्बो, श्रीलंका में है, जिसे आधिकारिक तौर पर 20 अगस्त, 2016 को खोला गया था.

126. (D) दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है.

127. (D)

x	x	y	z	y	y
↓	↓	↓	↓	↓	↓
c	c	b	a	b	b

विपरीत अक्षरों के जोड़े

इसलिए,

x	x	y	z	y	y
↓	↓	↓	↓	↓	↓
c	c	b	a	b	b

STUDYPDF WALLAH

128. (B) पहली आकृति 6 पंक्तियों से बनी है और इसे 2 से विभाजित करने पर हमें 3 प्राप्त होता है इसलिए 3 को रोमन अंकों में लिखा जाता है. इसी तरह का पैटर्न तीसरे और चौथी आकृति में है.

129. (A) तत्वों का एक आकृति में जगह बदलना नीचे दिए गए आरेख के अनुसार है और त्रिभुज अपने आप को क्रमागत आकृतियों में बड़ा और छोटा बनाता है.

अतः, 'विकल्प (A)' सही उत्तर है.

130. (C)

A, H के दाएं से पाँचवें स्थान पर बैठा है.

131. (C)

K	B	W
R	U	M
S	V	E

विकल्प (C) में J को U द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है.

132. (B)

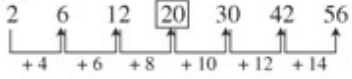

U ⟷ C   K N U C K L E S
K ⟷ H   ↓↓↓↓↓↓↓↓
L ⟷ U   H E C N H U K L
N ⟷ E
S ⟷ L
E ⟷ K
C ⟷ N

अतः विकल्प (B) सही उत्तर है.

133. (A)

2   6   12   [20]   30   42   56
+4   +6   +8   +10   +12   +14

अतः लुप्त संख्या 'a' का मान 20 है.

134. (D) उचित संकेतो का प्रयोग करते हुए, हम प्राप्त करते हैं.

$10\ x\ 10\ y\ 5\ \ z\ 5$

$10 + 10 - 5 \div 5 = 19$

135. (C) दी गई शृंखला में दो शृंखलाएं हैं.

शृंखला 1 :

A +4 E +4 I

C +4 G +4 K

शृंखला 2 :

X −4 T −4 **P**

V −4 R −4 **N**

136. (D) 2 + 11 + 5 = 18

अतः 18 व्यक्ति ठीक दो भाषाएँ बोल सकते हैं.

137. (A) यह देखते हुए कि 7 जून, 1984 को गुरुवार था.

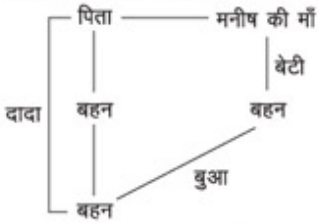

7 जून, 1983 से 7 जून, 1984 तक विषम दिनों की संख्या = 2 क्योंकि 1984 एक लीप वर्ष है.

अतः 7 जून, 1983 को दिन मंगलवार था.

138. (A) जीवन के दादा मनीष के पिता हैं.

139. (D) ऑपरेशन 'अजय' के तहत् भारत सरकार इजरायल में फँसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का अभियान चलाया है. पहली फ्लाइट में 212 भारतीयों को इजरायल से सुरक्षित लाया गया है. गौरतलब है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच कई भारतीय वहाँ फँसे हुए हैं.

140. (A) विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके साथ ही उन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक का भी रिकॉर्ड बना दिया. रोहित एकदिवसीय विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

●●●

शेष पृष्ठ 139 का

एक्सचेंज के रूप में एनएसई ने बीएसई को पीछे छोड़ दिया.

73. (A)

74. (D) किसी राष्ट्र के व्यापार की शर्तों को उसके निर्यात की कीमत और उसके आयात की कीमत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है. चूँकि दो-राष्ट्र के मॉडल में, एक राष्ट्र का निर्यात उसके व्यापार भागीदार का आयात होता है, दूसरे देश के व्यापार की शर्तें पूर्व के व्यापार की शर्तों के व्युत्क्रम, या पारस्परिक के बराबर होती हैं.

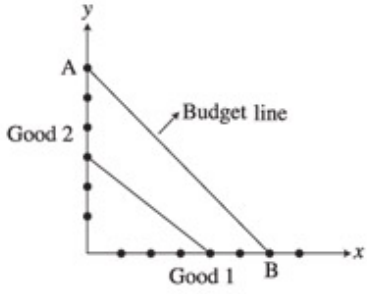

75. (B)   76. (B)

77. (A) G-20 की 18वीं बैठक का आदर्श वाक्य है "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" वसुधैव कुटुम्बकम्.

78. (B) ऊर्ध्वाधर अंतःखंड घट जाता है और क्षैतिज अंतःखंड वही रहता है. इस प्रकार बजट रेखा समतल हो जाती है.

79. (D)

80. (*) 'विदेशी विनियमन अधिनियम' जैसा कोई अधिनियम कभी नहीं बनाया गया था, इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं है.

81. (C) परिवेश मानक, जो प्राप्त वातावरण में स्वीकार्य प्रदूषण सांद्रता पर सीमा निर्धारित करते हैं.

82. (C)   83. (B)

84. (D) मानव विकास सूचकांक जीवन की प्रत्याशा के आधार पर मापित दीर्घ और स्वस्थ जीवन; स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और अध्ययन के औसत वर्ष द्वारा मापित ज्ञान; प्रति व्यक्ति जीएनआई द्वारा मापित जीवन स्तर का एक समग्र माप है.

85. (C)   86. (B)

87. (A) आईएडीपी को खरीफ 1960 से शुरू किया गया था. यह कार्यक्रम सभी उन्नत प्रथाओं के सामूहिक और एक साथ अपनाने के कारण लोकप्रिय रूप से 'पैकेज कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था : अर्थात् उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण, उपकरण, भंडारण सुविधाएं, विपणन सुविधाएं और ऋण आदि. प्रारंभ में इस कार्यक्रम के तहत 7 जिलों को शामिल किया गया था, अर्थात् (1) तंजावुर (तमिलनाडु), (2) पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश), (3) साहाबाद (बिहार), (4) रायपुर (म.प्र.), (5) अलीगढ़ (उ.प्र.), (6) लुधियाना (पंजाब), (7) पाली (राजस्थान), (19) डब्ल्यू के खरीफ के दौरान, (9) अतिरिक्त जिले शामिल किए गए थे (1) एलेप्पी (केरल), (2) पालघाट (केरल), (3) मांड्या (कर्नाटक), (4) सूरत (गुजरात), (5) संबलपुर (उड़ीसा), (6) बर्दवान (पश्चिम बंगाल), (7) कछार (असम), (8) भंडारा (महाराष्ट्र), (9) जम्मू और कश्मीर में छह ब्लॉक.

88. (C) 89. (D) 90. (A) 91. (B) 92. (D)

93. (D) 94. (C) 95. (A) 96. (D) 97. (D)

98. (B) 99. (B) 100. (C) ●●●

STUDYPDF WALLAH

आगामी बैंक पी.ओ., एम.बी.ए. आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न

उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता

1. किसानों की मदद के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत् कितने रुपए प्रति वर्ष की राशि पात्र किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है ?
   (A) ₹ 2000 (B) ₹ 4000
   (C) ₹ 6000 (D) ₹ 8000
2. पीएम किसान योजना के तहत् प्रति वर्ष देय वित्तीय सहायता कितनी किश्तों में सरकार द्वारा किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है ?
   (A) 1 (B) 2
   (C) 3 (D) 4
3. पीएम किसान योजना के तहत् सहायता की एक किश्त नवम्बर 2023 में किसानों को प्रदान की गई. यह इस योजना के तहत् अब तक की कौनसी किश्त थी ?
   (A) 12वीं (B) 13वीं
   (C) 14वीं (D) 15वीं
4. निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष हैं ?
   (A) नितिन गुप्ता
   (B) अरिंदम बागची
   (C) अरबिंद विरमानी
   (D) गौरव द्विवेदी
5. निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपना दूतावास स्थायी रूप से नवम्बर 2023 में बंद कर दिया है ?
   (A) अफगानिस्तान
   (B) कतर
   (C) ईरान
   (D) तुर्किये
6. नवम्बर 2023 में भारत के 42वें अन्तर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ हुआ था ?
   (A) नई दिल्ली (B) नोएडा
   (C) गुरुग्राम (D) चंडीगढ़
7. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कितने-कितने समय के अंतराल पर होता है ?
   (A) 6-6 माह
   (B) प्रति वर्ष
   (C) 2-2 वर्ष के अंतराल पर
   (D) 3-3 वर्ष के अंतराल पर
8. नवम्बर 2023 में भारत के 42वें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन राज्यों को भागीदार राज्य (Partner State) का दर्जा प्राप्त था ?
   (A) बिहार व झारखण्ड
   (B) झारखण्ड व पंजाब
   (C) पंजाब व बिहार
   (D) बिहार व केरल
9. नवम्बर 2023 में भारत के 42वें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी ?
   (A) आत्मनिर्भर भारत
   (B) मेक इन इंडिया
   (C) वसुधैव कुटुम्बकम
   (D) वोकल फॉर लोकल
10. 2023-24 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में अनिवेश से कुल कितनी राशि जुटाने का सरकार का लक्ष्य है ?
    (A) ₹ 41,000 करोड़
    (B) ₹ 51,000 करोड़
    (C) ₹ 61,000 करोड़
    (D) ₹ 71,000 करोड़
11. 2024-25 के दौरान किसानों को अपनी किस उपज के विपणन से उपज की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान है ?
    (A) गेहूँ (B) जौ
    (C) चना (D) सरसों
12. रबी उपजों के लिए 2024-25 के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के तहत् किस उपज के मामले में सबसे कम वृद्धि सरकार ने की है ?
    (A) गेहूँ (B) जौ
    (C) चना (D) सरसों
13. वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौनसे देश भूख की स्थिति के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में हैं ?
    (A) श्रीलंका व नेपाल
    (B) नेपाल व बांग्लादेश
    (C) म्यांमार व पाकिस्तान
    (D) उपुर्यक्त सभी
14. सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में आरक्षण के लिए बिहार में नवम्बर 2023 में लागू किए गए संशोधन अधिनियम के तहत् आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अब कितने प्रतिशत रह गया है ?
    (A) शून्य
    (B) 5 प्रतिशत
    (C) 7·5 प्रतिशत
    (D) पूर्ववत् 10 प्रतिशत
15. वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (H_1) में निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक वृद्धि प्राप्त की गई ?
    (A) वस्तुगत निर्यात
    (B) वस्तुगत आयात
    (C) सेवाओं का आयात
    (D) सेवाओं का निर्यात
16. पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी ?
    (A) 41 लाख
    (B) 51 लाख
    (C) 61 लाख
    (D) लगभग 1 करोड़
17. मंत्रालय की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में से सर्वाधिक पर्यटक, अमरीका के थे. इस मामले में दूसरा स्थान किस देश का था ?
    (A) ब्रिटेन
    (B) जापान
    (C) संयुक्त अरब अमीरात
    (D) बांग्लादेश
18. पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा रही (लगभग)—
    (A) 18 मिलियन डॉलर
    (B) 20 मिलियन डॉलर
    (C) 22 मिलियन डॉलर
    (D) 24 मिलियन डॉलर
19. भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक लोगों ने किस देश की यात्रा वर्ष 2022 के दौरान की ?
    (A) संयुक्त अरब अमीरात
    (B) सऊदी अरब
    (C) कतर
    (D) अमरीका

शेष पृष्ठ 164 पर

STUDYPDF WALLAH

वर्षांत समीक्षा 2022

रेल मंत्रालय

जॉन मथाई-भारत के पहले रेल मंत्री

चैलियाल जॉन मथाई का जन्म 10 जनवरी, 1886 को कोझिकोड में एक रूढ़िवादी सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था. उन्होंने 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उनका विवाह अचम्मा से हुआ था और उनके 3 बच्चे थे, वलसा, दलीप और रवि. 1908 में उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और 1910 में बीएल पूरा किया. बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट अनुसंधान किया. मथाई कांग्रेस पार्टी के टिकट पर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए थे. डॉ. जॉन मथाई का 2 नवम्बर, 1959 को बम्बई में निधन हो गया.

उपलब्धियाँ

- *1918 में मथाई मद्रास सरकार के सहकारी विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी बन गए. उन्होंने 1925 तक प्रेसीडेंसी कॉलेज में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया. वह एक सक्रिय सरकारी सेवक बन गए, उनकी आर्थिक कुशलता के कारण उन्हें 1940 में टाटा द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था.*
- *स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में कार्य किया. 1948 में उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया गया. उन्होंने वर्ष 1949-51 के बीच दो बजट पेश किए.*
- *वह बॉम्बे विश्वविद्यालय (1955-57) और केरल विश्वविद्यालय (1957-59) के कुलपति बने.*
- *शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के परिणामस्वरूप, उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.*

वर्ष 2022 के दौरान रेल मंत्रालय की उपलब्धियाँ

सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करना

सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सामने आई हैं. इन ट्रेनों में अति आधुनिक विशेषताएं हैं जैसे त्वरित त्वरण, यात्रा समय में पर्याप्त कमी, 160 किमी प्रति घण्टे की अधिकतम गति, ऑन-बोर्ड इंफोटेनमेंट और जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, रिट्रक्टेबिल फुटस्टेप्स और जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम बायो शौचालय, सीसीटीवी कैमरे वैश्विक मानकों के अनुसार कैमरे अन्य समकालीन विशेषताएं उपलब्ध हैं. वर्ष 2022 के दौरान, भारतीय रेलवे में छह वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं.

विस्टाडोम कोच-परिचय

विस्टाडोम कोच यात्रियों को उन स्थानों की प्राकृतिक सुन्दरता का आनंद लेने में सक्षम बनाता है जहाँ-जहाँ की वे यात्रा करते हैं. नवम्बर 2022 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न खण्डों में 82 विस्टाडोम कोच उपलब्ध हैं, निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं–

- कोच की अंतिम दीवार पर बड़ी खिड़की के साथ ऑब्जर्वेशन लाउंज,
- पारदर्शी बड़ी खिड़कियाँ,
- छत में विद्युत रूप से नियंत्रित ओपलेसेंस ग्लास खिड़कियाँ,
- डिजाइन किए गए एफआरपी आन्तरिक और एर्गोनॉमिक रूप से 180 डिग्री रोटेटिंग सुविधा के साथ डिजाइन की गई रिक्लाइनिंग सीटें,
- जीपीएस आधारित 'सार्वजनिक सम्बोधन एवं यात्री सूचना प्रणाली (पीएपीआईएस),
- दोनों तरफ कम्पार्टमेंट एंट्री पर स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे,
- प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम और बायो टैंक के साथ एफआरपी मॉड्यूलर शौचालय,
- अलार्म सिस्टम के साथ एस्पिरेशन टाइप ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन, सीसीटीवी प्रणाली.

तेजस राजधानी ट्रेन-परिचय

भारतीय रेलवे पर अल्ट्रा-मॉडर्न तेजस ट्रेनें शुरू की गई हैं. इनमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं–

- स्वचालित प्रवेश द्वार,
- यात्री घोषणा/यात्री सूचना प्रणाली,
- आग और धुएं का पता लगाने वाली प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे,
- बेहतर शौचालय-बायो-टॉयलेट के साथ वैक्यूम असिस्टेड फ्लशिंग आदि.

लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच

लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं–

- चढ़ाई रोधी विशेषता हैं,
- विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन (द्वितीयक) और
- कम संक्षारक शेल आदि.

पारम्परिक आईसीएफ कोचों वाली ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से एलएचबी कोचों से बदला जा रहा है.

एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसपीओ) योजना

केन्द्रीय बजट 2022-23 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की गई थी. इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों/हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों आदि को कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करना है. पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2022 को 19 स्टेशनों पर 15 दिनों के लिए लॉन्च किया गया था.

यह योजना 535 स्टेशनों पर 572 आउटलेट्स पर लागू की गई है. कुल 13,560 प्रत्यक्ष लाभार्थियों ने 30 नवम्बर, 2022 तक इस योजना के तहत् दिए जा रहे अवसरों का लाभ उठाया है. अप्रत्यक्ष लाभार्थियों को 5 प्रति आवंटन मानते हुए, कुल लाभार्थियों की संख्या 47,145 होने का अनुमान है.

विषय आधारित भारत गौरव पर्यटक सर्किट ट्रेनें

भारतीय रेलवे ने एक नया पर्यटन उत्पाद यानी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन–'भारत गौरव' लॉन्च किया. इस योजना के तहत्, समस्त देश में सेवा प्रदाता देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण समृद्ध खजाने को प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे. यह योजना रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में गुणक प्रभाव भी उत्पन्न करेगी.

(i) पहली भारत गौरव ट्रेन-शिरडी यात्रा जून 2022 को शुरू की गई थी.

(ii) जून 2022 को नई दिल्ली से आईआरसीटीसी द्वारा श्री रामायण यात्रा का शुभारम्भ किया गया. यह नेपाल (जनकपुर) में भगवान राम के महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है.

STUDYPDF WALLAH

'ऑपरेशन नार्कोस'

रेलवे सुरक्षा बल को अप्रैल 2019 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत् तलाशी, जब्ती एवं गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इस अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. इस ऑपरेशन के तहत् आरपीएफ ने एनसीबी व अन्य एलईए के समन्वय से ट्रेनों में तथा देश भर में पहचाने गए ब्लैक स्पॉट्स में अपनी जाँच तेज कर दी है और भारतीय रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों के वाहकों/ट्रांसपोर्टरों को लक्षित किया गया है. आरपीएफ ने वर्ष 2022 (नवम्बर तक) के दौरान, 1021 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ₹ 77·5 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थों की जब्ती की और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त एजेंसियों को सौंप दिया.

'ऑपरेशन डब्ल्यूआईएलईपी'

वन्यजीवों तथा जानवरों के अंगों की तस्करी करना प्रकृति के खिलाफ एक अपराध है. आरपीएफ इस मुद्दे पर काफी सक्रिय है और इसने वन्य जीवों के अवैध व्यापार में शामिल तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. आरपीएफ की टीम ने ऑपरेशन डब्ल्यूआईएलईपी के तहत् वर्ष 2022 (नवम्बर तक) के दौरान 47 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ 121 मामलों का पता लगाया है.

'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा'

वर्ष नवम्बर 2022 तक के दौरान 1·9 लाख से अधिक सुरक्षा सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनके समाधान के लिए उचित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की गई है. इसके अलावा, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक व कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित सम्पर्क में रहता है.

'ऑपरेशन रेल सुरक्षा' अर्थात् रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे पक्का करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. वर्ष नवम्बर 2022 तक के दौरान रेल सम्पत्ति की चोरी के मामले आरपीएफ द्वारा आरपी (यूपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत् दर्ज किए गए और जाँच के दौरान चोरी की रेलवे सम्पत्ति की बरामदगी तथा अपराधियों की गिरफ्तारी/अभियोजन आगे की कार्रवाई के तहत् की गई, ऐसे अपराधों में शामिल 10,337 व्यक्तियों को आरपीएफ ने पकड़ा और ऐसी गतिविधियों में ₹ 6·5 करोड़ की चोरी की रेलवे सम्पत्ति की बरामदगी भी हुई है.

'ऑपरेशन उपलब्ध'

एक समय था जब आरक्षित यात्रा के लिए रेलवे टिकटों की खरीद करना आम आदमी के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य रहा है, क्योंकि उन्हें दलालों द्वारा बड़ी मात्रा में ऊँचे दामों में बेचा जा रहा था. इसके अलावा, कन्फर्म रेलवे आरक्षण को ऑनलाइन सुनिश्चित कराने में अवैध सॉफ्टवेयर के उपयोग ने आम आदमी के लिए कन्फर्म टिकट की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था. आरपीएफ दलाली (अनधिकृत रूप से रेलवे टिकटों की खरीद व आपूर्ति का कारोबार करने वालों) में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ गहन तथा निरन्तर कार्रवाई कर रहा है. वर्ष 2022 (नवम्बर तक) के दौरान, आरक्षित रेलवे टिकटों के अवैध व्यापार में शामिल 4920 दलालों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. दलालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, 140 से अधिक अवैध सॉफ्टवेयरों को नष्ट किया गया और ऐसे अवैध सॉफ्टवेयरों के डेवलपर्स, सुपर सेलर्स, विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया.

'ऑपरेशन मातृशक्ति' (यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा में होने वाली महिलाओं की सहायता करना) एवं महिला सुरक्षा

महिला यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण सोचनीय विषय रहा है. इस सम्बन्ध में, खास तौर पर लम्बी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाली या अपराध की चपेट में आने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'मेरी सहेली' नामक पहल शुरू की गई है. महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा और संरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रमुख उपाय भी किए जाते हैं, जिनमें ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों और कोचों में सीसीटीवी सिस्टम, महिला विशेष उपनगरीय ट्रेनों में महिला एस्कॉर्ट्स, ट्रेनों में मिक्स्ड एस्कॉर्ट्स, महिला कोचों में अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ नियमित अभियान चलाना आदि भी शामिल हैं.

इसके अलावा, आरपीएफ कर्मी विशेष रूप से महिला आरपीएफ कर्मी, जिनकी आरपीएफ में कुल संख्या करीब 9 प्रतिशत है (वर्दी धारी बलों में सबसे अधिक), वे गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए तैनात रहते हैं और जो महिला अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान या रेलवे परिसर में प्रसव पीड़ा में होती है, उसकी पूरी मदद करते हैं. 2022 (नवम्बर तक) के दौरान, आरपीएफ ने 'ऑपरेशन मातृशक्ति' के तहत् ट्रेन में 123 महिलाओं तथा रेलवे परिसर में 62 महिलाओं को बच्चे के जन्म में सहायता की है.

मानव 'ऑपरेशन आहट'

मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए आरपीएफ की मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ भारतीय रेलवे के 740 से अधिक स्थानों पर तैनात की गई हैं. ये सभी इकाइयाँ मानव तस्करी को रोकने के कार्य में लगी हुई जिम्मेदार एजेंसियों के साथ नियमित सम्पर्क में हैं और इन्होंने तस्करी किए जा रहे बच्चों को बचाने व उन्हें सुरक्षित निकालने में उनकी सहायता की है. एक उद्देश्यपूर्ण अभियान अर्थात् ऑपरेशन आहट के तहत् आरपीएफ की टीम द्वारा 186 तस्करों (नवम्बर 2022 तक) की गिरफ्तारी के साथ 498 किशोरों एवं 43 वयस्कों को सुरक्षित बचाया गया है.

'ऑपरेशन जीवन रक्षा'

आरपीएफ के कर्मी अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जब यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने/उतरने की कोशिश करते हैं और ट्रेन के पहिये के नीचे आने के खतरे के साथ नीचे गिर जाते हैं. आरपीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आरपीएफ की टीम ने वर्ष 2022 (नवम्बर तक) में ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत् प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक और रेलगाड़ियों में 463 पुरुष तथा 326 महिला यात्रियों की जान बचाई है.

STUDYPDF WALLAH

जिसे अंततः बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, पिछले वर्ष से परिव्यय में बढ़ोत्तरी के आधार पर सृजित किए जा सकने वाले पदों की संख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है.

- कैलेंडर वर्ष 2022 (7 दिसम्बर, 2022 तक) में, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में रोलिंग स्टॉक और रेलवे परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए आईआरएफसी ने क्रमशः ₹ 12,300 करोड़ और एमओआर को ₹ 17,236·33 करोड़ की धनराशि प्रदान की है.
- **आईआरएफसी ने ग्रीन बांड के माध्यम से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर** का धन 3·57 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित कूपन दर पर जुटाया है. आईआरएफसी देश का पहला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन चुका है, जिसने अपने ऑफशोर बॉन्ड को विशेष रूप से गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में स्थापित भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया है. आईआरएफसी ने ग्रीन लोन के माध्यम से 1·10 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर ऑफशोर ग्रीन जेपीवाई ऋण भी जुटाया है, जिसमें क्रमशः 10 वर्ष और 7 वर्ष की अवधि के लिए 700 मिलियन अमरीकी डॉलर और 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की दो किश्तें शामिल हैं, जो ग्रीन लोन के माध्यम से 6 मिलियन टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट (टीओएनए) से जुड़ी हुई हैं. इन निधियों का उपयोग भारतीय रेलवे की रोलिंग स्टॉक परिसम्पत्तियों (यानी विद्युतीकृत रेल के लिए इलेक्ट्रिक लोको और यात्री कोच) का वित्त पोषण करने के लिए किया गया है.
- वर्ष 2022-23 के दौरान, एमएंडपी मदों के लिए लगभग ₹ 595 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और थोक और अलग-अलग उल्लेखित आरएसपी मदों दोनों के लिए लगभग ₹ 1,41,400 करोड़ मंजूर किए गए हैं.
- **वंदे भारत ट्रेनों से सम्बन्धित अनुबंध और अन्य मुद्दों** की जाँच की गई और उनका समाधान तेजी से किया गया.
- कॉनकॉर को अधिशेष डीजल इंजनों की बिक्री.
- नई वैगन डिजाइन पर नीति को अन्तिम रूप देने में सहायता प्रदान की गई.
- भारतीय रेल वित्त कोड खण्ड-I (आई-आरएफसी खण्ड-I) की समीक्षा की गई और संशोधित संस्करण को भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
- इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे वर्ष पुस्तिका, 2020-21, भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा, 2020-21, रेलवे तथ्य और आँकड़े 2020-21, भारतीय रेलवे वार्षिक सांख्यिकीय विवरण 2020-21 और 2020-21 के लिए अंतिम परिणाम माल ढुलाई और कोचिंग सेवा इकाई लागत सारांश का संकलन और प्रकाशन के लिए निम्नलिखित विशेष कार्य किए गए—
- **स्टेटमेंट-7ए का स्वतः निर्माण** (मूल आधार पर राजस्व माल भाड़ा यातायात सांख्यिकी).
- **भारत गौरव ट्रेन नीति** को अन्तिम रूप देने के लिए वहन शुल्क तैयार किया गया.
- **पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, दक्कन ओडिसी और गोल्डन** चेरियट जैसी लक्जरी पर्यटन ट्रेनों के वहन शुल्क को भारत गौरव ट्रेन नीति के अनुसार तैयार किया गया.
- **वंदे भारत ट्रेनों** के विभिन्न जोड़ियों की लाभप्रदता का पता लगाया गया.
- नई प्रस्तावित मालगाड़ियों, रैपिड ट्रांजिट मालभाड़ा ट्रेन और कार्गो लाइनर के वहन शुल्क पर काम किया गया.
- माल भाड़े के लिए श्रेणी-100 यानी ब्रेक-ईवन प्वाइंट का संशोधन.
- **महा मेट्रो ट्रेन के वहन शुल्क** का पता लगाया गया. ●●●

उपकार
Just Released
उत्तराखण्ड
सचिवालय/लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद् कार्यालय
समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक परीक्षा

पिछला प्रश्न-पत्र हल सहित
नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार
उत्तराखण्ड पर विशिष्ट जानकारी
Code 2439
₹ 250.00
डॉ. लाल एवं जैन
उपकार प्रकाशन, आगरा-5
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

उपकार
Just Released
धत्तीसगढ़
पुलिस आरक्षक
चयन परीक्षा
(जनरल इयूटी)

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण
परीक्षा सम्बन्धी सभी विषय
पिछले हल प्रश्न-पत्र
कोड : 1098 मूल्य : ₹ 170/-
डॉ. लाल एवं जैन
उपकार प्रकाशन, आगरा-5
• E-mail : sales@upkar.in
• Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

कि दलाई लामा के बारे में आप क्या जानते हैं ?

☞ दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परम्परा से सम्बन्धित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परम्परा है. तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में कुल 14 दलाई लामा हुए हैं. (पहले तथा दूसरे दलाई लामा को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी). 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेनज़िन ग्यात्सो हैं. माना जाता है कि दलाई लामा करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत, अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग की अभिव्यक्ति हैं. बोधिसत्व ऐसे साकार प्राणी हैं जिन्होंने मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी पर लौटने का प्रण किया है और सभी प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं.

दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया में पारम्परिक रूप से पूर्व दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना शामिल है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है. दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज सामान्यतः पूर्व दलाई लामा के निधन के बाद शुरू होती है. बौद्ध विद्वानों के अनुसार, वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद अगले दलाई लामा की खोज करना गेलुग्पा परम्परा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी है. यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो उचित उत्तराधिकारी का चुनाव अधिकारियों और भिक्षुओं द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में चिट्ठी डालकर किया जाता है. चयनित उम्मीदवार, जो आमतौर पर बहुत कम उम्र का होता है, को दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना जाता है और उसे कठोर आध्यात्मिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. दलाई लामा की भूमिका में तिब्बती बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व दोनों शामिल हैं तथा इनकी चयन प्रक्रिया तिब्बती सांस्कृतिक व धार्मिक परम्पराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं—यथा 14वें (वर्तमान) दलाई लामा को खोजने में 4 वर्ष लग गए थे. यह खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है, हालाँकि वर्तमान दलाई लामा ने कहा है कि ऐसी सम्भावना है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और यदि उनका पुनर्जन्म होगा, तो वह चीनी शासन के तहत् किसी देश में नहीं होगा.

कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में आप क्या जानते है ?

☞ ग्रीन क्रेडिट, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक इकाई को सन्दर्भित करता है. यह पर्यावरण संरक्षण और सतत् प्रथाओं में योगदान देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम व्यापक 'LiFE' अभियान (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का हिस्सा है और यह स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करता है. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पर्यावरणीय धारणीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से 8 प्रमुख प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं—

- सतत् कृषि
- वृक्षारोपण
- जल प्रबंधन
- अपशिष्ट प्रबंधन
- वायु प्रदूषण में कमी लाना
- मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापना
- इको मार्क लेबल का विकास
- टिकाऊ भवन और बुनियादी ढाँचा

कि हाइड्रोकार्बन विजन क्या है ?

☞ केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल ने भारतीय हाइड्रोकार्बन विजन अर्थात् आईएचवी रिपोर्ट तैयार की. इस रिपोर्ट में पहली बार विश्वस्तरीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में तेल और गैस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की गई. विजन 2025 में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं—

1. उद्योग के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उच्चीकरण और क्षमता निर्माण के जरिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में विकसित करना, जोकि अपने आपको विश्व में सर्वोत्तम सिद्ध कर सकें.

2. सामरिक और रक्षा सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश के लिए तेल सुरक्षा सुनिश्चित करना.

3. तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और विदेश में इक्विटी ऑयल में निवेश में बढ़ोतरी के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना.

4. उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुक्त बाजार की स्थापना और कारोबारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना.

5. स्वच्छ और हरे-भरे भारत का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों के स्तर में सुधार से जीवन-स्तर बेहतर बनाना.

कि समुद्री ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?

☞ अत्यधिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग से वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है. फलतः ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो अनेक दुष्परिणामों का कारण है. अतः जीवाश्म ईंधन के विकल्पों की तलाश हो रही है. इन्हीं विकल्पों में समुद्री ऊर्जा भी है. सागर परिवर्तनीय ऊर्जा का विशाल भण्डार है. विशाल समुद्र तट के कारण भारत में ताप, लहर, ज्वार-भाटा एवं लवण प्रवणता से प्राप्त होने वाली समुद्री ऊर्जा की असीम सम्भावनाएं हैं. आशा की जाती है कि इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की आर्थिक व्यवहार्यता अनुकूल होगी तथा कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस पर भारत की निर्भरता कम होगी. नई प्रौद्योगिकी नीति-1993 के अनुरूप समुद्री ऊर्जा स्रोतों के भरपूर उपयोग का कार्यक्रम बनाया गया है.

महासागरीय तरंगों से ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से 1982 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (चेन्नई) में तरंग ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया. भारतीय समुद्र तटों के पास तरंग शक्ति विभव का कई स्थानों पर अध्ययन किया गया तथा त्रिवेन्द्रम के निकट विजिंगम तट को उपयुक्त विस्तार के साथ 150 किलोवाट क्षमता वाले तरंग ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए चुना गया. इससे उत्पादित विद्युत् को केरल राज्य विद्युत् बोर्ड की ग्रिडों में पहुँचाया जाता है. इस परियोजना के कार्यान्वयन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के परियोजना दल के अतिरिक्त पोताश्रय इंजीनियरिंग विभाग, त्रिवेन्द्रम भी शामिल हैं.

कि डीपफेक टेक्नोलॉजी क्या है और यह कैसे काम करती है ?

☞ हाल के वर्षों में डीपफेक ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है जिसमें एक मौजूदा छवि या वीडियो में एक व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को लगा दिया जाता है और उनमें इतनी समानता होती है कि उनमें अन्तर करना कठिन हो जाता है, तो आखिर ये डीपफेक क्या हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं ?

दरअसल डीपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग जैसी गहन शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया सिंथेटिक मीडिया है. ये टेक्नोलॉजी छवियों, वीडियो और ऑडियो को हेरफेर करके विश्वसनीय नकली सामग्री बनाने की अनुमति देती हैं, जो वास्तविक सामग्री से लगभग समरूप होती है.

●●●

STUDYPDF WALLAH

(iii) दिव्य काशी-आदि अमावस्या टूरिस्ट ट्रेनें और ओणम हॉलिडे स्पेशल ट्रेने भी चलाई गईं.

(iv) नवम्बर 2022 को बेंगलूरू से 'कर्नाटक-भारत गौरव काशी दर्शन' ट्रेन की पहली यात्रा की शुरूआत की गई थी.

मानव श्रम योजना (एमपीपी)

सितम्बर 2021 में भारतीय रेल में रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है. योजना के तहत् सम्बन्धित तकनीकी ट्रेडों में क्षेत्रीय रेलवे और उद्योग इकाइयों के उत्पादन के लिए 90 से अधिक प्रशिक्षण स्थानों पर प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है. आरकेवीवाई की निगरानी के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित की गई है.

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के साथ एक कैबिनेट नोट को शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया गया है. विधेयक को अगस्त 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 को 17 अगस्त, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था. अधिनियम 6 दिसम्बर, 2022 से लागू किया गया है.

आधार आधारित सत्यापन प्रणाली

आरआरबी परीक्षाओं में पहली बार आधार आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू की गई है जिसके लिए एमईआईटीवाई का अनुमोदन और गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है. योजना को लागू करने के लिए यूआईडीएआई से सम्पर्क किया गया है और रेलटेल को एएसए नियुक्त किया गया है. इसे सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के दूसरे और तीसरे चरण और सीईएन आरआरसी 01/2019 (लेवल 1) के लिए सीबीटी हेतु लागू परीक्षाओं में प्रतिरूपण को समाप्त करने में काफी मदद मिलेगी.

डिजिटल इंडिया पहल

- **ई-नीलामी प्रक्रिया में वर्चुअल खाता संख्या (वैन) का कार्यान्वयन**—ई-नीलामी प्रक्रिया में वैन को लागू कर ई-नीलामी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे इसे बैंक से तटस्थ बनाया जा सके और एसबीआई के साथ चालू खाता खोलने की आवश्यकता समाप्त हो जाए.
- **ऑनलाइन बैंक गारंटी (बीजी) सत्यापन**—एसबीआई के समन्वय से ऑनलाइन बैंक गारंटी सत्यापन लागू किया गया. एसबीआई ने एक मंच तैयार किया जिसके माध्यम से रेलवे के पक्ष में बैंकों द्वारा जारी सभी बीजी को एसएफएमएस पर प्राप्त किया जा सकता है और समवर्ती आधार पर सीआरआईएस के साथ साझा किया जा सकता है और जिसे बाद में रेलवे के साथ साझा किया जाता है. इससे बीजी के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त होगी.
- पीएफ और अन्तिम निपटान बिलों के लिए एचआरएमएस और आईपीएएस का एकीकरण.
- पीएमएस और एफओआईएस में भुगतान की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए एसबीआई के साथ समन्वय.
- एनएसडीएल के साथ समन्वय में ऑनलाइन पीआरएएन जनरेशन मॉड्यूल का कार्यान्वयन. व्यक्तिगत हस्तक्षेप में कमी लाने के लिए एनएसडीएल के साथ सर्वर से सर्वर एकीकरण के माध्यम से एससीएफ को सीधा अपलोड करना.
- **भारतीय रेलवे लेखा कोड खण्ड I** और भारतीय रेलवे वित्त कोड खण्ड II का संशोधन—भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
- **पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण देने के लिए एनआईसी के साथ आईपीएएस का एकीकरण** और ई-पीपीओ और कर्मचारियों द्वारा फॉर्म 16 डाउनलोड करने की सुविधा के लिए डिजिलॉकर के साथ आईपीएएस का एकीकरण.
- वित्त वर्ष 2022 में रेलवे का पूँजीगत व्यय बढ़कर ₹ 1,90,267 करोड़ हो चुका है और वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान में इसे ₹ 2,45,800 करोड़ करने का प्रावधान किया गया है.

पेंशन/नियमों/संहिताओं/निर्देशों में अपडेट सम्बन्धी घटनाक्रम

- **कोड और मैनुअल में अपडेट**—भारतीय रेल स्थापना संहिता (आईआरईसी)-खण्ड-I, विशेष रूप से एफ (ई) से सम्बन्धित अध्याय अर्थात् टीए/डीए, राज्य रेलवे भविष्य निधि, अवकाश और विदेश सेवा अंशदान (एफएससी) का नकदीकरण मौजूदा निर्देशों के आधार पर अपडेट किया गया.
- **रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993,** रेलवे द्वारा अपनाने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एण्ड पीडब्ल्यू) से सम्बन्धित नियमों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियम और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान सम्बन्धी नियमों को संशोधित किया गया. हालाँकि, बाद के घटनाक्रमों के कारण इस पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि विभाग सम्बन्धित संसदीय स्थायी समिति द्वारा डीओपीएंडपीडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र में पेंशनभोगियों के लिए एकल इकाई की सिफारिश की गई. समिति की सिफारिशों पर डीओपीएंडपीडब्ल्यू द्वारा गठित समिति ने विचार-विमर्श किया और इस समिति की रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है.
- **पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए निर्देश जारी** किए गए, जोकि काल्पनिक वेतन के आधार पर हटाए गए/बर्खास्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त हुए हैं.
- **पेंशनभोगियों द्वारा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निपटारा** पीजीपोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया.
- **मापदंडों का पुनरीक्षण,** रेलवे के विभिन्न विभागों में अराजपत्रित संवर्ग के मापदंडों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित प्रस्तावों की एसोसिएट वित्त क्षमता और (1) विद्युत् सामान्य बिजली आपूर्ति, (2) मैकेनिकल ईएमयू/एमईएमयू, (3) एसएंडटी-टेलीकॉम, (4) सिविल इंजीनियरिंग आर्टिसन हेल्पर-एसएसई वर्क्स कैडर और (5) इलेक्ट्रिकल टी. आरडी उपनगरीय क्षेत्र विभाग के मानदंडों की जाँच की गई और उसे अन्तिम रूप प्रदान किया गया और उसे जारी किया गया.
- **रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को वाहन भत्ता देने का मुद्दा,** भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा संघ (आईआरएमएसए) से प्राप्त एक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रेलवे चिकित्सा अधिकारियों को संशोधित दरों पर 7वीं सीपीसी देने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया गया और बाद में इस भत्ते की दरों को संशोधित करने वाले निर्देशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद रेलवे बोर्ड ने दिनांक 10 जनवरी, 2022 के पत्र सं. एफ(ई)आई/202/एएल-7/1 को जारी किया.
- एसोसिएट फाइनेंस के रूप में, 2022-23 के लिए भारतीय रेलवे के निर्माण विभागों में राजपत्रित पदों के लिए मानदंडों को अन्तिम रूप देने वाले मानदंडों को पिछले मानदंडों की तुलना में 15 प्रतिशत कठोर बनाया गया. इस अतिरिक्त सख्ती के परिणामस्वरूप,

STUDYPDF WALLAH

प्रश्न–समरक्तता (Consanguinity) क्या है ?

उत्तर–सामाजिक रूप से समरक्तता (Consanguinity) अर्थ है चचेरे भाई अथवा बहन जैसे रक्त सम्बन्धियों से विवाह करना, जबकि आनुवंशिक रूप से यह निकट सम्बन्धी व्यक्तियों के बीच विवाह को सन्दर्भित करता है, इसे अक्सर अंतःप्रजनन कहा जाता है. यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका परिवार और जनसंख्या आनुवंशिकी दोनों पर प्रभाव पड़ता है. समरक्तता के अन्तर्गत सामाजिक और आनुवंशिक दोनों आयाम मौजूद होते हैं.

विश्व की लगभग 15-20% आबादी में समरक्तता की विशेषता पाई जाती है, इसका प्रचलन एशिया और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अधिक है. भारत रक्त सम्बन्ध अध्ययन के लिए एक समृद्ध स्थान है, क्योंकि यहाँ 4,000 से अधिक अंतर्विवाही समूहों या एक ही जाति, जनजाति या कबीले के सदस्य रहते हैं. आमतौर पर यह पाया गया कि जिन समुदायों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है वहाँ सजातीयता के कारण आबादी में मृत्यु दर और पुनरावर्ती आनुवंशिक रोगों की व्यापकता में वृद्धि हुई है.

प्रश्न–आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वाटर फुटप्रिंट के बारे में बताइए.

उत्तर–यह जल की वह मात्रा है, जिसका उपयोग विद्युत् उत्पन्न करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को चालित रखने वाले डेटा केन्द्रों को शीतलन प्रदान करने के लिए किया जाता है. इसे दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है: जल की प्रत्यक्ष खपत और जल की अप्रत्यक्ष खपत. AI का वाटर फुटप्रिंट कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है, जैसे कि AI मॉडल का प्रकार और आकार, डेटा केन्द्र का स्थान एवं दक्षता, विद्युत् उत्पादन के विभिन्न स्रोत. जल की प्रत्यक्ष खपत से आशय उस जल से है, जो डेटा सेंटर सर्वरों की शीतलन प्रक्रिया के दौरान वाष्पिकृत हो जाता है या फिर अपशिष्ट के रूप में निकलता है, जबकि जल की अप्रत्यक्ष खपत का सम्बन्ध उस जल से है जिसका उपयोग डेटा सेंटर सर्वरों को ऊर्जा प्रदान करने हेतु विद्युत् उत्पादन करने में किया जाता है.

प्रश्न–'विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा' के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर–विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केन्द्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं. यह वर्गीकरण वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था. यह गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित था जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिए निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित किए गए थे.

विशेष श्रेणी के राज्य के मापदंडों में उक्त क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व कम होना एवं जनजातीय आबादी का अधिक होना, पड़ोसी देशों से लगे (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा) सामरिक क्षेत्र में स्थित होना, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का निर्धारित नहीं होना आदि शामिल हैं. पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, सामरिक महत्व की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे पहाड़ी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता था, जिनके पास स्वयं के संसाधन-स्रोत सीमित होते थे.

प्रश्न–मक्का पेटी और मक्का पेटी जलवायु क्या है ?

उत्तर–फसलों, फलों और उत्पादों के नाम पर भी जगहों के नाम पड़ जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, केरल को मसालों का बगीचा, फिरोजाबाद को सुहागनगरी आदि. उसी तरह अमरीका में भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसे मक्का पेटी कहा जाता है. मक्का पेटी, संयुक्त राज्य अमरीका की महान् झीलों के दक्षिण एवं द.प. में स्थित मेखला है, जिसमें मुख्यतः मक्का की कृषि की जाती है और देश के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत यहीं से प्राप्त होता है. इस पेटी का विस्तार मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का तक तथा उत्तर में दक्षिणी विस्कान्सिन एवं मिनिसोटा से लेकर दक्षिण में इलिनोय राज्य तक है. इस पेटी की जलवायु और मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त है. अतः यह मक्का उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है. यहाँ मक्का की कृषि बड़े-बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से की जाती है. यहाँ अधिकांश मक्का उत्पादन का उपयोग सुअर तथा पशुपालन के लिए चारे के रूप में किया जाता है.

मक्का पेटी जलवायु (Corn Belt Climate)–एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु जो सं. रा. अमरीका के मक्का पेटी तथा इसी तुल्य यूरोप एवं एशिया के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्रों में पाई जाती है. यह आर्द्रमहाद्वीपीय जलवायु है जिसमें ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा होती है. संयुक्त राज्य की मक्का पेटी के अतिरिक्त इस प्रकार की जलवायु यूरोप में डेन्यूब बेसिन तथा एशिया में उत्तरी चीन में पाई जाती है जहाँ ग्रीष्मकाल लम्बा और शीतकाल अपेक्षाकृत छोटा होता है.

प्रश्न–रेड इंडियन की आकृति कैसी होती है ? वे कहाँ निवास करते हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर–सुनसान वनों में, द्वीपों पर और सभी जगह मानव की उपस्थिति है, चाहे वह बर्फ से ढका उत्तरी ध्रुव क्षेत्र हो (एस्किमो) का अण्डमान निकोबार द्वीप समूहों या अमरीका का आमेजन (रेड इंडियन).

रेड इंडियन उत्तरी अमरीका के मूल निवासी हैं, जो वर्तमान अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमरीका के डैकोटा क्षेत्र से लेकर कनाडा के विनिपेग झील तक के पठारी भू-भाग में तथा अरीजोना के पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं. रेड इंडियन सामान्यतः मंगोलाइट प्रजाति से सम्बद्ध लगते हैं जिनका कद छोटा तथा नाक चौड़ी होती है और शरीर पर रोमों का अल्प विकास पाया जाता है. आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व जब यूरोपीय उत्तरी अमरीका में नहीं पहुँचे थे, ये लोग सम्पूर्ण उत्तरी अमरीका में फैले हुए थे. यूरोपीयों के साथ हुए युद्धों में अमरीका के मूल निवासी अधिक संख्या में मारे गए और शेष पश्चिम के पहाड़ी-पठारी जंगलों में जा छिपे और बाद में कई समूहों में विभक्त हो गए. मूल रेड इंडियन कनाडा के भू-क्षेत्र में पाए जाते हैं. उत्तरी अरीजोना के मूल निवासियों को होपी इंडियन कहते हैं. रेड इंडियन आज भी पिछड़ी अवस्था में हैं और बैल के समान बिसन पशु का धनुष बाण है. शिकार करने में प्रवीण होते हैं. शिकार करना इनके जीवन का आधार बन गया है. होपी इंडियन प्राथमिक प्रकार की कृषि भी करते हैं.

प्रश्न–बूरान (Buran) क्या है ?

उत्तर–साइबेरिया तथा मध्यवर्ती एशिया में मुख्यतः शीत ऋतु में चलने वाली प्रचंड शीतल पवन, जो उत्तर या उत्तर-पूर्व की ओर चलती है. इसे पूर्गा (Purga) के नाम से भी जाना जाता है. शीत ऋतु में यह पवन किसी अवदाब के सहारे चलती है जिसमें बर्फ तथा हिम के कण भी विद्यमान होते हैं. इस प्रकार यह शीत लहर (ब्लीजार्ड के समान) के रूप में चलती है जिसके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे तक गिर जाता है और इससे उत्पन्न मौसम मनुष्यों तथा पशुओं सबके लिए अति कष्टदायक हो जाता है. ग्रीष्मकाल में चलने वाली प्रबल उत्तर-पूर्वी पवन को भी सामान्यतः बूरान कहा जाता है, किन्तु इसकी आवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है. ●●●

STUDYPDF WALLAH

शेष पृष्ठ 20 का

मार्च 2024) में वृद्धि धीमी रहेगी. इससे पूर्व 2022-23 में वृद्धि जहाँ 7·2 प्रतिशत रही थी, 2023-24 की पहली तिमाही Q_1 (अप्रैल-जून 2023) में यह 7·8 प्रतिशत रही है. 2023-24 की दूसरी तिमाही Q_2 (जुलाई-सितम्बर 2023) के जीडीपी के अनंतिम आँकड़े एनएसओ द्वारा 30 नवम्बर, 2023 को जारी किए जाएंगे.

भारत का 42वाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में सम्पन्न

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (ITPO) के तत्वावधान में भारत का 42वाँ

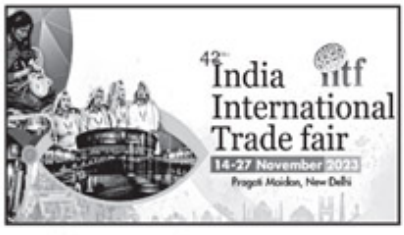

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (India International Trade Fair—IITF-2023) 14–27 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्पन्न हुआ. वाणिज्य मंत्रालय के इस वार्षिक व्यापार मेले का उद्घाटन केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया था. इस बार इस मेले का आयोजन 1,10,000 वर्गमीटर क्षेत्र में किया गया था, जो इस मेले के विगत 41 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक क्षेत्र था, पिछले वर्ष यह आयोजन 75,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ही था. मेले में पहले 5 दिन बिज़नेस-टू-बिज़नेस **बी2बी** बिक्री के लिए निर्धारित किए गए थे, जो केवल

व्यापार मेले का उद्घाटन करती हुई वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल

व्यापारियों के लिए थे. आम दर्शकों के लिए मेले के द्वार 19 नवम्बर से खोले गए थे. भारत के अतिरिक्त टर्की, लेबनान, मिस्र, किर्गिस्तान, ओमान, वियतनाम, ट्यूनीशिया व थाइलैण्ड, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, बांग्लादेश व संयुक्त अरब अमीरात व यूनाइटेड किंगडम (UK) सहित 13 देशों की सक्रिय भागीदारी इस मेले में थी. लगभग 10 लाख दर्शकों ने मेले का अवलोकन इस बार किया तथा मेले में कुल ₹ 1500 करोड़ से अधिक का व्यवसाय हुआ, जो पिछले वर्ष ₹ 950 करोड़ का था.

भारत के विभिन्न राज्यों, केन्द्रशासित क्षेत्रों व केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों ने भी पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अपने स्टॉल मेले में लगाए थे. इन स्टॉलों पर सम्बन्धित राज्यों एवं विभागों में हो रहे प्रौद्योगिकीय विकास के साथ-साथ इनकी कलाओं एवं संस्कृतियों का प्रदर्शन किया गया था, इस वर्ष मेले की थीम (Theme) **वसुधैव कुटुम्बकम** था. इस वर्ष मेले में दो राज्यों—बिहार व केरल को **साझीदार राज्य** (Partner State) का तथा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था.

27 नवम्बर को मेले के समापन पर विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शकों को पुरस्कार भी आईटीपीओ ने प्रदान किए. राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को स्वर्ण, असम को रजत व राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया, जबकि विशेष प्रशंसा प्रमाण-पत्र कर्नाटक, उत्तराखण्ड व गुजरात को प्रदान किया गया. विषयगत प्रस्तुति के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण, त्रिपुरा को रजत, आन्ध्र प्रदेश को कांस्य पदक और तमिलनाडु, नगालैण्ड व गोवा को विशेष प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिया गया. केन्द्रशासित प्रदेशों में अण्डमान व निकोबार को स्वर्ण व लद्दाख को रजत प्रदान किया गया. स्वच्छ पवेलियन के लिए पंजाब को स्वर्ण, हरियाणा को रजत, छत्तीसगढ़ को कांस्य व हिमाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए. विदेशी मण्डपों में संयुक्त अरब अमीरात ने स्वर्ण, थाइलैण्ड ने रजत व तुर्की ने कांस्य पदक जीता, जबकि मिस्र को विशेष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया. मंत्रालयों व विभागों, पीएसयू, पीएसवी और कमोडिटी बोर्ड श्रेणी में आयुष मंत्रालय ने स्वर्ण, करदाता, सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, आयकर निदेशालय ने रजत पदक व रेल मंत्रालय ने कांस्य पदक प्राप्त किया है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् 81·35 करोड़ लाभार्थियों को 5 वर्ष तक निःशुल्क अनाज : मंत्रिमण्डल का निर्णय

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को आगे और उपलब्ध कराने का निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 29 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न बैठक में किया गया है. कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मूलतः दिसम्बर 2022 तक के लिए थी तथा इसके सभी लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् दिसम्बर 2023 तक के लिए बढ़ा दिए गए थे. इस प्रकार 5-5 किग्रा निःशुल्क अनाज की योजना 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त होने को थी. इससे पूर्व ही 1 जनवरी, 2024 से पीएमजीकेएवाई को आगे और 5 वर्षों तक (31 दिसम्बर, 2028 तक) विस्तार करने का निर्णय मंत्रिमण्डल की 29 नवम्बर, 2023 की बैठक में किया गया. योजना के तहत् लक्षित 81·35 करोड़ व्यक्तियों के लिए 5-5 किग्रा खाद्यान्न (गेहूँ / चावल / मोटा अनाज / पोषक अनाज) निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 5 वर्षों के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी ₹ 11·80 लाख करोड़ होगी, जो पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन की जाएगी. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल करना है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में ₹ 11·80 लाख करोड़ की अनुमानित लागत से 81·35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भोजन एक पोषण सम्बन्धी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

ड्रोन सेवाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल के साथ-साथ महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups – SHGs) को ड्रोन प्रदान करने के लिए 2024-25 से 2025-26 के लिए एक केन्द्रीय योजना को मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की 29 नवम्बर, 2023 की बैठक में दी गई है. स्वीकृत योजना के तहत् 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कृषि उद्देश्यों के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक (अधिकतम ₹ 8 लाख) तक की सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. शेष राशि रियायती ब्याज पर ऋण के रूप में एसएचजी द्वारा जुटाई जा सकेगी. इन ड्रोन का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए, विशेषतः कीटनाशक व खाद के छिड़काव के लिए किया जाएगा, फसलों का रकबा नापने, मृदा परीक्षण व सिंचाई आदि के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा कृषि कार्यों के लिए ड्रोन किसानों को किराए पर दिए जाएंगे जिससे महिला एसएचजी को कमाई होगी. **इस योजना से कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा जिससे इनके निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा. ड्रोन के समुचित संचालन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी इस योजना के तहत् दिया जाएगा.**

●●●

STUDYPDF WALLAH

प्रथम पुरस्कृत निबन्ध

भारत के लिए चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता के निहितार्थ

✍ प्रभाष पाठक

सभ्यता की शुरूआत से ही मानव अंतरिक्ष की, विशेषकर चंद्रमा की, कल्पनाएं करता रहा है. इन रोमांचक कल्पनाओं में चांद कभी अध्यात्म का विषय रहा, तो कभी कविताओं और दंतकथाओं का. हमारे देश में चांद से लगाव इतना ज्यादा है कि आज भी बच्चों को चंदा मामा की कहानियाँ सुनाई जाती हैं. भारतीय साहित्य में ज्योतिष, कर्मकांड, आचार-व्यवहार आदि में चंद्रमा का अति महत्वपूर्ण स्थान है. यही कारण है कि चंद्रमा के प्रति वैज्ञानिक भी अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु निरन्तर खोज में लगे रहते हैं. इसी कारण जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षितिज की ओर देखते हैं, वहाँ आशा की एक किरण दिखाई देती है. इस क्रम में हमारे देश की अन्वेषण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के अग्रदूत के रूप में उभरता है–चन्द्रयान-3. आकाशीय अन्वेषण के इस युग में चन्द्रयान-3 केवल एक मिशन नहीं, यह भारत की नवीनीकृत चंद्रमा सम्बन्धी आकांक्षाओं की उत्पत्ति का भी प्रतीक है. भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त, 2023 को सफलतापूर्वक मानव रहित यान उतारने वाला पहला देश बन गया है. इसके अलावा भारत अब अमरीका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा पर यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश भी बन गया है. चन्द्रयान-3 की सफलता सिर्फ भारत के राष्ट्रीय गौरव बढ़ने की बात नहीं है. सच्चाई यह है कि इसके सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक प्रभावों को बिंदुवार समझे बिना हम चन्द्रयान-3 की सफलता के निहितार्थ को समझने में असमर्थ होंगे.

वर्ष 1969 में अमरीकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था और कहा था कि यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए लम्बी छलांग है. इसके बाद प्रत्येक देश ने चंद्रमा पर जाने का सपना देखा था. भारत ने भी सीमित संसाधन क्षमता के बावजूद चंद्रमा पर लैंडिंग का अतुलनीय साहस कर वर्ष 2023 तक अपने तीन चंद्र अभियान के साथ अंतरिक्ष में लम्बी छलांग लगाकर अपने-आप को शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित कर लिया है. यह तो सभी जानते हैं कि चन्द्रयान-3 द्वारा चंद्रमा के अनछुए इलाके पर लैंडिंग करने के साथ ही भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर आया है. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चन्द्रकम्पों का अध्ययन न केवल भारत के लिए, बल्कि नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के लिए भी विशेष रुचि का विषय है. इसरो का आईएलएसए पेलोड, दक्षिणी ध्रुव पर पहला चंद्र भूकम्पमापी, चंद्र भूविज्ञान और चन्द्रकम्पीय गतिविधि के पूरी तरह से नए पहलुओं को प्रकट करने की क्षमता रखता है, जो चंद्रमा के विकास और पृथ्वी से इसके सम्बन्ध की गहरी समझ में योगदान देने में समर्थ होगा.

चन्द्रयान-3 अभियान का सर्वप्रथम उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट संचालित करना था, जो सफल हुआ. तत्पश्चात् इसका मुख्य उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, चांद पर मौजूद खनिजों का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना है. साथ ही चांद को लेकर समझ विकसित करके उसे मानव कल्याण से जोड़ना भी इसका उद्देश्य है.

चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौरमण्डल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारी दे सकता है. इसके अलावा चंद्रमा की सतह का घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है. यह मिशन चंद्रमा के कई अन्य रहस्यों को उजागर करेगा. चंद्रमा पर जल का पक्ष, भारी वैज्ञानिक अवसरों से भरा हुआ है. यह अन्वेषण भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और स्टार्टअप उद्यमों के माध्यम से अन्तरिक्ष उद्यमिता का द्वारा खोल सकता है.

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा भूवैज्ञानिक रूप से अद्वितीय पाया गया है. यहाँ स्थायी छाया मिलती है. इसका अध्ययन करने के लिए इस मिशन में छः वैज्ञानिक पेलोड तैयार किए गए हैं. अभी तक इस क्षेत्र में कोई मिशन सफल नहीं हो सका है. अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अज्ञात चंद्र इलाकों की खोज करने का सपना देखने का साहस किया है. इसरो के मितव्ययी, लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण की विश्व स्तर पर प्रसंशा की जा रही है. चन्द्रयान-3 जैसे मिशन संसाधनशीलता की सीमितता, परन्तु नवीनता का प्रदर्शन करते हुए, अपने इच्छित जीवन से कहीं आगे तक फैले हुए हैं. मिशन का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है, यहाँ तक कि जापान के JAXA को उसके LUPEX मिशन में भी सहायता मिल रही है.

चन्द्रयान-3 भारत का वर्तमान अंतरिक्ष बाजार पिछले कुछ वर्षों से लगभग चार प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है. विश्लेषकों के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2040 तक 40 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी. चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थ-व्यवस्था में 9% की पैठ हासिल करने के भारत के लक्ष्य को उत्साहजनक बढ़ावा देगी. इस तर्क का आधार है कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 2023 की दूसरी तिमाही में 546 अरब डॉलर (₹ 45·23 लाख करोड़) तक पहुँचा गया, जो एक दशक में 91 प्रतिशत की वृद्धि है.

चंद्रमा की सबसे दुर्गम सतह पर सफल लैंडिंग से निवेशकों का भी भारत के प्रति विश्वास काफी बढ़ेगा. इमेजिंग, नेविगेशन और पोजिशनिंग में उपग्रह डेटा की माँग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है. अब चन्द्रयान-3 की ही तरह भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक समृद्धि भी आसमान को छूने के निकट आ गई है. इस मिशन की सफलता से स्टार्टअप और अंतरिक्ष तकनीक, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कम्पनियों के लिए एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है. विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बहुत अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने वाली है. ऐसे में निवेशक, विक्रेता, ग्राहक और बाहरी दुनिया के लोग अब भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को गम्भीरता से लेंगे. यह सब उस भारत में होने जा रहा है, जहाँ पहले ही 140 पंजीकृत स्पेस-टेक स्टार्टअप हैं. इस सफलता के बाद इन स्टार्टअप्स को अधिक निवेश मिलने की उम्मीद है. बढ़ते अंतरिक्ष तंत्र को निकट भविष्य में ही बजटीय आवंटन भी बढ़ा हुआ मिलने की उम्मीद है. निश्चित रूप से इससे वैश्विक बाजार में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय अंतरिक्ष उद्यम चल पड़ेगा. जिसका प्रभाव आमदनी से लेकर तकनीकी प्रगति, रोजगार और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों पर पड़ेगा.

चंद्रमा जैसा प्राकृतिक उपग्रह एक प्रमुख भू-राजनीतिक लक्ष्य के रूप में भी उभर रहा है. चीन और रूस एक 'अन्तर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन' पर

STUDYPDF WALLAH

काम कर रहे हैं. चन्द्रयान-3 की सफलता का महत्व वैज्ञानिक उपलब्धि के दायरे से कहीं अधिक है. इसमें नरम कूटनीति की शक्ति है, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल रोशनी प्रदान करती है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बनकर, भारत अपनी तकनीकी कौशल और अन्वेषण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने में सक्षम हुआ है. यह उपलब्धि विशिष्ट अंतरिक्ष यात्रा वाले देशों के बीच भारत की जगह को मजबूत करेगा, जो महत्वाकांक्षी दृष्टि को मूर्त वास्तविकताओं में बदलने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन करेगी.

चन्द्रयान-3 की सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1976 से पहले रूस के 24 लूना मिशनों की सॉफ्ट लैंडिंग सफलता दर मात्र 20% थी. साथ ही भारत के चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग सम्बन्धी चिन्ता को बढ़ावा तब दे दिया जब रूस के 47 वर्ष पश्चात् चंद्रमा पर भेजे गए लूना-25 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई. इस कारण चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग दुनिया भर के युवा दिमागों को एक शानदार सन्देश भेजती है. यह आशा की किरण के रूप में युवा दिलों को बड़े सपने देखने, साहसपूर्वक सोचने और ज्ञान की खोज के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है. **चन्द्रयान-3** की सफलता ऐसा ऐतिहासिक क्षण है, जो कदाचित जीवन में एक दो बार भी आता है. यह पूरे देश को एकजुट कर देता है, देश को आत्मविश्वास से भर देता है, भारत के युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ा. उभरते क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के लिए एक त्वरित मार्ग प्रशस्त कर देता है. चंद्रमा की धरती पर धीरे-धीरे आराम कर रहे एक अंतरिक्ष यान की छवि कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है और सपनों को बढ़ावा देती है.

सस्ती और भरोसेमंद तकनीक होने के कारण उपग्रह प्रक्षेपण हेतु एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के विकासशील देश भारत का रुख कर रहे हैं. इससे भविष्य में बनने वाली स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है. एक नया उद्यम चलने से आर्थिक विकास के साथ-साथ नवाचारों, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों को भी तीव्र बढ़ावा मिलेगा. नए बनते परिवेश में अधिक-से-अधिक छात्र एयरोस्पेस क्षेत्र की शिक्षा लेंगे और अंतरिक्ष-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होना चाहेंगे, जिससे भारत न केवल एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में आगे बढ़ने में समर्थ होगा, बल्कि घरेलू स्तर पर भी हर स्तर के रोजगारों की दर में वृद्धि होगी. यह सफलता 'मेक इन इंडिया' ब्रांड को भी स्वाभाविक तौर पर बढ़ावा देगी और इससे घरेलू कम्पनियों को भी विकास के अधिक अवसर मिलेंगे. माना जाता है कि उपग्रह-प्रणाली, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जुड़े क्षेत्रों को आरम्भिक स्तर पर ही इस मिशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. चन्द्रयान-3 की सफलता से भारत का शेयर बाजार जिस तरह आसमान छूने लगा था, वह इस मिशन के आर्थिक महत्व को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष है. मिशन की सफलता के तुरन्त बाद अंतरिक्ष-क्षेत्र की 13 कम्पनियों के शेयरों में भी तेजी आई और उनके बाजार मूल्य में 2·5 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई.

चन्द्रयान मिशन के राजनीतिक महत्व को देखें, तो इस मिशन से भारत के कद में वृद्धि हुई है. पृथ्वी से इतर ग्रह व उपग्रह के रहस्यों का भेद जान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले विश्व के चंद देशों में आज भारत भी शामिल है. आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है. भविष्य में अंतरिक्ष के अधिकार को लेकर यदि किसी प्रकार का समझौता होता है, तो उसमें भारत प्रमुख नेतृत्व कर्ता एवं नीति निर्माता के रूप में होगा. साथ ही, भारत की अंतरिक्ष में दक्षता भावी अंतरिक्ष सैन्यीकरण की स्थिति में भारत को शुद्ध राहत प्रदान करेगी. इतना ही नहीं भारत आज अन्य देशों को भी इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. चन्द्रयान-3 की सफलता, अंतरिक्ष तक भारत की पहुँच और जटिल अभियानों में उसके दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है. इससे चंद्रमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास की वैश्विक दौड़ में भी भारत एक अनुकूल स्थिति में आ जाता है. भविष्य में अंतरिक्ष खनन की जब सम्भावना बनेगी, तो भारत काफी लाभ की स्थिति में होगा. इस मिशन के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों के तकनीकी कौशल का सफल वैश्विक प्रदर्शन हुआ है. साथ ही भावी पीढ़ी को भी यह प्रेरणा प्रदान करता रहेगा. आशा है आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ प्राप्त करने में और अधिक सफल होगा.

सारतः यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि चन्द्रयान-3 की सफलता से भारत को वैज्ञानिक और राजनीतिक परिवेश में चंद्रमा के बढ़ते महत्व का वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. चन्द्रयान-3 खोज के एक अध्याय की शुरूआत करता है, जो इतिहास में गूँजेगा, क्योंकि इस सफलता का प्रभाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे भी है. चन्द्रयान-3 की सफलता का महत्व कहीं अधिक है. भारत के चन्द्रयान-3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा, नवीनता और अटूट समर्पण का प्रमाण है. चंद्रयान मिशन को मात्र चंद्रमा के लिए मिशन मनाना गलत होगा. यह सुदूर अंतरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक आधार प्रदान करेगा. भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले इसके सकारात्मक प्रभाव को कम करके आँका नहीं जाना चाहिए. यह मिशन भारत को न केवल वैज्ञानिक ऊँचाइयों पर ले गया है, बल्कि इसके वैश्विक मंच पर भारत का कद भी बढ़ाया है. अतः यह कहना उचित होगा कि चन्द्रयान-3 की सफलता ने हम भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊँचा कर इसकी सफलता के निहितार्थ को ना केवल वर्तमान स्थिति में, बल्कि भविष्य के लिए भी बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता प्रदान करने का कार्य किया है. ●●●

शेष पृष्ठ 155 का

20. प्रसिद्ध उद्यमी पृथ्वीराज सिंह ऑबेराय का निधन नवम्बर 2023 में हुआ है. वह भारत में किस उद्योग से मुख्यतः सम्बन्धित थे ?
(A) ऑटोमोबाइल (B) होटल
(C) दूरसंचार (D) टेक्सटाइल्स

21. निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए भारत की वार्ता इन दिनों प्रगति पर है ?
(A) फ्रांस (B) ब्रिटेन
(C) जर्मनी (D) आस्ट्रेलिया

22. भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवम्बर 2023 में कहाँ सम्पन्न हुआ ?
(A) मुम्बई (B) चेन्नई
(C) नई दिल्ली (D) गोवा

23. 54वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरिज-OTT फिल्म के लिए ज्यूरी के प्रमुख कौन थे ?
(A) राजकुमार हिरानी
(B) माइकल डगलस
(C) शेखर कपूर
(D) एकता कपूर

24. भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है—
(A) स्वर्ण कमल (B) स्वर्ण पाम
(C) स्वर्ण गज (D) स्वर्ण मयूर

25. वर्ष 2023 के लिए मिस यूनीवर्स चुनी गई शेन्निसं पलासियोस किस देश की नागरिक हैं ?
(A) निकारागुआ (B) एल सेल्वेडोर
(C) वेनेजुएला (D) थाइलैण्ड

उत्तरमाला

1. (C)	2. (C)	3. (D)	4. (A)	5. (A)
6. (A)	7. (B)	8. (D)	9. (C)	10. (B)
11. (A)	12. (C)	13. (D)	14. (D)	15. (D)
16. (C)	17. (D)	18. (A)	19. (A)	20. (B)
21. (B)	22. (D)	23. (A)	24. (D)	25. (A)

●●●

STUDYPDF WALLAH

प्रतियोगिता 'दर्पण'
हिन्दी मासिक

निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक–532 का परिणाम

विषय : भारत के लिए चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता के निहितार्थ

प्रथम प्रभाष पाठक
अवर सांख्यिकी पदाधिकारी
नीलकंठ नगर, तिलकामांझी
जिला–भागलपुर (बिहार)
पिन–812 001

द्वितीय डॉ. राजीव कुमार सिंह
क्वार्टर नं. 10, ब्लॉक-19
पुष्प विहार, सेक्टर-1
नई दिल्ली
पिन–110 017

तृतीय गजेन्द्र शर्मा
S/o श्री विश्वनाथ शर्मा
सरकारी अस्पताल के पास
वार्ड नं.-20, सूरजगढ़
जिला-झुंझनू (राजस्थान)
पिन–333 029

अन्य प्रशंसनीय प्रयास

1. माधव शर्मा
49, आशीर्वाद गार्डन,
मथुरा रोड,
जिला–हाथरस (उत्तर प्रदेश)
पिन–204 101

2. साधन राय
ग्राम + पोस्ट–लावापुर नारायण
जिला–वैशाली (बिहार)
पिन–844 506

3. संजय प्रसाद
S/o स्व. जगदेव प्रसाद
पोस्ट–चाकंद बाजार
जिला–गया (बिहार)
पिन–804 404

4. रणवीर सिंह
सहायक मुख्य अधिकारी
जैव पदार्थ उपयोग
इकाई-सस्यविज्ञान संभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
नई दिल्ली
पिन–110 012

5. मेघा अग्रवाल
शिव कटरा
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
पिन–208 007

प्रथम

द्वितीय

तृतीय

➡ उपर्युक्त प्रशंसित निबन्ध प्रतियोगियों में से प्रत्येक को उपकार प्रकाशन की ₹ 300 मूल्य तक की वांछित पुस्तक/पुस्तकें भेंटस्वरूप प्रदान की जाएंगी. **कृपया अपनी पसंद की पुस्तक अलग से प्रकाशक के नाम पत्र द्वारा सूचित करें.** यदि ₹ 300 से अधिक मूल्य की पुस्तक की माँग की गई, तो उसके मूल्य में से ₹ 300 पुरस्कारस्वरूप कम कर दिए जाएंगे.

शेष पृष्ठ 112 का

का जीवन जी रही हैं. आज भी औरतों को सिर्फ वंश बढ़ाने का साधन मात्र ही समझा जाता है. वे सारी उम्र एक सेविका के समान पति, परिवार और बच्चों की सेवा करती हैं और वैसे ही मर जाती हैं. गाँव की औरतों को मुँह खोलने तक का अधिकार नहीं है.

कामकाजी लड़कियों को भुगतना पड़ता है खामियाजा

मैट्रिमिनियल वेबसाइट पर नॉन वर्किंग वुमन की प्रोफाइल को अगर 100 पुरुषों ने देखा तो वर्किंग वुमन की प्रोफाइल को बस 78 लोगों ने ही देखा. दिवाघर अपनी स्टडी में इस निष्कर्ष पर पहुँचीं कि जब शादी की बात आती है, तो नौकरीपेशा होने न होने का असर पड़ता है. वह कहती है कि उसके कई दोस्तों ने शादी के बाद काम छोड़ दिया या जिस कॅरियर को लेकर वो आगे बढ़ रही थी, उसे शादी के बाद बीच में ही छोड़ दिया.

पुरुषों से ज्यादा कमाने वाली महिलाओं को कम पसंद किया जाता है

जो वर्किंग वुमन पुरुषों से अधिक कमाती है उनके प्रोफाइल को 10% कम पसंद किया गया, जबकि वैसी ही कामकाजी महिलाएं, जो पुरुषों से कम कमाती हैं, उन्हें 15% अधिक पसंद किया गया. कई रिश्ते इसलिए टूट गए, क्योंकि पति को पत्नी का काम करना नहीं पसंद था.

भारत में 99% महिलाएं 40 की उम्र तक पहुँचने से पहले शादी कर लेती है, स्टडी में दिवा ने बताया कि जब महिलाओं को लगता है कि नौकरीपेशा होने पर उन्हें शादी में परेशानी होगी, तो वो अपने कॅरियर के प्रति लापरवाह हो जाती हैं. अक्सर देखा गया है कि कॅरियर में नौकरी का त्याग हमेशा ही महिलाएं ही करती हैं.

एक सर्वे में पाया गया कि 40% महिलाएं अपने पति या पुरुष साथी के कॅरियर को ज्यादा तरजीह देती हैं.

अगर महिला शादी के बाद कॅरियर को प्राथमिकता देती है, तो एक अलग तरह का सामाजिक संकट पैदा होने लगता है. महिलाओं को निशाने पर लेते हुए कहा जाने लगा है कि पश्चमीकरण हो रहा है, परिवार टूट रहा है. तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि पुरुष समाज बदलाव के लिए तैयार नहीं है. वे चाहते हैं कि जब वे काम पर से लौटें तो पत्नी हाथ में चाय-पानी लिए उनके सामने खड़ी रहे, जबकि जॉब पर से तो वो भी थकी-मांदी लौट कर आती हैं. औरतें इसलिए यह सब कुछ सहती हैं ताकि घर में क्लेश न हो और पुरुषो को लगता है वो उससे डरती है.

समाज में बदलाव आ रहा है, संविधान के तहत् महिलाओं को अधिकार भी मिले, पर हकीकत यह है कि औरतों के पढ़े-लिखे नए रोल को समाज ने दिल से स्वीकार नहीं किया है.

कहने को तो पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार मिला है, लेकिन अगर सर्वे कराया जाए, तो पता चले कि कितनी बेटियों को सम्पत्ति में उनका अधिकार दिया गया है. हाँ, लेकिन भाई-बहन के रिश्ते जरूर बिगड़ गए.

कुछ महिलाओं का तो अपने शरीर पर भी पूर्ण अधिकार नहीं है, वहाँ भी पुरुषों ने अधिकार जमा रखा है.

अब समय की माँग है कि महिलाओं को जाग्रत होना होगा और अपनी क्षमता को पहचानना होगा. पारम्परिक रूढ़ियों को खण्डित कर के देश के बुनियादी ढाँचे में अधिक-से-अधिक योगदान देना होगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग भी सशक्तिकरण के स्थान पर शोषण पर ही केन्द्रित हैं. ●●●

STUDYPDF WALLAH

प्रथम पुरस्कृत समीक्षा

वाद-विवाद प्रतियोगिता

विषय–"पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित किए जाने से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल हो गया है."

पक्ष में : **– प्रभाष पाठक**

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतान्त्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेन्द्रीकरण हो, स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतन्त्र का अनोखा और नायाब उदाहरण है, परन्तु बहुत दिनों तक हमारे नीति-निर्धारण में समावेशी तत्व शामिल नहीं थे. यही नहीं महिलाओं की अलग पहचान और उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता भी नहीं थी. **पंचायती राज में महिला भागीदारी** भारतीय शासन व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व सम्बन्धी चिन्तन का महत्वपूर्ण विचार बिन्दु है.

इन्हीं विचारों के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के क्रम में इसके सभी स्तरों पर एक-तिहाई सीटों के आरक्षण की पहल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी, परन्तु यह प्रक्रिया वर्ष 1993 में पूरी हुई. स्व. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के पारित किए गए. महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण, रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया. इस प्रावधान से भारतीय नारी के राजनीतिक सशक्तिकरण की मुहिम पंचायत से लेकर संसद तक अपने अंकुरण को प्रतिद्वनित करने के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में अपनी प्रभावशीलता प्रकट कर रही है.

पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण शुरू होने के बाद से अब तक देश ने महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करने एवं उसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लैंगिक बाधाओं को दूर करते देखा गया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्द्धी राजनीति के कारण महिलाओं को आरक्षण से लाभ हुआ है. महिलाओं के लिए आरक्षण से राजनीतिक सशक्तिकरण किए जाने का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है. पंचायतों और नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनैतिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है. 2019 में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 44·37 प्रतिशत थी. महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अग्रणी राज्य बिहार के साथ भारत में 20 से अधिक राज्यों में यह लागू हो गया है. महिलाओं की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है, बल्कि घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारियाँ सँभाल पाने की असमर्थता के बारे में कई भ्राँतियाँ भी दूर हो गई है.

पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण, विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर, सबसे अधिक महिलाएं भारत में ही निर्वाचित होती हैं. आज देश में 2·5 लाख पंचायत में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं. इनमें से 14 लाख महिला प्रतिनिधि है, जो कुल निर्वाचित सदस्यों का लगभग 46% है. पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही हैं. पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों के बारे में महिलाओं की सोच व समझ का विस्तार हुआ है और वे पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही हैं. आज महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास से पंचायतों के अन्दर और बाहर अपनी भागीदारी से सुशासन के स्तर को और सशक्त बनाया है. पंचायत में पहुँची महिलाएं निःशुल्क भूमि आवंटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में बढ़-चढ़कर योगदान दे रही हैं. इनमें पेयजल की उपलब्धता, शौचालयों के निर्माण आदि मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं. स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, विकास आदि गतिविधियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है.

आरक्षण प्रावधान से एक ऐसे राज-नैतिक माहौल का निर्माण सम्भव हुआ है, जिससे महिलाएं सामाजिक दर्जा और आत्म-विश्वास हासिल करने तथा दमन की परम्परा की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने में सक्षम हो सकी है. महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ी है. भ्रूण हत्या जैसी कुरीति कम हुई हैं. आरक्षण व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर निर्णयन और कार्यक्रम कार्यान्वन में महिलाओं की न केवल भागीदारी सुनिश्चित की है, बल्कि अनेक मामलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि युवा महिलाओं के लिए रोल मॉडल साबित हुई हैं. कई कमियों और सामाजिक वर्जनाओं के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है और पुरुष प्रधान नौकरशाही व्यवस्था को अपने काम करने के तरीकों में सुधार लाने के लिए बाध्य किया है. कई समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण नीति के औचित्य की पुष्टि की है. महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार में प्रगति की दृष्टि से भी यह सराहनीय उपलब्धि है. अतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित किए जाने से महिला सशक्ति-करण का लक्ष्य हासिल हो गया है.

विपक्ष में :

– महेन्द्र सिंह (पटवारी) किरार

भारतीय महिलाएं सदियों तक पुरुषों के तथा सामाजिक उत्पीड़न का शिकार रही हैं. वह सामाजिक और आर्थिक के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर रही हैं. यह सही है कि भारत में कभी-कभी रजिया, सुल्तान, अहिल्याबाई होल्कर तथा इन्दिरा गांधी जैसी महिला शासक भी बनी हैं. मगर ये उदाहरण अपवाद मात्र हैं और इससे महिलाओं की सामान्य स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया. 19वीं सदी के मानवतावादी और समानतावादी विचारों से प्रेरित होकर तत्कालीन समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए शक्तिशाली आन्दोलन की शुरूआत की गई, जिसके अन्तर्गत महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देकर सती प्रथा और बाल-विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए कानून, महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर लाने, एक पत्नी प्रथा प्रचलित करने और महिलाओं को व्यवसाय तथा सरकारी रोजगार में जाने के योग्य बनाने के लिए प्रयास किए गए जिससे

STUDYPDF WALLAH

उनकी आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की शुरूआत तो हुई, लेकिन राजनीतिक निशक्तता ज्यों-की-त्यों बनी रही. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समानता के लिए स्त्रियों के संघर्ष में और तेजी आई.

वर्ष 1959 में पंचायतों के विकास लिए बलबंतराय मेहता समिति का गठन किया गया, तो इस समिति ने ग्राम स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी की बात कही. इसके लगभग तीन दशक बाद राजनीति में महिलाओं की समुचित भागीदारी का रास्ता वर्ष 1992 में खुला जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करके उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की शुरूआत की गई, किन्तु क्या वास्तव में पंचायत और नगरीय निकायों के शासन का नियन्त्रण महिलाओं को मिल पाया है तथा पुरुष प्रधान समाज में प्रतिनिधि बनने मात्र से क्या सामाजिक स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाया है? आज भी यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है.

विभिन्न सर्वे और रिपोर्टों की मानें तो जनप्रतिनिधित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी नगण्य नजर आती है. जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद भी केवल 5 से 10 प्रतिशत महिलाएं घर की दहलीज पार करके अपनी राजनैतिक जिम्मेदारी निभाकर स्वयं की 'राजनीतिक पहचान' स्थापित कर पाई है. भारतीय राजनीति में महिलाओं को अभी और आगे आने की जरूरत है. विभिन्न अधिकार और एक-तिहाई आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी आज पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या अन्य रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नजर आते हैं. अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को उनके पद की जिम्मेदारी की जानकारी भी नहीं होती है. इस कारण वे ग्राम सभा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठकों में मूक-दर्शक की भाँति बैठी रहती हैं और उनके पति ही उनके कामकाज का संचालन करते हैं. महिला प्रतिनिधि वहीं करती हैं, जो उनके पति या रिश्तेदार कहते हैं. अगर उनसे उनके कार्यक्षेत्र और कार्यों के विषय में कुछ पूछा जाए, तो वह एक ही वाक्य "हमारे उनसे जानिए" कहकर अपनी बात को समाप्त कर देती हैं.

आज भी महिला सरंपचों के पति ही उनके कामकाज सँभालते दिखाई देते हैं. इस कारण उन्हें 'सरपंच पति' या 'प्रधानपति' जैसे शब्दों से नवाजा जाता है. सरपंच पति का आशय उन पतियों से है जिनकी पत्नियाँ असल में सरपंच के पद पर चुनी जाती हैं और उनके पति उस पद के प्रभाव का अनुचित फायदा उठाते हैं और जब किसी राजनीतिक कार्यक्रम में किसी की मुलाकात इनसे होती है, तो बड़ी शान से यही व्यक्ति एसपी (सरपंच पति) के रूप में अपना परिचय देते हैं. इस समय देश भर में 'सरपंच पति' का चलन है जिसके चलते चुनाव जीतने के तुरन्त बाद महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है और पुरुष ही इनके स्थान पर सत्ता का वास्तविक संचालन करते हैं. महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका एक 'रबर स्टॉम्प' की तरह बनकर रह जाती है. यद्यपि महिलाओं में विभिन्न भूमिकाएं प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक निभाने की असीम क्षमता होती है. हाल ही में, नए संसद भवन से पारित पहला 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम को 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' के नाम से पारित तो कर दिया गया है, किन्तु इसे लागू आगामी जनगणना के पश्चात ही किया जाएगा. इससे स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में दिए गए एक-तिहाई महिला आरक्षण से आज भी महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है. इस कारण, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड तथा त्रिपुरा ने एक-तिहाई आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि केवल चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता निर्णय लेने की शक्ति मिली या नहीं तथा उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए किस तरह का वातावरण मिल रहा है, यह महत्वपूर्ण है.

●●●

शेष पृष्ठ 119 का

39. (C) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखण्ड के उलिहातू ग्राम के महानायक भगवान विरसा मुण्डा के जन्म दिन 15 नवम्बर, 2023 (जनजाति गौरव दिवस) के अवसर पर खुण्टी में ₹ 24000 करोड़ परिव्यय वाली प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) योजना तथा 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' लॉन्च की.
40. (A)
41. (B) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच रक्षा कृत्रिम मेघा डायलोग हेतु सहमति बनी है.
42. (A) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका रक्षा औद्योगिक सहयोग के हिस्से के रूप में एक पैदल सेना लड़ाकू वाहन का सह-उत्पादन करेंगे. इस आशय की घोषणा अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड जे. ऑस्टिन और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथसिंह के बीच 2 + 2 वार्ता के दौरान की गई.

●●●

वाद-विवाद प्रतियोगिता क्रमांक-210 का परिणाम

विषय : "पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित किए जाने से महिला. सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल हो गया है."

विजेता

पक्ष में :

प्रभाष पाठक
अवर सांख्यिकी पदाधिकारी
नीलकंठ नगर, तिलकामांझी
भागलपुर (बिहार) पिन-812 001

विपक्ष में :

महेन्द्र सिंह (पटवारी) किरार
केन्द्रीय विद्यालय के सामने
गुना (मध्य प्रदेश)

☞ उपर्युक्त प्रशंसित वाद-विवाद प्रतियोगियों में से प्रत्येक को उपकार प्रकाशन की ₹ 500 मूल्य तक की वांछित पुस्तक/पुस्तकें भेंटस्वरूप प्रदान की जाएंगी. **कृपया अपनी पसन्द की पुस्तक अलग से प्रकाशक के नाम पत्र द्वारा सूचित करें.** यदि ₹ 500 से अधिक मूल्य की पुस्तक की माँग की गई, तो उसके मूल्य में से ₹ 500 पुरस्कारस्वरूप कम कर दिए जाएंगे.

वाद-विवाद प्रतियोगिता

विषय-"समावेशी विकास समता-मूलक समाज की स्थापना कर सकता है."

अन्तिम तिथि-15 जनवरी, 2024

शब्द संख्या-अधिकतम 750 शब्द (पक्ष/विपक्ष)

पुरस्कार योजना-पक्ष/विपक्ष के प्रथम दो लेख.

विशेष-पक्ष/विपक्ष के प्रथम लेख पत्रिका में प्रकाशित होंगे.

कृपया अपनी प्रविष्टि पर अपना पूरा पता फोन नं. सहित अवश्य लिखें.

प्रथम पुरस्कृत पक्ष/विपक्ष अभ्यर्थी को पुरस्कारस्वरूप ₹ 500/- प्रदान किए जाएंगे.

कॉपीराइट अधिकार प्रकाशक का होगा. अन्य लेख वापस नहीं किए जाएंगे.

(कृपया लिफाफे पर निम्नलिखित कूपन को अवश्य चिपकाएं)

वाद-विवाद प्रतियोगिता क्रमांक-211
(पक्ष/विपक्ष/दोनों पक्ष)

उपकार CCC
कोर्स ऑन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट्स
हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में
Code 2687
₹ 270/-
प्रो. संजय कुमार,
प्रो. अतुल सहदेव
एवं
डॉ. सियम सुमन

उपकार प्रकाशन, आगरा-5
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

STUDYPDF WALLAH

TEST RANGE

TEST RANGE

अभ्यास | विश्लेषण | सुधार

नवीनतम पैटर्न पर आधारित
भारत का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट
सीरिज एप

टेस्ट अंग्रेजी व हिन्दी
भाषा में उपलब्ध

800+
परीक्षायें

Test Range
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगिता

नवीनतम पाठ्यक्रम

- वास्तविक परीक्षा के अनुरूप अनुभव
- मूल परीक्षा के पैटर्न व नवीनतम् पाठ्यक्रम पर आधारित
- चैप्टर एवं खण्ड के अनुरूप टेस्ट

बेहतर अभ्यास

- बेहतर अभ्यास के लिए पूर्व वर्षों के प्रश्न–पत्रों का संकलन
- ग्राफिकीय ढंग से अभ्यर्थी के किसी टेस्ट में सबल व निर्बल पक्ष का विश्लेषण कर उसे अवगत कराना

तथ्यपरक विश्लेषण

- शॉर्टकट एवं व्याख्यात्मक तरीकों से सभी प्रश्नों के हल
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की अखिल भारतीय स्तर पर रैंकिंग
- प्रत्येक परीक्षा के लिए फ्री टेस्ट उपलब्ध

BANK / SSC / TET / RAILWAY / IAS

Scan The QR Code
To Download The App

Feel free to contact us : testrange@upkar.in

STUDYPDF WALLAH

महत्वपूर्ण वार्षिक घटनाक्रम

[जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक]

(राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद)

'प्रतियोगिता दर्पण' के जनवरी अंक में गत पूरे वर्ष में घटित प्रमुख घटनाओं/ज्वलंत मुद्दों का विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत समीक्षात्मक लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का श्रमसाध्य प्रयास पत्रिका की परम्परा रही है. हमारे इस विनम्र प्रयास का उद्देश्य पत्रिका के पाठकों को ज्ञान व सामयिकी की नवीन ऊर्जा से एक नई दिशा देना है. पाठकों ने हमारे इस प्रयास को सदैव सराहा है. पाठकों के स्नेह से उत्साहित होकर तथा बदलते परीक्षा प्रतिमानों के अनुरूप इस वर्ष से हम इस परम्परा को नए कलेवर और गुणात्मक सुधारों के साथ पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं. आशा है हमारा यह प्रयास पाठकों के लिए बहुपयोगी सिद्ध होगा. नव वर्ष आपके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे व आप सफलता के शीर्ष पर प्रतिष्ठित हों, ऐसी हार्दिक कामना है.

—डॉ. सूर्यनारायण पाण्डेय

राष्ट्रीय घटनाक्रम

चुनाव/सत्ता परिवर्तन

- **नगालैण्ड**

27 फरवरी, 2023 को नगालैण्ड में 60 सदस्यीय विधान सभा के लिए सम्पन्न चुनावों के परिणाम की घोषणा 2 मार्च, 2023 को हुई. नगालैण्ड में 59 सीटों पर ही मतदान कराया गया था. भाजपा के एक उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने से 59 सीटों के लिए ही मतदान की वहाँ आवश्यकता थी. नगालैण्ड में पिछले 2018 के चुनावों के पश्चात् सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी-नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) गठबंधन ने एक बार पुनः 37 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा. इन चुनावों में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) को 25 तथा उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें प्राप्त हुईं. इनमें नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की सीटों की संख्या 18 से बढ़कर 25 रही, वहीं भाजपा की सीटें पूर्ववत् 12 ही रही हैं. अन्य दलों में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) तीसरे स्थान पर रही. कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) को 5 तथा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई हैं. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है. सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट (NPF) को केवल 2 सीटें प्राप्त हुईं और उसे 26 सीटों का नुकसान हुआ.

नगालैण्ड विधान सभा चुनाव-2023 : चुनाव परिणाम एक दृष्टि में

कुल सीटें-60

चुनाव हुए-59 (एक सीट निर्विरोध)

दल का नाम	प्राप्त सीटें	2018 की तुलना में परिवर्तन
नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP)	25	+ 7
भारतीय जनता पार्टी	12	–
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)	7	+ 7
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)	5	+ 3
लोक जनशक्ति पार्टी	2	+ 2
नगा पीपुल्स फ्रंट	2	– 24
रिपब्लिक पार्टी (अन्य वाले)	2	–
अन्य	5	+ 3
योग	60	

नगालैण्ड में प्राप्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने सरकार का गठन वहाँ किया. एनडीपीपी नेता **नेफ्यू रियो** (Neiphiu Rio) ही पाँचवीं बार मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं. 7 मार्च, 2023 को राजधानी कोहिमा में आयोजित एक समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली इस सरकार में दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं.

- **मेघालय**

27 फरवरी, 2023 को मेघालय में 60 सदस्यीय विधान सभा के लिए सम्पन्न चुनावों के परिणाम की घोषणा 2 मार्च, 2023 को हुई. मेघालय में 59 सीटों पर ही मतदान कराया गया था. एक उम्मीदवार के निधन के कारण 59 सीटों के लिए ही मतदान वहाँ कराया गया. चुनाव के परिणामों में त्रिशंकु विधान सभा की स्थिति वहाँ पैदा हुई. निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) के नेतृत्व वाली **नेशनल पीपुल्स पार्टी,** जो पूर्वोत्तर की अकेली ऐसी पार्टी है, जिसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, को ही सर्वाधिक 26 सीटें चुनाव में प्राप्त हुई हैं. उनके नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार में भाजपा व यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UPD) भी शामिल थी. इस बार इन तीनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़े थे. भाजपा को 2 तथा यूपीडी को 11 सीटें इस बार प्राप्त हुई थीं. अन्य दलों में कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस को 5-5 सीटें प्राप्त हुई थीं. पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 21 थी.

मेघालय में प्राप्त उक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ही लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं. उनके नेतृत्व वाले मेघालय प्रजातांत्रिक गठबंधन में उनकी स्वयं की नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी (NPP) के अतिरिक्त भाजपा, एचएसपीडीपी, पीडीएफ व निर्दलीय विधायक शामिल हैं. गठबंधन के नेता **कोनराड संगमा** (Conrad Sangma) ने ही लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं. 7 मार्च, 2023 को राजधानी शिलांग में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. मेघालय के संगमा सरकार में दो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं.

STUDYPDF WALLAH

मेघालय विधान सभा चुनाव-2023 : चुनाव परिणाम एक दृष्टि में कुल सीटें-60		चुनाव हुए-59
दल का नाम	प्राप्त सीटें	2018 की तुलना में परिवर्तन
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)	26	+ 6
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP)	11	+ 5
तृणमूल कांग्रेस	5	+ 5
कांग्रेस	5	– 16
वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी	4	+ 4
भारतीय जनता पार्टी	2	+ 1
हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP)	2	–
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (PDF)	2	– 2
निर्दलीय	2	– 1
योग	**59**	

• त्रिपुरा

16 फरवरी, 2023 को त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधान सभा के लिए सम्पन्न चुनावों के परिणाम की घोषणा 2 मार्च, 2023 को हुई. चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 32 स्थानों पर तथा उसकी सहयोगी पार्टी इण्डिजिनिस प्यूपिल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) को 1 सीट पर विजय प्राप्त हुई और गठबंधन ने सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा. पिछले 2018 के चुनावों में भाजपा ने 36 सीटों पर तथा आईपीएफटी ने 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी. 35 वर्षों तक सत्ता में रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) को 11 सीटों से सन्तोष करना पड़ा. चुनाव में माकपा की सहयोगी रही कांग्रेस को 3 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई. 2013 व 2018 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी. पृथक् टिप्रालैण्ड की माँग कर रही नई **टिप्रा मोथा** पार्टी 13 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी सदन में बनी है.

त्रिपुरा में इन चुनाव परिणामों के चलते 43 सीटों वाले भाजपा-आईपीएफटी गठबन्धन ने सरकार का गठन वहाँ किया. 2016 में भाजपा में शामिल हुए **माणिक साहा,** जिन्हें 2022 में विप्लव कुमार देव के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, को ही एक बार पुनः मुख्यमंत्री वहाँ बनाया गया है. 8 मार्च, 2023 को राजधानी अगरतला में स्वामी विवेकानन्द मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली.

त्रिपुरा विधान सभा चुनाव-2023 : चुनाव परिणाम एक दृष्टि में कुल सीटें-60		चुनाव हुए-60
दल का नाम	प्राप्त सीटें	2018 की तुलना में परिवर्तन
भारतीय जनता पार्टी	32	– 4
इण्डिजिनिस प्यूपिल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (IPFT)	01	– 7
कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	11	– 5
कांग्रेस	03	+ 3
टिप्रा मोथा पार्टी	13	+ 13
योग	**60**	

• कर्नाटक

कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधान सभा के लिए 10 मई, 2023 को एक ही चरण में चुनाव कराए गए. कनार्टक में चुनाव में हर 5 वर्ष बाद सरकार बदलने की 1985 से चली आ रही परम्परा को जनता ने कायम रखा. राज्य में सम्पन्न चुनाव के परिणाम की घोषणा 13 मई, 2023 को हुई. सदन की 224 सीटों में से 135 सीटों पर विजय दर्ज कर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस ने दर्ज किया. 4 वर्ष से सत्तारूढ़ रही भाजपा 66 सीटों के साथ उसके आधे तक भी नहीं पहुँच पाई. तीसरे स्थान पर जनता दल (एस), जिसने पिछले 2018 के चुनाव में 37 सीटें जीती थीं तथा जो विगत 4 वर्षों से भाजपा के साथ सत्ता में साझीदार थी, इस बार 19 सीटों पर ही सिमट गई.

कर्नाटक में प्राप्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के **सिद्धारमैया** एक बार पुनः राज्य के मुख्यमंत्री बने. वह दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं. 19 मई, 2023 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इससे पूर्व सिद्धारमैया मई 2013 से मई 2018 के दौरान 5 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे.

कर्नाटक विधान सभा चुनाव-2023 : चुनाव परिणाम एक दृष्टि में कुल सीटें-224			चुनाव हुए-224
दल का नाम	प्राप्त सीटें		2018 की तुलना में परिवर्तन
	2023	2018	
कांग्रेस	135	80	+ 55
भारतीय जनता पार्टी	66	104	– 38
जनता दल (एस)	19	37	– 18
अन्य	4	3	+ 1
योग	**224**	**224**	

विविध राजनीतिक गतिविधियाँ

• आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा

दिल्ली, गोवा, पंजाब व गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए 10 अप्रैल, 2023 को चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया. चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को जहाँ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, वहीं तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (CPI) व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया. इससे देश में अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की संख्या 6 (भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी व आम आदमी पार्टी) ही रह गई है.

☞ चुनाव आयोग के 10 अप्रैल, 2023 के फैसलों से राज्यस्तरीय पार्टियों की मान्यता में भी फेरबदल हुई.

• मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा का स्थगन

4 अगस्त, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक आरोपित की. इसके साथ ही इनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई. 2019

STUDYPDF WALLAH

में कर्नाटक में कोलार में एक जनसभा को सम्बोधन के दौरान मोदी उपनाम के सम्बन्ध में अपमानजनक टिप्पणी करने के 4 वर्ष पुराने एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मान हानि का दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा 23 मार्च, 2023 को सुनाई थी. लोक सभा सचिवालय ने इसके बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 के तहत् राहुल गांधी की लोक सभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव (23 मार्च, 2023) से समाप्त कर दी थी.

- **नए संसद भवन में विशेष सत्र**

19 सितम्बर, 2023 को नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरूआत हुई. इसकी शुरूआत, वर्षों से लम्बित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, प्रस्तुत कर, सरकार ने की. विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त यह विधेयक चर्चा के पश्चात् लोक सभा में 454-2 के भारी बहुमत से 20 सितम्बर, 2023 को पारित हो गया, जबकि राज्य सभा में 21 सितम्बर, 2023 को प्रस्तुत यह विधेयक उसी दिन सर्वसम्मति से पारित हुआ. इसके साथ ही नया संसद भवन अब आधिकारिक रूप से देश की नई संसद हो गई है. पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' नाम दिया गया है.

- **जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी**

5 अक्टूबर, 2023 को गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया. यह संगठन 1998 से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त था.

सम्मेलन/बैठक/महोत्सव/आयोजन

26वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव

12-16 जनवरी, 2023 के दौरान हुबली, धारवाड़ में कर्नाटक सरकार की मेजबानी में 26वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव सम्पन्न हुआ. केन्द्र सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह आयोजन कर्नाटक प्रशासन के सहयोग से किया गया. इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का **थीम** (Theme) था—**'विकसित युवा-विकसित भारत'.**

- **23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम—** फिट यूथ फिट इंडिया
- **24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम—** युवाह (Yuvaah)-उत्साह नए भारत का
- **25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम—** सक्षम युवा-सशक्त युवा
- पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में भोपाल में आयोजित किया गया था.

ऑटो एक्सपो-2023 (16वाँ)

11-18 जनवरी, 2023 के दौरान ग्रेटर नोएडा व नई दिल्ली में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के देश की सबसे बड़ी द्विवार्षिक प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो-2023 का आयोजन हुआ. मुख्य ऑटो एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ, जबकि ऑटो एक्सपो कम्पोनेंट शो का 16वाँ संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12-15 जनवरी, 2023 के दौरान हुआ.

सेमीकॉन-2023

28-29 जुलाई, 2023 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में देश में सेमी कंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन-2023 का आयोजन हुआ. विषय विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं व उद्योग जगत के संयुक्त भागीदारी वाले इस सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है.

49वाँ खजुराहो महोत्सव

20-26 फरवरी, 2023 के दौरान बहुचर्चित 49वाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में सम्पन हुआ. भारतीय शास्त्रीय नृत्य परम्परा पर आधारित इस महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया गया. यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के शानदार शहर में आयोजित किया जाता है. महोत्सव में कलाकार ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि में अपना प्रदर्शन करते हैं.

108वाँ भारतीय विज्ञान कांग्रेस

3-7 जनवरी, 2023 के दौरान 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ. इस वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम (Theme) था—महिला सशक्तिकरण के साथ सतत् विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment).

17वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन

8-10 जनवरी, 2023 के दौरान इन्दौर में भारतीय विदेश मंत्रालय व मध्य प्रदेश सरकार के तत्वावधान में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सम्पन्न हुआ. प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अन्तराल में होता है.

17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम (Theme) था—**डायस्पोरा : अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार** (Diaspora : Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal). गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे. इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. प्रवासी भारतीय दिवस को नियमित रूप से मनाने का उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार के साथ सम्बन्ध सशक्त करना है और उनकी जड़ों के साथ फिर से जोड़ना है.

भारतीय चावल कांग्रेस, 2023

11-14 फरवरी, 2023 के दौरान ओडिशा में कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में देश में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस (Indian Rice Congress) का आयोजन हुआ. इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने किया.

सीबीआई की हीरक जयंती (Diamond Jubilee of CBI)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI–Central Bureau of Investigation) की स्थापना, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा, 1 अप्रैल, 1963 को हुई थी. इस संगठन के 60 वर्ष 1 अप्रैल, 2023 को पूरे हुए. इस उपलक्ष्य में सीबीआई की हीरक जयंती समारोह 3 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया. समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सीबीआई जैसे पेशेवर व कुशल संस्थानों के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता. रैंक फ्रॉड से लेकर वन्य जीवन से जुड़े फ्रॉड तक सीबीआई के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं. सीबीआई का कार्य क्षेत्र कई गुना बढ़ गया है. प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में रेखांकित किया कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी है.

14वाँ विश्व मसाला कांग्रेस, 2023

16-18 फरवरी, 2023 के दौरान मुम्बई (महाराष्ट्र) में 14वाँ विश्व मसाला कांग्रेस, 2023 आयोजित हुआ. इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है. इसका पहला आयोजन 1990 में हुआ था. वर्ष 2023 के आयोजन का थीम है—'विजन 2023 : स्पाइसेज (SPICES)' {स्थायित्व (S-Sustainability), उत्पादकता (P-Productivity), न्वोन्मेषण

STUDYPDF WALLAH

(I-Innovation), सहयोग (C-Collaboration), उत्कृष्टता (E-Excellence) तथा सुरक्षा (S-Safety)}.

वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन

20-21 अप्रैल, 2023 के दौरान नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ (IBC–International Buddisht Confederation) व केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ. इसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व को बौद्ध जीवन दर्शन से जोड़ना तथा भगवान बुद्ध के विश्व शांति के सन्देश को सम्पूर्ण विश्व में पहुँचाना है. इस सम्मेलन में सम्पूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों वाले लगभग 30 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

श्री अन्न महोत्सव

20-21 अप्रैल, 2023 के दौरान जोधपुर में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में 2 दिवसीय मिलेट मेला सह प्रदर्शनी (श्री अन्न महोत्सव) का आयोजन हुआ. इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी हित धारकों को मोटे अनाज पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ उन्हें एक समान मंच पर लाने तथा मोटे अनाज आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित किया जाना है.

☞ उल्लेखनीय है कि राजस्थान भारत में मिलेट्स का बड़ा उत्पादक है. देश में इसके कुल उत्पादन में 16 प्रतिशत से अधिक योगदान राजस्थान का होता है.

दिव्य कला मेला

29 जून से 5 जुलाई, 2023 के दौरान राजस्थान के जयपुर में 'दिव्य कला मेला' का आयोजन हुआ. वर्ष 223-24 के दौरान यह मेला भारत के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा. इस शृंखला में यह 6वाँ आयोजन था. इसके पूर्व दिसम्बर 2022 में दिल्ली में, फरवरी 2023 में मुम्बई में, मार्च 2023 में भोपाल में, मई 2023 में गुवाहाटी में तथा जून 2023 में इंदौर में इस के आयोजन हो चुके हैं. यह दिव्यांगों के उत्पादों और कौशलों के विपणन एवं प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच है.

हरित हाइड्रोजन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2023

5-7 जुलाई, 2023 के दौरान नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH–International Conference On Green Hydrogen) सम्पन्न हुआ. इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना था. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 4 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारम्भ किया था.

वर्ष 2023 के कुछ विशिष्ट महोत्सव/आयोजन

- ***17वाँ प्रवासी भारतीय दिवस 2023** : जनवरी 2023; इंदौर*
- ***26वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव** : 12-16 जनवरी, 2023; हुबली-धारवाड़*
- ***विश्व पुस्तक मेला, 2023** : 25 फरवरी-5 मार्च, 2023 (नई दिल्ली)*
- ***108वाँ भारतीय विज्ञान कांग्रेस** : 3-7 जनवरी, 2023; नागपुर*
- ***14वाँ विश्व मसाला कांग्रेस, 2023** : 16-18 फरवरी, 2023; मुम्बई*
- ***49वाँ खजुराहो महोत्सव** (20-26 फरवरी, 2023; खजुराहो, मध्य प्रदेश)*
- ***श्री अन्न महोत्सव** : 20-21 अप्रैल, 2023; जोधपुर*
- ***जनजाति खेल महोत्सव** : 12 जून, 2023; कलिंग*
- ***साहित्य एवं संस्कृति का उन्मेष व उत्कर्ष महोत्सव** : 3-6 अगस्त, 2023; भोपाल*
- ***चौथा नदी उत्सव** : 22-24 सितम्बर, 2023; नई दिल्ली*
- ***लाइटहाउस महोत्सव** : 23 सितम्बर, 2023; गोवा*
- ***साहित्यिक महोत्सव** : 7-8 अक्टूबर, 2023; बेंगलूरू*

पहला उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी

21-25 सितम्बर, 2023 के दौरान ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में पहले उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन हुआ. इसमें 2000 से अधिक निर्यातकों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया. लगभग 66 देशों के 400 से अधिक खरीददार इस व्यापार प्रदर्शनी में शामिल हुए.

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन, 2023

23-24 सितम्बर, 2023 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ. देश में इस प्रकार का यह पहला आयोजन था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. इसका **मुख्य विषय** था—न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियाँ.

योजना / परियोजना / नीतियाँ / कार्यक्रम

पोषण भी, पढ़ाई भी

10 मई, 2023 को केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मिशन सक्षम आँगनबाड़ी और पोषण 2·0 के तहत् प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम 'पोषण भी, पढ़ाई भी' का शुभारम्भ किया. इसके तहत् 3-6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण के साथ-साथ बेहतर शिक्षा देने हेतु देशभर के आँगनबाड़ियों में कार्य किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि देश में 13·9 लाख आँगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत् हैं. सक्षम आँगनबाड़ी और पोषण 2·0 योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है.

महिला सम्मान बचत-पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक बचत योजना की घोषणा अपने बजट भाषण में की थी. वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए अधिसूचना जारी करते हुए 1 अप्रैल, 2023 से यह योजना प्रारम्भ की गई. इस बचत योजना को **महिला सम्मान बचत-पत्र** (Mahila Samman Savings Certificate) नाम दिया गया है. इस योजना के तहत् केवल महिलाएं अथवा नाबालिक लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक तें खाता खोल सकते हैं. इस योजना में न्यूनतम ₹ 1,000 व अधिकतम ₹ 2 लाख जमा किए जा सकते हैं. यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए (31 मार्च, 2025 तक) ही लागू की गई है.

बिहार जाति आधारित गणना, 2022

2 अक्टूबर, 2023 को बिहार सरकार ने बिहार जाति आधारित गणना के आँकड़े जारी किए. आँकड़ों के अनुसार बिहार की सीमा में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 12,53,53,288 है. इनमें हिन्दुओं की कुल संख्या 81·99 प्रतिशत है. जातियों में सर्वाधिक संख्या 14·26 प्रतिशत जनसंख्या यादव जाति की है.

बिहार जातीय गणना आँकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य है. बिहार में जाति आधारित गणना दो चरणों में सम्पन्न हुई. इसका पहला चरण 7 जनवरी, 2023 से 21 जनवरी, 2023 तक सम्पन्न हुआ. पहले चरण में घरों की संख्या की गणना की गई. दूसरा चरण 15 अप्रैल, 2023 से 15 मई, 2023 के दौरान सम्पन्न हुआ. दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनकी जाति, उपजातियों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी हासिल की गई. बिहार में कुल 215 जातियों की गणना हुई है.

STUDYPDF WALLAH

पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM) कार्यक्रम

रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करते हुए तथा वैकल्पिक एवं प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देते हुए उर्वरकों के सन्तुलित/सतत् उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **पीएम-प्रणाम** (PM-PRANAM-PM-Programme for Restoration, Awareness generation, Nourishment and Ameliration of Mother-Earth) **{धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम}** कार्यक्रम को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 28 जून, 2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई. इस कार्यक्रम के तहत् केन्द्र सरकार सभी राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग पर प्रोत्साहन देगी. इस कार्यक्रम का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में किया था. इसे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का अनुमोदन 28 जून, 2023 को प्राप्त हुआ.

विधेयक/अध्यादेश/अधिनियम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य-क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2023

मई 2023 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य-क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन को केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया. प्राधिकरण के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे. दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे. प्राधिकरण में सभी निर्णय उपस्थिति सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे तथा सहमति नहीं होने की स्थिति में दिल्ली के उप-राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा.

महिला आरक्षण अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम)

देश की संसद के नए भवन में स्थानान्तरण के लिए विशेष सत्र 18-22 सितम्बर, 2023 के दौरान आहूत किया गया था. नए संसद भवन में स्थानान्तरण के पश्चात् पहले ही सत्र (विशेष सत्र) में इतिहास उस समय रचा गया जब लोक सभा एवं राज्य सभा एव राज्य विधान सभाओं (दिल्ली विधान सभा सहित) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया था तथा जो मूलतः 128वाँ संविधान संशोधन विधेयक था, को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हो गया, जिसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया तथा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया.

चर्चित न्यायिक निर्णय व न्याय-पालिका से जुड़े चर्चित मुद्दे

उच्चतम व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या व रिक्तियाँ

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या, इन न्यायालयों में वास्तव में कार्यरत् न्यायाधीशों की संख्या तथा रिक्तियों के सम्बन्ध में 21 मार्च, 2023 की स्थिति की जानकारी केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में 24 मार्च, 2023 को दी गई. इसमें बताया गया कि 21 मार्च, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 34 पद (मुख्य न्यायाधीश सहित) भरे हुए थे तथा न्यायाधीशों का कोई पद रिक्त नहीं था.

देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के (मुख्य न्यायाधीश सहित) स्वीकृत 1114 पद (840 स्थायी + 274 अतिरिक्त न्यायाधीश) थे. इनमें कार्यशील न्यायाधीशों की संख्या 785 (640 स्थायी + 145 अतिरिक्त न्यायाधीश) थी. इन उच्च न्यायालयों में स्वीकृत स्थायी पदों के सापेक्ष 200 तथा अतिरिक्त पदों के सापेक्ष 129 पद रिक्त थे.

☞ 9 फरवरी, 2023 को उत्तरित एक अन्य प्रश्न के उत्तर के अनुसार 1 फरवरी, 2023 को देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 59,87,477 थी. इनमें सर्वाधिक 10·30 लाख मामले देश के सबसे बड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तथा सबसे कम 171 मामले सिक्किम उच्च न्यायालय में लम्बित थे. सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 69,511 बताई गई.

सर्वोच्च न्यायालय के दो नए न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र व वरिष्ठ एडवोकेट के. वी. विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय में मई 2023 में न्यायाधीश नियुक्त किया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने इन्हें पद की शपथ 19 मई, 2023 को ग्रहण कराई. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र इस नियुक्ति से पूर्व आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन को सीधे बार से ही यह नियुक्ति प्रदान की गई है. न्यायमूर्ति विश्वनाथन सीधे बार से ही सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति पाने वाले 10वें एडवोकेट हैं.

विज्ञान / प्रौद्योगिकी / अन्तरिक्ष / चिकित्सा

ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री

6 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक में तुमकुरु में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया. इसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी. ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जो शुरूआती दिनों में प्रति वर्ष लगभग 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का उत्पादन करेगा. एलयूएच स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित 3-टन क्लास, सिंगल-इंजन मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है.

आईएनएस वागीर

23 जनवरी, 2023 को प्रोजेक्ट-75 के तहत् मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स लि. (MDL) द्वारा निर्मित कलवारी श्रेणी की पाँचवीं पनडुब्बी वागीर (Vagir) को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया. एंटी-सरफेस वारफेयर एंटी-सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी एकत्र करने, माइंस बिछाने व निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों में सक्षम आईएनएस वागीर समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है तथा लगतार 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकती है. आईएनएस वागीर का जलावतरण 12 नवम्बर, 2020 को किया गया था.

इसरो द्वारा ब्रिटिश कम्पनी वनवेब के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण

26 मार्च, 2023 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) ने उपग्रहों के व्यावसायिक प्रक्षेपण के एक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, जब ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड (वनवेब ग्रुप) के 36 उपग्रहों को अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट एलवीएम-3 (LVM-3) के जरिए अन्तरिक्ष में उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया. 43·5 मीटर लम्बे इस रॉकेट का प्रक्षेपण आन्ध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र से किया गया. रवाना होने के 19 मिनट बाद ही इसके सभी उपग्रह अलग-अलग चरणों में इससे अलग होकर अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित हो गए.

STUDYPDF WALLAH

एनवीएस-01 का सफल प्रक्षेपण

29 मई, 2023 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) ने सेकण्ड जनरेशन नेवीगेशन सैटेलाइट (NVS-01) का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से अपने शक्तिशाली भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एमके-2-एफ-12 के माध्यम से किया. भारत की स्वदेशी नेवीगेशन प्रणाली 20 मीटर तक की सटीक पोजीशनिंग बता सकती है. इस नाविक प्रणाली की मजबूती के लिए अब दूसरे चरण में सेकण्ड जनरेशन सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है. एनवीएस-01 इसी शृंखला में पहला सैटेलाइट है.

रॉकेट इंजन रमन-1

जून 2023 में विक्रम-1 रॉकेट में प्रयोग के लिए रमन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. रॉकेट रमन-1, 3-डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन (Raman) का उन्नत संस्करण है. भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कम्पनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने रमन-1 इंजन का नाम नोबल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन के नाम पर रखा है. रमन-1 इंजन का उपयोग विक्रम-1 रॉकेट में रोल एटीट्यूट कंट्रोल के उद्देश्य से किया जाएगा.

चन्द्रयान-3

14 जुलाई, 2023 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने तीसरे चन्द्र मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया. सतीश धवन स्पेस सेंटर से एलवीएम3-एम4 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा गया. चन्द्रयान-3 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक की 41 दिन की जटिल यात्रा पर रवाना किया गया था. 5 अगस्त, 2023 को इसने चन्द्रमा की कक्षा में प्रवेश किया. जैसे-जैसे मिशन आगे बढ़ता गया, इसरो ने चन्द्रयान-3 की कक्षा को घटाने और उसे चन्द्रमा के निकट लाने की प्रक्रिया को पूरा किया. चंद्रयान-3 की सफलता से भारत न केवल चाँद पर पहुँचने वाले विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है, अपितु इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी नई दिशा मिली है.

भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चन्द्रयान-3 ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. विक्रम लैण्डर चन्द्रतल पर सफलतापूर्वक उतरा.

आदित्य-एल 1 मिशन

चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य-एल1 का प्रक्षेपण 2 सितम्बर, 2023 को किया. 1480·7 किग्रा वजन का आदित्य-एल1 एक वेधशाला है, जिसे सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है.

सी-295 परिवहन विमान

सितम्बर 2023 में सी-295 परिवहन विमान वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर तैनात किया गया. सेविले (स्पेन) स्थित यूरोपीय विमानन कम्पनी एयरबस डिफेंस एण्ड स्पेस के उत्पादन इकाई ने भारतीय वायु सेना के लिए यह पहला एयरबस सी-295 परिवहन विमान 13 सितम्बर, 2023 को सेविले में भारतीय वायुसेनाध्यक्ष एयर फील्ड मार्शल वीआर चौधरी को सौंपा था. स्पेन से ऐसा दूसरा सी-295 विमान मई 2024 तक भारत को प्राप्त होगा. इसके बाद प्रति महीने एक विमान भारत आएगा तथा कुल 16 सी-295 विमान तैयार हालत में स्पेन से प्राप्त किए जाएंगे.

मत्स्य-6000

चन्द्रमा व सूर्य की दिशा में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कदम बढ़ाने के पश्चात् अब गहरे समुद्र में भी संसाधनों एवं जैव विविधता के सम्बन्ध में अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए समुद्र से 6,000 मीटर गहराई तक समुद्रयान भेजने की भू-विज्ञान मंत्रालय की योजना है. इस समुद्रयान (पनडुब्बी) को मत्स्य-6000 नाम दिया गया है. मत्स्य-6000 की लाँचिंग 2026 में सम्भावित है.

प्रतिवेदन/निर्देश/समिति/आयोग/परिषद्

22वाँ विधि आयोग

जनवरी 2023 में केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में डेढ़ वर्ष की वृद्धि की. इस आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी, 2020 को की थी तथा इसका 3 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 तक ही था. आयोग के लिए अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवम्बर 2022 में की थी. अब इसका कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक के लिए बढ़ गया है.

सोमानाथन समिति

मार्च 2023 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु अपनी संस्तुति दिए जाने हेतु वित्त सचिव टी. वी. सोमानाथन की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया. यह समिति पेंशन के मुद्दे पर विचार करेगी तथा सुधार हेतु प्रस्ताव लाएगी.

अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जाँच हेतु समिति

मार्च 2023 में केन्द्र सरकार ने बहुचर्चित अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जाँच हेतु उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया. समिति शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कम्पनियों के शेयरों में गिरावट की जाँच करेगी तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 माह का समय निर्धारित किया गया है.

मणिपुर हिंसा की जाँच हेतु आयोग

4 जून, 2023 में केन्द्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जाँच हेतु गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लाम्बा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया. इसके 2 अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास व पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि मई 2023 में गैर-जनजातीय मैतेई (Meitei) समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की कार्यवाही करने पर मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी. राज्य की नगा तथा कुकी जनजाति सहित अन्य दर्जा प्राप्त जनजातियाँ मणिपुर में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही हैं.

अनुसुईया समिति

10 जून, 2023 को केन्द्र सरकार ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया. समिति में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जाति समूह के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं. समिति के गठन का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है.

यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व केन्द्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जाँच हेतु गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्बा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था.

गीता मित्तल समिति

7 अगस्त, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की समिति गठित की. समिति का अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को बनाया

STUDYPDF WALLAH

गया. दो अन्य महिला न्यायाधीशों में शालिनी पी. जोशी व आशा मेनन शामिल हैं.

कोविंद समिति

'एक देश-एक चुनाव' की धारणा की सम्भावनाएं तलाशने तथा इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन केन्द्र सरकार ने 2 सितम्बर, 2023 को किया. समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है. समिति की पहली औपचारिक बैठक 23 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एक देश एक चुनाव की सम्भावनाओं पर विचार के लिए यह समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा कर, उन विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिनकी एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यकता होगी.

समझौते/सम्बन्ध/विदेश नीति

भारत-रोमानिया

अप्रैल 2023 में रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारू ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए. रोमानिया और भारत पहले से ही संयुक्त राष्ट्र मिशन जैसे बहुराष्ट्रीय वातावरण में सहयोग कर चुके हैं, जिसने स्थिरता को बढ़ावा देने और शांति व सुरक्षा को मजबूत करने में दोनों देशों के संयुक्त योगदान को प्रकट किया.

भारत-थाइलैण्ड

20-21 अप्रैल, 2023 के दौरान बैंकॉक में भारत के रक्षा मंत्रालय व थाइलैण्ड के रक्षा मंत्रालय के मध्य रक्षा संवाद की 8वीं बैठक सम्पन्न हुई. बैठक का उद्देश्य भारत व थाइलैण्ड के मध्य रक्षा सहयोग की समीक्षा करना और द्विपक्षीय बैठकों को सशक्त करने के लिए नई पहल की खोज करना है. भारत व थाइलैण्ड के बीच रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग काफी विस्तृत हो गया है.

भारत-मालदीव

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1-3 मई, 2023 के दौरान अपनी मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित दो युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय बल (MNDF) को सौंपे. इनमें एक तेज गश्ती पोत (Fast Patrol Vessel) व एक अन्य लैण्डिंग क्रॉफ्ट आक्रमण पोत (Landing Craft Assault Ship) हैं.

भारत-बांग्लादेश

23 मई, 2023 को भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स अनुदान सहायता के तहत् सौंपे. इसे नई दिल्ली से बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया. बांग्लादेश को यह इंजन सौंपने की बात अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के समय भारत की ओर से कही गई थी. इससे पूर्व जून 2020 में भारत सरकार ने अनुदान के रूप में बांग्लादेश को 10 इंजन प्रदान किए थे.

- वर्तमान में भारत व बांग्लादेश के बीच 3 जोड़ी रेलगाड़ियाँ कोलकाता-ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता-खुलना बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका मिताली एक्सप्रेस चल रही है.
- रेल मंत्रालय की 23 मई, 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों के बीच लगभग 100 मालगाड़ियाँ चल रही हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2·66 मीट्रिक टन माल बांग्लादेश भेजा गया था.

भारत-अमरीका-ब्राजील

पेट्रोल व डीजल के प्रयोग से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उद्देश्य से जैव ईंधन (Biofuel) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GBA–Global Biofuel Alliance) नामक गठबन्धन की शुरूआत भारत द्वारा अमरीका व ब्राजील आदि देशों के साथ मिलकर सितम्बर 2023 में ही की गई है. इसके लिए सहयोगी देशों की पहली बैठक 9 सितम्बर, 2023 को जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित की गई थी.

राष्ट्रीय क्षतियाँ/निधन

शरद यादव

12 जनवरी, 2023 को गुरुग्राम में जनता दल (यू) के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया. वह 75 वर्ष के थे. वह जनता दल (यू) की स्थापना (2013) से 2016 तक इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे. शरद यादव ने नीतीश कुमार के साथ मतभेद बढ़ने पर इस पार्टी को छोड़कर 2019 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे. इस बीच लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी पार्टी का गठन भी उन्होंने किया था. बिहार की राजनीति में विशेष प्रभाव रखने वाले शरद यादव की गणना प्रमुख समाजवादी नेताओं में होती थी. वह 7 बार लोक सभा के लिए व 3 बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे. केन्द्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी वह रहे थे.

मंदीप रॉय

29 जनवरी, 2023 को बेंगलूरू में कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मंदीप रॉय का निधन हो गया. वह 74 वर्ष के थे. थियेटर से अपना कॅरियर शुरू करके 500 से अधिक फिल्मों में भूमिकाएं उन्होंने निभाई थीं.

के. विश्वनाथ

2 फरवरी, 2023 को हैदराबाद में दक्षिण भारत के जाने-माने फिल्म निर्माता के. विश्वनाथ का निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. कला तपस्वी के नाम से लोकप्रिय के. विश्वनाथ ने तमिल, तेलुगु व हिन्दी में लगभग 50 फिल्मों का निर्माण किया था. 2016 में उन्हें सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

जावेद खान अमरोही

14 फरवरी, 2023 को मुम्बई में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हो गया. वह 70 वर्ष के थे. 100 से अधिक हिन्दी फिल्मों में भूमिकाएं निभाने के अतिरिक्त छोटे पर्दे पर भी अभिनय की छाप उन्होंने छोड़ी थी. फिल्म लगान में रामसिंह के किरदार में विशेष प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी.

नंदमुरी तारक रत्न

18 फरवरी, 2023 को बेंगलूरू के एक अस्पताल में तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता नंदमुरी तारक रत्न का निधन हो गया. वह 39 वर्ष के थे. राजनीति में भी सक्रिय रहे तारक रत्न को कुछ दिन पूर्व एक पद यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, तभी से वह कोमा में थे.

सतीश कौशिक

9 मार्च, 2023 को नई दिल्ली बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता-निर्देशक, पटकथा लेखक सतीश कौशिक का निधन हो गया. वह 66 वर्ष के थे. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्र रहे सतीश कौशिक ने 'गॉड तुसी ग्रेट हो', 'हम किसी से कम नहीं', 'हसीना मान जाएगी', 'परदेशी बाबू', 'अंदाज', 'विषकन्या', 'वो सात दिन', 'मासूम', 'मिस्टर इंडिया' जैसी सुपरहिट फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई थीं.

सलीम दुर्रानी

2 अप्रैल, 2023 को चर्चित क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का निधन हो गया. वह 88 वर्ष के थे. सलीम दुर्रानी के निधन के साथ ही क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया. सुलीम दुर्रानी दर्शकों की माँग पर छक्के मारने वाले महान् क्रिकेटर थे. सलीम दुर्रानी ने 1960 से 1973 के मध्य 29 टेस्ट मैच खेले थे. सलीम दुर्रानी का जन्म काबुल में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला. साठ व सत्तर के दशक में क्रिकेट के मैदान में दर्शक दुर्रानी से

STUDYPDF WALLAH

छक्के की माँग करते थे और दुर्रानी ने कभी भी दर्शकों का दिल नहीं तोड़ा. वेस्टइंडीज के 1971 के दौरे पर अपनी पदार्पण सीरीज में 774 रन बनाकर गावस्कर ने भारतीय टीम को कैरिबियाई सरजमीं पर टेस्ट सीरीज में पहली जीत दिलाई. इस विजय का श्रेय दुर्रानी को जाता है, जिन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में एक ही स्पैल में क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स का विकेट लिया था. दुर्रानी ने साठ के दशक में आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने क्रिकेट कॅरियर की शुरूआत में मुम्बई में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के साथ किया था. इन्होंने अपनी अंतिम टेस्ट इंगलैण्ड के खिलाफ फरवरी 1973 में मुम्बई के ब्रेबोर्न स्टेडियम पर ही खेला था. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने गुजरात, राजस्थान और सौराष्ट्र के लिए खेला था.

सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे. उन्हें यह पुरस्कार 1961 में देने की घोषणा की गई थी, परन्तु दुर्रानी इसे लेना भूल गए थे. 47 वर्ष बाद उन्हें 2008 में यह सम्मान एक समारोह में दिया गया था. सलीम दुर्रानी ने फिल्मों में भी कार्य किया. सलीम ने 1973 में हिन्दी फिल्म 'चरित्र' में परवीन बॉबी के साथ काम किया था.

प्रकाश सिंह बादल

25 अप्रैल, 2023 को मोहाली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया. वह 95 वर्ष के थे. 1970 से 2017 के दौरान विभिन्न अवधि में वह 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे. वह मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 में कुछ समय तक केन्द्रीय कृषि मंत्री रहे थे. भारत सरकार ने वर्ष 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, किन्तु 2020-21 के किसान आन्दोलन के समर्थन में अपना यह सम्मान 3 दिसम्बर, 2020 को उन्होंने लौटा दिया था. वर्ष 1970 में पहली बार जब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने थे, उस समय सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया था. बाद में 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी, उस समय सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया था.

कौर सिंह

27 अप्रैल, 2023 को बीते वर्षों के जाने-माने भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज कौर सिंह का निधन हो गया. वह 74 वर्ष के थे. सेना में रहते हुए 1971 में भारत-पाक युद्ध में बहादुरी के लिए सेना पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था. सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने के पश्चात् 1980 में मुम्बई में एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में तथा 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों में हैवीवेट मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था. 1982 में अर्जुन पुरस्कार व 1983 में पद्मश्री से सम्मानित कौर सिंह ने 1984 में लॉस एंजेल्स ओलम्पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. 1980 में दिल्ली में एक प्रदर्शन मुकाबले में हैवीवेट मुक्केबाजी के विश्व चैम्पियन मोहम्मद अली के विरुद्ध खेलने का अवसर भी कौर सिंह को प्राप्त हुआ था.

जैमिनी शंकरन

23 अप्रैल, 2023 को कन्नूर में भारतीय सर्कस के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्कस कलाकार जैमिनी शंकरन का निधन हो गया. वह 99 वर्ष के थे. एक सर्कस कलाकार के रूप में कॅरियर की शुरूआत करने वाले जैमिनी शंकरन बाद में जैमिनी सर्कस व जम्बो सर्कस के मालिक बने.

समरेश मजूमदार

8 मई, 2023 को प्रसिद्ध बांग्ला लेखक समरेश मजूमदार का निधन हो गया. उनकी चर्चित कृतियों में 'दौर', 'कालपुरुष', 'दिन जाए रात जाए', 'काल बेला' आदि प्रमुख हैं. समरेश मजूमदार को वर्ष 1984 में 'काल बेला' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वर्ष 2018 में इन्हें 'बंग भूषण' पुरस्कार तथा 'बंकिम पुरस्कार' से पुरस्कृत किया गया था.

बालू धानोरकर

30 मई, 2023 को महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर का निधन हो गया. वह 48 वर्ष के थे. महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोक सभा सीट से निर्वाचित सांसद बालू धानोरकर का कुछ दिन पूर्व ही किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया गया था.

मंगल ढिल्लों

11 जून, 2023 को लुधियाना में अस्सी व नब्बे के दशक के लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों बुनियाद व जुनून से प्रसिद्ध हुए अभिनेता मंगल ढिल्लों का निधन हो गया. वह 64 वर्ष के थे तथा कैंसर से पीड़ित थे. ढिल्लों अपने कॅरियर में 'खून भरी माँग', 'विश्वात्मा' जैसी फिल्मों में भी काम किया था.

के.एम. वासुदेवन नंबूदिरी

7 जुलाई, 2023 को कोट्टकल में केरल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कला निर्देशक के. एम. वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हो गया. वह 98 वर्ष के थे. वह केरल ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष रहे थे तथा राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित थे.

डॉ. मंगला नार्लिकर

17 जुलाई, 2023 को पुणे में प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. मंगला नार्लिकर का निधन हो गया. वह 80 वर्ष की थीं. गणित की अनेक पुस्तकों की रचयिता प्रो. मंगला नार्लिकर पुणे यूनीवर्सिटी में अध्यापन से पूर्व इंगलैण्ड में कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी से भी सम्बद्ध रही थीं. वह प्रसिद्ध खगोलविद् प्रो. जयंत नार्लिकर की पत्नी थीं.

ओमान चांडी

18 जुलाई, 2023 को बेंगलूरू में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व केरल के पूर्व ओमान चांडी का निधन हो गया. वह 79 वर्ष के थे. वह 2004-06 तथा 2011-16 के दौरान केरल के मुख्यमंत्री रहे थे. उनके निधन पर केरल सरकार ने 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश व 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया.

बिंदेश्वरी पाठक

15 अगस्त, 2023 को सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया. वह 80 वर्ष के थे. बिहार के वैशाली जिले में जन्मे बिंदेश्वरी पाठक ने अपना पूरा जीवन स्वच्छता अभियान को समर्पित किया. 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल की नींव उन्होंने रखी थी. बिंदेश्वरी पाठक ने 'द टायलेट मैन ऑफ इंडिया' के नाम से ख्याति अर्जित की थी.

डॉ. सी. आर. राव

22 अगस्त, 2023 को अमरीका के बफेलो में प्रतिष्ठित गणितज्ञ एवं साख्यिकीविद् डॉ. सी. आर. राव का निधन हो गया. वह 102 वर्ष के थे. वर्ष 2023 में ही उन्हें स्टैटिस्टिक्स में अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है, से सम्मानित किया गया था.

सरोजा वैद्यनाथन

21 सितम्बर, 2023 को प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया. वह 86 वर्ष की थीं. वह कर्नाटक संगीत की भी विशेषज्ञ थीं. संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन को वर्ष 2002 में पद्मश्री व 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.

एम.एस. स्वामीनाथन

28 सितम्बर, 2023 को भारत में हरित क्रान्ति के जनक कहे जाने वाले महान् कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया. वह 98 वर्ष के थे. 1960 के दशक में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर गेहूँ के उच्च उत्पादकता वाले मिश्रित बीजों का विकास उन्होंने किया था. वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण व 1989 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था.

STUDYPDF WALLAH

अन्य विविध बहुचर्चित राष्ट्रीय घटनाएं

नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित

28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवनिर्मित व बहुचर्चित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया. इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत् किया गया है. यह 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है तथा इसकी चार मंजिल हैं. इसकी डिजाइन अहमदाबाद के प्रसिद्ध वास्तुकार विमल हसमुख पटेल ने की है. इस नए संसद भवन के निर्माण में ₹ 970 करोड़ का व्यय हुआ है. इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लि. ने किया है. नए संसद भवन में 1,272 सांसदों (888 सीटें लोक सभा कक्ष में व 384 राज्य सभा कक्ष में) के बैठने की क्षमता है. नए संसद भवन को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लोक सभा व राज्य सभा के संयुक्त सत्र के समय दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठ सकते हैं. दर्शक दीर्घा में 336 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है. नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार व 3 उपद्वार हैं.

प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष

भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 वर्ष 2023 में पूरे हुए. इस अवसर पर 9 अप्रैल, 2023 को मैसूर विश्वविद्यालय में **'प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम'** (Commemoration of 50 Years of Project Tiger) आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'अखिल भारतीय बाघ अनुमान (पाँचवाँ चक्र) की सारांश रिपोर्ट जारी की. इस गणना में देश में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई, जबकि 2018 की चौथे चक्र की गणना में यह संख्या 2967 थी. 1 अप्रैल, 1973 को जब प्राजेक्ट टाइगर प्रारम्भ किया गया था, देश में बाघों की कुल संख्या 263 थी, जबकि देश में बाघ अभयारण्यों (Tiger Reserve) की संख्या 9 थी. वर्तमान में देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या 53 है. 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत् अब तक बाघ गणना के 5 चक्र पूरे हुए हैं, जिनमें बाघों की संख्या क्रमशः बढ़ती रही है.

प्रोजेक्ट-चीता का एक वर्ष पूर्ण

पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जानवर चीते के भारत में विलुप्त होने के लगभग 75 वर्ष पश्चात् देश में उनके पुनर्वास के लिए 2022 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता का एक वर्ष 17 सितम्बर, 2023 को पूरा हुआ. इस प्रोजेक्ट के तहत् नामीबिया से लाकर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनों नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जबकि 12 अन्य चीते द. अफ्रीका से लाकर 18 फरवरी, 2023 को कूनों नेशनल पार्क में ही छोड़े गए थे. इनमें से 6 वयस्क चीतों की मृत्यु विगत एक वर्ष में विभिन्न कारणों से हो चुकी है. एक दीर्घकालिक परियोजना होने के नाते द. अफ्रीका/नामीबिया/अन्य अफ्रीकी देशों से 12-14 चीतों को अगले 5 वर्ष तक प्रति वर्ष और उसके पश्चात् आवश्यकता के आधार पर लाया जाएगा.

सेंगोल

नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के अनुक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा उपाध्यक्ष की कुर्सी के निकट सेंगोल (राजदण्ड) को स्थापित किया. इसका सम्बन्ध चोल साम्राज्य से है. हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान हैं. सेंगोल शब्द को तमिल शब्द 'सेम्मई' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'नीतिपरायणता'.

यह अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित किए जाने का प्रतीक है. इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 को तमिलनाडु के थिरूवदुयुराई अधीनम (मठ) से विशेष रूप से आए अधीनमों (पुरोहितों) से ग्रहण किया था. अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समारोह में इस्तेमाल किए जाने के बाद से इसे इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के आनंद भवन संग्रहालय की नेहरू गैलरी में रखा गया था.

राजस्थान में अब 50 जिले

7 अगस्त, 2023 से राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं. राज्य में नए जिलों के गठन की जनता की लम्बे समय से चली आ रही माँग व प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए राम लुभाया समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में 3 नए संभागों (Divisions) व 19 नए जिलों के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधान सभा में 2023-24 के लिए राज्य के बजट पर बहस का उत्तर देते हुए 17 मार्च, 2023 को की थी. नए जिलों के गठन के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमण्डल की 4 अगस्त, 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई. इसके साथ ही नए संभागों व जिलों के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई. सभी नवगठित जिलों की स्थापना 7 अगस्त, 2023 से औपचारिक रूप मानी गई है.

संविधान सदन

19 सितम्बर, 2023 को नया संसद भवन आधिकारिक रूप से देश की नई संसद हो गई. इसी दिन नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरूआत वर्षों से लम्बित महिला आरक्षण विधेयक (128वाँ संविधान संशोधन विधेयक), जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया, प्रस्तुत करके सरकार ने की. इसके साथ ही पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया.

केरलम

9 अगस्त, 2023 को केरल विधान सभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर 'केरलम' करने का केन्द्र से अनुरोध करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया. यह प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया था. इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा-यूडीएफ ने बिना किसी संशोधन या सुझाव दिए स्वीकार कर लिया.

प्रोजेक्ट उद्भव

प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा सैन्य सन्दर्भों में भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल है. रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2023 में प्रारम्भ किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षाशास्त्र का हिस्सा बनाना है.

शांति निकेतन व होयसल के पवित्र मंदिर समूह

पश्चिमी बंगाल स्थित शांति निकेतन तथा कर्नाटक स्थित 'होयसल के पवित्र मंदिर समूह' (The Sacred Ensembles of Hoysalas) को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन—यूनेस्को (The Sacred Ensembles of Hoysalas) की विश्व धरोहर सूची में सितम्बर 2023 में शामिल किया गया. इन्हें मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है. शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में कोलकाता से 180 किमी उत्तर की ओर बीरभूम जिले में स्थित है. यहीं पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रबीन्द्रनाथ टैगोर ने एक सदी पूर्व की थी. होयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था. 'होयसल के पवित्र मंदिर समूह' में बेलूर, हलेबिड तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं.

●●●

STUDYPDF WALLAH

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

विश्व के तनावग्रस्त क्षेत्र/बहुचर्चित प्रकरण/चर्चित मुद्दे

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट-2022

विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर नजर रखने वाली/आकलन करने वाली अमरीका स्थित स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय जर्मन संस्था **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** की वर्ष 2022 की रिपोर्ट 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई. भ्रष्टाचार धारणा/बोध सूचकांक (CPI–Corruption Perceptions Index) के आधार पर जारी इस रिपोर्ट में गत वर्ष की भाँति 180 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किए गए हैं. **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में सर्वोच्च 90 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक **डेनमार्क** का है. इसके बाद 87 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के साथ **फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड** का स्थान दूसरा व तीसरा आकलित किया गया है. इसका अर्थ यह है कि **डेनमार्क, फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड** क्रमशः सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं. वर्ष 2021 की रिपोर्ट में 88 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के साथ **डेनमार्क, फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड** को ही संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्ट देश आकलित किया गया था. इस मामले में सबसे निचले स्थान पर **सोमालिया** का है, जिसके लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 12 (सबसे कम) आकलित है. इसका आशय है सोमालिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है. 13 सूचकांक के साथ **सीरिया व दक्षिण सूडान** संयुक्त रूप से नीचे से दूसरे स्थान पर हैं.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index) 40 आकलित किया गया है तथा **कुल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 85वाँ स्थान दिया गया है.** वर्ष 2020 व 2021 की सूची में भारत के लिए भ्रष्टाचार धारणा/बोध सूचकांक 40 ही था तथा 180 देशों में 86वाँ व 85वाँ स्थान भारत को दिया गया था. इस प्रकार 2022 के लिए भारत के लिए सूचकांक गत वर्ष की भाँति 40 ही रहा है, इसकी वैश्विक रैंकिंग भी यथावत् है.

भारत के पड़ोसी देशों में 25वें व 65वें स्थान के साथ क्रमशः **भूटान व चीन भारत** से बेहतर स्थिति में हैं. पिछले वर्ष चीन 66वें स्थान पर था. चीन की रैंक में एक पायदान का सुधार हुआ है. अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश में स्थिति भारत से भी खराब है. वर्ष 2022 की इस सूची में श्रीलंका 101वाँ, नेपाल 110वें, पाकिस्तान 140वें, बांग्लादेश 147वें, अफगानिस्तान 150वें व म्यांमार 157वें स्थान पर है. इस प्रकार इन देशों में भ्रष्टाचार का स्तर भारत से भी अधिक आकलित किया गया है.

कोरोना : अब वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति नहीं

विश्व के विभिन्न भागों में कोरोना महामारी की शिथिलता के समाचारों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी 5 मई, 2023 को यह घोषणा की कि कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल (Global Health Emergency) नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस ने घोषणा करते हुए यह स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका खतरा अब नहीं है.

डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस ने 5 मई, 2023 को मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि 1,221 दिन पूर्व डब्ल्यूएचओ को चीन के वुहान में अज्ञात कारणों से निमोनिया का पता चला था. इस बीमारी के तेजी से विस्तार के चलते अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत् 30 जनवरी, 2020 को बुलाई गई आपातकालीन समिति की सलाह पर कोरोना को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आपात स्थिति डब्ल्यूएचओ ने घोषित की थी. यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत् उच्चतम स्तर की चेतावनी थी.

कोरोना ने तीन वर्ष की अवधि में पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया. डब्ल्यूएचओ की सूचना के अनुसार इस बीमारी से लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई, परन्तु मौतों की वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक है. कोरोना से लगभग 2 करोड़ मौतों की बात डब्ल्यूएचओ की महानिदेशक ने स्वीकार की है.

ब्रिटेन में सम्राट् चार्ल्स-III का औपचारिक राज्याभिषेक

6 मई, 2023 को लंदन में ब्रिटिश राजघराने की लगभग एक हजार वर्ष पुरानी परम्परानुसार चार्ल्स-III व उनकी पत्नी क्वीन कैमिला का औपचारिक राजतिलक (Coronation) शाही रीति-रिवाज के अनुसार हुआ. यद्यपि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के पश्चात् उनके पुत्र चार्ल्स-III को ब्रिटेन का नया सम्राट् सितम्बर 2022 में ही घोषित कर दिया गया था. ब्रिटेन में लगभग 70 वर्ष के पश्चात् इस प्रकार का समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्रप्रमुखों या उनके प्रतिनिधियों सहित लगभग 2,000 हस्तियाँ आमंत्रित थीं. समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपत्नीक किया. तीन दिन चले इस समारोह में 100 मिलियन पाउंड (लगभग ₹ 1,029 करोड़) के व्यय का अनुमान है.

- इससे पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक 2 जून, 1953 को हुआ था.
- 6 मई, 2023 को सम्पन्न मुख्य समारोह में किंग चार्ल्स-III व क्वीन कैमिला की ताजपोशी खानदानी वेस्टमिंस्टर ऐबे (Westminster Abbey) चर्च में हुई. 1066 ई. में विलियम प्रथम की ताजपोशी के बाद राजघराने की सभी ताजपोशियाँ इसी चर्च में हुई हैं.

सूडान में गृह युद्ध की त्रासदी

सेना द्वारा तख्ता पलटने के पश्चात् अफ्रीकी देश सूडान अब भीषण गृह युद्ध में झुलस रहा है. अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के नेतृत्व वाले सैन्य शासन में साझीदार रहे अर्द्ध-सैन्य बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) ने देश के शासन पर नियंत्रण वाली सेना के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठा लिया है. 15 अप्रैल, 2023 से शुरू हुए इस विद्रोह में एक ओर सत्तारूढ़ नेता अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के नेतृत्व वाली सूडान की सशस्त्र सेना है, तो दूसरी ओर मोहम्मद हमदान दगालो 'हेमेदती' के नेतृत्व वाली अर्द्ध-सैन्य बल आरएसएफ है. विद्रोह से पूर्व हेमेदती' अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के साथ सत्ता में साझीदार रहे थे. दोनों के बीच मतभेदों ने सूडान में गृह युद्ध को जन्म दिया. इस गृह युद्ध से हजारों लोगों को सूडान से पलायन करना पड़ा और अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार 400 से अधिक लोग अपनी जान गवां चुके थे.

सूडान में रह रहे लगभग 3,000 भारतीयों की सुरक्षा व इनकी वहाँ से सुरक्षित निकासी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ-साथ पड़ोसी देश सऊदी अरब की मदद, भारत द्वारा, ली गई थी. इसके लिए ऑपरेशन कावेरी वहाँ संचालित किया गया था, जिसके तहत् बड़ी संख्या में भारतीयों को सूडानी पार्ट से सऊदी अरब के जेद्दाह लाया गया, जहाँ से भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा उन्हें भारत लाया गया.

रूस-यूक्रेन युद्ध के एक वर्ष

24 फरवरी, 2023 को रूस-यूक्रेन युद्ध को एक वर्ष पूरा हो गया. यह युद्ध आज भी जारी है. अद्यतन विश्व की सबसे कष्टकारी व विचलित करने वाला समाचार रूस-यूक्रेन युद्ध

STUDYPDF WALLAH

ही है. रूस और यूक्रेन के मध्य लम्बे समय से चल रहे शीत युद्ध की परिणिति अन्ततः यूक्रेन पर रूस के भीषण आक्रमण में हुई थी. यूक्रेन के पश्चिमी देशों की ओर बढ़ रहा झुकाव तथा 'नाटो' में शामिल होने के इरादे के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी. 21 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन से अलग होने का दावा करने वाले पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों **लुहान्स्क** (Luhansk) व **दोनेस्क** (Donetsk) को अलग गणराज्यों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी. 23 फरवरी, 2022 को ही अमरीका ने अपनी खुफिया रिपोर्टों व उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर रूसी हमले की चेतावनी यूक्रेन को दे दी थी तथा अमरीका एवं उसके सहयोगी राष्ट्रों ने रूस के विरुद्ध अनेक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा भी कर दी थी. इन प्रतिबन्धों की परवाह किए बिना रूस ने पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन पर जल, थल एवं वायु मार्ग से हमले 24 फरवरी, 2022 को किए थे.

गैबॉन में तख्ता पलट

अगस्त 2023 में मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन में सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटते हुए सत्ता पर नियंत्रण कर लिया. गैबॉन की सेना ने सत्ता पर कब्जे की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो ओन्डिम्बा को 30 अगस्त, 2023 को तड़के उस समय गिरफ्तार कर नजरबन्द कर लिया जब 26 अगस्त, 2023 को सम्पन्न चुनावों में उन्हें तीसरी बार पुनर्निर्वाचित घोषित कर दिया गया था तथा 30 अगस्त, 2023 को ही तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार वह सँभालने वाले थे. अफ्रीका के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिने जाने वाले अली बोंगो 2009 से अपने पिता ओमार बोंगो के निधन के बाद से ही वहाँ सत्ता पर कब्जा जमाए हुए थे तथा इनसे पूर्व उनके पिता ने 41 वर्ष तक देश में शासन किया था.

गैबॉन में सत्ता पर कब्जा करते हुए जनरल ब्राइस सी. ओलिगुई नगुएमा ने स्वयं को संक्रमणकालीन राष्ट्रपति घोषित करते हुए रेमंड नडोंग सीमा को अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ घोषित किया.

इजरायल-हमास संघर्ष, 2023

वर्ष 2023 की एक दुःखद घटनाक्रम इजरायल-हमास संघर्ष है. नवीनतम संघर्ष का प्रारम्भ 7 अक्टूबर, 2023 को हमास चरमपंथियों द्वारा इजरायल पर भीषण हमले से हुआ जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया. हमास, फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है, जो गाजा पट्टी से संचालित होता है तथा इसे विभिन्न राष्ट्रों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है.

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/चर्चित संगठन/बैठक

फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो

18-22 जनवरी, 2023 के दौरान स्पेन के मैड्रिड में विश्व की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक FITUR का आयोजन हुआ. देश-विदेश की पर्यटन से सम्बन्धित 10 हजार से अधिक कम्पनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज की. **ग्वाटेमाला** (Guatemala) को इस वर्ष इस प्रदर्शनी में साझेदार देश (Partner Country) का दर्जा दिया गया था. प्रदर्शनी का थीम था—Citizens of the world, We are tourism.

'क्वाड' का शिखर सम्मेलन

20 मई, 2023 को जापान के हिरोशिमा में भारत, अमरीका, जापान व आस्ट्रेलिया के बीच बने चतुर्भुज गठबंधन 'क्वाड' (QUAD–Quadrilateral Security Dialogue) की शिखर बैठक सम्पन्न हुई. यह इस संगठन की 5वीं (भौतिक उपस्थिति वाली तीसरी) शिखर बैठक थी. इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी,** मेजबान जापान के प्रधानमंत्री **फूमिया किशिदा** के अतिरिक्त अमरीकी राष्ट्रपति **जोसेफ बाइडन** व आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री **एंथनी अल्बनीज** व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे.

क्वाड के इस शिखर बैठक में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की सहनीयता (Resilience) व समृद्धि के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की गई. क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क लॉन्च करने, जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने, आपसी सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने, क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे क्वाड बैठक में मुख्यतः शामिल थे. क्वाड की स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं और साझा सकारात्मक दृष्टिकोण को शिखर बैठक में सभी नेताओं ने दुहराया तथा आपसी सहयोग के इन मुद्दों पर नियमित सम्पर्क बनाए रखने और उच्चस्तरीय वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की.

जी-7 का 49वाँ शिखर सम्मेलन

19-21 मई, 2023 के दौरान जापान के हिरोशिमा में विश्व के औद्योगिक रूप से सम्पन्न 7 देशों के समूह जी-7 का 49वाँ शिखर सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा की मेजबानी में सम्पन्न हुआ. इस शिखर सम्मेलन में जी-7 के सदस्य देशों- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमरीका के राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. विशेष आमंत्रियों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डि सिल्वा, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो कोमोरस के राष्ट्रपति अजाली असूमनि, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यिओल व वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह आदि के अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे.

इस शिखर सम्मेलन में चर्चा के विभिन्न मुद्दों में रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सर्वाधिक ज्वलंत था. रूस-यूक्रेन युद्ध के मामले में जी-7 सदस्य देशों ने यूक्रेन के विरुद्ध रूस के अवैध, अनुचित व अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार पुनः दोहराया. सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया है कि समूह के सातों देशों के नेता रूस के अवैध आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए ठोस कदम उठाएंगे. पारस्परिक सहयोग संवर्द्धन के साथ-साथ विकासशील व उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग व सम्बन्धों में सुदृढ़ता लाने पर बल बातचीत में दिया गया.

सुरक्षा परिषद् के स्थायी/अस्थायी सदस्य

15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के लिए पाँच अस्थायी सदस्यों—अल्जीरिया, सियरा लियॉन, दक्षिण कोरिया, गुयाना व स्लोवेनिया का चुनाव 6 जून, 2023 को किया गया. इनका 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी, 2024 से प्रारम्भ होगा तथा 31 दिसम्बर, 2025 तक रहेगा. 2024-25 के लिए चुने गए पाँचों सदस्य पहले भी सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य रह चुके हैं. अल्जीरिया को 3 बार, गुयाना व द. अफ्रीका को 2-2 बार तथा सियरा लियॉन व स्लोवेनिया को 1-1 बार यह अवसर पहले भी मिल चुका है. इसके साथ ही सुरक्षा परिषद् की संरचना अब इस प्रकार हो गई है—

- ***स्थायी सदस्य (5) :*** *अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस व चीन*
- ***अस्थायी सदस्य (10) :***

(1) 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कार्यकाल : *अल्बानिया, ब्राजील (11वीं बार), गैबॉन, घाना व संयुक्त अरब अमीरात*

(2) 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2024 तक कार्यकाल : *जापान (रिकॉर्ड 12वीं बार), ईक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक व स्विट्जरलैण्ड*

(3) 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2025 तक कार्यकाल : *अल्जीरिया, सियरा लियॉन, दक्षिण कोरिया, गुयाना व स्लोवेनिया*

STUDYPDF WALLAH

डेनिस फ्रांसिस : संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष

त्रिनिडाड एवं टुबेगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस (Dennis Francis) संयुक्त राष्ट्र संघ में 12 सितम्बर, 2023 से प्रारम्भ होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 1 जून, 2023 को निर्वाचित हुए. 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वह 78वें अध्यक्ष हैं.

उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष सितम्बर माह में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव आमतौर पर जून माह में होता है. इसके लिए 5 अलग-अलग क्षेत्रों—अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लेटिन व कैरीबियाई तथा पश्चिम यूरोप व अन्य देश से बारी-बारी से चुनाव किया जाता है. इस वर्ष इस पद हेतु ***लैटिन अमरीका व कैरीबियाई*** *क्षेत्र की बारी थी तथा त्रिनिडाड एवं टुबेगो के* ***डेनिस फ्रांसिस*** *इस क्षेत्र से इस पद हेतु अकेले ही उम्मीदवार थे.*

- *संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में अर्जेन्टीना, ईक्वेडोर, नाइजीरिया, चिली व हंगरी ऐसे देश हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर दो बार प्राप्त हुआ है.*
- *विश्व के अधिक शक्तिशाली माने-जाने वाले देशों—अमरीका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन आदि से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि महासभा की अध्यक्षता हेतु नहीं चुना गया है.*
- *सुरक्षा परिषद् के किसी स्थायी सदस्य देश से महासभाध्यक्ष न चुनने की परम्परा रही है.*

भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था, जब ***भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं. वह 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थीं.*** *केवल 4 महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के रूप में अब तक चुना गया है. इनमें भारत की विजयलक्ष्मी पंडित (1953, 8वें सत्र हेतु) के अतिरिक्त लाइबेरिया की* ***एंजी एलिजावेथ ब्रूक्स*** *(1969, 24वें सत्र हेतु), बहरीन की* ***हया राशेद अल-खलीफा*** *(2006, 61वें सत्र हेतु) तथा ईक्वेडोर की मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा (2018, 73वें सत्र हेतु) शामिल हैं.*

संयुक्त राष्ट्र संघ के विगत वार्षिक अधिवेशनों के अध्यक्ष

- ***74वाँ (2019)****—तिजानी मोहम्मद बांडे (Tijani Muhammad Bande) {तंजानिया}—अफ्रीकी क्षेत्र से*
- ***75वाँ (2020)****—वोल्कन बोज़्किर (Volkan Bozkir) {टर्की}—पश्चिमी यूरोप क्षेत्र से*
- ***76वाँ (2021)****—अब्दुल्ला शाहिद (Abdullah Shahid) {मालदीव}—एशिया प्रशांत क्षेत्र से*
- ***77वाँ (2022)****—कसाबा कोरोसी (Csaba Lorosi) {हंगरी}—पूर्वी यूरोपीय देशों के क्षेत्र*

'आसियान' का 43वाँ शिखर सम्मेलन

5-7 सितम्बर, 2023 के दौरान इंडोनेशिया में जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह 'आसियान' (ASEAN–Association of South East Asian Nations) का 43वाँ शिखर सम्मेलन व उससे सम्बन्धित विभिन्न अन्य बैठकें सम्पन्न हुईं. 18वाँ पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ 'आसियान' की शिखर बैठकें तथा आसियान+3 बैठक (चीन, दक्षिण कोरिया व जापान की शिखर बैठक) आदि इन अन्य बैठकों में शामिल थे तथा आसियान के तत्वावधान में होने वाले पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भारत शामिल रहता है. इस समूह का आदर्श वाक्य है—One Vision, One Identity, One Community.

'ब्रिक्स' का 15वाँ शिखर सम्मेलन

22-24 अगस्त, 2023 के दौरान दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में जोहान्सबर्ग में विश्व के 5 देशों के समूह 'ब्रिक्स' (BRICS–Brazil, Russia, India, China and South Africa) का 15वाँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ. पाँचों सदस्य देशों के शासन प्रमुखों—रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डि सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा व भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा इस सम्मेलन में की. इनके अतिरिक्त 67 देशों के नेताओं को भी मेजबान द. अफ्रीका द्वारा आमंत्रित किया गया था.

इस शिखर सम्मेलन का थीम—'ब्रिक्स और अफ्रीका : पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत् विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी था. इस 15वें शिखर सम्मेलन में व्यापार, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, स्वास्थ्य, परम्परागत औषधियों, पर्यावरण आदि के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय मंचों पर ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग आदि के मुद्दे चर्चा के विषयों में शामिल थे. **आगामी 16वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रूस में कज़ान में प्रस्तावित है.**

जी-20 का 18वाँ शिखर सम्मेलन

9-19 सितम्बर, 2023 के दौरान भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-20 का 18वाँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ. यह पहला अवसर था जब जी-20 का शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ. इस शिखर सम्मेलन का थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम' (One Earth, One Family, one Future) था. इस शिखर सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लुला डि सिल्वा, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित विश्व के शीर्षस्थ नेताओं ने भाग लिया.

सम्मेलन की समाप्ति पर साझा घोषणा-पत्र जारी किया गया. भारत की कूटनीतिक प्रयासों से यूक्रेन मुद्दे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि दोनों धुरविरोधी विचारधाराओं को इन पर सन्तोष रहा तथा घोषणा-पत्र के सभी 83 बिन्दुओं को निर्विरोध सभी ने स्वीकार किया. आतंकवाद को अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गम्भीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निन्दा इसमें की गई. जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने तथा ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात जहाँ दिल्ली घोषणा-पत्र में कही गई है वहीं वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे विकासशील देशों के संकट को प्रभावी ढंग से सुलझाने तथा तेज, सस्ते, अधिक पारदर्शी व समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प इसमें लिया गया है.

चुनाव/सत्ता परिवर्तन/सत्ता संघर्ष

साइप्रस

12 फरवरी, 2023 को यूरेशिया के द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस में सम्पन्न राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार **निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स** (Nikos Christodoulides) नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए. निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को 51·9 प्रतिशत तथा इनके प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार मावरो-यियानिस को 48·1 प्रतिशत मत प्राप्त हुए. निवर्तमान राष्ट्रपति निकोस एनास्तासिएड्स, जो लगातार दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे, संवैधानिक प्रावधानों के तहत् तीसरे कार्यकाल के लिए वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते थे.

STUDYPDF WALLAH

चीन

चीन के राष्ट्रपति **शी जिनपिंग** (XI Jinping) लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इस देश के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए. लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु उनका यह चुनाव चीन की संसद 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' (NPC) की बैठक में 10 मार्च, 2023 को हुआ. चीनी संसद एनपीसी की यह बैठक 5-13 मार्च, 2023 के दौरान सम्पन्न हुई. संसद के 2,952 सदस्यों ने निर्विरोध ही उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया. लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले वह चीन के पहले राष्ट्रपति हैं.

नेपाल

नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए 9 मार्च, 2023 को सम्पन्न चुनाव में मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस व 7 अन्य दलों के साझा उम्मीदवार **रामचंद पौडेल** (Ramchandra Poudel) निर्वाचित हुए. इस चुनाव में कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनीफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) के सुभाष चन्द्र नेमवांग को 15,518 के मुकाबले 33,802 चुनावी मतों के अन्तर से उन्होंने पराजित किया. इस पद पर 13 मार्च, 2023 को 78 वर्षीय पैडोल ने बिद्या देवी भंडारी, जो अक्टूबर 2015 से राष्ट्रपति थीं, का स्थान लिया. वह नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं.

बांग्लादेश

23 अप्रैल, 2023 को बांग्लादेश के विगत 10 वर्षों से राष्ट्रपति रहे मोहम्मद अब्दुल हामिद के इस पद पर कार्यकाल की समाप्ति के बाद **शहाबुद्दीन चुप्पू** (Shahabuddin Chuppu) ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की. पूर्व न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता सेनानी शहाबुद्दीन चुप्पू इस पद के लिए सत्तारूढ़ दल की ओर से उम्मीदवार थे. वह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं. बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है.

तुर्किए

मई 2023 में तुर्किए (टर्की) में सम्पन्न राष्ट्रपति चुनाव में **निवर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन** (Recep Tayyip Erdogan) ही इस पद पर पुनर्निवाचित हुए. 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे एर्दोगन 2014 के बाद लगातार राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं. राष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ही 600 सदस्यीय संसद के लिए भी चुनाव 14 मई, 2023 को कराए गए थे. इस चुनाव में एर्दोगन की पार्टी को 267 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि कमाल किलिचदारोग्लू की दूसरी पार्टी CHP की सीटों की संख्या 169 रही.

जिम्बाब्वे

23 अगस्त, 2023 को जिम्बाब्वे में सम्पन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति **एमर्सन मनांगाग्वा** (Emmerson Mnangagwa) ही लगतार दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए. सत्तारूढ़ ZANU PF पार्टी के एमर्सन मनांगाग्वा ने अपने निकटतम उम्मीदवार सिटीजन्स कोलिशन फॉर चेंज (CCC) के नेल्सन चामिसा को पराजित कर इस पद पर कब्जा बरकरार रखा. मनांगाग्वा, जिन्होंने चार दशकों तक सत्ता में रहे रॉबर्ट मुगावे को नवम्बर 2017 के सैन्य तख्ता पलट के पश्चात्, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सँभाला था, को 53 प्रतिशत मत इस चुनाव में प्राप्त हुए, जबकि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार नेल्सन को 44 प्रतिशत मत मिले.

कम्बोडिया

कम्बोडिया के 38 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् सत्ता परिवर्तन अगस्त 2023 में हुआ तथा 1985 से वहाँ प्रधानमंत्री रहे हुन सेन के स्थान पर उनके पुत्र **डॉ. हुन मानेट** वहाँ प्रधानमंत्री 22 अगस्त, 2023 से बने हैं.

सिंगापुर

1 सितम्बर, 2023 को सिंगापुर में सम्पन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय मूल के **थर्मन शनमुगरत्नम** (Tharman Shanmugaratnam) इस पद पर निर्वाचित हुए. देश के नौवें राष्ट्रपति के इस चुनाव में 66 वर्षीय शनमुगरत्नम के अतिरिक्त दो अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. शनमुगरत्नम ने 70·4 प्रतिशत मत प्राप्त करके यह चुनाव जीता. उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में 16 सितम्बर, 2023 को शपथ ग्रहण किया और निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का स्थान लिया. थर्मन शनमुगरत्नम का सिंगापुर के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल 6 वर्ष का होगा.

ईक्वेडोर

15 अक्टूबर, 2023 को **डेनियल नोबोआ** (Daniel Noboa) को ईक्वेडोर का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया. वह इस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं. ईक्वेडोर दक्षिण अमरीका में पश्चिमी तट पर भूमध्य रेखा तक फैला एक देश है. (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि : 25 नवम्बर, 2023).

विज्ञान/प्रौद्योगिकी/अन्तरिक्ष/चिकित्सा

सारा (Sara)

27 अप्रैल, 2023 को सऊदी अरब के एयरलाइन एमिरेट्स ने 'सारा' नाम के विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया. यह सुविधा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियन सेंटर (DIFC) के आईसीडी ब्रुकफील्ड प्लेस में प्रारम्भ की गई है. 'सारा' स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी. यात्रियों की जाँच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी.'सारा' के साथ यात्री अपनी उड़ान से 24 घंटे पहले और 4 घंटे पहले तक अपना सामान चेक इन और ड्रॉप कर सकते हैं.

एच-3 रॉकेट

जापानी अंतरिक्ष एजेंसी (JAXA–Papan Aerospace Exploration Agency) को एक बड़ा झटका मार्च 2023 में उस समय लगा, जब उसका एक नया रॉकेट पहली ही उड़ान में विफल हो गया. इस मीडियम-लिफ्ट रॉकेट एच-3 का विकास जापानी एजेंसी द्वारा तीन दशकों में किया गया था.

नेक्स्ट सैट-2

25 मई, 2023 को दक्षिण कोरिया ने नेक्स्ट सैट-2 (NEXT Sat 2) माइक्रो सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया. इसका प्रक्षेपण स्वदेशी रॉकेट नूरी (KSLV-2) के माध्यम से किया गया. यह नूरी (KSLV-2) का तीसरा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण था. नेक्स्ट सैट-2 का वजन 200 टन तथा लम्बाई 47·2 मीटर है.

पनडुब्बी टाइटन

जून 2023 में पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गया था, जो बाद में विस्फोट होने के कारण सभी 5 यात्रियों सहित नष्ट हो गया. 18 जून, 2023 को टाइटन पनडुब्बी में धमाका होने से हादसा हो गया था, जिसके बाद हादसे की जाँच में अमरीका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के जाँचकर्ता मिलकर काम कर रहे थे. यह भी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक टाइटैनिक के डूबने के स्थल से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र तल पर पनडुब्बी टाइटन के 5 बड़े टुकड़े मिले हैं.

लूना-25

11 अगस्त, 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस (Roscosmos) ने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए लूना-25 (Luna-25) का प्रक्षेपण किया था. इसके मूल कार्यक्रम के तहत् चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 21 अगस्त, 2023 को होनी थी. सोयुज 2·1 बी रॉकेट के जरिए रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना ग्लोब मिशन के तहत् किया गया यह प्रक्षेपण विफल रहा. चन्द्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले ऑर्बिट बदलते समय असामान्य स्थिति में आ जाने के कारण यह ठीक ढंग से ऑर्बिट नहीं बदल सका तथा चन्द्रमा की सतह से टकराकर यह नष्ट हो गया.

STUDYPDF WALLAH

विभिन्न देशों की विशिष्ट गतिविधियाँ

चीन

- **वर्ष 2023 : चीन में 'खरगोश का वर्ष'** : चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के आधार पर लगातार 12 वर्षों का नामकरण अलग-अलग जानवरों के नाम के आधार पर होता है. इसी श्रृंखला में 1 फरवरी, 2022 से 'चीते का वर्ष' (Year of the Tiger) वहाँ शुरू हुआ था, जो 21 जनवरी, 2023 को समाप्त हुआ. उसके पश्चात् 22 जनवरी, 2023 से वहाँ 'खरगोश का वर्ष' (Year of the Water Rabbits) वहाँ शुरू हुआ, जो 9 फरवरी, 2024 तक रहेगा.

जर्मनी

- **अन्तिम तीन परमाणु संयंत्र भी बन्द**—जर्मनी ने अपने तीनों अन्तिम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन 15 अप्रैल, 2023 से बन्द कर दिया. इसके साथ ही विगत 6 दशकों से भी अधिक समय तक चले परमाणु युग का वहाँ अन्त हो गया. वर्ष 2011 में जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के कारण हवा में विकिरण फैलने की आशंकाओं ने सम्पूर्ण विश्व को भयभीत कर दिया था. उस दुर्घटना के बाद ही जर्मनी ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संस्थानों को बन्द करने का निश्चय कर लिया था.

फिनलैण्ड

- **नाटो का 31वाँ सदस्य**—अप्रैल 2023 में रूस की सीमा से सटा नॉर्डिक देश फिनलैण्ड नाटो (NATO) का 31वाँ सदस्य बना. फिनलैण्ड को नाटो की सदस्यता की घोषणा 3 अप्रैल, 2023 को नाटो के महासचिव जेन्स स्टोनटेनबर्ग ने की और 4 अप्रैल, 2023 को नाटो की सदस्यता की औपचारिकताएं पूर्ण की गई. सोवियत संघ काल में अमरीका व सोवियत रूस के बीच तटस्थता की नीति पर रहे फिनलैण्ड व स्वीडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के पश्चात् सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन मई 2022 में किया था.
  4 अप्रैल, 1949 को स्थापित 'नाटो' यूरोप व उत्तरी अमरीकी देशों का एक राजनीतिक व सैन्य गठबंधन है. अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि देश इसके सदस्यों में शामिल हैं.
- **हज कोटा सऊदी अरब को**—मई 2023 में 75 वर्ष में पहली बार पाकिस्तान ने अपना हज कोटा सऊदी अरब को प्रदान करने का निर्णय लिया. ऐसा करने वाले दुनिया के कुछ देशों में से एक बन गया है. यह कदम देश में बढ़ती महँगाई के कारण उठाया गया, जिसके कारण हजारों पाकिस्तानियों ने इस वर्ष तीर्थ यात्रा छोड़ दी है. पाकिस्तान ने कुल मिलाकर 8,000 अप्रयुक्त सीटों को वापस किया, जिससे लगभग 24 मिलियन डॉलर की बचत होगी.
- **संसद भंग/कार्यवाहक प्रधानमंत्री**—पाकिस्तान में नए संसदीय चुनावों का समय आने पर प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेम्बली को उसका कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पूर्व ही 9 अगस्त, 2023 को भंग कर दिया था. 12 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवर-उल-हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया.

पुर्तगाल

- **इच्छामृत्यु वैध**—मई 2023 में पुर्तगाल ने एक कानून पारित किया है, जो इच्छामृत्यु को वैध बनाता है. ऐसा करने वाला वह दुनिया के कतिपय देशों में एक हो गया है. नए कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मरने में सहायता का अनुरोध करने के पात्र हैं. कानून निर्दिष्ट करता है कि यह केवल स्थायी और असहनीय दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए ही है.

सिंगापुर

- **19 वर्ष के अन्तराल पर किसी महिला अपराधी को फाँसी**—28 जुलाई, 2023 को सिंगापुर में 19 वर्ष के अन्तराल के बाद एक महिला अपराधी को फाँसी पर चढ़ा दिया गया. 45 वर्षीय सारी देवी जमानी को 31 ग्राम हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था तथा उसके लिए 2018 में उसे मृत्युदण्ड सुनाया गया था. सिंगापुर के कानूनों में 15 ग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी करने वालों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान है. पुरुषों को फाँसी पर चढ़ाने के मामले वहाँ होते रहे हैं, किन्तु किसी महिला को फाँसी पर चढ़ाए जाने का मामला 19 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् वहाँ हुआ. सारी देवी जमानी से पूर्व 2004 में 36 वर्षीय एक महिला अपराधी को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में ही फाँसी पर चढ़ाया गया था.

अन्तर्राष्ट्रीय क्षतियाँ/निधन

परवेज़ मुशर्रफ

5 फरवरी, 2023 को दुबई में पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह व पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का निधन हो गया. वह 79 वर्ष के थे. निधन के पश्चात् परवेज़ मुशर्रफ का पार्थिव शरीर पाकिस्तान लाया गया जहाँ बिना किसी राजकीय सम्मान के कराची में उन्हें दफनाया गया. परवेज़ मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त, 1943 को दिल्ली में हुआ था, किन्तु स्वतंत्रता के समय उनका परिवार पाकिस्तान जा बसा था. अक्टूबर 1998 में पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार सँभालने के पश्चात् मई-जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध के खलनायक रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस युद्ध में पराजय का ठीकरा तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ पर फोड़ते हुए उनकी सरकार का तख्ता 1999 में पलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था. बाद में 2008 तक राष्ट्रपति के रूप में सत्ता पर कब्जा उन्होंने जारी रखा. राष्ट्रपति रहते हुए 3 नवम्बर, 2007 को संविधान को निलम्बित करने का आरोप इन पर 30 मार्च, 2014 को लगाया गया था. राजद्रोह के इस मामले में एक विशेष अदालत ने मौत की सजा उन्हें 17 दिसम्बर, 2019 को सुनाई थी, किन्तु उससे पूर्व ही मार्च 2016 में इलाज के लिए वह दुबई चले गए थे, जहाँ से वह स्वदेश नहीं लौटे. इस बीच अदालत ने उन्हें भगोड़ा भी करार दिया था.

तारिक फतेह

24 अपैल, 2023 को पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक एवं स्तम्भकार तारिक फतेह का निधन हो गया. वह 73 वर्ष के थे. भारत के प्रति अपने उदारवादी रुख के चलते वह काफी लोकप्रिय थे. पाकिस्तानी परम्पराओं एवं व्यवस्थाओं के वह कड़े आलोचक थे. वह अपने आप को पाकिस्तान में पैदा हुआ भारतीय तथा इस्लाम में पैदा हुआ एक पंजाबी कहते थे.

रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर
(Robert E. Lucas Jr)

15 मई, 2023 को प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर का निधन हो गया. उन्हें वर्ष 1995 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

सिल्वियो बर्लुस्कोनी
(Silvio Berlusconi)

12 जून, 2023 को मिलान के एक अस्पताल में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बुर्लस्कोनी का निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. 1994–2011 के दौरान कई बार इटली के प्रधानमंत्री रहे बुर्लस्कोनी की गणना विश्व के सबसे धनी नेता के रूप में की जाती है.

STUDYPDF WALLAH

राजनीति में आने से पूर्व वह मीडिया टायकून रहे थे.

येवगेनी विक्टारोविच प्रिगोझिन (Yevgeny Viktorovich Prigozhin)

23 अगस्त, 2023 को पूर्व वर्षों में रूसी राष्ट्रपति के घनिष्ठ समर्थक एवं विश्वासपात्र रहे येवगेनी विक्टारोविच प्रिगोझिन का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. वह 62 वर्ष के थे. वह एक प्राइवेट मिलिट्री कम्पनी वैगनर के प्रमुख थे. यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध में वैगनर के लड़ाकुओं ने रूसी सेना का साथ दिया था. 2022 में यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध में, वैगनर की निजी सेना का बड़ा योगदान रहा था, किन्तु बाद में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मतभेद होने पर जून 2023 में वैगनर समूह ने पुतिन के विरुद्ध, विद्रोह कर दिया था. उस समय विद्रोह शांत हो गया था, परन्तु प्रिगोझिन को बेलारूस निर्वासित कर दिया गया था.

हीथ हील्टन स्ट्रीक (Heath Hilton Streak)

3 सितम्बर, 2023 को हरारे में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीथ का निधन हो गया. वह 49 वर्ष के थे. स्ट्रीथ ने 1993 से 2005 के दौरान जिम्बाब्वे की ओर से 65 टेस्ट मैच व 189 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेले थे. जिम्बाब्वे की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 216 तथा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 239 विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके ही नाम दर्ज है.

विविध अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं

अर्थ ऑवर 2023

वर्ष 2023 का अर्थ ऑवर 25 मार्च, 2023 को विश्वभर में मनाया गया. अपने ग्रह पृथ्वी (Earth) की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए **वर्ल्ड वाइड फण्ड (WWF) फॉर नेचर की पहल पर 'अर्थ ऑवर'** (Earth Hour) प्रति वर्ष मार्च के किसी शनिवार, प्रायः अन्तिम शनिवार, को स्थानीय समयानुसार रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे के दौरान मनाया जाता है. इसके तहत् स्थानीय समयानुसार रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे तक सभी अनावश्यक बत्तियाँ बन्द रखा जाता है. वर्ल्ड वाइड फण्ड (WWF) फॉर नेचर द्वारा अर्थ ऑवर की शुरूआत सर्वप्रथम 2007 से आस्ट्रेलिया में सिडनी में की गई थी. इस वर्ष 2023 में अर्थ ऑवर का लगातार 17वाँ आयोजन था तथा भारत सहित विश्व के अधिकांश देश इस वर्ष 25 मार्च, 2022 को इसमें शामिल थे.

- **वर्ष 2019 में अर्थ ऑवर**–30 मार्च, 2019
- **वर्ष 2020 में अर्थ ऑवर**–28 मार्च, 2020
- **वर्ष 2021 में अर्थ ऑवर**–27 मार्च, 2021
- **वर्ष 2022 में अर्थ ऑवर**–26 मार्च, 2022
- **वर्ष 2023 में अर्थ ऑवर**–25 मार्च, 2023

अर्थ ओवरशूट डे (Earth Over Shoot Day)

वर्ष 2022 में 'अर्थ ओवर शूट डे' 2 अगस्त, 2023 को मनाया गया. अर्थ ओवर शूट डे (EOD–Earth Over Shoot Day) से तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष में उस तिथि से है, जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए आवंटित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है. वर्ष 2023 के 'अर्थ ओवरशूट डे' को 2 अगस्त, 2023 होने से तात्पर्य यह है कि पूरे कैलेण्डर वर्ष (जनवरी-दिसम्बर) में जितने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन विश्व को करना चाहिए था, वह वर्ष के पहले 8 महीनों (1 जनवरी-2 अगस्त, 2023 तक) में ही किया जा चुका था.

पूर्व वर्षों में अर्थ ओवरशूट डे दिवस	
2014	*19 अगस्त*
2015	*13 अगस्त*
2016	*8 अगस्त*
2017	*2 अगस्त*
2018	*1 अगस्त*
2019	*29 जुलाई*
2020	*22 अगस्त*
2021	*29 जुलाई*
2022	*28 जुलाई*

☞ *1987 में पहला अर्थ ओवर शूट डे 19 दिसम्बर को मनाया गया था.*

●●●

शेष पृष्ठ 50 का

पहचान सकते हैं और अपने पास मौजूद समय के अनुसार तैयारी की गति को समायोजित कर सकते हैं.

आप अपनी सीखने की विशिष्ट-शैली को जारी रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. आत्म-अनुशासन जरूरी है. इसमें छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और समय सीमा के भीतर इसे हासिल करने की दिशा में काम करना शामिल है. आप त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक और यहाँ तक कि दैनिक योजनाएं भी बना सकते हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं.

आपको समसामयिक मामलों के मोर्चे पर विशेष निगरानी रखनी होगी और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और मुद्दों के बारे में नवीनतम जानकारी से अवगत रहना होगा. पुनरीक्षण और नियमित अभ्यास आवश्यक है और साथ ही उत्तरों का मूल्यांकन आवश्यक है.

तैयारी के दौरान किसी प्रकार की निराशा से बचने के लिए आपको सकारात्मक रहना होगा, लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा और आत्म-प्रेरित होना होगा. यहाँ तक कि अगर आप किसी समय कुछ संशय या नकारात्मकता का अनुभव हो तो आपको एक सहायता प्रणाली की आवश्यकता है–ऐसे में आपका परिवार और दोस्त आपके आस-पास हों जो जरूरत के समय आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ हों.

वैसे भी, तैयारी के लिए यदि किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; यूट्यूब वीडियो, ट्यूटोरियल, सोशल मीडिया पोस्ट और सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल. आप कुछ भी सर्च करें और आपको बहुत सारे विकल्प दिखाए जाते हैं. आप विश्वसनीय स्रोतों से इनका उपयोग कर सकते हैं.

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2023 का परिणाम नजदीक है

मेन्स 2023 का परिणाम दिसम्बर में आने की उम्मीद है और यह सफल उम्मीदवारों को अंतिम सफलता के करीब ले जाएगा. यही वह समय है जब आपको अपने व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी करनी है और साक्षात्कार बोर्ड का सामना करने के लिए तैयार होना होगा.

अगले अंक में, मैं कुछ अंतर्दृष्टि के साथ वापस आऊँगा जो आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी.

यूपीएससी को कभी भी अबूझ पहेली के रूप में न देखें; यह नहीं है

हर वर्ष आप जैसे आम उम्मीदवार अपना मिशन पूरा करके यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं.

विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर चाहे आप कितने भी निराश क्यों न हो जाएं; कभी भी हार न मानें. अभी जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें परिणाम बदलने की ताकत है और यह आपका भाग्य बदल सकता है. आपको खूब पढ़ना, दोहराना और अभ्यास करना होगा.

क्या मुझे आपको प्रारंभिक परीक्षा में आपके परिणाम का परिणाम फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है; यहाँ सफलता आशाओं को जीवित रखेगी और असफलता आपके प्रयास को बर्बाद कर सकती है. जब यह सब शुद्ध प्रदर्शन के बारे में है, तो आपकी अध्ययन-योजना और आपकी कार्य-योजना ऐसी होनी चाहिए, जो आपको दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे.

आप सफल होना चाहते हैं; लेकिन जब तक आप अपने लिए निर्धारित लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा.

तो, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबद्ध रहें !

सफलता आपकी ही हो, ऐसी शुभकामनाओं सहित!

●●●

STUDYPDF WALLAH

आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

राष्ट्रीय आय

2022-23 में देश की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में एनएसओ के अनंतिम अनुमान

2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) व राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनंतिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा 31 मई, 2023 को जारी किए गए. वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी पहले अग्रिम अनुमान 7 जनवरी, 2023 को तथा दूसरे अग्रिम अनुमान 28 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए गए थे.

- चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी में वृद्धि 7·2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.
- अंतिम आकलन में वर्ष 2022-23 में जीडीपी में 7·2 प्रतिशत की वृद्धि रही, जबकि 2021-22 में 9·1 प्रतिशत की वृद्धि इसमें प्राप्त की गई थी.
- एनएसओ के आँकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर (2011-12 के मूल्य स्तर पर) 2022-23 में सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA—Gross Value Addition) में वृद्धि 7·0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है. पूर्व वर्ष 2021-22 में जीवीए में 8·8 प्रतिशत की वृद्धि रही थी.

2021-22 व 2022-23 की राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित प्रमुख आँकड़े एक दृष्टि में (₹ लाख करोड़ में)

	2021-22 (28 फरवरी, 2023 के पहले संशोधित आकलन)	2022-23 (31 मई, 2023 के अनंतिम आकलन)
2011-12 के स्थिर मूल्यों पर (At Constant 2011-12 Price)		
● मूल कीमतों पर मूल्यवर्द्धन (GVA at Basic price)	137·98 (8·8)	147·65 (7·0)
● उत्पादन पर निवल कर (Net Taxes on Production)	11·28(12·1)	12·42(10·1)
● सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	149·26 (9.1)	160·06 (7·2)
● शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI)	126.71 (8·6)	136·04 (7.4)
● प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	92,583 (7·6)	98,374 (6·3)
प्रचलित मूल्यों पर (At Current Price)		
● मूल कीमतों पर मूल्यवर्द्धन (GVA at Basic price)	214·39 (17·9)	247·43 (15·4)
● उत्पादन पर निवल कर (Net Taxes on Production)	20·32 (23·8)	24·98 (22·9)
● सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	234·71 (18·4)	272·41 (16·1)
● शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI)	203·27 (18·0)	238·24 (17·2)
● प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1,48,524 (16·9)	1,72,276 (16·0)

नोट–कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं.

विशिष्ट आर्थिक गतिविधियाँ/बजट

कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्रक

- **2022-23 में देश में कृषिगत उत्पादन : चावल, मक्का, दलहन, तिलहन व गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन**

फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश के प्रमुख कृषिगत उपजों के फाइनल अनुमान (Final Estimates) कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए. इन आँकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 329·69 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है. सन्दर्भित वर्ष 2022-23 में गेहूँ, चावल व मक्का सहित खाद्यान्नों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है.

इससे पूर्व वर्ष 2022-23 के कृषिगत उत्पादों के तीसरे अग्रिम अनुमान 25 मई, 2023 को, दूसरे अग्रिम अनुमान 14 फरवरी, 2023 को तथा पहले अग्रिम अनुमान 22 सितम्बर, 2022 को जारी किए गए थे. पहले अग्रिम अनुमान मंत्रालय द्वारा उस समय जारी किए गए थे जब केवल खरीफ उपजों के सम्बन्ध में ही आँकड़े उपलब्ध थे. 14 फरवरी, 2023 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों में रबी एवं खरीफ दोनों ही उपजों के उत्पादन के आँकड़े शामिल थे. इन आँकड़ों में ही संशोधन करके अब फाइनल अनुमान 18 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए हैं. कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसन्धान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है.

फाइनल अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नवत् है–

- **कुल खाद्यान्न**–329·69 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- **चावल**–135·76 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- **गेहूँ**–110·55 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- **पौष्टिक/मोटे अनाज**–57·32 मिलियन टन
- **मक्का**–38·09 मिलियन टन
- **कुल दलहन**–26·06 मिलियन टन
- **अरहर**–3·31 मिलियन टन
- **चना**–12·27 मिलियन टन
- **कुल नौ तिलहन**–41·36 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
- **सोयाबीन**–14·99 मिलियन टन
- **रेपसीड एवं सरसों**–12·64 मिलियन टन
- **मूँगफली**–10·30 मिलियन टन
- **कपास**–336·60 मिलियन गाँठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम)
- **जूट एवं मेस्ता**–93·92 मिलियन गाँठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम)
- **गन्ना**–490·53 मिलियन टन

STUDYPDF WALLAH

● 2022-23 में देश में बागवानी उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित : दूसरे अग्रिम अनुमान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान देश में उत्पादित विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 19 अक्टूबर, 2023 को जारी किए हैं. इसके अनुसार, वर्ष 2022-23 में देश में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 351·92 मिलियन टन होने का अनुमान है. इससे पूर्व पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में बागवानी उत्पादन 350·87 मिलियन टन रहने का अनुमान था. बागवानी उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान 26 जून, 2023 को जारी किए गए थे.

19 अक्टूबर को दूसरे अग्रिम अनुमान जारी करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न के साथ ही बागवानी का भी लगातार रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जो हमारे किसानों की अथक् मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता तथा केन्द्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सद्परिणाम है.

भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	कुल उत्पादन (मिलियन टन)
2021-22	28·04	347·18
2022-23*	28·12	351·92
	(0·29)	(1·37)

नोट—कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शा रहे हैं.
* 19 अक्टूबर, 2023 दूसरे अग्रिम अनुमान

19 अक्टूबर, 2023 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में—

- ❖ वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 351·92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए उत्पादन की तुलना में लगभग 4·74 मिलियन टन (1·37 प्रतिशत) अधिक है.
- ❖ 2021-22 की तुलना में 2022-23 फलों, सब्जियों, बागानी फसलों, फूलों व शहद में उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है.
- ❖ फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 107·51 मिलियन टन की तुलना में 2022-23 में 108·34 मिलियन टन होने का अनुमान है.
- ❖ सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 212·91 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में यह 209·14 मिलियन टन था.
- ❖ बागवानी फसलों (Plantation Crops) का उत्पादन 2021-22 में 15·76 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2022-23 में 16·05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो लगभग 1·78% की वृद्धि है.
- ❖ 2022-23 में आलू का उत्पादन 60·54 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 56·18 मिलियन टन था.

● 2023-24 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

7 जून, 2023 को केन्द्र सरकार ने 2023-24 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs—Minimum Support Prices) की घोषणा की. नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं, ताकि किसानों को उनके उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (All India Weighted Average Cost of Production) का न्यूनतम डेढ़ गुना मूल्य प्राप्त हो सके. इसी परिप्रेक्ष्य में सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी लागत की तुलना में डेढ़ गुना या उससे भी अधिक किए गए हैं. दालों व तिलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों को विशेष लाभप्रद बनाने का प्रयास नए समर्थन मूल्यों में किया गया है. इसके लिए तिल (Sesamum), मूँग, मूँगफली व अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि इस वर्ष की गई है. न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वर्ष सर्वाधिक ₹ 805 प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल के मामले में हुई है जिसे ₹ 7,830 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 8,635 प्रति क्विंटल किया गया है.

उल्लेखनीय है कि कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को उनकी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (All India Weighted Average Cost of Production) का कम-से-कम डेढ़ गुना रखने की घोषणा 2018-19 के केन्द्रीय बजट में की गई थी. इस नीति का अनुपालन 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में किया गया है. उपजों की उत्पादन लागत में सभी भुगतान की गई लागतों यथा—चुकाई गई श्रम लागत (Hired human labour), बैल श्रम/मशीन श्रम, भूमि पट्टा के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक साधनों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों व फार्म भवनों का मूल्यह्रास (depreciation of implement and farm buildings), वर्किंग कैपिटल पर ब्याज, पम्प सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली व अन्य विविध व्ययों के अतिरिक्त पारिवारिक श्रम का आकलित मूल्य (Imputed value of family labour) शामिल है.

खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपज धान (Paddy) की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹ 143-143 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. इससे सामान्य किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2,040 प्रति क्विंटल से बढ़कर ₹ 2,183 प्रति क्विंटल हो गया है. 2023-24 में धान की लागत ₹ 1,455 प्रति क्विंटल आकलित की गई है. इस प्रकार उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 2,183 प्रति क्विंटल) लागत की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है.

- ☞ **'ए' ग्रेड धान** के मामले में यह इतनी ही वृद्धि से यह ₹ 2,060 प्रति क्विंटल से बढ़कर ₹ 2,203 प्रति क्विंटल हो गया है.
- ☞ **अरहर** का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 6,600 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 7,000 प्रति क्विंटल 2023-24 में किया गया है. इस प्रकार इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹ 400 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. नया समर्थन मूल्य इसकी लागत ₹ 4,444 प्रति क्विंटल की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है.
- ☞ **उड़द** का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में ₹ 6,600 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 6,950 प्रति क्विंटल 2023-24 में किया गया है. नया समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 350 प्रति क्विंटल अधिक है. लागत (₹ 4,592 प्रति क्विंटल) की तुलना में यह 51 प्रतिशत अधिक है.
- ☞ **मूँगफली** का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में ₹ 5,850 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 6,377 प्रति क्विंटल 2023-24 में किया गया है. नया समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 527 प्रति क्विंटल अधिक है. लागत (₹ 4,251 प्रति क्विंटल) की तुलना में यह 50 प्रतिशत अधिक है.
- ☞ **मीडियम स्टेपल** (मध्यम रेशा) कपास का समर्थन मूल्य ₹ 540 प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जिससे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 6,620 प्रति क्विंटल हो गया है. लॉग स्टेपल (लम्बा रेशा) वाली कपास के मामले में यह वृद्धि ₹ 640 प्रति क्विंटल की गई है, जिससे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 7,020 प्रति क्विंटल हो गया है.
- ☞ **सोयाबीन** का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022–23 में ₹ 4,300 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2023-24 में ₹ 4,600 प्रति क्विंटल किया गया है. तिल (Sesamum) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 7,830 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 8,685 प्रति क्विंटल किया गया है.

नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल (Maximum per

STUDYPDF WALLAH

cent Return Over Cost) बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2,350 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 2,500 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो इसकी लागत पर 82 प्रतिशत प्रतिफल किसानों को उपलब्ध कराएगा.

विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष 2023-24 की रबी उपजों का विपणन अप्रैल 2024 व उसके बाद ही होगा. 2024-25 में विपणन की जाने वाली (2023-24 की) रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (Minimum Support Prices—MSPs) की घोषणा केन्द्र सरकार ने 19 अक्टूबर, 2023 को की. यह नए समर्थन मूल्यों में गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹ 150 प्रति क्विंटल तथा चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹ 105 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है.

नए समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप ही निर्धारित किए गए हैं **इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्यों को उपजों की लागत से न्यूनतम डेढ़ गुना रखने की नीति का अनुपालन किया गया है.** दलहनों व तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इन फसलों के लिए अपेक्षकृत उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं—

- **विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2,125 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 2,275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. इस प्रकार ₹ 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि गेहूँ के एमएसपी में की गई है.** गेहूँ का यह समर्थन मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर 102 प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को देगा. सरकारी आकलन में 2024-25 में गेहूँ की उत्पादन में गेहूँ की उत्पादन लागत ₹ 1,128 प्रति क्विंटल आकलित की गई है.
- चना (Gram) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 5,335 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर (2024-25 के लिए) ₹ 5,440 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.
- जौ (Barley) की उत्पादन लागत 2024-25 में ₹ 1,158 प्रति क्विंटल आकलित की गई है. इस पर 60 प्रतिशत की प्रतिफल प्रदान करते हुए विपणन वर्ष 2024-25 के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 1,850 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. यह इसके वर्ष 2023-24 के एसएसपी की तुलना में ₹ 115 प्रति क्विंटल अधिक है.

रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य			
उपज	(₹ प्रति क्विंटल)		न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि (₹ प्रति क्विंटल)
	फसल वर्ष/विपणन वर्ष (2022-23/2023-24)	फसल वर्ष/विपणन वर्ष (2023-24/2024-25)	
गेहूँ	2,125	**2,275**	150
जौ	1,735	**1,850**	115
चना	5,335	**5,440**	105
मसूर	6,000	**6,425**	425
रेपसीड एवं सरसों	5,450	**5,650**	200
सैफ्लॉवर	5,650	**5,800**	150
नोट : 2023-24 की रबी उपजों का विपणन वित्तीय वर्ष 2024-25 में होगा.			

- मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 6,000 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 6,425 प्रति क्विंटल किया गया है. **इस प्रकार ₹ 425 प्रति क्विंटल की सर्वोच्च वृद्धि इसमें की गई है.** {यह इसकी लागत (₹ 3,405 प्रति क्विंटल) पर 89 प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्रदान करेगा.}
- कुसुम (Safflower) के न्यूनतम समर्थन में ₹ 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे ₹ 5,650 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 5,800 प्रति क्विंटल किया गया है. इससे लागत पर 52 प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्राप्त हो सकेगा.
- रेपसीड एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को ₹ 5,450 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2024-25 के लिए ₹ 5,650 प्रति क्विंटल किया गया है. इसकी उत्पादन लागत ₹ 2,855 प्रति क्विंटल आकलित की गई है.

इस प्रकार इसके नए समर्थन मूल्य से 98 प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्राप्त हो सकेगा.

2024-25 के लिए नए समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक ₹ 425 प्रति क्विंटल की वृद्धि मसूर (Lentil) तथा ₹ 200 प्रति क्विंटल की वृद्धि रेपसीड/सरसों के मामले में की गई है. चना के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सबसे कम ₹ 105 प्रति क्विंटल की तथा जौ व गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः ₹ 115 व ₹ 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि इस वर्ष की गई है. इसके बावजूद गेहूँ की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक 102 प्रतिशत प्रतिफल किसानों को नए समर्थन मूल्य से प्राप्त होगा.

● जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य

जूट सत्र 2023-24 के लिए 'रॉ जूट' (Raw Jute) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP–Minimum Support Price) की घोषणा सरकार ने 24 मार्च, 2023 को की. टीडी-3 ग्रेड के लिए यह मूल्य ₹ 5,050 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. नया समर्थन मूल्य कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की संस्तुति पर आधारित है तथा यह 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित नीति कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज के अखिल भारतीय औसत भारित लागत (All India Weighted Average Cost of Production) का कम-से-कम 150 प्रतिशत हो, के अनुरूप उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित होता है. 2023-24 सत्र के लिए रॉ जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी लागत पर 63·20 प्रतिशत लाभ प्रदान करेगा.

● चीनी सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)

28 जून, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति (CCEA) की बैठक में 2023-24 के पेराई सत्र (अक्टूबर, 2023-सितम्बर, 2024) के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP—Fair and Remunerative Price) का अनुमोदन किया गया. यह निर्णय कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग (CACP—Commission for Agricultural Costs and Prices) की संस्तुति के आधार पर लिया गया. पेराई सत्र 2023-24 (अक्टूबर, 2023–सितम्बर, 2024) के लिए यह मूल्य ₹ 315 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. पिछले पेराई सत्र 2022-23 के लिए यह ₹ 305 प्रति क्विंटल था. कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग ने 2023-24 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत ₹ 157 प्रति क्विंटल आकलित की थी. पिराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का उपर्युक्त उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 10·25 प्रतिशत रिकवरी वाले गन्ने के लिए निर्धारित किया गया है. इससे अधिक प्रति 0·1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी

STUDYPDF WALLAH

की स्थिति में ₹ 3·07 प्रति क्विंटल अधिक मूल्य देय होगा. 9·5 प्रतिशत से कम रिकवरी वाले गन्ने के मामले में ₹ 3·07 प्रति क्विंटल की कटौती एफआरपी में की जाएगी.

विभिन्न पिराई सत्रों में गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य

पिराई सत्र	मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
2015-16	230
2016-17	230
2017-18	255
2018-19	275
2019-20	275
2020-21	285
2021-22	290
2022-23	305
2023-24	315

☞ केन्द्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है. चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती हैं.

☞ किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में राज्य सरकारें इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती हैं, जिसे राज्य सलाहकारी मूल्य (SAP—State Advisory Price) कहा जाता है.

उद्योग एवं उत्पादन

● कोयला उत्पादन में भारत का रिकॉर्ड

अप्रैल 2023 में भारत ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में उच्चतम कोयला बाहर निकालने का एक नया रिकॉर्ड बनाया. भारत ने अप्रैल 2022 के दौरान 67·20 मिलियन टन की तुलना में 8·67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 73·02 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन किया. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अप्रैल 2023 में 57·57 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया है, जबकि अप्रैल 2022 में 53·47 मिलियन टन कोयला बाहर आया था, जो 7·67 प्रतिशत अधिक है.

☞ **कोयला मंत्रालय की 3 मई, 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार 2018-19 में देश में कोयले का कुल उत्पादन 728·72 मिलियन टन था, जो 2022-23 में 22·6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 893·08 मिलियन टन रहा है.**

अधोरचना क्षेत्रक

● देश में दूरसंचार परिदृश्य

मई 2023 में देश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार उपभोक्ताओं की कुल संख्या व टेलीडेंसिटी आदि के सम्बन्ध में मार्च, 2023 के अन्त तक की स्थिति के विस्तृत आँकड़े दूरसंचार नियामक निकाय 'ट्राई' (TRAI—Telecom Regulatory Authority of India) ने जारी किए. इन आँकड़ों के अनुसार मार्च, 2023 के अन्त में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की **कुल संख्या 117·23 करोड़ थी.** इसमें 114·39 करोड़ कनेक्शन वायरलेस व 2·84 करोड़ उपभोक्ता वायरलाइन टेलीफोन के थे. पूर्व वर्ष में जारी आँकड़ों के अनुसार मार्च, 2022 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 116·69 करोड़ थी. इस प्रकार टेलीफोन कलेक्शनों की संख्या में 54 लाख की वृद्धि 2022-23 में दर्ज की गई है.

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार मार्च, 2023 के अन्त में देश में टेलीडेंसिटी 84·51 प्रतिशत थी. टेलीडेंसिटी से तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से है. 31 मार्च, 2022 को टेलीडेंसिटी 84·88 थी.

'ट्राई' (TRAI) के इन आँकड़ों के अनुसार मार्च, 2023 के अन्त में देश में कुल 117.23 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन में शहरी कनेक्शन की संख्या 65·37 करोड़ थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शनों की संख्या 51·86 करोड़ दर्ज की गई थी. इस प्रकार मार्च, 2023 के अन्त में टेलीडेंसिटी शहरी क्षेत्रों में 133·8 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 57·07 थी. मार्च, 2023 के अन्त में सर्वाधिक टेलीडेंसिटी 273·67 जहाँ दिल्ली में थी, वहीं यह बिहार में न्यूनतम 55·23 थी. इससे पूर्व वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 व 2022 में भी सर्वाधिक टेलीडेंसिटी दिल्ली की और न्यूनतम बिहार की थी. लगातार आठवें वर्ष भी सर्वाधिक टेलीडेंसिटी दिल्ली में तथा सबसे कम टेलीडेंसिटी बिहार में दर्ज की गई है.

भारत में टेलीफोन परिदृश्य : एक दृष्टि में (31 मार्च, 2023 की स्थिति)

	योग
टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या (करोड़ में)	**117·23 करोड़**
शहरी उपभोक्ता	65·37 करोड़
ग्रामीण उपभोक्ता	51·86 करोड़
टेलीडेंसिटी (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या)	**84·51**
शहरी क्षेत्र में	133·08
ग्रामीण क्षेत्र में	57·07
कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत	55·76
ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत	44·24
ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या (करोड़ में)	84·66

मार्च 2023 के अन्त में देश में मोबाइल फोन सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की हिस्सेदारी 9·27 प्रतिशत (बीएसएनएल की 9.06 प्रतिशत तथा एमटीएनएल की 0·21 प्रतिशत) थी, जबकि 90·73 प्रतिशत बाजार निजी कम्पनियों के कब्जे में था. 'ट्राई' के इन आँकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवाप्रदाता कम्पनी मार्च, 2023 में रिलायंस जियो थी, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 37·61 प्रतिशत थी. मार्च, 2022 में 32·42 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल का दूसरा स्थान था. तीसरा स्थान वोडाफोन-आइडिया का था, जिसकी मार्च, 2023 के अन्त में बाजार हिस्सेदारी 20·70 प्रतिशत रही.

'ट्राई' के आँकड़ों के अनुसार मार्च, 2023 के अंत में देश में ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या 78·83 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च, 2023 के अन्त में 83·93 करोड़ हो गई थी.

टेलीफोन सेवा प्रदाता कम्पनियों की बाजार हिस्सेदारी (31 मार्च, 2023 की स्थिति)

क्र. सं.	दूरसंचार कम्पनी का नाम	हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			
		मार्च 2020	मार्च 2021	मार्च 2022	मार्च 2023
1.	रिलायंस जियो	33·47	35·81	35·37	37·61
2.	भारती एयरटेल	28·31	29·84	31·54	32·42
3.	वोडाफोन आइडिया	27·57	24·02	22·83	20·70
4.	बीएसएनएल	10·35	10·05	9·96	9·06
5.	एमटीएनएल	0·29	0·28	0·28	0·21
6.	रिलायंस कम्यूनिकेशन	0·002	0·001	0·003	0·0002
	योग	100	100	100	100

STUDYPDF WALLAH

मुद्रा एवं बैंकिंग

● ₹ 2,000 के नोटों की वापसी

19 मई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 2,000 के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया. यद्यपि यह नोट अब जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन विधि ग्राह्य (Legal Tender) के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे. व्यक्तियों के पास 30 सितम्बर, 2023 तक अपने बैंक खातों में अपने ₹ 2,000 के बैंक नोटों को बदलने या जमा करने का अधिकार है. नवम्बर, 2016 में ₹ 2,000 के बैंक नोटों की शुरूआत ₹ 500 व ₹ 1,000 के नोटों की विधि ग्राह्य स्थिति वापस लिए जाने का विकल्प था. 2018-19 में ₹ 2,000 के बैंक नोटों की छपाई रोक दी गई थी.

● भारत विदेशी मुद्रा भण्डार

जुलाई 2023 के मध्य में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष एक बार पुनः 600 अरब डॉलर का बिन्दु पार कर गए. भारत में आरक्षित मुद्रा कोष जून, 2021 में पहली बार 600 अरब डॉलर के बिन्दु को पार कर गए थे. दिसम्बर, 2021 के अंतिम सप्ताह में 634 अरब डॉलर तक यह जा पहुँचे थे. इन कोषों में बाद में कुछ गिरावट 2022-23 में आई, जिससे मार्च, 2023 के अंत में यह कोष 578·449 अरब डॉलर के ही रह गए थे. मई, 2022 में यह कोष 600 अरब डॉलर से अधिक के हुए थे.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 21 जुलाई, 2023 को जारी ताजा आँकड़ों के अनुसार 14 जुलाई, 2023 को कुल विदेशी मुद्रा कोष 609·022 अरब डॉलर के थे. आरबीआई के आँकड़ों के अनुसार विगत एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा कोष में 124·74 अरब डॉलर की वृद्धि हुई. एक सप्ताह पूर्व 7 जुलाई, 2023 को सप्ताह में विदेशी मुद्रा कोष 596·28 अरब डॉलर के थे.

विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त स्वर्ण कोष, विशेष आहरण अधिकार (SDR-Special Drawing Right) व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि शामिल की जाती है. रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन आँकड़ों के अनुसार देश में कुल 609·022 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियाँ (Foreign Currency Assets) 540·166 अरब डॉलर की थीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 28·604 अरब डॉलर अधिक थी. भारत में कुल 609·022 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा कोष में स्वर्ण कोष 45·197 अरब डॉलर के थे. एसडीआर 18·484 अरब डॉलर के तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि (Reserve With IMF) 5·175 अरब डॉलर की थी.

भारत में विदेशी मुद्रा (अरब डॉलर में)

	30 दिसम्बर, 2022 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	14 जुलाई, 2023 की स्थिति
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियाँ (Foreign Currency Assets)	491·818	509·691	540·166
स्वर्ण (Gold)	41·323	45·200	45·197
विशेष आहरण अधिकार (SDR—Special Drawing Right)	18·182	18·392	18·484
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि (Reserve With IMF)	5·159	5·165	5·175
कुल विदेशी मुद्रा कोष	562·851	578·449	609·022

● एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का विलय

1 जुलाई, 2023 को आवास वित्त क्षेत्र की निजी कम्पनी एचडीएफसी (HDFC—Housing Development and Finance Corporation) का विलय एचडीएफसी बैंक में हो गया. इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की जा चुकी थी. सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात् इस विलय के लिए मार्ग जून, 2023 में प्रशस्त हो गया था तथा विलय प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए दोनों वित्तीय संस्थानों के निदेशक मण्डलों की पृथक्-पृथक् बैठकें 30 जून, 2023 को हुईं. एचडीएफसी बोर्ड की यह अंतिम बैठक थी. इसके पश्चात् एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई, 2023 को प्रभावी हो गया.

प्रमुख बैंकिंग दरें : एक दृष्टि में (6 अक्टूबर, 2023 की स्थिति)

☞ बैंक दर	6·75 प्रतिशत
☞ नकद आरक्षण अनुपात (CRR)	4·50 प्रतिशत
☞ सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)	18·00 प्रतिशत
☞ रेपो दर	6·50 प्रतिशत
☞ रिवर्स रेपो दर	3·35 प्रतिशत
☞ सीमान्त स्थायी सुविधा/मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी (MSF)	6·75 प्रतिशत

वैदेशिक क्षेत्रक

● भारत की नई विदेश व्यापार नीति, 2023

भारत के विदेश व्यापार को सुदृढ़ता प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च, 2023 को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति 2023 (Foreign Trade Policy, 2023) की घोषणा की. पिछली विदेश व्यापार नीतियों से पहली भिन्नता इसमें यह है कि यह नीति किसी निर्धारित अवधि के लिए नहीं है. यह एक गतिशील नीति है और उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए यह पूरी तरह से खुली (Open ended) बनाई गई है. नीति की घोषणा करते हुए सरकार ने रेखांकित किया कि सेवाओं तथा वस्तुओं सहित भारत का समग्र निर्यात पहले ही 750 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है और वर्ष 2023 में इसके 760 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है.

पिछली विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी और इसके समाप्त होने की तिथि 31 मार्च, 2020 थी, परन्तु कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस नीति को कई बार विस्तार दिया गया. इसे अन्तिम बार सितम्बर, 2022 में 31 मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था.

नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई है. **नई नीति में 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है.** नई विदेश व्यापार नीति, 2023 का दृष्टिकोण चार स्तम्भों पर आधारित है. यह स्तम्भ हैं–

(1) प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना (Incentive to Remission)

(2) गठबंधनों–निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्द्धन (Export promotion through collaboration—Exporters, States, Districts, Indian Missions)

(3) व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई-पहल (Ease of doing

STUDYPDF WALLAH

business – reductions transaction costs and e-initiations)

(4) उभरते क्षेत्र–निर्यात हबों के रूप में ई–कॉमर्स विकासशील जिले तथा स्कोमेट नीति को विवेकपूर्ण बनाना (Emerging Areas Developing districts as Export Hubs and Streamling SCOMET policy) {SCOMET से तात्पर्य है–Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies. यह दोहरे उपयोग (सिविलियन व मिलिट्री) वाले वस्तुएँ हैं.}

- विदेश व्यापार नीति, 2023 एक नीतिगत दस्तावेज है, जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है तथा एक ऐसा दस्तावेज है जो द्रुतगामी है और व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति उत्साहपूर्वक अनुकूल है.
- विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करना है.
- नई नीति में निर्यातकों के लिए पुराने लम्बित प्राधिकरणों को बंद करने तथा तथा नए सिरे से आरम्भ करने के लिए एकमुश्त एमनेस्टी स्कीम लाने की बात कही गई है.
- विदेश व्यापार नीति 2023 'टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस स्कीम' (TEES—Towns of Export Excellence Scheme) के माध्यम से नए शहरों तथा 'स्टेट्स होल्डर स्कीम' के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करती है.
- निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट योजनाओं का कार्यान्वयन अब एक नियम आधारित आईटी प्रणाली वातावरण में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा जिससे मैनुअल इंटरफेस की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी.
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एडवांस एवं ईपीसीजी योजनाओं के तहत् जारी करने, पुनर्सत्यापन तथा ईओ विस्तार सहित सभी प्रक्रियाएँ चरणबद्ध तरीके से कवर की जाएंगी. जोखिम प्रबंधन संरचना के तहत पहचाने गए मामलों की जाँच भौतिक रूप से यानि मैनुअली की जाएगी, जबकि अधिकांश आवेदकों के आरभ में 'ऑटोमैटिक रूप से' कवर किए जाने की उम्मीद है.
- चार नए शहरों–फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता के शहर (TEE—Towns of Export Excellence) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है. टीईई की एमएआई (MAI—Market Access a Initiative) स्कीम के तहत् निर्यात संवर्द्धन फण्डों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुँच होगी और वे ईपीसीजी स्कीम के तहत् निर्यात पूर्ति के लिए सामान्य सेवा प्रदाता (CSP) का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे. इन शहरों के जोड़े जाने से हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा दरियों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना नीति में व्यक्त की गई है.
- 'ईच वन, टीच वन' पहल के समान ही, 2-स्टार और उससे ऊपर वाले स्टेटस धारकों को इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल करीकुलम पर आधारित व्यापार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसे भारत को 2030 से पहले 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की सेवा करने में सक्षम, कुशल श्रमबल समूह का निर्माण करने में मदद मिलेगी.
- 4 एवं 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए अधिक-से-अधिक निर्यातक कम्पनियों को सक्षम बनाने के लिए स्टेटस रिकौग्निशन नियमों को पुनः ठीक किया गया है, जिससे निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग अवसर प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो.
- ई-कॉमर्स निर्यात एक आशाजनक वर्ग है जिसके लिए पारंपरिक ऑफलाइन व्यापार से विशिष्ट नीतिगत युक्तियों की आवश्यकता होती है. विभिन्न अनुमानों में कहा गया है कि 2030 तक 200 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर की सीमा में ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता होगी.
- एफटीपी 2023 ई-कॉमर्स हबों की स्थापना तथा पेमेंट रिकौंसिलिशन, बुककीपिंग, रिटर्न नीति तथा निर्यात पात्रता जैसे संबंधित तत्वों के लिए अभिप्राय तथा रूपरेखा दर्शाती है.
- भारत को एक मर्चेंटिंग व्यापार हब के रूप में विकसित करने के लिए, एफटीपी 2023 ने मर्चेंटिंग व्यापार के लिए प्रावधान प्रस्तुत किए हैं. निर्यात नीति के तहत् सीमित एवं प्रतिबंधित मदों का मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव हो सकेगा. मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है जिसमें एक भारतीय मध्यवर्ती की भागीदारी होती है. यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा.
- सरकार निर्यात दायित्वों पर डिफॉल्ट पर ध्यान देने के लिए एफटीपी 2023 के तहत् एक विशेष एकमुश्त एमनेस्टी (माफी) स्कीम लागू कर रही है. इस स्कीम का प्रयोजन उन निर्यातकों को राहत प्रदान करना है जो ईपीसीजी और अग्रिम प्राधिकरणों के तहत् अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हैं और जो उच्च शुल्क तथा लम्बित मामलों से जुड़ी ब्याज लागत के बोझ से दबे हुए हैं.

भारत का विदेशी व्यापार : आँकड़े एक दृष्टि में

वस्तुगत व्यापार (Merchandise Trade) (अरब डॉलर में)

	अप्रैल-सितम्बर	
	2022-23	**2023-24**
निर्यात (Exports)	231·73	211·40 (–8·77 प्रतिशत वृद्धि)
आयात (Imports)	–372·56	326·98 (–12·23 प्रतिशत वृद्धि)
व्यापार शेष (Trade Balance)	**–140·83**	**–115·58**
सेवाओं का व्यापार (Trade in Services)		
सेवाओं का निर्यात (प्राप्तियाँ)	256·07	164·89 (5·65 प्रतिशत वृद्धि)
सेवाओं का आयात (भुगतान)	90·58	89·22 (–1·5 प्रतिशत वृद्धि)
सेवाओं का शेष	65·49	+75·67
कुल विदेशी व्यापार (वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार वृद्धि)		
कुल निर्यात	387·80	376·29 (–2.97 प्रतिशत वृद्धि)
कुल आयात	463·14	416·20 (–10·14 प्रतिशत वृद्धि)
कुल व्यापार शेष	–75·34	–39·91

STUDYPDF WALLAH

● भारत में विदेशी ऋण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट

भारत में विदेशी ऋण की स्थिति के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक में अपनी ताजा रिपोर्ट 28 सितम्बर, 2023 को जारी की. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पर कुल विदेशी ऋण जून, 2023 के अंत में 629·1 अरब डॉलर था, जो पूर्व मार्च, 2023 के अंत में 624·30 अरब डॉलर था. इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 4·7 अरब डॉलर (0·75 प्रतिशत) की वृद्धि 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान हुई. जून, 2023 के अन्त में भारत में कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 18·6 प्रतिशत था, जो तीन माह पूर्व मार्च, 2023 के अन्त में 18·8 प्रतिशत था.

- जून 2023 के अंत में भारत के 629·1 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 505·5 अरब डॉलर व अल्पकालिक ऋण 123·6 अरब डॉलर था.
- जून 2023 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 80.4 प्रतिशत भाग दीर्घकालिक ऋणों का था, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग 19·6 प्रतिशत था.
- रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 54·4 प्रतिशत भाग डॉलर में निरूपित था. दूसरे स्थान पर 30·4 प्रतिशत भाग भारतीय रुपए में निरूपित था. कुल विदेशी ऋण का 5·9 प्रतिशत भाग एसडीआर में 5·7 प्रतिशत जापानी येन में तथा 3·0 प्रतिशत भाग यूरो में निरूपित था.
- रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात (Debt Service Ratio-निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋणों व ब्याज की अदायगियाँ) जून, 2023 के अन्त में 6·8 प्रतिशत था, जो मार्च, 2023 में 5·3 प्रतिशत हो गया था.

भारत में विदेशी ऋण : एक दृष्टि में (जून, 2023 के अन्त की स्थिति)	
मद	**जून 2023 के अन्त की स्थिति**
कुल विदेशी ऋण (Total External Debt)	629·1 अरब डॉलर
कुल दीर्घकालिक ऋण	505·5 अरब डॉलर
कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग	80·4 प्रतिशत
अल्पकालिक ऋण (Short Term Debt)	23·6 अरब डॉलर
कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग	19·6 प्रतिशत
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण	18·6 प्रतिशत
मार्च, 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात	7·8 प्रतिशत
मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना	
डॉलर मूल्य में	54·4 प्रतिशत
रुपए मूल्य में	30·4 प्रतिशत
एसडीआर में	5·9 प्रतिशत
येन में	5·7 प्रतिशत
यूरो में	3·0 प्रतिशत

नीतिगत आर्थिक पहलें

● आकाशवाणी व दूरदर्शन के लिए प्रसारण अवसंरचना व नेटवर्क विकास योजना (BIND)

प्रसार भारती अर्थात् आकाशवाणी व दूरदर्शन के बुनियादी ढाँचे एवं कंटेंट के उन्नयन तथा संगठन से सम्बन्धित सिविल वर्क आदि के विकास के लिए ₹ 539·61 करोड़ की लागत वाली प्रसारण अवसंरचना व नेटवर्क विकास (BIND—Broadcasting Infrastructure and Network Development) योजना को केन्द्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (CCEA) ने 4 जनवरी, 2023 को मंजूरी दी.

- वर्तमान में दूरदर्शन देश में 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है तथा ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केन्द्रों का संचालन करता है.
- बाइंड (BIND) योजना देश में ऑल इंडिया के एफएम ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत और जनसंख्या की दृष्टि से 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर देगी.

● राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

देश में हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) व इसके सहायक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात के अवसरों के सृजन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन तथा औद्योगिक एवं ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरूआत की गई है. इस महत्वाकांक्षी मिशन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 4 जनवरी, 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई.

- मिशन के लिए प्रारम्भिक व्यय ₹ 19744 करोड़ स्वीकृत किया गया है.
- देश में हरित हाइड्रोजन की कम-से-कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का विकास.
- वर्ष 2023 तक ₹ 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश तथा छह लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना.
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की कमी.

● स्वर्णाभूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता

स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे सभी उत्पादों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है. केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की 4 मार्च, 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार सभी आभूषण विक्रेता अब 6 अंकों व अक्षरों वाले अल्फान्यूमेरिक (Alphanumeric) हॉलमार्किंग के बिना आभूषणों व कलाकृतियों की बिक्री नहीं करेंगे. हॉलमार्किंग के इस चिह्न को हुइड (HUID—Hallmarking Unique Identification Number) कहा गया है. ग्राहकों द्वारा बेचे जाने वाले पुराने आभूषणों की बिकी के लिए यह चिन्हान्कन आवश्यक नहीं होगा. स्वर्ण आभूषणों व उत्पादों की बिक्री के मामले में यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है. इससे पूर्व 4 डिजिट वाले हॉल मॉर्क की व्यवस्था लागू थी. 4 डिजिट वाले हॉलमार्किंग को 1 अप्रैल, 2023 को पूरी तरह बन्द कर दिया गया है.

वैश्विक निर्देशांकों में भारत

● एनएसएसओ: मल्टीपल नमूना सर्वेक्षण

कतिपय महत्वपूर्ण सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs—Sustainable Development

STUDYPDF WALLAH

Goals) के संकेतकों के मामले में तथा 31 मार्च, 2014 के पश्चात् आवासीय उद्देश्यों के लिए परिवारों द्वारा घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण के सम्बन्ध में जानकारियाँ एकत्र करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO—National Sample Survey Office) द्वारा 2020-21 के दौरान किया जिसके परिणाम मार्च, 2023 में जारी किए गए. एनएसएसओ के 78वें दौर के इस सर्वेक्षण में परिवारों के घर, शौचालय, शैक्षणिक स्तर, टेलीफोन, ऊर्जा के स्वच्छ सोत आदि के सम्बन्ध में प्रश्न शहरों व गाँवों दोनों में निवासियों से इसमें पूछे गए थे. इसी परिप्रेक्ष्य में मल्टीपल इंडीकेटर सर्वे (MIS) इस सर्वेक्षण को नाम दिया गया था. इस सर्वे के प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् हैं–

- पानी के पीने के बेहतर सोत की उपलब्धि के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर 97·2 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में 95·0 प्रतिशत ने यह पुष्टि की.
- शौचालयों की उपलब्धियों की बात कहने वाले व्यक्तियों में से 98 प्रतिशत ने उन्नत शौचालय की उपलब्धि की बात कही. ग्रामीण क्षेत्रों में 97·5 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 99 प्रतिशत ने ऐसा बताया.
- खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक सोत के रूप में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 63·1 प्रतिशत इस सर्वेक्षण में पाया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों का प्रतिशत जहाँ 49·8 प्रतिशत दर्ज किया गया. शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 92·0 प्रतिशत था.
- 31 मार्च, 2014 के बाद किसी नए घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत 9·9 प्रतिशत दर्ज किया गया. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत क्रमशः 11·2 प्रतिशत व 7·2 प्रतिशत रहा.
- 31 मार्च, 2014 के बाद किसी नए घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत 49·9 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिन्होंने पहली बार नए घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण किया है. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत क्रमशः 47·5 प्रतिशत व 57·9 प्रतिशत रहा.

● एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिंग, 2023

26 जून, 2023 को जारी एस एण्ड पी (S&P) ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन वर्षों में 6·7 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्राप्त करेगी. एजेंसी की इस नवीनतम रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा 6 प्रतिशत के पहले के अनुमान पर ही इसे बरबरार रखा गया है. 2023-24 में भारत में वृद्धि दर 6·0 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान एस एण्ड पी ने पहले व्यक्त किया था. अगले दो वित्तीय वर्षों 2024-25 व 2025-26 में देश में जीडीपी में वृद्धि 6·9-6·9 प्रतिशत रहने का एजेंसी का अनुमान है. 2023-24 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को एस एण्ड पी ने 6·0 प्रतिशत के स्तर पर बरकरार जहाँ रखा है, वहीं चीन में 2023 में वृद्धि के पूर्वानुमान को 5·5 प्रतिशत से घटाकर 5·2 प्रतिशत एस एण्ड पी ने जून, 2023 में किया है.

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्य में गिरावट को देखते हुए 2023-24 में भारत में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में भी शिथिलता आने की बात एजेंसी की जून, 2023 की रिपोर्ट में कही गई है. रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत रहने की सम्भावना है, जो इसके पश्चात् 2024-25 व 2025-26 में 4·5-4·5 प्रतिशत ही सम्भावित है.

● अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)–2023

जुलाई 2023 में अंकटाड (UNCTAD—United Nations Conference on Trade and Development) की विभिन्न राष्ट्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के अन्तर्प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के सम्बन्ध में वर्ष 2023 की रिपोर्ट विश्वभर में जारी की गई. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट (World Investment Report)–2023 शीर्षक वाली इस 33वीं वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के वैश्विक अन्तर्प्रवाह में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि जहाँ दर्ज की गई थी, वहीं 2022 में इसमें गिरावट रही है, जिससे यह कोविड-19 महामारी के स्तर तक पहुँच गया. सन्दर्भित वर्ष 2022 में यह कुल मिलाकर 1295 अरब डॉलर (1·3 ट्रिलियन डॉलर) का रहा है. वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वैश्विक अन्तर्प्रवाह 1478 अरब डॉलर ही रहा था.

रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 1295 अरब डॉलर के एफडीआई के कुल अन्तर्प्रवाह में 378 अरब डॉलर का अन्तर्प्रवाह विकसित देशों में, 916 अरब डॉलर विकासशील देशों में हुआ, जो पूर्व वर्ष 2021 में क्रमशः 597 व 881 अरब डॉलर था. **अंकटाड की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में एफडीआई का अन्तर्प्रवाह 49 अरब डॉलर रहा है, जो 2021 में प्राप्त किए गए 55 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत कम है. रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई के अन्तर्प्रवाह के मामले में भारत का स्थान 2022 में 8वाँ रहा है, जोकि पूर्व वर्ष 2021 में भी 8वाँ ही था.**

वर्ष 2023 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का सर्वाधिक 285 अरब डॉलर का अन्तर्प्रवाह अमरीका में रहा है.** इस मामले में **चीन** व **सिंगापुर** का स्थान क्रमशः दूसरा (189 अरब डॉलर) व **तीसरा** (141 अरब डॉलर) रहा है. इस मामले में आगे के स्थान क्रमशः हांगकांग, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, कनाडा व भारत के हैं.

अंकटाड की इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का बाह्य प्रवाह (Out flow) के मामले में भी शीर्ष स्थान अमरीका का ही रहा है जहाँ 373 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह वर्ष 2022 में हुआ. 161 अरब डॉलर के बाह्य प्रवाह के साथ जापान का इस मामले में दूसरा स्थान 2022 में रहा. इस मामले में तीसरा स्थान 147 अरब डॉलर के बाह्य प्रवाह के साथ चीन का रहा है.

● नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index), 2022

नीति आयोग द्वारा राज्यों की निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index) जारी किए जाते हैं. आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए ऐसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 26 अगस्त, 2020 को तथा वर्ष 2021 के लिए ऐसे दूसरे निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च, 2022 में जारी किए गए थे. इसी शृंखला में वर्ष 2022 के लिए सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई, 2023 को जारी किए गए. आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए निर्यात वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना आवश्यक है. इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग द्वारा यह पहल की गई है.

- वर्ष 2022 के निर्यात तत्परता सूचकांक भी नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्द्धता संस्थान (Institute of Competitiveness) के साथ साझीदारी में तैयार किए गए हैं. इस सूचकांक की संरचना चार स्तम्भों-नीति (Policy), व्यवसाय परितंत्र (Business Ecosystem), निर्यात परितन्त्र (Export Ecosystem) व निर्यात निष्पादन (Export Performance) पर तथा निर्यात संवर्द्धन नीति, बिजनेस एन्वायरमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तथा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जैसे 10 विभिन्न उपस्तम्भों (Sub-pillers) पर आधारित है.

STUDYPDF WALLAH

☞ वर्ष 2020 व 2021 के लिए सूचकांकों की तर्ज पर 2022 के लिए जारी किए गए यह सूचकांक भी भारत के प्रतिस्पर्द्धता संस्थान (Institute of Competitiveness) के सहयोग से तैयार किए गए हैं. 0-100 मान वाले इस सूचकांक का मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक है, उतना ही अधिक उस राज्य की निर्यात तत्परता एवं क्षमता को यह दर्शाता है.

☞ उपर्यक्त मानकों के आधार पर विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक-2022 में पहला स्थान तमिलनाडु का है, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र व कर्नाटक का है. ताजा रैंकिंग में तमिलनाडु ने बड़ी छलांग लगाई है, 2021 के चौथे स्थान से इस बार तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान पा लिया है. हरियाणा पाँचवें स्थान पर बरकरार है. उत्तर प्रदेश छठे स्थान से एक पायदान गिर कर सातवें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि मध्य प्रदेश 7वें से गिर कर 12वें स्थान पर, पंजाब 8वें से 10वें स्थान पर तथा आन्ध्र प्रदेश 9वें से 8वें स्थान पर आ गया है. राजस्थान 11वें स्थान से 13वें स्थान पर, उत्तराखण्ड 17वें से 9वें स्थान पर तथा छत्तीसगढ़ 21वें स्थान से 25वें स्थान पर आ गया है. झारखण्ड 21वें स्थान पर बरकरार है. दिल्ली का इस मामले में स्थान 12वें से गिर कर 18वाँ हो गया है.

☞ ईपीआई-2022 के आधार पर निर्यात तैयारी में पहले 10 स्थानों पर रहे राज्यों में वर्ष 2020 व 2021 की भाँति छह तटीय राज्य हैं. गैर–तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान हरियाणा का है, जिसके पश्चात् क्रमशः तेलंगाना व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के स्थान हैं. हिमालयी राज्यों में पहला स्थान पूर्व वर्ष 2020 व 2021 की भाँति उत्तराखण्ड का ही है, जबकि दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः हिमाचल प्रदेश व मणिपुर का है. केन्द्रशासित क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर का ईपीआई-2022 में शीर्ष स्थान है, जबकि दिल्ली व अण्डमान-निकोबार का क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है.

● भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट-2022

विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर नजर रखने वाली/आकलन करने वाली अमरीका स्थित स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई. भ्रष्टाचार धारणा/बोध सूचकांक (CPI—Corruption Perceptions Index) के आधार पर जारी इस रिपोर्ट में गत वर्ष की भाँति 180 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किए गए हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में सर्वोच्च 90 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के साथ डेनमार्क का पहला स्थान है. फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड का स्थान 87-87 सूचकांक के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान आकलित किया गया है. इसका अर्थ यह है कि डेनमार्क, फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड क्रमशः सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं. वर्ष 2021 की वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट में 85 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के साथ डेनमार्क, फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड को ही संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे तथा इन देशों में सबसे कम भ्रष्ट देश आकलित किया गया था. इस मामले में सबसे निचले स्थान पर सोमालिया का है, जिसके लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 12 (सबसे कम) आकलित है. इसका आशय है सोमालिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है. 13-13 सूचकांक के साथ सीरिया व दक्षिण सूडान संयुक्त रूप से नीचे से दूसरे स्थान पर हैं.

☞ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्सन परसेप्शन इंडेक्स) 40 आकलित किया गया है तथा कुल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 85वाँ स्थान दिया गया है. वर्ष 2020 व 2021 की सूची में भारत के लिए भ्रष्टाचार धारणा/बोध सूचकांक 40 ही था तथा 180 देशों में कमशः 86वाँ व 85वाँ स्थान भारत को दिया गया था. इस प्रकार 2022 के लिए भारत के लिए सूचकांक गत वर्ष की भाँति 40 ही रहा है, इसकी वैश्विक रैंकिंग भी यथावत् बना हुआ है.

☞ भारत के पड़ोसी देशों में 25वें व 65वें स्थान के साथ क्रमशः भूटान व चीन भारत से बेहतर स्थिति में हैं. पिछले वर्ष चीन 66वें स्थान पर था. चीन की रैंक में एक पायदान का सुधार हुआ है. अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश में स्थिति भारत से भी खराब है. वर्ष 2022 की इस सूची में श्रीलंका 101वें ,नेपाल 110वें, पाकिस्तान 140वें, बांग्लादेश 147वें, अफगानिस्तान 150वें व म्यांमार 157वें स्थान पर है. इस प्रकार इन देशों में भ्रष्टाचार का स्तर भारत से भी अधिक आकलित किया गया है.

● ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख की गम्भीर स्थिति बरकरार : 125 देशों में भारत का 111वाँ स्थान

विभिन्न राष्ट्रों में भूख (Hunger) की स्थिति को निरूपित करने वाली वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख की स्थिति गम्भीर अभी बनी हुई है. पिछले वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 121 देशों में भुखमरी की रैंकिंग में भारत का जहाँ 107वाँ स्थान था. इस वर्ष 125 देशों में 111वाँ स्थान भारत का बताया गया है.

इस मामले में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर रिपोर्ट में बताई गई है. वर्ष 2023 की ताजा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में विश्व भर में जारी हुई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 60वाँ, म्यांमार को 72वाँ, नेपाल को 69वाँ, बांग्लादेश को 81वाँ, पाकिस्तान को 102वाँ स्थान दिया गया है. यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी भारत के निकट 114वाँ स्थान प्रदान किया गया है. भारत का स्थान 111वाँ है. इस प्रकार अफगानिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023
भारत व पड़ोसी देशों की रैंकिंग
(125 देशों में)

देश	रैंकिंग
श्रीलंका	60
नेपाल	69
म्यांमार	72
बांग्लादेश	81
पाकिस्तान	102
भारत	111
अफगानिस्तान	114

136 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) के आधार पर भुखमरी की स्थिति का आकलन इस वर्ष की रिपोर्ट में किया गया है, किन्तु पर्याप्त आँकड़ों के चलते 125 देशों के लिए ही रैंकिंग का निर्धारण किया गया है, जिनमें भारत का 111वाँ स्थान रहा है. **(विकसित देशों के लिए यह सूचकांक आकलित नहीं किए जाते हैं)** भूख के मामले में, जो देश भारत से भी खराब स्थिति में हैं. उनमें अफगानिस्तान के अतिरिक्त तिमोर लेस्ते (112वाँ स्थान), मोजाम्बिक (113वाँ स्थान), हैती (115वाँ स्थान), सिएरा लियॉन (116वाँ स्थान), लाइबेरिया (117वाँ स्थान), गिनी बिसाऊ नाइजर (118वाँ स्थान), चाड (119वाँ स्थान), लिसोथो (121वाँ स्थान), कांगो (122वाँ स्थान), यमन (123वाँ स्थान), मैडागास्कर (124वाँ स्थान) तथा सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक का (125वाँ नीचा स्थान) शामिल हैं.

STUDYPDF WALLAH

आर्थिक कार्यक्रम/योजनाएं/मिशन

● महिला सम्मान बचत-पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक बचत योजना की घोषणा अपने बजट भाषण में की थी. वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए अधिसूचना जारी करते हुए 1 अप्रैल, 2023 से यह योजना प्रारम्भ कर दी है. इस बचत योजना को **महिला सम्मान बचत-पत्र** (Mahila Samman Savings Certificate) नाम दिया गया है.

- इस योजना के तहत केवल महिलाएँ अथवा नाबालिक लड़कियों के नाम से अभिभावक डाक घर अथवा किसी अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं.
- यह निवेश 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए ही किया जा सकता है.
- विशेष निर्दिष्ट परिस्थितियों में परिपक्वता से पहले धन की निकासी संभव है.
- इस योजना में न्यूनतम ₹ 1,000 व अधिकतम ₹ 2 लाख जमा किए जा सकते हैं.
- जमा राशि पर 7·5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगी जो तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाएगी.
- यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए (31 मार्च, 2025 तक) ही लागू की गई है.

● 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' से सम्बन्धित नवीनतम तथ्य/आँकड़े

गरीब परिवारों को खाना बनाने के लिए एलपीजी के रूप में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' का शुभारम्भ मई 2016 में किया गया था. इस योजना के तहत् डिपॉजिट राशि के बिना ही एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है. योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 मार्च, 2023 को 9·59 करोड़ थी.

एलपीजी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के चलते देश में भी एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई है. इस मूल्य वृद्धि से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें ₹ 200 प्रति सिलेण्डर की सब्सिडी 22 मार्च, 2022 से दी जा रही है. योजना के 9·59 करोड़ लाभार्थियों के लिए इस सब्सिडी को जारी रखते हुए प्रति 14·2 किग्रा सिलेण्डर पर प्रति वर्ष अधिकतम 12 रिफिल तक ₹ 200 प्रति रिफिल की सब्सिडी को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की 24 मार्च, 2023 की बैठक में मंजूरी दी गई. इससे 2023-24 के दौरान कुल सब्सिडी व्यय ₹ 7,680·00 करोड़ अनुमानित है. 2022-23 में यह व्यय 6100·00 करोड़ रहा.

केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 24 मार्च, 2023 की विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3·01 रिफिल थी, जो बढ़कर 2021-22 में 3·68 रिफिल हो गई थी.

● आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)

जुलाई 2023 में केन्द्र सरकार की नवोन्मेषी रोजगार प्रोत्साहन योजना–आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने प्रारम्भिक रोजगार सृजन लक्ष्यों को पार कर लिया. 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके नई नौकरी के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था. इस योजना का उद्देश्य 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान (मजदूरी का 24 प्रतिशत) को कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करना है. 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारी का ईपीएफ योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) कवर किया गया था.

● पीएम विश्वकर्मा योजना

17 सितम्बर, 2023 को सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार व चर्मकार आदि पारम्परिक कारीगरों के हिमार्थ केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर किया. इस योजना से पारम्परिक कौशल वाले कर्मियों को अपना कारोबार प्रारम्भ करना तथा उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत् 18 ट्रेड्स के कारीगरों को इस योजना के तहत् लाभ प्राप्त हो सकेगा. योजना के तहत् पात्र कारीगरों को कारोबार शुरू करने व उसके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण आधुनिक डिजिटल तकनीक व टूल किट प्रोत्साहन आदि कर सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी. पात्र कारीगरों को ₹ 3 लाख तक का ऋण 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज पर इस योजना के तहत् उपलब्ध कराया जाएगा.

विविध/सामयिक आर्थिक टिप्पणियाँ

● रेल विकास निगम : नवरत्न कम्पनी का दर्जा

मई 2023 में रेल मंत्रालय के उपक्रम–रेल विकास निगम लि. (RVNL) को 'नवरत्न' कम्पनी का दर्जा प्रदान किया गया. सितम्बर, 2013 में इसे मिनी रत्न कम्पनी का दर्जा प्रदान किया गया था. इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने से देश में नवरत्न कम्पनियों की संख्या अब 16 हो गई है. सार्वजनिक क्षेत्र की इस कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹ 3,000 करोड़ है, जबकि चुकता पूँजी (Paid up Capital) ₹ 2085 करोड़ है.

भारत की महारत्न कम्पनियाँ : एक दृष्टि में (15 नवम्बर, 2023)

13 महारत्न कम्पनियाँ

1. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (BHEL)
2. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (BPCL)
3. कोल इण्डिया लि.
4. GAIL इण्डिया लि.
5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
6. NTPC लि.
7. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
8. पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
9. पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
10. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
11. भारत इस्पात निगम लि.
12. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
13. ऑयल इण्डिया लि.

भारत की नवरत्न कम्पनियाँ : एक दृष्टि में (मई 2023 की स्थिति)

● 16 नवरत्न कम्पनियाँ

1. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (CONCOR)
2. महानगर टेलीफोन निगम लि. (MTNL)
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL)
4. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HEL)
5. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) (जनवरी 2008)
6. नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी–नाल्को (NALCO) (मई 2008)
7. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) (अगस्त 2008)
8. निवेली लिग्नाइट लि. (NLL)
9. ओएनजीसी विदेश लि.
10. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (RINL)
11. नेशनल बिल्डिंबग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCCL)
12. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (EIL)
13. रेल विकास निगम लि. (RVNL)
14. राष्ट्रीय केमीकल एवं फर्टीलाइजर्स लि.
15. IRCON इण्टरनेशनल लि.
16. RITES लि.

●●●

STUDYPDF WALLAH

नवीनतम सामान्य ज्ञान

चर्चित शब्द संक्षेप

- **बीएनएस** (BNS)—भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita)
- **बीएनएसएस** (BNSS)—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)
- **बीएसएस** (BSS)—भारतीय साक्ष्य संहिता (Bharatiya Sakshya Sanhita)
- **सीईपीए** (CEPA)—कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (Comprehensive Economic Partnership Agreement)
- **जीबीए** (GBA)—ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (Global Biofuel Alliance)
- **एचयूआईडी** (HUID)—हॉल मार्क यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (Hall Marked Unique Identification Number)
- **आईएनडीआईए** (इंडिया—I. N. D. I. A.)—इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव एलायंस (Indian National Developmental Inclusive Alliance)
- **आरवीएनएल** (RVNL)—रेल विकास निगम लि. (Rail Vikas Nigam Ltd.) {सन्दर्भ : मई, 2023 में 'नवरत्न कम्पनी' का दर्जा}
- **आरआरटीएस** (RRTS)—रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Regional Rapid Transit System) {सन्दर्भ : इसके तहत् पहली नमो भारत रेलगाड़ी 20-21 अक्टूबर, 2023 से शुरू}
- **एसएसएलवी** (SSLV)—स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (Small Satellite Launch Vehicle)
- **यूसीसी** (UCC)—यूनीफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code)

पुरस्कार/सम्मान (राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय)

☞ **ज्ञानपीठ पुरस्कार :**

57 वाँ (2021)—दामोदर मौजी (कोंकणी उपन्यासकार)

56 वाँ (2020)—नीलमणि फूकन जूनियर (असमिया लेखक)

55वाँ (2019)—अक्कीथम अच्युतन नम्बूदिरी (Akkitham Achuthan Namboothiri) (मलयालम के सुप्रसिद्ध कवि)

☞ **व्यास सम्मान, 2021**—डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी (**कृति**—पागलखाना, उपन्यास) (मार्च 2023 में घोषित)

2021—असगर वजाहत (**कृति**—महाबली, नाटक)

☞ **बिहारी पुरस्कार, 2022 (31वाँ)**—डॉ. माधव हाडा (राजस्थान)
(**कृति**—पंचरंग चोला पहाड़ सखी री (आलोचना) (मार्च, 2023)

2021 (31वाँ)—मधु कांकरिया
{**कृति**—हम यहाँ थे (उपन्यास}

☞ **चमेली देवी जैन पुरस्कार, 2022-23 :** धन्य राजेन्द्रन (मार्च 2023)
{न्यूज मिनट्स (News Minutes) की सह-संस्थापक व प्रधान सम्पादक}

2021-22 : आरेफा जौहरी

☞ **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2021**—वहीदा रहमान (सुप्रसिद्ध अभिनेत्री व नृत्यांगना; 26 सितम्बर, 2023 को प्रदत्त)

2020—आशा पारेख (सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक व नृत्यांगना)

☞ **श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, 2023**—मधु कांकरिया (हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका) (30 सितम्बर, 2023)

☞ **डॉ. विद्या निवास मिश्र पुरस्कार, 2022-23**—डॉ. सूर्यनारायण पाण्डेय (हिन्दी के साहित्यकार) (मार्च 2023)

☞ **गांधी शांति पुरस्कार, 2021**—गीता प्रेस, गोरखपुर (18 जून, 2023)

☞ **लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार,** 2023 (दूसरा) : आशा भोंसले {24 अप्रैल, 2023}

2022—नरेन्द्र मोदी (राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए)

☞ **13वाँ भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार, 2023**—योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री)

☞ **सरस्वती सम्मान, 2022 (32वाँ)**—शिव शंकरी (तमिल भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार शिव शंकरी) {**कृति**—सूर्य वामसम, आत्मकथा}
(घोषणा—मार्च 2023; पुरस्कार मिला—12 अक्टूबर, 2023)

2021 (31वाँ)—प्रो. रामदरश मिश्र (प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार)
{**कृति**—मैं तो यहाँ हूँ, काव्य संग्रह}

☞ **राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 2020-21**—वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) (20 अगस्त, 2023)

☞ **लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार**—नरेन्द्र मोदी (1 अगस्त, 2023)

☞ **गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार, 2023**—प्रो. लुइस ए. कैफेरेल्ली (Luis A. Caffarelli) (अमरीका) {23 मार्च, 2023}

2022—डेनिस पार्नेल सुलीवान (Dennis Parnell Sullivan) (अमरीका)

☞ **अन्तर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2023**—जोर्जी गोस्पोदिनोव (बुल्गारिया)
(**कृति**—टाइम शेल्टर (Time Shelter) (अंग्रेजी में अनुवाद—एंजेला रोडेल) {24 मई, 2023}

2022—गीतांजलि श्री (भारत)
(**कृति**—टॉम्ब ऑफ सैंड, हिन्दी उपन्यास 'रेत समाधि' का अनुवाद (अनुवादक—डेजी रॉकवैल)

☞ **प्रिट्जर पुरस्कार, 2023**—सर डेविड एलन चिपरफील्ड (Sir David Alan Chipperfield) (ब्रिटेन के जाने-माने आर्कीटेक्ट) {मार्च, 2023}

2022—फ्रांसिस केरे (Francis Kere)

☞ **विश्व खाद्य पुरस्कार, 2023**—हेददी कुन्ह (Heidi Kuhn) (अमरीका की गैर-लाभ संस्था 'रूट्स ऑफ पीस' की संस्थापक) (वितरण—26 अक्टूबर, 2023)

2022—सिंथिया रोसेनजवेग (Cynthia Rosenzweig) (अमरीकी कृषि और जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक)

☞ **टेम्पलटन पुरस्कार, 2023**—डॉ. एडना अदन इस्माइल (मई 2023)
{सोमालीलैण्ड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत्}

2022—फ्रैंक विल्जेक {भौतिक विज्ञानी}

☞ **अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, 2023**—प्रो. सी. आर. राव (भारतीय सांख्यिकीविद् एवं गणितज्ञ (अप्रैल 2023)

☞ **शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, 2023**—रूइक्सियांग झांग (घोषणा—सितम्बर 2023; पुरस्कार वितरण—22 दिसम्बर, 2023)

☞ **राइट लिवलीहुड पुरस्कार, 2023**
{पुरस्कार की घोषणा—28 सितम्बर, 2023 (पुरस्कार वितरण—29 नवम्बर, 2023}

1. यूनिस ब्रुक मैन अमिसाह (Eunice Brookman-Amissah) {घाना}
2. मदर नेचर ग्रुप्स (Mother Nature Groups) {कम्बोडिया}
3. फैलिस ओमिडो (Phyllis Omido) {कीनिया}
4. एसओएस मेडीटिरेनी (SOS Mediterranee) {भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव में संलग्न रहे मानवतावादी समूह}

☞ **गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, 2023**—नीलोफर हमीदी, इलाहेह

STUDYPDF WALLAH

मोहम्मदी तथा नर्गेस मोहम्मदी (ईरान कह जेल में निरुद्ध तीन महिला पत्रकार) (2 मई, 2023)

2022—बेलारूस के पत्रकारों के संगठन का (Belarusian Association of Journalists)

- **आन्द्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, 2023**—महसा अमीनी {कुर्दिश मूल की दिवंगत ईरानी महिला} (**घोषणा**—19 अक्टूबर, 2023; पुरस्कार वितरण—13 दिसम्बर, 2023)
- **नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार, 2023**—डॉ. स्वाति नायक (भारत) (24–26 अक्टूबर, 2023) {यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है}
- **स्टॉकहोम जल पुरस्कार** (Stockholm Water Prize), 2023

  प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो (Andrea Rinaldo) {23 मार्च, 2023; स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (Stockholm International Water Institute—SIWI) द्वारा प्रदत्त}

  2022—प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट (Wilfried Brutsaert)
- **ओलम्पिक ऑर्डर**—डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस (जून 2023; विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक)
- **जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, 2023**—सलमान रूश्दी (जून 2023) (भारत मूल के ब्रिटिश लेखक)
- **ग्रैण्ड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर**—नरेन्द्र मोदी (भारत के प्रधानमंत्री) (फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान, 14 जुलाई, 2023)
- **जीवनभर की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार**—शिव नडार (मानद चेयरमैन, एचसीएल टेक्नोलॉजीस)

  बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर—सुनील मित्तल (चेयरमैन, भारती इंटरप्राइजेज)
- **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी** (Enterpreneur of the year)—नितिन कामथ (जिरोधा के संस्थापक)
- **बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर**—आरती कृष्णा (प्रबंध निदेशक, सुंदरम फास्टनर्स)
- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कम्पनी** (Company of the year)—आईसीआईसीआई बैंक
- **एमर्जिंग कम्पनी ऑफ द ईयर**—अडानी ट्रांसमिशन
- **ईटी कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर**—मैरिको (Marico)
- **ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर**—जयश्री उल्लाल (अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ)

अर्स्ट एवं यंग के एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार (2022) {फरवरी 2023}

- **सर्वश्रेष्ठ उद्यमी** (E & Y Enterpreneur of the year)—सज्जन जिंदल (जूएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक)
- **ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर**—विवेक कुमार जैन (सीएमडी, गुजरात फ्लूरो कैमिकल्स लि.)
- **लाइफटाइम एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर**—के. पी. सिंह ('डीएलएफ ग्रुप' के मानद अध्यक्ष)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (मैन्युफैक्चरिंग)**—प्रदीप खेरुका (एक्जीक्यूटिव चेयरमैन, बोरेसिल ग्रुप)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (रिटेल एण्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स)**—रवि मोदी (सीएमडी, वेदांता फैशंस, मान्यवर)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (फाइनेंशियल सर्विसेज)**—वी. वैद्यनाथन (आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी व सीईओ)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (एनर्जी, रीयल एस्टेट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर)**—इरफान रजाक (सीएमडी, प्रेस्टिज ग्रुप)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (सर्विसेज**—पवन जैन (चेयरमैन) व रूबल जैन (एमडी) (सेफ एक्सप्रेस प्रा. लि.)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (स्टार्ट अप)**—महेश प्रतापनेनी (Med Genome के संस्थापक)
- **एण्टरप्रिन्योर ऑफ द ईयर (लाइफ साइंसेज एण्ड हैल्थकेयर)**—समीना हमीद (एक्जीक्यूटीव वाइस चेयरपर्सन, सिपला ग्रुप)

हाल ही में सम्पन्न प्रमुख सौन्दर्य प्रतियोगिताएं : एक दृष्टि में

- ***फेमिना मिस इंडिया—2023*** *(Femina Miss India-2023) : नंदिनी गुप्ता (राजस्थान) {15 अप्रैल, 2023; इम्फाल, मणिपुर}*
- ***मिस डीवा अर्थ, 2023***—*श्वेता शारदा (भारत) {अगस्त 2023}*
- ***डिवाइन मिस अर्थ इंडिया, 2023***—*प्रियन सेन (जयपुर) {26 अगस्त, 2023}*
- ***मिस इंटरनेशनल इंडिया, 2023***—*प्रवीना अंजना (राजस्थान) {26 अगस्त, 2023}*

खेल जगत् के लॉरियस पुरस्कार, 2023 (8 मई, 2023; पेरिस में घोषणा)

- **लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर** (Laureus Sportsman of the Year) : लियोनिल मैसी (फुटबाल, अर्जेन्टीना)
- **लॉरियस स्पोर्ट्सवुमैन ऑफ द ईयर** (Laureus Sportswoman of the Year) : शैली एन. फ्रेसर {जमैका}, एथलेटिक्स
- **लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर** (Laureus World Team of the Year) : अर्जेन्टीना की पुरुषों की फुटबाल टीम
- **लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाला/वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी** (Laureus World Comeback of the Year) : क्रिस्चियन एरिक्सेन (डेनमार्क का फुटबाल खिलाड़ी)
- **लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर** (Laureus Breakthrough of the Year) : कार्लोस अल्कराज (स्पेन के टेनिस खिलाड़ी)
- **स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड** (Sport for Good Award) : टीम अप
- **लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर** (Action Sportsperson of the Year) : चीनी मूल की अमरीकी फ्रीस्टाइल स्कीअर ईलीन जो यू
- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी** (Sportsperson of the Year with a Disability) केथरीन डेबरनर (स्विट्जरलैण्ड के व्हील चेयर एथलीट)

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) के वर्ष 2021-22 के पुरस्कार (18वाँ) (28–30 जनवरी 2023; दुबई)

- **सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर** (Cricketer of the Year) {गैरी सोबर्स ट्रॉफी}, 2021-22 : बाबर आजम (पाकिस्तान)
- **सर्वश्रेष्ठ वन डे क्रिकेटर** (One day Player of the Year) 2021-22 : बाबर आजम (पाकिस्तान) {लगातार दूसरे वर्ष}
- **सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर** (Test Player of the Year) 2021-22 : बेन स्टोक्स (इंगलैण्ड)

  2020-21 : जो रूट (Joe Root) (इंगलैण्ड)
- **सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी** (Emerging Player of the Year) 2021-22 : मार्को जैनसन (द. अफ्रीका)
- **स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार, 2021-22** : आसिफ शेख (नेपाल)
- **अम्पायर ऑफ द ईयर (डेविड शेफर्ड ट्रॉफी), 2021-22** : रिचर्ड इलिंग वर्थ (इंगलैण्ड)
- **ट्वेंटी-20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2021-22** : सूर्य कुमार यादव (भारत)

  2020-21 : मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)
- **एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर, 2021-22** : गेरहार्ड इरास्मुस (नामीबिया)

महिला क्रिकेटरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) के वर्ष 2021-22 के पुरस्कार {8–30 जनवरी, 2023; (अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC—International Cricket Council) ने पुरुष क्रिकेटरों के लिए पुरस्कारों की घोषणा के साथ}

- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर** (Women Cricketer of the Year) {**राशेल हेह्होई-फ्लिंट ट्रॉफी**}, **2021-22** : नताली रूथ स्कीवर (Natalie Ruth Sciver) (इंगलैण्ड)

STUDYPDF WALLAH

- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर** (Women ODI Cricketer of the Year), 2021-22 : नताली रूथ स्कीवर (इंगलैण्ड)

फीफा के वर्ष 2022 के पुरस्कार (27 फरवरी, 2023)

- **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबालर** (The Best FIFA Men's Player)—लियोनिल मैसी (Lionel Messi) {अर्जेन्टीना}
- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबालर** (The Best FIFA Women's Player)—एलेक्सिया पुटेलास (Alexia Putellas) (स्पेन)
- **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच**—लियोनिल स्कालोनी (अर्जेन्टीना की टीम के कोच)
- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच**—सारिना वीग्मैन (ब्रिटेन की महिला टीम की कोच)
- **वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (पुरुष)**—एमिलियानो मार्टिनेज (अर्जेन्टीना की टीम के गोलकीपर)
- **वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर (महिला)**—मैरी ईअप्से (इंगलैण्ड)

65वें ग्रेमी (Grammy) पुरस्कार {5 फरवरी, 2023; लॉस वेगास (अमरीका)}

- **एलबम ऑफ द ईयर**—हैरीज हाउस (हैरी स्टाइल्स)
- **रिकॉर्ड ऑफ द ईयर**—अबाउट डैम टाइम्स (लिज्जो)
- **सांग ऑफ द ईयर**—जस्ट लाइक दैट (बोनी रायट)
- **सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट**—समारा जॉय
- **सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस**—ईजी ऑन मी (अडेले)
- **सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एलबम**—हैरीज हाउस (हैरी स्टाइल्स)
- **सर्वश्रेष्ठ रॉक एलबम**—पेशेंट नम्बर 9 (ओजी ऑसबूर्ने)
- **सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक एलबम**—वैटलैग (वैट लैग)
- **सर्वश्रेष्ठ आर एण्ड बी** (Rhythm and Blues) एलबम-ब्लैक रेडियो-III (रॉबर्ट ग्लास्पट)
- **सर्वश्रेष्ठ रैप एलबम**—मॉरेल एण्ड द बिग स्टैपर्स (केंड्रिक लामार)
- **सर्वश्रेष्ठ कंट्री एलबम**—ए ब्यूटीफुल टाइम (विली नेल्सन)
- **सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक फिल्म**—द मूवमेंट (अल्फा वेट रॉकर्स)
- **सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एलबम**—द क्लेजिर (डेव चैचल)
- **सर्वश्रेष्ठ गोस्पेल एलबम**—किंगडम बुक वन डीलक्स (मेवरिक सिटी म्यूजिक एक किर्क फ्रैंकलिन)
- **सर्वश्रेष्ठ फॉक एलबम**—रिलीवर (मेडिसन कनिंघम)
- **सर्वश्रेष्ठ हिस्टोरिकल एलबम**—यांकी होटल फॉक्सट्रॉट (चेरिल पावेल्सकी व अन्य)
- **सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो**—ऑल टू वैल : द शार्ट फिल्म (टेलर स्विफ्ट)
- **सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड पोएट्री एलबम**—द पोइट हू सैट बाई द डोर (जे. इवी)

80वें गोल्डन ग्लोब (Golden Globe) पुरस्कार (10 जनवरी, 2023; बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजेल्स, कैलीफोर्निया)

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म :**
  ड्रामा श्रेणी—द फेबलमैंस (The Fabelmans) (**निर्देशक**—स्टीवन स्पीलवर्ग)
  म्यूज़िकल/कॉमेडी श्रेणी—द बंशीज ऑफ इनिशेरिन (The Banshees of Inisherin) (**निर्देशक**—मार्टिन मैकडॉनाघ)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता :**
  ड्रामा श्रेणी—ऑस्टिन बटलर (Austin Butler) (**फिल्म**—एल्विस में भूमिका हेतु)
  म्यूजिकल/कॉमेडी श्रेणी—कोलिन फैरेल (Colin Farrell) (**फिल्म**—'द बंशीज ऑफ इनिशेरिन' में भूमिका हेतु)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री :**
  ड्रामा श्रेणी—केट ब्लैंचेट (Cate Blanchett) (**फिल्म**—'तार' में भूमिका के लिए)
  म्यूजिकल/कॉमेडी श्रेणी—मिशेल येओह (Michelle Yeoh) (**फिल्म**—'एवरीथिंग, एवरी ह्वेयर ऑल एट वंस' में भूमिका हेतु)

दोनों ही श्रेणियों में संयुक्त पुरस्कार

- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**—स्टीवन स्पीलबर्ग (**फिल्म**—द फैबलमैंस के निर्देशन हेतु)
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता**—के हुइ क्वान (Ke Huy Quan) (**फिल्म**—'एवरीथिंग, एवरी ह्वेयर ऑल एट वंस)
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री**—एंजेला बेसेट (**फिल्म**—ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉर एवर)
- **सर्वश्रेष्ठ एनीमेटेड फीचर फिल्म**—गुइलेर्मो डेल टोरांस पिनोचियो
- **गैर-अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म**—अर्जेन्टीना, 1985 (अर्जेन्टीना) {अंग्रेजी भाषा से इतर किसी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की इस श्रेणी में नामांकित 5 फिल्मों में भारत की आरआरआर भी शामिल थी, किन्तु यह पुरस्कार फिल्म अर्जेंटीना को दिया गया.}
- **सर्वश्रेष्ठ पटकथा** (Screenplay)—मार्टिन मैकडॉनाघ (**फिल्म**—द बंशीज ऑफ इनिशेरिन के लिए)
- **सर्वश्रेष्ठ मूल गीत**—'नाटू-नाटू' (**फिल्म**—आरआरआर, भारत)

68वें फिल्म फेयर पुरस्कार, 2023 (27 अप्रैल, 2023; मुम्बई)

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म**—गंगूबाई काठियावाड़ी (**निर्देशक**—संजय लीला भंसाली)
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**—संजय लीला भंसाली (**फिल्म**—गंगूबाई काठियावाड़ी)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**—राजकुमार राव (**फिल्म**—बधाई हो)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**—आलिया भट्ट (**फिल्म**—गंगूबाई काठियावाड़ी)
- **सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेता**—अनिल कपूर (**फिल्म**—जुग-जुग जियो)
- **सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री**—शीबा चड्डा (**फिल्म**—बधाई हो)
- **सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक**—राजेश (फिल्म—लूटकेस)
- **सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक**—अरिजीत सिंह (**फिल्म**—बह्मास्त्र-1, गीत-केसरिया...)
- **सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका**—कविता सेठ (**फिल्म**—जुग-जुग जियो, गीत-रंगीसारी)
- **सर्वश्रेष्ठ गीतकार**—अमिताभ भट्टाचार्य (**फिल्म**—बह्मास्त्र-1, गीत-केसरिया..)
- **सर्वश्रेष्ठ कहानी-फिल्म**—बधाई हो
- **सर्वश्रेष्ठ संवाद**—प्रकाश कपाड़िया व अन्य (**फिल्म**—गंगूबाई काठियावाड़ी)
- **सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन-प्ले फिल्म**—बधाई हो
- **लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार**—प्रेम चोपड़ा

समालोचना (क्रिटिक्स) श्रेणी के पुरस्कार

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म (क्रिटिक्स)**—बधाई हो (**निर्देशक**—प्रतीक वत्स)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स)**—संजय मिश्र (**फिल्म**—वध)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स)**—भूमि पेडनेकर (**फिल्म**—बधाई हो) व तब्बू (**फिल्म**—भूल भूलैया-2)

23वें आइफा (IIFA) पुरस्कार, 2023; 26-27 मई, 2023 (संयुक्त अरब अमीरात)

पॉपुलर श्रेणी के पुरस्कार :

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म**—दृश्यम-2 (**निर्देशक**—अभिषेक पाठक)
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**—आर. माधवन (**फिल्म**—रॉकेट्री : द नांबी इफेक्ट)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**—ऋतिक रोशन (**फिल्म**—विक्रम वेधा)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**—आलिया भट्ट (**फिल्म**—गंगूबाई काठियावाड़ी)
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता**—अनिल कपूर (**फिल्म**—जुग-जुग जियो)
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री**—मौनी राय (**फिल्म**—ब्रह्मास्त्र : पार्ट-1 शिवा)

69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (2021) (24 अगस्त, 2023)

फीचर फिल्म श्रेणी :

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म**—रॉकेट्री : द नांबी इफेक्ट (**निर्देशक**—आर. माधवन)
  {स्वर्ण कमल व निर्माता/निर्देशक प्रत्येक को ₹ 2·50-2·50 लाख नकद}

STUDYPDF WALLAH

- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक** {स्वर्ण कमल व ₹ 2·50 लाख नकद}—निखिल महाजन (**फिल्म**—गोदावरी : द होली वाटर; मराठी)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—अल्लू अर्जुन (**फिल्म**—पुष्पा)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—आलिया भट्ट (**फिल्म**—गंगूबाई काठियावाड़ी) व कृति सेनन (**फिल्म**—मिमी)
- **सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेता** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—पंकज त्रिपाठी (**फिल्म**—मिमी. हिन्दी)
- **सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—पल्लवी जोशी (**फिल्म**—कश्मीर फाइल्स; हिन्दी)
- **सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—काला भैरव (कामिराम भीमुदो, **फिल्म**—आरआरआर, तेलुगू)
- **सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—श्रेया घोषाल (···मायावा चायावा, इरविन निझाल; तमिल)
- **सर्वश्रेष्ठ गीत** (रजत कमल व ₹ 50 हजार नकद)—चन्द्र बोस (**फिल्म**—कोंडा पोलम; तेलुगू)
- **सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म** (रजत कमल के साथ निर्माता व निर्देशक को ₹ 1·50-1·50 लाख नकद)—अनुनाद-द रेजोनेंस, असमी (**निर्देशक**—रीमा बोरा)
- **पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म** (रजत कमल के साथ निर्माता व निर्देशक को ₹ 1·50-1·50 लाख नकद)—आवास व्यूहम, मलयालम (**निर्देशक**—कृष्नद)
- **हिन्दी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म** (रजत कमल व ₹ 1·00 लाख नकद)—सरदार ऊधम सिंह (**निर्देशक**—सुजीत सरकार)

गैर-फीचर फिल्म श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार

- **सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म**—एक था गाँव (निर्माता-निर्देशक : सृष्टि लाखेदा) {स्वर्ण कमल व ₹ 1·50 लाख नकद}
- **किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म**—अंकित कोठारी (**फिल्म**—पांचिका) {रजत कमल व ₹ 75 हजार नकद}

सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार

- **सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक**—म्यूजिक बाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल : द इनक्रेडिबली मेलोडियस जर्नी (**लेखक**—राजीव विजयाकर) {स्वर्ण कमल व ₹ 75 हजार नकद}
- **सर्वश्रेष्ठ आलोचक**—पुरुषोत्तम चारियुलु (तेलुगू) {स्वर्ण कमल व ₹ 75 हजार नकद}

76वें कान (Cannes) फिल्मोत्सव के पुरस्कार (2023) (16–27 मई, 2023; कान, फ्रांस)

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म** (Palm d'Or)—एनाटॉमी ऑफ द फॉल (**निर्देशक**—जस्टिन ट्रीट)
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**—ट्रान आन्ह हुंग (**फिल्म**—The Pot-a-feul)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**—कोजी याकुशो, जापान (**फिल्म**—परफेक्ट डेज)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**—मर्वे डिजदार, टर्की (**फिल्म**—अबाउट ड्राई ग्लासेस)
- **गोल्डन कैमरा पुरस्कार** (Camera d'Or)—इनसाइड द येलो कोकू शैल (**निर्देशक**—फाम थीन एन, वियतनाम)

पुलित्जर पुरस्कार, 2023
(घोषणा—8 मई, 2023)

पत्रकारिता

- **जनसेवा** (Public Service)—एसोसिएटेड प्रेस
- **ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग**—लॉस एंजेल्स टाइम्स का स्टाफ
- **इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग**—वॉल स्ट्रीट जनरल का स्टाफ
- **नेशनल रिपोर्टिंग**—वाशिंगटन पोस्ट की पत्रकार कैरोलिन किचनर
- **इंटरनेशनल रिपोर्टिंग**—न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ (गत वर्ष भी)
- **फीचर फोटोग्राफी**—लॉस एंजेल्स टाइम्स का क्रिस्टीना हाउस

पुस्तकें, ड्रामा एवं संगीत

- **फिक्शन**—ट्रस्ट (हरनाम डियाज) व डेमोन कॉपरहैड (बारबरा किंग सोल्वर)
- **ड्रामा**—English (सानाज टोसी)
- **पोएट्री**—Then the War : And Selected Poems 2007–2020 (कार्ल फिलिप्स)
- **बायोग्राफी**—G. Man : J Edgar Hoover and the Making of American Century (बेवर्ली गेज)

95वें अकादमी (ऑस्कर) पुरस्कार–2023
(12 मार्च, 2023; लॉस एंजेल्स, अमरीका)

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म**—एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस (**निर्देशक**—डेनियल क्वान व डेनियल शीइनर्ट)
  2022—कोडा (Coda) (**निर्देशक**—सियान हेडर)
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**—डेनियल क्वान व डेनियल शीइनर्ट (**फिल्म**—एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता**—ब्रेंडन फ्रेजर (Brendan Frazor) (**फिल्म**—द ह्वेल)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**—मिशेल योह (मलेशियाई अभिनेत्री) (**फिल्म**—एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस)
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता** (सपोर्टिंग रोल)—के हुए क्वान (K Huy Quan) (**फिल्म**—एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस)
- **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री** (सपोर्टिंग रोल)—जेमी ली कर्टिस (**फिल्म**—एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस)
- **सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म**—ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट (जर्मनी) {सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में प्रतिस्पर्द्धा हेतु पान नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म द छेल्लो शो (The Chhello Show) इस वर्ष भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, जो नामांकित फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी.}
- **सर्वश्रेष्ठ एनीमेटेड फिल्म**—गुइलेर्मो डेल टोरोस पिन्नोचियो
- **सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री (फीचर)**—नवलनी (Navalny) {इस श्रेणी में भारतीय फिल्म 'ऑल दैट ब्रीथ्स' भी नामांकित थी, जो पुरस्कार से वंचित रही.}
- **सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी**—जेम्स फ्रेड {ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट}
- **सर्वश्रेष्ठ परिधान डिजाइनिंग** (Costume Design)—रूथ ई. कार्टर
- **सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री** (शार्ट सबजेक्ट)—द एलीफेंट ह्वीस्पर्स (**निर्देशिका**—कार्तिकी गोंजाल्विस व **निर्माता**—गुनीत मोंगा)
- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग**—एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस
- **सर्वश्रेष्ठ संगीत** (ओरिजिनल स्कोर)— वोल्कर बर्टेल मान्न (**फिल्म**—ऑल क्वाइट ऑन·····)
- **सर्वश्रेष्ठ संगीत** (ओरिजिनल सांग)—नाटू-नाटू (**फिल्म**—आरआरआर)
- **सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म** (लाइव एक्शन)—एन आयरिश गुड बॉय
- 95वें अकादमी (ऑस्कर) पुरस्कारों के तहत् फिल्म 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस' को विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त हुए.
- फिल्म 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस' सर्वाधिक 11 श्रेणियों में नामांकित हुई थी.

STUDYPDF WALLAH

☞ **संगीत**—Omar (रियानॉन गिडेन्स व माइकल एबेल्स)

बहुचर्चित नवीनतम पुस्तकें

कोचिंग बियॉंड : माई डेज़ विद द इंडियन क्रिकेट टीम (Coaching Beyond : My Days with the Indian Cricket Team)—आर. श्रीधर, आर. कौशिक

एटोमिक हैबिट्स (Atomic Habits)—जेम्स क्लीयर

टर्म्स एण्ड कंडीशंस (Terms and Conditions)—लॉरेन एशर

दोगलापन : द हार्ड ट्रुथ अबाउट लाइफ एण्ड स्टार्ट अप्स (Doglapan : The Hard Truth about Life and Starts Ups)—अशनीर ग्रोवर

राइटिंग फॉर माई लाइफ (Writing for My Life)—रस्किन बॉंड

गौतम अडानी : रीइमैजिनिंग बिज़नेस इन इंडिया एण्ड द वर्ल्ड (Gautam Adani : Reimagining Business in India and the World)—आर. एन. भास्कर

स्पेयर (Spare Memoir) (आत्मकथा)—प्रिंस हैरी (द ड्यूक ऑफ सक्सेस)

पंचफोरन—डॉ. सूर्यनारायण पाण्डेय

विक्ट्री सिटी (Victory City)—सलमान रुश्दी

नैवर नैवर (Never Never)—कोलीन हूवर एवं टैरीन फिशर

होम कमिंग (Home Coming)—केट मॉर्टन

लोक मांझे संगति (मराठी)—शरद पवार (आत्मकथा)

हैप्पी प्लेस (Happy Place)—एमिली हेनरी

ब्लड मेरिडियन, ऑल द प्रिटीहॉर्सेज तथा द ऑर्चर्ड कीपर—कार्मेक मैक्कार्थी (अमरीकी उपन्यासकार, 13 जून, 2023 को निधन)

हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड (How the best Leaders Lead)—ब्रायन ट्रेसी

स्मोक एण्ड एशेज़ (Smoke and Ashes)—अमिताभ घोष

हैप्पी प्लेस (Happy Place)—एमिली हेनरी

थ्रू द ब्रोकेन ग्लास : एन ऑटोबायोग्राफी (Throgh the Broken Glass : An Autobiography)—टी.एन. शेषन

द्रौपदी मुर्मू : फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैण्ड्स टु रायसीना हिल (Droupadi Murmu : From Tribal Hinterlands to Raisina Hill)—कस्तूरी रे

मैडम प्रेजीडेंट : द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू (Madam President : The Biography of Droupadi Murmu—सदीप साहू

बिफोर वी वर इनोसेंट (Before we were Innocent)—इला बर्मन

मिराकिल मेकर्स : इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक (Miracil Makers : Indian Cricket's Greatest Epic)—भरत सुंदरेसन व गौरव जोशी

इंडिया राइजिंग : मेमोइर ऑफ ए साइंटिस्ट (India Rising : Memoir of a Scientist)—आर. चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा

द गोल्डन ईयर्स : द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग एण्ड गुड लॉंग लाइफ (The Golden Years : The Many Joys of Living and Good Long Life)—रस्किन बॉंड

द हीरो ऑफ कुमायूँ : द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट (The Hero of Kumaon : The Life of Jim Corbett)—डफ हार्ट-डेविस

स्मोक एण्ड एशेज (Smoke and Ashes)—अमिताभ घोष

द एक्सचेंज (The Exchange)—जॉन ग्रीशम

एलन मस्क (Elon Musk)—वाल्टर इसाक्सॉन

नोबेल पुरस्कार–2023

***पुरस्कारों की घोषणा**—अक्टूबर 2023 (विभिन्न तिथियों में)*
***वितरण**—10 दिसम्बर, 2023*
- ***वितरण स्थल—शांति का**—ओस्लो*
  ***शेष सभी**—स्टॉकहोम*

***साहित्य**—जॉन ओलाव फॉसे (John Olav Fosse) {नॉर्वे}*
***2022**—एनी एरनॉक्स (Annie Ernaux) {फ्रांस}*
***शांति**—नरगिस मोहम्मदी {ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता}*
***2022**—एलेस बियालियात्सकी {बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता} व दो संस्थाओं—मेमोरियल, रूस तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन को*
***चिकित्सा**—कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन {अमरीका}*
***रसायन विज्ञान**—एलेक्सी आई. एकीमो, लुइस ई. ब्रूस तथा मोंगी जी. बावेंडी*
***भौतिक विज्ञान**—पियरे एगोस्टिनी {अमरीका}, फेरेन्क क्रॉस्ज {जर्मनी} तथा एनी एल ह्युलियर {स्वीडन}*
***अर्थशास्त्र**—क्लाउडिया गोल्डिन (Claudia Goldin) {अमरीका}*

बुकर पुरस्कार–2023 के लिए अल्पसूचीबद्ध (Short List) 6 पुस्तकें

(21 सितम्बर, 2023 को अल्पसूचीबद्ध)

पुस्तक का नाम	लेखक
वेस्टर्न लेन (Western Lane)	चेतन मारू (भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका)
प्रोफेट साँग (Prophet Song)	पॉल लिंच (आयरलैण्ड)
बी स्टिंग (Bee Sting)	पॉल मुरे (आयरलैण्ड)
स्टडी फॉर ओबीडिएंस (Study for Obedience)	सारा बर्नस्टीन (कनाडा)
इफ आई सर्वाइव यू (If I Survive You)	जोनाथन एस्कॉफ्री (अमरीका)
दिस अदर ईडन (This Other Eden)	पॉल हॉर्डिंग

यू मस्ट नो योअर कॉन्स्टीट्यूशन (You Must Know Your Constitution)—फाली एस. नरीमन

वी आल्सो मेक पॉलिसी (We Also Make Policy)—सुभाष चंद्र गर्ग

अनब्रोकेन : द अनटोल्ड स्टोरी (Unbroken : The Untold Story)—इन्द्राणी मुखर्जी

मेमोइर्स ऑफ ए मैवेरिक (Memoirs of a Maverick)—मणिशंकर अय्यर

हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड (How Prime Ministers Decide)—नीरजा चौधरी

विशिष्ट नियुक्तियाँ/निर्वाचन/मनोनयन

☞ **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के अध्यक्ष**—न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (22 अगस्त, 2023)

☞ **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII—Confederation of Indian Industry) के अध्यक्ष**—आर. दिनेश (जून 2023) {सत्र 2023-24 के लिए}

☞ **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अध्यक्ष**—सिद्धार्थ मोहंती (अप्रैल 2023 (29 जून, 2024 तक के लिए)

☞ **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष**—डॉ. मनोज सोनी (16 मई, 2023)

☞ **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक**—अमरेंदु प्रकाश (31 मई, 2023)

STUDYPDF WALLAH

- **नैस्कॉम (NASSCOM) के अध्यक्ष**—अनन्त माहेश्वरी (सत्र 2023-24 के लिए)
- **बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक सह सीईओ (MD & CEO)**—देबदत्त चंद (जुलाई 2023)
- **बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह सीईओ (MD & CEO)**—रजनीश कर्नाटक (मई 2023)
- **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (SECI) के प्रबंध निदेशक**—अजय यादव (जून 2023)
- **इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के प्रबंध निदेशक**—कमल किशोर चटीवाल (जून 2023)
- **हिंदुजा समूह के अध्यक्ष**—गोपीचन्द हिंदुजा (जून 2023)
- **द हिन्दू ग्रुप पब्लिशिंग प्रा.लि. के निदेशक मण्डल की अध्यक्ष**—निर्मला लक्ष्मण (जून 2023)
- **यूको बैंक के प्रबंध निदेशक**—अश्विनी कुमार (जून 2023)
- **टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक सह सीईओ (CEO)**—टी. वी. नरेन्द्रन (19 सितम्बर, 2023 से सितम्बर, 2028 तक के लिए पुनर्नियुक्त)
- **कोल इंडिया लिव (CIL) चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक**—पी. एम. प्रसाद (1 जुलाई, 2023)

विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष/महासचिव

- ***समाजवादी पार्टी***—*अखिलेश यादव*
- ***माकपा (CPI-M) के महासचिव***—*सीताराम येचुरी*
- ***भाजपा (BJP) के अध्यक्ष***—*जगत प्रकाश नड्डा (जनवरी 2023 (कार्यकाल में वृद्धि)*
- ***पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष***—*महबूबा मुफ्ती (अक्टूबर 2023 में पुनर्निर्वाचित)*

- **विश्व बैंक के अध्यक्ष**—अजय बंगा (मई 2023)
- **रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के महानिदेशक**—मनोज यादव (1 अगस्त, 2023)
- **केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त** (CVC—Central Vigilance Commissioner)—प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (29 मई, 2023)
- **देश के मुख्य न्यायाधीश :**
  49वें—न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (27 अगस्त, 2022–8 नवम्बर, 2022 तक)
  50वें—न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (9 नवम्बर, 2022 से)
- **ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस (ABC) के अध्यक्ष**—श्रीनिवासन के स्वामी (सितम्बर 2023; सत्र 2023-24 के लिए)
- **फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (FTII) के अध्यक्ष**—आर. माधवन (सितम्बर 2023; तमिल व हिन्दी फिल्मों के अभिनेता)
- **रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन सह सीईओ**—जया वर्मा सिन्हा (सितम्बर 2023)

अविस्मरणीय निधन (राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय)

राष्ट्रीय (National)

शरद यादव (12 जनवरी, 2023)—जनता दल (यू) के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री

अगम प्रसाद माथुर (25 जनवरी, 2023)—राधा स्वामी मत के पाँचवें धर्म गुरु

मंदीप रॉय (29 जनवरी, 2023)—कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता

के. विश्वनाथ (2 फरवरी, 2023)—दक्षिण भारत के जाने-माने फिल्म निर्माता

वाणी जयराम (4 फरवरी, 2023)—प्रसिद्ध पार्श्व गायिका

जावेद खान अमरोही (14 फरवरी, 2023)—बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता

नंदमुरी तारक रत्न (18 फरवरी, 2023—तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता

सतीश कौशिक (9 मार्च, 2023)—बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता-निर्देशक, पटकथा लेखक

सलीम दुर्रानी (2 अप्रैल, 2023)—चर्चित क्रिकेटर

प्रकाश सिंह बादल (25 अप्रैल, 2023)—पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक

कौर सिंह (27 अप्रैल, 2023)—बीते वर्षों के जाने-माने भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज

जैमिनी शंकरन (23 अप्रैल, 2023)—भारतीय सर्कस के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्कस कलाकार

समरेश मजूमदार (8 मई, 2023)—प्रसिद्ध बांग्ला लेखक

आमिर रजा हुसैन (3 जून, 2023)—रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता

सुलोचना नाटकर (4 जून, 2023)—प्रसिद्ध अभिनेत्री-माँ की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध

नंबूथिरी (7 जुलाई, 2023)—केरल के प्रसिद्ध मूर्तिकार व चित्रकार

डॉ. मंगला नार्लिकर (17 जुलाई, 2023)—प्रसिद्ध गणितज्ञ

ओमान चांडी (18 जुलाई, 2023)—वरिष्ठ कांग्रेसी नेता

अरुण कुमार सिन्हा (6 सितम्बर, 2023) – स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के निदेशक

सरोजा वैद्यनाथन (21 सितम्बर, 2023) – प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना

एम.एस. स्वामीनाथन (28 सितम्बर, 2023)—भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध महान् कृषि वैज्ञानिक

उस्ताद अजी जकी हैदर (सितम्बर 2023)—प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक.

मनोहर सिंह गिल (15 अक्टूबर, 2023)—भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

बिशन सिंह बेदी (22 अक्टूबर, 2023)—बीते वर्षों के महान् क्रिकेटर

सुब्रत राय उर्फ सहाराश्री (14 नवम्बर, 2023)—सहारा इंडिया के संस्थापक

कतिपय राज्यों के नए मुख्यमंत्री

- ***कर्नाटक :*** *सिद्धारमैया (20 मई, 2023)*
- ***त्रिपुरा :*** *डॉ. माणिक साहा (8 मार्च, 2023; दूसरी बार)*
- ***मेघालय :*** *कोनराड संगमा (7 मार्च, 2023; लगातार दूसरी बार)*
- ***नगालैण्ड :*** *नीफ्यू रियो (5 मार्च, 2023; पाँचवीं बार मुख्यमंत्री)*

विभिन्न देशों के नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष (वर्ष 2023)

- ***ब्राजील के राष्ट्रपति***—*लुइज इनालियो लूला डी सिल्वा (निर्वाचन—अक्टूबर 2022; कार्यभार—1 जनवरी, 2023 से)*
- ***निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स***—*साइप्रस के राष्ट्रपति (12 फरवरी, 2023)*
- ***शी जिनपिंग***—*चीन के राष्ट्रपति (10 मार्च, 2023; तीसरे कार्यकाल के लिए)*
- ***रामचंद्र पौडेल***—*नेपाल के राष्ट्रपति (9 मार्च, 2023)*
- ***शहाबुद्दीन चुप्पू***—*बांग्लादेश के राष्ट्रपति (23 अप्रैल, 2023)*
- ***रेसेप तैयप एर्दोगन***—*तुर्किए (टर्की) के राष्ट्रपति (मई 2023; पुनर्निर्वाचित)*
- ***पेटेरी ओर्पो***—*फिनलैण्ड के प्रधानमंत्री (20 जून, 2023; 47वें प्रधानमंत्री)*
- ***एमर्सन मनांगाग्वा***—*जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति (चुनाव—23 अगस्त, 2023; कार्यभार—4 सितम्बर, 2023)*
- ***थर्मन शनमुगरत्नम***—*सिंगापुर के राष्ट्रपति (चुनाव—1 सितम्बर, 2023; कार्यभार—16 सितम्बर, 2023)*

STUDYPDF WALLAH

अन्तर्राष्ट्रीय (International)

परवेज़ मुशर्रफ (5 फरवरी, 2023)—पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह व पूर्व राष्ट्रपति

तारिक फतेह (24 अप्रैल, 2023)—पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक एवं स्तम्भकार

रॉबर्ट ई. लुकास जूनियर (15 मई, 2023)—प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री

कॉर्मेक मैक्कार्थी (13 जून, 2023)—प्रसिद्ध अमरीकी उपन्यासकार

ग्लेंडा जैक्सन (15 जून, 2023)—प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री

सी.आर. राव (22 अगस्त, 2023)—भारतीय मूल के अमरीकी गणितज्ञ

येवगेनी प्रिगोझिन (23 अगस्त, 2023)—पूर्व वर्षों में रूसी राष्ट्रपति के घनिष्ठ समर्थक

हीथ स्ट्रीक (3 सितम्बर, 2023)—जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान

जियोर्जियो नेपोलितानो (13 अक्टूबर, 2023)—इटली के पूर्व राष्ट्रपति

मार्टी अहमिसारी (16 अक्टूबर, 2023)—फिनलैण्ड के पूर्व राष्ट्रपति

ली केक्यांग (27 अक्टूबर, 2023)—चीन के पूर्व प्रधानमंत्री

बहुचर्चित व्यक्ति (राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय)

मनीष सिसौदिया—दिल्ली प्रशासन की वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने 'आप' सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया.

दीपिका पादुकोण—मई 2023 में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अमरीका की चर्चित पत्रिका 'टाइम' (Time) ने अपने मुखपृष्ठ पर स्थान दिया. दीपिका वर्ष 2018 में इस पत्रिका द्वारा प्रकाशित विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल थीं.

कैप्टेन शिवा चौहान—भारतीय थल सेना के फायर एण्ड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टेन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है. इस पोस्ट पर तैनात होने वाली वह पहली महिला हैं. इसके लिए कैप्टेन शिवा चौहान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह भारत की नारी शक्ति को दर्शाते हुए प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा.

शालिजा धामी—भारतीय वायु सेना के इतिहास में पहली बार किसी लड़ाकू यूनिट की कमान एक महिला अधिकारी को दी गई है. यह श्रेय ग्रुप कैप्टेन शालिजा धामी को प्राप्त हुआ. उन्हें पश्चिमी क्षेत्र में एक अग्रिम मोर्चे का दायित्व मार्च 2023 में सौंपा गया.

कामी रीता शेरपा—नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा मई 2023 में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे. दो दशकों से अधिक समय तक गाइड कामी रीता शेरपा ने पहली बार 1994 में 8,848 मीटर की चोटी पर चढ़ाई की थी.

वर्ष 2023 में भारत यात्रा पर आए कुछ विशिष्ट अतिथि

- ***जॉर्जिया मेलोनी***—*इटली की प्रधानमंत्री (2–3 मार्च, 2023)*
- ***एंथनी एल्बानीस***—*आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री (8–11 मार्च, 2023)*
- ***फुमियो किशिदा***—*जापान के प्रधानमंत्री (20–21 मार्च, 2023)*
- ***जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक***—*भूटान नरेश (3–5 अप्रैल, 2023)*
- ***एली कोहेन***—*इजरायल के विदेश मंत्री (9–11 मई, 2023)*
- ***पुष्प कमल दहल प्रचण्ड***—*नेपाल के प्रधानमंत्री (31 मई–3 जून, 2023)*
- ***रानिल विक्रमसिंघे***—*श्रीलंका के राष्ट्रपति (20–21 जुलाई, 2023)*

वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि

गणतंत्र दिवस समारोह में किसी-न-किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करने की परम्परा भारत में रही है. वर्ष 2023 के भारत के 74वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था.

वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राएं—एक दृष्टि में

देश का नाम	अवधि
जापान	*19–21 मई, 2023*
पापुआ न्यू गिनी	*21 मई, 2023*
अमरीका व मिस्र	*20–24 जून, 2023*
फ्रांस	*13–14 जुलाई, 2023*
ग्रीस	*22–24 अगस्त, 2023*
इण्डोनेशिया	*5–7 सितम्बर, 2023*

अक्षय कुमार—बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म अभिनेता एवं निर्माता अक्षय कुमार को अब पुनः भारत की नागरिकता अगस्त 2023 में प्राप्त हो गई. अमृतसर में 1967 में जन्मे अक्षय कुमार, जिनका मूल नाम राजीव हरी ओम भाटिया है, ने कुछ फिल्में फ्लॉप होने पर कनाडा की नागरिकता 2011 में ले ली थी. बाद में पुनः भारतीय नागरिकता के लिए औपचारिक आवेदन 2019 में उन्होंने किया था.

सुर्खियों में स्थान (राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय)

जोशीमठ—पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड के चमोली जिले में वर्ष 2023 की शुरूआत में ही जोशीमठ में जमीन धँसने के कारण जमीन धसने की घटना.

अमृत उद्यान—आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया है. 27 जनवरी, 2023 को प्रातः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नया नामकरण किया.

नर्मदापुरम्—यह पश्चिमी मध्य रेलवे के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम है. जनवरी 2023 में भारतीय रेलवे ने यह नामकरण किया. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम फरवरी 2022 में ही नर्मदापुरम् कर दिया गया था. अब इसके रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम् किया गया है.

सम्मेद शिखर—जैन समुदाय के पवित्र स्थल श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने की 3 वर्ष पुरानी अधिसूचना को केन्द्र सरकार ने 5 जनवरी, 2023 को वापस ले लिया. इससे झारखण्ड में गिरडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित यह स्थल पूर्ववत् तीर्थ स्थल ही बना रहेगा. जैन अनुयायियों के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी. 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था.

कोच्चि फिशिंग हार्बर—11 जून, 2023 को केरल के थोप्पुमपडी में कोच्चि फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यों की आधारशिला रखी गई. यह परियोजना अनुमानित लागत ₹ 140·35 करोड़ की राशि से विकसित की जा रही है.

ज्ञानवापी—4 अगस्त, 2023 को वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई से सर्वेक्षण कराने पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने एएसआई को सर्वेक्षण की अनुमति के फैसले में दखल देने से मना करते हुए एएसआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में किसी तरह की खुदाई से किसी भी संरचना को नुकसान नहीं पहुँचे.

STUDYPDF WALLAH

केरलम

9 अगस्त, 2023 को केरल विधान सभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर 'केरलम' करने का केन्द्र से अनुरोध करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया. यह प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया था. इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा—यूडीएफ ने बिना किसी संशोधन या सुझाव दिए स्वीकार कर लिया.

नूंह—यह हरियाणा का एक स्थान है. जुलाई-अगस्त 2023 में नूंह हिंसा के कारण समाचारों के सुर्खियों में बना रहा. नूंह अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाने के कारण भी चर्चा में रहा.

बर्लिन—17–25 जून, 2023 के दौरान जर्मनी के बर्लिन में 16वें विशेष ओलम्पिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित हुए.

न्यूयॉर्क—अप्रैल 2023 में लंदन में जारी हेनली एण्ड पार्टनर्स की रिपोर्ट में न्यूयॉर्क शहर को वर्ष 2023 में विश्व का सबसे अमीर शहर बताया गया है. दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः टोक्यो (जापान) और सिलिकॉन वैली हैं.

फिनलैण्ड—तुर्की की स्वीकृति के बाद अप्रैल 2023 में फिनलैण्ड 'नाटो' (NATO—North Atlantic Treaty Organisation) का 31वाँ सदस्य बन गया.

विश्वनाथ घाट—सितम्बर 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने असम में विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में घोषित किया. विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित विश्वनाथ घाट को 'गुप्त काशी' के नाम से भी जाना जाता है.

ऑपरेशन/अभियान

वरुण-XXI

16–20 जनवरी, 2023 के दौरान पश्चिमी समुद्र तट पर भारत व फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 'वरुण' सम्पन्न हुआ. यह इस शृंखला का 21वाँ संस्करण (वर्ष 1993 में प्रारम्भ) था. दोनों देशों के युद्धपोतों व नौकाओं ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया. 5 दिन के इस संयुक्त अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की इकाइयों ने समुद्र में अपने युद्ध विरोधी कौशल को और निखारने का प्रयास किया.

साइक्लोन-I (Cyclone-I)

14-27 जनवरी, 2023 के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत व मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन-I सम्पन्न हुआ. यह सैन्याभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला ही संयुक्त अभ्यास था. इसके तहत् रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवराना कौशल को एक-दूसरे से साझा किया गया. इस संयुक्त अभ्यास में आतंकवाद विरोधी, टोह लगाना, धावा बोलना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया था.

ऑपरेशन दोस्त

फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में तुर्किये व सीरिया में आए भीषण भूकम्पों से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई. इस दुःखद आपदा के समय राहत कार्यों में हाथ बटाने के लिए भारत ने विशेष टीम वहाँ 7 फरवरी, 2023 को ही रवाना की, जिसमें एनडीआरएफ के सदस्यों के अतिरिक्त सेना, वायु सेना व अन्य विभागों के जवान जिनमें कुछ महिला कर्मी भी शामिल थे. इनके लिए रातों-रात पासपोर्ट विदेश विभाग ने तैयार किए तथा वीज़ा की व्यवस्था की. भारत के इस राहत मिशन को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था. इसके तहत् भारतीय दल ने एक सप्ताह से भी अधिक समय तक रहकर राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग किया.

ऑपरेशन कावेरी

गृह युद्ध से ग्रसित सूडान में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया था. यह उसी तर्ज पर चलाया गया जैसे कि युद्ध से ग्रसित यूक्रेन में फँसे भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था.

स्लाइनेक्स, 2023 (SLINEX, 2023)

3–8 अप्रैल, 2023 के दौरान कोलम्बो के तट पर भारत व श्रीलंका का द्विपक्षीय वार्षिक नौसैनिक अभ्यास 'स्लाइनेक्स' सम्पन्न हुआ. यह इस शृंखला का 10वाँ संस्करण था. भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस किस्टन व आईएनएस सावित्री ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया. 'स्लाइनेक्स, 2023' का पहला बंदरगाह चरण 3–5 अप्रैल, 2023 के दौरान व दूसरा समुद्री चरण 6–8 अप्रैल, 2023 के दौरान सम्पन्न हुआ.

कोप इंडिया, 2023 (Cope India, 2023)

10–24 अप्रैल, 2023 के दौरान पश्चिम बंगाल में कलाइकुंडा में भारत व अमरीका की वायु सेनाओं का का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'कोप इंडिया' सम्पन्न हुआ. इस संयुक्त अभ्यास में जापान वायु आत्मरक्षा

विशिष्ट राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ आयोजनों के कारण चर्चित स्थल

स्थान	बहुचर्चित सम्मेलन/आयोजन (अवधि)
नई दिल्ली	*शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक (28 अप्रैल, 2023) जी-20 का 18वाँ शिखर सम्मेलन (9-10 सितम्बर, 2023)*
इन्दौर	*17वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (8–10 जनवरी, 2023)*
हिरोशिमा (जापान)	*चार सदस्यीय क्वाड (QUAD) का शिखर सम्मेलन (20 मई, 2023)*
विनियस (Vinius) (लिथुआनिया)	*नाटो (NATO) का शिखर सम्मेलन (11-12 जुलाई, 2023)*
पटना (बिहार)	*जी-20 देशों की पहल पर एल-20 शिखर सम्मेलन {21–23 जून, 2023}*
कोलम्बो (श्रीलंका)	*ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की 67वीं कन्वेंशन (6–9 जुलाई, 2023)*
जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)	*15वाँ ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन (22–24 अगस्त, 2023)*
पेरिस (फ्रांस)	*ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल (26 जुलाई –11 अगस्त, 2024)*
जकार्ता (इण्डोनेशिया)	*आसियान का 43वाँ शिखर सम्मेलन (5–7 सितम्बर, 2023) 18वाँ पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (7 सितम्बर, 2023) आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (7 सितम्बर, 2023)*
गोवा	*भारत का पहला लाइटहाउस महोत्सव (23 सितम्बर, 2023) भारत का 54वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (20–28 नवम्बर, 2023)*

STUDYPDF WALLAH

बल (Japan Air Self Defence Force) ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था.

दुस्तलिक

20 फरवरी–5 मार्च, 2023 के दौरान विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) में भारत की सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण सम्पन्न हुआ. उज्बेकिस्तान व भारतीय सेना के 45-45 सैनिक इस अभ्यास में शामिल थे. भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इन्फैंट्री बटालियन के सैनिक शामिल थे. इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक सम्बन्धों को बढ़ावा देना था. इस अभ्यास का पहला संस्करण नवम्बर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था.

इनियोचोस, 2023 (Iniochos, 2023)

24 अप्रैल–4 मई, 2023 के दौरान ग्रीस की वायु सेना हेलेनिक एयर फोर्स की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास इनियोचोस, 2023 ग्रीस के आंद्राविडा एयरबेस पर सम्पन्न हुआ. भारत भी इसमें भागीदार था. भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई एमकेआई तथा 2 सी-17 विमान इसमें शामिल रहे.

अभ्यास ओरिअन, 2023 (Exercise Orian, 2023)

17 अप्रैल–5 मई, 2023 के दौरान फ्रांस की एयर एण्ड स्पेस फोर्स (FASF) के मॉन्ट डे मारसन स्थित वायु सेना बेस स्टेशन में बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरिअन सम्पन्न हुआ. भारतीय वायु सेना व फ्रांस की फ्रेंच एयर एण्ड स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैण्ड्स, ब्रिटेन, स्पेन व अमरीका की वायु सेनाओं ने इसमें भाग लिया. इस बहुपक्षीय अभ्यास में भागीदारी के लिए भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में चार राफेल विमान, 2सी-17 व 2 II 78 विमानों के साथ 165 वायु सैनिक शामिल किए गए थे. **भारतीय वायु सेना के राफेल विमानों का यह पहला ही विदेशी अभ्यास था.**

अजेय वॉरियर, 2023

27 अप्रैल–11 मई, 2023 के दौरान ब्रिटेन के सैलिस बेरी ग्राउण्ड में भारत व ब्रिटेन के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर-2023 सम्पन्न हुआ. यह इस शृंखला का सातवाँ आयोजन था. यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास भारत व ब्रिटेन में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है. इस अभ्यास का पिछला संस्करण भारत में उत्तराखण्ड में चौबटया में अक्टूबर 2021 में आयोजित हुआ था.

जिमेक्स-2023 (JIMEX-2023)

5–10 जुलाई, 2023 के दौरान विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय नौसेना तथा जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) के संयुक्त अभ्यास 'जिमेक्स' का सातवाँ संस्करण सम्पन्न हुआ. इसमें पहले तीन दिन बन्दरगाह चरण के कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुए, जबकि बाद में समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास सम्पन्न हुआ. वर्ष 2022 में जापान में प्रारम्भ हुए इस संयुक्त अभ्यास का पिछला छठा संस्करण सितम्बर 2022 में विशाखापट्टनम व बंगाल की खाड़ी में ही सम्पन्न हुआ था.

ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस-2023

10–12 जुलाई, 2023 के दौरान सेशेल्स के तट पर सम्पन्न अमरीका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स के रक्षा बलों व समुद्री पुलिस तथा EUNAVFOR (European Union Naval Force) देशों के संयुक्त समुद्री बलों के साथ भारत ने भी एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रडिनेस में भाग लिया. भारत की ओर से आईएनएस सुनयना ने इसमें भागीदारी की.

नोमैडिक एलीफेंट-2023

जुलाई 2023 में भारत व मंगोलिया के सैनिक नोमैडिक एलीफेंट-2023 नाम से द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुए. यह द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास इस नाम के अभ्यास का 15वाँ संस्करण था. यह संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज मंगोलिया के उलानबटार में सम्पन्न हुई. नोमैडिक एलीफेंट एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित होता है. इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था.

युद्ध अभ्यास-2023

भारत व अमरीकी सेनाओं के संयुक्त वार्षिक 'युद्ध अभ्यास' का 19वाँ संस्करण अमरीका में फोर्ट वेनराइट अलास्का में 25 सितम्बर-8 अक्टूबर, 2023 के दौरान सम्पन्न हुआ. दोनों देशों के बीच 'युद्ध अभ्यास' का 18वाँ संस्करण नवम्बर 2022 में भारत में उत्तराखण्ड में ऑली में आयोजित किया गया था.

कतिपय विशिष्ट टिप्पणियाँ (वर्ष 2023)

गंगा डॉल्फिन

अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया. उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित करने का निर्णय 'मेरी गंगा, मेरी डॉल्फिन-2023' अभियान का शुभारम्भ करते हुए किया गया. उत्तर प्रदेश में गांगेय डॉल्फिन की अनुमानित आबादी वर्तमान में लगभग 2000 है.

बिपरजॉय (Biperjoy)

जून 2023 के पूर्वार्द्ध में अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई. 15 जून, 2023 की रात्रि में गुजरात के तट से टकराए इस चक्रवात की तेज हवाओं से हजारों गाँवों में बिजली के खम्भे गिए गए तथा अंधेरा छा गया. बड़ी संख्या में पेड़ उखड़कर धाराशायी हो गए. तूफान के चलते द्वारका, जामनगर, भावनगर, बनासकाठा व मोरबी जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. बिपरजॉय 15 जून, 2023 को सौराष्ट्र व कच्छ पहुँचने के पश्चात् 18 जून, 2023 तक कमजोर पड़ गया था.

गैब्रियल (Gabrielle)

फरवरी 2023 के मध्य में न्यूजीलैण्ड में गैब्रियल नाम के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ने भारी तबाही मचाई. चक्रवाती तूफान के चलते देश के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ व भूस्खलन की घटनाएं हुईं. साथ ही, 13 फरवरी, 2023 को भीषण वर्षा से 60 हजार से अधिक घरों में पानी घुस जाने से बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए तथा 40 हजार से अधिक घरों में बिजली बंद हो गई. इस भीषण आपदा में आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस (Chris Hipkins) ने 14 फरवरी, 2023 को की.

विभिन्न वर्ष के रूप में घोषित वर्ष 2022, 2023 व आगामी वर्ष

2022

- कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्यपालन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष *(International Year of Artisonal Fisheries and Aquaculture) (संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित)*
- चीन में 'चीते का वर्ष' *(Year of the Tiger)*

2023

- ज्वार-बाजरा का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष (इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट) *{खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा घोषित}*
- चीन में 'खरगोश का वर्ष' *(Year of the Rabbits)*

देश में सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज

देश में सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊँचे पोल पर लहराया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित इस राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने 19 अक्टूबर, 2023 को किया.

●●●

STUDYPDF WALLAH

खेलकूद

टेनिस (Tennis)

आस्ट्रेलियाई ओपन–2023 {16–29 जनवरी, 2023; मेलबर्न (111वाँ आयोजन (ओपन युग में 55वाँ)}

पुरुष एकल–

विजेता–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

उपविजेता–स्टेफानोस सितसिपास (ग्रीस)

☞ **2021**–नोवाक जोकोविच (सर्बिया)

☞ **2022**–राफेल नडाल (स्पेन)

महिला एकल–

विजेता–आर्यना सबालेंका (बेलारूस)

उपविजेता–एलेना रिबाकिना (कजाखस्तान)

☞ **2021**–नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) (जापान)

☞ **2022**–एश्ले बार्टी (आस्ट्रेलिया)

पुरुष युगल–

विजेता–रिंकी हिजिकाता व जैसन कूबलर (दोनों आस्ट्रेलिया)

उपविजेता–ह्यूगो निस (मोनाको) व जान जीलिंस्की (दोनों आस्ट्रेलिया)

महिला युगल–

विजेता–बारबोरा क्रेजीकोवा व कैटेरिना सिनियाकोवा (दोनों चेक गणराज्य)

उपविजेता–शूको आओयामा व इना शिबाहारा (दोनों जापान)

मिश्रित युगल–

विजेता–लूसिया स्टेफनी व राफेल माटोस (दोनों ब्राजील)

उपविजेता–सानिया मिर्जा व रोहन बोपन्ना (दोनों भारत)

फ्रेंच ओपन–2023 (28 मई-11 जून, 2023; पेरिस)

पुरुष एकल–

विजेता–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

उपविजेता–कैस्पर रूड (नॉर्वे)

☞ **2021**–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

☞ **2022**–राफेल नडाल (स्पेन)

महिला एकल–

विजेता–इगा स्वियातेक (पोलैण्ड)

उपविजेता–कैरोलिना मुचोवा (चेक गणराज्य)

☞ **2021**–बारबोरा क्रेजीकोवा (चेक गणराज्य)

☞ **2022**–इगा स्वियातेक (पोलैण्ड)

पुरुष युगल–

विजेता–इवान डोडिग (क्रोएशिया) व ऑस्टिन क्राजिसेक (अमरीका)

उपविजेता–सैंडर गिले और जोरान वीलीजेन (दोनों चेक गणराज्य)

महिला युगल–

विजेता–सीह सू-वेई (ताइवान) व वांग जिन्यू (चीन)

उपविजेता–लेहा फर्नांडिज (कनाडा) और टेलर टाउनसेंड (अमरीका)

मिश्रित युगल–

विजेता–मिमा काटो (जापान) और टिम पुट्ज (जर्मनी)

उपविजेता–बिनाका वनेसा एंड्रेस्कू (कनाडा) और माइकल वीनस (न्यूजीलैण्ड)

विम्बलडन ओपन टेनिस–2023 (3-16 जुलाई, 2023; लंदन)

पुरुष एकल

विजेता–कार्लोस अल्काराज (Carlos Alcaraz) (स्पेन)

उपविजेता–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

☞ **2021**–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

☞ **2022**–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

महिला एकल

विजेता–मार्केटा वोंड्रोसोवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता–ओंस जेब्युर (ट्यूनीशिया)

☞ **2021**–एश्ले बार्टी (आस्ट्रेलिया)

☞ **2022**–एलिना रिबाकिना (कजाखस्तान)

पुरुष युगल–

विजेता–वेस्ले कूल हॉफ (नीदरलैड्स) व नील स्कुप्स्की (ब्रिटेन)

उपविजेता–मार्सेल ग्रोनोलस (स्पेन) व होरासियो जेबालोस (अर्जेन्टीना)

महिला युगल–

विजेता–सीह सू वेई (ताइवान) व बारबोरा स्ट्राइकोवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता–एलिसे मर्टेन्स (बेल्जियम) व स्टॉर्म हंटर (आस्ट्रेलिया)

मिश्रित युगल–

विजेता–मेट पैविक (क्रोएशिया) व ल्यूडमाइला किचेनॉक (यूक्रेन)

उपविजेता–जोरान व्लीगेन (बेल्जियम) व शू यिफान (चीन)

अमरीकी ओपन टेनिस–2023 (28 अगस्त–10 सितम्बर, 2023; न्यूयॉर्क)

पुरुष एकल

विजेता–नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) (सर्बिया)

उपविजेता–डेनिल मेदवेदेव (रूस)

☞ **2021**–डेनिल मेदवेदेव (रूस)

☞ **2022**–कार्लोस अल्कारेज (स्पेन)

महिला एकल

विजेता–कोको गॉफ (अमरीका)

उपविजेता–आर्यना सबालेंका (बेलारूस)

☞ **2021**–एम्मा रादुकानू (ब्रिटेन)

☞ **2022**–इगा स्वियातेक (पोलैण्ड)

पुरुष युगल

विजेता–राजीव राम (अमरीका) व जो सेलिसबरी (ब्रिटेन)

उपविजेता–रोहन बोनप्पा (भारत) व मैथ्यू एबडेन (आस्ट्रेलिया)

महिला युगल

विजेता–गैब्रिएला डाब्रोव्स्की (कनाडा) व एरिन रूटलिफ (न्यूजीलैण्ड)

उपविजेता–लॉरा सीगमुंड (जर्मनी) व वेरा ज्वोनारेवा (रूस)

मिश्रित युगल

विजेता–अन्ना डानिलिना (कजाखस्तान) व हैरी हैलियोवारा (फिनलैण्ड)

उपविजेता–जेसिका पेगुला व ऑस्टिन क्राजिसेक (दोनों अमरीका)

टाटा महाराष्ट्र ओपन टेनिस–2023 (जनवरी, 2023; पुणे)

एकल : विजेता–टल्लोन ग्रीक (Tallone Grikspoor) (डेनमार्क)

युगल एकल : विजेता–सैंडर गिले व जोरान व्लीगेन (दोनों बेल्जियम)

कतर ओपन टेनिस–2023 (11-25 फरवरी, 2023; दोहा, कतर)

पुरुष एकल : विजेता–डेनियल मेदवेदेव (रूस)

उपविजेता–एण्डी मरे (ब्रिटेन)

महिला एकल : विजेता–इगा स्वियातेक (पोलैण्ड)

उपविजेता–जेसिका पेगुला (अमरीका)

बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस/इंडियन वेल्स (मास्टर्स) टेनिस–2023

(6-19 मार्च, 2023; इंडियन वेल्स, कैलीफॉर्निया)

पुरुष एकल : विजेता–कार्लोस अल्कराज (Carlos Alcaraz) (स्पेन)

उपविजेता–डेनियल मेदवेदेव (रूस)

महिला एकल : विजेता–एलेना रिबाकिना (कजाखस्तान)

उपविजेता–आर्यना सबालेंका (बेलारूस)

मियामी ओपन टेनिस, 2023 (21 मार्च-2 अप्रैल, 2023; फ्लोरिडा, मियामी; अमरीका)

पुरुष एकल : विजेता–डेनियल मेदवेदेव (रूस)

उपविजेता–जानिक सिन्नट (इटली)

महिला एकल : विजेता–पेत्रा क्वितोवा (चैक गणराज्य)

उपविजेता–एलेना रिबाकिना (कजाखस्तान)

महिलाओं का पोर्श ग्रांड प्रिक्स ओपन टेनिस–2023 (स्टुटगार्ट ओपन) (17-23 अप्रैल, 2023; स्टुटगार्ट, जर्मनी)

एकल : विजेता–इगा स्वियातेक (Iga Swiatek) (पोलैण्ड)

युगल : विजेता–डिजायरे मैरी क्रॉजिक (अमरीका) व डेमी शूर्स (नीदरलैण्ड्स)

पुरुषों का मोंटोकार्लो मास्टर्स टेनिस–2023 (116वाँ) (अप्रैल, 2023; मोंटोकार्लो कंट्री क्लब, फ्रांस)

एकल : विजेता–आन्द्रे रूबालेव (रूस)

युगल : विजेता–इवान डोडिग (क्रोएशिया) व ऑस्टिन क्राजिसेक (अमरीका)

इटैलियन ओपन टेनिस–2023 (रोम मास्टर्स) (9-21 मई, 2023; रोम)

पुरुष एकल : विजेता–डेनियल मेदवेदेव (रूस)

STUDYPDF WALLAH

उपविजेता–होल्कर रून (डेनमार्क)
महिला एकल : विजेता–ऐलना रिबाकिना (Elena Rybakina) (कजाखस्तान)
उपविजेता–आनहेलिना किलिनीना (यूक्रेन)

मैड्रिड ओपन टेनिस–2023 (25 अप्रैल–7 मई, 2023; मैड्रिड, स्पेन)
पुरुष एकल : विजेता–कार्लोस अल्कराज (Carlos Alcaraz) (स्पेन)
महिला एकल : विजेता–आर्यना सबालेंका (बेलारूस)

बॉस ओपन टेनिस–2023 (12-18 जून, 2023; स्टुटगार्ड, जर्मनी)
पुरुष एकल : विजेता–फ्रांसिस टियाफोए (अमरीका)
उपविजेता–जान-लेनार्ड स्ट्रफ (जर्मनी)

हॉप मैन कप–2023 (32वाँ) (19-23 जुलाई, 2023; नीस, फ्रांस)
विजेता–क्रोएशिया (2-0)
उपविजेता–स्विट्जरलैण्ड

लेवर कप–2023 (22-24 सितम्बर, 2023; वैंकुवर, कनाडा)
विजेता–विश्व टीम (2-0)
उपविजेता–यूरोपीय टीम

चीन ओपन टेनिस–2023 (अक्टूबर, 2023; बीजिंग, चीन)
एकल विजेता :
पुरुष वर्ग–जानिक सिनर (इटली)
महिला वर्ग–इगा स्वियातेक (पोलैण्ड)

महिलाओं की टोरे पैन पैसिफिक टेनिस–2023 (अक्टूबर, 2023; टोक्यो)
एकल विजेता : वेरोनिका एडुवर्ड डोविना कुदेरमेतोवा (रूस)
युगल विजेता : उलरीकी ईकेरी (नॉर्वे) व इन्ग्रिड नील (एस्टोनिया)

क्रिकेट (Cricket)

न्यूजीलैण्ड–इंगलैण्ड 2 टेस्ट मैचों की शृंखला (फरवरी, 2023; न्यूजीलैण्ड)
परिणाम–1-1 से बराबर

भारत–वेस्टइंडीज व दक्षिण अफ्रीका महिला त्रिकोणीय शृंखला (2023)
(19 जनवरी–2 फरवरी, 2023; ईस्ट लंदन)
ट्वेंटी–20 मैचों की शृंखला
विजेता–दक्षिण अफ्रीका (5 विकेट से)
उपविजेता–भारत

दक्षिण अफ्रीका–वेस्टइंडीज टेस्ट शृंखला (2023) (मार्च, 2023; द. अफ्रीका)
02 टेस्ट मैचों की शृंखला
विजेता–दक्षिण अफ्रीका (2-0)

भारत-आस्ट्रेलिया शृंखला (2023) (फरवरी-मार्च, 2023; भारत)
04 टेस्ट मैचों की शृंखला (बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी)
विजेता–भारत (2-1)
03 एकदिवसीय मैचों की शृंखला
विजेता–आस्ट्रेलिया (2-1)

ईरानी कप (2022–23) (1-5 मार्च, 2023; ग्वालियर)
विजेता–शेष भारत (238 रन)
उपविजेता–मध्य प्रदेश

88वीं रणजी ट्राफी (2022–23) (13 दिसम्बर, 2022-20 फरवरी, 2023; फाइनल-ईडेन गार्डन्स, कोलकाता)
विजेता–सौराष्ट्र (9 विकेट से)
उपविजेता–बंगाल

न्यूजीलैण्ड-श्रीलंका शृंखलाएं (मार्च-अप्रैल, 2023; न्यूजीलैण्ड)
02 टेस्ट मैचों की शृंखला
विजेता–न्यूजीलैण्ड (2-0)
03 एकदिवसीय मैचों की शृंखला
विजेता–न्यूजीलैण्ड (2-0)
03 टी-20 मैचों की शृंखला
विजेता–न्यूजीलैण्ड (2-1)

अफगानिस्तान-बांग्लादेश एक टेस्ट मैच की शृंखला (14-18 जून, 2023; मीरपुर , बांग्लादेश)
विजेता–बांग्लादेश (546 रन)

आईपीएल–XVI क्रिकेट प्रतियोगिता, 2023 (फाइनल : 29 मई, 2023)
विजेता–चेन्नई सुपरकिंग्स (पाँचवीं बार)
उपविजेता–गुजरात टाइटंस

भारत-वेस्टइंडीज शृंखला (जुलाई, 2023 (वेस्टइंडीज)
☞ दो टेस्ट मैचों की शृंखला
विजेता–भारत (1–0)

इंगलैण्ड-आस्ट्रेलिया महिला एशेज शृंखला (जून-जुलाई, 2023; इंगलैण्ड)
☞ 1 टेस्ट मैच, एकदिवसीय व 3 टी-20 मैचों की एशेज शृंखला खेलने के लिए आस्ट्रेलिया की महिला किकेट टीम ने इंगलैण्ड का दौरा जून-जुलाई, 2023 में किया था.
☞ इस शृंखला में खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच आस्ट्रेलिया ने 89 रनों से जीता.
☞ 3 ट्वेंटी-20 मैचों का पहला मैच आस्ट्रेलिया ने जीता, किन्तु अन्तिम दोनों मैच जीतकर इंगलैण्ड ने यह शृंखला 2-1 से अपने नाम की.
☞ 3 ओडीआई मैचों की शृंखला का दूसरा मैच ही आस्ट्रेलिया ने जीता. पहला व तीसरा मैच जीतकर इंगलैण्ड ने यह शृंखला भी 271 जीती.

दलीप ट्रॉफी, 2021-22 (18 जून-16 जुलाई, 2023)
विजेता–दक्षिणी क्षेत्र (14वीं बार)
उपविजेता–पश्चिमी क्षेत्र

आस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका शृंखलाएं (अगस्त-सितम्बर, 2023; दक्षिण अफ्रीका)
05 एकदिवसीय मैचों की शृंखला
विजेता–दक्षिण अफ्रीका (3-2)
03 टी-20 मैचों की शृंखला
विजेता–आस्ट्रेलिया (3–0)

16वाँ एशिया कप क्रिकेट–2023 (30 अगस्त-17 सितम्बर, 2023; पाकिस्तान, श्रीलंका)
विजेता–भारत (8वीं बार)
उपविजेता–श्रीलंका (गत विजेता)

भारत-आस्ट्रेलिया 3 एकदिवसीय मैचों की शृंखला (सितम्बर, 2023; भारत)
विजेता–भारत (2-1)

एथलेटिक्स (Athletics)

चेन्नई मैराथन–2023 (11वीं) (जनवरी, 2023; चेन्नई)
बोस्टन मैराथन–2023 (127वीं) (17 अप्रैल, 2023; बोस्टन, अमरीका)
49वीं बर्लिन मैराथन (24 सितम्बर, 2023 (बर्लिन, जर्मनी)

पुरुष वर्ग–
विजेता–इलियुड किपचोगे (कीनिया)
{2 घण्टे : 02 मिनट : 42 सेकण्ड; पाँचवीं बार विजेता}

चेन्नई मैराथन, 2023 : परिणाम एक दृष्टि में
पूर्ण मैराथन (42·195 किमी)

क्र.	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग
प्रथम	**विनोद कुमार श्रीनिवासन** (भारत) {2 : 37 : 28}	**ब्रिगिड जेरेंड किमितई** (कीनिया) {3 : 31 : 36}
द्वितीय	**ज्ञान बाबू** (भारत) {2 : 48 : 46}	**संध्या शंकर** (भारत) {3 : 33 : 57}
तृतीय	**जगदीशन मुनासामी** (भारत) {2 : 27 : 39}	**ममता रावत** (भारत) {3 : 53 : 41}

बोस्टन मैराथन, 2023 : परिणाम एक दृष्टि में
पूर्ण मैराथन (42·195 किमी)

प्रथम	**इवांस चैबेट** (कीनिया) {2 : 05 : 54}	**हेलेन ओबीरी** (कीनिया) {2 : 21 : 38}
द्वितीय	**गैब्रिएल गीए** (तंजानिया) {2 : 06 : 04}	**अमाने बोरिसो** (इथियोपिया) {2 : 21 : 50}
तृतीय	**बेंसन किपरुतो** (कीनिया) {2 : 06 : 06}	**लोनाह सालपीटर** (इजरायल) {2 : 21 : 57}

STUDYPDF WALLAH

महिला वर्ग–

विजेता–टिगिस्ट असीफा {कीनिया} {2 : 11 : 53; नया विश्व रिकॉर्ड}

☞ **पाँचवीं बार विजेता**

शिकागो मैराथन, 2023 (8 अक्टूबर, 2023; शिकागो)

पुरुष वर्ग–

विजेता–केल्विन किप्टम {कीनिया} {2 घण्टे : 00 मिनट : 35 सेकण्ड; नया विश्व रिकॉर्ड}

महिला वर्ग–

विजेता–सिफान हसन {नीदरलैण्ड्स} {2 : 13 : 44}

18वीं दिल्ली अर्द्ध मैराथन, 2023 (15 अक्टूबर, 2023; नई दिल्ली)

पुरुष वर्ग–

विजेता–डेनियल एबेन्यो {कीनिया} {00 घण्टे : 59 मिनट : 27 सेकण्ड}

उपविजेता–चालेस मटाटा {कीनिया} {01 घण्टे : 00 मिनट : 05 सेकण्ड}

महिला वर्ग–

विजेता–अलमाज अयाना {इथियोपिया} {1 : 07 : 58}

उपविजेता–स्टेला चेसांग {युगांडा} {01 घण्टे : 08 मिनट : 28 सेकण्ड}

☞ भारतीय धावकों में 2018 के विजेता अभिषेक पाल पुरुषों में व कविता यादव महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ रहे.

62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2023 (11-15 अक्टूबर, 2023; बेंगलूरू)

- **टीम खिताब**
  पुरुष वर्ग–सेना
  महिला वर्ग–रेलवे
- **सर्वश्रेष्ठ एथलीट**
  पुरुष वर्ग–मनु डीपी (सेना)
  महिला वर्ग–यमुना लदकत (महाराष्ट्र)

हॉकी (Hockey)

महिलाओं की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप (15-26 फरवरी, 2023; काकिनादा, आन्ध्र प्रदेश)

विजेता–मध्य प्रदेश (5-1)
उपविजेता–महाराष्ट्र
तीसरा स्थान–झारखण्ड

महिला हॉकी जूनियर एशिया कप हॉकी, 2023 (8वीं) (3-11 जून, 2023 (काकामिगाहारा, जापान)

विजेता–भारत (2-1) {पहली बार}
उपविजेता–दक्षिण कोरिया

पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी, 2023 (10वीं) (23 मई-1 जून, 2023; सलालाह, ओमान)

विजेता–भारत (2-1) {गत विजेता भी}
उपविजेता–पाकिस्तान

फुटबाल (Football)

संतोष ट्रॉफी (2022-23) {पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप} (फरवरी–मार्च, 2023)

विजेता–कर्नाटक (3-2)
उपविजेता–मेघालय
तीसरा स्थान–सेना

'ला लीगा' फुटबाल टूर्नामेंट, 2023 {12 अगस्त, 2022– 4 जून, 2023}

विजेता–बार्सीलोना क्लब (27वीं बार)

'कोपा डेल रे' (121 वाँ संस्करण) फुटबाल टूर्नामेंट, 2023 {6 मई, 2023 (सेविले}

विजेता–रीयल मैड्रिड (2-1)
उपविजेता–ओसासुना क्लब

इंटरकॉंटीनेंटल कप (तीसरा संस्करण) फुटबाल टूर्नामेंट, 2023 {9-18 जून, 2023; भुवनेश्वर}

विजेता–भारत (2-0)
उपविजेता–लेबनान

142वाँ फा कप (FA Cup) फुटबाल, 2022-23 (3 जून, 2023; वेम्बले स्टेडियम, लंदन)

विजेता–मैनेचेस्टर सिटी {2-1}
उपविजेता–मैनेचेस्टर यूनाइटेड

14वाँ सैफ (SAFF) फुटबाल, 2023 (21 जून-4 जुलाई, 2023; कांतीरवा स्टेडियम, बेंगलूरू)

विजेता–भारत {सर्वाधिक 9वीं बार विजेता}
उपविजेता–कुवैत

132वाँ डुरंड कप फुटबाल, 2023 (3 अगस्त–3 सितम्बर, 2023; कोलकाता, गुवाहाटी व कोकराझार)

विजेता–मोहन बगान {रिकॉर्ड 17वीं बार विजेता}
उपविजेता–ईस्ट बंगाल (16 बार की विजेता टीम)

बैडमिंटन (Badminton)

मलेशियाई ओपन बैडमिंटन, 2023 (10–15 जनवरी, 2023; कुआलालम्पुर)

पुरुष एकल :
विजेता–विक्टर एक्सेलसेन (डेनमार्क)
उपविजेता–कोडाइ नाराओका (जापान)

महिला एकल :
विजेता–अकाने आमागुची (जापान)
उपविजेता–आन से-यंग (द. कोरिया)

इंडिया ओपन बैडमिंटन, 2023 {योनेक्स सनराइज़ इंडिया ओपन} (17-22 जनवरी, 2023; नई दिल्ली)

पुरुष एकल :
विजेता–कुनलावुत वितिदसर्न (थाइलैण्ड)
उपविजेता–विक्टर एक्सेलसेन (डेनमार्क)

महिला एकल :
विजेता–आन से-यंग (द. कोरिया)
उपविजेता–अकाने आमागुची (जापान)

इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन, 2023 (24-29 जनवरी, 2023; जकार्ता, इंडोनेशिया)

पुरुष एकल :
विजेता–जोनातन क्रिस्टी (Jonatan Christe) (इंडोनेशिया)
उपविजेता–चिको औरा डूवी वार्डोयो (इंडोनेशिया)

महिला एकल :
विजेता–आन से-यंग (An Se-young) (द. कोरिया)
उपविजेता–कैरोलिना मारिन (स्पेन)

84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप (22-28 फरवरी, 2023; पुणे)

पुरुष एकल :
विजेता–मिथुन मंजूनाथ
उपविजेता–प्रियांशु राजावत

महिला एकल :
विजेता–अनुपमा उपाध्याय
उपविजेता–आकर्षि कश्यप

ऑल इंगलैण्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप, 2023 (14-19 मार्च, 2023; बर्मिंघम, इंगलैण्ड)

पुरुष एकल :
विजेता–ली शिफेंग (चीन)
उपविजेता–शी युकी (चीन)

महिला एकल :
विजेता–आन से-यंग (द. कोरिया)
उपविजेता–चेन यूफी (चीन)

स्विस ओपन बैडमिंटन, 2023 (21-26 मार्च, 2023; बासेल, स्विट्जरलैण्ड)

पुरुष एकल :
विजेता–कोकी वातानबे (जापान)
उपविजेता–चोउ टिएन चेन (चीनी ताइपे)

महिला एकल :
विजेता–पोर्नपावी चोचुवोंग (थाइलैण्ड)
उपविजेता–मिया ब्लिचफेल्ड (डेनमार्क)

पुरुष युगल :
विजेता–सात्विकसाइराज रैंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी (भारत)
उपविजेता–रियान शियानग्यू व टैन कियांग (दोनों चीन)

एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप, 2023 (25-30 अप्रैल, 2023; दुबई, संयुक्त अरब अमीरात)

पुरुष एकल :
विजेता–एंथनी सिनिसुका गिनटिंग (इण्डोनेशिया)
उपविजेता–लोह कियान यिउ (सिंगापुर)

महिला एकल :
विजेता–ताइ त्जू-यिंग (चीनी ताइपै)
उपविजेता–आन से-यंग (द. कोरिया)

पुरुष युगल :
विजेता–सात्विकसाइराज रैंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी (भारत)
उपविजेता–आंग यी सिन व तिओ एई यी (दोनों मलेशिया)

ओर्लियांस मास्टर्स बैडमिंटन, 2023 (4–9 अप्रैल, 2023; ओर्लियांस, फ्रांस)

पुरुष एकल :
विजेता–प्रियांशु राजावत (भारत)
उपविजेता–मैगनस जोहान्नेसेन (डेनमार्क)

महिला एकल :
विजेता–कैरोलिन मारिन (स्पेन)
उपविजेता–बीवेन झांग (चीन/अमरीका)

स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन, 2023 (28 मार्च-2 अप्रैल, 2023; मैड्रिड, स्पेन)

पुरुष एकल :
विजेता–कैंटा निशिमोतो (जापान)
उपविजेता–कांता त्सुनियामा (जापान)

STUDYPDF WALLAH

महिला एकल :
विजेता–ग्रगोरिया मारिस्का (इंडोनेशिया)
उपविजेता–पी.वी. सिंधु (भारत)

सुदीरमन कप बैडमिंटन (18वीं) (14-21 मई, 2023; सूचो, चीन)
विजेता–चीन (3-0)
उपविजेता–दक्षिण कोरिया

मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन (23-28 मई, 2023; कुआलालम्पुर)

एकल खिताब :
पुरुष वर्ग : विजेता–एच. एस. प्रणय {भारत}
उपविजेता–वैंग यांग हांग (चीन)
महिला वर्ग : विजेता–अकाने यामागुची (जापान)
उपविजेता–ग्रिगोरिया मारिस्का तुजुंग (इंडोनेशिया)

इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन (13-18 जून, 2023; जकार्ता)

पुरुष एकल :
विजेता–विक्टर एक्सेल (Viktor Axelsen) {डेनमार्क}
उपविजेता–एंथनी सिनिसुका गिंटिंग (इंडोनेशिया)

महिला एकल :
विजेता–चेन यूफी (चीन)
उपविजेता–कैरोलिना मारिन (स्पेन)

कोरिया ओपन बैडमिंटन (18-23 जुलाई, 2023; यि ओ सु, दक्षिण कोरिया)

पुरुष एकल :
विजेता–एंडर्स एंटोनसेन (Anders Antonsen) {डेनमार्क}
उपविजेता–लोह कीन यिउ (सिंगापुर)

महिला एकल :
विजेता–आन से-यंग (An Se-Young) {दक्षिण कोरिया}
उपविजेता–ताइ त्जू यिंग (Tai Tzuying) {चीनी ताइपै}

कनाडा ओपन बैडमिंटन (4-9 जुलाई, 2023; कैलगरी, कनाडा)

पुरुष एकल :
विजेता–लक्ष्य सेन {भारत}
उपविजेता–ली शीफेंग (चीन)

महिला एकल :
विजेता–अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) {जापान}
उपविजेता–रत्चानोक इंटानौन (थाइलैण्ड)

हांगकांग ओपन, 2023 (33वाँ) (12-17 सितम्बर, 2023; हांगकांग)

पुरुष एकल :
विजेता–जोनाथन क्रिस्टी (इण्डोनेशिया)
उपविजेता–कैंटा निशिमोतो (जापान)

महिला एकल :
विजेता–अकाने यामागुची (जापान)
उपविजेता–झांग यिमान (चीन)

चीनी ओपन, 2023 (5-10 सितम्बर, 2023; चांगझू, चीन)

पुरुष एकल :
विजेता–विक्टर एक्सेलसेन (डेनमार्क)
उपविजेता–लू जुआंग झू (चीन)

महिला एकल :
विजेता–आन से यंग (दक्षिण कोरिया)
उपविजेता–अकाने यामागुची (जापान)

डेनमार्क ओपन, 2023 (17-22 अक्टूबर, 2023; एरेना फिन, डेनमार्क)

पुरुष एकल :
विजेता–ही वेंग होंगयांग (चीन)
उपविजेता–ली जी जिया (मलेशिया)

महिला एकल :
विजेता–चेन यू फी (चीन)
उपविजेता–कैरोलिना मारिन (स्पेन)

गोल्फ (Golf)

ऑगस्ता मास्टर्स गोल्फ, 2023 (6–9 अप्रैल, 2023; जॉर्जिया, अमरीका)
विजेता–जॉन राहम (Jon Rahm) (स्पेन)

105वीं पीजीए चैम्पियनशिप–2023 (18–21 मई, 2022; पिट्सफोर्ड, न्यूयॉर्क, अमरीका)
विजेता–ब्रूक्स कोएप्का (Brooks Koepka) (अमरीका)

गोल्फ के मेज़र खिताब–एक दृष्टि में

- चार मेज़र खिताब होते हैं–ऑगस्ता मास्टर्स, पीजीए चैम्पियनशिप, यूएस ओपन व द ओपन चैम्पियनशिप
- इनका आयोजन क्रमशः अप्रैल, मई, जून व जुलाई माह में होता है.

यूएस ओपन गोल्फ–2023 (15-18 जून, 2023; लॉस एंजेल्स, अमरीका)
विजेता–विंधम क्लार्क (Wyndham Clark) (अमरीका)

राइडर कप गोल्फ–2023 (44वाँ) {अक्टूबर, 2023; रोम (इटली)}
विजेता–यूरोप
उपविजेता–अमरीका

शतरंज (Chess)

फिडे (FIDE) शतरंज विश्व चैम्पियनशिप, 2023 (9–30 अप्रैल, 2023; अस्ताना, कजाखस्तान)
विजेता–डिंग लिरेन (Ding Liren) (चीन)
उपविजेता–इयान नेपोमनियाचची (Ian Nepomniachtchi) (नॉर्वे)

नॉर्वे शतरंज चैम्पियनशिप, 2023 (29 मई – 9 जून, 2023; स्टावान्गर, नॉर्वे)
विजेता–हिकारू नाकामुरा (अमरीका)
उपविजेता–फैबियानो कारूआना (अमरीका)
तीसरा स्थान–मुकेश डी. (भारत)

49वीं भारतीय महिला शतरंज चैम्पियनशिप, 2023 (30 जून–10 जुलाई, 2023; अहमदाबाद, गुजरात)
विजेता–पद्मिनी राउत
उपविजेता–मैरी एन. गोम्स

वी.गेजा हेटेनयी मेमोरियल सुपर जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, 2023 (11-19 जुलाई, 2023; बुडापेस्ट, हंगरी)
विजेता–आर. प्रज्ञानानन्द (भारत)
उपविजेता–एम. अमीन तबाताबेई (ईरान)

फिडे (FIDE) महिला शतरंज विश्व चैम्पियनशिप, 2023 (5–23 जुलाई, 2023; शंघाई, चीन)
विजेता–जू वेनजुन (Ju Wenjun) (चीन) {चौथी बार}
उपविजेता–लेई टिंगजी (चीन)

फॉर्मूला-1 रेसिंग (Formula-1 Racing)

बहरीन ग्रांड प्रिक्स (5 मार्च, 2023; साखिर, बहरीन)
विजेता–एम. वर्स्टापेन (M. Verstappen) {रेडबुल टीम}
उपविजेता–सऊदी अरबियन ग्रांड प्रिक्स (19 मार्च, 2023; जेद्दा सर्किट)
विजेता–एस. पेरेज (रेडबुल टीम)
उपविजेता–एम. वर्स्टापेन (M. Verstappan) {रेडबुल टीम}

अरबेजान ग्रांड प्रिक्स (30 अप्रैल, 2023; बाकू)
विजेता–एस. पेरेज (रेडबुल टीम)
उपविजेता–एम. वर्स्टापेन (M. Verstappan) {रेडबुल टीम}

मियामी ग्रांड प्रिक्स (7 मई, 2023; मियामी)
विजेता–एम. वर्स्टापेन (M. Verstappan) {रेडबुल टीम}
उपविजेता–एस. पेरेज (रेडबुल टीम)

मोनाको ग्रांड प्रिक्स (28 मई, 2023; मियामी)
विजेता–एम. वर्स्टापेन (M. Verstappan) {रेडबुल टीम}
उपविजेता–एफ. एलोंसो

कनाडियन ग्रांड प्रिक्स (16–18 जून, 2023; कनाडा)
विजेता–एम. वर्स्टापेन (M. Verstappan) {रैडबुल टीम}
उपविजेता–एफ. एलोंसो (स्पेन)

ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स (9 जुलाई, 2023; सिल्वर-स्टोन सर्किट, यूके)
विजेता–मैक्स वर्सटापेन, नीदरलैंड्स (रेडबुल टीम)
उपविजेता–एल. नॉरिस (मैकलारेन टीम)

आस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स (30 जून – 2 जुलाई, 2023; रेड बुल रिंग, स्पीलबर्ग, आस्ट्रिया)
विजेता–मैक्स वर्सटापेन, नीदरलैंड्स (रेडबुल टीम)
उपविजेता–चार्ल्स लक्लर्क, मोनाको (फरारी टीम)

हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स (जुलाई 2023 हुगांरोहिंग सर्किट)
विजेता–मैक्स वर्सटापेन, नीदरलैंड्स (रेडबुल टीम)

बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स (जुलाई, 2023)
विजेता–मैक्स वर्सटापेन, नीदरलैंड्स (रेडबुल टीम)

इटैलियन ग्रांड प्रिक्स (3 सितम्बर, 2023; मोंजा, इटली)
विजेता–एम. वर्स्टापेन (रेड बुल टीम)

STUDYPDF WALLAH

सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स (17 सितम्बर, 2023; मरीना बे स्ट्रीट सर्किल)

विजेता–एम. वर्स्टापेन (रेड बुल टीम)

जापानी ग्रांड प्रिक्स (24 सितम्बर, 2023; सुजुकी इण्टरनेशनल रेसिंग कोर्स)

विजेता–एम. वर्सटापेन, नीदरलैण्ड (रेडबुल टीम)

खेलकूद के कुछ विशिष्ट आयोजन/ चर्चित गतिविधियाँ-2023

☞ पुरुषों की विश्व कप हॉकी, 2023

अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वावधान में पुरुषों के 15वें विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भारत की मेजबानी में भुवनेश्वर व राउरकेला में 13–29 जनवरी, 2023 के दौरान सम्पन्न हुआ. इसका खिताब गत विजेता बेल्जियम को फाइनल में पेनल्टी शूटआउट दौर में 5- 4 से हराकर जर्मनी ने जीता. भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम पर निर्धारित समय तक फाइनल मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहने पर हार-जीत का फैसला पेनल्टी शूट आउट में हुआ. तीसरा स्थान नीदरलैण्ड्स का रहा. जर्मनी ने तीसरी बार पुरुषों की हॉकी का विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की. जर्मनी के निक्लास वेलेन (Niklas Wellen) को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

☞ महिलाओं का अंडर-19 आईसीसी विश्व कप क्रिकेट, 2023

14-19 जनवरी, 2023 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के चार विभिन्न शहरों में महिलाओं के अंडर-19 आईसीसी टी-20 विश्व कप (Under-19 World Cup) का आयोजन हुआ. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) के तत्वावधान में आयोजित इस विश्व कप का खिताब भारत ने पोटचेफस्ट्रूम में फाइनल में इंगलैण्ड को हराकर अपने नाम किया. टी-20 प्रारूप में खेले गए आईसीसी के इस विश्व कप में कुल 16 टीमें शामिल थीं. इनमें सेमीफाइनल्स में पहुँचने वाली चार टीमें भारत, इंगलैण्ड, न्यूजीलैण्ड व आस्ट्रेलिया थीं. 29 जनवरी, 2023 को फाइनल मुकाबला भारत व इंगलैण्ड के बीच था, जिसमें 7 विकेट से विजय दर्ज करके आईसीसी का महिलाओं का पहला अंडर-19 विश्व कप भारत के नाम रहा. फाइनल मुकाबले में इंगलैण्ड की पूरी टीम को 68 रन पर आउट कर भारतीय टीम ने विजय का लक्ष्य 3 विकेट खोकर ही प्राप्त कर लिया.

☞ आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप क्रिकेट, 2023

10-26 फरवरी, 2023 के दौरान द. अफ्रीका में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) के तत्वावधान में आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप, 2023 (8वाँ) का आयोजन हुआ. 26 फरवरी, 2023 को केपटाउन में खेले गए फाइनल में मेजबान द. अफ्रीका को 19 रन से हाराकर आस्ट्रेलिया ने टी-20 विश्व कप का खिताब 6ठीं बार जीत लिया.

- महिला टी-20 विश्व कप के इस संस्करण में कुल 10 देशों की महिला क्रिकेट टीमों ने भाग लिया. यह 10 देश हैं–आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंगलैंड, भारत, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और थाइलैण्ड.
- टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन (230 रन) दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ट ने बनाए.
- टूर्नामेंट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' (Player of the Series) का पुरस्कार आस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) को मिला.
- सर्वाधिक 11 विकेट स्विट्जरलैण्ड्स की सोफी एक्लेस्टोन को प्राप्त हुआ.
- इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थीं. भारतीय टीम सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया से पराजित हुई थी.
- वर्ष 2024 में आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप (9वें) का आयोजन बांग्लादेश की मेजबानी में प्रस्तावित है.

☞ पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2023

30 जनवरी–11 फरवरी, 2023 के दौरान मध्य प्रदेश की मेजबानी में पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स सम्पन्न हुए. 27 खेलों की स्पर्द्धाएं इस बार इन खेलों में शामिल थीं. 13 दिन तक चले इन खेलों में 56 स्वर्ण, 55 रजत व 50 कांस्य सहित सर्वाधिक 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने इस बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. यह तीसरा अवसर है, जबकि महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा. 2019 व 2020 में क्रमशः दूसरे व तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा था.

☞ महिलाओं का पहला प्रीमियर लीग, 2023

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के महिलाओं के पहले प्रीमियर लीग (WPL-Women's Premier League) टूर्नामेंट का आयोजन मार्च, 2023 में हुआ. इसका खिताब दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली मुम्बई इंडियन्स ने जीता. पुरुषों की आईपीएल के तर्ज पर महिला क्रिकेटरों के इस लीग में पाँच टीमें शामिल थीं. इन टीमों के फ्रैंचाइजियों का निर्धारण जनवरी, 2023 में नीलामी के माध्यम से हुआ था, जबकि टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 13 फरवरी, 2023 को हुई थी.

इन टीमों के मध्य कुल 22 मैच 4–26 मार्च, 2023 के दौरान मुम्बई में ब्रेबोर्न स्टेडियम व डीबाई पाटिल स्टेडियम पर खेले गए. प्ले ऑफ दौर के पश्चात् फाइनल में पहुँची दो टीमें दिल्ली कैपिटल्स व मुम्बई इंडियन्स थीं. 26 मार्च, 2023 को ब्रेबोर्न स्टेडियम पर खेले गए फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर मुम्बई इंडियन्स ने पहले डब्ल्यूपीएल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. इस खिताबी विजय के लिए ट्रॉफी के साथ ₹ 6 करोड़ का पुरस्कार में मुम्बई इंडियन्स को मिले. उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को ₹ 3 करोड़ प्राप्त हुए.

- मुम्बई इंडियन्स की नताली रूथ स्कीवरब्रंट को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.
- प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मुम्बई इंडियन्स की ही हाइले क्रिस्टन मैथ्यूज (Hayley Kristen Matthews) को मिला.
- टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन (345 रन) बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिल्ली कैपिटल्स की मेग लैनिंग (Meg Lanning) को मिली.
- टूर्नामेंट में सर्वाधिक 16 विकेट किफायत के लेने के लिए पर्पल कैप मुम्बई इंडियन्स की हाइले क्रिस्टन मैथ्यूज को मिली.
- **टूर्नामेंट में हैट्रिक्स**–1 (इस्सी वोंग)
- **फेयर प्ले अवार्ड**–मुम्बई इंडियन्स व दिल्ली कैपिटल्स
- **शतकीय परियाँ**–कोई नहीं
- किसी मैच में सर्वाधिक छक्के–8 छक्के
  (सोफी डिवाइन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू)
- **सीरीज में सर्वाधिक छक्के**–13 छक्के (सोफी डिवाइन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू तथा शैफाली वर्मा, दिल्ली कैपिटल्स)
- **व्यक्तिगत सर्वोच्च पारी**–99 रन (सोफी डिवाइन, रॉयल चैलेंजर्स)
- **कैच ऑफ द सीरीज**–हरमनप्रीत कौर {मुम्बई इंडियन्स, देविका वैद्या (यूपी वारियर्स) को आउट करने के लिए लिया गया कैच}

☞ आईसीसी अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट, 2022

14 जनवरी–5 फरवरी, 2022 के दौरान वेस्टइंडीज की मेजबानी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) के तत्वावधान में 14वें अंडर–19 विश्व कप (Under-19 World Cup) क्रिकेट का आयोजन हुआ. इसके खिताब के लिए फाइनल मुकाबला भारत व इंगलैण्ड के बीच हुआ. 5 फरवरी, 2022 को खेले गए फाइनल में इंगलैण्ड को फाइनल में हराकर भारत ने खिताब पर कब्जा किया. भारत ने कुल मिलाकर पाँचवीं बार यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की.

16 देशों की टीमें इस टूर्नामेंट तक शामिल थीं. कोरोना सम्बन्धी कड़े प्रतिबन्धों के कारण न्यूजीलैण्ड के अंतिम समय में टूर्नामेंट से हटने के कारण उसके स्थान पर स्कॉटलैण्ड को इसमें शामिल किया गया था. फाइनल सहित कुल 48 मैच इस टूर्नामेंट में खेले जाने थे, किन्तु कोविड–19 के कारण कनाडा के दो मैच रद्द कर दिए गए थे.

STUDYPDF WALLAH

यह मैच एंटीगुआ, गुयाना, सेंट किट्स व त्रिनिदाद में खेले गए थे.

- वर्ष 2022 के इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन (506 रन) बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के डिवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया.
- टूर्नामेंट में सर्वाधिक 17 विकेट श्रीलंका के डूयूनिथ वेल्लालेज (Dunith Wellalage) ने लिए.
- यश ढुल इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान थे.
- 16 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थीं.
- भारत पाँच बार (2000, 2008, 2012, 2018 व 2022) अण्डर–19 विश्व कप का विजेता रहा है.
- भारत तीन बार उपविजेता रहा है. भारत 2006, 2016 व 2020 में उपविजेता था.

☞ **आईपीएल-XVI क्रिकेट प्रतियोगिता, 2023**

मई, 2023 में ट्वेंटी–20 क्रिकेट का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इण्डियन प्रीमियर लीग (IPL) के 16वें संस्करण–आईपीएल–XVI क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच देश के विभिन्न शहरों में खेले गए. 29 मई, 2023 को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम पर टूर्नामेंट का फाइनल मैच महेन्द्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स व हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस के मध्य खेला गया. फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स टीम आईपीएल के 16वें सत्र की विजेता बनी. वर्षा से बाधित फाइनल मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत् 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य विजय के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स को मिला था. इससे पूर्व पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15वें अंतिम ओवर में 13 रन तथा अंतिम दो गेंदों पर 10 रन सीएसके को चाहिए थे. अंतिम दो गेंदों पर एक छक्का व एक चौका लगाकर रविन्द्र जडेजा ने विजय का सेहरा सीएसके को दिलवा दिया.

चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल में यह पाँचवां खिताब है. इससे पूर्व 2010, 2011, 2018 व 2021 में वह इसकी विजेता रही थी.

आईपीएल–XVI क्रिकेट टूर्नामेन्ट–2023 : प्रमुख रिकॉर्ड/पुरस्कार एक दृष्टि में

- ☞ **विजेता**–*चेन्नई सुपरकिंग्स (कप्तान–महेन्द्र सिंह धोनी) {₹ 20 करोड़}*
- ☞ **उपविजेता**–*गुजरात टाइटंस (कप्तान–हार्दिक पांड्या) {₹ 12·50 करोड़}*
- ☞ ***प्लेयर ऑफ द सीरीज***–*शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस) {₹ 10·00 लाख}*
- ☞ ***सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप***–*शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस) {सर्वाधिक 890 रन} {₹ 10·00 लाख*
- ☞ ***सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप***–*मोहम्मद शमी (गुजरात टाइटंस) {सर्वाधिक 28 विकेट} {₹ 10·00 लाख}*
- ☞ ***फेयर प्ले अवार्ड***–*दिल्ली कैपिटल्स {₹ 10·00 लाख}*
- ☞ ***एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन***–*यशस्वी जैसवाल (राजस्थान रॉयल्स) {₹ 10·00 लाख}*
- ☞ ***गेम चेंजर ऑफ द सीजन***–*शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस) {₹ 10·00 लाख}*
- ☞ ***सीरीज में कुल छक्के***–*1124 (आईपीएल के किसी भी संस्करण से अधिक)*
- ☞ ***सीरीज में कुल चौके***–*2174*
- ☞ ***सीजन में कुल शतक***–*12*
- ☞ ***सीजन में हैट्रिक***–*1 (राशिद खान, गुजरात टाइटंस विरुद्ध केकेआर)*

☞ **19वें एशियाई खेल–2023**

23 सितम्बर-8 अक्टूबर, 2023 के दौरान चीन के हांगझोऊ में 19वें एशियाई खेल सम्पन्न हुए. 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने पदकों की संख्या 100 से पार की. कुल 107 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत व 41 कांस्य) जीतकर 2018 के 18वें एशियाई खेलों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी काफी पीछे छोड़ दिया. जकार्ता में सम्पन्न 18वें एशियाई खेलों में भारत ने 16 स्वर्ण, 23 रजत व 31 कांस्य सहित कुल 70 पदक जीते थे तथा पदक तालिका में आठवाँ स्थान प्राप्त किया था. 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया.

19वें एशियाई खेलों में 40 खेलों की 61 स्पर्द्धाएं, जिनमें 481 पदक प्रतियोगिताएं दाँव पर थीं, शामिल थीं. 'हार्ट टु हार्ट/फ्यूचर (Heart to Heart /Future) 19वें एशियाई खेलों का सिद्धान्त वाक्य/नारा (Motto) था. कांगकांग (Congcong), लियानलियान (Lianlian), व चैनचेन (Chenchen), जिन्हें मेमोरीज् ऑफ जियांगनान (Memories of Jiangnan) नाम दिया गया था, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर (Mascot) थे. खेलों के आधिकारिक गीत With you and Me को एंजेला झांग व अन्य ने गाया था.

19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक 383 पदक (201 स्वर्ण, 111 रजत व 71 कांस्य) जीतकर चीन ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. यह लगातार 11वाँ आयोजन था, जब चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. दूसरे स्थान पर रहे जापान (गत 18वें एशियाड में भी जापान दूसरे स्थान पर था) ने 52 स्वर्ण, 67रजत व 69 कांस्य पदकों सहित कुल 188 पदक इन खेलों में प्राप्त किए. तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा जिसने कुल 190 पदक (42 स्वर्ण, 59 रजत व 89 कांस्य) इन खेलों में प्राप्त किए.

खेलकूद : मील के पत्थर

☞ **रोहित शर्मा : क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले भारतीय टीम के पहले कप्तान**

10 फरवरी, 2023 को नागपुर में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रन की पारी खेली. टेस्ट क्रिकेट में यह उनका नौवाँ शतक था. इसके साथ ही वह ऐसे पहले भारतीय कप्तान हो गए, जिन्होंने कप्तान रहते हुए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाए हैं.

☞ **टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार एक रन से विजय**

28 फरवरी, 2023 को न्यूजीलैण्ड की क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन में इंगलैण्ड के विरुद्ध शृंखला का दूसरा टेस्ट मैच केवल एक रन से जीता. टेस्ट क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई टेस्ट मैच 1 रन के अन्तर से जीता गया. इससे पूर्व 1993 में वेस्टइंडीज ने एडीलेड टेस्ट में आस्ट्रेलिया को 1 रन से हराकर विजय दर्ज की थी.

☞ **सयानतन दास : भारत के 81वें ग्रांड–मास्टर**

कोलकाता के 26 वर्षीय सयानतन दास शतरंज में देश के 81वें ग्रांडमास्टर (GM) फरवरी, 2023 में बने. इस खिताब के लिए आवश्यक तीन ग्रांडमास्टर नॉर्म (GM Norm) वह 2017 में ही हासिल कर चुके थे. ग्रांडमास्टर खिताब के लिए आवश्यक 2500 अंक 26 फरवरी, 2023 को फ्रांस के कान्स ओपन का खिताब जीतकर उन्होंने पूरी कर ली. इस प्रकार ग्रांडमास्टर खिताब के लिए 6 वर्ष की प्रतीक्षा उन्हें करनी पड़ी

कोलकाता के सयानतन दास ग्रांडमास्टर का खिताब पाने वाले भारत के 81वें (प. बंगाल के 11वें) व्यक्ति हैं. उनसे पूर्व यह खिताब पाने वाले भारत के 80वें खिलाड़ी चेन्नई के विग्नेश एन. आर. थे, जिन्होंने खिताब के लिए अपनी इलो रेटिंग सयानतन से एक सप्ताह पूर्व जर्मनी में एक टूर्नामेंट में पूरी की. यह भी उल्लेखनीय है कि विग्नेश के

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रनों से जीत

विजेता	विजय का रन–अन्तर	बनाम	स्थान	वर्ष
वेस्टइंडीज	*1*	*आस्ट्रेलिया*	*एडिलेड*	*1993*
न्यूजीलैण्ड	*1*	*इंगलैण्ड*	*वेलिंगटन*	*2023*
इंगलैण्ड	*2*	*आस्ट्रेलिया*	*बर्मिंघम*	*2005*
आस्ट्रेलिया	*3*	*इंगलैण्ड*	*मानचेस्टर*	*1902*
इंगलैण्ड	*3*	*आस्ट्रेलिया*	*मेलबर्न*	*1982*

STUDYPDF WALLAH

आगामी खेलों की गतिविधियाँ

- **यूरो कप–2024** : *जर्मनी*
- **फीफा विश्व कप फुटबाल**
- ***23वाँ–2026** में संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा व मैक्सिको में*
- **ओलम्पिक खेल**
- ***33वाँ** ओलम्पिक खेल वर्ष 2024 में पेरिस, फ्रांस में.*
- ***34वाँ** ओलम्पिक खेल वर्ष 2028 में लॉस एंजेल्स, अमरीका में.*
- **शीतकालीन ओलम्पिक खेल**
- ***25वें** शीतकालीन ओलम्पिक खेलों का आयोजन 2026 में मिलान व कोर्टिना में*
- **शीतकालीन पैरालिम्पिक खेल**
- ***14वें** शीतकालीन पैरालिम्पिक खेलों का आयोजन 6–15 मार्च, 2026 के दौरान मिलान व कोर्टिना में*
- **महिलाओं का अंडर–19 टी–20 विश्व कप**
- **दूसरा आयोजन** : *2025 में मलेशिया व थाइलैण्ड की संयुक्त मेजबानी में*

बड़े भाई विसाख एन.आर. ने भी ग्रांडमास्टर खिताब 2019 में प्राप्त किया था तथा वह भारत के 59वें ग्रांडमास्टर बने थे. विसाख व विग्नेश की जोड़ी भारत की पहली दो ग्रांडमास्टर भाइयों की जोड़ी है.

रणजी ट्रॉफी : पहली बार किसी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक

3 जनवरी, 2023 को राजकोट में सौराष्ट्र एवं दिल्ली के बीच रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर हैट्रिक बनाने में सफलता प्राप्त की. किसी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने का रणजी ट्रॉफी के 88 वर्षों के इतिहास में यह पहला ही मामला है तथा जयदेव उनादकट ऐसी उपलब्धि वाले पहले गेंदबाज हैं.

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीत का भारतीय टीम का विश्व रिकॉर्ड

भारत के दौरे पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम 15 जनवरी, 2023 को तिरुवनंतपुरम में तीन एकदिवसीय मैचों की शृंखला के तीसरे मैच में 317 रनों से पराजित हुई. श्रीलंका के विरुद्ध 317 रनों की यह विजय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से अब तक की सबसे बड़ी जीत है. इस मामले में पिछला रिकॉर्ड न्यूजीलैण्ड के नाम था जिसने 2008 में आयरलैण्ड को 290 रनों से हराया था.

शुभमन गिल : एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के पाँचवें बल्लेबाज

भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के पाँचवें बल्लेबाज जनवरी, 2023 में हो गए. 18 जनवरी, 2023 को हैदराबाद में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैण्ड के विरुद्ध एकदिवसीय मैच में 208 रन की पारी खेलकर दोहरा शतक बनाने वाले क्रिकेटरों की सूची में अपना नाम उन्होंने दर्ज करा लिया. एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले वह विश्व के आठवें तथा भारत के पाँचवें बल्लेबाज हैं. साथ ही ऐसी उपलब्धि वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी वह हैं.

उल्लेखनीय है कि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 10 बल्लेबाजों ने दोहरा शतक अद्यतन लगाए हैं. 7 दोहरे शतक भारतीय बल्लेबाजों ने ही बनाए हैं भारत के रोहित शर्मा ने 3 बार यह उपलब्धि प्राप्त की है.

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के दोहरे शतक

खिलाड़ी	रन	विरुद्ध	वर्ष
रोहित शर्मा	264	श्रीलंका	2014
वीरेन्द्र सहवाग	219	वेस्टइंडीज	2011
ईशान किशन	210	बांग्लादेश	2022
रोहित शर्मा	209	आस्ट्रेलिया	2013
रोहित शर्मा	208	श्रीलंका	2017
शुभमन गिल	208	न्यूजीलैण्ड	2023
सचिन तेंदुलकर	200	द. अफ्रीका	2010

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रनों की दृष्टि से पाँच बड़ी जीतें

तिथि/वर्ष/स्थान	विजयी टीम	विरुद्ध	रनों का अन्तर
15 जनवरी, 2023 ; तिरुवनंतपुरम	भारत	श्रीलंका	317
1 जुलाई, 2008 ; एवर्डीन	न्यूजीलैण्ड	आयरलैण्ड	290
4 मार्च, 2015 ; पर्थ	आस्ट्रेलिया	अफगानिस्तान	275
22 अक्टूबर, 2010 ; बेनोनी	द. अफ्रीका	जिम्बाब्वे	272
11 जनवरी, 2012 ; पार्ल	द. अफ्रीका	श्रीलंका	258

फॉलो ऑन मिलने के बाद न्यूजीलैण्ड विजय दर्ज करने वाली चौथी टीम

फरवरी 2023 में इंगलैण्ड-न्यूजीलैण्ड टेस्ट शृंखला के वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मैच में फॉलो ऑन का सामना न्यूजीलैण्ड ने किया. इसके बाद भी मैच में वापसी करते हुए न्यूजीलैण्ड ने 28 फरवरी, 2023 को यह टेस्ट 1 रन से जीता. टेस्ट क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में यह चौथी बार ही ऐसा हुआ कि फॉलो ऑन का सामना करने के बाद किसी टीम ने मैच में विजय दर्ज की. 1894 व 1981 में इंगलैण्ड ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध तथा 2001 में भारतीय टीम ने इंगलैण्ड के विरुद्ध ऐसी सफलता प्राप्त की थी.

200 अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबालर

20 जून, 2023 को पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबालर बने. उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड (पुरुष/महिला) अमरीका की महिला फुटबालर क्रिस्टीन लिली के नाम है. लिली ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय कॅरियर में वर्ष 1987 से 2010 के दौरान कुल 354 मैच खेले. महिला फुटबालर 300 से अधिक मैच खेल चुकी हैं, जिनमें कनाडा की क्रिस्टीन सिंक्लेयर (323), अमरीका की कार्ली लॉयड (316) और क्रिस्टी पियर्स (311) शामिल हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक

अन्तर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने का नया रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला ने हांगझोऊ में 19वें एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध खेलते हुए 27 सितम्बर, 2023 को स्थापित किया. इस मैच में केवल 34 गेंदों पर शतक बनाकर दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर द्वारा 29 अक्टूबर, 2017 को स्थापित 35 गेंदों के शतक के रिकॉर्ड, जिसकी बराबरी भारत के रोहित शर्मा ने 22 दिसम्बर, 2017 को श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए की थी, को भंग किया.

अन्तर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में केवल 9 गेंदों पर अर्द्ध शतक

अन्तर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से अर्द्ध शतक बनाने का नया रिकॉर्ड नेपाल के दीपेन्द्र सिंह ऐरी ने हांगझोऊ में 19वें एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध खेलते हुए 27 सितम्बर, 2023 को स्थापित किया. इस मैच में केवल 9 गेंदों पर अर्द्ध शतक बनाकर भारत के युवराज सिंह द्वारा 19 सितम्बर, 2007 को इंगलैण्ड के विरुद्ध खेलते हुए स्थापित 12 गेंदों पर अर्द्ध शतक के रिकॉर्ड को भंग किया.

●●●

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक राहुल जैन द्वारा मैसर्स प्रतियोगिता दर्पण के लिए उन्हीं के द्वारा थॉमसन प्रेस (इंडिया) लि., 18/35 देहली–मथुरा रोड, फरीदाबाद–121 007 (हरियाणा) से मुद्रित एवं 2/11A, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-2 से प्रकाशित

STUDYPDF WALLAH